सत्यमेव जयते

विदेश मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट । 2018-19

विदेश मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट । 2018-19

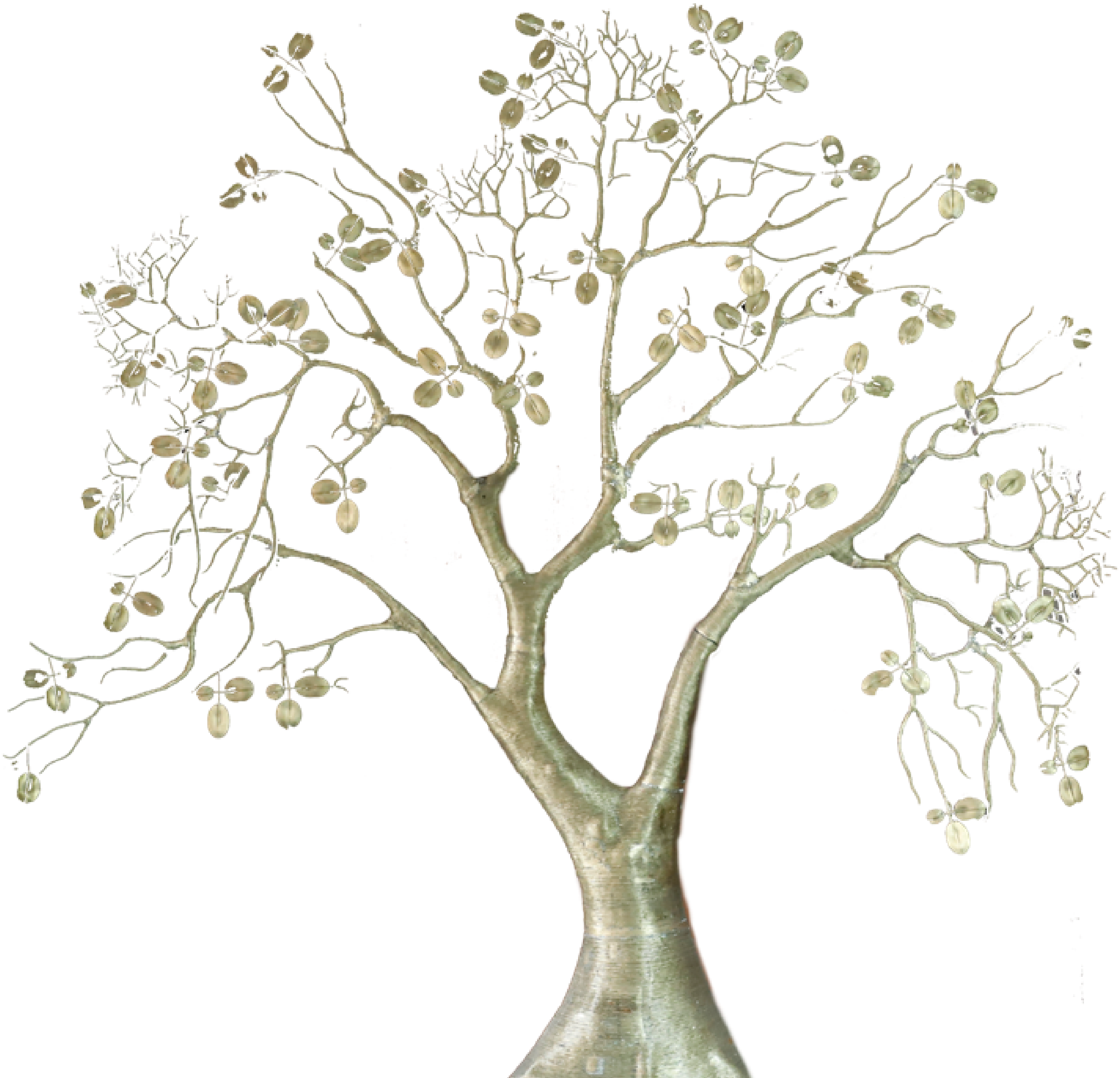

प्रकाशितः
नीति नियोजन एवं अनुसंधान प्रभाग, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

यह वार्षिक रिपोर्ट वेबसाइट www.mea.gov.in पर भी देखी जा सकती है।

Designed and Produced by
creativEdge
ce@aravalifoundation.in
www.creativedge.in

विषय सूची

प्रस्तावना और सार-संक्षेप	6
1. भारत के पड़ोसी	36
2. दक्षिण-पूर्व एशिया और एशिया-प्रशांत	70
3. पूर्वी एशिया	102
4. यूरेशिया	108
5. खाड़ी और पश्चिम एशिया	122
6. अफ्रीका	136
7. यूरोप और यूरोपीय संघ	160
8. अमेरिका	196
9. संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कानूनी और संधियाँ प्रभाग	224
10. निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले	246
11. बहुपक्षीय आर्थिक संबंध	254
12. सार्क और बिम्सटेक	262
13. विकास सहयोग	268
14. आर्थिक कूटनीति	280
15. राष्ट्र	290
16. आतंकवाद का मुकाबला	296
17. वैश्विक साइबर मुद्दे	298
18. बाउंड्री सेल	299
19. नीति नियोजन और अनुसंधान	300
20. प्रोटोकॉल	304
21. कॉन्सुलर, पासपोर्ट और वीजा सेवाएं	318
22. प्रवासी भारतीय मामले	332
23. प्रशासन और स्थापना	346
24. सूचना का अधिकार और मुख्य लोक सूचना कार्यालय	350
25. ई-शासन और सूचना प्रौद्योगिकी	352
26. संसद और समन्वय प्रभाग	356
27. बाहरी प्रचार और लोक राजनय प्रभाग	360
28. विदेशी सेवा संस्थान	366

29.	नालंदा प्रभाग	372
30.	राजभाषा नीति का कार्यान्वयन और विदेशों में हिंदी का प्रचार	374
31.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद	376
32.	भारतीय विश्व मामलों की परिषद	380
33.	विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली	390
34.	पुस्तकालय और अभिलेखागार	404
35.	वित्त और बजट	408
36.	परिशिष्ट	417

प्रस्तावना और सार-संक्षेप

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, विदेश मंत्रालय ने भारत की सुरक्षा में वृद्धि करने, अपनी प्रादेशिक एकता को बनाए रखने और भारत के आर्थिक रूपांतरण को सुकर बनाने संबंधी अपने व्यावहारिक और परिणामोन्मुखी क्रियाकलापों को निष्पादित करना जारी रखा। ऐसा द्विपक्षीय, प्रादेशिक और बहुपक्षीय भागीदारियों को मज़बूत बनाकर तथा प्रमुख वैश्विक मंचों में प्रभाव निर्माण करने के प्रयासों को जारी रखते हुए अति-सक्रिय तरीके से किया गया। प्रवासी भारतीयों के साथ गहन संपर्क स्थापित करने के हमारे प्रयासों की गति भी बनी रही जिसके लिए विशिष्ट उत्साह और अभिनव तंत्रों का प्रयोग किया गया।

द्विपक्षीय रूप से, रूस और चीन के साथ प्रधानमंत्री के अनौपचारिक शिखर-सम्मेलनों, यूएस के साथ 2+2 वार्ताएं, अफ्रीका, मध्य एशियाई गणराज्यों, लातिन अमेरिका, कैरिबियाई देशों के उच्च स्तरीय दौरे, और प्रथम भारत-नोरडिक शिखर सम्मेलन भी भारत के राजनयिक संबंधों के विस्तार में नए चरण के द्योतक हैं। सामुद्रिक मामलों पर भारत के विस्तारित होते क्षितिज को छह-सूत्रीय भारत-प्रशांत नीति के प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रतिबिंबित किया गया जिसने हमारी सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) की अवधारणा को पुन:प्रबलित किया। भारत ने 2 अक्टूबर, 2018 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि की प्रथम महासभा के आयोजन के साथ जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापवृद्धि के मुद्दों के संबंध में अग्रणी भूमिका निभाई। इसके साथ ही महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में दो-वर्षीय समारोहों की श्रृंखला का भी शुभारंभ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वैश्वीकरण पर विचार-विमर्श के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में भारत का अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के आयोजन के माध्यम से प्रदर्शित हुआ जिसमें भू-राजनीति, भू-अर्थव्यवस्था और भू-प्रौद्योगिकी जैसे तीनों स्तम्भों को शामिल किया गया था।

भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान किया जाना जारी रखा गया और स्थायित्व तथा समृद्धि के लिए पारस्परिक दृष्टि से लाभप्रद, लोक-केन्द्रित, क्षेत्रीय ढांचे का सृजन करने पर मुख्यत: ध्यान-केन्द्रित किया गया। द्विपक्षीय संबंधों की गति को कायम रखा गया तथा अवसंरचना और संपर्क परियोजनाओं के कार्य निष्पादन में प्रगति हासिल करने पर ध्यान-केंद्रित किया गया। पड़ोसी क्षेत्र में हमारे भागीदारों के साथ रेल, सड़क, पत्तनों, अंतर्देशीय जलमार्गों, पोत परिवहन तथा ऊर्जा और ईंधन पारेषण संबंधी

परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इसके साथ-साथ, लोगों-के-लोगों आपसी संबंधों को व्यापक बनाने के लिए अभिनव पहल भी जारी रखे गए।

नेपाल में, प्रधानमंत्री मोदी की राजकीय यात्रा के दौरान मई में अरुण III जल-विद्युत परियोजना तथा नेपाल-भारत रामायण परिपथ का शुभारंभ किया गया था। भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री इस बात पर सहमत हुए कि यह द्विपक्षीय संबंधों का 'स्वर्णिम अध्याय' है जिसके अंतर्गत परिवहन और ऊर्जा के क्षेत्र में संपर्क परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक पहल की जा रही हैं। भारत ने बांग्लादेश को तीन लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान किए हैं जिनकी कुल राशि 8 बिलियन यूएस डॉलर है। म्यांमार में उत्तरी रखाईन राज्य से विस्थापित लोगो को राहत प्रदान करने के बांग्लादेश के प्रयासों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए भारत ने ऑपरेशन इंसानियत प्रारंभ किया तथा तीन किश्तों में पर्याप्त मात्रा में मानवीय सहायता प्रदान की।

भारत रखाईन राज्य विकास कार्यक्रम के माध्यम से विस्थापित लोगों की वापसी के लिए अनुकूल माहौल का सृजन करने में म्यांमार की सहायता भी कर रहा है। दोनों देशों ने भूमि सीमा क्रासिंग करार पर हस्ताक्षर किए है जिसके अनुसार वीजा-धारक यात्रियों की सामान्य आवाजाही के लिए निर्दिष्ट सीमा स्थलों को खोला गया है जिसमें तीसरे देशों से आने वाले यात्री भी शामिल हैं। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को गहन बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

मालदीव और भूटान के नव-निर्वाचित नेताओ ने भारत का चयन अपने प्रथम विदेशी दौरे के लिए किया। श्रीलंका के साथ भारत के संबंध सकारात्मक बने हुए हैं तथा वर्ष के दौरान इनमें और भी मजबूती आई है और यह उच्चतम राजनीतिक स्तर पर स्थापित घनिष्ठ संपर्कों, बढ़ते हुए व्यापार और निवेश तथा लोक-केन्द्रित विकासात्मक परियोजनाओं के क्रियान्वयन से स्पष्ट है।

वर्ष के दौरान भारत-अफगानिस्तान संबंधों में अनेक महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिले जिसमें भारत की ओर से अफगानिस्तान को गेहूं और दालों का वितरण, दोनों देशों के बीच हवाई माल-परिवहन गलियारे का विस्तार तथा वर्ष 2017 में घोषित नई विकास भागीदारी के अंतर्गत अफगानिस्तान में अनेक भारत-समर्थित सामाजिक-आर्थिक विकास परियोजनाओं के लिए कार्य प्रारंभ किया जाना शामिल है।

अपने क्रियाकलापों के केन्द्र में रणनीतिक स्वायत्तता के समावेश के साथ भारत ने विश्व की सभी प्रमुख शक्तियों के साथ अपने संबंधों में वृद्धि करना जारी रखा और राष्ट्रीय हित में स्वतंत्र निर्णय लिए गए। वूहान में चीन तथा सोची में रूस के साथ 'अनौपचारिक शिखर-सम्मेलन' तंत्र महत्वपूर्ण उपलब्धि थे। भारत और यूएस के विदेश और रक्षा मंत्रियों के मध्य अपनी प्रथम 2+2 वार्ता आयोजित की गई जिससे वैश्विक रणनीतिक भागीदारी मजबूत हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ 13वें भारत-जापान वार्षिक शिखर-सम्मेलन के लिए अक्टूबर, 2018 में की गई टोक्यो की यात्रा ने पिछले लगभग पांच वर्षों में भारत और जापान के विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक भागीदारी में अभूतपूर्व रूपांतरण को और बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जिसमें सहयोग के अनेक क्षेत्रों को शामिल किया गया था और इससे दोनों देशों के साझे मूल्य और हित भी प्रदर्शित हुए। कुल मिलाकर, इन वार्ताओं ने घरेलू, प्रादेशिक और वैश्विक मुद्दों पर अग्रदर्शी रणनीतिक वार्ताएं प्रारंभ करने के लिए संबंधित नेताओं के मध्य विचारों के प्रत्यक्ष और निष्पक्ष आदान-प्रदान को सुकर बनाया।

एक्ट ईस्ट नीति ने भारत-प्रशांत क्षेत्र पर दिए गए नवीकृत वैश्विक बल से एक नई ऊर्जा प्राप्त की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शांग्री-ला वार्ता में आधार-व्याख्यान दिया, जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाने वाला ऐसा प्रथम व्याख्यान है, जिसके दौरान उन्होंने भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत की नीति का वर्णन किया। भारत-प्रशांत के बारे में भारत का दृष्टिकोण 'क्षेत्र में सभी के लिए समावेशी सुरक्षा और विकास (सागर)' संबंधी हमारी हिंद महासागर नीति को एक अंतर्वेशी भारत-प्रशांत ढांचे में एकीकृत करता है।

भारत-प्रशांत क्षेत्र के साथ भारत का अनवरत संबंध निरंतर उच्च स्तरीय दौरों; रक्षा और संरक्षा सहयोग, जिसमें आतंकवाद का विरोध और अन्य सीमापार अपराध शामिल हैं; व्यापक आर्थिक संबंधों; शिक्षा और कौशल विकास पर नियमित वार्ताओं; छात्रवृत्तियों तथा आईटीईसी कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण सांस्कृतिक सहयोग तथा भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों के माध्यम से भारतीय संस्कृति का संवर्धन तथा प्रवासी भारतीयों के साथ निरंतर प्रगाढ़ होते संबंध से अत्यंत स्पष्ट प्रदर्शित होता है। भारत और आसियान ने सामुद्रिक सहयोग तथा भौतिक, डिजिटल और सांस्कृतिक संपर्क को बल प्रदान करने के लिए सहयोग में वृद्धि की है। आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और पर्यावरणीय चुनौतियों जैसे गैर-पारंपरिक सुरक्षा मुद्दों पर भी पारस्परिक सहयोग और भी गहन होता जा रहा है।

भारत की 'थिंक वेस्ट' नीति को आगे बढ़ाने तथा ऊर्जा और सुरक्षा हितों में समन्वय स्थापित करने के लिए विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने वर्ष के दौरान द्विपक्षीय करारों के लिए बहरीन, कुवैत, कतर और यूएई की यात्रा की। दिसम्बर में, इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कंपनी ने ईरान के चाबहार पत्तन में प्रचालन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया को समुद्री-भूमि संपर्क साधन प्रदान करेगा। यूएस से छूट प्राप्त कर ली गई है जिसने ईरानी तेल के आयातों को जारी रखने में सहायता प्रदान की तथा भुगतानों और सामुद्रिक बीमा के लिए पृथक तंत्र तैयार किए गए।

जुलाई में युगांडा की संसद में दिए गए प्रधानमंत्री मोदी के ऐतिहासिक संबोधन में रेखांकित किए गए 10 सिद्धांतों के साथ ही अफ्रीका के साथ हमारे संबंधों को एक नई गति मिली। जुलाई 2018 में, 'सहयोग न कि विरोध' की हिमायत करते हुए, भारत ने द्विपक्षीय सहयोग का प्रस्ताव किया जिसमें लाइन ऑफ केडिट्स, प्रौद्योगिकी के अंतरण के माध्यम से अफ्रीका के विकास के लिए वित्त-पोषण पर बल प्रदान किया जाएगा तथा विकास में तेजी लाने तथा अफ्रीका के मानव संसाधन के प्रशिक्षण का विस्तार करने के लिए डिजिटल परिक्षेत्र को भी शामिल किया जाएगा। भारत ने इस क्षेत्र में ज़िबूती, सोमालिया और अन्य देशों के साथ अपने सहयोग में वृद्धि की है ताकि समुद्री-डकैती को रोकने तथा सामुद्रिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के मामले में उनके हितों की रक्षा की जा सके। भारत एमओएनयूएससीओ (कांगो डोमेस्टिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र स्थायित्व मिशन) के लिए सैन्य टुकड़ियों के साथ-साथ सैन्य प्रेक्षकों और पुलिस कार्मिकों को भी भेजता रहा है।

कुल मिलाकर, भारत की राजनयिक पहुंच में तेजी और मजबूती समूचे वर्ष के दौरान बनी रही। राज्य और सरकार प्रमुखों के स्तर पर यह वर्ष, अन्य के साथ-साथ, रूस, मालदीव, शेशेल्स, कोरिया गणराज्य, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों, भूटान, नेपाल, नीदरलैंड्स, श्रीलंका, इटली, बांग्लादेश और नार्वे के प्रधानमंत्रियों की यात्राओं का साक्षी रहा है। इसी प्रकार, विदेशी दौरों में राष्ट्रपति की वियतनाम, आस्ट्रेलिया, ताजिकिस्तान, म्यांमार, इक्वेटोरियल गुयाना, स्वाजीलैंड, जाम्बिया, ग्रीस, सूरीनाम, क्यूबा, साइप्रस, बुल्गारिया

और चेक गणराज्य की यात्राएं शामिल हैं। उपराष्ट्रपति ने बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मलावी, फ्रांस, बेल्जियम, ग्वाटेमाला, पनामा, पेरू, सर्बिया, माल्टा, रोमानिया और यूएसए की यात्रा की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने दौरों के माध्यम से चीन, स्वीडन, यूके, जर्मनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल, रूस, रवांडा, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका, जापान, अर्जेंटीना और मालदीव के साथ अपने संबंधों को नई ऊर्जा प्रदान की। यह व्यापक राजनयिक पहुंच तेजी से बदलती हुई विश्व व्यवस्था में सक्रिय संबंध स्थापित करने की सरकार की नीति को प्रदर्शित करती है ताकि राष्ट्रीय हित का संवर्धन किया जा सके।

26/11 के हमलों की दसवीं बरसी के अवसर पर समूचा विश्व एकजुट होकर भारत के साथ खड़ा रहा। भारत ने वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के संकट से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया तथा आतंकवाद के समस्त स्वरूपों और अभिव्यक्तियों में उसकी कड़ी भर्त्सना की। भारत ने आतंकवाद का सामना करने संबंधी संयुक्त कार्य दल के माध्यम से ठोस विचार-विमर्श आयोजित किया। वर्ष 2018 के दौरान, भारत ने आस्ट्रेलिया, कनाडा, मिस्र, फ्रांस, इंडोनेशिया, रूस, ट्यूनीशिया, यूके, यूएस, उज्बेकिस्तान के साथ तथा ईयू, ब्रिक्स और बिम्स्टेक के साथ आतंकवाद-रोधी वार्ताएं आयोजित की।

बहुपक्षीय स्तर पर, भारत ने विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक एजेंडा निर्धारित करने के लिए अपना योगदान देना जारी रखा जैसे जलवायु परिवर्तन, परमाणु नि:शस्त्रीकरण और काला धन। आर्थिक अपराधियों की धर-पकड़ करने के बारे में प्रधानमंत्री का प्रस्ताव जी-20 के एजेंडे तथा ब्यूनर्स आयर्स में आयोजित जी-20 शिखर-सम्मेलन में परिणाम घोषणा का भाग बना। जी-20 शिखर-सम्मेलन में रूस-भारत-चीन (आरआईसी) त्रिपक्षीय वार्ता के साथ-साथ प्रथम जापान-अमेरिका-भारत (जेएआई) त्रिपक्षीय वार्ता संचालित की गई। भारत ने घोषणा की कि वह भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर वर्ष 2022 में जी-20 शिखर-सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि (आईएसए) की महासभा का उद्घाटन 2 अक्टूबर, 2018 को दिल्ली में किया गया जिसके साथ-साथ द्वितीय आईओआरए नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयी बैठक तथा द्वितीय ग्लोबल री-इंवेस्ट आयोजन भी प्रारंभ हुआ। आईएसए भारत में मुख्यालय बनाने वाला प्रथम संयुक्त राष्ट्र-संबद्ध अंतर-सरकारी संगठन है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को 'वैश्विक मंच पर उनके निर्भीक पर्यावरणीय नेतृत्व' के लिए संयुक्त राष्ट्र चैंपियंस ऑफ दि अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया।

भारत विभिन्न क्षेत्रों में भागीदार देशों के साथ विकास सहयोग कार्यक्रम संचालित करता रहा। इस वर्ष लगभग 1.03 बिलियन यूएस डॉलर के लाइंस ऑफ क्रेडिट (एलओसी) विभिन्न देशों को प्रदान किए गए तथा 101.13 मिलियन यूएस डॉलर की कुल राशि से नौ परियोजनाएं पूर्ण की गईं और भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के अंतर्गत 161 भागीदार देशों को दस हजार से अधिक नागरिक प्रशिक्षण स्थान प्रदान किए गए। इसकी लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए तथा समूचे विश्व में बदलती हुई आवश्यकताओं और प्रौद्योगिकीय प्रगति के अनुरुप आईटीईसी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की श्रृंखला में ई-आईटीसी और आईटीईसी-ऑनसाइट जैसे नए मंचों को शामिल किया गया है।

भारत द्वारा आपदाओं से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान की गई। अन्य के साथ-साथ, मोजम्बिक, सीरिया, यमन, सोमालिया, युगांडा, तंजानिया, मेडागास्कर, स्वाजीलैंड और केन्या को औषधियां उपलब्ध कराई गई तथा बांग्लादेश और सीरिया को खाद्य तथा अन्य राहत सामग्री की आपूर्ति की गई। भारत ने इंडोनेशिया को भूकंप और सुनामी के लिए सहायता प्रदान करने के प्रयोजनार्थ 'समुद्र मैत्री' नामक अभियान संचालित किया।

स्वदेश रूपांतरण को भारत की विदेश नीति संबंधी कार्यनीति का अभिन्न हिस्सा बनाया गया है। हमारे भागीदार देशों के साथ स्थापित किए गए अत्यंत गहन संबंधों ने संवर्धित विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोगों के माध्यम से भारत के लोगों के लिए दृश्यमान आर्थिक लाभ प्रदान किए हैं जिनके परिणामस्वरूप कारखानों को स्थापित किया गया है और रोजगार सृजन हुआ है। विकास और समृद्धि के साथ राजनयिकता के सामंजस्य के फलस्वरूप राष्ट्रीय नवीकरण की योजनाओं के संवर्धन के लिए विदेशी सहयोग हासिल करने में सहायता प्राप्त हुई है जिनमें मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटीज़, डिजिटल इंडिया और स्टार्ट-अप इंडिया शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भारत के सभ्यतामूलक मूल्यों का निरंतर बढ़ता हुआ प्रभाव, जो 'वसुधैव कुटुम्बकम' के

चिरस्थायी अवधारणात्मक ढांचे पर आधारित है, उस समय अत्यंत सुस्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुआ जब 124 देशों के कलाकार महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक साथ सामने आए और उन्होंने गांधीजी के प्रिय भजन 'वैष्णव जन तो' को अंतर्राष्ट्रीय अंहिसा दिवस के अवसर पर वैश्विक श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत किया। जनवरी, 2019 में वाराणसी में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस समारोहों ने प्रवासी भारतीयों तथा उनकी मातृभूमि के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ किया।

सेवा परिदाय और नागरिक-केन्द्रित अभिशासन पर सरकार द्वारा प्रदान दिया बल ई-क्रांति (डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का चौथा स्तंभ) की चार मिशन मोड परियोजनाओं के क्रियावयन के लिए उठाए गए कदम से परिलक्षित होता है अर्थात् ई-आफिस, ई-अधिप्राप्ति, आप्रवासन, वीजा, विदेशी रजिस्ट्रीकरण और ट्रैकिंग प्रणाली (आईवीएफआरटी) तथा पासपोर्ट सेवा परियोजनएं (पीएसपी)। ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय तथा विदेश स्थित मिशनों/पोस्टों में क्रियान्वित की जा रही हैं। डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप विदेश मंत्रालय द्वारा अनेक ई-अभिशासन और स्वचालन परियोजनाएं भी कार्यान्वित की गई हैं जैसे विदेश सेवा संस्थान पूर्व-छात्र पोर्टल, ई-लेखापरीक्षा पोर्टल, नवीकृत 'भारत को जानें' कार्यक्रम तथा प्रवासी भारतीय दिवस पोर्टल, राजनयिक पहचान-पत्र रजिस्ट्रीकरण और निर्गम प्रणाली आदि।

आगामी पृष्ठों में वर्ष के दौरान भारत के विदेशी संबंधों से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की और जानकारी प्रदान की गई है।

भारत के पड़ोसी

अफगानिस्तान

भारत और अफगानिस्तान के बीच बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी में लगातार मजबूती दिखाई दी। सितंबर 2018 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद अशरफ गनी और जून 2018 और सितंबर 2018 में मुख्य कार्यकारी डॉ. अब्दुल्ला अब्दुल्ला की यात्राओं ने, उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय आदान-प्रदान की गति को बनाए रखा। 'एयर फ्रेट कॉरिडोर' सहित अन्य पहलों के परिणामस्वरूप द्विपक्षीय व्यापार 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंचा; अफगानिस्तान के लिए भारत की विकास साझेदारी और क्षमता निर्माण कार्यक्रम में वृद्धि हुई; और सुरक्षा, कनेक्टिविटी के क्षेत्रों सहित सहयोग; और मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया गया। भारत ने अपनी एकरूप नीति के अनुसार समावेशी शांति और सुलह के ऐसे सभी प्रयासों को समर्थन दिया जो अफगान के नेतृत्व, स्वामित्व नियंत्रण में हो; और अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा, एकता, संप्रभुता, बहुलता और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए अपना समर्थन देने की प्रतिबद्धता प्रकट की।

पाकिस्तान

भारत के खिलाफ सीमा-पार आतंकवाद को पाकिस्तान में निरंतर समर्थन; पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवाद को समर्थन करने वाले बुनियादी ढांचे पर किसी विश्वसनीय कार्रवाई के अभाव; नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आतंकवादी घुसपैठ को समर्थन सहित, पाकिस्तानी सेना द्वारा अकारण संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाओं में वृद्धि के कारण द्विपक्षीय संबंध बाधित रहे। भारत ने अपनी सुसंगत नीति के तहत, पाकिस्तान के साथ आतंक और हिंसा-मुक्त वातावरण में सामान्य संबंध रखने की अपनी इच्छा व्यक्त की, और पाकिस्तान से इसके लिए अनुकूल वातावरण बनाने का आह्वान किया। कैदियों, मछुआरों और तीर्थयात्रियों सहित मानवीय और लोगों के पारस्परिक मुद्दों पर आगे बढ़ने के निरंतर प्रयास किए गए। लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप, नवंबर 2018 में, भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पाकिस्तानी तरफ गुरुद्वारा करतारपुर साहिब तक अबाधित और आसान पहुंच के लिए कोरीडोर स्थापित करने के भारतीय प्रस्ताव पर पाकिस्तान द्वारा सहमति प्रकट की गई।

बांग्लादेश

समीक्षाधीन वर्ष में भारत-बांग्लादेश संबंधों की गहराई और जटिलता में विस्तार हुआ। शांतिनिकेतन में बांग्लादेश भवन खोलने और काजी नजरूल इस्लाम विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत (पश्चिम बंगाल) यात्रा के दौरान, दोनों प्रधानमंत्रियों ने इसपर सहमति व्यक्त की कि हमारे संबंध 'स्वर्ण युग' तक पहुंच गए हैं। पिछले चार वर्षों में, द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार की अनिवार्यता रही तथा पूर्णतया सरकारी

स्तर पर बिजली, रक्षा और वाणिज्य विभाग से लेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नौवहन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तक द्विपक्षीय सहयोग के लिए नए कार्यक्रम विकसित करते रहे।

इस परिप्रेक्ष्य में, दोनों पक्षों की सरकारों ने लगभग 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की भारत की तीन ऋण श्रृंखलाओं का उपयोग सुनिश्चित करने का काम तेज कर दिया है। ये ऋण श्रृंखलाएं अबतक की सर्वाधिक हैं और सबसे अच्छी शर्तों पर दी गई हैं। बांग्लादेश, पैंतीस पूर्ण लघु विकास परियोजनाओं और चालीस चालू परियोजनाओं सहित, अनुदान सहायता का एक प्रमुख प्राप्तकर्ता भी है।

म्यांमार

सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री के सफल राजकीय दौरे और भारत-आसियान संबंधों की 25वीं वर्षगांठ पर जनवरी 2018 में स्टेट काउंसलर दाव आंग सान सू की की भारत यात्रा के बाद, द्विपक्षीय संबंधों के सकारात्मक प्रक्षेप को कायम रखा गया। मई 2018 में विदेश मंत्री ने म्यांमार का दौरा करते हुए, अपनी यात्रा के दौरान पांच समझौता ज्ञापनों सहित भूमि सीमा पार समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत तीसरे देशों सहित वीजाधारक यात्रियों की सामान्य आवाजाही के लिए निर्दिष्ट सीमा बिंदु खोले गए। नई दिल्ली में जून 2018 में विदेश सचिव के स्तर पर विदेश कार्यालय परामर्श भी आयोजित किए गए।

कलादन मल्टी-मॉडल परिवहन परियोजना के तीन (बंदरगाह और अंतर्देशीय जलमार्ग) में से दो घटकों के निर्माण के पूरा होने के साथ, हमारी कुछ विरासत अवसंरचना परियोजनाओं को गति प्रदान करने में प्रगति दर्ज की गई। भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच ट्रांस-एशियन (त्रिपक्षीय) राजमार्ग पर 69 पुलों के चौड़ीकरण और विस्तार और इस सड़क के कलेवा-यारगुई खंड सहित अन्य प्रमुख परियोजनाओं को पूरा करने का प्रयास चल रहा है। अक्टूबर 2018 में विदेश सचिव की म्यांमार यात्रा के दौरान, कलादन परियोजना के बंदरगाह और जलमार्ग दोनों के प्रचालन और रखरखाव के लिए निजी ऑपरेटर नियुक्त करने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने से इस दिशा में और प्रगति हुई।

म्यांमार के लगभग 1000 अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और नागरिकों को भारतीय संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और इस प्रकार क्षमता निर्माण परियोजनाओं का विस्तार जारी रहा। वायु सेना प्रमुख और म्यांमार के सेना प्रमुख (नौसेना) के दौरे से म्यांमार के साथ रक्षा संबंधों का भी विस्तार हुआ। अब हमारे संबंधों का तटीय सुरक्षा प्रणालियों की आपूर्ति के लिए तकनीकी समझौते के साथ रक्षा अवसंरचना के निर्माण में भागीदारी के लिए विस्तार होगा।

समीक्षाधीन वर्ष में, हमने ऊर्जा क्षेत्र में रिफाइनरियों, बिजली उत्पादन और वितरण सहित डाउनस्ट्रीम उत्पाद विकास के लिए खोज शुरू करने के लिए तेल और गैस के पूर्वानुमान और गवेषण से आगे बढ़ते हुए, सहयोग को बढ़ाने के लिए संबंधों का विस्तार किया। म्यांमार को मदद करने के महत्व को स्वीकार किया गया क्योंकि इससे म्यांमार में रखाईन राज्य से विस्थापितों की वापसी के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित होगा, भारत ने दिसंबर 2017 में रखाईन राज्य विकास कार्यक्रम दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए और इसके तहत उस राज्य के सभी समुदायों के लिए 250 में से 50 प्रीफैब्रिकेटेड घरों का कार्य पूरा किया। इस वर्ष के अंत में भारत के राष्ट्रपति की म्यांमार की राजकीय यात्रा 2006 के बाद इस स्तर की पहली यात्रा होगी।

भूटान

भारत और भूटान में दोस्ती और सहयोग के असाधारण संबंध हैं जो आपसी समझ, सदभावना और आपसी हितों के लिए सम्मान पर आधारित हैं। दोनों देशों ने संयुक्त रूप से 2018 में औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया और इस अवसर पर यादगार घटनाओं की श्रृंखला दिखाई गई जो दोनों देशों के बीच लोगों के मजबूत संबंधों को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2018-19 में पनबिजली, संचार, रक्षा और सुरक्षा, अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, आईटी उद्योग और कृषि सहित सहकारिता के सभी क्षेत्रों में निरंतर प्रगति देखी गई। उच्च-स्तरीय यात्राओं और कार्यकारी स्तर पर परस्पर संवाद की श्रृंखला के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों की गति को बनाए रखा गया। भूटान नरेश महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने अगस्त 2018 में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत की यात्रा की।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर, भूटान के प्रधान मंत्री डॉ. लोटे शेरिंग ने एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल सहित, 27 से 29 दिसंबर 2018 तक भारत की राजकीय यात्रा की। यह प्रधानमंत्री डॉ लोटे शेरिंग की नवंबर 2018 में पदभार संभालने के बाद पहली विदेश यात्रा थी। यात्रा के दौरान, भारत सरकार द्वारा भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में 4500 करोड़ रुपये

की सहायता दिए जाने की घोषणा की गई। इस यात्रा ने जल-विद्युत, आर्थिक सहयोग और स्वर्ण जयंती समारोह सहित द्विपक्षीय सम्बद्धताओं के व्यापक स्पेक्ट्रम की समीक्षा करने का अवसर भी प्रदान किया। इससे पहले वर्ष के दौरान, भूटान के तत्कालीन प्रधानमंत्री दशो शेरिंग तोबगे ने 5 से 7 जुलाई 2018 तक भारत की राजकीय यात्रा की।

भूटान की 11वीं पंचवर्षीय योजना (2013-18) के लिए 4500 करोड़ रुपये के भारत सरकार के सहायता पैकेज के तहत वर्ष 2018-19 में विकास परियोजनाओं पर काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कुल मिलाकर 500 करोड़ रुपये के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के अलावा, भारत सरकार ने भूटान की 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 5000 करोड़ रुपये की प्रतिबद्ध राशि में से 4975 करोड़ रुपये का संवितरण किया; भारत सरकार की समयबद्ध सहायता भूटान के लोगों के कल्याण संबंधी अनेक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहायक बनी है।

नेपाल

भारत-नेपाल संबंध सदियों पुराने सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध, लोगों के घनिष्ठ संबंध, बहुआयामी आर्थिक और विकास भागीदारी से शक्ति व प्रमुखता प्राप्त करते हैं और खुली सीमाओं से यह और अधिक प्रबलित होता है। दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय यात्राओं सहित गहन द्विपक्षीय भागीदारियां 2018-19 में जारी रहीं। नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने 6 से 8 अप्रैल 2018 तक भारत की राजकीय यात्रा की। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की दो यात्राएं कीं - 11-12 मई 2018 तक राजकीय यात्रा और 30-31 अगस्त 2018 को काठमांडू में 4थे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए की गई यात्रा। उच्च-स्तरीय यात्राओं ने द्विपक्षीय साझेदारी के साथ ही कृषि, अंतर्देशीय जलमार्गों और रेलवे के क्षेत्रों में नई पहल शुरू करने का अवसर प्रदान किया। इस वर्ष भी गहन आधिकारिक और तकनीकी स्तर की द्विपक्षीय भागीदारी देखी गई। भारत और नेपाल के बीच व्यापक आर्थिक और विकासपरक सहयोग है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार और नेपाल में सबसे बड़ा निवेशक है। नेपाल में कई सामाजिक और भौतिक अवसंरचना परियोजनाएं और सीमा पार संपर्क परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। बीरगंज (नेपाल) में एक एकीकृत चेक पोस्ट और काठमांडू में 400-बिस्तरों वाला नेपाल-भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला का उद्घाटन क्रमशः अप्रैल और अगस्त 2018 में किया गया। दो और सीमा पारीय पारेषण लाइनों के पूरा होने के साथ ही 900 मेगावाट की अरुण III जलविद्युत परियोजना पर काम शुरू करने के साथ विद्युत क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है। समुदाय संचालित लघु विकास परियोजनाओं जैसे स्कूलों, सड़कों, पुलों, सिंचाई सुविधाओं से नेपाल के विभिन्न जिलों में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त 1.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर की चार ऋण श्रृंखलाओं के तहत, नेपाल में भूकंप-पश्चात पुनर्निर्माण परियोजनाओं सहित कई अवसंरचना परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। भारत और नेपाल का क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में मजबूत सहयोग है। भारत नेपाल और भारत में अध्ययन के अवसर देने के लिए नेपाली छात्रों को प्रति वर्ष लगभग 3000 छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। आईटीईसी कार्यक्रम के तहत, नेपाल के सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारियों को भारत में तकनीकी संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए प्रति वर्ष 250 से अधिक छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

चीन

अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग के बीच वुहान में आयोजित पहले अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के जरिए भारत और चीन के बीच घनिष्ठ विकास साझेदारी 2018 में एक नए मुकाम पर पहुंची। अपने द्विपक्षीय संबंधों के स्तर को बढ़ाने की दोनों पक्षों की इच्छा को परिलक्षित करने वाले इस अनौपचारिक शिखर सम्मेलन, ने वर्ष भर उच्चस्तरीय नियोजनों के लिए मंच तैयार किया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी ने वर्ष के दौरान बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन के अवसर पर स्वयं तीन और द्विपक्षीय बैठकें कीं। भारत के एससीओ में एक पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने और चीन द्वारा 2018 में एससीओ की अध्यक्षता ग्रहण करने से दोनों पक्षों के बीच वरिष्ठ स्तरों पर अधिकाधिक वार्ताओं के लिए अधिक अवसर प्राप्त हुए हैं। चीन के रक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा और विदेश मामलों के मंत्रियों की द्विपक्षीय यात्राओं से दोनों पक्षों के बीच सहयोग का दायरा और विस्तारित हुआ। लोगों के स्तर पर संपर्कों को और मजबूत करने के लिए, दोनों पक्षों द्वारा सांस्कृतिक और लोगों के बीच आदान-प्रदान पर एक उच्चस्तरीय तंत्र की भी शुरूआत की गई। कुल मिलाकर, इस वर्ष भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर सकारात्मक गति देखी गई।

हिंद महासागर क्षेत्र

हिंद महासागर में छोटे द्वीप देशों के साथ संबंधों को घनिष्ठ बनाना और इस क्षेत्र में स्थिरता, शांति और विकास के माहौल का पोषण करना भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण आधार हैं। हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री द्वारा अपने सागर सिद्धांत "क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा और विकास" में व्यक्त किया गया है।

श्रीलंका

भारत-श्रीलंका संबंध वर्ष भर फले-फूले। प्रधानमंत्री की श्रीलंका की ऐतिहासिक यात्रा की गति को लोक-केंद्रित विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन और आर्थिक भागीदारी के विस्तार के साथ कायम रखा गया। उच्च-स्तरीय राजनीतिक संबद्धताओं और लोगों के निकट संपर्क से द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए। मध्य और दक्षिणी श्रीलंका में अब तक अछूते क्षेत्रों में भारत की विकास सहायता परियोजनाओं के दायरे और प्रसार में विस्तार ने विश्वसनीय विकास भागीदार के रूप में भारत के प्रति धारणा बदलने में मदद की है। कुल मिलाकर, सुरक्षा और रक्षा सहयोग, आपदा प्रबंधन, शिक्षा, संस्कृति, व्यापार और वाणिज्य, पर्यटन, अंतरिक्ष और संपर्क जैसे क्षेत्रों में संबंध परिपक्व हुए हैं और इन संबंधों को बहुआयामी कहा जा सकता है।

मालदीव

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, 2018 में मालदीव ने अपने राष्ट्रपति का चुनाव कराया, जिसमें विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार इब्राहिम मोहम्मद सोलिह (इबू सोलिह) विजयी होकर उभरे। भारत इबू सोलिह को उनकी जीत पर बधाई देने और चुनाव परिणामों को मान्यता देने वाले पहले देशों में एक था। निर्वाचित राष्ट्रपति इबू सोलिह के आमंत्रण पर, प्रधानमंत्री मोदी ने 17 नवंबर 2018 को राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए विशेष अतिथि के तौर पर मालदीव की यात्रा की। नई सरकार ने अपनी भारत-प्रथम नीति को दोहराया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति सोलिह को भारत की राजकीय यात्रा पर आमंत्रित किया। राष्ट्रपति सोलिह की यात्रा की तैयारी के लिए, नवनियुक्त विदेश मंत्री श्री अब्दुल्ला शाहिद ने 24 से 27 नवंबर, 2018 तक भारत की यात्रा की।

रक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा। भारत सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर, 2018 तक विशाखापत्तनम में मालदीव के तटरक्षक जलयान हुरावी की छोटी-मोटी मरम्मत की। भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय संयुक्त नौसेना अभ्यास, "दोस्ती-14" का 14वां आयोजन 25 से 29 नवंबर, 2018 तक मालदीव में किया गया। माले में 26-27 जून 2018 को तृतीय संयुक्त कर्मचारी वार्ता आयोजित की गई।

मॉरीशस

भारत और मॉरीशस के संबंधों में पारंपरिक घनिष्ठ राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रवासी संबंधों को ध्यान में रखते हुए जुड़ाव गहन हुआ। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 18 से 20 अगस्त 2018 तक मॉरीशस में आयोजित 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस सम्मेलन में दुनिया भर के हिंदी प्रेमी लोगों ने भी भाग लिया। आर्थिक मोर्चे पर सीईसीपीए (व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते) के समापन के लिए कई दौर की वार्ता हुई, जिसके परिणामस्वरूप नवंबर 2018 में संयुक्त अध्ययन रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए गए।

पुनः अनुप्राणित विकास साझेदारी में कई अनुदान सहायता परियोजनाओं जैसे मेट्रो एक्सप्रेस, ईएनटी अस्पताल, न्यू सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, 353 मिलियन अमरीकी डालर के विशेष आर्थिक पैकेज के तहत सामाजिक आवास और स्कूली बच्चों के लिए डिजिटल टैबलेट, सिविल सर्विस कॉलेज; और 500 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला के तहत 18 अन्य प्राथमिकता वाली परियोजनाओं का कार्यान्वयन शामिल था। ओसीआई योजना में विशेष मेहनत भी मॉरीशस में लोकप्रिय बनी है और हमारे लोगों के बीच परस्पर संबंधों को मजबूत कर रही है। मॉरीशस के प्रधानमंत्री महामहिम श्री प्रवीण जगन्नाथ को जनवरी 2019 में वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।

सेशेल्स

भारत सरकार द्वारा प्रतिबद्ध बढ़ती विकास साझेदारी सहायता पर आरूढ़, भारत-सेशेल्स संबंधों ने द्विपक्षीय साझेदारी के नए चरण में प्रवेश किया। हमारे व्यावहारिक, परिणाम उन्मुख नियोजन को जून 2018 में राष्ट्रपति महामहिम श्री डैनी फॉरे की भारत यात्रा से और बल मिला। इस यात्रा में सहयोग के

विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 6 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए और ईईजेड सर्विलांस बढ़ाने के लिए सेशेल्स को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर का डोर्नियर विमान उपहार में दिया गया। प्रधानमंत्री ने सेशेल्स को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रक्षा ऋण श्रृंखला की भी घोषणा की।

इससे पूर्व मई 2018 में, भारत के विदेश सचिव और सेशेल्स के विदेश मामलों के सचिव की अगुवाई में 9वें संयुक्त आयोग की बैठक माहे में 5 साल से अधिक अंतराल के बाद आयोजित की गई। भारत और सेशेल्स के मुख्य हाइड्रोग्राफर की अगुवाई वाली पहली हाइड्रोग्राफी बैठक ने भी हाइड्रोग्राफी क्षमता निर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया। इस अवधि के दौरान सेशेल्स के रक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य, अक्षय ऊर्जा और सामुदायिक विकास क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने के अलावा, विकास साझेदारी सहायता का विशेष ध्यान संस्था निर्माण पर रहा।

हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA)

इस क्षेत्र में इस खाली आकांक्षा को साकार करने में आईओआरए तंत्र को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। सहयोग को बढ़ावा देने और क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारत आईओआरए को एक महत्वपूर्ण माध्यम मानता है। भारत अक्षय ऊर्जा और ब्लू इकोनॉमी से लेकर समुद्री संरक्षा और सुरक्षा तक आईओआरए कार्यकलापों को और अधिक आगे बढ़ाने का समर्थन करता रहा है।

जकार्ता में 7 मार्च 2017 को आईओआरए नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा घोषित व्यापक पहलों के सफल क्रियान्वयन, और पूर्ववर्ती वर्षों में मंत्रिपरिषद और वरिष्ठ अधिकारियों की समिति की बैठकों के बाद भारत ने नवंबर 2018 में डरबन में 18वीं आईओआरए मंत्रिपरिषद की बैठक में कुछ नई पहलों की घोषणा की।

दक्षिण पूर्व एशिया और एशिया प्रशांत

2014 में शुरू की गई भारत की एक्ट ईस्ट नीति (AEP) के अंतर्गत, भारत दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र, ओशिनिया, पूर्वोत्तर एशिया और पूर्वी एशिया के देशों के साथ मजबूती से जुड़ रहा है। आसियान एईपी के मूल में है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2018 को शांगरी-ला वार्ता में आधार व्याख्यान दिया, जिसके दौरान उन्होंने भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत की नीति को स्पष्ट किया। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में आसियान केंद्रीयता की पुष्टि की। भारत-प्रशांत विचार के माध्यम से, भारत ने व्यापक क्षेत्र में अपने लिए एक बड़ी भूमिका की परिकल्पना की है। लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट में उन्नयन न केवल अधिक सक्रिय और व्यावहारिक दृष्टिकोण के माध्यम से क्षेत्र के महत्व को उजागर करता है, बल्कि प्रमुख सामरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवसरों को संबोधित करते ते हुए प्रवासियों की भूमिका को भी स्वीकार करता है।

राजनीतिक समझ, सुरक्षा और रक्षा सहयोग और आर्थिक जुड़ाव के माध्यम से भारत ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप देशों (PICs) से भी सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। भारत-प्रशांत क्षेत्र के साथ भारत का निरंतर जुड़ाव निरंतर उच्च-स्तरीय यात्राओं; मजबूत रक्षा सहयोग, जिसमें प्रशिक्षण, पोत यात्रा, संयुक्त समन्वित गशत, रक्षा बिक्री और रक्षा आपूर्ति शामिल हैं; विशेष रूप से आतंकवाद-रोधी और अन्य अपराधिक अपराधों में घनिष्ठ सुरक्षा सहयोग; व्यापक आर्थिक जुड़ाव; शिक्षा और कौशल विकास पर नियमित संवाद; छात्रवृत्ति और आईटीईसी कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण; भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने और प्रवासी भारतीयों के साथ बढ़ते संबंधों सहित सांस्कृतिक सहयोग से स्पष्ट है।

प्रधानमंत्री मोदी ने मई-जून 2018 में तीन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों (इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर) की यात्रा की और 1 जून 2018 को शांगरी-ला वार्ता में मुख्य भाषण देने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। भारत के राष्ट्रपति ने नवंबर-दिसंबर 2018 में ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और म्यांमार की यात्रा की। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने कंबोडिया, वियतनाम और लाओस की यात्रा की। भारत सरकार के अन्य मंत्रियों ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों की यात्रा की। पहली बार राज्यमंत्री स्तर पर विभिन्न प्रशांत द्वीप देशों की मंत्रिस्तरीय यात्रा की गई जिनमें समोआ, टोंगा, मार्शल आइलैंड्स, नाउरू, तिमोर लेस्ते और तुवालु शामिल थे।

भारत सरकार अपने विभिन्न विकास सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से कंबोडिया, लाओस और वियतनाम और प्रशांत द्वीप देशों के संपर्क में है।

दक्षिणपूर्वी एशियाई देशों का संगठन (आसियान)

जनवरी 2018 में भारत-आसियान स्मारक शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी करने के बाद, भारत ने आसियान के साथ गतिशील और बहुआयामी संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए अपने सटीक प्रयासों को जारी रखा। अपनी 'एक्ट ईस्ट नीति' के अनुसार, भारत ने आसियान के सदस्य देशों के साथ राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा दिया है। नवंबर 2018 में आसियान-संबंधित शिखर सम्मेलनों में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री की सिंगापुर यात्रा हमारे पड़ोस में अति महत्वपूर्ण क्षेत्र से बढ़ते हमारे सामरिक जुड़ाव को और अधिक मजबूत करती है, जिसके साथ हमारे एक चिरकालिक सभ्यतामूलक संबंध हैं। आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और पर्यावरणीय खतरों जैसे गैर-पारंपरिक सुरक्षा मुद्दों से निपटने के लिए भारत और आसियान दोनों ओर से जोर बढ़ता जा रहा है। समुद्री क्षेत्र में सहयोग को आसियान और अन्य क्षेत्रीय मंचों के साथ भारत की वार्ताओं में अधिक प्रमुखता मिली है। भारत ने आसियान देशों के साथ भौतिक, डिजिटल और सांस्कृतिक क्षेत्रों में संयोजकता को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। कंबोडिया, लाओ पीडीआर, म्यांमार और वियतनाम में डिजिटल गांवों के सृजन के लिए ग्रामीण संयोजकता पर प्रमुखता से पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की भारत की पेशकश के साथ डिजिटल संयोजकता पर ध्यान केंद्रित किया गया। लोगों का निकट संपर्क बढ़ाने की दिशा में की जा रही पहलों में आसियान-भारत विश्वविद्यालय नेटवर्क; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में पीएचडी करने के लिए आसियान छात्रों को 1000 फैलोशिप; और 2019 को आसियान-भारत पर्यटन वर्ष के तौर पर घोषित किया जाना शामिल हैं।

पूर्वी एशिया

डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके)

2018 में डीपीआरके के साथ भारत के संबंधों में प्रमुख घटनाक्रमों में डीपीआरके सरकार के निमंत्रण पर मई 2018 में विदेश राज्यमंत्री जनरल डॉ. वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) की डीपीआरके की यात्रा शामिल रही। इसके अलावा, भारत ने पनमुनजोम (27 अप्रैल 2018) और प्योंगयांग (18 से 20 सितंबर 2018) में आयोजित अंतर-कोरियाई शिखर बैठकों और सिंगापुर में आयोजित यूएसए-डीपीआरके शिखर बैठक (12 जून 2018) का इस आशा से स्वागत किया कि ऐसे सम्मेलनों से कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव कम करने और स्थायी शांति और सामंजस्य का मार्ग प्रशस्त करने में मदद मिलेगी।

जापान

भारत-जापान संबंध अधिक महत्व और उद्देश्य के साथ साझेदारी में बदल गया है और यह भारत की एक्ट ईस्ट नीति की आधारशिला है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान निर्मित भारत-जापान विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी, 2018 में महत्वपूर्ण प्रगति करती रही। 2018 में द्विपक्षीय संबंधों का मुख्य आकर्षण 28-29 अक्टूबर 2018 की प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा रही जिसने दो महत्वपूर्ण लोकतंत्रों के रूप में हमारे हितों और मूल्यों के बढ़ते अभिसरण को दर्शाया और विभिन्न क्षेत्रों में हमारी गहन साझेदारी के नए मार्ग प्रशस्त किए।

कोरियाई गणराज्य (ROK)

2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आरओके की यात्रा के दौरान विशेष सामरिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचे, भारत-आरओके द्विपक्षीय संबंधों को, राष्ट्रपति मून जे-इन की 8 से 11 जुलाई 2018 तक भारत की राजकीय यात्रा के साथ और गति मिली। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कोरिया गणराज्य की प्रथम महिला श्रीमती किम जुंग-सूक की यात्रा ने उच्च स्तरीय यात्राओं की गति को बनाए रखा। 2018 की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं में क्रमशः मार्च और अगस्त 2018 में आरओके के नेशनल असेंबली के स्पीकर और आरओके के रक्षा मंत्री की भारत की यात्राएं शामिल रहीं।

मंगोलिया

मई 2015 में प्रधानमंत्री की मंगोलिया की ऐतिहासिक यात्रा जब द्विपक्षीय संबंधों को सामरिक भागीदारी में बदला गया, के बाद मंगोलिया के साथ भारत के पारंपरिक रूप से मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध पिछले कुछ वर्षों में लगातार बेहतर हुए हैं। 2018 में मार्च और दिसंबर 2018 में क्रमशः मंगोलियाई रक्षा

मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव की यात्राओं सहित दोनों देशों के बीच कई उच्च-स्तरीय यात्राएं हुईं। भारतीय पक्ष की ओर से, विदेश मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने क्रमशः अप्रैल और जून 2018 में मंगोलिया की यात्रा की।

यूरेशिया

रूस

भारत की विदेश नीति के एक महत्वपूर्ण आयाम, रूस के साथ 'विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त' सामरिक संबंधों ने, मई 2018 में सोची, रूस में रूसी राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बीच पहले ऐतिहासिक अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में एक नया मुकाम हासिल किया। इसे अक्टूबर 2018 में 19वें द्विपक्षीय वार्षिक शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के साथ पुन: मजबूती मिली। जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सिंगापुर में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और ब्यूनस आयर्स में जी-20 शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन की प्रधानमंत्री के साथ बैठकों और वर्ष के दौरान मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर नियमित यात्राओं से हमारे द्विपक्षीय जुड़ाव में और गहराई आई। दोनों पक्षों ने रक्षा, सिविल परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष के सामरिक क्षेत्रों में सहयोग की विभिन्न परियोजनाओं को जारी रखा। राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा दौरान आयोजित पहले भारत-रूस व्यापार सम्मेलन और नवंबर 2018 में सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित पहली भारत-रूस सामरिक आर्थिक वार्ता के साथ द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया।

मध्य एशिया

मध्य एशिया के अपने विस्तारित पड़ोस के साथ भारत की पहुंच में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा और अक्टूबर 2018 में हमारे राष्ट्रपति की ताजिकिस्तान यात्रा से और प्रगति हुई। अगस्त 2018 में अपने मध्य एशिया दौरे के दौरान तुर्कमेनिस्तान में संक्षिप्त विराम के बाद विदेश मंत्री ने कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य और उजबेकिस्तान की यात्रा की। वह 11-12 अक्टूबर, 2018 को एससीओ प्रमुखों की बैठक में भाग लेने ताजिकिस्तान भी गईं। मध्य एशिया में भारत की निरंतर पहुंच के फलस्वरूप, अफ़गानिस्तान की भागीदारी के साथ 13 जनवरी, 2019 को समरकंद में विदेश मंत्रियों के स्तर पर पहली ''भारत-मध्य एशिया वार्ता'' आयोजित करने की ऐतिहासिक पहल हुई। इस वार्ता से मध्य एशियाई क्षेत्र के साथ भारत का जुड़ाव गहरा हुआ।

यूक्रेन और बेलारूस

भारत ने यूक्रेन के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों को जारी रखा। दोनों देशों ने जून 2018 में रक्षा सहयोग पर एक संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठक आयोजित की। भारत और बेलारूस के संबंधों में जून 2018 में लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल की मिन्स्क यात्रा से एक गुणात्मक अग्रसारण गति दिखाई दी। भारत और बेलारूस ने भी क्रमश: सितंबर और अक्टूबर 2018 में मिंस्क और नई दिल्ली में अंतर-सरकारी आयोग और विदेश कार्यालय परामर्श की बैठकें आयोजित कीं।

दक्षिण काकेशस

अज़रबैजान, जॉर्जिया और आर्मेनिया के साथ भारत के संबंध आगे बढ़ने जारी रहे। भारत और अजरबैजान ने अक्टूबर 2018 में नई दिल्ली में आयोजित अंतर-सरकारी आयोग की बैठक के लिए पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधन मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के साथ फलदायी आदान-प्रदान जारी रखा। इससे पहले, अप्रैल 2018 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) की मध्यावधि मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री ने अज़रबैजान का दौरा किया। जॉर्जिया के साथ सांस्कृतिक संबंध जॉर्जिया में अत्यधिक सम्मानित, सेंट क्वीन केटेवन के भारत में पाए गए अवशेषों की प्रदर्शनी की विस्तारित अवधि से मजबूत हुए। शिक्षा के क्षेत्र में भारत-आर्मेनिया संबंधों को नवंबर 2018 में नई दिल्ली में फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अर्मेनियाई उप शिक्षा और विज्ञान मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल की यात्रा से मजबूती मिली।

शंघाई सहयोग संगठन

एस.सी.ओ. देशों के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। ये संबंध आपसी विश्वास और सद्भावना पर टिके हैं जो हमारे बहुआयामी संबंधों का मुख्य स्तंभ हैं। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज 23-24 अप्रैल 2018 को बीजिंग में आयोजित विदेश मंत्रियों की एससीओ परिषद में सम्मिलित हुईं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 9-10 जून 2018 को चीन

के किंगडाओ में एससीओ के राष्ट्र प्रमुखों के शिखर सम्मेलन के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। शिखर सम्मेलन में कुल बाईस परिणामी दस्तावेजों जिसमें संयुक्त विज्ञप्ति और कट्टरपंथ के खिलाफ 'युवाओं से अपील' शामिल हैं, पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश मंत्री ने 11-12 अक्टूबर 2018 को ताजिकिस्तान के दुशांबे में एससीओ प्रमुखों की बैठक में भाग लिया।

खाड़ी क्षेत्र और पश्चिम एशिया

खाड़ी क्षेत्र

भारत के खाड़ी क्षेत्र के साथ घनिष्ठ और मजबूत संबंध हैं जो हमारे विस्तारित पड़ोस में प्रमुख महत्व का क्षेत्र बना रहा है। खाड़ी के प्रत्येक देश के साथ हमारे द्विपक्षीय मैत्रीपूर्ण संबंधों की गहरी जड़ों का एक साझा इतिहास है और बढ़ते बहुआयामी सहयोग और लोगों के परस्पर जीवंत जुड़ाव के माध्यम से इनका लगातार पोषण हुआ है।

यह क्षेत्र 2017-18 में 123 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार, हमारे देश की 50% से अधिक कच्चे तेल और 70% एलएनजी जरूरतों की ऊर्जा आपूर्ति के साथ, हमारा एक सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसके अलावा, भारत के साथ क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग के साथ बनाया जा रहा सामरिक तेल भंडार और हरित क्षेत्र की तेल रिफाइनरी परियोजना में निवेश हमारे ऊर्जा सुरक्षा आश्वासनों को बढ़ाते हैं। 9 मिलियन से अधिक भारतीय प्रवासियों का विशाल समूह 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2017 में) से अधिक के वार्षिक प्रेषण में अंशदान के अतिरिक्त, देशों के बीच सदभावना में योगदान करता है।

पिछले कुछ वर्षों में, गहन उच्च-स्तरीय आदान-प्रदानों के फलस्वरूप इस क्षेत्र के साथ जुड़ाव बढ़ा है और विविधीकरण हुआ है। खाड़ी क्षेत्र के देशों के साथ यह अभूतपूर्व ध्यान केंद्रित और लक्षित जुड़ाव स्पष्ट तौर पर चिन्हित विदेश नीति के उद्देश्यों का एक हिस्सा है और इसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और ठोस परिणाम प्राप्त हुए हैं।

वर्ष 2018-19 में, फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री की यूएई और ओमान की यात्रा के साथ शुरू होने वाले वर्ष के दौरान इस क्षेत्र के देशों के साथ घनिष्ठ और बढ़ती राजनीतिक व्यस्तता जारी रही। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने वर्ष के दौरान द्विपक्षीय वार्ताओं के लिए बहरीन, कुवैत और कतर और यूएई की यात्रा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने भारत-ओमान जेसीएम के 8वें सत्र की सह-अध्यक्षता करने के लिए 15 से 18 जुलाई 2018 तक ओमान की यात्रा की।

ईरान

वर्ष के दौरान भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती दिखाई दी। उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय राजनीतिक आदान-प्रदानों में फरवरी 2018 में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के राष्ट्रपति महामहिम डॉ. हसन रूहानी की राजकीय यात्रा और मई, 2018 और जनवरी 2019 में ईरान के विदेश मंत्री की भारत की दो यात्राएं शामिल थीं। आर्थिक, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, लोक संपर्क के क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय सहयोग को विस्तारित किया गया। चाबहार के रास्ते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पारगमन गलियारे की स्थापना के लिए भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच त्रिपक्षीय समझौता जुलाई 2018 में प्रभावी हुआ और भारतीय कंपनी ने अपना कार्यालय खोलकर दिसंबर 2018 से चाबहार में शहीद बेहस्ती बंदरगाह पर प्रचालन शुरू किया।

पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका

पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका (वाना) ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बना रहा है। संस्थागत संवाद तंत्र और यात्राओं के उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान के नियमित नियोजन के माध्यम से, वाना क्षेत्र के सभी देशों के साथ संबंधों को सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाया गया। यह क्षेत्र रॉक फॉस्फेट और इसके व्युत्पन्नों, और विभिन्न उर्वरकों के उत्पादन के लिए प्रमुख कच्चे माल पोटाश का एक प्राथमिक स्रोत है। इस क्षेत्र के देशों से रॉक फॉस्फेट की 80% से अधिक जरूरतों की पूर्ति की जाती हैं। यह क्षेत्र खनिजों में भी समृद्ध है। भारत ने इस क्षेत्र में अपने ऊर्जा हितों को और अधिक सुरक्षित करने के अपने प्रयासों को तेज किया। भारत ने औपचारिक और अनौपचारिक तंत्रों के माध्यम से इस क्षेत्र के अधिकांश देशों के साथ अधिक से अधिक रक्षा और सुरक्षा सहयोग किया है जिसमें आसूचना साझाकरण; आतंकवाद रोध; साइबरस्पेस आदि शामिल हैं। भारत ने इस क्षेत्र में जिबूती, सोमालिया और अन्य देशों के साथ अपने सहयोग में वृद्धि की है ताकि

जलदस्युता रोधी और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्रों में उनके हितों को सुरक्षित किया जा सके। पिछले वर्ष कई उच्च-स्तरीय आदान-प्रदानों द्वारा निर्मित गति को 2018 में मंत्रिस्तरीय/आधिकारिक यात्राओं की श्रृंखला के आदान-प्रदान सहित जारी रखा गया। हमारे आर्थिक और व्यापारिक हितों को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में कई वाणिज्यिक प्रतिनिधिमंडलों का भी आदान-प्रदान किया गया। यूएनआरडब्लूए के समक्ष आ रहे वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में, भारत ने 2018 से यूएनआरडब्लूए में अपना वार्षिक अंशदान 1.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया।

अफ्रीका

पूर्व और दक्षिण अफ्रीका

वर्ष 2018-19 के दौरान, भारत-अफ्रीका संबंधो में एक अभूतपूर्व प्रगति जारी रही। हमने अफ्रीकी देशों के साथ अपने राजनीतिक जुड़ाव को और बढ़ाया। इस वर्ष अप्रैल 2018 में पहली बार किसी भारतीय राष्ट्रपति ने स्वाज़ीलैंड (इस्वातिनी) और इक्वेटोरियल गिनी की यात्रा की और जुलाई 2018 में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री की रवांडा यात्रा हुई। राष्ट्रपति ने जाम्बिया (अप्रैल 2018) का भी दौरा किया और प्रधानमंत्री ने 21 वर्ष के अंतराल के बाद युगांडा और जुलाई 2018 में दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया। उपराष्ट्रपति ने बोत्सवाना (अक्टूबर-नवंबर 2018), जिम्बाब्वे (नवंबर 2018) और मलावी (नवंबर 2018) का दौरा किया। वर्ष के दौरान संसदीय आदान-प्रदान में युगांडा के संसदीय प्रतिनिधिमंडल के अतिरिक्त, ज़ाम्बिया के स्पीकर और उनके प्रतिनिधिमंडल की यात्रा भी शामिल थी।

उच्च-स्तरीय राजनीतिक विनियोजन के तहत मंत्री-स्तरीय सहित, संस्थागत तंत्रों की नियमित बैठकें आयोजित की गई। हमने तंजानिया के साथ 9वीं संयुक्त आयोग बैठक (JCM) (अक्टूबर 2018), इथियोपिया के साथ दूसरी जेसीएम (मई 2018) और मोज़ाम्बिक के साथ तीसरी जेसीएम (नवंबर 2018) की मेजबानी की। अगस्त 2018 में भारत-केन्या संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक आयोजित की गई। विदेश मंत्री ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक और आईबीएसए विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया। विदेश राज्यमंत्री ने कोट दी आइवरी, लाइबेरिया, बुर्किना फासो, नाइजीरिया और इक्वेटोरियल गिनी का दौरा किया। आधिकारिक स्तर के विनियोजनों में युगांडा और रवांडा (अप्रैल और मई 2018) के साथ पहले विदेशी कार्यालय परामर्श और मलावी के साथ स्वास्थ्य पर पहला संयुक्त कार्य समूह शामिल थे।

रवांडा के राष्ट्रपति महामहिम पॉल कागमे ने मार्च 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की। कोमोरो के राष्ट्रपति महामहिम अज़ाली असौमानी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संस्थापक सम्मेलन के सिलसिले में 10 से 12 मार्च, 2018 तक भारत का दौरा किया। ज़िम्बाब्वे गणराज्य के उपराष्ट्रपति माननीय जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. कांस्टेंटिनो चिवेंगा, मलावी गणराज्य के उपराष्ट्रपति माननीय सैलोस क्लॉस चिलिमा, युगांडा के उपराष्ट्रपति माननीय एडवर्डकीवानुका सेकंडी ने 25-27 मार्च 2018 को आयोजित सीआईआई-एक्जिम बैंक कॉन्क्लेव के 13वें संस्करण में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। कॉन्क्लेव के अंत में उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। जिम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति, जो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के विशेष दूत भी थे, ने 23 मार्च 2018 को भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से मुलाकात की।

अफ्रीका में अधिक सार्थक राजनयिक उपस्थिति बनाने के लिए, भारत सरकार ने अगले 4 वर्षों में अफ्रीका में 18 नए दूतावास/उच्चायोग खोलने का निर्णय लिया है जिससे अफ्रीका में भारतीय मिशनों की संख्या 47 हो जाएगी। इस संदर्भ में, रवांडा और जिबूती में इस वर्ष पहले ही भारतीय मिशन खोले जा चुके हैं।

भारत द्वारा मंत्री/उच्च-स्तर पर आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में दक्षिण अफ्रीका के पीटरमैरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी के साथ घटित वाकये के 120वें वर्ष का स्मरणोत्सव और नवंबर 2018 में नाइजीरिया में पश्चिम अफ्रीका क्षेत्रीय सीआईआई-एक्ज़िम बैंक कॉन्क्लेव और मलावी में भारत का मानवता कार्यक्रम का शुभारंभ शामिल था। भारत में, अफ्रीका के गणमान्य व्यक्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (अक्टूबर 2018) और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन (सितंबर-अक्टूबर 2018) की पहली असेम्बली में भाग लिया।

भौगोलिक पहुंच और क्षेत्रीय कवरेज दोनों कार्यक्रमों में उल्लेखनीय विस्तार हुआ। भारत ने अफ्रीकी देशों को अनुदान सहायता (दवाएं, किताबें, वाहन आदि), ऋण श्रृंखलाएं, तकनीकी परामर्श, आपदा राहत, मानवीय सहायता, उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति और अल्पकालिक नागरिक और सैन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों सहित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की श्रृंखला को सहायता प्रदान करना जारी रखा। 1 अप्रैल 2018 से, स्वाज़ीलैंड (एस्वतिनी) में संसद भवन के निर्माण, बुरूंडी में संसद भवन, मलावी में आपदा रिकवरी केंद्र के निर्माण, कृषि परियोजनाओं और उत्पादों, डेयरी सहयोग, बिजली लाइनों और सबस्टेशनों, जल परियोजनाओं आदि के निर्माण के लिए 1038 मिलियन अमेरिकी डॉलर राशि के 11 नए ऋण प्रदान किए गए। मोज़ाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी ने मोजाम्बिक के सोफाला प्रांत में सड़क निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सड़क परियोजना की आधारशिला रखी। 2018-19 में कुल 101.13 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नौ परियोजनाएं पूर्ण हो गई हैं।

नए क्षमता निर्माण संस्थानों में दक्षिण अफ्रीका में गांधी-मंडेला कौशल केंद्र और जिम्बाब्वे में इंडो-ज़िम प्रौद्योगिकी केंद्र का उन्नयन शामिल है। क्षमता निर्माण और कौशल विकास कार्यक्रम भारत के विस्तार विकास साझेदारी के केंद्र में बने रहे। हमने आईटीईसी, आईसीसीआर, आईएएफएस कार्यक्रम और पीपीपी प्रशिक्षण पहलों के तहत अपने लोकप्रिय प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति कार्यक्रमों को जारी रखा। इस वर्ष के दौरान डेयरी सहयोग पर नए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए।

आर्थिक मोर्चे पर, अफ्रीका के साथ हमारा व्यापार कई गुना और विविधतापूर्ण रहा। वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार के आंकड़े 62.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर है जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 22% अधिक है। एसएडीसी कारोबारी शिखर सम्मेलन का दक्षिण अफ्रीका और इन्वेस्ट इन इंडिया बिजनेस फोरम का जोहान्सबर्ग में नवंबर 2018 में आयोजन किया गया।

इस वर्ष संपन्न किए गए महत्वपूर्ण समझौतों में मलावी के साथ प्रत्यर्पण संधि, रवांडा के साथ डेयरी सहयोग पर समझौता ज्ञापन, मलावी के साथ असैन्य परमाणु सहयोग में क्षमता निर्माण, दक्षिण अफ्रीका के साथ अंतरिक्ष सहयोग, कई देशों के साथ राजनयिक वीजा छूट समझौते और युगांडा के साथ रक्षा सहयोग समझौता शामिल हैं।

रक्षा सहयोग के संबंध में, वर्ष 2018 में कोमोरोस में भारतीय नौसेना के जहाजों ने पहली बार सदभावना यात्रा की, मेडागास्कर (अक्टूबर 2018), मोजाम्बिक (सितंबर 2018) और दक्षिण अफ्रीका (अक्टूबर 2018) में सदभावना जहाज यात्रा संपन्न हुई। इस वर्ष सेना प्रमुख और सीओएससी ने केन्या और तंजानिया का दौरा किया। दक्षिण अफ्रीकी नौसेना प्रमुख ने नवंबर 2018 में भारत का दौरा किया।

लेसोथो, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, मेडागास्कर और जिम्बाब्वे सहित विभिन्न अफ्रीकी देशों को भाभाट्रोन और एंबुलेंसों सहित, दवाइयों और चिकित्सा उपस्करों का उपहार देने के साथ स्वास्थ्य और फार्मास्युटिकल क्षेत्र में सहयोग पर फोकस बनाए रखा गया। सार्वजनिक-निजी सहयोग के क्षेत्र में नई पहल इस साल जारी रही और अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अधिक अस्पतालों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया।

भारतीय और अफ्रीकी लोगों के आवागमन को आसान बनाने के लिए, अफ्रीका से 33 देशों को कवर करने के लिए ईटीवी सुविधा का विस्तार किया गया। दिसंबर 2018 से एयर तंज़ानिया द्वारा दार एस सलाम से सीधी उड़ानों की घोषणा के साथ एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाया गया।

समान विचारधारा वाले देशों के साथ त्रिपक्षीय सहयोग की हमारी पहल के तहत, हमने अफ्रीका में संयुक्त परियोजनाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ पहले दक्षिण-दक्षिण सहयोग समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया। 11 दिसंबर 2018 को फ्रांस के साथ वार्ता का दूसरा दौर आयोजित किया गया था। जापान के साथ, हमने केन्या में कैंसर अस्पताल की संयुक्त स्थापना की घोषणा की। जापान के साथ, हम एशिया और अफ्रीका में औद्योगिक गलियारों और औद्योगिक नेटवर्क विकसित करने की दिशा में भारतीय और जापानी व्यवसायों के साथ आदान-प्रदान बढ़ाने के लिए एशिया-अफ्रीका क्षेत्र में जापान-भारत व्यापार सहयोग का एक मंच भी स्थापित कर रहे हैं।

भारत ने कुछ अफ्रीकी देशों में सकारात्मक आंतरिक राजनीतिक विकास में भाग लिया। भारत सरकार ने निरस्त्रीकरण, सैन्य विघटन और पुनर्घटन (डीडीआर) शांति प्रक्रिया के लिए मोजाम्बिक में मुख्य विपक्षी दल की सेना विंग के साथ एक शांति पर्यवेक्षक को प्रतिनियुक्त किया। भारत ने जुलाई 2018 में जिम्बाब्वे में होने वाले ऐतिहासिक चुनावों का अवलोकन करने के लिए 8 चुनाव पर्यवेक्षकों की एक टीम भी भेजी।

पश्चिम अफ्रीका

वर्ष के दौरान **पश्चिम अफ्रीका** क्षेत्र के देशों के साथ भारत के संबंधों का विस्तार और विविधीकरण जारी रहा। इस अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय/बहुपक्षीय सम्मेलनों के अवसर पर कई उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय यात्राएं हुई तथा बैठकें आयोजित की गई। हमारी सक्रिय भागीदारी ने राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने, आर्थिक (व्यापार और निवेश) संबंधों को बढ़ाने और विकास साझेदारी को गहन बनाने में योगदान दिया।

यह क्षेत्र (पश्चिम, उत्तर-पश्चिम, मध्य और दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका के 25 देशों सहित) अफ्रीका की सबसे अधिक जनसंख्या और ऊर्जा संसाधनों तथा खनिजों के सबसे बड़े भंडारों वाला सबसे तीव्र अर्थव्यवस्थाओं का गढ़ है। यह क्षेत्र सभी ज्ञात खनिजों से समृद्ध है। भारत इस क्षेत्र से कच्चे तेल की लगभग 18% जरूरतें पूरी करता है (अकेले नाइजीरिया से 11-12%)। भारत प्रति वर्ष घाना से 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का सोना आयात करता है। भारत को इस क्षेत्र के कोट डी'आइवरी, गिनी बिसाऊ और सेनेगल सहित देशों से उल्लेखनीय मात्रा में कच्चा काजू प्राप्त करता है।

यह क्षेत्र राजनीतिक रूप से स्थिर रहा। हालांकि, आतंकवाद और संगठित अपराधों से उत्पन्न चुनौतियों का खतरा कई देशों को प्रभावित करता रहा। आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए क्षेत्र के देशों के बीच प्रयासों का समन्वय और तालमेल बेहतर रहा है। इन प्रयासों में बुर्किना फासो, चाड, माली, मॉरिटानिया और नाइजर द्वारा स्थापित सहेल (जी5 सहेल) या एफसी-जी5एस के पांच के समूह की संयुक्त सेना शामिल है। भारत मॉनूसको (कांगो डोमेस्टिक रिपब्लिक में संयुक्त राष्ट्र स्थिरीकरण मिशन) को सैन्य पर्यवेक्षकों और पुलिसकर्मियों सहित सैनिक योगदान दे रहा है। वर्तमान में 2,930 भारतीय कार्मिक मॉनसको के साथ तैनात किए गए हैं।

अप्रैल 2018 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान, माली (जुलाई 2018); कैमरून (अक्टूबर 2018); डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो [दिसंबर 2018]; नाइजीरिया [फरवरी 2019] और सेनेगल [फरवरी 2019], चाड, डीआरसी, गैबॉन, गिनी (जनवरी 2019) में राष्ट्रपति चुनाव हुए, माले, मॉरिटानिया, साओ टोम और प्रिंसिपे और टोगो ने भी संसदीय चुनाव देखे।

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने अप्रैल 2018 में इक्वेटोरियल गिनी का दौरा किया। वर्ष के दौरान, राज्यमंत्री श्री एम.जे. अकबर ने कोट डी'आइवरी, लाइबेरिया, बुर्किना फासो, नाइजीरिया और इक्वेटोरियल गिनी की यात्रा की। मार्च 2018 में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के संस्थापक सम्मेलन में पश्चिम अफ्रीका के देशों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया और इसमें बुर्किना फासो, नाइजर के राष्ट्रपति, कोटे डी'आइवरी के उपराष्ट्रपति और कई मंत्री शामिल थे।

पश्चिम अफ्रीका के देशों के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 28.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर (वित्तीय वर्ष 2017-18) रहा। वित्त वर्ष 2016-17 की तुलने में इसमें 29% की वृद्धि हुई। यह वृद्धि निर्यात और आयात दोनों में हुई थी। क्षमता निर्माण, कौशल विकास और भौतिक और सामाजिक अवसंरचना को मजबूत करना इस क्षेत्र के साथ भारत की विस्तारित विकास साझेदारी के केंद्र में रहा है। 2017-18 के लिए, लगभग 1450 नागरिक आईटीईसी (भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम) स्लॉट; 200 से अधिक रक्षा स्लॉट (नाइजीरिया को 111 स्लॉट) और पश्चिम अफ्रीकी देशों को 300 आईसीसीआर छात्रवृत्तियां आवंटित की गईं। सभी 25 पश्चिम अफ्रीकी देशों ने संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय निकायों में विभिन्न चुनावों में भारत की उम्मीदवारी को समर्थन जारी रखा। 14 पश्चिम अफ्रीकी देशों ने आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर और पुष्टि की है।

यूरोप और यूरोपीय संघ

मध्य यूरोप

भारत ने मध्य यूरोप के देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की अपनी नीति जारी रखी। राजनीतिक मुद्दों पर, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों मंचों पर अच्छी समझ रही। बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार, व्यापारिक आदान-प्रदान, शैक्षिक आदान-प्रदान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने इस क्षेत्र के साथ हमारे बढ़ते संबंधों में वृद्धि की। इस वर्ष नॉर्वे, माल्टा, चेक गणराज्य और डेनमार्क से उच्च-स्तरीय यात्राएं दिखाई दी। राष्ट्रपति ने ग्रीस, साइप्रस, बुल्गारिया और चेक गणराज्य और उपराष्ट्रपति ने सर्बिया, माल्टा और रोमानिया की यात्राएं कीं। प्रधानमंत्री ने पहली बार स्टॉकहोम

में भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया और स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड के नेताओं के साथ बातचीत की। वर्ष के दौरान कारोबार करने की आसानी के मापदंडों में प्रगति, माल एवं सेवा कर के माध्यम से एक एकीकृत बाजार बनाने, निवेश और लाइसेंसिंग नीतियों के उदारीकरण, दिवाला और दिवालियापन संहिता, उत्पादक विनिवेश उपायों, डिजिटल रोजगार कार्यालयों के शुभारंभ और सरकार की पहल अर्थात् मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप/स्टैंड-अप इंडिया, सबके लिए आवास, शहरी नवीकरण और कायाकल्प, डिजिटल अवसंरचना और औद्योगिक गलियारों, स्वच्छ भारत और कौशल भारत सहित अवसंरचना के बारे में जानकारी के प्रसार पर फोकस रहा। भारत और मध्य यूरोपीय देशों ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक-दूसरे को समर्थन देना जारी रखा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में एक-दूसरे के उम्मीदवारों का समर्थन भी शामिल था।

पश्चिमी यूरोप

भारत ने बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, आयरलैंड, नीदरलैंड, आदि सहित पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ अपना बहुमुखी जुड़ाव जारी रखा। भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम. वैंकैया नायडू ने 18-19 अक्टूबर 2018 को यूरोपीय संघ की मेजबानी में आयोजित 12वीं एशिया-यूरोप बैठक (एएसईएम) के लिए ब्रुसेल्स का दौरा किया और बेल्जियम के राजा से मुलाकात की तथा बेल्जियम और भारत के बीच उत्कृष्ट द्विपक्षीय सहयोग के साथ ही साझा हित के समकालीन मुद्दों पर चर्चा की। उपराष्ट्रपति ने प्रथम विश्व युद्ध की आर्मिस्टिस शताब्दी के स्मारक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 11 नवंबर 2018 को पेरिस में उद्घाटन पेरिस शांति मंच में भाग लिया। उन्होंने 10 नवंबर 2018 को विलियर्स गुइस्लान में मारे गए भारतीय सैनिकों के स्मारक का उदघाटन किया।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 17 से 23 जून 2018 तक इटली, फ्रांस, लक्ज़मबर्ग और ब्रुसेल्स की 4 देशों की आधिकारिक यात्रा की। चार यूरोपीय देशों की यात्रा ने राजनीतिक नेतृत्व के साथ वैश्विक, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों के व्यापक स्तर पर गहन विचार-विमर्श करने और यूरोपीय संघ के साथ हमारे बढ़ते सामरिक जुड़ाव को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान किया।

भारत और फ्रांस ने अपनी सामरिक साझेदारी के बीस वर्षों को चिन्हित किया जो 1998 में स्थापित की गई थी। यह संबंध एक करीबी और बढ़ते द्विपक्षीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों के अभिसरण द्वारा चिन्हित है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग, अंतरिक्ष सहयोग और असैनिक परमाणु सहयोग के क्षेत्र सामरिक भागीदारी के प्रमुख आधार हैं। सहयोग के इन पारंपरिक क्षेत्रों के अलावा, भारत और फ्रांस हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) सहित जलवायु परिवर्तन और अन्य बातों के बीच स्थायी विकास और विकास जैसे सहयोग के नए क्षेत्रों में तेजी से संलग्न हैं। रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपनी समकक्ष फ्रांस की सशस्त्र बलों की मंत्री सुश्री फ्लोरेंस पार्ली के साथ पहले द्विपक्षीय मंत्री स्तरीय वार्षिक रक्षा संवाद के लिए 11-12 अक्टूबर, 2018 को पेरिस का दौरा किया।

भारत और जर्मनी के बीच उच्च-स्तरीय यात्राओं ने 2018 में द्विपक्षीय संबंधों में गति बनाए रखने में मदद की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2018 में जर्मनी का दौरा किया। जर्मनी के संघीय राष्ट्रपति डॉ. फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर ने मार्च 2018 में भारत की अपनी पहली यात्रा की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और चांसलर सुश्री एंजेला मर्केल द्वारा साझा किए गए विश्वास और समझ को वर्ष के दौरान आयोजित कई बैठकों और फोन वार्तालापों में प्रकट किया गया। दोनों पक्षों की ओर से, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर नियमित रूप से द्विपक्षीय दौरे किए गए और व्यापार और निवेश, विनिर्माण, कौशल विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, अवसंरचना, नवोन्मेष, रक्षा सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में परस्पर संवाद और सहयोग जारी रहा।

भारत और इटली ने भारत और इटली में साल भर उत्सवों के साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मनाई। पूर्व इतालवी प्रधानमंत्री श्री पाओलो जेंटिलोनी की यात्रा के ठीक एक साल बाद, अक्टूबर 2018 में प्रधानमंत्री श्री ग्यूसेप कोंटे की आधिकारिक यात्रा से संबंधों को और बढ़ावा मिला। जून 2018 में कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री श्री ग्यूसेप कोंटे की एशिया की यह पहली यात्रा थी। उसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग-भारतीय उद्योग परिसंघ (डीएसटी)-(सीआईआई) प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 24वें संस्करण में इतालवी आधिकारिक-सह-व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया जिसमें इटली साझेदार देश था। 17 जून 2018 को विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज की इटली की यात्रा, इटली की नई सरकार के साथ पहला बड़ा राजनीतिक आदान-प्रदान था।

डच प्रधानमंत्री श्री मार्क रुटे ने 24 और 25 मई 2018 को भारत में एक व्यापार मिशन का नेतृत्व किया। यह भारत में अब तक का सबसे बड़ा डच व्यापार मिशन था।

भारत और ब्रिटेन के बीच बहुआयामी सामरिक साझेदारी को 18 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री की लंदन यात्रा, तीन साल की अवधि के भीतर प्रधानमंत्री स्तर पर तीसरी, से नई गति प्राप्त हुई। यात्रा के दौरान साइबर संबंध ढ़ांचे, गंगा नदी के कायाकल्प, कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा, सुरक्षित परमाणु ऊर्जा के उपयोग, पशुपालन, मत्स्यपालन और डेयरी सहयोग, आपराधिक रिकॉर्ड साझा करने, न्यूटन-भाभा कार्यक्रम के तहत मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान और आयुर्वेद और पारंपरिक भारतीय चिकित्सा में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने जैसे विभिन्न क्षेत्रों में दस समझौता ज्ञापनों/समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद, दोनों पक्षों की कई मंत्रिस्तरीय यात्राओं के साथ वर्ष भर द्विपक्षीय सहयोग में गति बनाए रखी गई।

यूरोपीय संघ: भारत और यूरोपीय संघ के बीच वर्ष 2000 से शिखर सम्मेलन स्तरीय बैठकों सहित सहयोग का बहु-स्तरीय संस्थागत स्थापत्य मौजूद है। 2004 में इस संबंध को 'सामरिक साझेदारी' में उन्नत किया गया। आज, भारत और यूरोपीय संघ के 30 से अधिक संवाद तंत्रों में आपसी हित के मुद्दों का एक विशाल सप्तक निहित है।

2018, सभी मानकों के अनुसार, भारत-यूरोपीय संघ की सामरिक साझेदारी में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। हमारी गहन भागीदारी हमारे एजेंडा 2020 और 14वें भारत-यूरोपीय संघ संयुक्त वक्तव्य में हमारे द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में रचनात्मक और परिणामोन्मुखी रही है।

यूरोपीय संघ ने 20 नवंबर 2018 को भारत के लिए एक नया सामरिक पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें अगले 10-15 वर्षों में किए जाने वाले ठोस कार्रवाई बिंदुओं सहित व्यापक कैनवास को शामिल किया गया।

2018 में, विभिन्न मंत्रिस्तरीय यात्राओं के अलावा, हमने जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, नीदरलैंड और पुर्तगाल के साथ शिखर स्तर की बैठकें की हैं, जिनसे हमारे पहले से मजबूत संबंध और मजबूत हुए। अनुसरण के लिए यूरोपीय आयोग के आयुक्तों के भी दौरे आयोजित किए गए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए रोड मैप बनाए गए हैं।

2017-18 में यूरोपीय संघ के साथ भारत के 101 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के द्विपक्षीय व्यापार के साथ यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापार साझेदार है।

अमेरिका

2018-19 में अमेरिका के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों और कनाडा के साथ संबंधों में निरंतर प्रगति के लिए महत्वपूर्ण अग्रगामी हलचल देखी गई। भारत, अमेरिका और जापान के नेताओं सहित पहला त्रिपक्षीय सम्मेलन नवंबर 2018 में ब्यूनस आयर्स में हुआ। सितंबर 2018 में भारत-अमेरिकी मंत्रिस्तरीय 2+2 वार्ता की उदघाटन बैठक ने विदेश नीति, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों पर समृद्ध चर्चा और परिणामों के लिए मंच तैयार किया। दोहरे उपयोग की वस्तुओं में अमेरिकी व्यापार के उद्देश्य से एक सामरिक व्यापार प्राधिकरण टियर-I भागीदार देश के रूप में भारत का उन्नयन अमेरिकी आतंकरोधी सहयोग के एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में भारत का लाभ परिलक्षित किया और क्षेत्रीय आतंकवाद-प्रतिरोधी चुनौतियों पर अमेरिका के साथ समन्वय में काफी सुधार हुआ। फरवरी, 2018 में ही कनाडा के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा और दोनों विदेश मंत्रियों की भारत-कनाडा सामरिक वार्ता, ने आतंकवाद और हिंसक चरमपंथ का सामना करने सहित कई क्षेत्रों में कार्यात्मक सहयोग को प्रोत्साहन प्रदान किया।

लैटिन अमेरिका

भारत लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है। एक मिलियन से अधिक भारतीय प्रवासियों जो सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से भारत से जुड़े हुए हैं, की उपस्थिति इस संबंध को एक विशेष आयाम देती है।

2018 के दौरान, क्षेत्र के साथ भारत के संबंध हमारे राजनीतिक जुड़ाव के साथ ही हमारे व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों के संदर्भ में कई वीवीआईपी यात्राओं और परिसंवादों इंटरैक्शन द्वारा चिन्हित किए गए। भारत और एलएसी देशों के नेतृत्व के बीच संदेशों के नियमित आदान-प्रदान ने निकट संपर्क बनाए रखने में मदद की।

संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कानूनी और संधियां प्रभाग

2018 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र (यू एन), गुट निरपेक्ष आंदोलन (नैम) और राष्ट्रमण्डल सहित अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ अपनी सक्रिय संलग्नता को जारी रखा। प्रधान मंत्री ने अप्रैल 2018 में लंदन में आयोजित राष्ट्रमण्डल शासन प्रमुखों की बैठक (चोगम) में भारतीय शिष्टमण्डल की अगुवाई की, जिसके दौरान उन्होंने अनेक घोषणाएं की जैसे तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्रमण्डल निधि और साथ ही न्यू यॉर्क और जेनेवा में राष्ट्रमण्डल लघु राष्ट्र कार्यालयों को भारत द्वारा वित्तीय योगदान को दोगुना किया जाना, भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी निधि के अंतर्गत राष्ट्रमण्डल उप-विंडो को शुरू किया जाना, भारत में राष्ट्रमण्डल देशों के 16 वर्ष से कम उम्र के लिए समुद्री विकास और क्रिकेट प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत क्षमता निर्माण कार्यक्रम। ये घोषणाएं राष्ट्रमण्डल में भारत द्वारा अपनी संलग्नता को बढ़ाने के प्रयासों का संकेत देती है।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने अप्रैल 2018 में बाकू में आयोजित नैम मध्यकालिक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारतीय शिष्टमण्डल की अगुवाई की। विदेश मंत्री ने 25 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2018 को आयोजित 73वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के उच्चस्तरीय सेगमेंट के दौरान भी भारतीय शिष्टमण्डल की अगुवाई की। यूएनजीए में अपने वक्तव्य में विदेश मंत्री ने यूएनजीसी के सुधार की तात्कालिक जरूरत पर जोर दिया और कहा कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (सीसीआईटी) को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए। उच्च स्तरीय आदान-प्रदान में अगस्त 2018 में यूएनजीए के 73वें सत्र की अध्यक्ष सुश्री मारिया फर्नाण्डा एस्पीनोसा और जून 2018 में यूएन शान्तिरक्षा ऑपरेशन हेतु अवर महासचिव श्री जीन पियरे लैक्रोइक्स द्वारा किए गए आदान-प्रदान शामिल थे।

भारत ने नवम्बर 2018 में सियरे लियोन के लिए रेजिडुअल विशेष न्यायालय को स्वैच्छिक योगदान के रूप में 100000 अमेरिकी डॉलर प्रदान किया। रेजिडुअल न्यायालय अन्य बातों के साथ-साथ गवाहों और पीड़ितों को संरक्षण और सहयोग प्रदान करने, सजा को लागू किए जाने की निगरानी करने; कानूनी सहायता प्रदान करने और अवमानना कार्यवाहियां आयोजित करने के लिए अधिदेशित है।

भारत और शांतिरक्षाः-

अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा मंत्रिस्तरीय बैठक 29 मार्च 2019 को न्यू यॉर्क में आयोजित की जाएगी। इसका आयोजन 2017 के वैंकुअर और 2016 के लंदन मंत्रिस्तरीय संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा सम्मेलनों के अनुक्रम में किया जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) का 73वां सत्र, जिसका विषय "संयुक्त राष्ट्र को सभी देशों के लिए सुसंगत बनानाः शांति, समतामूलक और संधारणीय समाजों के लिए वैश्विक नेतृत्व और साझा जिम्मेदारी" था न्यूयॉर्क में 18 सितम्बर 2018 को प्रारंभ हुआ। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 25 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2018 को 73वें यूएनजीए सत्र के उच्च स्तरीय सेगमेंट के दौरान भारतीय शिष्टमण्डल की अगुवाई की और 29 सितम्बर 2018 को भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य दिया।

संयुक्त राष्ट्र में जी-4 और एल69 जैसे सुधारोन्मुख समूहों के साथ सक्रिय संलग्नता करते हुए भारत ने अवधि के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी रखा। एल 69 समूह ने भारत सहित अपने सभी सदस्यों के सहयोग से "सुरक्षा परिषद सुधारः 25 वर्षों की वार्ताएं" पर हैण्डबुक तैयार किया जिसमें विगत 25 वर्षों के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार प्रक्रिया के अधीन तैयार किए गए सभी दस्तावेज़ों को संकलित किया गया है।

जी-4 विदेश मंत्री (जिसमें भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान शामिल हैं) ने यूएनएससी सुधार की प्रगति की समीक्षा के लिए 73वें यूएनजीए सत्र के दौरान 25 सितम्बर, 2018 को न्यू यॉर्क में अपनी वार्षिक बैठक आयोजित की।

भारत ने वैश्विक आतंकवाद-रोध प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के भीतर और अधिक प्राथमिकता दिए जान का प्रयास जारी रखा। यह बार-बार रेखांकित किया गया कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए अपने विधिक ढांचे को मजबूत बनाने की आवश्यकता है जो अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय पर करार द्वारा अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद-रोध सहयोग का समर्थन करें और मौजूदा आतंकवाद-रोध ढांचे की और अधिक पारदर्शिता एवं प्रभाविकता सुनिश्चित करें।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री एण्टोनियो गुटरेस ने विदेश मंत्री के बुलावे पर 1 से 4 अक्टूबर, 2018 को भारत की यात्रा की। महासचिव गुटरेस ने 2 अक्टूबर, 2018 को महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन में हिस्सा लिया।

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सौर गठजोड़ (आईएसए) की प्रथम सभा के संयुक्त उद्घाटन समारोह, द्वितीय रि-इन्वेस्ट सम्मेलन और हिंद महासागर रिम राष्ट्र संघ सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लिया।

भारत संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा फौज का सबसे बड़ा समेकित सहयोगकर्ता बना रहा, उसने 1950 के दशक से 200,000 से अधिक फौजियों और पुलिस कर्मियों की व्यवस्था की है। 31 अक्टूबर, 2018 की स्थिति के अनुसार भारत चौथा सबसे बढ़ा फौज योगदाता देश है जिसने 9 शांतिरक्षा मिशनों में 6,608 कार्मिकों का नियोजन किया है।

भारत का चयन 2019-2021 की अवधि के लिए सं. रा. मानवाधिकार परिषद (एचआरसी) में हुआ है जो पूरे 18 उम्मीदवार देशों के बीच सर्वाधिक मत (193 में से 188) पाने वाला देश था। भआरत को 2019-2022 की अवधि के लिए गैर-सरकारी संगठन की समिति के लिए पुनः चुना गया है। भारत को 2019-21 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र निकायः अपराध निवारण और दाण्डिक न्याय आयोग (सीसीपीसीजे) में, 2019-2021 की अवधि के लिए यूएनडीपी/यूएनएफपीए/यूएनओपीएस के कार्यकारी बोर्ड, 2019-2021 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र-महिला (यूएन- महिला का कार्यकारी बोर्ड), 16 अप्रैल 2018 से 2021 की अवधि के लिए सीपीडी (जनसंख्या और विकास आयोग) और 16 अप्रैल 2015 से 2021 तक सीएसओसीडी (सामाजिक विकास आयोग) में भी चुना गया है। भारत को 2019-2022 की अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ परिषद (आईटीयू) के सदस्य के रूप में पुनः चुना गया है।

निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले

2018-19 में, भारत निरस्त्रीकरण, अप्रसार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रूप से संलग्न रहा और विभिन्न क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों में अपने अनुभवों और भागीदारियों के आधार पर एक मजबूत और विश्वसनीय कथानक को कायम रखा। भारत ने सार्वभौमिक और गैर-भेदभावपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के साथ ही सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के लिए निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर सक्रिय भूमिका निभाना जारी रखा।

निरस्त्रीकरण के मुद्दों पर भारत का रुख अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों और अंतर्राष्ट्रीय भू-स्थैतिक माहौल में वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सहयोगी प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ घनिष्ठ जुड़ाव की परंपरा से निर्देशित रहा।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र की पहली समिति, संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग, निरस्त्रीकरण सम्मेलन, जैविक और विषाक्त हथियारों के सम्मेलन (बीटीडब्ल्यूसी), रासायनिक हथियार सम्मेलन (सीडब्ल्यूसी), कुछ पारंपरिक हथियारों पर सम्मेलन (सीसीडब्ल्यू) और संयुक्त राष्ट्र छोटे अस्त्रों और हल्के हथियारों पर कार्रवाई कार्यक्रम (यूएनपीओए ऑन एसएएलडब्ल्यू) के साथ ही इन मुद्दों से निपटने वाले विभिन्न अन्य बहुपक्षीय मंचों और तंत्रों की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

भारत 2018 में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप (एजी) का सदस्य बना। भारत ने अप्रसार के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वैश्विक प्रयासों में योगदान करते हुए, वासेनार अरेंजमेंट (डब्ल्यूए), मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (एमटीसीआर) और हेग आचार संहिता के साथ भी सक्रिय रूप से कार्य किया।

बहुपक्षीय आर्थिक संबंध

ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका)

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 25 से 27 जुलाई 2018 तक दसवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। नेताओं ने आर्थिक और वित्त सहयोग, वैश्विक आर्थिक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के परिणामों में जोहान्सबर्ग घोषणा शामिल थी जिसमें ब्रिक्स नेताओं द्वारा आतंकवाद पर सशक्त विचार व्यक्त किए गए। ब्रिक्स नेताओं ने अपने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की निंदा की। उन्होंने अपने देशों से आतंकवादी नेटवर्क और उनके कार्यों के खतरे को रोकने के लिए सभी देशों की जिम्मेदारी की याद दिलाया। ब्रिक्स नेताओं ने ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में 30 नवंबर 2018 को जी20 शिखर सम्मेलन के अंत में अपनी प्रथागत अनौपचारिक बैठक भी की। नेताओं ने जी20 बैठक की कार्यसूची पर चर्चा की और वैश्विक राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और महत्व और आपसी चिंता के वैश्विक प्रशासन मुद्दों की विस्तृत श्रृंखला पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

तेरहवां जी20 शिखर सम्मेलन

प्रधानमंत्री ने 30 नवंबर और 1 दिसंबर 2018 को ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में तेरहवें जी20 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। शिखर सम्मेलन का विषय "निष्पक्ष और सतत विकास के लिए सहमति का निर्माण" था। शिखर सम्मेलन के एजेंडे में वैश्विक अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, 2030 तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, सतत विकास, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जलवायु स्थिरता, अवसंरचना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऊर्जा संक्रमण और स्थायी खाद्य भविष्य शामिल थे। जी20 नेताओं ने शिखर सम्मेलन में एक विज्ञप्ति जारी की जिसमें घोषणा की गई कि शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एक एजेंडे के माध्यम से निष्पक्ष और सतत विकास के लिए आम सहमति का निर्माण करना है जो जन-केंद्रित, समावेशी और दूरंदेशी हो। शिखर सम्मेलन में 30 नवंबर 2018 को 'एक उचित और सतत भविष्य' पर नेताओं का रिट्रीट आयोजित किया गया।

आईबीएसए (भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका)

वर्ष के दौरान आईबीएसए के विदेश मंत्रियों की दो बैठकें आयोजित की गईं। विदेश मंत्री (ईएएम) श्रीमती सुषमा स्वराज ने 27 सितंबर 2018 को न्यूयॉर्क में आयोजित नौवें आईबीएसए त्रिपक्षीय मंत्री आयोग की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 4 जून 2018 को प्रीटोरिया में आईबीएसए के विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर एक आईबीएसए संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया।

सार्क और बिम्सटेक

बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी पहल

बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी पहल भारत की प्रमुख विदेश नीति की प्राथमिकताओं 'नेबरहुड फर्स्ट' और 'एक्ट ईस्ट' को पूरा करती है। 30-31 अगस्त 2018 को काठमांडू में आयोजित चौथे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में बिम्सटेक को महत्वपूर्ण प्रेरणा मिली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। शिखर सम्मेलन का विषय था "शांतिपूर्ण, समृद्ध और सतत बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की ओर"। शिखर सम्मेलन में अपनाई गई काठमांडू घोषणा सुरक्षा और आतंकवाद, आपदा प्रबंधन, संपर्क और व्यापार, ऊर्जा, कृषि और गरीबी उन्मूलन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति, पर्यटन और लोगों के निकट संपर्क के प्रमुख क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग को तेज करने का प्रयास करती है।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 27 सितंबर 2018 को न्यूयॉर्क में 73वें यूएनजीए सत्र के अवसर पर आयोजित सार्क मंत्रिपरिषद की एक अनौपचारिक बैठक में भाग लिया। मार्च 2018 में ढाका में आयोजित बिम्सटेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की दूसरी बैठक के आयोजन से क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को और बढ़ावा मिला। भारत ने 5 से 7 दिसंबर 2018 तक आईडीएसए, नई दिल्ली में बिम्सटेक क्षेत्रीय साइबर सुरक्षा संवाद का आयोजन किया। आतंकवाद-रोधक विषय पर पहला बिम्सटेक सैन्य अभ्यास (बिम्सटेक माइलक्स-2018) पुणे में 10 से 16 सितंबर 2018 तक आयोजित किया गया।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 27 सितंबर 2018 को न्यूयॉर्क में 73वें यूएनजीए सत्र के अतिरिक्त आयोजित सार्क मंत्रिपरिषद की एक अनौपचारिक बैठक में भाग लिया। सचिव (आर्थिक कार्य) ने 4 मई 2018 को मनीला, फिलीपींस में एशियाई विकास बैंक की वार्षिक बैठक के अतिरिक्त सार्क वित्त मंत्रियों की 12वीं अनौपचारिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

भारत ने उनके क्षेत्रीय केंद्रों/विशिष्ट निकायों और क्षेत्रीय बैठकों सहित सार्क की अन्य आधिकारिक और तकनीकी स्तर की बैठकों में भाग लिया। दक्षिण एशिया के देशों में अपने राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का विस्तार करने की भारत की पहल, 15 जनवरी 2018 को श्रीलंका में अपने विस्तार के पहले चरण के उदघाटन के साथ आगे बढ़ी। भारत ने दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (एसएयू) को अपना समर्थन जारी रखा, जिसे भारत में उत्कृष्टता के एक केंद्र के तौर पर स्थापित किया गया था। सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र (आईयू), गांधीनगर का भारत द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषण जारी है।

विकास सहयोग

विकास सहयोग भारत के बाहरी जुड़ाव का एक प्रमुख स्तंभ है। भारत के भूराजनीतिक, सामरिक और आर्थिक हितों और साझा समृद्धि के प्रति प्रतिबद्धता ने इसके वृहद्-स्तरीय और व्यापक विकास सहायता कार्यक्रम को निर्देशित किया है। विदेश मंत्रालय में विकास साझेदारी प्रशासन भारत की विकास सहायता का प्रबंधन करता है जो सहचर विकासशील देशों की प्राथमिकताओं और जरूरतों का अनुकूलन करता है। ऐसी सहायता भारत के अपने संचित अनुभवों और कई क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साझाकरण और स्थायी दीर्घकालिक क्षमताओं और परिसंपत्तियों के निर्माण में सहयोग करती है, जो अपने सहचर देशों के चुने हुए विकास प्रक्षेपवक्र में योगदान करती हैं।

विकास सहायता मुख्य रूप से भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटीईसी) के तहत ऋण सीमा (एलओसी), अनुदान सहायता, लघु विकास परियोजनाओं, तकनीकी परामर्श, मानवीय सहायता और आपदा राहत के साथ ही क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के रूप में प्रदान की जाती है।

निकटस्थ पड़ोस और दक्षिण-पूर्व एशिया भारत की विकास सहायता का पारंपरिक और मजबूत केंद्र रहा है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ विकास सहयोग भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' और 'एक्ट ईस्ट' नीति की पुष्टि करता है। इससे इन देशों के साथ घनिष्ठ और बहुआयामी संबंधों के बढ़ते आयाम का निर्माण होता है। भारत का अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, मॉरीशस, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका सहित पड़ोस में अपने सभी साझेदारों के साथ सक्रिय और व्यापक विकास सहयोग है। ऐसे सहयोग में सड़क और पुल, जलमार्ग और ट्रांसमिशन लाइन, निर्माण, बिजली उत्पादन, कृषि, क्षमता निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक विकास सहित अवसंरचना विकास शामिल है।

विकास सहयोग भारत की विदेश नीति का एक अभिन्न अंग है। हाल के वर्षों में, विभिन्न देशों में भारत के विकास कार्यक्रमों की भौगोलिक पहुंच और क्षेत्रीय कवरेज दोनों में, काफी विस्तार हुआ है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ अनुदान सहायता, ऋण सीमा, तकनीकी परामर्श, आपदा राहत, मानवीय सहायता, शैक्षिक छात्रवृत्ति और अल्पकालिक नागरिक और सैन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सहित कई क्षमता निर्माण कार्यक्रम शामिल हैं।

विकास साझेदारी प्रशासन (डीपीए) की स्थापना जनवरी 2012 में संकल्पना, प्रक्षेपण, कार्यान्वयन और कमीशनिंग के चरणों के माध्यम से भारत की विकास परियोजनाओं के कुशल निष्पादन और निगरानी के लिए विदेश मंत्रालय में की गई थी।

मेजबान सरकारों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्रों के रूप में चिन्हित प्रमुख विकास परियोजनाएं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव में अवसंरचना, पनबिजली, बिजली पारेषण, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन के अधीन हैं। इसके अलावा, भारत के पड़ोसियों के साथ सीमा पार कनेक्टिविटी के विकास और सुदृढ़ता के लिए आरंभ की गई विभिन्न परियोजनाएं संतोषजनक रूप से प्रगति कर रही हैं। पड़ोस के पार, ऊर्जा, बिजली संयंत्र, बिजली पारेषण और वितरण, सड़क, रेलवे, बंदरगाह, कृषि और सिंचाई, औद्योगिक इकाइयों, पुरातत्व संरक्षण, सूचना और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और लघु और मध्यम उद्यमों जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय परियोजनाएं दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में चलाई गई हैं।

पिछले कुछ वर्षों में भारत की विकास सहायता का एक प्रमुख पहलू अन्य विकासशील देशों के लिए रियायती शर्तों पर ऋण श्रृंखला का विस्तार है। इन वर्षों में, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न देशों को 26.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर के 269 ऋण आवंटित किए गए हैं, जिसमें 11.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर अफ्रीकी देशों और 15.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर एशिया, लैटिन अमेरिका और ओशिनिया के देशों के लिए आवंटित किया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, लगभग 1.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एलओसी विभिन्न देशों को प्रदान किए गए। अप्रैल से नवंबर 2018 के बीच, कुल 1.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर के 11 नए एलओसी का अनुमोदन किया गया है। 2018-19 में (अप्रैल से नवंबर 2018 तक) कुल 101.13 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नौ परियोजनाएं पूरी की गई हैं।

2018-19 के दौरान, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत 161 भागीदार देशों को 11051 नागरिक प्रशिक्षण स्लॉट पेश किए गए। इन क्षमता निर्माण पाठ्यक्रमों में विभिन्न देशों में विशेष रूप से भागीदार देशों के विशिष्ट अनुरोधों पर आधारित डिज़ाइन किए गए पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल थे। आईटीईसी कार्यक्रम ने साझेदार देशों द्वारा चयनित और अनुरोध किए गए क्षेत्रों

में भारत के विशेषज्ञता और विकास के अनुभव को साझा करने के लिए विदेशों में भारतीय विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति को शामिल किया। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए और दुनिया भर में बदलती जरूरतों और तकनीकी प्रगतियों के अनुरूप, आईटीईसी पेशकशों के गुलदस्ते में ई-आईटीईसी और आईटीईसी-ऑनसाइट जैसे नए तौर-तरीके शामिल किए गए हैं।

आपदा से प्रभावित देशों को भारत द्वारा मानवीय मोर्चे पर सहयोग बढ़ाया गया था। अन्य बातों के साथ-साथ, मोजाम्बिक, सीरिया, यमन, सोमालिया, युगांडा, तंजानिया, मेडागास्कर, स्वाज़ीलैंड और केन्या को दवाएं उपलब्ध कराई गईं। बांग्लादेश और सीरिया को खाद्य सामग्री और अन्य राहत सामग्री की आपूर्ति की गई थी।

आर्थिक कूटनीति

आर्थिक कूटनीति प्रभाग देश की विदेश नीति के आर्थिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। इसने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कई पहलें कीं। भारत के निर्यात की पहुंच का विस्तार करने, विदेशों में भारतीय उद्यमों के लिए नए व्यापार के अवसर खोलने, निकट पड़ोस में और उससे परे आर्थिक वृद्धि करने, अधिक निवेश आकर्षित करने, पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने और भारत को एक आकर्षक व्यवसाय गंतव्य बनाने के उद्देश्य से विदेश मंत्रालय, केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, व्यापार मंडलों और विदेश स्थित मिशनों/नियुक्तियों के बीच अधिक समन्वय सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए।

भारतीय मिशनों/केंद्रों को उनके प्रत्यायन के देशों के साथ आर्थिक जुड़ाव को तेज करने में सक्षम बनाने के लिए, ईडी और राज्य प्रभागों ने अपने ''बाजार विस्तार कार्यकलाप'' बजट के अंतर्गत वित्तपोषण को बढ़ाकर 16 करोड़ रुपये कर दिया है। वित्तपोषण का उपयोग कैटलॉग शो और क्रेता-विक्रेता की बैठकों के माध्यम से भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करने, बाजार अध्ययनों को तैयार करने के लिए सलाहकारों को लगाने, विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के लिए व्यापार सेमिनार आयोजित करने और विदेशों में व्यापार के अवसरों की तलाश करने वाले भारतीय उद्यमों के हितों को बढ़ावा देने की वकालत करने के लिए किया गया है। इसके अलावा, ईडी प्रभाग ने भी भारत में शीर्ष व्यापार मंडलों द्वारा भारत में विशिष्ट व्यापार और निवेश प्रोत्साहन कार्यकलापों का समर्थन करने के लिए 6 करोड़ रुपये तक के प्रस्तावों को संसाधित किया है।

राज्य

राज्य प्रभाग का सृजन सहकारी संघवाद और विकास के लिए कूटनीति के सिद्धांतों को प्रचालनरत बनाने के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की बाहरी पहुंच को सुविधाजनक बनाना और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, विदेश मंत्रालय और भारतीय मिशनों और केंद्रों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना है। यह प्रभाग द्विपक्षीय संबंधों में प्रांतीय और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। 2017 में, प्रभाग ने विभिन्न सिस्टर सिटी/सिस्टर स्टेट्स अनुबंधों और राज्यों और विदेशी संस्थानों के बीच अन्य समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने की सुविधा प्रदान की। प्रभाग ने विभिन्न प्रांतीय और क्षेत्रीय निवेशकों की बैठकों और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। प्रभाग ने भारतीय राज्यों में संकटग्रस्त विदेशियों को सहायता प्रदान की है। प्रभाग भारतीय राज्यों और भारत में स्थित विदेशी दूतावासों और राजनयिकों के बीच संवाद की सुविधा भी प्रदान करता है।

आतंकवाद का मुकाबला

वर्ष के दौरान दुनिया के विभिन्न हिस्सों में घटने वाली आतंकवाद की विभिन्न घटनाओं के मद्देनजर सभी स्तरों पर विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों में आतंकवाद के मुद्दे का प्रमुखता से उल्लेख हुआ। ऐसी सभी वार्ताओं के दौरान, भारत ने वैश्विक स्तर पर खतरे से निपटने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और इसके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की कड़ी निंदा की। भारत ने विभिन्न साझेदार देशों के साथ आतंकवाद-रोधी संयुक्त कार्य समूहों के माध्यम से संरचित परामर्श जारी रखा। वर्ष 2018 के दौरान, भारत ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मिस्र, फ्रांस, इंडोनेशिया, रूस, ट्यूनीशिया, ब्रिटेन, अमेरिका, उज्बेकिस्तान और यूरोपीय संघ, ब्रिक्स और बिम्सटेक के साथ आतंकवाद-रोधक वार्ता की।

वैश्विक साइबर मुद्दे

विदेश मंत्रालय के अधीन, साइबर कूटनीति प्रभाग, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों स्तरों पर अंतर्राष्ट्रीय साइबर मुद्दों को देखता है। बहु-हितधारक दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए

ऐसे कार्यों का मुख्य उद्देश्य भारत के साइबर हितों की रक्षा करना है। संयुक्त राष्ट्र के एक प्रमुख सदस्य के तौर पर, भारत ने विचार-विमर्श में भाग लिया जिसके परिणामस्वरूप महासभा की संयुक्त राष्ट्र की पहली समिति में दो प्रस्तावों- पहला छठे यूएनजीजीई (सरकारी विशेषज्ञों के संयुक्त राष्ट्र समूह) की स्थापना, और दूसरा सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में विकास पर एक नए ओपन-एंडेड समूह की स्थापना को स्वीकार किया गया। इन समूहों से आम समझ, सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में मौजूदा और संभावित खतरों और उनका समाधान करने के संभावित सहकारी उपायों को बढ़ावा देने और राज्यों द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर अंतर्राष्ट्रीय कानून कैसे लागू होता है के साथ ही राज्यों के जिम्मेदार व्यवहार, विश्वास-निर्माण उपायों और क्षमता-निर्माण के मानदंडों, नियमों और सिद्धांतों के दृष्टिकोण से इन मुद्दों का अध्ययन जारी रखने की अपेक्षा की जाती है। भारत की बहु-हितधारक टीम के तौर पर, विदेश मंत्रालय ने अक्टूबर 2018 में बार्सिलोना में आयोजित आईसीएएनएन 63 बैठक में भाग लिया। भारत ने 2018 में ब्राजील और ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय साइबर संवाद और स्वीडन के साथ साइबर सुरक्षा पर संयुक्त कार्य बल आयोजित किया। विदेश मंत्रालय ने एनएससीएस के नेतृत्व में रूस के साथ साइबर सुरक्षा पर चर्चा में भी भाग लिया। भारत और अमेरिका ने साइबर सुरक्षा मुद्दों में सहयोग के लिए अपने समझौते का नवीनीकरण किया। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किंगडम ऑफ मोरक्को और सेशेल्स के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

सीमा प्रकोष्ठ

सीमा प्रकोष्ठ मंत्रालय को आंतरिक कार्टोग्राफिक विशेषज्ञता, सलाह और तकनीकी इनपुट्स प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। यह भूमि और समुद्री सीमाओं के बारे में स्पष्टीकरण सहित क्षेत्रीय प्रभागों की सहायता करता है। यह प्रकोष्ठ विदेशी पत्रिकाओं और एटलसों में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के चित्रण पर नजर रखता है। सीमा प्रकोष्ठ ने भारत की समुद्री सीमाओं सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित विभिन्न अंतर-मंत्रालयी बैठकों में भाग लिया। सीमा प्रकोष्ठ ने वर्गीकृत और संवेदनशील जानकारी से संबंधित रिकॉर्ड तक पहुंच के लिए अनुसंधान विद्वानों के अनुरोधों का निपटान किया।

नीति नियोजन और अनुसंधान

नीति नियोजन और अनुसंधान प्रभाग ने हमारी प्रमुख विदेश नीति के उद्देश्यों का निरंतर विश्लेषण और मंत्रालय को विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर अनुसंधान आधारित दृष्टिकोण प्रदान करने का अपना अधिदेश जारी रखा। यह आंतरिक और विभिन्न भारतीय विचार मंचों और अनुसंधान संगठनों तक सक्रिय पहुंच दोनों माध्यमों से किया गया।

प्रभाग ने भारत में मंचों को विकसित करने के उद्देश्य से प्रमुख विचार मंचों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी में सम्मेलन आयोजित किए, जिनमें दुनिया भर के प्रमुख सामरिक विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के बीच समकालीन विदेश नीति के मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है।

प्रभाग ने दीर्घकालिक सामरिक नियोजन और प्राथमिकताओं पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए हमारे महत्वपूर्ण राजनयिक भागीदारों के साथ नीति नियोजन पर संस्थागत संवाद विकसित किए। भारत और विदेश में महत्वपूर्ण राजनयिक सम्मेलनों में भारत की भागीदारी भी आयोजित की गई, ताकि भारत के परिप्रेक्ष्य और साथ ही ऐसे सम्मेलनों में विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के बीच आदान-प्रदान से लाभ मिल सके।

प्रोटोकॉल

प्रोटोकॉल प्रभाग में कुल सात अनुभाग अर्थात् प्रोटोकॉल-1, प्रोटोकॉल-II, प्रोटोकॉल-III, प्रोटोकॉल (हैदराबाद हाउस), प्रोटोकॉल विशेष, प्रोटोकॉल (आतिथ्य और सहायक उपकरण, लेखा) और सरकारी आतिथ्य संगठन (जीएचओ) शामिल हैं।

2018 में (03 दिसंबर 2018 तक), प्रोटोकॉल-I अनुभाग ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सरकार के प्रमुख और विदेश मंत्री स्तर पर 151 आवक/जावक यात्राओं का प्रबंधन किया।

कॉन्सुलर, पासपोर्ट और वीज़ा सेवाएं

हाल के वर्षों में पासपोर्ट जारी करना विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सबसे उल्लेखनीय सांविधिक और नागरिक सेवा के रूप में उभरा है। मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवाओं की अदायगी में कई मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार किए

हैं। भारतीय पासपोर्ट [अन्य यात्रा दस्तावेजों जैसे पहचान प्रमाणपत्र (आईसी), भारत लौटने वालों के लिए आपात प्रमाणपत्र (ईसी), पुलिस क्लीयरेंस प्रमाणपत्र (पीसीसी) और जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा यात्रा परमिट सहित] विदेश मंत्रालय द्वारा केंद्रीय पासपोर्ट संगठन और 36 पासपोर्ट कार्यालयों, सीपीवी प्रभाग (केवल राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट) और अंडमान और निकोबार द्वीप प्रशासन के अपने अखिल भारतीय नेटवर्क के माध्यम से जारी किए जाते हैं। पासपोर्ट कार्यालयों की विस्तारित शाखाओं के रूप में, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) माध्यम में 93 पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीएसके) और 263 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीओपीएसके) को जोड़कर इस नेटवर्क का विस्तार किया गया है। विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए, कांसुलर दस्तावेजों के सत्यापन के अलावा पासपोर्ट, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड, ईसी और अन्य विविध कांसुलर सेवाएं विदेशों में 184 भारतीय मिशनों/पोस्टों द्वारा प्रस्तुत की जा रही हैं।

2018 के दौरान, मंत्रालय ने भारत में 2017 के दौरान 1.17 करोड़ की तुलना में 4% की वृद्धि दर्शाते हुए 1.21 करोड़ पासपोर्ट और पासपोर्ट संबंधी आवेदनों पर कार्रवाई की। 36 पासपोर्ट कार्यालयों, मुख्यालय और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव कार्यालय को पुलिस क्लीयरेंस प्रमाणपत्रों सहित 1,21,74,758 पासपोर्ट और पासपोर्ट से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर 1,12,54,704 पासपोर्ट (449 राजनयिक पासपोर्टों, 18,009 आधिकारिक पासपोर्टों सहित) जारी किए गए। साथ ही, 5,112 अभ्यर्पण प्रमाणपत्र (एससी), 3,315 पहचान प्रमाणपत्र आईसी) और 1,946 नियंत्रण रेखा (एलओसी) परमिट जारी किए गए। विदेशों में 184 भारतीय मिशनों/पोस्टों ने लगभग 11,63,026 पासपोर्ट जारी किए। इस प्रकार, भारत सरकार ने वर्ष 2018 में कुल 1,24,17,733 पासपोर्ट जारी किए। दिसंबर 2018 तक 7.96 करोड़ से अधिक नागरिकों के पास वैध पासपोर्ट थे। भारत आज वैश्विक पासपोर्ट जारी करने के मामले में चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है।

विदेश मंत्रालय ने, डाक विभाग के सहयोग से, देश के प्रमुख डाकघरों (एचपीओ)/डाकघरों में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने की एक अभिनव पहल की है, जिसे 'डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र' (पीओपीएसके) के नाम से जाना जाता है। मंत्रालय ने 407 पीओपीएसके खोलने की घोषणा की है। इनमें से 263 पीओपीएसके 2 जनवरी, 2019 को चालू हो गए हैं। 2018 के दौरान इन पीओपीएसके में लगभग 14 लाख पासपोर्ट आवेदनों पर कार्रवाई की गई है। 263 पीओपीएसके को मिलाकर, 2 जनवरी, 2019 तक पासपोर्ट केंद्रों की कुल संख्या 356 हो गई है।

पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवेदन, भुगतान और शेड्यूल अपॉइंटमेंट सहित एम पासपोर्ट सेवा मोबाइल ऐप, 26 जून, 2018 को आरंभ किया गया। यह ऐप एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। वर्ष 2018 में, एम पासपोर्ट सेवा मोबाइल ऐप का उपयोग करते हुए 2.23 लाख आवेदन जमा किए गए। पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवेदन करने वाले नागरिकों को कंप्यूटर और प्रिंटर तक पहुंचना आवश्यक नहीं रहेगा। 26 जून, 2018 से, आवेदक भारत में कहीं से भी पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है। योजना के तहत वर्ष 2018 के दौरान एक लाख आवेदन जमा किए गए। नागरिक-हितैषी यह पहल आवेदकों को पासपोर्ट कार्यालय (पीओ) और इस प्रकार पासपोर्ट कार्यालय के अधीन इच्छित पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके)/ डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) का चयन करने में सक्षम बनाएगी, जहां वे अपना आवेदन जमा करना चाहते हैं, चाहे आवेदन पत्र में निर्दिष्ट वर्तमान आवासीय पता चयनित आरपीओ के क्षेत्राधिकार क्षेत्र में हो या नहीं। पुलिस सत्यापन (पीवी) उस पुलिस थाने द्वारा कराया जाएगा, जिसके क्षेत्राधिकार में उल्लिखित पता आता है और पासपोर्ट भी उसी पते पर भेजा जाएगा।

पासपोर्ट का पूर्व-मुद्रित भाग पहले ही हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में है। इस समय, आवेदक का निजी विवरण केवल अंग्रेजी भाषा में मुद्रित किया जाता है। अब सरकार ने पासपोर्ट पर निजी विवरण हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मुद्रित करने का निर्णय लिया है।

विदेश में भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को पासपोर्ट सेवा परियोजना में एकीकृत करने की प्रक्रिया अक्टूबर 2018 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य विदेश में रहने वाले और पासपोर्ट संबंधित सेवाएं चाहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक केंद्रीकृत पासपोर्ट निर्गम और आवेदन मंच उपलब्ध कराना है। प्रयोगिक परियोजना के अंतर्गत, लंदन में भारत के उच्चायोग ने 24 अक्टूबर, 2018 को क्रमशः बर्मिंघम और एडिनबर्ग में भारतीय महावाणिज्य दूतावास से पासपोर्ट सेवा परियोजना की शुरुआत की। वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास, न्यूयॉर्क, सेन फ्रांसिस्को, शिकागो, ह्यूस्टन और अटलांटा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने नवंबर 2018 में इस परियोजना का शुभारंभ किया।

मंत्रालय का लक्ष्य सभी भारतीय दूतावासों और विदेश में वाणिज्य दूतावासों के एकीकरण को जल्द से जल्द पूरा करना है। 'न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन 'को साकार करने में कार्यात्मक वृद्धि और प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए, मंत्रालय ने निम्नलिखित उपायों की शुरूआत की:

i. सरोगेट बच्चों को पासपोर्ट जारी करने संबंधी नीति की समीक्षा की गई और पंजीकृत सरोगेसी समझौते की जरूरत को हटाया गया।

ii. तत्काल योजना के तहत बिना बारी आधार पर पासपोर्ट जारी करना सरल बना दिया गया है और इस योजना के तहत पासपोर्ट जारी करने के लिए अब सत्यापन प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं है।

iii. पुलिस सत्यापन प्रक्रिया को नया रूप दिया गया है और उन्हें अब सिर्फ पासपोर्ट आवेदक की आपराधिकता और राष्ट्रीयता की जांच करना अपेक्षित है, जिससे प्रक्रिया सरल हो गई है।

iv. आपात प्रमाणपत्र की वैधता 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दी गई है।

प्रवासी भारतीय मामले

प्रवासी भारतीय मामले प्रभाग सीमारहित संसार में गठबंधन के माध्यम से विकास की दृष्टि से प्रेरित हैं। वे भारतीय प्रवासी समुदाय को भारत से जोड़ना और उस संस्थागत ढांचे को भी मजबूत करना चाहते हैं जिसमें प्रवासी भारतीयों की सहायता और कल्याण संभव हो सके। यह भारतीय प्रवासियों से संबंधित सभी मामलों में सूचना, साझेदारी और सुविधा प्रदान करता है। यह प्रभाग प्रवासी भारतीयों के लिए व्यापार और निवेश, उत्प्रवास, शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य और विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने वाली कई पहलों में भी संलग्न रहा।

प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ाव को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता के रूप में, 2018-2019 के दौरान की गई प्रमुख पहलों में विदेश संपर्क आउटरीच कार्यक्रम, भारत को जानें कार्यक्रम, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम और सुरक्षित और कानूनी प्रवासन पर जागरूकता अभियान शामिल थे।

प्रशासन और स्थापना

प्रशासन प्रभाग का निरंतर प्रयास रहा है कि मुख्यालय और विदेश में 187 भारतीय मिशनों/केंद्रों में मंत्रालय की मानव पूंजी का प्रबंधन करके जनशक्ति का अनुकूल उपयोग किया जाए। इसके लिए, प्रभाग संवर्ग प्रबंधन की देखरेख करता है जिसमें भर्ती, प्रशिक्षण, तैनाती/स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति और कैरियर प्रगति जैसे अन्य पहलू शामिल हैं। इसके अलावा, प्रभाग कार्मिकों तथा भारतीय मिशनों और केन्द्रों में स्थानीय कर्मियों से संबंधित भारत सरकार के सभी संगत नियमों और विनियमों के निर्माण, संशोधन और सुधारों के माध्यम से भी अपने कार्मिक नीतियों की जांच करता है।

मार्च 2018 में अफ्रीका में 2018-21 के दौरान 18 नए मिशनों के उदघाटन को कैबिनेट की मंजूरी के अनुसरण में पहले चरण में खोले जाने वाले छह मिशनों को चिन्हित किया गया है। इनमें से रवांडा में मिशन पहले ही खोला जा चुका है और शीघ्र ही जिबूती और इक्वेटोरियल गिनी में मिशन खोले जाएंगे। कांगो गणराज्य, बुर्किना फ़ासो और गिनी में मिशनों के संबंध में प्रारंभिक प्रशासनिक और स्थापना संबंधी कार्य पहले से ही चल रहे हैं।

स्थापना प्रभाग मंत्रालय के सभी कार्यालय भवनों और आवासीय परिसरों; कार्यालय उपस्करों, फर्नीचर और स्टेशनरी की खरीद और आपूर्ति; और विदेशों में मिशनों और पोस्टों के लिए विशेष खरीद वस्तुओं और सरकारी वाहनों की खरीद और आपूर्ति से संबंधित मामलों की देखरेख एवं रखरखाव करता है। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 के दौरान स्वच्छ भारत से जुड़े विभिन्न कार्यकलापों में सक्रिय रूप से भाग लिया है।

सूचना का अधिकार और मुख्य लोक सूचना अधिकारी

वर्ष के दौरान, मंत्रालय ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के पूर्ण कार्यान्वयन का प्रयास जारी रखा। स्व-प्रेरित प्रकटीकरण पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOP&T) के निर्देशों के अनुसार, आरटीआई आवेदन/अपीलें/जबाव और मासिक आरटीआई आंकड़े आम जनता के लिए अपलोड किए गए हैं। आरटीआई आवेदनों की ऑनलाइन स्वीकृति और निपटान की प्रणाली को आरटीआई वेब पोर्टल के साथ

संरेखित करके इसे विदेशों में 184 मिशनों/पोस्टों में लागू किया गया है। 1 अप्रैल 2018 से 30 नवंबर 2018 की अवधि के दौरान आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगने वाले कुल 1946 आरटीआई आवेदन और 160 प्रथम अपीलें मंत्रालय में प्राप्त हुई हैं और इनका संतोषजनक ढंग से निस्तारण किया गया है।

ई-गवर्नेंस और सूचना प्रौद्योगिकी

ईजीएंडआईटी प्रभाग विदेश मंत्रालय और विदेश स्थित सभी मिशनों/केंद्रों में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विभिन्न घटकों को लागू करने के लिए कदम उठा रहा है। ई-क्रांति की चार मिशन मोड परियोजनाएं (डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का चौथा स्तंभ) अर्थात् ई-ऑफिस, ई-प्रोक्योरमेंट, इमिग्रेशन, वीजा, विदेशियों का पंजीकरण और ट्रैकिंग प्रणाली (आईवीएफआरटी) और पासपोर्ट सेवा परियोजनाएं (पीएसपी) वर्तमान में विदेश मंत्रालय में और मिशनों/केंद्रों में चालू हैं। विदेश मंत्रालय में डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसार कई ई-गवर्नेंस और ऑटोमेशन परियोजनाएं भी चलाई गई हैं जैसे विदेश सेवा संस्थान एलुमनी पोर्टल, ई-ऑडिट पोर्टल, पुनर्गठित भारत जानें कार्यक्रम और प्रवासी भारतीय दिवस पोर्टल, राजनयिक पहचान पत्र पंजीकरण और निर्गम प्रणाली इत्यादि। ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के संचालन के अलावा, प्रभाग ने साइबर सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों के प्रबंधन और शमन के लिए निरंतर केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है।

संसद और समन्वय

संसद प्रभाग संसद के साथ मंत्रालय का इंटरफेस और इस मंत्रालय के संसद संबंधी सभी कार्यों के लिए नोडल बिंदु है। प्रभाग ने विदेश मामलों से संबंधित परामर्शदात्री समिति की बैठकें आयोजित कीं और विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति और अन्य संसदीय समितियों के साथ मंत्रालय की बातचीत से संबंधित कार्यों का समन्वय किया।

समन्वय प्रभाग ने मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और गैर-सरकारी संगठनों सहित स्वायत्त निकायों और निजी संस्थानों के बीच बातचीत का समन्वय किया। प्रभाग ने मंत्रियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, न्यायपालिका और सरकारी अधिकारियों की निजी/आधिकारिक विदेश यात्राओं को राजनीतिक मंजूरी दी। इसने भारत में विदेशी प्रतिभागिता वाले सम्मेलनों/सेमिनारों/कार्यशालाओं के आयोजन, भारत में विदेशी प्रतिभागियों को आमंत्रित करने वाले खेल टूर्नामेंटों, विदेशी सैन्य उड़ानों की अवतरण/आगे की उड़ान क्लीयरेंस, विदेशी नौसैनिक जहाजों के दौरों आदि, भारत में पढ़ रहे विदेशी छात्रों और विभिन्न संस्थानों में फील्ड विजिट/प्रशिक्षण/निरीक्षण आदि के लिए भारत आने वाले विदेशी छात्रों के संबंध में छात्र वीजा के अनुसंधान वीजा में रूपांतरण को भी स्वीकृति दी गई। अप्रैल 2018 से दिसंबर 2018 की अवधि के दौरान कुल 4,186 मंजूरियां जारी की गई।

मंत्रालय के शिक्षा अनुभाग ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस मंत्रालय को आवंटित सीटों पर स्व-वित्तपोषण योजना के तहत भारत में विभिन्न संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी/एमएस, बी.आर्क, बीई, बी.फार्मेसी और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए 57 मित्र पड़ोसी और विकासशील देशों से विदेशी छात्रों के चयन, नामांकन और प्रवेश के मामलों को हल किया। भारत में बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए उत्पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यक प्रवासियों को भी इस योजना के तहत सीटें प्रदान की जाती हैं।

विदेशी प्रचार

तेजी से विकसित होते संचार परिवेश में, एक्सपीडी प्रभाग ने बाहरी दुनिया के लिए हमारी विदेश नीति की प्राथमिकताओं की बेहतर समझ को बढ़ावा देने का प्रयास निरंतर जारी रखा। इसे मीडिया के साथ अपने व्यापक जुड़ाव के माध्यम से और भारत और विदेश दोनों में लोक राजनय को बढ़ाते हुए हासिल किया गया है। यह मंत्र 'लोक-केंद्रित' है, जो मौजूदा और नई पहल की श्रृंखला के साथ विदेश नीति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए है। हमारे वांछित उद्देश्यों को अधिकतम करने के लिए डिजिटल मीडिया और आधुनिक उपस्करों का लाभ उठाया गया है।

प्रभाग ने इस दौरान तीन विशेष पहलों का बीड़ा उठाया। छात्र और विदेश मंत्रालय जुड़ाव कार्यक्रम (SAMEEP) के तहत, भारतीय विदेश सेवा अधिकारी अपने स्कूलों या विश्वविद्यालयों में वापस जाते हैं और विदेश मंत्रालय की भूमिका और भारतीय विदेश नीति पर प्रस्तुति देते हैं। इसके अतिरिक्त, एक्सपीडी प्रभाग ने, 'विदेश आया प्रदेश के द्वार' (आपके द्वार पर विदेश नीति) भी शुरू की,

जिसके तहत क्षेत्रीय मीडिया को आकर्षक बनाने के लिए राज्य की राजधानियों में विशेष संपर्क सत्र आयोजित किए गए। विदेश में उत्सुक युवाओं के लिए, प्रभाग ने विदेशों में पुस्तकालयों में एक अलग भारत कॉर्नर बनाने के लिए 'भारत एक परिचय' का शुभारंभ किया, जिसमें भारत के बारे में सतर्कतापूर्वक चयनित 51 शीर्षक पुस्तकें रखी जायेंगी।

एक्सपीडी प्रभाग ने भारत और विदेशों में महात्मा गांधी के 150वीं जयंती समारोह में नोडल भूमिका निभाई। उल्लेखनीय बात विश्व भर में 140 देशों के गायकों द्वारा प्रस्तुत महात्मा के पसंदीदा भजन, वैष्णव जन तो की वीडियो मेडली का शुभारंभ था। मेडली का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2018 को स्वच्छ भारत सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। एक विशिष्ट और महत्वाकांक्षी पहल के तौर पर, 2 अक्टूबर को विश्व के देशों की राजधानियों में महात्मा गांधी पर एलईडी प्रक्षेपण प्रदर्शित किया गया।

मंत्रालय और सरकार की विदेश नीति को क्रियोन्मुख और प्रभावी छवि बनाने में इन प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसके मूर्त परिणाम प्राप्त हुए हैं और विश्व में भारत का कद बढ़ा है।

विदेश सेवा संस्थान

जुलाई 2013 में अंगीकृत विदेश मंत्रालय के नए प्रशिक्षण ढांचे के अनुसार सामग्री के साथ ही कार्यप्रणाली के संदर्भ में वर्ष 2018-19 के दौरान, विदेश सेवा संस्थान (एफएसआई) में प्रशिक्षण कार्यक्रमों आगे की समीक्षा की गई और इसे संशोधित और वर्गीकृत किया गया है। प्रशिक्षण का लक्ष्य कर्तव्यों और कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए दक्षताओं और कौशलों को विकसित करते हुए कार्यात्मक अपेक्षाओं के लिए प्रत्यक्षतः प्रासंगिक बनाने पर जोर देने पर केंद्रित है। इस अधिदेश के साथ, विभिन्न स्तरों पर अनिवार्य मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रमों (MCTPs) पर भी अधिक जोर दिया गया है। प्रशिक्षण में नए घटकों को प्रस्तुत करके आईएफएस के समूह ख के प्रशिक्षण को भी नया रूप देते हुए इसे गहन बनाया गया।

2018 में, एफएसआई की स्थापना के बाद से विदेशी राजनयिकों के लिए सर्वाधिक संख्या में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें अफगान, सोमाली, बांग्लादेश, गैम्बियन, नाइजीरियाई, ट्यूनीशियाई, म्यांमार और ईरानी राजनयिकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम शामिल थे। लैटिन अमेरिकी देशों के रेजीडेंट हेड्स ऑफ मिशन (HOMs) के लिए प्रथम परिचय कार्यक्रम और एशिया-यूरोप बैठक (ASEM) के राजनयिकों और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (ASEAN) के राजनयिकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम शुरू किए गए।

नालंदा प्रभाग

2018-19 में नालंदा विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय पदचिन्हों में वृद्धि जारी रही। इस समय, इसमें लगभग 378 छात्र हैं जिनमें चालीस अंतर्राष्ट्रीय छात्र शामिल हैं। वर्ष 2018 में नए स्कूल खोलने के लिए विश्वविद्यालय के प्रबंधन के समेकन को भी चिन्हित किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर के निर्माण का पहला चरण जारी है। सरकार बौद्धिक, दार्शनिक, और ऐतिहासिक अध्ययन और इसके साथ जुड़े मामलों के संबंध में एक उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन और विदेश में हिंदी का प्रचार

मंत्रालय का अपने मिशनों/केंद्रों की भागीदारी सहित विदेशों में हिंदी के प्रचार-प्रसार का सुव्यवस्थित कार्यक्रम है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरीशस में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया जिसमें विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। दुनिया भर में हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, एक द्विपक्षीय समझौते और भारत तथा मॉरीशस की सरकारों के संयुक्त बजटीय समर्थन के तहत मॉरीशस में एक विश्व हिंदी सचिवालय स्थापित किया गया।

विदेश मंत्रालय अपने मिशनों और केंद्रों, सांस्कृतिक संगठनों और संगठनों के सहयोग से, हिंदी पखवाड़ा, और विश्व हिंदी दिवस सहित, विदेशों में हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित करता है। हिंदी शिक्षण सामग्री, जिनमें हिंदी पाठ्य पुस्तकें और बच्चों की किताबें आदि शामिल हैं, की विदेशों में शिक्षण संस्थानों में निःशुल्क आपूर्ति की जाती है। विदेश मंत्रालय विदेश स्थित शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को उच्च प्राथमिकता देना जारी रखा। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज की अध्यक्षता में विदेश मंत्रालय में एक हिंदी सलाहकार समिति कार्यरत है। विदेश मंत्रालय

आधिकारिक भाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग का जायजा लेने के लिए नियमित रूप से अपने अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करता है।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद

वर्ष 2018-19 के दौरान, आईसीसीआर ने विदेश में भारत की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के कार्यकलाप किए। अपने शैक्षणिक और बौद्धिक कार्यकलापों के रूप में, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) ने अपनी विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत भारत में अध्ययन के लिए विदेशी नागरिकों को 3,940 छात्रवृत्ति स्लॉट प्रदान किए। एडमिशन टू एलुमनी (A2A) पोर्टल की शुरूआत करके, आईसीसीआर ने पहली बार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया संपन्न की।

आईसीसीआर ने नई पीठों की स्थापना के लिए दस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए और भारतीय अध्ययन की सत्तर मौजूदा पीठों का प्रबंधन किया। आईसीसीआर विश्व भर में सैंतीस संपूर्ण भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों (ICCs) और पीपीपी मॉडल के तहत दो केंद्रों का संचालन करता है। आईसीसीआर ने सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित इंडोलॉजिस्ट पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन; न्यूयॉर्क शहर में आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन; मानविकी और सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान, तेहरान के सहयोग से फारसी और संस्कृत भाषा (संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनी के विशेष संदर्भ सहित) के बीच भाषाई लिंक पर सेमिनार सहित चार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/सेमिनारों का आयोजन किया और "डेलीवरिंग डेमोक्रेसी" पर सेमिनार की श्रृंखला का आयोजन अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, यूएई और सिंगापुर में किया गया। आईसीसीआर ने 21 मई 2018 को विश्व संस्कृति दिवस के अवसर पर एक व्याख्यान श्रृंखला – पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मारक अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान – का शुभारंभ किया। पहला व्याख्यान विदेश मंत्री (ईएएम) श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा दिया गया।

आईसीसीआर ने इक्यानबे देशों के 778 कलाकारों वाले 128 कला समूहों की यात्रा को प्रायोजित किया, जिन्होंने विश्व भर में 396 प्रस्तुतियां दी। भारत मैक्सिको में सर्वान्टिनो समारोह में सम्मानित अतिथि देश था। आईसीसीआर ने उन्नीस देशों के इक्कीस प्रदर्शक कला समूहों द्वारा पूरे भारत में चौवन प्रस्तुतियां आयोजित की। मई 2018 में अफ्रीका उत्सव, अक्टूबर 2018 में अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव और अक्टूबर/नवंबर 2018 में भारत के रूसी संस्कृति के दिन प्रमुख आकर्षण थे।

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

विश्व मामलों की भारतीय परिषद (ICWA) ने एशिया, अफ्रीका, यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा विकास और व्यापक भू-सामरिक माहौल पर अपना शोध जारी रखा। उन मुद्दों के समाधान करने के प्रयास जारी रहे, जो विदेश नीति के एजेंडे में सबसे ऊपर थे और इसके शोध को अधिक नीति प्रभावी बनाते हैं। किए गए शोध को सप्रू हाउस पेपर्स, इश्यू ब्रीफ्स, पॉलिसी ब्रीफ्स एंड व्यूप्वाइंट्स, डिस्कशन पेपर्स, शोध लेख के रूप में प्रसारित किया गया था, जिसे आईसीडब्ल्यूए की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया।

अपने अधिदेश के अनुरूप, आईसीडब्ल्यूए ने बड़ी संख्या में कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें संवाद, सम्मेलन, सेमिनार, व्याख्यान, बातचीत, गोलमेज चर्चाएं और पहुंच कार्यकलाप शामिल हैं। इसके अलावा, आईसीडब्ल्यूए ने अपने अकादमिक आउटपुट का हिंदी में अनुवाद करने की प्रक्रिया जारी रखी, जिसे नियमित रूप से अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किया जाता रहा। अब आईसीडब्ल्यूए ने अपना पुस्तकालय आम जनता के लिए खोल दिया है और सदस्यता नियमों को आसान कर दिया गया है।

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस) ने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें अन्य के बीच, "भारत-आसियान समुद्री सहयोग को मजबूत करना" थीम पर दिल्ली संवाद का 10वां संस्करण शामिल है। आरआईएस ने आर्थिक कार्य विभाग (डीएई), वित्त मंत्रालय के साथ, एआईआईबी के लिए ज्ञान भागीदार के रूप में, भारत के प्रमुख उद्योग संघों–फिक्की, सीआईआई और एसोचैम के साथ निकट संपर्क से कार्य किया है। आरआईएस कई क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पहलों की अंतर सरकारी प्रक्रियाओं में संलग्न है। अपने विचार मंचों के गहन नेटवर्क के जरिए,

आरआईएस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों और विकास साझेदारी कैनवास पर नीतिगत सामंजस्य बढ़ाने का प्रयास करता है।

पुस्तकालय और अभिलेखागार

विदेश मंत्रालय पुस्तकालय एक पुस्तकालय के कर्तव्यों का निर्वहन और मुख्यालय तथा विदेश में भारतीय मिशनों और केंद्रों में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और कार्मिकों के उपयोग के लिए संसाधन और सूचना केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। पुस्तकालय वर्तमान में पटियाला हाउस और जवाहरलाल नेहरू भवन (जेएनबी) में कार्यरत है। पटियाला हाउस स्थित पुस्तकालय में 8 क्यूबिकल्स का वर्चुअल रीडिंग रूम उपयोक्ताओं/शोधकर्ताओं के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा से सुसज्जित है।

मंत्रालय का अभिलेखागार और अभिलेख प्रबंधन प्रभाग अभिलेखागार और अभिलेख प्रबंधन से संबंधित सभी मामलों का प्रबंधन करता है। ई-गवर्नेंस और सूचना प्रौद्योगिकी (ईजीएण्डआईटी) प्रभाग द्वारा अभिलेख प्रबंधन सॉफ्टवेयर (आरईएम) का उन्नयन, मौजूदा सॉफ्टवेयर का प्रतिस्थापन और दो नए सर्वरों से मौजूदा सर्वर के साथ ही अभिलेख प्रबंधन सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटा प्राप्त करने में उपयोग किए जा रहे पुराने डेस्कटॉप का प्रतिस्थापन किया जा रहा है। नए सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड की स्कैनिंग/डिजिटलीकरण करने के प्रावधान से, मौजूदा डेटा पुराने सॉफ़्टवेयर से नए सॉफ़्टवेयर में स्थानांतरित किया जा सकता है। नवंबर 2018 तक, इस प्रभाग ने विध्वंस स्वीकृति प्राप्त होने पर 2256 पुराने रिकॉर्डों/रजिस्टरों/पुस्तकों को नष्ट किया। सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम और नियम 1993/1997 के तहत उचित मूल्यांकन के बाद संरक्षण और स्थायी अभिरक्षा के लिए 25 वर्ष से अधिक पुराने 3752 गैर-मौजूदा सार्वजनिक अभिलेख/फाइलें भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थानांतरित की गईं।

वित्त और बजट

वित्तीय वर्ष (एफवाई) 2018-19 के लिए विदेश मंत्रालय को आवंटित कुल बजट, बजट अनुमान (बीई) चरण में 15011.00 करोड़ रुपये था। मंत्रालय के बजट में सर्वाधिक आवंटन विदेशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग (टीईसी) के लिए अनुदान और ऋण के रूप में था। वित्त वर्ष 2018-19 में, 15011 करोड़ रुपये के कुल बजट में, टीईसी परिव्यय 41.53% या 6235.05 करोड़ रुपये था, जिसमें 5398.55 करोड़ रुपये (35.96%) अनुदान कार्यक्रमों और 836.50 करोड़ रुपये (5.57%) ऋण के लिए था। मंत्रालय के बजट में दूसरा सर्वाधिक आवंटन विदेशों में 180 से अधिक भारतीय राजनयिक मिशनों और केंद्रों के रखरखाव के लिए था। वित्त वर्ष 2018-19 के 15,011 करोड़ रुपये के कुल बजट में से, स्थापना शीर्षों और गैर-स्थापना शीर्षों के बीच आवंटन का विभाजन क्रमशः 28% (4,223 करोड़ रुपये) और 72% (10,788 करोड़ रुपये) था। मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2018-19 में 31 दिसंबर 2018 तक पासपोर्ट सेवाओं (1,957.64 करोड़ रुपये), वीजा शुल्क (1,823.08 करोड़ रुपये) और अन्य प्राप्तियों (499.39 करोड़ रुपये) से 4,280.11 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया है।

1

भारत के पड़ोसी देश

अफ़ग़ानिस्तान

अफगानिस्तान एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है और भारत के साथ रणनीतिक संबंध साझा करता है। भारत और अफगानिस्तान द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव इसके समृद्ध इतिहास और सभ्यतागत संबंधों में है, जो कई सदियों पुराने हैं। हमारे संबंधों को हमारे दोनों देशों और इस समूचे क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की दृष्टि द्वारा आगे मार्गनिर्देशित किया जाता है। इस वर्ष अफगानिस्तान और भारत के सामूहिक प्रयासों को इस दर्शन द्वारा निर्देशित किया गया था। नतीजतन, इस वर्ष दोनों पक्षों के बीच कई उच्च स्तरीय यात्राएं हुई और कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए, जिसमें भारत से अनुदान सहायता के रूप में अफगानिस्तान को 170,000 टन गेहूं और 2,000 टन दालों की डिलीवरी, अफगानिस्तान के लिए सुनिश्चित आवागमन सुविधा के लिए चाबहार पोर्ट का त्वरित विकास और परिचालन, दोनों देशों के बीच एयर फ्रेट कॉरिडोर का विस्तार, 40% से अधिक की वृद्धि के साथ 1.143 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक का द्विपक्षीय व्यापार और 2017 में घोषित 'न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप' के अंतर्गत चिन्हित अफगानिस्तान में कई भारतीय-सहायता प्राप्त सामाजिक-आर्थिक विकास परियोजनाओं के लिए काम शुरू करना शामिल है।

दोनों ओर से उच्च स्तरीय यात्राएं

इस साल दोनों देशों के बीच कई उच्च स्तरीय यात्राएं हुई। इन यात्राओं के स्तर और आवृत्ति ने दोनों पक्षों के बीच सुविधा और आपसी विश्वास और समझ के स्तर को दर्शाया। इन यात्राओं में सितंबर 2018 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी की यात्रा; जून और सितंबर 2018 में अफगानिस्तान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अब्दुल्ला अब्दुल्ला की यात्रा; सितंबर 2018 में अफगानिस्तान के वित्त मंत्री श्री हुमायूँ कयूमि की यात्रा, अप्रैल 2018 में अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल तारिक शाह बेहरामी की यात्रा; सितंबर 2018 में अफगानिस्तान के स्वतंत्र प्रशासनिक सुधार और सिविल सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. नादर नादरी की यात्रा; और सितंबर 2018 में अफगानिस्तान के ग्रामीण पुनर्वास और विकास मंत्री श्री मुजीब रहमान करीमी की यात्रा शामिल थी।

भारत से अफगानिस्तान की उच्च स्तरीय यात्राओं में सितंबर 2018 में विदेश सचिव श्री विजय केशव गोखले की यात्रा, अक्टूबर 2018 में वाणिज्य सचिव डॉ. अनूप वधावन और अगस्त 2018 में सचिव (आर्थिक संबंध), श्री टीएस तिरुमूर्ति की काबुल यात्रा शामिल थी।

अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री हमदुल्ला मोहिब ने 3-5 जनवरी 2019 तक भारत का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान, एनएसए श्री अजीत डोभाल के साथ द्विपक्षीय चर्चा हुई।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 12-13 जनवरी, 2019 को समरकंद में हुई सी-5+भारत मंत्रिस्तरीय बैठक के अवसर पर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री श्री सलाहुद्दीन रब्बानी के साथ मुलाकात की।

आर्थिक और आवागमन सुविधा सहयोग

दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा में पिछले वित्त वर्ष में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिसमें 40% वृद्धि दर्ज की गई और यह 1 बिलियन अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार कर गया है। इस क्षेत्र में, उल्लेखनीय उपलब्धियों में दोनों देशों के बीच एयर-फ्रेट कॉरिडोर का विस्तार और ईरान में चाबहार बंदरगाह पर वाणिज्यिक संचालन शुरू करना शामिल है।

एयर फ्रेट कॉरिडोर जिसने जून 2017 में भारत और अफगानिस्तान के बीच संचालन शुरू किया था, अब इसका विस्तार भारत में नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता और अफ़ग़ानिस्तान में काबुल और कंधार तक कर दिया गया है। दोनों पक्षों ने अन्य शहरों के लिए इस ऑपरेशन का विस्तार करने का वादा किया है। अप्रैल और नवंबर 2018 के बीच, अफगानिस्तान और भारत के बीच लगभग बहत्तर उड़ानें संचालित हुईं, जिनमें 90 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की 1,227 टन एयर कार्गो लाया-ले जाया गया। एयर फ्रेट कॉरिडोर ने विशेष रूप से अफगान किसानों और छोटे व्यापारियों को बड़े भारतीय बाजार में अपना सामान निर्यात करने में लाभान्वित किया है। इसके अलावा, अधिकाधिक आवागमन सुविधा के माध्यम से भारत की आर्थिक सहायता से संबंधित, 170,000 टन गेहूं और 2,000 टन दालों के 5000 से अधिक कंटेनरों को चाबहार पोर्ट के रास्ते अफगानिस्तान में भारत के अनुदान के रूप में भेजा गया था।

भारत-अफगानिस्तान व्यापार और निवेश प्रदर्शन का दूसरा संस्करण सितंबर 2018 में दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में आयोजित किया गया था। ट्रेड शो का पहला संस्करण सितंबर 2017 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। दूसरा संस्करण ने सैकड़ों भारतीय और अफगान कंपनियों, व्यापारियों और उद्यमियों ने व्यापक रूप से भाग लिया, और अनुमानित रूप से 270 मिलियन अमरीकी डॉलर के 500 से अधिक व्यापार और निवेश सौदों को व्यापार कार्यक्रम में अंतिम रूप दिया गया। व्यापार, वाणिज्य और निवेश पर भारत, अफगानिस्तान संयुक्त व्यापार समूह की काबुल में नवंबर 2018 में बैठक हुई। इस क्षेत्र में हाल की उपलब्धियों पर संतोष व्यक्त करते हुए, दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया गया।

विकास भागीदारी

विकास सहयोग पर भारत-अफगानिस्तान संयुक्त कार्यकारी समूह की अगस्त 2018 में काबुल में बैठक हुई जिसमें हाल ही में पूरी हुई और भविष्य की विभिन्न परियोजनाओं की व्यापक समीक्षा की गई। सितंबर 2017 में अनावरण की गई 'नई विकास साझेदारी' के तहत कार्यान्वयन के लिए चिन्हित की गई नई परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। भारत और अफगानिस्तान के बीच नई विकास भागीदारी के तहत सबसे प्रमुख परियोजनाओं में काबुल सिंचाई की सुविधा और पीने के पानी की आपूर्ति की समस्या का समाधान करने के लिए शतूत बांध, वापस आ रहे शरणार्थियों के लिए नांगरहार प्रांत में कम लागत वाले आवास, बामियान प्रांत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बंद-ए-अमीर के लिए सड़क संपर्क, अफगानिस्तान के सभी चौंतीस प्रांतों में 116 उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाएं और कई अन्य परियोजनाएं शामिल हैं।

क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास

भारत अपने कई चल रहे छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अफगानिस्तान में क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास के प्रयासों में योगदान दे रहा है। हर साल भारत, भारत में 3,500 से अधिक छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण स्लॉट प्रदान करता है। इस संदर्भ में सबसे लोकप्रिय छात्रवृत्ति कार्यक्रम आईसीसीआर द्वारा संचालित अफगान नागरिकों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना है, जो भारत में अध्ययन करने के लिए सालाना 1,000 छात्रवृत्ति स्लॉट प्रदान करती है। अफगान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बलों (ANDSF) के शहीदों के परिजनों के लिए 500 छात्रवृत्तियों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम का कार्यान्वयन चालू शैक्षणिक वर्ष से शुरू हुआ। उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, इस समय

15,000 से अधिक अफगान छात्र भारत में अध्ययन कर रहे हैं। अफगान पदाधिकारियों और विशेषज्ञों को भी आईटीईसी और कई अन्य योजनाओं के तहत प्रशिक्षित किया गया है। अक्टूबर में, भारत ने अफगान राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए चीन के साथ एक संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

सामाजिक-सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों के बीच परस्पर संपर्क

भारत-अफगानिस्तान फाउंडेशन को दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संपर्क और सामाजिक-सांस्कृतिक, कला और शैक्षिक संपर्कों को बढ़ावा देने के लिए अधिदेशित किया गया है। इस वर्ष पाँच अफगान कवियों और लेखकों को भारत-अफगानिस्तान फाउंडेशन द्वारा अक्टूबर 2018 में नई दिल्ली में वार्षिक दक्षिण एशिया साहित्य महोत्सव में भाग लेने के लिए प्रायोजित किया गया था।

अफगानिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

भारत अफगानिस्तान में शांति और मेल-मिलाप को बढ़ावा देने की दिशा में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। भारत की सिद्धांतगत रुख कि इस तरह के प्रयास अफगान के नेतृत्व वाले, अफगान के स्वामित्व वाले और अफगान-नियंत्रित होने चाहिए, को व्यापक अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिला है और इसकी अफगानिस्तान में भी सराहना की गई है। 2018 में, भारत ने अफगानिस्तान के संबंध में कई महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया, जहां उसने अफगानिस्तान में आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा स्थिति में सुधार के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। इस साल अफगानिस्तान के संबंध में हुई कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में अन्य बैठकों के साथ-साथ दूसरी काबुल प्रक्रिया, ताशकंद सम्मेलन, मॉस्को फॉर्मेट वार्ता और जिनेवा सम्मेलन शामिल हैं। इनमें से कुछ बैठकों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

- **दूसरी काबुल प्रक्रिया:** काबुल प्रक्रिया की दूसरी बैठक 28 फरवरी 2018 को काबुल में हुई। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश सचिव श्री गोखले ने किया। भारत ने राष्ट्रपति अशरफ गनी द्वारा सशस्त्र समूहों को हथियार डालने और राष्ट्रीय मुख्यधारा का हिस्सा बनने के लिए किए गए शांति और मेल-मिलाप के आह्वान का स्वागत किया।

विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में अफगानिस्तान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री ले.जनरल तारीक शाह बहरामी से मुलाकात की (13 अप्रैल, 2018)

- **ताशकंद सम्मेलन:** ताशकंद सम्मेलन 27 मार्च 2018 को ताशकंद में आयोजित किया गया, जहां अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने राष्ट्रपति गनी की दूसरी काबुल प्रक्रिया की बैठक में किए गए शांति के आह्वान का समर्थन किया। भारत का प्रतिनिधित्व पूर्व विदेश राज्य मंत्री श्री एम.जे. अकबर ने किया था।
- **मास्को फॉर्मेट वार्ता:** भारत ने अफगानिस्तान में मास्को वार्ता में 9 नवंबर 2018 को गैर-आधिकारिक स्तर पर भाग लिया।
- **जिनेवा सम्मेलन:** अफगानिस्तान के संबंध में जिनेवा सम्मेलन 27-28 नवंबर 2018 को जिनेवा में आयोजित किया गया। सम्मेलन में 2015-2024 के परिवर्तन के दशक के तहत संस्थागत और सामाजिक-आर्थिक दोनों सुधार पहलों के संबंध में अफगानिस्तान द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री जनरल डॉ. वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) ने किया।
- **एससीओ-अफगानिस्तान संपर्क समूह की बैठक:** अपर सचिव श्री गितेश सरमा ने 28 मई 2018 को बीजिंग में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन-अफगानिस्तान संपर्क समूह की दूसरी बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस बैठक में तीन कार्यवृत्तों नामत: अफगानिस्तान और उसके पड़ोसी क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, अफगानिस्तान में मेल-मिलाप प्रक्रिया और एससीओ की भूमिका और एससीओ और अफगानिस्तान के बीच सहयोग के उपायों के मुद्दों पर चर्चा की गई।

बांग्लादेश

भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंध 2018 में और मजबूत हुए। कई उच्च-स्तरीय वार्ताएं हुईं जिन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को एक मजबूत संवेग प्रदान किया। बांग्लादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना ने शांतिनिकेतन विश्वविद्यालय में बांग्लादेश भवन के संयुक्त उद्घाटन के लिए 24 और 25 मई 2018 को दो दिवसीय भारत यात्रा की। उन्हें आसनसोल में काजी नजरूल विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर (डी.लिट) की उपाधि से सम्मानित किया गया। भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों ने अप्रैल 2018 में लंदन में कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ़ गवर्नमेंट मीटिंग (चोगम) और अगस्त 2018 में काठमांडू में बिम्सटेक के शिखर-सम्मेलन के दौरान मुलाकात की।

दो प्रधानमंत्रियों ने सितंबर 2018 में संयुक्त रूप से भारत सरकार ऋण श्रृंखला / अनुदान वित्तपोषण के तहत बांग्लादेश में निम्नलिखित परियोजनाओं के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया: (i) भारत से बांग्लादेश को 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति; (ii) अखौरा-अगरतला रेल लिंक; (iii) बांग्लादेश रेलवे के कुलौरा-शाहबाज़पुर खंड का पुनर्स्थापन; (iv) सिलीगुड़ी से परबतीपुर, बांग्लादेश तक 130 किलोमीटर की भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन और (v) बांग्लादेश रेलवे के ढाका-टोंगी-जोयदेवपुर खंड की अतिरिक्त रेल लाइनें।

गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारत-बांग्लादेश गृह मंत्री स्तर की वार्ता की 6 वीं बैठक के लिए 13-16 जुलाई 2018 तक तीन दिन की ढाका की आधिकारिक यात्रा की। वार्ता में चर्चाओं में सीमा प्रबंधन, अवैध गतिविधियों से निपटने में सहयोग, कौंसुली और वीजा मुद्दों आदि सहित विभिन्न सुरक्षा संबंधी मुद्दे शामिल थे।

वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने 24-28 सितंबर 2018 तक बांग्लादेश की यात्रा की। उन्होंने बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री श्री तॉफेल अहमद, बांग्लादेश के नागरिक उड्डयन और पर्यटन मंत्री श्री ए. के. एम. शाहजहां कमाल और सड़क परिवहन एवं पुल मंत्री श्री ओबैदुल कादर के साथ मुलाकात की। दोनों वाणिज्य मंत्रियों ने एक व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) पर हस्ताक्षर करने, भू-सीमा शुल्क एमएस के प्रचालन और बुनियादी ढांचे में सुधार, बांग्लादेश-भारत सीमा पर स्टेशन, परीक्षण प्रमाणपत्रों की मान्यता, डंपिंग रोधी उपायों, बंदरगाह प्रतिबंधों को हटाने और नीतिगत स्तर के इनपुट के लिए बांग्लादेश-भारत सीईओ फोरम के गठन आदि सहित व्यापार, निवेश और आवागमन सुविधाओं के बहुत से मुद्दों पर चर्चा की।

नौवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने 9 और 10 अक्टूबर, 2018 को ढाका में आयोजित दूसरे दक्षिण एशिया समुद्री संभारिकी मंच में भाग लेने के लिए बांग्लादेश की यात्रा की। उन्होंने द्विपक्षीय हित के मुद्दों पर चर्चा करने के

लिए फोरम की बैठक के दौरान बांग्लादेश के जहाजरानी मंत्री श्री शाहजहाँ खान से मुलाकात की।

बांग्लादेश की ओर से, महत्वपूर्ण मंत्री स्तरीय यात्राओं में अगस्त 2018 में भारत के पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री श्री अबुल हसन महमूद अली की यात्रा; अप्रैल 2018 में सांस्कृतिक मामलों के मंत्री श्री असदज़्ज़मान नूर की शांतिनिकेतन की यात्रा; अप्रैल 2018 में स्वच्छ पानी के लिए एशिया और प्रशांत के आठ क्षेत्रीय 3आर फोरम में भाग लेने के लिए उद्योग मंत्री श्री मुहम्मद आमिर हुसैन की यात्रा; अगस्त 2018 में 6 वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिए नागरिक उड्डयन और पर्यटन मंत्री श्री ए.के.एम शाहजहाँ कमाल की यात्रा; उद्योग मंत्री अगस्त 2018 में इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर के उद्घाटन में भाग लेने के लिए श्री अमीर हुसैन अमू की यात्रा; अक्टूबर 2018 में नई दिल्ली में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन में भाग लेने के लिए बांग्लादेश के योजना मंत्री श्री ए.एच.एम मुस्तफा कमाल की यात्रा; अक्टूबर 2018 में नई दिल्ली में दूसरी हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) अक्षय ऊर्जा मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए विदेश राज्य मंत्री श्री शहरयार आलम की यात्रा शामिल थी।

दोनों देशों के बीच उपरोक्त उच्च-स्तरीय यात्राओं और आदान-प्रदानों के अलावा, विभिन्न द्विपक्षीय तंत्रों के लिए नियमित रूप से वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर लगातार यात्राएं भी हुए हैं। इस वर्ष दोनों देशों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए पच्चीस समझौता ज्ञापनों / करारों पर हस्ताक्षर किए गए।

सुरक्षा और सीमा प्रबंधन

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ)-बार्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के 46 वें और 47 वें महानिदेशक (डीजी) स्तरीय सम्मेलन क्रमशः 23 अप्रैल और 3 सितंबर 2018 को ढाका और नई दिल्ली में आयोजित किए गए। 3 अगस्त 2018 को सिलीगुड़ी में बार्डर गार्ड बांग्लादेश के जेस्सौर और रंगपुर क्षेत्र कमांडरों और सीमा सुरक्षा बल के उत्तर बंगाल, दक्षिण बंगाल और गुवाहाटी फ्रंटियर्स के फ्रंटियर महानिरीक्षकों के बीच सीमा समन्वयन सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय तट रक्षक के महानिदेशक ने 8-11 जनवरी, 2018

प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश भवन के उद्घाटन के अवसर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ (25 मई, 2018)

को बांग्लादेश की यात्रा की और बांग्लादेश तटरक्षक बल (बीसीजी) के महानिदेशक ने दो तटरक्षकों के बीच तीसरे और चौथे महानिदेशक स्तरीय बैठकों में भाग लेने के लिए 26-30 अगस्त 2018 तक भारत की यात्रा की।

रक्षा सहयोग

रक्षा संबंधी मसलों पर नियमित रूप से दोनों तरफ से यात्राएं और बैठकें होती रही हैं। थल सेनाध्यक्ष जनरल अजीज अहमद ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के रूप में 31 जुलाई -5 अगस्त 2018 तक भारत की यात्रा की। भारतीय नौसेनाध्यक्ष ने 24-29 जून 2018 तक बांग्लादेश की यात्रा की। बांग्लादेश के वायुसेनाध्यक्ष, एयर चीफ मार्शल माशिहुज्जमां सरनिअबत 13-17 अक्टूबर 2018 तक पांच दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत आए। भारत और बांग्लादेश के सशस्त्र बलों के बीच उद्घाटन वार्षिक रक्षा वार्ता 7 मई 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच पहली समन्वित गश्त (कॉर्पैट) 27 जून -4 जुलाई 2018 तक की गई थी। यह पहली बार था जब दोनों देशों के बीच एक समन्वित गश्त का आयोजन किया गया था।

इस वर्ष मुक्तियोद्धा संबंधी कार्यक्रम, विजय दिवस के अवसर पर मुक्तियोद्धाओं और युद्ध के दिग्गजों की एक-दूसरे के देश की वार्षिक यात्रा आयोजित की गई और मुक्तियोद्धाओं के 1900 से अधिक आश्रितों में 7.12 करोड़ बांग्लादेश टका (6.14 करोड़ रुपये) की छात्रवृत्ति वितरित की गई।

आर्थिक और वाणिज्यिक

भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय व्यापार पिछले कुछ वर्षों से लगातार बढ़ रहा है। 2017-18 में बांग्लादेश को भारत का निर्यात 8614.35 मिलियन अमेरिकी डॉलर और इसी अवधि के दौरान बांग्लादेश से आयात 685.65 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा। अप्रैल-सितंबर 2018 की अवधि में भारत को बांग्लादेश का निर्यात 414.62 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसी अवधि में बांग्लादेश को भारत का निर्यात 4387.53 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

इस साल द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत तंत्र की विभिन्न बैठकें आयोजित की गईं जिनमें 4 और 5 जून 2018 को नई दिल्ली में मत्स्य पालन पर संयुक्त कार्य दल की 4 वीं बैठक; 22 और 23 जुलाई 2018 को त्रिपुरा में अगरतला में सीमा हाट पर संयुक्त समिति की पहली बैठक; 7 और 8 अक्टूबर 2018 को ढाका में सीमा शुल्क के संयुक्त समूह की 12 वीं बैठक; 24 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली में अंतर्देशीय जल व्यापार और पारगमन पर प्रोटोकॉल पर स्थायी समिति की 19 वीं बैठक और 25 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली में शिपिंग सचिव स्तर की वार्ता शामिल थी।

ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के क्षेत्र में 15 वें संयुक्त कार्यदल (जेडब्ल्यूजी) और 15 वीं संयुक्त संचालन समिति (जेएससी) की बैठकें क्रमशः 24 और 25 सितंबर 2018 को सिलहट में आयोजित की गईं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में, भारत-बांग्लादेश के बीच सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स पर पहली संयुक्त कार्य दल की बैठक 29 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। 5 वीं संयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति की बैठक ढाका में 26 और 27 फरवरी 2018 को हुई और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त समिति की पहली बैठक 25 और 26 जुलाई 2018 को कोलकाता में आयोजित की गई थी।

द्विपक्षीय व्यापार में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तंत्रों की उपरोक्त नियमित बैठकों के अलावा, भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक बीस-सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने सितंबर 2018 में बांग्लादेश की यात्रा की और भारत के खाद्य सचिव के नेतृत्व में भारतीय चीनी उद्योग के प्रतिनिधियों ने बांग्लादेश में कच्ची चीनी के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने के लिए नवंबर 2018 में ढाका की यात्रा की।

आवागमन सुविधा

दोनों सरकारों ने दोनों देशों के बीच आवागमन सुविधा बढ़ाने के लिए इस वर्ष कई उपाय किए। इनमें अप्रैल 2018 में भारत और बांग्लादेश के बीच कंटेनर रेल सेवा का ट्रायल रन; अगस्त 2018 में कोलकाता-ढाका-कोलकाता मार्ग पर नई उड़ान सेवाओं का शुभारंभ; तटीय और प्रोतोकॉल मार्गों पर यात्री और क्रूज सेवाओं के संबंध में समझौता ज्ञापन के प्रचालन के लिए अक्टूबर 2018 में मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर हस्ताक्षर करना, और अक्टूबर 2018 में भारत को/से माल के हस्तांतरण के लिए चटगांव और मोंगला बंदरगाहों के उपयोग पर करार पर हस्ताक्षर करना शामिल है। इन उपायों से भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच परस्पर संपर्क में और दोनों देशों के व्यापार संबंधों में और तेजी आएगी।

विकास भागीदारी

भारत सरकार बांग्लादेश में रेलवे, बंदरगाहों, सड़कों, जहाजरानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, संस्कृति, शहरी विकास और आपदा प्रबंधन आदि सहित कई क्षेत्रों में 'बांग्लादेश को सहायता' के अंतर्गत ऋण श्रृंखला/अनुदान वित्तपोषण के अंतर्गत कई विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का सहयोग दे रही है।

भारत और बांग्लादेश के बीच संचयी रूप से 8 बिलियन अमरीकी डॉलर की तीन ऋण श्रृंखलाओं के तहत विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेने के लिए 13 वीं ऋण श्रृंखला की समीक्षा बैठक 6 और 7 जून 2018 को ढाका में आयोजित की गई थी। ऋण श्रृंखलाओं के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में काफी प्रगति हुई है।

'बांग्लादेश को सहायता' अनुदान वित्तपोषण कार्यक्रम के तहत, अब तक, 126.2 करोड़ बांग्लादेशी टका (रु 107.6 करोड़) की पैंतीस लघु विकास परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं, जिनमें छात्रों के छात्रावास, सांस्कृतिक केंद्रों, अनाथालय आदि का निर्माण शामिल है और वर्तमान में 230.9 करोड़ बांग्लादेशी टका (196.4 करोड़ रुपये) के परिव्यय के साथ 40 परियोजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने बांग्लादेश में 1121 करोड़ बांग्लादेशी टका (957.3 करोड़ रुपए) की कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए इस कार्यक्रम के तहत अनुदान सहायता भी प्रदान की है, जिनमें अखौरा-अगरतला रेल लिंक का निर्माण, बांग्लादेश में अंतर्देशीय जलमार्गों की सफाई और भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइप लाइन का निर्माण शामिल है।

विगत की तरह, इस अवधि में नियमित आईटीईसी पाठ्यक्रम और आईसीसीआर छात्रवृत्तियों के अलावा बांग्लादेशी सिविल सेवकों, पुलिस अधिकारियों, नार्कोटिक्स विभाग के अधिकारियों, सीमा सुरक्षा बलों, न्यायिक अधिकारियों, परमाणु वैज्ञानिकों, रक्षा प्रतिष्ठानों और शिक्षकों आदि के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ढाका में हिंदी, योग, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन और वाद्य संगीत, कथक, मणिपुरी नृत्य, चित्रकला और संस्कृत का बुनियादी पाठ्यक्रम के विभिन्न अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किए गए। इस वर्ष के दौरान सांस्कृतिक केंद्र ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए।

वीजा

वर्ष 2018 में, मिशन की वीजा प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाने और वीजा जारी करने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए प्रक्रिया से संबंधित पहल सहित विभिन्न नीतियाँ लागू की गई थी। जुलाई 2018 में जमुना फ्यूचर पार्क, ढाका में गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा एकीकृत अधुनातन भारतीय वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर (आईवीएसी) का उद्घाटन भारतीय वीजा जारी करने की प्रणाली को अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने की दिशा में एक और कदम था। इस सुविधा के उद्घाटन के साथ, कोटा आधारित ऑनलाइन आवेदन प्रणाली की पिछली प्रणाली को खत्म कर दिया गया था और बांग्लादेश में सभी 9 आईवीएसी में वॉक-इन सबमिशन प्रणाली लागू की गई थी। बांग्लादेश में मिशन / केन्द्र द्वारा जारी किए जाने वाले वीजा 2018 में पिछले वर्ष को रुझान को बरकरार रखते हुए 1.4 मिलियन को पार करने की उम्मीद है।

भूटान

भारत और भूटान के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं जो पूरी तरह परस्पर विश्वास और समझ पर आधारित है। दोनों देशों ने वर्ष 2018 के दौरान संयुक्त रूप से औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना की स्वर्ण जयंती मनाई। उच्च स्तरीय द्विपक्षीय आदान-प्रदान और यात्राओं ने विशेष स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान द्विपक्षीय संबंधों की गति को बनाए रखा।

स्वर्ण जयंती स्मारक कार्यक्रम

वर्ष के दौरान अनेक स्मारक कार्यक्रमों को संयुक्त रूप से मनाया गया जिसमें विशेष द्विपक्षीय संबंधों की विभिन्न थीमों को शामिल किया गया जिनमें कला, शिल्प, खेलकूद, साझा आध्यात्मिक संबंधों को भी शामिल किया गया जिससे न केवल हमारे अनूठे संबंध रेखांकित हुए अपितु हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक जुड़ावों, लोगों के बीच परस्पर संबंधों, गहन आर्थिक सहयोग और शैक्षणिक/युवा आदान-प्रदान को भी उजागर किया गया। जनवरी 2018 में विदेश मंत्री और भूटान के तत्कालीन विदेश मंत्री ल्योनपो डैमचो दोर्जी द्वारा संयुक्त लोगो के शुभारंभ के साथ, इस वर्ष के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती राज्यों सहित

राष्ट्रपति की नई दिल्ली में भूटान के प्रधानमंत्री डॉ. लोटे शेरिंग के साथ मुलाकात (29 दिसंबर, 2018)

भारत के विभिन्न शहरों को शामिल किया गया जिनमें से सभी ने सीमा के दोनों ओर संस्कृतियों की बेहतर समझ में योगदान दिया है।

उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान: विकास और आर्थिक साझेदारी का विस्तार

एडवांटेज असम समिट में 'गेस्ट ऑफ ऑनर 'के रूप में भाग लेने के लिए फरवरी 2018 में भूटान के प्रधान मंत्री टीशेरिंग तोबगे ने गुवाहाटी की यात्रा की। यात्रा के दौरान पीएम तोबगे ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। गुवाहाटी में रॉयल भूटानी कौंसुलावास का उद्घाटन संयुक्त रूप से भूटान के विदेश मंत्री ल्योनपो दामचो दोर्जी और असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने पीएम तोबगे की उपस्थिति में किया।

विदेश सचिव श्री विजय गोखले ने दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना की स्वर्ण जयंती के अवसर पर 2018 में स्मारक क्रियाकलापों सहित द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा करने के लिए 1 और 2 अप्रैल, 2018 को भूटान की आधिकारिक यात्रा की।

प्रधान मंत्री त्शेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर 5-7 जुलाई 2018 से भारत की आधिकारिक यात्रा की। उनके साथ वित्त मंत्री ल्योनपो नमगई दोरजी और भूटान की रॉयल सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी थे। यात्रा के दौरान, प्रधान मंत्री टीशेरिंग टोबगे ने भारत के राष्ट्रपति से मुलाकात की और प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधान मंत्री त्शेरिंग तोबगे ने भूटान की 11 वीं पंचवर्षीय योजना के समर्थन के लिए भारत के लोगों और भारत सरकार को धन्यवाद दिया ।

महामहिम भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक ने 17 अगस्त 2018 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को अंतिम सम्मान देने के लिए नई दिल्ली का दौरा किया।

विदेश सचिव श्री विजय गोखले ने 18-20 नवंबर, 2018 तक भूटान की आधिकारिक यात्रा की और उच्च स्तरीय आदान-प्रदान, आर्थिक और विकास सहयोग, जल विद्युत सहयोग, लोगों के बीच आपसी संबंध और स्वर्ण जयंती वर्ष में संयुक्त रूप से आयोजित किए जाने वाले क्रियाकलापों सहित विभिन्न द्विपक्षीय मामलों पर भूटानी नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की।

भारत और भूटान के बीच विकास सहयोग पर भारत-भूटान द्विपक्षीय परामर्श 12 दिसंबर 2018 को नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। परामर्श के दौरान, दोनों पक्षों ने 11

वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की और भूटान की 12 वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भारत सरकार के विकास सहायता के तत्वों पर चर्चा की ।

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर, भूटान के प्रधान मंत्री डॉ लोटे त्सरिंग ने 27-29 दिसंबर 2018 तक भारत की राजकीय यात्रा की। उनके साथ विदेश मंत्री ल्योनपो डॉ तंदी दोरजी, आर्थिक मामलों के मंत्री ल्योनपो लोकनाथ शर्मा और भूटान की शाही सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी थे। दोनों पक्षों ने पारस्परिक हित के व्यापक द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों की समीक्षा की। इस यात्रा के दौरान, भूटान की 12 वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 1 नवंबर 2018 से 31 अक्टूबर 2023 तक की अवधि के लिए भारत सरकार के सहायता पैकेज की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सूचित किया कि भारत भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 4500 करोड़ रुपए तथा द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संपर्कों को सुदृढ़ करने के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए 400 करोड़ रुपए की माध्यमिक व्यापार सहयोग सुविधा का सहायता अनुदान प्रदान करेगा। दोनों पक्षों ने आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के महत्व को स्वीकार करते हुए, भूटान में चल रही द्विपक्षीय पनबिजली परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की और उनके कार्यान्वयन में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने भूटान में 10,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन क्षमता को संयुक्त रूप से विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और इस संबंध में सोकोश जलविद्युत परियोजना पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने 720 मेगावाट की मंगदेछु एचईपी की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और भारत द्वारा परियोजना से अधिशेष बिजली के आयात के लिए टैरिफ पर दोनों पक्षों की आपसी समझ का स्वागत किया।

आर्थिक और पनबिजली सहयोग

वर्ष के दौरान, भूटान में भारत सरकार की सहायता से बनाए जा रहे 720 मेगावाट मंगदेछु एचईपी पर तेजी से काम किया गया, परियोजना 2019 में चालू होने वाली है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान भारत सरकार की सहायता वाली पुनात्संगछु-I, II पनबिजली परियोजनाओं पर प्रगति हुई है। पुनात्सांगछु-II, II और मंगदेछु परियोजनाओं की द्वि-राष्ट्रीय परियोजना प्राधिकरण की बैठकें नई दिल्ली में 2 और 3 मई 2018 को आयोजित की गईं ।

वाणिज्य सचिव स्तर पर भारत और भूटान की द्विपक्षीय बैठक 17 और 18 मई 2018 को थिम्मू में आयोजित की गई थी ।उच्च स्तरीय बैठक ने नई दिल्ली में 18 और 19 जनवरी 2017 को आयोजित व्यापार और पारगमन पर अंतिम द्विपक्षीय बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की।

'भूटान-भारत व्यापार और निवेश संवर्धन एक्सपो' (बीआईटीआईपीई), भारतीय हस्तशिल्प पर 7 वें विषयगत प्रदर्शनी और चौथे कृषि फ़्लोरी मेला 2018 का उद्घाटन समारोह चंगलीमियांग स्टेडियम, थिम्पू के पास 12 सितंबर 2018 को हुआ। यह आयोजन भारत के दूतावास, थिम्पू के सहयोग से भूटान चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (बीसीसीआई) द्वारा आयोजित किया गया था।

क्षमता निर्माण और लोगों के बीच आपसी संबंध

उच्च शिक्षा के भारतीय संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन करने के लिए भूटानी छात्रों को भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 1200 छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। 2018 के दौरान, नेहरू-वांगचुक छात्रवृत्ति के तहत आठ विद्वानों, राजदूत की छात्रवृत्ति के तहत 864 और स्नातक छात्रवृत्ति के तहत उन्यासी छात्रों का लाभ मिला। आईटीईसी के तहत भारत सरकार द्वारा बीस प्रशिक्षण स्लॉट प्रदान किए जाते हैं। वित्त वर्ष 2018-19 में, भूटान के कई सरकारी अधिकारियों को भारत के आईएएस, आईएफएस, आईएएएस और आईआरएस अधिकारियों के साथ प्रमुख सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके अलावा, भारत भूटान के रॉयल विश्वविद्यालय से संबद्ध विभिन्न कॉलेजों में व्याख्याताओं की तैनाती कर रहा है। वित्त वर्ष 2018-19 में, ग्यारह व्याख्याताओं को भारत से भूटान के रॉयल विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्त किया गया है।

चीन

नेतृत्व स्तर की बातचीत

27 और 28 अप्रैल, 2018 को वुहान में आयोजित प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अध्यक्ष श्री शी जिनपिंग के बीच पहले अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के साथ भारत और चीन के बीच घनिष्ठ विकास साझेदारी वर्ष 2018 में एक नए मुकाम पर पहुंच गई। इस अनौपचारिक शिखर सम्मेलन ने अपने द्विपक्षीय संबंधों के स्तर को बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों की इच्छा को प्रतिबिंबित किया और दोनों नेताओं को एक-दूसरे के विकास संबंधी आकांक्षाओं और आपसी संवेदनशीलता के साथ मतभेदों के विवेकपूर्ण प्रबंधन के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित भारत-चीन संबंधों की भविष्य की दिशा की एक आम समझ बनाने में मदद की। दोनों पक्ष 2019 में भारत में दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमत हुए।

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन के अवसर पर वर्ष के दौरान तीन बार द्विपक्षीय बैठकें कीं, जिनमें 9 जून, 2018 को किंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन, 26 जुलाई, 2018 को जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और 30 नवंबर, 2018 को ब्यूनस आयर्स में जी-20 शिखर सम्मेलन शामिल हैं।

उच्च स्तरीय आदान-प्रदान

भारत और चीन के बीच नियमित रूप से उच्च स्तरीय विनियोजन के हिस्से के रूप में, विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 21-24 अप्रैल, 2018 तक चीन की आधिकारिक यात्रा की। इस यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री ने चीन के स्टेट काउंसलर और चीन के विदेश मंत्री श्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय बैठक की और बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी भाग लिया।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल ने 12 और 13 अप्रैल, 2018 को चीन का दौरा किया और श्री यांग जियेची, पोलित ब्यूरो के सदस्य और शंघाई में सीपीसी केंद्रीय समिति

प्रधानमंत्री और चीन जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग 28 अप्रैल, 2018 को वुहान, चीन में

के विदेशी मामलों के आयोग के निदेशक के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर परामर्श किया।

चीन के स्टेट काउंसिलर और विदेश मंत्री श्री वांग यी ने 21-23 दिसंबर 2018 तक भारत की आधिकारिक यात्रा की और नई दिल्ली में सांस्कृतिक और लोगों के पारस्परिक आदान-प्रदान संबंधी भारत-चीन उच्च स्तरीय तंत्र की पहली बैठक की सह-अध्यक्षता की। यात्रा के दौरान, उन्होंने राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की और एनएसए के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

विशेष प्रतिनिधि वार्ता

सीमा मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधि - राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री श्री वांग यी ने विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता के 21वें दौर के लिए 24 नवंबर, 2018 को चेंगदू में आपस में मुलाकात की। वुहान शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा प्रदान किए गए उनके कार्यों के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन और समर्थन को याद करते हुए, विशेष प्रतिनिधियों ने यथाशीघ्र भारत-चीन सीमा विवाद का उचित, तर्कसंगत और परस्पर स्वीकार्य समाधान हासिल करने के अपने प्रयासों को तेज करने का संकल्प लिया। विशेष प्रतिनिधियों ने सहमति व्यक्त की कि सीमा विवाद का अंतिम समाधान होने तक यह आवश्यक है कि सीमा क्षेत्रों में शांति एवं अमन-चैन बनाए रखा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सीमा विवाद द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास को प्रभावित न करे।

भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र के 12वें और 13वें दौर की वार्ताएं क्रमशः 27 सितंबर, 2018 को चेंगदू में और 29 जनवरी, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत-चीन सीमा क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा की ।

अन्य उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान

चीन से भारत की उच्च-स्तरीय यात्राओं में, 21-25 अक्टूबर, 2018 तक स्टेट काउंसलर और लोक सुरक्षा मंत्री श्री झाओ केज़ी की यात्रा शामिल थी। यात्रा के दौरान, गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह और श्री झाओ केज़ी ने 22 अक्टूबर, 2018 को नई दिल्ली में द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग पर पहली भारत-चीन उच्च स्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता की और द्विपक्षीय आतंकवादरोधी सहयोग सहित आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की और भारत और चीन के बीच सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में अधिक से अधिक सहयोग का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों द्वारा गृह मंत्रालय और चीन के लोक सुरक्षा मंत्रालय के बीच सुरक्षा सहयोग के एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।

वर्ष के दौरान विभिन्न द्विपक्षीय संवाद तंत्रों के तहत आदान-प्रदान भी किए गए। निरस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण वार्ता 10 अप्रैल, 2018 को बीजिंग में आयोजित की गई। बीजिंग में 13 जुलाई, 2018 को समुद्री मामलों से संबंधित वार्ता आयोजित की गई थी। कौंसुली वार्ता 27 जून, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। आतंकवाद रोध पर 8वीं भारत-चीन संयुक्त कार्य समूह की बैठक 30 जनवरी, 2019 को बीजिंग में हुई थी। एक और महत्वपूर्ण घटना अफगान राजनयिकों के लिए पहली भारत-चीन संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम थी, जो 15-26 अक्टूबर, 2018 तक नई दिल्ली और 19-30 नवंबर, 2018 को बीजिंग में आयोजित की गई थी।

भारत और चीन के बीच नियमित आदान-प्रदान के एक हिस्से के रूप में विदेश मंत्रालय और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंतरराष्ट्रीय विभाग के बीच निष्पन्न समझौता ज्ञापन के तहत झारखंड के मुख्यमंत्री श्री रघुबर दास ने 2-6 सितंबर, 2018 तक चीन का दौरा किया। असम, त्रिपुरा, नागालैंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्य से मंत्रियों एवं वरिष्ट अधिकारियों ने भी अलग से चीन की यात्रा की।

भारत का शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में एक पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने और चीन द्वारा 2018 में शंघाई सहयोग संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाल लेने से और दोनों पक्षों के बीच मंत्रालयी स्तर के साथ-साथ आधिकारिक स्तर पर बातचीत के लिए और अधिक अवसर प्राप्त हुए। एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 21-24 अप्रैल, 2018 तक विदेश मंत्री की बीजिंग यात्रा के अलावा, रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भी 23-25 अप्रैल, 2018 तक बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक के लिए चीन का दौरा किया। पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री ए.के. अल्फोंस वुहान में एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक के लिए 8 और 9 मई 2018 को चीन गए। संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ० महेश शर्मा 15-18 मई, 2018 तक सान्या, चीन गए। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री राजिंदर खन्ना ने 21 और 22 मई, 2018 तक बीजिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिवों

की बैठक के लिए चीन का दौरा किया। न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी, न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 23-27 मई 2018 तक सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्षों की बैठक के लिए चीन का दौरा किया।

जल संसाधन में सहयोग

जून 2018 में प्रधान मंत्री की किंगदाओ यात्रा के दौरान, चीन द्वारा भारत को बाढ़ के मौसम में ब्रह्मपुत्र नदी की जल संबंधी जानकारी देने की व्यवस्था करने के लिए दोनों पक्षों ने अगले पांच साल के लिए मौजूदा समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया। सतलुज नदी के लिए इसी तरह का समझौता ज्ञापन पहले से ही लागू है। मौजूदा समझौता ज्ञापनों के अनुपालन में, चीन ने 2018 में बाढ़ के मौसम के दौरान भारत को ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियों के लिए हाइड्रोलॉजिकल जानकारी प्रदान की।

रक्षा आदान-प्रदान

भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय रक्षा और सैन्य-से-सैन्य आदान-प्रदान पूरे वर्ष जारी रहे। चीन के स्टेट काउंसलर और रक्षा मंत्री जनरल वेई फ़ेंगहे ने 21-24 अगस्त 2018 तक भारत का दौरा किया। यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधी बातचीत के साथ-साथ क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर व्यापक चर्चा की। इसके बाद 9वीं भारत-चीन वार्षिक रक्षा और सुरक्षा वार्ता का आयोजन 13 नवंबर, 2018 को बीजिंग में किया गया। इस वार्ता के दौरान दोनों पक्ष 2019 के लिए विशिष्ट रक्षा आदान-प्रदान पर सहमत हुए, जिसकी सह-अध्यक्षता रक्षा सचिव श्री संजय मित्रा और केंद्रीय सैन्य आयोग के संयुक्त स्टाफ विभाग के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल शाओ युआनिंग ने की।

वर्ष के दौरान अन्य आदान-प्रदानों में जून 2018 में चीन के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के प्रतिनिधिमंडल का दौरा और जुलाई 2018 में पश्चिमी कमान के उप-कमांडर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल का भारत दौरा शामिल है। इन यात्राओं के उपरांत अगस्त 2018 में भारतीय सेना के पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ ने चीन की यात्रा की। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जिसने 4-8 नवंबर, 2018 से चीन के झुहाई एयर शो में भाग लिया। 7वां भारत-चीन संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास 'हैंड इन हैंड 2018' 10-23 दिसम्बर, 2018 को चेंगदू, चीन में हुआ।

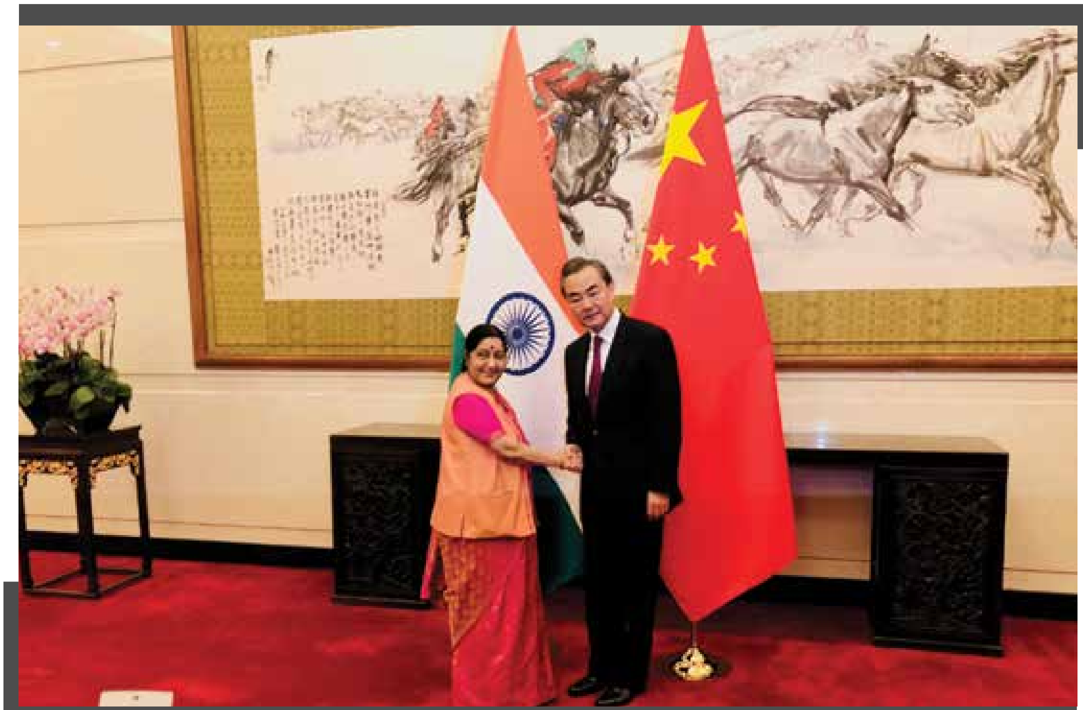

विदेश मंत्री बीजिंग में चीन के स्टेट कौंसलर एवं विदेश मंत्री से मुलाकात करते हुए (22 अप्रैल, 2018)

विदेश सचिव नई दिल्ली में चीन के उप विदेश मंत्री श्री कौंग जुआनयू से मुलाकात करते हुए (05 जून, 2018)

व्यापार और आर्थिक संबंध

आर्थिक मोर्चे पर, जून 2018 में प्रधान मंत्री की किंगदाओ यात्रा के दौरान भारत से चीन को चावल के निर्यात के लिए प्रोटोकॉल के अलावा, दोनों पक्षों ने भारत से चीन को मछली और मछली के तेल के निर्यात और तंबाकू की पत्तियों के निर्यात से संबंधित दो और प्रोटोकॉल पर नवंबर 2018 और जनवरी, 2019 में हस्ताक्षर किए। चीन को भारतीय रेपसीड मील का निर्यात करने के लिए रेपसीड मील के निर्यात से संबंधित प्रक्रियाएं भी पूरी की गईं।

वाणिज्य विभाग के अपर सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जून और अगस्त 2018 में चीनी पक्ष के साथ द्विपक्षीय वाणिज्यिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए चीन का दौरा किया। वाणिज्य सचिव डॉ॰ अनूप वधावन ने 4 से 6 नवंबर 2018 तक शंघाई में होने वाले पहले चीन अंतर्राष्ट्रीय आयात एक्सपो में भाग लेने के लिए चीन के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने चीन के वाणिज्य मंत्रालय के वाइस मिनिस्टर श्री वांग शॉवेन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। वाणिज्य सचिव डॉ. अनूप वाधवा ने द्विपक्षीय चर्चाओं को तथा आरसीईपी संबंधी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए 21-22 जनवरी, 2019 को चीन की यात्रा की। इन बैठकों के दौरान, बढ़ते व्यापार असंतुलन पर अपनी चिंता को दोहराते हुए भारतीय पक्ष ने कृषि उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं और पर्यटन जैसे क्षेत्रों का उल्लेख किया जिनमें भारत ने अपनी ताकत और महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति दर्ज की है, लेकिन चीन में जिनकी उपस्थिति नगण्य है और द्विपक्षीय व्यापार में इन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

नीति आयोग और चीन के राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग (एनडीआरसी) के बीच 5वीं भारत-चीन रणनीतिक आर्थिक वार्ता 14 अप्रैल, 2018 को बीजिंग में आयोजित की गई थी। इसके पांच कार्यकारी समूहों ने - बुनियादी सुविधाएं, हाई-टेक, ऊर्जा, संसाधन संरक्षण और नीति समन्वय के क्षेत्रों में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की और इन क्षेत्रों में आगे के सहयोग के लिए चर्चा की। नीति आयोग और स्टेट काउंसिल ऑफ चाइना के विकास अनुसंधान केंद्र (डीआरसी) की चौथी वार्ता 1 नवंबर, 2018 को मुंबई में आयोजित की गई थी। भारत और चीन ने 28 और 29 मई, 2018 को बीजिंग

में सामाजिक सुरक्षा समझौते पर एक तकनीकी बैठक की। दोनों पक्षों ने 29 और 30 अक्टूबर, 2018 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉ० एम.एम. कुट्टी की चीन यात्रा के दौरान ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा की। नीति आयोग में प्रधान सलाहकार की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने बीजिंग में 11-12 जनवरी, 2019 तक चीन में सबसे बड़े इलैक्ट्रिकल व्हीकल फोरम, 5वें ईवी-100 में भाग लिया। कौशल विकास पर दूसरी भारच-चीन संयुक्त कार्य समूह बैठक 18-22 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में हुई।

भारत गणराज्य और चीन जनवादी गणराज्यके हॉग कॉग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के बीच कर के संबंध में दोहरे कराधान से बचाव और वित्तीय चोरी की रोकथाम संबंधी करार पर दोनों पक्षकारों द्वारा सभी संगत प्रक्रिया के पूरा होने के बाद 30 नवंबर, 2018 को हस्ताक्षर किए गए।

सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान

दोनों पक्षों ने लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान को बढ़ाने के लिए संयुक्त प्रयास किए और जैसा कि वुहान में अपने अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी, सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान पर एक उच्च-स्तरीय तंत्र स्थापित किया गया। इस तंत्र की पहली बैठक 21 दिसंबर 2018 को नई दिल्ली में हुई, इस दौरान दोनों पक्षों ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान, मीडिया एक्सचेंज, फिल्म और टेलीविजन, संग्रहालय प्रबंधन, खेल, युवा आदान-प्रदान, पर्यटन, राज्य और शहर-स्तरीय आदान-प्रदान, पारंपरिक चिकित्सा और योग, और शिक्षा और शैक्षणिक आदान-प्रदान के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। उच्च स्तरीय तंत्र की बैठक के दौरान कई अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें भारत-चीन थिंक टैंक फोरम की तीसरी बैठक (20-21 दिसंबर 2018), तीसरा भारत-चीन उच्च स्तरीय मीडिया फोरम (21 दिसंबर 2018) एक फिल्म महोत्सव (22-24 दिसंबर 2018) और संग्रहालय प्रबंधन पर एक फोरम (20 दिसंबर 2018) का आयोजन शामिल था।

2006 से भारत और चीन के बीच युवा आदान-प्रदान की परंपरा को जारी रखते हुए, जुलाई 2018 में 200 सदस्यीय भारतीय युवा प्रतिनिधिमंडल ने चीन का दौरा किया और नवंबर 2018 में 200 सदस्यीय चीनी युवा प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया।

भारत में आने वाले चीनी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री ए.के. अल्फोंस ने अगस्त 2018 में चीन का दौरा किया और बीजिंग, वुहान और शंघाई में पर्यटन रोड शो को संबोधित किया। 2018 में स्पाइस जेट और इंडिगो ने क्रमशः दिल्ली से हॉगकॉग और बेंगलुरु से हॉगकॉग को जोड़ने वाली उड़ाने शुरू की।

चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारतीय दूतावास और कौंसुलावासों द्वारा पूरे चीन में योग का आयोजन किया गया। इन आयोजनों में बड़ी संख्या में चीनी योग प्रेमियों ने भाग लिया। अगस्त 2018 में अध्यक्ष, आईसीसीआर की चीन यात्रा के दौरान आयोजित एक समारोह में, भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, बीजिंग को स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र का नया नाम दिया गया।

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के जश्न की शुरुआत 2 अक्टूबर 2018 को गांधी जयंती के साथ हुई। 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित अन्य गतिविधियों में चीनी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में गांधी विषयक कार्यक्रमों का आयोजन, चीनी भाषा में गांधीवादी साहित्य का वितरण, 'लाइफ एंड टाइम्स ऑफ गांधी' पर एक फोटो प्रदर्शनी और गांधीवादी विचारों के अच्छे जानकार विद्वानों के साथ 'सत्य वर्ता ' का आयोजन शामिल था। एक चीनी गायक द्वारा महात्मा गांधी के पसंदीदा भजन 'वैष्णव जन तो' का एक वीडियो भी इस दौरान जारी किया गया था।

कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड, सिक्किम और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर हर साल जून से सितंबर तक किया जाता है। 2018 में यात्रा के लिए कुल 3,734 लोगों ने आवेदन किया और 1,328 यत्रियों ने यात्रा की। नाथू-ला मार्ग, जिससे होकर वर्ष 2017 में यात्रा नहीं की गई थी, वर्ष 2018 में यात्रियों के लिए फिर से खोल दिया गया। 2018 में, 906 यत्रियों ने लिपुलेख मार्ग से होकर और 422 यात्रियों ने नाथू ला मार्ग से होकर यात्रा की।

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति श्री इब्राहिम मोहम्मद सोलिह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में (17 दिसंबर, 2018)

मालदीव

भारत ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध मालदीव देखने की अपनी इच्छा से सरकार और मालदीव सरकार और वहाँ के लोगों के साथ अपनी निकटता जारी रखी। विभिन्न क्षेत्रों में उच्च-स्तरीय यात्राओं और सहयोग का आदान-प्रदान हुआ।

23 सितंबर, 2018 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की जीत के बाद प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर, 2018 को उन्हें टेलीफोन पर बधाई दी। प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विशेष आदर-भाव दर्शाते हुए राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के निमंत्रण पर उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार किया और 17 नवंबर, 2018 को मालदीव का दौरा किया। विशेष आदर-भाव दर्शाते हुए तथा परंपरा से हटकर, राष्ट्रपति श्री इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। मई 2014 में प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद से यह प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा थी और उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। पिछले भारतीय प्रधान मंत्री की मालदीव यात्रा नवंबर 2011 में ठीक सार्क शिखर बैठक के तुरंत बाद हुई थी।

प्रधानमंत्री राष्ट्रपति श्री इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान (17 नवंबर, 2018)

प्रधान मंत्री ने राष्ट्रपति श्री इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को भारत की राजकीय यात्रा पर आने का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ने प्रथम महिला फ़ज़ना अहमद के साथ 16-18 दिसंबर, 2018 तक भारत की राजकीय यात्रा की।

राष्ट्रपति की भारत यात्रा की तैयारी में विदेश मंत्री श्री अब्दुल्ला शाहिद ने पदभार संभालने के बाद 24-27 नवंबर, 2018 तक भारत की अपनी पहली यात्रा की। उनके साथ वित्त मंत्री श्री इब्राहिम आमेर, आर्थिक विकास मंत्री उज़ फय्याज इस्माइल, विदेश राज्य मंत्री श्री अहमद खलील, विदेश सचिव श्री अब्दुल गफूर मोहम्मद और विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी थे।

रक्षा सेना के प्रमुख मेजर जनरल अहमद शियाम ने कोचीन में 13-14 नवंबर, 2018 तक भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (आईओएनएस) की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय संयुक्त नौसेना अभ्यास, "दोस्ती -14" का 14वां संस्करण 25-29 नवंबर, 2018 को मालदीव में आयोजित किया गया था। भारत सरकार ने 1 अगस्त - 30 नवंबर, 2018 को विशाखापत्तनम में मालदीव के तटरक्षक जहाज हुरावी में मामूली मरम्मत कार्य किया। मालदीव सरकार के अनुरोध पर 15 नवंबर, 2018 तक मरम्मत कार्य पूरा कर लिया गया और यह जहाज 23 नवंबर, 2018 को "दोस्ती -14" अभ्यास में भाग लेने के लिए मालदीव लौट आया। तीसरा संयुक्त स्टाफ वार्ता 26-27 जून, 2018 को माले में आयोजित की गई। भारतीय नौसेना डोर्नियर (इंडो 222) द्वारा संयुक्त ईईजेड की निगरानी 18-22 जून, 2018 तक की गई। आईएनएस सुमेधा ने 12-15 मई, 2018 तक जहाज पर एमएनडीएफ कर्मियों के साथ ईईजेड की निगरानी की। भारतीय नौसैनिक मरीन कमांडो और एमएनडीएफ मरीन्स के बीच एकता 2018 अभ्यास का आयोजन 28 अप्रैल - 14 मई, 2018 तक मालदीव में किया गया। भारतीय तटरक्षक जहाज (आईसीजीएस) समर्थ 28 अप्रैल से 10 भारतीय नौसेना मरीन कमांडो के साथ एकता 2018 अभ्यास के लिए मालदीव पहुंचा।

भारतीय निजी एयरलाइन, 'गोएयर ' ने 14 अक्टूबर, 2018 को अपनी उद्घाटन उड़ान के साथ मालदीव के लिए परिचालन शुरू किया जिसमें मुंबई से माले तक 80 यात्रियों के साथ ए 320 ने उड़ान भरी। इंडिगो एयरलाइंस ने भी 15 नवंबर, 2018 को अपनी उद्घाटन उड़ान के साथ मालदीव के लिए ऑपरेशन शुरू किया। इंडिगो कोचीन, बैंगलोर और मुंबई को मालदीव से जोड़ेगा।

मॉरीशस

वर्ष 2018-19 में भारत-मॉरीशस संबंधों में और मजबूती आई तथा इसमे नए आयाम जुड़े जिसके तहत सांस्कृतिक, भाषाई तथा प्रवासी पुनर्सम्पर्क, त्वरित आर्थिक सहयोग, जैविक विकास साझेदारी और लोगों के बीच जीवंत आपसी संपर्क देखा गया। **सागर** रणनीति के एक अभिन्न भागीदार के रूप में, हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, विकास और सुरक्षा स्थापित करने के लिए मॉरीशस ने अपनी महत्ता साबित की है।

गहन द्विपक्षीय विनियोजन के हिस्से के रूप में, विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने अगस्त 2018 में पोर्ट लुई में आयोजित 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लिया। इससे पहले (श्रीमती) लीला देवी दुकन लछुमन, शिक्षा और मानव संसाधन, तृतीयक शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री ने अप्रैल 2018 में विश्व हिंदी सम्मेलन की शासी परिषद की बैठक के लिए भारत का दौरा किया। 10 अप्रैल 2018 को, विदेश मंत्रालय, जवाहरलाल नेहरू भवन, नई दिल्ली में 11 वें विश्व हिंदी सम्मेलन (डब्ल्यूएचसी) का लोगो और वेबसाइट का विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज और मॉरीशस की शिक्षा और मानव संसाधन, तृतीयक शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से शुभारंभ किया गया था। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने सितंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर न्यूयॉर्क में और ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने दक्षिण अफ्रीका जाते समय मार्ग में पोर्ट लुई में मॉरीशस के प्रधान मंत्री से मुलाकात की थी। भारत के पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के पश्चात् एकजुटता दिखाते हुए मॉरीशस की सरकार ने मॉरीशस में सभी सरकारी भवनों पर भारतीय और मॉरीशस दोनों के झंडों को आधा झुका दिया। द्विपक्षीय संबंधों में दिवंगत नेता के योगदान की याद में, मॉरीशस सरकार ने एबेने साइबरसिटी (प्रधान मंत्री वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान भारतीय सहायता से निर्मित) में साइबर टॉवर 1 का नाम बदलकर "अटल बिहारी वाजपेयी टॉवर" रख दिया।

राष्ट्रपति वाराणसी में मॉरीशस गणराज्य के प्रधानमंत्री श्री प्रवीण जगन्नाथ के साथ मुलाकात करते हुए (23 जनवरी, 2019)

मॉरीशस सरकार के निमंत्रण पर, बिहार विधानसभा के ग्यारह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने नवंबर 2018 में अप्रवासी दिवस की 184वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेने के लिए आधिकारिक यात्रा पर मॉरीशस का दौरा किया। 16-19 जुलाई, 2018 तक ग्रामीण विकास में सहयोग पर गठित पहली संयुक्त समिति की बैठक मॉरीशस में आयोजित की गई जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय के नेतृत्व में अंतर-मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी हुई।

दोनों पक्षों की नियमित मंत्रिस्तरीय यात्राओं ने विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में सहयोग बढ़े हैं। मॉरीशस की कुछ उल्लेखनीय यात्राओं में (कार्यवाहक) राष्ट्रपति श्री परमासिवम पिल्ले व्यापूरी की अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव (11-18 दिसंबर, 2018) के लिए भारत यात्रा, अंतरराष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन (16-20, नवंबर 2018) में भाग लेने के लिए स्पीकर सुश्री शांति बाई हनुमानजी की भारत यात्रा, द्विपक्षीय बैठकों के लिए (15-21 नवंबर 2018) पब्लिक सर्विस कमीशन एंड डिसिपलींड फोर्सेस सर्विस कमीशन के अध्यक्ष श्री एस गनेसी की यात्रा, आईएसए की पहली आम सभा (2-4 अक्टूबर 2018) में शामिल होने के लिए श्री इवान लेस्ली कोलेंडा वेल्लू, उप प्रधान मंत्री, ऊर्जा मंत्री और मॉरीशस गणराज्य की सार्वजनिक उपयोगिताएँ मंत्री की यात्रा, द्विपक्षीय बैठक के लिए (27 सितंबर -4 अक्टूबर, 2018) श्रम और रोजगार मंत्री श्री एस.एस. कालीचरण की यात्रा, 5वीं वैश्विक तमिल आर्थिक मंच (11-15 अक्टूबर 2018) में शामिल होने के लिए (कार्यवाहक) राष्ट्रपति श्री परमशिवम पिल्ले व्यापूरी की भारत यात्रा, पर्यटन मंत्री श्री अनिल गायन (20-23 सितंबर, 2018) की यात्रा, एशियन समिट फॉर एजुकेशन एंड स्किल्स (एएसईएस) में शामिल होने के लिए श्रीमती लीला देवी दुकन-लछुमन, शिक्षा और मानव संसाधन, तृतीयक शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री की 2-4 अक्टूबर, 2018 तक और 2-7 अप्रैल, 2018 तक विश्व हिंदी सम्मेलन की शासी परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए भारत यात्रा और प्रौद्योगिकी, संचार एवं नयाचार मंत्री श्री योगिदा स्वामीनाथन की 2-8 अगस्त तक भारत यात्रा शामिल हैं।

आर्थिक मोर्चे पर, मॉरीशस भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रमुख स्रोतों में से एक रहा। भारत और मॉरीशस में भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते (सीईसीपीए) पर चल रही वार्ता के कई दौर आयोजित किए गए। मॉरीशस में 19-23 नवंबर, 2018 तक हाल ही

में 7वें दौर की बैठक का आयोजन किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री केशव चंद्रा, संयुक्त सचिव (एफटी-अफ्रीका), वाणिज्य विभाग ने किया और मॉरीशस की ओर से नेतृत्व व्यापार नीति, विदेश मामले, क्षेत्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय के निदेशक श्री नारायण बूधु ने किया।

बैठक के दौरान व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते संबंधी भारत-मॉरीशस संयुक्त अध्ययन रिपोर्ट (जेएसआर) पर हस्ताक्षर किए गए। रिपोर्ट में 25 क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग को लाभकारी पाया गया। भारत और मॉरीशस ने दिसंबर 2018 में द्विपक्षीय निवेश संधि पर वार्ता शुरू की थी।

रक्षा और सुरक्षा सहयोग में नियमित रूप से सद्भावना यात्राएं और भारतीय जहाजों द्वारा मॉरीशस के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) निगरानी यात्राएं की गईं। इस अवधि के दौरान भारत सरकार की सहायता के तहत मॉरीशस के तट रक्षक जहाज गार्जियन को अनुदान आधार पर सर्विस लाइफ एक्सटेंशन रिफिट (एसएलईआर) प्रदान किया गया। यह जहाज खोज और बचाव मिशन के साथ-साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में निगरानी कार्य करेगा।

भारत द्वारा 2018-19 में मॉरीशस को दी गई विकास साझेदारी सहायता में अन्य के साथ-साथ 353 मिलियन अमरीकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज के तहत प्रतिबद्ध पांच प्रमुख परियोजनाओं जैसे मेट्रो एक्सप्रेस, ईएनटी हॉस्पिटल, न्यू सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, सोशल हाउसिंग और स्कूली बच्चों के लिए डिजिटल टैबलेट का कार्यान्वयन शामिल है। मॉरीशस सरकार की अठारह अन्य प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए 500 मिलियन अमरीकी डॉलर की एक ऋण श्रृंखला भी कार्यान्वयन चरण में है।

ओसीआई योजना में की गई विशेष व्यवस्था ने मॉरीशस में भी लोकप्रियता हासिल की है और यह दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को मजबूत कर रही है। जनवरी 2019 में वाराणसी में मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री प्रवीण जगन्नाथ को प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था।

कई भारतीय सांस्कृतिक समूहों ने 2018 में मॉरीशस की स्वतंत्रता की 50 वीं वर्षगांठ पर वर्षभर चलने वाले विशेष सांस्कृतिक समारोहों में भाग लिया था। योग का चौथा अंतर्राष्ट्रीय दिवस, महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती समारोह का उत्सव और राष्ट्रीय दिवस समारोह भी अलग-अलग दलों की मॉरीशस की भागीदारी के साथ उत्साहपूर्वक मनाये गए।

म्यांमार

म्यांमार की भारत के साथ 1,600 किमी भूमि सीमा है। यह एक्ट ईस्ट और पड़ोसी प्रथम नीति के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाला एकमात्र आसियान देश है। भारत के म्यांमार के साथ एक लंबे समय से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं, और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग और म्यांमार में चिन, काचिन और सागांग के लोगों के बीच साझी जातीय, भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। यह संबंध हमारे मजबूत विकास सहयोग, रक्षा, व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों, उच्च-स्तरीय दौरों आदि से प्रगाढ़ हुआ है। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज की म्यांमार यात्रा के दौरान 10 और 11 मई 2018 को निम्नलिखित करारों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे:

- ''मोनवा, म्यांमार में भारत-म्यांमार औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना'' पर भारत गणराज्य की सरकार और म्यांमार संघ गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर 10 मई, 2018 को हस्ताक्षर किए गए।
- "थाटोन, म्यांमार में भारत-म्यांमार औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना" पर भारत गणराज्य की सरकार और म्यांमार संघ गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर 10 मई 2018 को हस्ताक्षर किए गए।
- मयिंगयान में स्थापित और 2013 में सौंप दिए गए औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र की पांच साल की व्यापक रखरखाव योजना के लिए भारत गणराज्य की सरकार और म्यांमार संघ गणराज्य की सरकार के बीच विनिमय पत्र पर 10 मई 2018 को हस्ताक्षर किए गए ।
- बागान में भूकंप से क्षतिग्रस्त पगोडा के संरक्षण के लिए भारत गणराज्य की सरकार और म्यांमार संघ गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर 11 मई 2018 को हस्ताक्षर किए गए।

राष्ट्रपति ने पी तो, म्यांमार में म्यांमार के राष्ट्रपति श्री यू विन मिंट से मुलाकात करते हुए (11 दिसंबर, 2018)

- भारत गणराज्य की सरकार और म्यांमार संघ गणराज्य की सरकार के बीच भूमि सीमा पारगमन समझौते पर 11 मई 2018 को हस्ताक्षर किए गए।
- कम्प्यूटर और अन्य संबद्ध उपकरणों की आपूर्ति के लिए सामाजिक मामलों के विभाग (रखाइन राज्य सरकार) और भारत के राजदूतावास, यंगून के बीच समझौता ज्ञापन पर 12 सितंबर 2018 को हस्ताक्षर किए गए।
- 20 जुलाई 2018 को केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री यू क्यॉ टिन की भारत यात्रा के दौरान म्यांमार ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसने समझौते की पुष्टि भी की है।

8 अगस्त 2018 को, तमू-मोरेह और रिहकवदर-ज़ोखवथर में दो अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमा निकास / प्रवेश केन्द्रों के खोलने के साथ भूमि सीमा पारगमन पर महत्वपूर्ण समझौता अस्तित्व में आया। यह स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं, तीर्थयात्रा और पर्यटन सहित लोगों को पासपोर्ट और वीजा के साथ भूमि सीमा पार करने में सक्षम बनाकर लोगों के आपसी संपर्कों को बढ़ाएगा।

इस प्रकार, अब तक भारत ने 1.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सहायता राशि प्रदान की है, जिनमें से लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजनाएं पूरी तरह से अनुदान-पोषित हैं, और अन्य रियायती वित्तपोषण के माध्यम से हैं। सितंबर 2018 में, रखाइन राज्य कृषि, पशुधन, वन और खदान मंत्रालय के लिए पंद्रह ट्रैक्टर, पंद्रह कटाई मशीनें और कम्प्यूटर अध्ययन विश्वविद्यालय, सिटवे को चालीस कम्प्यूटर सौंपने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए थे।

भारत सरकार ने रखाइन राज्य से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए म्यांमार सरकार की सहायता के लिए म्यांमार सरकार को पाँच वर्षों में 25 मिलियन अमरीकी डालर की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह सहायता पहले से ही विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन चरणों में प्रदान की जा रही है और विस्थापितों की जरूरतों को पूरा करने के लिए रखाइन राज्य में 250 पूर्वनिर्मित घरों का निर्माण किया जा रहा है।

भारत की प्रमुख कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना (केएमटीटीपी) पूरी तरह से अनुदान-प्राप्त है और पूरी परियोजना पर परिव्यय लगभग 484 मिलियन

अमरीकी डॉलर है। 22 अक्तूबर 2018 को भारत के विदेश सचिव की म्यांमार यात्रा के दौरान सिटवे पोर्ट के संचालन और रखरखाव, पलेतवा अंतर्देशीय जल टर्मिनल और इस परियोजना की संबद्ध सुविधाओं के लिए एक निजी पोर्ट ऑपरेटर की नियुक्ति हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना इस दिशा में एक सकारात्मक कदम था।

सिटवे में बंदरगाह के विकास, पलेतवा में अंतर्देशीय जल टर्मिनल (आईडब्ल्यूटी) और कलादान नदी चैनल में नौवहन सुविधाओं संबंधी कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। परियोजना के हिस्से के रूप में निर्मित 300 मीट्रिक टन क्षमता की छह नदी बाज भी म्यांमार प्राधिकारियों को सौंप दी गई हैं।

व्यापार

- म्यांमार के श्रम, आव्रजन और जनसंख्या मंत्रालय के अनुरोध पर, यूआईडीएआई द्वारा 29 और 30 अक्टूबर 2018 को आधार के बारे में ने पई ताव में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला का आयोजन म्यांमार के अनुरोध पर आधार-जैसा विशिष्ट पहचान पत्र तैयार करने के लिए म्यांमार की सहायता के लिए आयोजित किया गया था।
- यंगून में बौद्ध कॉन्क्लेव को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा एक रोड-शो का आयोजन किया गया था। जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी) ने 2 जुलाई 2018 को यंगून में रत्नों और आभूषणों पर एक रोड-शो का आयोजन किया ।
- अगस्त 2018 में यंगून में फार्मा और चिकित्सा उपकरणों की प्रदर्शनी, मेडेक्स में एक साठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया।

विकास सहयोग

- **आनंद मंदिर:** आनंद मंदिर का संरक्षण और जीर्णोद्वार, बागान का काम पूरा हो चुका है।
- **मोनवा** : 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर से लघु विकास परियोजना के तहत मोनवा में दो सौ बिस्तर वाला महिला अस्पताल स्थापित किया गया है।
- **सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम:** भारत-म्यांमार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में लगभग 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर वाले दूसरे वर्ष के परियोजना कार्य पूरे हो चुके हैं। लगभग 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर व्यय वाली तीसरे वर्ष की परियोजना प्रगति पर है और इसके वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूरा होने की संभावना है।
- **रिह-मिन्दात मार्ग पर माइक्रोवेव रेडियो लिंक:** टेलीकम्यूनिकेशन कन्सलटेंट इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) द्वारा रिह-मिन्दात मार्ग पर माइक्रोवेव रेडियो लिंक का कार्यान्वयन पूरा कर लिया गया है। भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त ऋण श्रृंखला के तहत टीसीआईएल द्वारा 6 मिलियन अमरीकी डॉलर की इस परियोजना का कार्यान्वयन किया गया।

रक्षा

भारत-म्यांमार रक्षा भागीदारी 2018 में और मजबूती आई। पर्याप्त उच्च-स्तरीय यात्राएं, सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्षमता निर्माण और स्थापित पारस्परिक संपर्क तंत्र जोशपूर्ण तरीके से चलते रहे। जबकि कार्यात्मक स्तर की सद्भावना यात्राएं नियमित रूप से जारी रही, 1 अप्रैल 2018 से निम्नलिखित महत्वपूर्ण यात्राएं की गई (कालानुक्रमिक क्रम में):

- म्यांमार रक्षा उद्योग के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल थीन हेटे ने अप्रैल 2018 में डैफएक्सपो इंडिया 2018 के लिए चेन्नई का दौरा किया। उन्होंने फिर से अगस्त 2018 में भारतीय रक्षा उद्योग से परिचित होने के लिए पुणे का दौरा किया।
- अगस्त 2018 में, म्यांमार सशस्त्र बल प्रशिक्षण के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मौंग ऐ ने भारतीय सेना के दोनों प्रमुख सैन्य प्रशिक्षण संस्थाओं, मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग (एमसीईएमई) और कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट (सीडीएम) का दौरा किया।
- वाइस-सीनियर जनरल सो विन, डिप्टी सी इन सी म्यांमार डिफेंस सर्विसेज और सी-इन-सी (आर्मी) ने सितंबर 2018 में बिम्सटेक आर्मी चीफ कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए दौरा किया और सद्भावना यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने कई प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों का दौरा करने के अलावा, रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मुलाकात की।

- सितंबर 2018 में वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ , पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, वीएम, एडीसी ने म्यांमार की सद्भावना यात्रा की। उन्होंने म्यांमार के सैन्य और नागरिक नेताओं के साथ बातचीत की।
- नेशनल डिफेंस कॉलेज (एनडीसी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने अगस्त 2018 में स्ट्रैटेजिक नेबरहुड स्टडी टूर के लिए म्यांमार का दौरा किया।
- कमांडेंट के नेतृत्व में म्यांमार एनडीसी के प्रतिनिधिमंडल ने नवंबर 2018 में भारत का दौरा किया।
- 26-28 नवंबर 2018 को वीसीएनएस के निमंत्रण पर म्यांमार के सीओएस नेवी वाइस एडमिरल मो ऑंग मिन ने भारत का दौरा किया।

सैन्य प्रशिक्षण

- आईटीईसी -1 के तहत लगभग 120 म्यांमार सैन्य प्रशिक्षुओं को भारतीय सैन्य प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में भेजा गया।
- म्यांमार सेना के अनुरोध पर उनकी आवश्यकतानुसार तैयार किए गए निम्नलिखित प्रशिक्षण प्रदान किए गए थे:
- अप्रैल 2018 में आर्मर्ड कॉर्प्स सेंटर एंड स्कूल (एसीसी एंड एस) अहमदनगर में एक कॉम्बैट टीम (65 व्यक्तियों) को दो सप्ताह के लिए प्रशिक्षित किया गया था।
- नवंबर-दिसंबर 2018 में काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल (सीआईजेडब्ल्यू) वैरांगटे में एक प्लाटून (35 व्यक्ति) चार सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
- भारतीय वायु सेना (आईएएफ) द्वारा म्यांमार वायु सेना (एमएएफ) के चयनित व्यक्तियों को एरोबैटिक उड़ान प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

संयुक्त अभ्यास: म्यांमार सेना की एक पलटन (पैंतीस व्यक्तियों) ने सितंबर 2018 में पुणे में बिम्सटेक मिलैक्स 2018 में भाग लिया। यह पहली बार है जब म्यांमार सेना ने एक संयुक्त या बहुपक्षीय अभ्यास में भाग लिया। म्यांमार सेना से एक वरिष्ठ पर्यवेक्षण दल और वाइस सीनियर जनरल सो विन ने मिलैक्स में शिरकत की।

संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा प्रशिक्षण: भारतीय सेना के एक दल ने अगस्त 2018 में म्यांमार सेना के लिए 5 वें संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा प्रशिक्षण कैप्सूल का आयोजन किया। भारतीय सेना प्रशिक्षण, किटिंग और दस्तावेज़ीकरण में परामर्श के मामले में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों के लिए म्यांमार सेना को उनकी तैयारी में लगातार सहायता कर रही है।

स्थापित तंत्रों के तहत पारस्परिक बातचीत

- भारतीय सेना और म्यांमार सेना के बीच 12 वीं क्षेत्रीय सीमा समिति (आरबीसी) की बैठक जून 2018 में म्यांमार के कलाय में हुई थी। भारतीय सेना के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जीओसी, 3 कोर और म्यांमार सेना के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उत्तर पश्चिम कमान के कमांडर ने किया।
- नवंबर 2018 में इंफाल के मंत्रीपुखरी में 13 वीं आरबीसी की बैठक हुई।
- अगस्त 2018 को तीसरी भारत-म्यांमार स्टाफ वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई।

क्षमता निर्माण और विविध सहायता

- भारतीय सेना द्वारा डिफेंस सर्विसेज अकादमी, पाइन ओ लोविन में चार अंग्रेजी भाषा प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई और जुलाई 2018 में इन्हें म्यांमार सेना को सौंप दिया गया।
- म्यांमार सशस्त्र बल अपने प्रशिक्षण के लिए सीडीआर7 वॉरगेमिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं जिसे 2013 में सीओएएस द्वारा उपहार में दिया गया था। म्यांमार सेना के अनुरोध पर, एक उन्नत संस्करण, जो म्यांमार की सैन्य आवश्यकताओं के लिए विशेष रूप से वारडेक द्वारा तैयार किया गया और सितंबर 2018 में वाइस सीनियर जनरल सो विन की भारत यात्रा के दौरान सीओएएस ने उन्हें उपहार में दिया गया था।
- अगस्त 2018 में म्यांमार सेना के अंगच्छेदन व्यक्तियों के लिए एक कृत्रिम अंग फिटमेंट शिविर का आयोजन किया गया था। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (बीएमवीएसएस) की तकनीकी टीम द्वारा 102 अंग लगाए गए थे।

नौसेना सहयोग

समन्वित गश्त, मार्ग अभ्यास, मिलन-2018 में म्यांमार नौसेना की भागीदारी और नियमित पोर्ट कॉल के संदर्भ में 2018 में दोनों नौसेनाओं के बीच अच्छी परिचालन भागीदारी रही। प्रशिक्षण, यात्राओं, सी-राइडर कार्यक्रम और हाइड्रोग्राफी के क्षेत्रों में एक बेहतर संपर्क और सहयोग भी बना रहा।

संस्थागत तंत्र: नौसेना की नौसेना कर्मचारियों से 7 वीं वार्ता 10 से 12 अक्तूबर 2018 तक नई दिल्ली में हुई। दोनों नौसेनाओं के बीच समन्वित गश्त (कॉर्पेट) की आवृत्ति को 2018 से दो चक्र तक कर दिया गया था (प्रति वर्ष एक चक्र की तुलना में)। छठां कॉर्पेट 14-18 मार्च 2018 और 7 वां कॉर्पेट 24-29 सितंबर 2018 तक आयोजित किया गया। इसके अलावा, 7वें कॉर्पेट में दोनों तरफ से पहली बार मैरीटाइम पैट्रोल एयरक्राफ्ट की भागीदारी हुई, जिसने गश्ती क्षेत्र का स्वैथ बढ़ गया है और इसने चल रही प्रणाली में एक नया आयाम भी जोड़ा है।

सहायता संबंधित परियोजनाएं: सितंबर 2017 में म्यांमार को तटीय निगरानी प्रणाली की आपूर्ति संबंधी तकनीकी करार पर हस्ताक्षर के पश्चात म्यांमार के सभी दूरस्थ स्थानों का साइट सर्वेक्षण पूरा हो गया है और कार्यक्षेत्र मैसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा म्यांमार नौसेना कार्मिकों के साथ कार्यक्षेत्र तैयार कर लिया गया है। यह परियोजना पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इस पर 2019 की शुरुआत में काम शुरू हो जाएगा। यह समुद्री सुरक्षा सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन के अनुसार है, जिस पर सितंबर 2017 में दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए थे।

नेपाल

उच्च स्तरीय राजनीतिक आदान-प्रदान की एक श्रृंखला के साथ 2018-19 में गहन द्विपक्षीय बातचीत जारी रही। कार्यात्मक स्तर पर कई द्विपक्षीय तंत्रों की बैठकें जारी रहीं जिनमें आर्थिक और विकास सहयोग, जल संसाधन, संस्कृति, बिजली सहयोग, रक्षा और सुरक्षा, और कनेक्टिविटी परियोजनाओं जैसे मुद्दे शामिल थे।

भारत के प्रधान मंत्री के निमंत्रण पर, नेपाल के प्रधान मंत्री के.पी. शर्मा ओली ने 6-8 अप्रैल, 2018 तक भारत की राजकीय यात्रा की। उनके साथ उनकी पत्नी सुश्री राधिका शाक्य, श्री प्रदीप कुमार ग्यावली, विदेश मामलों के मंत्री, श्री मत्रिका प्रसाद यादव, उद्योग और वाणिज्य मंत्री, श्री रघुबीर महासेठ , भौतिक अवसंरचना तथा परिवहन मंत्री थे। यात्रा के दौरान, दोनों प्रधानमंत्रियों ने बीरगंज (नेपाल) में एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया और मोतिहारी, भारत के

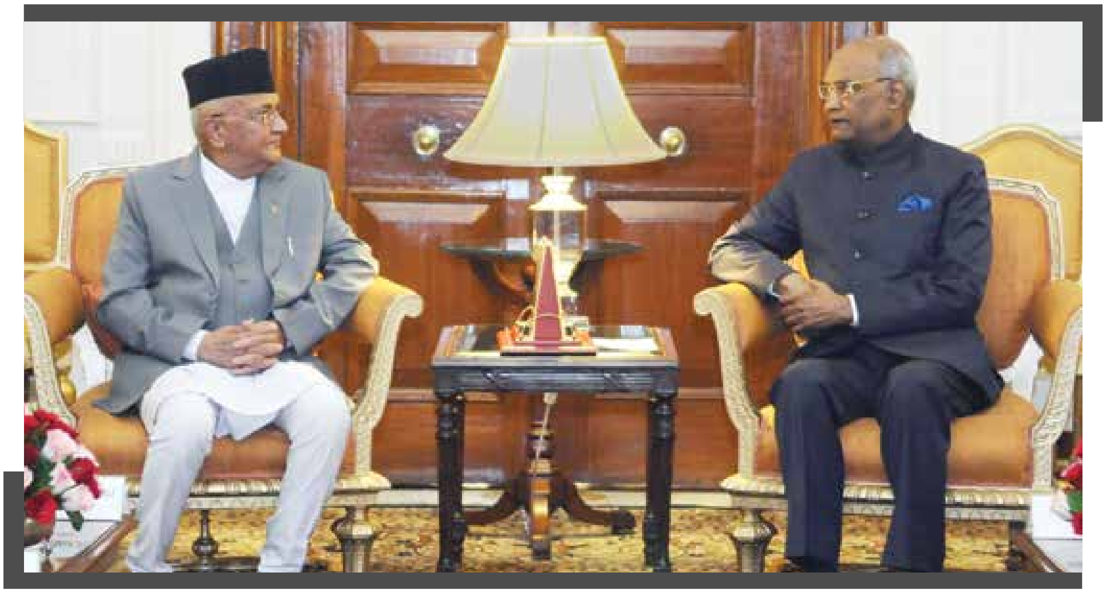

राष्ट्रपति नई दिल्ली में नेपाल के प्रधानमंत्री श्री के.पी. शर्मा औली के साथ मुलाकात करते हुए (07 अप्रैल, 2018)

मोतिहारी-अमलेखगंज पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाए जाने से संबंधित भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। तीन अलग-अलग संयुक्त वक्तव्य; (i) भारत-नेपाल: कृषि में नई भागीदारी; (ii) रेल संपर्क का विस्तार: भारत में रक्सौल को नेपाल में काठमांडू से जोड़ा जाना; और (iii) भारत और नेपाल के बीच अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से नई कनेक्टिविटी संबंधी वक्तव्य जारी किए गए।

नेपाल से चौदह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बिजली क्षेत्र में सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह और संयुक्त संचालन समिति (जेएससी) की 5वीं बैठक में भाग लिया, जो क्रमशः 16 और 17 अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। जेएससी की सह-अध्यक्षता सचिव, ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार और नेपाली पक्ष के ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्रालय के सचिव द्वारा की गई थी।

भारत-नेपाल संयुक्त समिति की बाढ़ और बाढ़ प्रबंधन पर 12वीं बैठक 16-20 अप्रैल, 2018 तक नेपाल में आयोजित की गई थी। बाढ़ और बाढ़ प्रबंधन संबंधी भारत और नेपाल संयुक्त समिति की उप-समूह ने जून, 2018 में भारत-नेपाल सीमा पर बाढ़ और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का संयुक्त निरीक्षण किया।

अनाधिकृत व्यापार को रोकने के लिए व्यापार, पारगमन तथा सहयोग संबंधी भारत-नेपाल अंतर-सरकारी उप-समिति और अंतर-सरकारी समिति (आईजीसी) की बैठकें काठमांडू में क्रमशः 24-25 अप्रैल और 26-27 अप्रैल, 2018 तक आयोजित की गई थी। आईजीसी की सह-अध्यक्षता नेपाल की ओर से सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय द्वारा और भारत की ओर से वाणिज्य सचिव द्वारा की गई।

पंचेश्वर विकास प्राधिकरण के शासी निकाय की छठी बैठक काठमांडू में 26 अप्रैल, 2018 को आयोजित की गई थी। बैठक में जल संसाधन मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में भारत के एक प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया।

नेपाल के प्रधान मंत्री के निमंत्रण पर, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 11 और 12 मई, 2018 को नेपाल की राजकीय यात्रा की। उन्होंने नेपाल में जनकपुर, काठमांडू और मुक्तिनाथ का दौरा किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से नेपाल में 900 मेगावाट की अरुण-III पनबिजली परियोजना की आधारशिला रखी।

30 मई -12 जून, 2018 तक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत-नेपाल सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास के 300वें संस्करण में नेपाल के 300 सैन्यकर्मियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया।

नेपाल के सेनाध्यक्ष जनरल राजेंद्र छेत्री 6-11 जून, 2018 तक भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में पासिंग आउट परेड के समीक्षा अधिकारी के रूप में भारत आए। उन्होंने विभिन्न सैन्य प्रतिष्ठानों का भी दौरा किया और यात्रा के दौरान भारत के रक्षा मंत्री और थल सेना के प्रमुखों से मुलाकात की।

नेपाल के कृषि, भूमि प्रबंधन और सहकारिता मंत्रालय के दो प्रतिनिधियों ने सिक्किम ऑर्गेनिक मिशन, सिक्किम का 10-13 जून, 2018 तक और जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर का 17-18 जून 2018 तक दौरा किया।

भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री राधामोहन सिंह और नेपाल के कृषि, भूमि प्रबंधन और सहकारिता मंत्री श्री चक्र पाणिखनाल के बीच भारत-नेपाल 'कृषि में नई साझेदारी' की उद्घाटन बैठक जून 2018 में नई दिल्ली में आयोजित की गई।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने काठमांडू में 14 और 15 जून, 2018 को नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के प्रतिनिधियों के साथ तकनीकी चर्चा की। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के एक प्रतिनिधिमंडल ने 11 और 12 अक्टूबर, 2018 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ संयुक्त तकनीकी दल की बैठक के लिए भारत का दौरा किया।

भारत-नेपाल सर्वेक्षण अधिकारी समिति की आठवीं बैठक 17-19 जून, 2018 को काठमांडू में आयोजित की गई थी। भारत-नेपाल सीमा कार्य समूह की 5वीं बैठक 19-21 सितंबर, 2018 तक काठमांडू में आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत के सर्वेयर जनरल ने किया और नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नेपाल के सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक ने किया। भारत-नेपाल सर्वेक्षण अधिकारियों की समिति की 9वीं बैठक 11-13 अक्टूबर, 2018 को देहरादून में आयोजित की गई थी।

चरण- I के तहत भारत-नेपाल सीमा पार रेल संपर्क के संचालन पर संयुक्त समिति की तीसरी बैठक काठमांडू में हुई और 19 और 20 जून, 2018 को जयनगर-कुर्था के लिए परियोजना स्थल का दौरा किया।

भारत-नेपाल ऊर्जा आदान-प्रदान समिति की 12वीं बैठक 5 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। नेपाल के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में, नेपाल विद्युत प्राधिकरण ने नई दिल्ली का दौरा किया।

पर्यटन सहयोग पर भारत-नेपाल संयुक्त कार्यदल की दूसरी बैठक 6 जुलाई, 2018 को काठमांडू में आयोजित की गई थी।

परियोजना संचालन समिति की 6ठी बैठक 9 जुलाई, 2018 को काठमांडू में आयोजित की गई थी। भारत-नेपाल सीमा पार रेल संपर्क पर संयुक्त कार्यदल की तीसरी बैठक 10 जुलाई, 2018 को काठमांडू में आयोजित की गई थी।

नेपाल सरकार को भारत सरकार द्वारा दी गई ऋण श्रृंखलाओं के तहत की जा रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए परियोजना समीक्षा बैठक 11 जुलाई, 2018 को काठमांडू में आयोजित की गई थी।

भारत-नेपाल निगरानी तंत्र की 6ठी बैठक 18 जुलाई, 2018 को काठमांडू में आयोजित की गई थी। बैठक की सह-अध्यक्षता नेपाल में भारत के राजदूत और नेपाल के विदेश सचिव द्वारा की गई थी।

भारत-नेपाल सीमा पार परिवहन सुविधा संबंधी संयुक्त कार्य समूह की तीसरी बैठक 20 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

बीपी कोइराला इंडिया-नेपाल फाउंडेशन ने अपनी 34वीं बोर्ड बैठक 21 जुलाई, 2018 को गंगटोक, सिक्किम में आयोजित की। बैठक की सह-अध्यक्षता नेपाल में भारत के राजदूत और नेपाल के प्रभारी राजदूत द्वारा की गई थी।

भारत-नेपाल व्यापार संधि की व्यापक समीक्षा करने हेतु पहली बैठक के लिए नेपाल के एक प्रतिनिधिमंडल ने 9 अगस्त, 2018 को भारत का दौरा किया। नेपाल के महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल और आईजी, सशस्त्र पुलिस बल, नेपाल के बीच तीसरी समन्वय बैठक 7-10 अगस्त, 2018 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई। 7वीं भारत-नेपाल संयुक्त कृषि कार्य समूह की बैठक 16-17 अगस्त, 2018 को काठमांडू में आयोजित की गई थी। नेपाल के उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्री श्री मत्रिका प्रसाद यादव ने 27-30 अगस्त, 2018 तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक में शामिल होने के लिए भारत का दौरा किया।

भारत और नेपाल के प्रधानमंत्रियों ने काठमांडू में बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (बिम्सटेक) शिखर सम्मेलन के लिए चौथी बंगाल की खाड़ी पहल के दौरान 31 अगस्त 2018 को एक द्विपक्षीय बैठक की। यात्रा के दौरान रक्सौल (भारत) और काठमांडू (नेपाल) के बीच रेल लाइन के प्रारंभिक सर्वेक्षण के संबंध में समझौता ज्ञापन पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए। दोनों प्रधानमंत्रियों ने काठमांडू में 400 बिस्तरों वाली नेपाल-भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला का उद्घाटन किया, जिसका निर्माण भारत सरकार की सहायता से किया गया था।

सड़क परिवहन और राजमार्ग, नौवहन, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख एल. मंडाविया ने नेपाल के भौतिक अवसंरचना और परिवहन मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए 2-5 सितंबर 2018 को नेपाल की आधिकारिक यात्रा की।

नेपाल के पूर्व प्रधान मंत्री और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सह-अध्यक्ष, पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' ने 6-9 सितंबर 2018 तक भारत का दौरा किया और 7 सितंबर 2018 को विश्व मामलों की भारतीय परिषद में 31 वां सप्रू हाउस व्याख्यान दिया।

बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 11 सितंबर 2018 को बोधगया-पटना-काठमांडू और पटना-जनकपुर मार्गों पर दो शुरुआती भारत-नेपाल बस सेवाओं की शुरूआत की गई। नेपाली पक्ष की ओर से, भौतिक अवसंरचना और परिवहन मंत्री ने 13 सितंबर 2018 को काठमांडू-पटना-बोधगया मार्ग पर शुरुआती बस सेवा का शुभारंभ किया और नेपाल के प्रांत 2 के मुख्यमंत्री ने 16 सितंबर 2018 को जनकपुर-पटना मार्ग पर शुरुआती बस सेवा को रवाना किया।

भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की जल विकास मार्ग परियोजना का अध्ययन करने के लिए 17-21 सितंबर 2018 तक नेपाल से एक तकनीकी संभावना मिशन ने वाराणसी और कोलकाता का दौरा किया। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉ. राजीव कुमार ने 20-21 सितंबर 2018 तक काठमांडू का दौरा किया। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 28-29 सितंबर 2018 को नेपाल की आधिकारिक यात्रा की। उन्होंने नेपाल के उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

नेपाल की जल आपूर्ति मंत्री, सुश्री बीना मागर ने 29 सितंबर - 2 अक्टूबर 2018 तक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता

सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली का दौरा किया। यात्रा के दौरान, नेपाली जल आपूर्ति मंत्री ने पेयजल और स्वच्छता मंत्री से मुलाकात की।

19-20 नवंबर, 2018 को काठमांडू में सीमा शुल्क सहयोग पर 19 वीं भारत-नेपाल डीजी स्तर की वार्ता हुई। बैठक की सह-अध्यक्षता महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, भारत सरकार और महानिदेशक, सीमा शुल्क विभाग, नेपाल सरकार द्वारा की गई थी।

भारत-नेपाल सीमा के साथ लगे क्षेत्रों का दूसरा संयुक्त निरीक्षण 19-23 नवंबर 2018 तक बाढ़ और बाढ़ प्रबंधन संबंधी संयुक्त समिति(जेसीआईएफएम) के उप-समूह द्वारा किया गया था।

भारतीय राजदूतावास, काठमांडू ने 22 नवंबर 2018 को आईटीईसी दिवस और मौलाना आज़ाद दिवस मनाया। शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री गिरिराज मणि पोखरेल मुख्य अतिथि थे। इस समारोह में 150 से अधिक आईटीईसी पूर्व छात्रों ने भाग लिया।

कोसी गंडक परियोजना पर भारत-नेपाल संयुक्त समिति की नौवीं बैठक 28 और 29 नवंबर, 2018 को काठमांडू में आयोजित की गई थी। बैठक की सह-अध्यक्षता जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के प्रधान सचिव और नेपाल सरकार के सिंचाई और जल संसाधन विभाग के महानिदेशक ने की।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 दिसंबर 2018 को बिबाह पंचमी पर्व में भाग लेने के लिए जनकपुर की यात्रा की। सुरक्षा मामलों संबंधी भारत-नेपाल द्विपक्षीय सलाहकार समूह की 13 वीं बैठक 14 दिसंबर 2018 को काठमांडू में आयोजित की गयी।

नेपाल सरकार के संघीय मामलों और सामान्य प्रशासन मंत्री, श्री लालबाबू पंडित के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत की संघीय प्रणाली को समझने के लिए भारत की आधिकारिक यात्रा की। नेपाल के मंत्री ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री और अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग से मुलाकात की; और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में एक कार्यशाला में भाग लिया।

26 दिसंबर 2018 को आयोजित भारत-नेपाल ऊर्जा विनिमय समिति की 13 वीं बैठक में भाग लेने के लिए नेपाल विद्युत प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में नेपाल के एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली की यात्रा की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के सदस्य (पावर सिस्टम) ने किया था।

नेपाल के युवा और खेल मंत्री श्री जगत बहादुर सुनार (बिस्वकर्मा) 8-11 दिसंबर 2018 के दौरान भारत आए।

नेपाल के विदेश मंत्री, प्रदीप कुमार ग्यावली, रायसीना डायलॉग 2019 के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए 10 और 11 जनवरी 2019 को नई दिल्ली आए। इस यात्रा के दौरान नेपाल के विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज से मुलाकात की।

नई दिल्ली में 11 जनवरी 2019 को जल संसाधन संबंधी संयुक्त समिति की सचिव-स्तरीय बैठक हुई। संयुक्त स्थायी तकनीकी समिति की बैठक का आयोजन नई दिल्ली में 9 और 10 जनवरी 2019 को किया गया।

नेपाल सेना के सेनाध्यक्ष 11-16 जनवरी 2019 तक भारत का दौरा करेंगे। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया जाएगा। जी2जी व्यवस्था के तहत उर्वरकों की आपूर्ति संबंधी समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने के लिए 14 और 15 जनवरी 2019 को काठमांडू में एक बैठक आयोजित की गई।

बिजली क्षेत्र में सहयोग पर भारत-नेपाल संयुक्त संचालन समिति (जेएससी) और संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की छठीं बैठक 23 और 24 जनवरी 2019 को नेपाल के पोखरा में आयोजित की गई।

पुनर्निर्माण संबंधी संयुक्त परियोजना निगरानी समिति की बैठक 28 जनवरी 2019 को काठमांडू में आयोजित की गई। काठमांडू में गृह सचिव स्तरीय वार्ताएं 7-8 मार्च 2019 के लिए निर्धारित है।

क्षेत्रीय सहयोग

भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी 30 और 31 अगस्त 2018 को चौथें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए काठमांडू गए थे। शिखर सम्मेलन से पहले 29 अगस्त 2018 को 16 वीं विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने भाग लिया। प्रधान मंत्री ने द्विपक्षीय चर्चा के लिए शिखर सम्मेलन के दौरान अपने नेपाली समकक्ष से मुलाकात की।

नेपाल के उप प्रधान मंत्री और स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्री, श्री उपेन्द्र यादव डब्ल्यूएचओ पार्टनर्स फोरम 2018 में भाग

लेने के लिए 11-14 दिसंबर 2018 के दौरान भारत आए।

नेपाल के राजस्व अन्वेषण विभाग के महानिदेशक ने नई दिल्ली में 4 और 5 दिसंबर 2018 को भारत के राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा आयोजित 5 वीं क्षेत्रीय सीमा शुल्क प्रवर्तन बैठक में भाग लिया।

15 से 16 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल एविएशन शिखर सम्मेलन में नेपाल के संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री रवीन्द्र प्रसाद अधिकारी भाग लेंगे।

पाकिस्तान

पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों के प्रति भारत का दृष्टिकोण शिमला समझौते और लाहौर घोषणा के आधार पर हिंसा और आतंक से मुक्त माहौल में सामान्य पड़ोसी संबंधों को बनाए रखने के लिए दृढ़ नीति द्वारा लगातार निर्देशित हो रहा है।

पाकिस्तान में 25 जुलाई को हुए आम चुनावों के बाद जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई को श्री इमरान खान से वार्ता की और उन्हें जीत की बधाई दी और भारतीय उपमहाद्वीप में शांति, सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करने, और इसे आतंक और हिंसा से मुक्त बनाने और विकास पर ध्यान केंद्रित करने की भारत की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी 18 अगस्त को प्रधान मंत्री इमरान खान को पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने उन्हें प्रधान मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए बधाई दी, क्षेत्र के लोगों के लाभ के लिए शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने और पाकिस्तान के साथ सार्थक और रचनात्मक भागीदारी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 22 अगस्त को पाकिस्तान के विदेश मंत्री एसएम कुरैशी को पत्र लिखा और उन्हें ऐसी ही भावनाओं से अवगत कराया।

14 सितंबर 2018 को, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने भारत के प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ न्यूयॉर्क में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच एक बैठक का प्रस्ताव था । पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के पत्र में आतंकवाद पर चर्चा के लिए तत्परता के साथ-साथ एक सकारात्मक परिवर्तन और शांति की पारस्परिक इच्छा की बात कही गई। इसके बाद 17 सितंबर 2018 को पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री को पत्र लिखा। 20 सितंबर 2018, को पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के पत्र में परिलक्षित भावना के जवाब में भारत न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच एक बैठक के लिए सहमत हो गया।हालांकि, घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर, पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों द्वारा जम्मू और कश्मीर के तीन पुलिस कर्मियों का अपहरण कर लिया गया और उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। एक और विचलित कर देने वाला घटनाक्रम पाकिस्तान की सरकार द्वारा जारी किए गए डाक टिकट के माध्यम से आतंकवादियों और भारत के खिलाफ आतंकवाद के महिमामंडन की खबर का आना था। इससे नए सिरे से बातचीत करने के पाकिस्तान के प्रस्ताव के पीछे छिपे बुरे एजेंडे को उजागर कर दिया। यह आकलन किया गया था कि ऐसे माहौल में पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत निरर्थक होगी। भारत के पास न्यूयॉर्क में भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।

पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में भारत द्वारा 'मानवाधिकार उल्लंघन' की झूठी अफवाह फैलाकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बदनाम करने का अपना एजेंडा जारी रखा। पहले की तरह, पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए यूएनजीए का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री एसएम कुरैशी ने भी भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी की। पाकिस्तान ने भारत में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप कई सुरक्षाकर्मी और निर्दोष नागरिक मारे गए। पाकिस्तान ने भारत में अलगाववादी प्रवृत्तियों का समर्थन करके भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना जारी रखा। एक नियमित अभ्यास के रूप में तथाकथित खालिस्तान आंदोलन का समर्थन करने वाले पोस्टर गुरुद्वारों के अंदर देखे गए थे। पाकिस्तान में भारतीय सिख तीर्थ यात्रियों की यात्राओं के दौरान पाकिस्तानी नेताओं द्वारा भारत विरोधी भाषण दिए गए। पाकिस्तान ने कई मौकों पर भारतीय उच्चायुक्त सहित भारतीय उच्चायोग के प्रतिनिधियों को भारतीय सिख तीर्थयात्रियों से मिलने से रोका। हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन जैसे अंतरराष्ट्रीय

स्तर पर कुख्यात आतंकवादी पाकिस्तान में स्वतंत्र रूप से सक्रिय हैं और भारत विरोधी बयान देते रहते हैं।

पाकिस्तान में पठानकोट आतंकी हमले के मामले में जांच और मुंबई आतंकी हमले की सुनवाई में प्रगति न होना गंभीर चिंता का विषय है। 26 नवंबर 2018 को 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले की 10 वीं वर्षगांठ पर मुंबई में पुलिस मेमोरियल और ताज होटल, मुंबई में एक पवित्र स्मारक कार्यक्रम और पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने राज्य के अन्य गणमान्य व्यक्तियों और राजनयिक कोर के सदस्यों के साथ इन आयोजनों में भाग लिया। अमेरिका, जापान, फ्रांस, मॉरीशस सहित उन अन्य देशों द्वारा बयान जारी किए गए थे, जिनके नागरिक मुंबई आतंकवादी हमलों में मारे गए थे। उन सभी ने आतंकवाद की निंदा की और अपराधियों को सजा दिलाने की मांग की।

इस अवधि के दौरान द्विपक्षीय भागीदारी कार्यात्मक स्तर पर जारी रही। भारत-पाकिस्तान स्थायी सिंधु आयोग की 115 वीं बैठक 29 और 30 अगस्त को लाहौर में आयोजित की गई थी। टेलीफोन पर डीजीएमओ की वार्ता 29 मई 2018 को हुई, जहां 2003 के संघर्ष विराम समझौते का पालन करने का निर्णय लिया गया। 27-30 मई 2018 को दिल्ली में भारतीय तटरक्षक और पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी के बीच एक बैठक हुई। बैठक में एक-दूसरे के मछुआरों की रिहाई और प्रत्यावर्तन के लिए प्रक्रियाओं को उदार बनाने और समुद्री खोज और बचाव कार्यों के समन्वय के साथ-साथ समुद्री पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए काम करने के उपायों पर चर्चा की गई।

पाकिस्तान के तत्कालीन कानून और सूचना मंत्री सैयद अली जफर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल 17 अगस्त 2018 को दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दिल्ली आया था। श्री सैयद अली जफर ने दिल्ली में विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के साथ बैठक की ।

1 जनवरी 2019 को,भारत ने भारत की हिरासत में 249 पाकिस्तानी नागरिक कैदियों और अठानवे मछुआरों की सूची पाकिस्तान को सौंप दी। पाकिस्तान ने उनकी हिरासत में चौवन असैनिक कैदियों और 483 मछुआरों की सूची साझा की, जो भारतीय हैं या माना जाता है कि वे भारतीय हैं। 2018 में ही, पाकिस्तान द्वारा 174 मछुआरों सहित 179 भारतीय कैदियों को रिहा और प्रत्यावर्तित किया गया, जबकि अड़तालीस मछुआरों सहित पैंसठ पाकिस्तानी कैदियों को भारत द्वारा रिहा किया गया।

1 जनवरी 2019 को, भारत और पाकिस्तान ने भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले के निषेध संबंधी समझौते के तहत शामिल परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान-प्रदान किया। दोनों देशों के बीच इस तरह की सूची का यह लगातार अट्ठाइसवां आदान-प्रदान है, जिसमें से पहला 1 जनवरी 1992 को हुआ था।

मानवीय प्रयासों के तहत, अप्रैल-नवंबर 2018 के दौरान भारत ने सैंतालीस पाकिस्तानी कैदियों और मछुआरों को रिहा कर दिया और पाकिस्तान ने बत्तीस भारतीय कैदियों और मछुआरों को रिहा कर दिया। भारत सरकार ने 22 नवंबर को भारत की ओर 'करतारपुर कॉरिडोर' बनाने की अपनी पहल के बारे में पाकिस्तान सरकार को सूचित किया और पाकिस्तान से उनके क्षेत्र में उपयुक्त सुविधाओं के साथ एक गलियारा बनाने का आग्रह किया।भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने 26 नवंबर को गुरदासपुर में परियोजना का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इमरान खान ने 28 नवंबर को पाकिस्तान के 'करतारपुर कॉरिडोर' के हिस्से का भूमि पूजन किया। श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री) और श्री हरदीप सिंह पुरी (केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार) ने इस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसे एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में देखा गया था, जो भारत के सिख तीर्थयात्रियों के लिए करतारपुर साहिब श्रद्धेय तीर्थ की यात्रा को सुविधाजनक बनाएगा।

2017-18 के लिए द्विपक्षीय व्यापार 2.41 बिलियन अमरीकी डॉलर था जबकि 2016-17 के लिए 2.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

सेशेल्स

सेशेल्स के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध ऐतिहासिक संपर्कों और सेशेल्स की सुरक्षा के लिए उसे निरंतर समर्थन के रूप में विकसित हुआ है, हालांकि हमारा द्विपक्षीय व्यापार अभी मामूली सा है। आज, भारत-सेशेल्स संबंध एक विशेष संबंध

प्रधानमंत्री हैदराबाद हाऊस, नई दिल्ली में सेशेल्स के राष्ट्रपति श्री डैनी एनट्वान रॉलेन फौरे के साथ मुलाकात करते हुए (25 जून, 2018)

द्वारा चिन्हित है जो पारस्परिक विश्वास, विशाल सद्भावना और साझा मूल्यों की नींव पर तैयार किए गए हैं।

22-27 जून, 2018 से भारत में सेशेल्स के राष्ट्रपति डैनी फॉरे के पहले राजकीय दौरे से द्विपक्षीय संबंधों में गहनता आई है। राष्ट्रपति फौरे ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू और विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के साथ द्विपक्षीय बैठक की। राष्ट्रपति श्री डैनी फॉरे ने नई दिल्ली में अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों के अलावा गुजरात, गोवा और उत्तराखंड राज्यों का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान भारत ने सेशेल्स को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत वाला दूसरा डोर्नियर -228 विमान उपहारस्वरूप दिया और 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रक्षा ऋण श्रृंखला प्रदान की। हैदराबाद चिड़ियाघर को सेशेल्स द्वारा एल्ड्रा कछुओं के उपहार की बहुत सराहना की गई।

इस राजकीय यात्रा के दौरान छह करारों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें व्हाइट शिपिंग डेटा करार, साइबरसिटी पर एक समझौता ज्ञापन, लघु विकास परियोजनाओं पर एक समझौता ज्ञापन, विदेशी सेवा संस्थान भारत और सेशेल्स के विदेश विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन वर्ष 2018-2022 के लिए एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और पनाजी शहर के निगम और सेशेल्स गणराज्य के विक्टोरिया शहर के बीच एक ट्विनिंग समझौता शामिल है ।

सेशेल्स की 13 उल्लेखनीय यात्राओं में चेन्नई में डेफएक्सपो (11 अप्रैल, 2018) में शामिल होने के लिए गृह, स्थानीय सरकार, युवा, खेल, संस्कृति, और जोखिम और आपदा प्रबंधन (नामित मंत्री) मंत्री श्रीमती मैकसूज़ी मोंडन की यात्रा नई दिल्ली (2-4 अक्टूबर, 2018) में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की महासभा में भाग लेने के लिए पर्यावरण, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री वालेस कॉस्ग्रो की यात्रा, और सेशेल्स में कृषि के क्षेत्र में क्षमता वृद्धि के अवसरों का पता लगाने के लिए और श्री चार्ल्स बैस्टिएन, मत्स्य पालन मंत्री की तेलंगाना (23-25 अक्टूबर, 2018) यात्रा शामिल है।

भारत और सेशल्स के बीच वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक सहयोग बैठक (जेसीएम) पर संयुक्त आयोग का 9वाँ सत्र 14-15 मई, 2018 को भारत के विदेश सचिव श्री विजय गोखले और सेशेल्स के विदेश राज्य सचिव श्री बैरी फ्योर की सह-अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। विदेश सचिव ने इस यात्रा के दौरान सेशेल्स के राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय परामर्श भी किया।

भारत-सेशेल्स संयुक्त समिति की हाइड्रोग्राफी पर पहली बैठक 14-15 जून 2018 को सेशेल्स में हुई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर ने

किया था। इस अवधि के दौरान भारत सरकार की सहायता के तहत तटीय निगरानी रडार प्रणाली के लिए वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी) पर 18 मई, 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे। निम्नलिखित जहाजों ने सेशेल्स की सद्भावना यात्राएं की: आईसीजीएस शूर (16-19 अप्रैल 2018), आईएनएस मुंबई और आईएनएस त्रिकंड (21-24 अप्रैल 2018), आईएनएस तरकश (26-30 जून 2018) और आईएनएस महादेई और आईएनएस तारिणी (26 नवंबर - 3 दिसंबर 2018)।

2018-19 में भारत द्वारा सेशेल्स को दी गई विकासात्मक सहायता में अन्य चीजों के साथ-साथ सामाजिक और भौतिक अवसंरचना परियोजनाओं के विकास, चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति, सेशेल्स सार्वजनिक परिवहन निगम (एसपीटीसी) के लिए बसें और स्वास्थ्य देखभाल के लिए एम्बुलेंस शामिल हैं। सेशेल्स में भारत की पहली निर्माण परियोजना, 3.45 मिलियन अमरीकी डॉलर (एससीआर 45 मिलियन) की लागत वाले मजिस्ट्रेट कोर्ट हाउस का शिलान्यास औपचारिक रूप से, 28 सितंबर 2018 को किया गया था।

इस वर्ष के दौरान पुलिसिंग, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, नवीकरणीय ऊर्जा, आदि सहित कई प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के प्रयासों को परिपूर्ण किया गया था। हाल का केन्द्र बिन्दु सेशेल्स में चल रही परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन पर रहा है। राष्ट्रपति श्री डैनी फॉरे ने भारत द्वारा वित्तपोषित सभी परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारत-सेशेल्स परियोजना संचालन समिति का गठन किया।

श्री लंका

श्रीलंका के साथ भारत के संबंध सकारात्मक बने रहे और इस वर्ष के दौरान इन्हें और मजबूत किया गया। द्विपक्षीय संबंधों को उच्चतम राजनीतिक स्तर पर निकट संपर्क, व्यापार और निवेश में वृद्धि, शिक्षा, संस्कृति, अवसंरचना विकास, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, कौशल विकास और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग द्वारा चिह्नित किया गया है। हाल के वर्षों में जनता-उन्मुख विकासात्मक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है जिससे दोनों लोगों के बीच मित्रवत् संबंधों को बढ़ाने में मदद मिली है।

दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय यात्राएं हुई हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्री रानिल विक्रमसिंघे ने 18-20 अक्टूबर 2018 तक भारत की आधिकारिक यात्रा की। पूर्व राष्ट्रपति श्री महिंदा राजपक्षे ने एक निजी कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए 10-13 सितंबर, 2018 तक नई

प्रधानमंत्री हैदराबाद हाऊस, नई दिल्ली में श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्री रानिल विक्रमसिंघे के साथ मुलाकात करते हुए (20 अक्टूबर, 2018)

दिल्ली का दौरा किया। श्रीलंका के स्पीकर श्री कारू जयसूर्या ने सितंबर 2018 में भारत में एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारत से अन्य सदस्यों सहित, लोकसभा अध्यक्ष ने 11 और 12 जुलाई 2018 को सतत विकास लक्ष्यों पर दूसरे दक्षिण एशियाई वक्ताओं के शिखर सम्मेलन के लिए श्रीलंका का दौरा किया।

श्रीलंका भारत सरकार से सबसे अधिक विकास सहायता प्राप्त करने वालों में से एक है। भारत की समग्र प्रतिबद्धता 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब है, जिसमें से लगभग 550 मिलियन अमेरिकी डॉलर पूर्णतः अनुदान हैं। युद्ध प्रभावितों के साथ-साथ बागान क्षेत्रों में संपत्ति के श्रमिकों के लिए 50,000 घरों के निर्माण की प्रारंभिक प्रतिबद्धता के साथ भारतीय आवास परियोजना भारत सरकार (जीओआई) की श्रीलंका को विकासात्मक सहायता की प्रमुख परियोजना है। अब तक, उत्तरी और पूर्वी प्रांतों के सभी प्रतिबद्ध 46,000 घरों को पूरा कर लिया गया है। केंद्रीय और यूवा प्रांत में निर्माणाधीन शेष 4,000 घरों में से, एक अभिनव सामुदायिक-संचालित दृष्टिकोण के माध्यम से संपत्ति श्रमिकों के लिए करीब 1000 घरों का कार्य पूरा कर लिया गया है। 12 अगस्त, 2018 को प्रधान मंत्री श्री रानिल विक्रमसिंघे द्वारा आयोजित एक समारोह में बागान क्षेत्रों में निर्मित इन घरों में से अधिकांश को सौंप दिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश के माध्यम से शामिल हुए।उस समय, मई 2017 में अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 10,000 अतिरिक्त घरों का निर्माण शुरू करने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके साथ श्रीलंका में घर बनाने की भारत की कुल प्रतिबद्धता 60,000 घरों की है।

आवास के अलावा भारत ने अनुदान सहायता के तहत देश भर में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन संपर्क, लघु और मध्यम उद्यम विकास और प्रशिक्षण के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लघु विकास परियोजनाओं (एसडीपी) की सहायता करना जारी रखा। इस वर्ष के दौरान पूरी की गई परियोजनाओं में हंबनटोटा में मत्स्य पालन और कृषक समुदाय के लगभग 70,000 लोगों को आजीविका सहायता का प्रावधान, ववुनिया अस्पताल को चिकित्सा उपकरण की आपूर्ति और मुल्लाथिवु मछुआरों के लिए 150 नाव और मत्स्य पालन गियर शामिल हैं। श्रीलंका के विश्वविद्यालयों में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मातार में रुहुना विश्वविद्यालय में श्री रवींद्रनाथ टैगोर के नाम पर एक आधुनिक 1500 सीट का सभागार को भी अक्टूबर 2018 में श्रीलंका को सौंपा गया था।

अनुराधापुरा में सोबिता थेरो गांव में 153 घरों के निर्माण पर काम, कैंडी में पुसलावा में सरस्वती सेंट्रल कॉलेज का उन्नयन; श्रीलंका के 25 जिलों में मॉडल विलेज हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत 600 घरों का निर्माण और श्रीलंका के दक्षिणी प्रांत में 600 घरों के निर्माण के लिए ग्राम-शक्ति हाउसिंग प्रोजेक्ट, पोलोन्नारुवा में त्रिभाषी स्कूल और कई अन्य विकास परियोजनाएं इस साल शुरू की गई थीं और इनकी अच्छी प्रगति हुई है। नए एसडीपीज़ के माध्यम से बत्तिसलोआ में 3400 शौचालय का निर्माण, मन्नार में 300 पारगमन आवासीय इकाइयों के निर्माण, दांबुला में 5000 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज का निर्माण, मॉडल गांव परियोजनाओं के अंतर्गत उत्तरी और दक्षिणी प्रांतों में 600 घरों के निर्माण पर अप्रैल से नवंबर 2018 की अवधि के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

भारतीय अनुदान सहायता के तहत वित्तपोषित श्रीलंका में 1990 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा के द्वीप-व्यापी परिचालन का शुभारंभ, 21 जुलाई 2018 को जाफना में हुआ, जिसमें प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री श्री रानिल विक्रमसिंघे के साथ नई दिल्ली से लाइव वीडियो लिंक के माध्यम से भाग लिया। लगभग 7.56 मिलियन अमेरिकी डॉलर (88 एंबुलेंस) की भारतीय अनुदान सहायता के तहत जुलाई 2016 में श्रीलंका के पश्चिमी और दक्षिणी प्रांतों में शुरू की गई सेवा को, वर्तमान में 15.02 मिलियन अमरीकी डॉलर के भारतीय अनुदान के तहत श्रीलंका के सभी प्रांतों में विस्तारित की जा रही है और नौ प्रांतों में से सात का कार्यान्वयन पूरा हो गया है। अनुदान में 209 अतिरिक्त एम्बुलेंस की खरीद, प्रशिक्षण लागत और साथ ही सेवाओं के आरम्भ के बाद एक वर्ष के लिए परिचालन लागत शामिल है।

जून 2017 में भारत के एक्जिम बैंक और श्रीलंका सरकार के बीच हस्ताक्षर318 मिलियन अमरीकी डॉलर के भारतीय ऋण श्रृंखला (एलओसी) करार के तहत 7 सितंबर 2018 को कोलंबो में राईट्स लिमिटेड और श्रीलंका सरकार के बीच श्रीलंका रेलवे को 160 यात्री डिब्बों की आपूर्ति के लिए लगभग 82.64 मिलियन अमरीकी डॉलर की संविदा करार पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने 11 मार्च, 2018 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संस्थापक सम्मेलन के दौरान श्रीलंका में सौर

परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला की एक नई घोषणा की, जिसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री मैत्रीपाला सिरिसेना ने भाग लिया।

भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को निरंतर उच्च स्तरीय बातचीत और विकास परियोजनाओं में प्रगति के माध्यम से मजबूत किया गया। द्विपक्षीय व्यापार 2016 में 4.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2017 में 5.23 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो लगभग 20% की वृद्धि है। 2017 में श्रीलंका को भारत का निर्यात 4.54 बिलियन अमेरिकी डॉलर और भारत का श्रीलंका से आयात 690 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। जनवरी से सितंबर 2018 की अवधि के लिए भारत से श्रीलंका को निर्यात 3.19 बिलियन अमेरिकी डॉलर और श्रीलंका से आयात 571 मिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ। 2017 में लगभग 130 मिलियन अमरीकी डॉलर की कुल निवेश के साथ भारत श्रीलंकाई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता था। भारत 2017 में 384,000 से अधिक आगमन के साथ श्रीलंका में पर्यटन के लिए उच्चतम स्रोत बाजार बना रहा।

ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करते हुए 9 अप्रैल, 2018 को कोलंबो में भारत, जापान और श्रीलंका की कंपनियों के बीच श्रीलंका में एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने पर एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और श्रीलंका के बीच प्रस्तावित आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते (ईटीसीए) पर तीन दौर की वार्ता (9-11) अप्रैल-नवंबर 2018 के दौरान हुई थी।भारत और श्रीलंका के बीच विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की तीसरी बैठक 7 जुलाई, 2018 को कोलंबो में आयोजित की गई थी।

भारतीय तट रक्षक के महानिदेशक, थल सेनाध्यक्ष, नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख की श्रीलंका यात्रा और श्रीलंका के कमांडर की भारत यात्रा सहित दोनों पक्षों की उच्च स्तरीय यात्राओं से श्रीलंका के साथ रक्षा जुड़ाव जारी रहा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया दूसरा उन्नत अपतटीय गश्ती पोत श्रीलंकाई नौसेना को सौंप दिया गया था, जिसे 19 अप्रैल, 2018 को श्रीलंका नेवल शिप सिंदुरला के रूप में कमीशन किया गया था। एसएलआईएनईएक्स नामक अब तक द्विवार्षिक नौसेना अभ्यास को 2018 से वार्षिक अभ्यास में बदल दिया गया और 7-13 सितंबर 2018 से त्रिंकोमाली में आयोजित किया गया। रक्षा संबंधों को और मजबूत करने के लिए, श्रीलंका के सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके परिवारों के लिए बोधगया की पहली तीर्थ यात्रा 24-26 जून 2018 से आयोजित की गई थी। श्रीलंकाई सशस्त्र बल के जवानों और उनके परिवारों को बोध गया ले जाने और वहाँ से वापस आने के लिए एक विशेष भारतीय वायु सेना सी -17 विमान को कोलंबो में तैनात किया गया था।

इस अवधि के दौरान दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध और लोगों के बीच संपर्क को और गहरा किया गया। सारनाथ से पवित्र अवशेष को 29 अप्रैल से 2 मई 2018 को आयोजित वेसाक प्रदर्शनी के लिए श्रीलंका लाया गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति की भागीदारी के साथ 23 जून 2018 को कोलंबो में प्रतिष्ठित इंडिपेंडेंट स्क्वायर में योग का चौथा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती समारोह की शुरुआत और श्री गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती भी मनाई गई।

शिक्षा क्षेत्र में भी संबंधों में और मजबूती देखी गई। भारत अब श्रीलंका के छात्रों को प्रतिवर्ष लगभग 710 छात्रवृत्ति स्लॉट प्रदान करता है, जिसमें श्रीलंका और भारत में अध्ययन शामिल है। इसके अलावा, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग योजना और कोलंबो योजना के तहत, भारत श्रीलंकाई नागरिकों को सालाना 400 स्लॉट प्रदान करता है, जो विभिन्न प्रकार के तकनीकी और व्यावसायिक विषयों में लघु और मध्यम अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए है।

हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए)

प्रधान मंत्री की एसएजीएआर की रणनीतिक दृष्टि के अनुरूप, इस अवधि के दौरान हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के दृष्टिकोण में गुणात्मक परिवर्तन हुआ। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) के सदस्य राष्ट्रों के साथ भारत की संबद्धता को और गहन किया क्योंकि एसोसिएशन ने अपनी स्थापना के 20 साल पूरे कर लिए थे। इस अवसर पर भारत द्वारा घोषित प्रमुख पहलों में भारत के तटीय शहरों में से एक में आईओआरए उत्कृष्टता केंद्र (आईसीई) स्थापित करना था, जो कि हिंद महासागर से संबंधित मुद्दों पर एक केंद्र बिंदु और संसाधन भंडार के रूप में काम करेगा और जो सभी आईओआरए सदस्य राष्ट्रों में नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा।

डरबन में 18 वीं आईओआरए मंत्रिपरिषद की बैठक में, क्षेत्र में सॉफ्टपावर और विज्ञान कूटनीति का उपयोग करने के लिए विभिन्न नई पहलों की घोषणा की गई। भारत ने आईओआरए प्राथमिकता क्षेत्र-आपदा जोखिम प्रबंधन का नेतृत्व समन्वयक होने के नाते नई दिल्ली में 5-6 फरवरी, 2019 को आपदा जोखिम प्रबंधन पर क्लस्टर समूह की पहली बैठक की घोषणा की। भारत में प्राथमिकता वाले अन्य क्षेत्र अर्थात अकादमिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए लीड समन्वयक भी है। क्लस्टर समूह के सदस्य के रूप में, भारत ने मार्च 2017 में जकार्ता में पहली आईओआरए लीडर्स समिट में अपनाए गए आईओआरएएक्शन प्लान को आगे बढ़ाने के लिए समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी और पर्यटन पर कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए कार्य समूह की बैठकों में भाग लिया।

इस अवधि का मुख्य आकर्षण भारत में आईओआरए मंत्रिपरिषद और वरिष्ठ अधिकारियों की समिति की पिछली बैठकों में भारत द्वारा घोषित व्यापक पहलों का कार्यान्वयन था। 2018 के अंत तक, भारत ने आईओआरए, भारत सरकार द्वारा हाल में आयोजित 2 आईओआरए अक्षय ऊर्जा मंत्रिस्तरीय बैठक और नई दिल्ली में 2-4 अक्टूबर, 2018 को सीआईआई द्वारा अपनी घोषित तेरह पहलों में से बारह को सफलतापूर्वक लागू किया था। यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन महासभा और द्वितीय वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो (आरईआईएनवीईएसटी- 2018) के साथ आयोजित किया गया था। नई दिल्ली में 2 अक्टूबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की उपस्थिति में तीनों कार्यक्रमों का उद्घाटन प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। तीन घटनाओं का सामूहिक लक्ष्य हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा का विकल्प तैयार करने का था। 2 आईओआरए अक्षय ऊर्जा मंत्रिस्तरीय बैठक में 17 आईओआरए सदस्य राज्यों और 3 संवाद साझेदारों ने भाग लिया।

“आईओआरए सेंटर ऑफ एक्सिलेंस” मार्च 2017 में जकार्ता में हुए पहले लीडर्स समिट में उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू द्वारा घोषित प्रमुख परियोजना है। इस डिजिटल नॉलेज हब की परिकल्पना एक डेटा सेंटर और विशेषज्ञता, ज्ञान, डेटा और विश्लेषण के संसाधन के रूप में की गई है। यह सामूहिक रूप से सदस्य देशों के ज्ञान, संसाधनों, विशेषज्ञता को पूल करने के लिए विकसित किया जा रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म को विकसित करने पर काम चल रहा है।

भारत ने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (सीएसआईआर) - सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स (सीआईएमएपी) और तेहरान स्थित आईओआरए रीजनल सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (आरसीएसटीटी) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद फरवरी 2018 में तेहरान में आईओआरए-आरसीएसटीटी समन्वय केंद्र में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की मेजबानी की। सीएसआईआर-सीआईएमएपी कैंपस, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, लखनऊ में औषधीय पौधों पर आईओआरए-आरसीएसटीटी समन्वय केन्द्र में 25 नवंबर-1 दिसंबर, 2018 तक आईओआरए सदस्य देशों और वार्ता साझेदारों के लिए “विविधता, प्रलेखन, जीन बैंकिंग और औषधीय पौधों के लिए डेटा बेस” पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

2

दक्षिण-पूर्व एशिया और एशिया-प्रशांत

ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया भारत का एक रणनीतिक साझेदार है। दोनों ओर से होने वाली नियमित उच्च-स्तरीय यात्राएं भारत-ऑस्ट्रेलिया के बढ़ते संबंधों का प्रमाण हैं। ऑस्ट्रेलिया व्यापार और निवेश, शिक्षा और कौशल, खनिज संसाधनों और रक्षा और सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभर रहा है। वर्ष के दौरान 21-24 नवंबर 2018 तक ऑस्ट्रेलिया में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा के साथ दोनों देशों के बीच संबंध एक नई ऊंचाई पर पहुंच गए। यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल सर पीटर कॉसग्रोव और प्रधान मंत्री स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात की। महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती समारोह के एक हिस्से के रूप में, राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने न्यू साउथ वेल्स के परामत्ता में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया और भारतीय प्रवासियों और स्थानीय समुदाय की एक बड़ी सभा को संबोधित किया। यात्रा के दौरान विकलांगता के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन; द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा देना; वैज्ञानिक सहयोग को आगे बढ़ाना; कृषि अनुसंधान और शिक्षा में सहयोग, और एक संयुक्त पीएचडी कार्यक्रम विकसित करने सहित पांच करारों / समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने ऑस्ट्रेलियाई वित्तीय समीक्षा और ऑस्ट्रेलिया-भारत व्यापार परिषद द्वारा आयोजित इंडिया बिजनेस समिट 2018 में दो व्यावसायिक कार्यक्रमों को भी संबोधित किया। उनकी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले मार्च 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के संस्थापना सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर-जनरल पीटर पीटर कॉसग्रोव की भारत यात्रा हुई थी।

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 अप्रैल 2018 को लंदन में राष्ट्रमंडल राष्ट्राध्यक्षों (चोगम) की बैठक के दौरान ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधान मंत्री श्री मैल्कम टर्नबुल से और

14 नवंबर 2018 को सिंगापुर में एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) बैठक के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री श्री स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात की। बैठकों के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को काफी प्रोत्साहन मिला।

जुलाई 2018 में, ऑस्ट्रेलिया ने एन इंडिया इकॉनोमिक स्ट्रैटजी टु 2035 जारी की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के भारत के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंध बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। नवंबर 2018 में राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान आयोजित इंडिया बिजनेस शिखर सम्मेलन 2018 में प्रधान मंत्री मॉरिसन द्वारा दिए गए भाषण के दौरान ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा औपचारिक रूप से रिपोर्ट का समर्थन किया गया था। दोनों पक्ष रिपोर्ट की सिफारिश को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं।

2018 में दोनों देशों के बीच कई मंत्रिस्तरीय बातचीत और आधिकारिक यात्राएं हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा ने कैनबरा में ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप की उद्घाटन बैठक और सिडनी में इंटरनेशनल डिजिटल हेल्थ सिंपोजियम में भाग लेने के लिए 18-21 फरवरी 2018 तक ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की। युवा और खेल राज्य मंत्री कर्नल (सेवानिवृत्त) श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 12-16 अप्रैल 2018 तक ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की। वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने 15 वें भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग (जेएमसी), जो 25 जून 2018 को कैनबरा में आयोजित किया गया था, के लिए 24-26 जून 2018 तक कैनबरा और सिडनी की यात्रा की। मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच दो-तरफा निवेश प्रवाह बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। कैनबरा में, वाणिज्य मंत्री ने ऑस्ट्रेलियाई

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री स्कॉट जॉन मॉरीशन सिडनी में राष्ट्रपति से मुलाकात करते हुए (22 नवंबर, 2018)

प्रधान मंत्री से मुलाकात की और कोषाध्यक्ष, कृषि और जल संसाधन मंत्री और विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं। मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऑस्ट्रेलिया-भारत शिक्षा परिषद की चौथी बैठक में भाग लेने के लिए 28 जून से 3 जुलाई 2018 तक ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की। यात्रा के दौरान, ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय शैक्षिक संस्थानों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय और भारत के सेंचुरियन विश्वविद्यालय के बीच एक करार, कर्टिन विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के बीच एक संयुक्त पीएचडी करार, और डीकिन विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू; अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और डीकिन विश्वविद्यालय; और जवाहरलाल स्नात्कोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान और डीकिन विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन शामिल हैं। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर 25 सितंबर 2018 को न्यूयॉर्क में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री सुश्री मारिज पायने के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मारिज पायने ने रायसीना वार्ता 2019 में भाग लेने के लिए 8-9 जनवरी 2019 को नई दिल्ली की यात्रा की। उन्होंने 9 जनवरी 2019 को मंत्री के रूप में संबोधन दिया। उन्होंने विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजित डोभाल के साथ बैठकें की। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा बलों के प्रमुख जनरल एंगस कैंपबेल ए.ओ. डी.ए.सी ने भी रायसीना वार्ता में भाग लिया और इंडो-पेसिफिक: एंसियन्ट वाटर्स एंड इमर्जिंग ज्योमेटरिज शीर्षक पर पैनल वार्ता में अपने विचार रखे। उन्होंने रक्षा मंत्रालय के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की।

उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के व्यापार, निवेश, संसाधन शैडो मंत्री जैसन क्लेयर एमपी, ने 13-20 जनवरी 2019 को भारत की यात्रा की।

न्यू साउथ वेल्स के गवर्नर, ऑस्ट्रेलिया के सहायक व्यापार, पर्यटन और निवेश मंत्री महामहिम श्री डेविड हर्ले, मार्क कुलटन एमपी, ने जीवंत गुजरात शिखर सम्मेलन 2019 में भाग लेने के लिए 16-20 जनवरी 2019 तक भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र तथा गुजरात के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों के साथ बैठकें की। जीवंत गुजरात शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की।

राष्ट्रपति सिडनी में पैरामेट्टा में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण करते हुए (22 नवंबर, 2018)

प्रधानमंत्री लंदन में राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन के अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री मैकुलम टॅनबुल से मुलाकात करते हुए (19 अप्रैल, 2018)

मार्क कुलटन एमपी, ऑस्ट्रेलिया के व्यापार, पर्यटन और निवेश सहायक मंत्री और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को शिक्षा एवं प्रशिक्षण मंत्री सुज़ैन एलरी एमएलसी के ने भी जीवंत गुजरात शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

विदेश सचिव श्री विजय गोखले और रक्षा सचिव श्री संजय मित्रा ने 10 अक्टूबर 2018 को दूसरी विदेश और रक्षा सचिव (2+2) वार्ता के लिए कैनबरा की यात्रा की। इंडोनेशिया-ऑस्ट्रेलिया-भारत वरिष्ठ पदाधिकारियों का दूसरा संवाद 21 सितंबर 2018 को कैनबरा में आयोजित किया गया था। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्रालय के पदाधिकारियों ने 7 जून 2018 और 15 नवंबर 2018 को सिंगापुर में भारत-प्रशांत क्षेत्र में साझा हित के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

दोनों देशों के बीच बढ़ते उच्च स्तरीय संपर्कों और रक्षा अभ्यास में जमीनी स्तर की भागीदारी से वर्ष के दौरान रक्षा सहयोग मजबूत हुआ। पहली बार भारतीय वायु सेना ने 27 जुलाई से 17 अगस्त 2018 तक पिच ब्लैक नामक अभ्यास में भाग लिया। भारतीय वायुसेना ने ऑस्ट्रेलियाई केसी-30 विमानों के साथ आकाश में ईंधन भरने का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। भारतीय तटरक्षक पोत 'वैभव' ने 21 से 25 फरवरी 2018 तक डार्विन की यात्रा की। एक ऑस्ट्रेलियाई नौसेना पोत एचएमएएस लारकिया ने मार्च 2018 में भारत में नौसेना अभ्यास 'मिलन' में भाग लिया। भारतीय नौसैना पोत सह्याद्रि 30 अगस्त से 15 सितंबर 2018 तक ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास काकाडू में भाग लेने के लिए डार्विन गया। सेना के विशेष बलों के संयुक्त अभ्यास ऑस्ट्राहिंद का तीसरा संस्करण सितंबर 2018 में भारत में आयोजित किया गया। अक्टूबर 2018 में, सिंगापुर में आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक (एडीएमएम प्लस) के मौके पर, दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने द्विपक्षीय बैठक की। दोनों देशों ने वर्ष के दौरान दोनों सेनाओं, दोनों नौसेनाओं और वायुसेनाओं के बीच सामान्य परस्पर वार्ता भी आयोजित की।

ब्रुनेई दारुस्सलाम

भारत और ब्रुनेई के बीच द्विपक्षीय संबंध घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण बने रहे और राजनीतिक, रक्षा , सांस्कृतिक और खेल सहित सभी क्षेत्रों में संबंधों में बढ़ोतरी हुई। इस वर्ष दोनों देशों के बीच नियमित बातचीत और यात्राओं होती रही। ऊर्जा और उद्योग उप-मंत्री श्री दातो मत्सुटेजो सोकियाव ने 11-12 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली की यात्रा की और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ वार्ता की। उन्होंने यूआईडीएआई और एनएएसएससीओएम कार्यालयों का भी दौरा किया और भारत की ई-गवर्नेंस पहलों के बारे में जानकारी प्राप्त की। श्री अब्दुल मुतालिब , संचार मंत्री ने भारत की यात्रा की और 19-20 जुलाई 2018 को नई दिल्ली में दिल्ली संवाद के दसवें संस्करण में भाग लिया। उनकी यात्रा के दौरान सैटेलाइट और प्रक्षेपण वाहनों के लिए टेलीमेट्री ट्रैकिंग और टेलिकमांड स्टेशन के संचालन में सहयोग और अंतरिक्ष अनुसंधान, विज्ञान और अनुप्रयोग के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश राज्य मंत्री, जनरल डॉ. वीके सिंह (सेवानिवृत्त) ने 2 अगस्त 2018 को सिंगापुर में आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक (एएमएम) के मौके पर ब्रुनेई के विदेश मंत्री श्री हसनल बोल्कैया से मुलाकात की।

भारत-ब्रुनेई संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक 5 सितंबर 2018 को ब्रुनेई में आयोजित की गई, जिसके दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने की क्षमता वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए विचारों का आदान-प्रदान किया। ब्रुनेई रक्षा मंत्रालय के तीन सदस्यीय दल ने 10-14 अप्रैल 2018 से चेन्नई में आयोजित दसवीं रक्षा प्रदर्शनी में भाग लिया।

ऑटिस्टिक-स्पेक्ट्रम बच्चों को जीवन-कौशल प्रदान करने के लिए समर्पित स्मार्टर ब्रुनेई के संस्थापक-अध्यक्ष, श्री मलाई हाजी अब्दुल्ला ने सामाजिक कार्यों में उनके योगदान के लिए नई दिल्ली में 2 अप्रैल 2018 को आयोजित एक समारोह में भारत के राष्ट्रपति से पद्मश्री सम्मान प्राप्त किया ।

ब्रुनेई में भारत के उच्चायुक्त ने 27 अगस्त 2018 को विश्वविद्यालय में आयोजित एक समारोह में विश्वविद्यालय इस्लाम शरीफ अली (यूएनआईएसएसए) को इस्लामी सुलेख के बत्तीस प्रस्तर दान किए। ये रामपुर रज़ा लाइब्रेरी से इस्लामी सुलेख के फोटोग्राफिक प्रतिकृतियां थी, जो 9 से 25 नवंबर 2017 तक ब्रुनेई में आयोजित इस्लामी सुलेख की प्रदर्शनी में पहले प्रदर्शित की गई थी। प्रदर्शनी को स्थायी रूप से विश्वविद्यालय के सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रदर्शित किया जाएगा।

आसियान-भारत मीडिया आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत, ब्रुनेई के दो पत्रकारों ने 14-20 जुलाई 2018 तक कोलकाता, गुवाहाटी और नई दिल्ली की यात्रा की। भारतीय महिला रग्बी टीम ने 20 और 21 अक्टूबर 2018 को ब्रुनेई में आयोजित एशिया रग्बी महिला सेवन्स ट्रॉफी 2018 में भाग लिया। टूर्नामेंट में दस टीमों ने भाग लिया और भारतीय टीम पांचवें स्थान पर रही।

कंबोडिया

भारत और कंबोडिया के बीच गर्मजोशी वाले सौहार्दपूर्ण संबंध हैं, जो व्यापार और वाणिज्य, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास परियोजनाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते जा रहे हैं। कई मंत्रिस्तरीय यात्राएं की गई, जिनसे भारत-कंबोडिया के द्विपक्षीय संबंधों को गति मिली। वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने पांचवें भारत-सीएलएमवी (कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम) व्यापार कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए 21 और 22 मई 2018 को नोम पेन्ह की यात्रा की। यात्रा के दौरान, उन्होंने कंबोडिया के प्रधान मंत्री से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सुविधा, कृषि, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य परिचर्या सहित व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा की। रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 11 जून 2018 को कंबोडिया की यात्रा की और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 29 और 30 अगस्त 2018 को कंबोडिया की यात्रा की और कंबोडिया के उप प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री श्री प्राक सोखोन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। यात्रा के दौरान दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें प्रीह विहिएर में यूनेस्को विरासत स्थल का पुनर्रुद्धार और भारत के विदेशी सेवा संस्थान (एफएसआई) और कंबोडिया के राष्ट्रीय राजनय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध संस्थान के बीच सहयोग शामिल थे। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने प्रधान मंत्री श्री हुन सेन और सीनेट के अध्यक्ष श्री समडेक सा छम से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज की यात्रा से द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर गहन चर्चा करने का अवसर मिला। विकास सहायता दो देशों के बीच सहयोग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

भारत ने जल संसाधनों के विकास, मंदिरों के जीर्णोद्वार और संरक्षण और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में कंबोडिया को अपनी सहायता जारी रखी है। कंबोडिया में ग्रामीण जल आपूर्ति में वृद्धि के लिए 1500 हैंड पंपों की आपूर्ति और स्थापना के लिए परियोजना अच्छी प्रगति कर रही है। मेकांग गंगा सहयोग (एमजीसी) पहल के तहत शुरू की गई त्वरित प्रभाव परियोजना (क्यूआईपी) योजना ने कंबोडिया में लाभार्थियों के बीच एक अलग और स्पष्ट प्रभाव पैदा किया है। इस योजना को कंबोडिया की शाही सरकार के विभिन्न संबंधित मंत्रालयों की भारी समर्थन मिला है। वर्ष 2017-18 के लिए पांच परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं। वर्ष 2018-19 से प्रभावी दस परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं जिसमें प्रत्येक परियोजना के लिए 50,000 अमेरिकी डॉलर की भारतीय अनुदान सहायता दी जा रही है। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) के तहत शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग जारी है। 2018-19 में, आईटीईसी के तहत तीन विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें दो सीनेट के लिए और एक नेशनल अथॉरिटी फॉर कॉम्बेटिंग ड्रग्स (एनएसीडी) के अधिकारियों के लिए है। फरवरी 2019 में पंद्रह एनएसीडी अधिकारियों के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किया जाना है।

भारत और कंबोडिया के बीच सांस्कृतिक संबंध मजबूत होते जा रहे हैं। कंबोडिया के धम्मयुत्त पंथ के परम पूज्य सुप्रीम पैट्रिआर्क के नेतृत्व में एक छह सदस्यीय बौद्ध भिक्षु प्रतिनिधिमंडल ने 6 वीं अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए अगस्त 2018 में भारत की यात्रा की। दूतावास द्वारा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) और प्रेय सिंहानोकराजा बौद्ध विश्वविद्यालय, नोम पेन्ह के सहयोग से सितंबर 2018 में "दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म" पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था।

कंबोडिया में योग कार्यक्रम विशेष रूप से युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय रहे हैं। जून 2018 में नोम पेन्ह, सिएम रीप, सिहानोकविले और बट्टामबांग में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और कंबोडियाई मंत्रालयों के सहयोग से एक योग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में, अक्टूबर 2018 में गांधियन फोरम फॉर इथिकल कॉरपोरेट गवर्नेंस, नई दिल्ली की मुख्य कार्यकारी सुश्री शोभना राधाकृष्ण, द्वारा नोम पेन्ह

में कंबोडिया विश्वविद्यालय और पन्नास्त्र विश्वविद्यालय में गांधी पर व्याख्यान सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इस अवधि के दौरान द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंध बढ़ते रहे। इस वर्ष भी कंबोडिया के कई व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने भारत में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया जैसे कि तकनीकी वस्त्रों पर सातवीं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन, गुवाहाटी में एडवांटेज असम इंडिया एक्सप्रेस वे टु आसियान और भारत पर्यटन मार्ट 2018.

इंडोनेशिया

भारत और इंडोनेशिया के बीच लंबे समय से घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं, जो 29-31 मई 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया की पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान व्यापक रणनीतिक साझेदारी की स्थापना से और मजबूत हुए। इस यात्रा के दौरान पंद्रह करारों और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें रक्षा सहयोग पर दोनों सरकारों के बीच नौ समझौता ज्ञापन, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में सहयोग, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग, रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग, तकनीकी सहयोग, स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग, फॉर्मास्युटिकल, जैविक और सौंदर्य प्रसाधन नियामक कार्यों में सहयोग, सरकारों के बीच नीतिगत संवाद और विशेषज्ञ मंडलों के बीच बातचीत शामिल है। भारत और इंडोनेशिया के बीच सत्तर वर्षों के राजनयिक संबंधों को मनाने के लिए वर्ष 2019-20 में भारत और इंडोनेशिया में आयोजित किए जाने वाले कार्यकलापों की एक योजना का भी इस यात्रा के दौरान आदान-प्रदान किया गया।

दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को प्रधान मंत्री मोदी की यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला, जब दो समुद्री पड़ोसी देशों और व्यापक रणनीतिक भागीदारों के बीच आर्थिक सहयोग और लोगों के बीच संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए दोनों पक्षों ने विशेष रूप से समुद्री संपर्कों के संबंध में अधिक मजबूत आवागमन सुविधा के महत्व को रेखांकित करते हुए 'भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत-इंडोनेशिया समुद्री सहयोग का साझा दृष्टिकोण' जारी किया। उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और आसेह के बीच आवागमन

प्रधानमंत्री जकार्ता में अपने स्वागत समारोह के दौरान सम्मान गारद का निरीक्षण करते हुए (30 मई, 2018)

सुविधा बनाने की योजना का स्वागत किया ताकि दोनों क्षेत्रों की आर्थिक क्षमताओं को उन्मुक्त किया जा सके। इस दृष्टिकोण के अनुरूप, जकार्ता में भारत के राजदूत ने बांदा जुलाई 2018 में आसेह के लिए एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया गया, जिसमें अंडमान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदस्य, अंडमान और निकोबार प्रशासन के अधिकारी शामिल थे और प्रथम भारत-इंडोनेशिया निवेश मंच का आयोजन किया। इसके जवाब में, एक तीस सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें चैंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ आसेह, राज्य और स्थानीय उद्यमों, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स कंपनियों के सदस्य, शिक्षाविद, मीडिया और इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय के पदाधिकारी शामिल थे, ने चेन्नई के रास्ते पोर्ट ब्लेयर की यात्रा की और 29 नवंबर 2018 को भारत-इंडोनेशिया व्यापार मंच का आयोजन किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की यात्रा ने दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और गति दी। संयुक्त रक्षा समन्वय समिति (जेडीसीसी) की छठी बैठक अगस्त 2018 में आयोजित की गई थी, जहां दोनों पक्ष नौसेना और वायु सेना द्विपक्षीय अभ्यास शुरू करने के लिए सहमत हुए। रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने रक्षा पर द्विपक्षीय वार्ता के लिए 21-24 अक्टूबर, 2018 को इंडोनेशिया की यात्रा की। इसके बाद भारत और इंडोनेशिया के बीच पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 'समुद्र शक्ति' हुआ जो 13-18 नवंबर 2018 तक आयोजित किया गया था। दोनों देशों की वायु सेना ने 20-23 नवंबर 2018 तक जकार्ता में एयर स्टाफ वार्ता आयोजित की। इंडोनेशियाई कोस्ट गार्ड के प्रमुख वाइस एडमिरल श्री ए. तौफीक आर. ने अपने समकक्षी के साथ चर्चा के लिए 17-19 दिसंबर 2018 तक भारत की यात्रा की। पांचवां भारत-इंडोनिशिया विदेश कार्यालय विचार-विमर्श 21 जनवरी 2019 को योग्यकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। इसकी सह-अध्यक्षता सचिव (पूर्व) श्रीमती विजय ठाकुर सिंह और इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय में एशिया-पैसिफिक एवं अफ्रीकी मामलों के महानिदेशक ने की।

28 सितंबर 2018 को इंडोनेशिया के पश्चिमी सुलावेसी प्रांत के पालू और डोंगाला में भूकंप और सुनामी के बाद भूकंप और सुनामी पीड़ितों के लिए मानवीय सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए इंडोनेशिया की स्वीकृति के बाद 3 अक्टूबर 2018 को 'ऑपरेशन समुद्र मैत्री' नामक कार्रवाई शुरू की गई। भारत ने चिकित्सा कर्मियों और राहत सामग्री के साथ दो वायुसेना के विमानों को प्रभावित क्षेत्र में भेजा। तीन भारतीय पोत भी प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा आपूर्ति के साथ जकार्ता पहुंचे।

इंडोनेशिया 2017-18 में कुल 20.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार के साथ आसियान क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना हुआ है। दूसरा मुख्य कार्यकारी अधिकारी फोरम जकार्ता में 29 और 30 मई 2018 को आयोजित किया गया, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता की यात्रा के समय आयोजित किया गया था। समुद्री मामलों के समन्वयक मंत्री श्री लुहूत बिनसर पंडजैतन ने 17 और 18 मई 2018 को भारत की यात्रा की और विदेश मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री के साथ बैठकें की और आर्थिक सहयोग की और संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सदस्यों के साथ बातचीत की।

वर्ष 2018 में गरुड़ एयरलाइंस ने मुंबई और बाली के बीच अपनी सीधी उड़ान शुरू की। इंडोनेशिया के पर्यटन मंत्री श्री आरिफ याहया ने 23 अप्रैल 2018 को पहलीउड़ान पर यात्रा की। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवा को और बेहतर बनाने के लिए, भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों और इंडोनेशिया के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अधिकारियों के बीच नई दिल्ली में 19 और 20 सितंबर 2018 को हवाई सेवा वार्ता आयोजित की गई।

जकार्ता में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की यात्रा के दौरान जारी संयुक्त वक्तव्य के अनुसार, भारत-इंडोनेशिया प्रथम अंतर-आस्था वार्ता योग्यकार्ता में आयोजित की गई, जिसमें भारतीय पक्ष की ओर से पूर्व विदेश राज्य मंत्री श्री एमजे अकबर के नेतृत्व में सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ, जबकि इंडोनेशिया के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व इंडोनेशिया के उप विदेश मंत्री श्री ए. एम. फकीर ने किया।

18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 तक जकार्ता और पालमबांग में 18 वें एशियाई खेल आयोजित किए गए और इस आयोजन में शामिल होने के लिए खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री, कर्नल (सेवानिवृत्त) श्री राज्यवर्धन राठौर ने 25-29 अगस्त 2018 तक जकार्ता की यात्रा की। पैरा एशियाई खेल 2018, 6-15 अक्टूबर 2018 तक जकार्ता में आयोजित किए गए जिसके लिए योजना और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह 5-14 अक्टूबर 2018 तक वहां उपस्थित रहे।

भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और इंडोनेशिया के राष्ट्रीय एंटी-नारकोटिक्स एजेंसी के बीच 28-29 जून, 2018 को नई दिल्ली में तीसरे महानिदेशक संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठक; 10-11 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में आतंकवाद रोध पर संयुक्त कार्य समूह की 5 वीं बैठक; और कैनबरा में 21 सितंबर 2018 को दूसरी भारत-ऑस्ट्रेलिया-इंडोनेशिया (आईएआई) वरिष्ठ अधिकारियों की वार्ता सहित विभिन्न द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय संस्थागत तंत्र के तहत बैठकें आयोजित की गईं।

आयोग I के इंडोनेशियाई संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने 27-31 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली की यात्रा की और रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ) वीके सिंह (सेवानिवृत्त), और प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉ ए. सूर्य प्रकाश से मुलाकात की।

नगर सरकारों और प्रमुख विश्वविद्यालयों के सहयोग से, अप्रैल 2018 में मलंग में और सितंबर 2018 में सुराबाया में भारत संस्कृति सप्ताह का आयोजन किया गया।

लाओ जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य (पीडीआर)

लाओ जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ संबंध बढ़ना जारी रहा। श्री थौंगफैन सावनफेट, विदेश मामलों के उप मंत्री ने 19 और 20 जुलाई 2018 को नई दिल्ली में दिल्ली संवाद के 10 वें संस्करण में भाग लेने के लिए लाओस विदेश मंत्रालय से एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। लाओ जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली संवाद के मौके पर आयोजित समुद्री अर्थव्यवस्था के संबंध में एक कार्यशाला में भाग लिया।

विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) ने 02 अगस्त 2018 को सिंगापुर में आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक (एएमएम) के मौके पर लाओ जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य के विदेश मंत्री श्री प्राक सोकोन से मुलाकात की।

वात फु में विश्व धरोहर स्थल, एक प्राचीन शिव मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए मई 2007 में सूचना और संस्कृति मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने वात फु परिसर के उत्तरी के जीर्णोद्धार के संबंध में 2008 से 2017 तक परियोजना का चरण I पूरा किया और परियोजना के चरण II (2018-2028) पर जीर्णोद्धार का काम शुरू किया।

विदेश मंत्री लाओ पीडीआर के विदेश मंत्री सेलुमजे कोमासिथ से मुलाकात करते हुए (23 नवंबर, 2018)

विदेश मंत्री विंशिऐन में लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री श्री थॉगुलून सिसुलिथ के साथ मुलाकात करते हुए (23 नवंबर, 2018)

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 22 और 23 नवंबर 2018 को वियनतियाने की यात्रा की और अपने लाओ समकक्षी के साथ 9 वें भारत-लाओ जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य जेसीएम की सह-अध्यक्षता की। यात्रा के दौरान, उन्होंने लाओस के प्रधान मंत्री श्री थोंगलोउन सिसोलॉथ से मुलाकात की और द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न मुद्दों और भविष्य के रोडमैप पर चर्चा की। दोनों देश ऊर्जा और खनन क्षेत्र, परिवहन, व्यापार और निवेश, मानव संसाधन विकास और कृषि जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारत प्रतिवर्ष दीर्घकालिक और अल्पकालिक प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए लाओ पीडीआर के छात्रों और अधिकारियों को छात्रवृत्ति प्रदान करता रहा है। भारत ने कृषि तथा ऊर्जा के क्षेत्र लाओ पीडीआर को कम-ब्याज दर पर ऋण और सूचना संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुदान दिया है।

सॉफ्टवेयर विकास और प्रशिक्षण में लाओस-भारत उत्कृष्टता केन्द्र जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यावहारिक सॉफ्टवेयर समाधान विकसित करने में सक्षम उच्च स्तरीय मानव संसाधन का निर्माण करना है, का उद्घाटन 26 नवंबर, 2018 को वियनतियाने में भारत के वित्तीय और तकनीकी समर्थन के साथ किया गया।

मलेशिया

दोनों देशों और उनके लोगों के बीच साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों के माध्यम से दोस्ती के मजबूत बंधन लगातार उच्च स्तरीय परस्पर यात्राओं से मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 31 मई 2018 को मलेशिया के नवनिर्वाचित प्रधान मंत्री श्री तुन डॉ० महातिर बिन मोहम्मद को बधाई दी। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए रोडमैप पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा के दौरान उप प्रधान मंत्री श्री वान अजीज़ा वान इस्माइल से भी मुलाकात की।

दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम, पार्टी केडिलन रक्यात के राष्ट्रपति ने 8-12 जनवरी, 2019 तक भारत की यात्रा की और रायसीना वार्ता 2019 में अपना समापन भाषण दिया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने 11 जनवरी, 2019 को बेंगलुरु की भी यात्रा की और मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी और कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर से मुलाकात की और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों से बातचीत की।

प्रधानमंत्री पुत्राजय, मलेशिया में मलेशिया के प्रधानमंत्री श्री महातिर बिन मोहम्मद से मुलाकात करते हुए (31 मई, 2018)

विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ०) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) ने 2 अगस्त, 2018 को सिंगापुर में एएमएम के अवसर पर मलेशियाई विदेश मंत्री से मुलाकात की। मलेशिया के मानव संसाधन मंत्री श्री वाई.बी. एम. कुलसेगरन ने 7-12 अक्टूबर, 2018 तक भारत की पहली यात्रा की। उन्होंने द्विपक्षीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विदेश मंत्री, वित्त

मलेशिया के उप प्रधानमंत्री श्री वान अजीजाह वान इस्माइल क्वालालम्पुर में प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हुए (31 मई, 2018)

मंत्री, आईटी मंत्री और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री से मुलाकात की।

इस वर्ष दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को उल्लेखनीय बढ़ावा मिला। मलेशिया-भारत रक्षा सहयोग बैठक (एमआईडीसीओएम) का ग्यारहवां दौर 20-22 नवंबर, 2018 तक कुआलालंपुर में आयोजित किया गया, जहाँ रक्षा सचिव श्री संजय मित्रा ने छह सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। एमआईडीसीओएम का एक महत्वपूर्ण परिणाम संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना था।

4-7 जुलाई 2018 को कुआलालंपुर में सातवें नौसेना-से-नौसेना स्टाफ वार्ता आयोजित की गई थी। भारतीय नौसेना मलेशिया में लैंगकॉवी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और एयरोस्पेस प्रदर्शनी (लीमा) में एक नियमित भागीदार रही है और भारतीय नौसेना जहाज और भारतीय तटरक्षक जहाज अक्सर मलेशियाई बंदरगाहों पर ठहरते हैं। आईएनएस कामोत्रा ने कोटा किनाबालु में 13-17 मई, 2018 तक पड़ाव डाला। मलेशिया में 30 अप्रैल -11 मई, 2018 तक पहले कंपनी स्तर का आर्मी फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज (एफटीएक्स) आयोजित किया गया था। वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल श्री बी.एस. धनोआ ने 5-8 सितंबर, 2018 तक मलेशिया का दौरा किया। मलेशिया में सबंग एयर बेस में 18-23, अगस्त 2018 तक सभी रैंकों के 130 सैन्यकर्मियों द्वारा पहली बार वायुसेना का द्विपक्षीय हवाई अभ्यास किया गया।

न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड के साथ भारत के संबंध सद्भावना और मित्रता पर आधारित है क्योंकि न्यूजीलैंड में उत्तरोत्तर सरकारें भारत-न्यूजीलैंड संबंधों को प्राथमिकता देती रही हैं। एक-दूसरे के देश की नियमित यात्राएं की गई हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री श्री मनसुख लाल मंडाविया ने 24 अप्रैल, 2018 को ऑकलैंड की एक दिवसीय यात्रा की और वहाँ पर भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत की। जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह भाभोर 22 और 23 मई, 2018 को न्यूजीलैंड गए। भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के अलावा, उन्होंने न्यूजीलैंड की स्वदेशी माओरी आबादी के लिए कई महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने 1 जून, 2018 को न्यूजीलैंड का दौरा किया। मंत्रिस्तरीय यात्राओं के अलावा, नेशनल डिफेंस कॉलेज, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने अपने समकक्षों के साथ बातचीत के लिए न्यूज़ीलैंड का दौरा किया। न्यूज़ीलैंड के साथ ट्रैक- II वार्ता 23-25 अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। 18-27 अक्टूबर, 2018 से ऑकलैंड में आरसीईपी वार्ता में वाणिज्य मंत्रालय के अपर सचिव श्री सुधांशु पांडे के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया।

न्यूजीलैंड के कृषि, जैव-सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण समुदाय और व्यापार और निर्यात विकास राज्य मंत्री श्री डेमियन ओ'कॉनर 14 नवंबर, 2018 को सिंगापुर में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) के अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु से मिले। श्री बेन किंग, उप सचिव, एशिया एंड अमेरिकाज ग्रुप, विदेश तथा व्यापार मंत्रालय ने 3-5 फरवरी, 2019 तक भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने 5 फरवरी, 2019 को श्रीमती विजय ठाकुर सिंह, सचिव (पूर्व) के साथ विदेश कार्यालय परामर्श बैठक की सह-अध्यक्षता की।

फिलीपींस

वर्ष 2018 में भारत-फिलीपींस के बीच राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे हुए और दोनों देशों के बीच साझेदारी में एक नया जोश दिखा। भारत में आयोजित आसियान-भारत स्मारक शिखर सम्मेलन के कारण इन संबंधों में एक नई गति आई जिसके तहत राजनीतिक, रक्षा, आर्थिक, संस्कृति, युवा, मीडिया, थिंक टैंकों और विश्वविद्यालयों से विभिन्न फिलिपिनो प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया। नवंबर 2018 में, दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ का जश्न शुरू हो गया है और इसे मनाने के लिए 2019 में भारत महोत्सव आयोजित किया जाना है।

फिलीपींस के श्री जोस मा जॉय कॉन्सेपियन को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा मार्च 2018 में राष्ट्रपति भवन में पद्म श्री से सम्मानित किया गया।

विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) नेअगस्त 2018 में 51वीं आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक (एएमएम) और संबंधित बैठकों के अवसर पर सिंगापुर में फिलीपींस के विदेश मामलों के सचिव श्री एलन पीटर कायेटानो के साथ मुलाकात की। स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की बैठकें क्रमशः मनीला में अप्रैल और मई, 2018 में संपन्न हुईं। इसके अलावा, दोनों देशों के बीच हवाई सेवा वार्ता 11 और 12 जुलाई, 2018 को आयोजित की गई, जिसके परिणामस्वरूप 13 वर्षों के बाद हवाई सेवा समझौता निष्पन्न किया गया।

मार्च 2018 में फिलीपींस के 'सचिव' नेशनल डिफेंस की यात्रा से विशेष रूप से रक्षा निर्यात के संबंध में सहयोग के नए द्वार खुले हैं। एक संयुक्त रक्षा उद्योग और संभार तंत्र समिति (जेडीआईएलसी) के प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया, एक आईएन विमान P81 ने सुलु क्षेत्र और बेन्हम राइज क्षेत्र में एक हवाई अभ्यास किया गया और भारत ने फिलीपींस को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देने की पेशकश की है। इसके अलावा, भारतीय नौसेना की बहु-भूमिका वाली मिसाइल विध्वंसक आईएनएस राणा 23- 26 अक्टूबर, 2018 तक फिलीपींस की सद्भावना यात्रा पर थी।

वाणिज्यिक संबंध मजबूत हुए हैं। वैश्विक मंदी के बावजूद, दोतरफा व्यापार में पर्याप्त वृद्धि हुई है। जीएमआर मेगा व्यापक समूह ने सेबू-मैक्टन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक नया टर्मिनल सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसका उद्घाटन 7 जून, 2018 को राष्ट्रपति श्री रोड्रिगो डुटर्टे द्वारा किया गया। जीएमआर को क्लार्क अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार के लिए एक परियोजना का ठेका भी मिला है। भारत में फिलीपींस की ओर से किए जा रहे निवेश में भी बढ़ोतरी हो रही है और फिलीपींस की एक कंपनी एजीएंडपी दक्षिण भारत में एलएनजी परियोजनाओं में 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक का निवेश करने जा रही है।

इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (ईईपीसी) ने पहली बार अगस्त 2018 में मनीला में अपना फ्लैगशिप टेक्नोलॉजी एक्सपो आईएनडीईई 2018 आयोजित किया, जिसमें लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने भाग लिया। ईईपीसी ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए आपसी सहयोग पर फिलीपींस-भारत व्यापार परिषद (पीआईबीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए।

फिलीपींस में भारत के राजदूत ने भारत सरकार की ओर से 2,00,000 अमेरिकी डॉलर का एक चेक (नवंबर 2017 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा फिलिपींस की अपनी यात्रा के दौरान जिसकी घोषणा की गई थी) महावीर फिलीपीन फाउंडेशन इंक को 27 अप्रैल, 2018 को कृत्रिम हाथ-पैर के जरूरतमंद फिलिपिनो लोगों को भारत (जयपुर फुट) में विकसित मुक्त कृत्रिम अंग मुफ्त प्रदान करने के लिए सौंपा गया।

न केवल प्रदर्शन और दृश्य कला के संदर्भ में, बल्कि आदान-प्रदान और सेमिनार के माध्यम से भी सांस्कृतिक संपर्क बढ़ रहे हैं। मई 2018 में आसियान-भारत छात्र आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत फिलीपींस के पच्चीस छात्र भारत आए थे। इसके अलावा, दो फिलिपिनो पत्रकारों ने जुलाई 2018 में आसियान-भारत मीडिया आदान-प्रदान कार्यक्रम में भी भाग लिया। मनीला स्थित फिलीपींस विश्वविद्यालय का एक छात्र वर्तमान में छात्रवृत्ति योजना के तहत आगरा में केंद्रीय हिंदी संस्थान में हिंदी का अध्ययन कर रहा है।

सिंगापुर

आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा और 17वीं शांगरी-ला वार्ता में बीज़ वक्तव्य देने के लिए 31 मई से 2 जून, 2018 तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा और 14-15 नवंबर, 2018 को आसियान-भारत, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) तथा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उनकी दूसरी यात्रा से भारत और सिंगापुर के बीच रणनीतिक साझेदारी में एक नई गति आई तथा इसे एक नई दिशा मिली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शांगरी-ला वार्ता में बीज़ वक्तव्य देने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे। मई-जून, 2018 में उनकी यात्रा के परिणामस्वरूप समझौता ज्ञापनों, करारों और नई पहलों सहित 35 से भी अधिक ठोस नतीजे सामने आए, जिनमें लॉजिस्टिक्स एंड सर्विसेज

सपोर्ट के आपसी समन्वय संबंधी करार भी शामिल है, जो द्विपक्षीय नौसेना सहयोग को और बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चांगी नौसेना बेस की एक ऐतिहासिक यात्रा भी की, जहां वे सिंगापुर और भारतीय नौसेना के जहाजों में सवार हुए और नौसेना कर्मियों के साथ बातचीत की। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर भी नए सिरे से समझौते किए। आर्थिक क्षेत्र में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) की दूसरी समीक्षा पूरी की, जो 2010 से लंबित थी, और तीसरी समीक्षा शुरू की तथा नर्सिंग विषय पर संबद्ध पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए। कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापन निष्पन्न किए गए जिनमें सर्वप्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित करने में सहयोग करने; सार्वजनिक प्रशासन और शासन; कचरा प्रबंधन और जल पुनर्चक्रण सहित शहरी आयोजना एवं विकास; व्यापार और निवेश प्रोत्साहन; और, संभार तंत्र तथा बुनियादी ढांचे से संबंधित करार शामिल हैं। सीनियर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, रक्षा मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय डॉ. मोहम्मद मलिकी उसमान ने रायसीना वार्ता में भाग लेने के लिए 8-10 जनवरी, 2019 तक नई दिल्ली की यात्रा की। उन्होंने 8 जनवरी, 2019 को विदेश राज्यमंत्री जनरल (डॉ.) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) से मुलाकात की।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्टार्ट-अप और फिनटेक द्विपक्षीय विनियोजन के नए और महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरे। दोनों सरकारों ने फिनटेक पर एक संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के वित्तीय उत्पादों- रुपे कार्ड, बीएचआईएम-यूपीआई ऐप और यूपीआई-आधारित क्रॉस-बॉर्डर रेमिटेंस ऐप का पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ किया। नीति आयोग और पेशेवर भारतीय प्रवासी संघों (आईआईटी और आईआईएम के पूर्व छात्र संघों सहित) ने भारत में डिजिटलीकरण और नवाचार का समर्थन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में नई तकनीक (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन), शैक्षणिक अनुसंधान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए नानयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और प्रमुख भारतीय संस्थानों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। विदेशों में भारतीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने और ग्रामीण आजीविका का समर्थन करने के लिए एक अभिनव तंत्र के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कारीगरों को नियमित आधार पर सिंगापुर लाने के लिए भारतीय विरासत केंद्र में एक मंच का अनावरण किया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 1948 में सिंगापुर में महात्मा गांधी के अस्थि विसर्जन स्थल पर एक पट्टिका का अनावरण किया।

प्रधानमंत्री की नवंबर माह की यात्रा के दौरान नवाचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी में सहयोग को और बढ़ावा मिला। दोनों पक्षों ने विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक भारत-सिंगापुर

भारत-सिंगापुर उद्यम और नवोन्मेषिता प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री और सिंगापुर के प्रधानमंत्री श्री ली शिएन लूंग (31 मई, 2018)

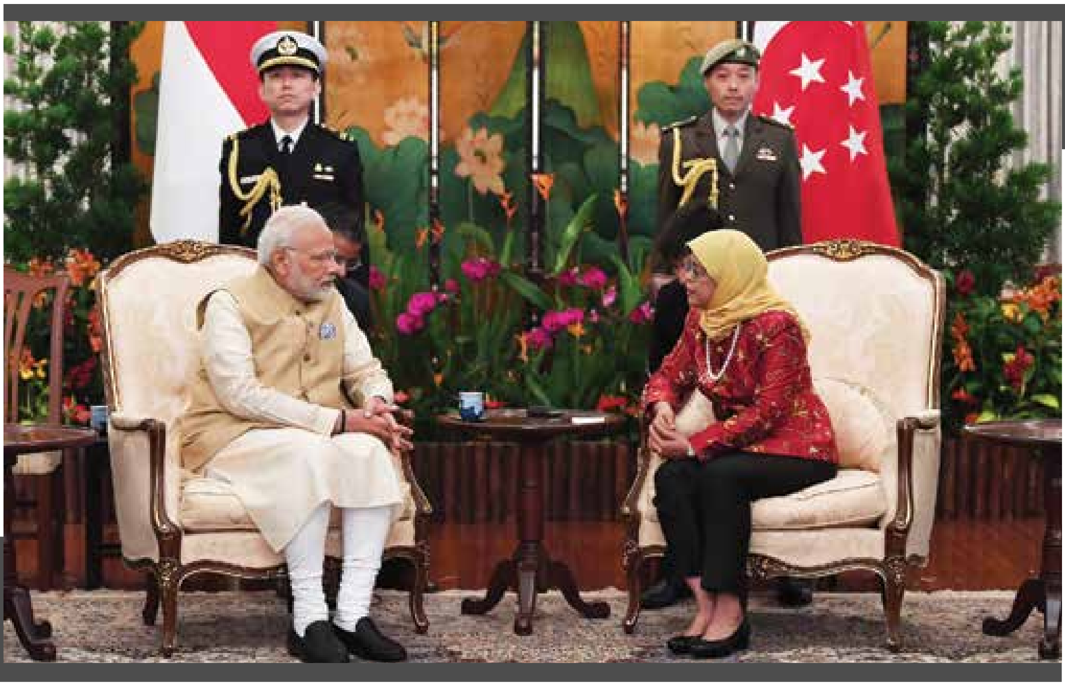

प्रधानमंत्री सिंगापुर की राष्ट्रपति हालीमाह याकोब से मुलाकात करते हुए (1 जून, 2018)

हैकथॉन पूरा किया, जिसका प्रस्ताव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पिछली यात्रा के दौरान किया था। लगभग 40,000 प्रतिभागियों के साथ इस क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े आयोजन, सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में मुख्य भाषण देने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहले शासनाध्यक्ष बने, जहां उन्होंने आर्थिक प्रगति और सशक्तिकरण के साधन के रूप में वित्तीय समावेशन और डिजिटलीकरण में भारत की सफलता का उल्लेख किया। उन्होंने भारत और आसियान के साथ शुरू होने वाले फिनटेक कंपनियों और बैंकों को जोड़ने के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म एपीआईएक्स का भी शुभारंभ किया।

इस वर्ष दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग और सिंगापुर की आसियान के अध्यक्ष के रूप में भूमिका के परिणामस्वरूप द्विपक्षीय स्तर पर नियमित रूप से परस्पर उच्च-स्तरीय यात्राएं हुईं। भारत की ओर से उच्च स्तरीय यात्राओं में वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री सुरेश प्रभु का दौरा; नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी की यात्रा; रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की यात्रा; विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) की यात्रा; सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर; युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री कर्नल (सेवानिवृत्त) श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर; आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू; उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत; और गुजरात, पंजाब, केरल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के राज्य प्रतिनिधिमंडलों की यात्राएं शामिल हैं। इनके अलावा, भारत के 150 से अधिक प्रतिनिधिमंडलों जिनमें संसद सदस्य, सचिव और वरिष्ठ अधिकारीगण शामिल थे, ने सिंगापुर का दौरा किया।

सिंगापुर की ओर से, वित्त मंत्री श्री हेंग स्वे केट; संचार, सूचना और व्यापार संबंध मंत्री, श्री एस ईश्वरन; विदेश मंत्री डॉ. विवियन बालाकृष्णन; रक्षा मंत्री डॉ. एनजी इंग हेन; राष्ट्रीय विकास मंत्री श्री लॉरेंस वोंग; सामाजिक और पारिवारिक विकास मंत्री और राष्ट्रीय विकास द्वितीय मंत्री डेसमंड ली; और वरिष्ठ परिवहन और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ. लाम पिन मिन ने दिल्ली में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के साथ-साथ राज्यों की बैठकों में भी भाग लिया। मंत्री श्री एस. ईश्वरन अक्टूबर, 2018 में देहरादून में 'डेस्टिनेशन उत्तराखंड: इन्वेस्टर्स समिट' के उद्घाटन समारोह में भाग लेने वाले एकमात्र विदेशी मंत्री थे।

इस वर्ष सिंगापुर में भारत के एक स्टार्ट-अप विनियोजन मंच, भारत-सिंगापुर एंटरप्रेन्योरशिप ब्रिज (इन्स्प्रिनियर) का सफल

शुभारंभ किया गया, जिसके तहत जनवरी 2018 और जून 2018 में दो सम्मेलन हुए जिनमें भारी तादाद में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इन्स्प्रिनियर के दूसरे संस्करण में भारत और सिंगापुर से 31 स्टार्टअप कंपनियों ने अपना प्रदर्शन किया, जिसमें उन्हें दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला। एक निजी पहल, "न्यू इंडिया इनोवेशन हब" जो सिंगापुर तथा आसियान देशों में प्रवेश करने के इच्छुक भारतीय स्टार्ट-अप्स के लिए 50,000 वर्ग फुट किराया मुक्त जगह उपलब्ध कराता है, की घोषणा की गई।

सिंगापुर भारत के लिए एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है। यह भारत के लिए निवेश का एक प्रमुख स्रोत और गंतव्य है। इस वर्ष सिंगापुर और भारत के बीच संपर्क व्यवस्था में और सुधार हुआ। जबकि गुवाहाटी को अगस्त में एक डुक एयर फ़्लाइट द्वारा सिंगापुर के साथ जोड़ा गया वहीं पुणे और विजयवाड़ा को दिसंबर 2018 में भारतीय विमान सेवा द्वारा सिंगापुर से जोड़ा गया। सिंगापुर अब अट्ठारह शहरों से सीधे जुड़ गया है जिसके तहत नौ एयरलाइनों द्वारा दोनों दिशाओं में 576 साप्ताहिक उड़ानें संचालित की जाती हैं।

इस वर्ष का मुख्य आकर्षण सिंगापुर-भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास (एसआईएमबीईएक्स) का 25वां संस्करण था, जो नवंबर 2018 में दो सप्ताह तक बंगाल की खाड़ी/अंडमान सागर क्षेत्र में आयोजित किया गया, जिसमें दोनों ओर से 20 से अधिक जहाजों, विमानों तथा पनडुब्बियों ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया। सिंगापुर सेना ने नवंबर 2018 में भारत के साथ अपना वार्षिक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया। इस वर्ष ग्यारह भारतीय नौसेना और तटरक्षक जहाजों ने सिंगापुर का दौरा किया।

दोनों पक्षों ने संस्थागत आदान-प्रदान की गति बनाए रखी। नवंबर 2018 में सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉ. एनजी इंग हेन ने एसआईएमबीईएक्स में हिस्सा लिया और रक्षा मंत्रियों की वार्ता बैठक (डीएमडी) की सह-अध्यक्षता की। अप्रैल 2018 में वार्षिक सचिव-स्तरीय रक्षा नीति वार्ता और नौसेना-से-नौसेना स्टाफ वार्ता, अगस्त 2018 में रक्षा प्रौद्योगिकी संचालन समिति की बैठक (डीटीएस), सितंबर 2018 में रक्षा कार्य समूह (डीडब्ल्यूजी) की बैठक और अक्टूबर 2018 में द्विपक्षीय आसूचना आदान-प्रदान बैठक हुई। भारत में संयुक्त प्रशिक्षण और अभ्यास के लिए द्विपक्षीय समझौते का नवीनीकरण रक्षा मंत्रियों की वार्ता बैठक (डीएमडी) में किया गया।

मंच कला, नाटक, संग्रहालय आदान-प्रदान, कला और भाषाओं सहित सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ता रहा। सिंगापुर में रहने वाले विशाल भारतीय डायस्पोरा और भारतीय विरासत केंद्र के माध्यम से सिंगापुर के आधिकारिक सहयोग से सिंगापुर में उच्चस्तरीय सांस्कृतिक गतिविधियाँ चलती रहीं जिनमें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद तथा मिशन का भी सहयोग प्राप्त हुआ। मई-जून 2018 में अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस क्षेत्र के साथ भारत के प्राचीन संबंधों को उजागर करने के लिए भारत से जुड़े तीन अलग-अलग धर्मों के पूजा स्थलों का दौरा किया, जो एक ही सड़क पर स्थित हैं, और भारतीय उच्चायोग द्वारा प्रकाशित पुस्तक "इंडिया-सिंगापुर: एंशिएंट रूट, न्यू जर्नी" का विमोचन किया।

हिंदुस्तान टाइम्स-मिंट एशिया लीडरशिप शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण अप्रैल 2018 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था। भारत-सिंगापुर रणनीतिक वार्ता, एक ट्रैक II पहल अगस्त 2018 में आयोजित की गई थी। इसका आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), अनंत-एस्पेन सेंटर और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ सिंगापुर (एनयूएस) द्वारा किया गया था। चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 30 संगठनों के सहयोग से 117 केंद्रों में 173 योग सत्रों के माध्यम से मनाया गया और इसमें लगभग 8,000 लोगों ने भाग लिया, जबकि हैशटैग # IDYSG2018 पर 76 मिलियन से भी अधिक लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह का बड़े पैमाने पर आयोजन किया गया जिसके अंतर्गत सनटेक कन्वेंशन सेंटर में दुनिया की सबसे बड़ी हाई डेफिनिशन वीडियो स्क्रीन पर गांधीजी पर वीडियो दिखाई गई और एक अंतर-स्कूल प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी की पोती श्रीमती इला गांधी, महात्मा गांधी पर वार्ता और सेमिनार की श्रृंखला में शामिल होने के लिए सिंगापुर गईं। मिशन ने स्वामी विवेकानंद द्वारा विश्व धर्म सभा में दिए गए ऐतिहासिक भाषण की 125वीं जयंती और डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का जन्मोत्सव मनाया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। मिशन ने सितंबर में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ सिंगापुर के भाषा अध्ययन केंद्र के साथ हिंदी दिवस भी मनाया। मिशन और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने अगस्त-सितंबर 2018 में डांस इंडिया एशिया पैसिफिक (डीआईएपी) के आठवें संस्करण के आयोजन में सहयोग किया।

तिमोर लेस्ते

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर ने भारत सरकार के विशेष दूत के रूप में 7-10 अप्रैल, 2018 तक दिली, तिमोर लेस्ते का दौरा किया। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और तिमोर लेस्ते के बीच दोस्ती के बंधन को और मजबूत करना था। यात्रा के दौरान, दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जो तिमोर लेस्ते के लोगों के लिए सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवा के विस्तार में सहयोग के नए रास्ते खोलेगा। विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) ने अगस्त 2018 में सिंगापुर में आयोजित एएमएम के अवसर पर तिमोर लेस्ते के विदेश मंत्री से मुलाकात की।

तिमोर लेस्ते में भारत के राजदूत श्री प्रदीप कुमार रावत ने 20-22 अगस्त, 2018 को दिली में शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले छह सदस्यीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस प्रतिनिधिमंडल ने तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति श्री फ्रांसिस्को गुटेरेस लू ओलो और तिमोर लेस्ते के प्रधान मंत्री श्री टाउर मटन रुआक से मुलाकात की और तिमोर लेस्ते के विकास लक्ष्यों में वृद्धि में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए संपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। प्रतिनिधिमंडल ने तिमोर लेस्ते चैंबर ऑफ कॉमर्स (सीसीआई), नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ तिमोर लेस्ते और यूएन हाउस में विस्तार से चर्चा की थी।

थाईलैंड

थाईलैंड के साथ भारत के संबंध वर्ष के दौरान मजबूत होते रहे। अगस्त 2018 से थाईलैंड भारत-आसियान रणनीतिक साझेदारी के लिए राष्ट्र-समन्वयक है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 31 अगस्त 2018 को काठमांडू में चौथे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के अवसर पर और 14 नवंबर, 2018 को सिंगापुर में 33वें आसियान शिखर सम्मेलन और संबंधित बैठकों के दौरान थाईलैंड के प्रधान मंत्री श्री प्रयुत चान-ओ-चा से मुलाकात की, जिस दौरान दोनों नेताओं ने पारस्परिक हित के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की।

रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 26-29 अगस्त, 2018 तक थाईलैंड का दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने थाईलैंड के प्रधान मंत्री से मुलाकात की और उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री जनरल प्रवीत वोंगसुवोन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। उन्होंने विमानवाहक पोत एचटीएमएस चक्री नरुएबेट और रॉयल थाई नेवी के नौसेना स्पेशल वारफेयर कमांड का भी दौरा किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 17-18 अप्रैल, 2018 को थाईलैंड में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने बैंकाक में दो कार्यक्रमों "फोरम ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉच्र्युनिटीज ऑन फूड प्रोसेसिंग" और "फोरम ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉच्र्युनिटीज इन लग्जरी/वेलनेस टूरिज्म" का नेतृत्व किया। उन्होंने नावा नकोर्न इंडस्ट्रियल एस्टेट का भी दौरा किया। 17 अप्रैल 2018 को बैंकॉक में "उत्तराखंड पर्यटन रोड शो" का आयोजन किया गया। उत्तराखंड पर ध्यान देने के साथ "भारत: आपका भाग्य, आपका नया गंतव्य" पर एक सेमिनार 18 अप्रैल, 2018 को थाईलैंड के वाणिज्य मंत्रालय और दूतावास द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।

थाई पक्ष की ओर से, ऊर्जा मंत्री श्री सिरी जिरापोंगफान ने 11-12 अप्रैल, 2018 को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच में भाग लेने के लिए दिल्ली का दौरा किया। 19 जुलाई, 2018 को विदेश मंत्री के सलाहकार श्री चिसिरी अनामरन नई दिल्ली में थाईलैंड के विदेश मंत्री के विशेष दूत के रूप में दिल्ली वार्ता में भाग लेने के लिए भारत आए। राजकुमारी महा चक्रि सिरिंधोर्न ने 26-29 नवंबर, 2018 तक भारत का दौरा किया। उनकी भारत यात्रा में दिल्ली, त्रिपुरा और मणिपुर के दौरे शामिल थे। 30 नवंबर, 2018 को भारत की यात्रा के दौरान थाई विदेश मंत्री श्री डॉन प्रमुदविनई ने नई दिल्ली में विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज से मुलाकात की।

द्वितीय भारत-थाईलैंड सैन्यकर्मी वार्ता 11-13 जुलाई, 2018 तक थाईलैंड में आयोजित की गई। 10वीं भारतीय नौसेना-रॉयल थाई नौसेना स्टाफ वार्ता 16-18 जुलाई, 2018 तक दिल्ली में आयोजित की गई थी। 8वीं भारतीय वायु सेना-रायल थाई वायु सेना स्टाफ वार्ता 6-10 अगस्त, 2018 तक दिल्ली में आयोजित की गई।

प्रधानमंत्री काठमांडू में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के अवसर पर थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्री प्रयुत चान-ओ-चा से मुलाकात करते हुए (31 अगस्त, 2018)

रॉयल थाई नौसेना के कमांडर-इन-चीफ एडमिरल लूचाई रुडिट ने 18-20 दिसंबर, 2018 तक भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री से मुलाकात की, नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा के साथ विचार-विमर्श किया और मुम्बई में पश्चिमी नौसेना कमान में आईएनएस कोलकाता तथा आईएनएस सिंधु विजय को देखा। भारत और थाईलैंड के बीच श्वेत पोत परिवहन सूचना आदान-प्रदान संबंधी तकनीकी करार पर 19 दिसंबर, 2018 को हस्ताक्षर किए गए।

थाई विदेश मंत्री की सलाहकार सुश्री पॉर्नपिमोल कंचनालक ने रायसीना वार्ता में शामिल होने के लिए 8-10 जनवरी, 2019 तक भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने श्रीमती विजय ठाकुर सिंह, सचिव (पूर्व) के साथ 9 जनवरी, 2019 को मुलाकात की।

दोनों पक्षों के बीच सांस्कृतिक सहयोग में प्रगति बनी रही। 28 मई 2018 को आईसीसीआर चेयर ऑफ इंडियन स्टडीज की स्थापना के लिए आईसीसीआर और चियांग माई यूनिवर्सिटी (सीएमयू) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे यह बैंकॉक के बाहर पहली आईसीसीआर पीठ बन गई।

17 जून 2018 को बैंकॉक में दूतावास द्वारा स्थानीय भागीदारों और समुदाय के सहयोग से चौथा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हई याई (सोंगख्ला प्रांत), चियांग माई, रयोंग और खॉन के में क्रमशः 10 जून, 17 जून, 23 जून और 24 जून, 2018 को अलग-अलग योग कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

थाईलैंड में पूर्व भारतीय राजदूत श्री भगवंत सिंह बिश्नोई ने 27 जून 2018 को थाईलैंड के सुप्रीम पैट्रिआर्क परम पावन सोमदत फ्रा अरियावांगसाखोट्टायम के पावन वचन सुने और उन्हें पद्म श्री पुरस्कार और अलंकरण सौंपा।

भारतीय दूतावास और थम्मासैट विश्वविद्यालय की एक संयुक्त पहल, इंडिया कॉर्नर का उद्घाटन 20 अगस्त 2018 को प्रिडी बैनोमॉन्ग इंटरनेशनल कॉलेज में किया गया था। इंडिया कॉर्नर का उद्देश्य सामान्य रूप से थम्मासैट विश्वविद्यालय के छात्रों को किताबें और आवधिक पत्रिकाएं प्रदान करना है और भारतीय अध्ययन कार्यक्रम और भारतीय अध्ययन केंद्र के लिए अधिगम केंद्र के रूप में स्थापित होना भी है।

यूएनईएससीएपी के सहयोग से दूतावास ने 2 अक्टूबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन केंद्र, बैंकॉक में अहिंसा अंतर्राष्ट्रीय दिवस और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में समारोह की शुरुआत की ।

थम्मासैट विश्वविद्यालय, बैंकॉक और आईसीसीआर के बीच आईसीसीआर हिंदी पीठ के लिए समझौता ज्ञापन का 12 अक्टूबर 2018 को तीन साल के लिए नवीनीकरण किया गया है। थम्मासैट यूनिवर्सिटी के रेक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर गैसिने विटूनचार्ट और चार्ज डीआफेयर्स श्री अबबागानी रामू ने विश्वविद्यालय के संकाय, भारतीय दूतावास और समुदाय के लगभग 50 व्यक्तियों की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

रॉयल थाई नौसेना के कमांडर-इन-चीफ एडमिरल लूचाई रुडिट ने 18-20 दिसंबर, 2018 तक भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री से मुलाकात की, नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा के साथ विचार-विमर्श किया और मुम्बई में पश्चिमी नौसेना कमान में आईएनएस कोलकाता तथा आईएनएस सिंधुविजय को देखा। भारत और थाईलैंड के बीच श्वेत पोत परिवहन सूचना आदान-प्रदान संबंधी तकनीकी करार पर 19 दिसंबर, 2018 को हस्ताक्षर किए गए।

थाई विदेश मंत्री की सलाहकार सुश्री पॉर्नपिमोल कंचनालक ने रायसीना वार्ता में शामिल होने के लिए 8-10 जनवरी, 2019 तक भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने श्रीमती विजय ठाकुर सिंह, सचिव (पूर्व) के साथ 9 जनवरी, 2019 को मुलाकात की।

2019 में 5वीं भारत-थाईलैंड विदेश कार्यालय परामर्श बैठक, 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता और 8-10 फरवरी 2019 तक पहला उत्तर पूर्व भारत उत्सव होंगे।

वियतनाम

आसियान-भारत स्मारक सम्मेलन और गणतंत्र दिवस पर माननीय अतिथि के रूप में वियतनामी प्रधान मंत्री श्री गुयेन जुआन फुच की आधिकारिक यात्रा से शुरू होकर 2018 में भारत-वियतनाम संबंधों ने भागीदारी का उल्लेखनीय स्तर प्राप्त किया है। वियतनाम के पूर्व राष्ट्रपति (स्वर्गीय) श्री त्रान दाई क्वांग की 2-4 मार्च, 2018 तक भारत की राजकीय यात्रा के साथ इसमें और गति आई है। राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने 18-20 नवंबर, 2018 तक कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री अनंत कुमार हेगड़े और संसद सदस्य डा. हिना गावित और श्री कामाख्या प्रसाद तासा के साथ वियतनाम की तीन दिवसीय राजकीय यात्रा की, जोकि दक्षिणपूर्व की उनकी पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान, वियतनाम के सूचना और संचार मंत्रालय और भारत के संचार मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन; हो ची मिन्ह नेशनल एकेडमी ऑफ पॉलिटिक्स और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन और सीआईआई और वियतनाम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (वीसीसीआई) के बीच एक सहयोग करार सहित चार करारों पर हस्ताक्षर किए गए ।

रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 12-15 जून 2018 तक वियतनाम की आधिकारिक यात्रा की। यात्रा के दौरान, उन्होंने वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के साथ वार्ता की और वियतनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात की और चौथी भारत-वियतनाम रक्षा उद्योग व्यापार बैठक हनोई में आयोजित की गई। उन्होंने न्हा ट्रांग में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क की आधारशिला रखी, जिसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में अपनी यात्रा के दौरान 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान देने की घोषणा की।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 16 वें संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता और तीसरे हिंद महासागर सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए 26-28 अगस्त 2018 को हनोई का दौरा किया। यात्रा के दौरान, नन्ह थुआन प्रांत में चाम समुदाय के लाभ के लिए अनुदान सहायता सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नन्ह थुआन प्रांत की पीपुल्स समिति के साथ 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सात समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने यात्रा के दौरान चांसरी परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने एमएसएमई क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के अवसरों का पता लगाने के लिए 4-6 सितंबर 2018 तक वियतनाम की एक अध्ययन यात्रा की । पूर्व राज्य मंत्री श्री एम जे अकबर ने 10-13 सितंबर 2018 को आसियान पर विश्व आर्थिक मंच में भाग लेने के लिए हनोई का दौरा किया।

विशिष्ट आगंतुक कार्यक्रम (डीवीपी) के तहत, मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में असम से एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें विधान सभा के सदस्य और किसान शामिल थे, ने

नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में वियतनाम समाजवादी गणराज्य के राष्ट्रपति श्री ट्रान डाई क्यांग के स्वागत समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री (03 मार्च, 2018)

मई 2018 में वियतनाम का दौरा किया। इसी तरह, क्वांग नेम प्रांत की पार्टी कमेटी के सचिव श्री गुयेन नोंग क्वैंग के नेतृत्व में वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीवी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने 16-20 अक्टूबर, 2018 तक भारत का दौरा किया।

9 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली में विदेशी कार्यालय परामर्श और सातवीं रणनीतिक वार्ता के 10 वें दौर की बैठक आयोजित की गई। भारतीय पक्ष का नेतृत्व पूर्व सचिव-पूर्व श्रीमती प्रीति सरन और वियतनामी पक्ष का नेतृत्व उप विदेश मंत्री श्री डांग दिन कुय द्वारा किया गया। वियतनाम के रक्षा सचिव और राष्ट्रीय रक्षा उप-मंत्री श्री लेफ्टिनेंट जनरल न्गुयेन ची विन्ह के नेतृत्व में, रक्षा सचिव स्तर पर वार्षिक सुरक्षा संवाद 1 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नवंबर 2016 में वियतनाम के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) और सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के उप-मंत्री के बीच हनोई में जुलाई 2018 में पहली उप मंत्री स्तरीय सुरक्षा वार्ता हुई।

2017-18 में 12.83 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार के साथ द्विपक्षीय आर्थिक भागीदारी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है । 2018 के पहले नौ महीनों के दौरान, द्विपक्षीय व्यापार 10.76 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया, जिससे 2017 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 25.21% की वृद्धि दर्ज की गई है। उच्च विकास की गति को बनाए रखने के लिए, दोनों देशों के बीच व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों की यात्राओं ने व्यापार और निवेश के अवसरों का पता लगाने के प्रयासों को सुविधाजनक बनाया है। सेकेंड सोर्स इंडिया 2018 को बढ़ावा देने के लिए सिंथेटिक रेयन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (एसआरटीईपीसी) द्वारा एक रोड शो 16 जुलाई 2018 को हनोई में आयोजित किया गया था। वियतनाम में स्मार्ट डिजिटल विलेज परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में वियतनाम में संबंधित प्राधिकरणों के साथ काम करने के लिए दो सदस्यीय टेलिकम्यूनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया प्रतिनिधिमंडल ने 20-23 अगस्त 2018 तक वियतनाम का दौरा किया। 27-28 सितंबर 2018 को, "इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 में डिजिटल कनेक्टिविटी" विषय के तहत दूसरा भारत-आसियान आईसीटी एक्सपो, 2018, हनोई, वियतनाम में आयोजित किया गया था और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का

नेतृत्व श्री रविकांत, सदस्य (सेवा), दूरसंचार आयोग ने किया था। नवयुग समूह के एक प्रतिनिधिमंडल ने उच्च तकनीकी कृषि क्षेत्र में सहयोग की संभावना का पता लगाने के लिए 23-27 अक्टूबर 2018 तक वियतनाम का दौरा किया। 19 नवंबर 2018 को राष्ट्रपति की वियतनाम यात्रा के दौरान, वियतनाम-भारत बिजनेस फोरम का आयोजन किया गया था जिसमें फिक्की, एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसोचैम) और आईएमसी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ समन्वय में सीआईआई के नेतृत्व में भारत के 60 से अधिक प्रतिनिधियों सहित 400 वियतनामी और भारतीय व्यापारियों ने भाग लिया था। व्यापार संबंधी चौथे भारत-वियतनाम संयुक्त उप-आयोग का आयोजन 22-23 जनवरी, 2019 को हनोई, वियतनाम में किया गया था।

श्री होआंग क्वोक वुओंग, उद्योग और व्यापार मंत्री के नेतृत्व में छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 9-14 अप्रैल 2018 तक 16 वें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम मंत्री बैठक में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। श्री काओ क्वोक हंग, उद्योग और व्यापार उप-मंत्री के नेतृत्व में 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सीआईआई द्वारा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के साथ सहयोग में नोम पेन्ह, कंबोडिया में 21 और 22 मई 2018 को आयोजित पांचवें भारत सीएलएमवी बिजनेस कॉन्क्लेव में भाग लिया।

भारत और वियतनाम के बीच विकास साझेदारी परियोजनाएं जारी हैं और नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। वियतनाम आईटीसीई कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का एक बड़ा लाभार्थी रहा है। वर्तमान में, वियतनाम को सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना (जीसीएसएस) के तहत 20 छात्रवृत्ति के साथ हर साल 130 आईटीईसी स्लॉट दिए जा रहे हैं ; सितंबर 2016 में प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की वियतनाम यात्रा के दौरान वियतनाम बौद्ध संघ के लिए बौद्ध और संस्कृत अध्ययन के लिए चार छात्रवृत्तियों, शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (ईईपी) के तहत 14 छात्रवृत्ति और एमजीसी छात्रवृत्ति योजना के तहत 10 छात्रवृत्ति की घोषणा की गई। त्वरित प्रभाव परियोजना योजना के तहत वर्तमान में पांच परियोजनाओं पर वियतनाम के विभिन्न प्रांतों में कार्यान्वयन के लिए काम किया जा रहा है।

रक्षा सहयोग वियतनाम के साथ हमारी व्यापक सामरिक भागीदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। दोनों देश 2015-2020 की अवधि के लिए रक्षा संबंधों पर मई 2015 में दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच हस्ताक्षरित 'संयुक्त विजन स्टेटमेंट' के आधार पर संबंधों को विकसित कर रहे हैं। शिक्षा और प्रशिक्षण इस रिश्ते में एक महत्वपूर्ण घटक बने हुए हैं। भारत वर्तमान में वियतनामी रक्षा कर्मियों को हर साल साठ-सत्तर आईटीईसी स्लॉट प्रदान करता है। थल सेना, नौसेना और वायु सेना के भारतीय प्रशिक्षण दल वियतनाम में वियतनामी सशस्त्र बलों के कर्मियों को विभिन्न भाषा, तकनीकी और परिचालन प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

दोनों सशस्त्र बलों के बीच उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान वर्ष के दौरान जारी रहा। इनमें अक्टूबर 2018 में वियतनाम पीपुल्स एयर फोर्स के कमांडर-इन-चीफ की भारत यात्रा, नवंबर 2018 में भारतीय सेना स्टाफ के प्रमुख की वियतनाम यात्रा और दिसंबर 2018 में वियतनाम पीपल्स नेवी के कमांडर-इन-चीफ की यात्रा शामिल है। दोनों सेनाओं और दोनों वायु सेनाओं के बीच वार्षिक युवा अधिकारियों का आदान-प्रदान और भारत के राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) और वियतनाम के युवा संघ के बीच युवाओं का आदान-प्रदान जारी है। अक्टूबर 2018 में वियतनाम में द्वितीय सेना-से-सेना स्टाफ वार्ता आयोजित की गई। तीसरी नौसेना-नौसेना स्टाफ वार्ता दिसंबर 2018 में और दूसरी वायु सेना-वायु सेना स्टाफ वार्ता वियतनाम में 2019 की पहली तिमाही में किए जाने के लिए निर्धारित हैं।

भारतीय जहाज नियमित रूप से वियतनाम को मैत्री पोर्ट कॉल करते हैं। तीन आईएनएस सहयाद्रि, कामोर्ता और शक्ति ने मई 2018 में दा नंगिन की सद्भावना यात्राएं की। सितंबर 2018 में, आईएनएस राणा ने हो ची मिन्ह सिटी को पोर्ट कॉल किया। अक्टूबर 2018 में वियतनाम तट रक्षक जहाज सीएसबी 8001पहली वियतनाम के तत्काल पड़ोस चेन्नई, भारत के लिए रवाना हुआ।

भारत द्वारा प्रदान की गई 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण श्रृंखला के हिस्से के रूप में बारह अपतटीय गश्ती जहाजों की खरीद के लिए मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड और वियतनाम बॉर्डर गार्ड्स के बीच संविदा कार्यान्वित की जा रही है।

दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव मजबूत बना हुआ है और वियतनामी लोगों में भारतीय संस्कृति के प्रति अत्यधिक दिलचस्पी है। चौथे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोहों में विभिन्न शहरों में हजारों वियतनामी लोगों की जोश और उत्साह के साथ भागीदारी देखी गई। हनोई के स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र (एसवीसीसी) में योग, वेद और संस्कृत

कक्षाएं और कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।एसवीसीसी ने 2018 में गणेश, दशहरा और दिवाली त्योहार मनाए।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने फरवरी 2017 के अंत में मध्य वियतनाम में माई सन में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए पंचवर्षीय परियोजना शुरू की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल के लिए दूसरा कार्य सत्र जून 2018 में समाप्त हुआ। भगवान महावीर विकलांग विकास सहयोग समिति (बीएमवीएसएस) के सहयोग से जुलाई 2018 में वियतनाम के फु थो और विन्ह फुच प्रांतों में जयपुर पैर कृत्रिम अंग फिटमेंट कैंप का आयोजन किया गया था जिसमें 500 वियतनामी नागरिकों को लाभ पहुंचा और उन्हें संतुष्ट और गरिमापूर्ण जीवन जीने में मदद मिली।

प्रशांत द्वीप देश

कुक द्वीप

कुक आइलैंड्स में 16 जून 2018 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2018 को बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में कूक आइलैंड्स के संस्कृति विभाग के सचिव श्री एंथनी तुरुआ मुख्य अतिथि थे और इसमें अस्सी से अधिक योग उत्साही लोगों ने भाग लिया।

माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य (एफएसएम)

दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध न्यूनतम लेकिन सौहार्दपूर्ण हैं। फोरम ऑफ इंडिया-पेसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन (एफआईपीआईसी) की शुरुआत के बाद से ही संबंधों में गर्मजोशी आयी है। बहुपक्षीय मंचों में, एफएसएम अंतर्राष्ट्रीय निकायों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता रहा है। भारत ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग की भावना में एफएसएम के साथ विकासात्मक सहयोग जारी रखा है और हम उनके साथ हमारे विकासात्मक अनुभव को साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। 2018 तक, एफएसएम में सैंतीस भारतीय नागरिक हैं।

फ़िजी

फिजी के साथ भारत के संबंध मजबूत हो रहे हैं। द्विपक्षीय बातचीत अधिक व्यापक और विविधतापूर्ण थी, जिसमें द्विपक्षीय दौरे, विकास साझेदारी, आईटीईसी, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान शामिल थे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने मई 2018 में फिजी का दौरा किया। यात्रा के दौरान, मंत्री ने फिजियन संसद के अध्यक्ष डॉ. जिको लुवेनी और फिजी की स्वास्थ्य मंत्री सुश्री रोजी अकबर के साथ मुलाकात की। मंत्री महोदय ने फिजी के महान्यायवादी अय्याज सईद-खैयूम की उपस्थिति में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, सुवा का स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र, सुवा के रूप में पुनः उद्घाटन किया। इस अवसर पर, मंत्री महोदय ने फिजी सरकार के एसएमई क्षेत्र में भारत सरकार की ओर से निरंतर सहायता के रूप में फिजी के अटॉर्नी जनरल को 1,704,586.80 फिजी डॉलर (840,000 अमरीकी डॉलर के बराबर) का चेक सौंपा।

सड़क परिवहन, राजमार्ग, नौवहन, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख एल. मंडाविया ने 25 और 26 अप्रैल 2018 को टोंगा का दौरा किया। वापसी में नाडी, फिजी में रूकने के दौरान, मंत्री ने 26 अप्रैल 2018 को लुटोका में गिरीमिट सेंटर में भारतीय समुदाय और प्रवासी संघों के सदस्यों की एक सभा को संबोधित किया। आयोजन के दौरान, मंत्री ने भारतीय उच्चायोग, सुवा के द्वारा नमस्ते पैसिफ़िका

महोत्सव के सफल आयोजन में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए प्रवासी संघों को अनुदान चैक और समुदाय के सदस्यों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए।

फिजी के प्रधान मंत्री कार्यालय के स्थायी सचिव श्री योगेश करण और फिजी के प्रधान मंत्री कार्यालय की मुख्य सहायक सचिव, सुश्री अमेलिया कोतोबालवु कटोआ कोइमासवाई ने 2-5 अक्टूबर, 2018 को नई दिल्ली में आईएसए की पहली महासभा में भाग लिया।

27 सितंबर 2018 को यूएनजीए की बैठक के दौरान विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने फिजी के प्रधानमंत्री (जो विदेश मंत्री भी है) रियर एडमिरल (सेवानिवृत्त) श्री जोसिया वोर्क बैनीमाराामा से मुलाकात की। फिजी के प्रधान मंत्री श्री बैनीमारमा ने फिजी के विकास, संस्कृति और लोगों के आपसी संपर्क सुदृढ़ करने में भारत के कई योगदानों को स्वीकार किया। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने फिजी के लघु एवं मध्यम उद्यम को 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की थी और 2.2 मिलियन अमरीकी डॉलर पहले ही वितरित किया जा चुका है, जबकि शेष 2.8 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि को 2018-19 के दौरान चरणों में वितरित किया जा रहा है।

आईएनएस सहयाद्री ने हवाई में बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास रिम ऑफ पैसिफिक (रिम्पैक) से लौटने के बाद 13-16 अगस्त 2018 को सुवा में सद्भावना पोर्ट कॉल किया। पोर्ट कॉल के दौरान, आईएनएस सहयाद्री ने फिजी सैन्य बल गणराज्य (आरएफएमएफ) के साथ कई संयुक्त गतिविधियां शुरू की। 15 अगस्त 2018 को, जहाज पर एक राष्ट्रीय दिवस रिसेप्शन का आयोजन किया गया; फिजी के प्रधान मंत्री मुख्य अतिथि थे। जहाज के कर्मचारियों ने यात्रा के दौरान सुवा में एक मुफ्त चिकित्सा स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन किया।

भारत ने ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के साथ, फिजी आम चुनाव 2018 के लिए बहुराष्ट्रीय पर्यवेक्षक समूह (एमओजी) की सह-अध्यक्षता की। असम के मुख्य चुनाव अधिकारी श्री मुकेश चंद्र साहू के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग के दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने एमओजी में भाग लिया। भारत सरकार ने पांच महिंद्रा एसयूवी वाहनों और 6000 अमिट स्याही की बोतलें उपहार में देकर फिजी के चुनाव कार्यालय को भी सहयोग दिया।

महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किए जा रहे मंत्रालय के कार्यक्रमों के अनुसरण में, उच्चायोग ने 2 अक्टूबर 2018 को इंडिया हाउस में गांधीजी के जीवन और शिक्षाओं पर स्लाइडों को एलईडी पर दर्शाया।

पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से, उच्चायोग ने 19-21 अक्टूबर 2018 को सुवा में भारतीय व्यवसायों को प्रदर्शित करने के लिए "बेस्ट ऑफ इंडिया शो" का आयोजन किया। चालीस से अधिक भारतीय कंपनियों ने शो में भाग लिया और फिजीयन खरीदारों के साथ बी 2 बी बैठकें की। भारतीय उच्चायोग ने नाडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ संयुक्त रूप से भारत-फिजी व्यापार संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 4 अगस्त 2018 को नाडी में भारत-फिजी व्यापार मंच की दूसरी बैठक की।

फिजी में 16-24 जून 2018 के दौरान अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2018 को योग सप्ताह के रूप में बड़े पैमाने पर मनाया गया। फिजी के लाबासा, सुवा और लुतोका शहरों में तीन कार्यक्रम आयोजित किए गए। आईसीसीआर द्वारा प्रायोजित 10-सदस्यीय तपस्या, एक समकालीन नृत्य समूह, ने 72 वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह में प्रस्तुत दी, जिसे 15 अगस्त 2018 को आईएनएस सहयाद्री पर मनाया गया, 14 अगस्त 2018 को सुवा हिबिस्कस समारोह, मैत्रीपूर्ण उत्तर महोत्सव, 23 अगस्त,2018 को लबासा में और 16-22 अगस्त, 2018 को उनकी यात्रा के दौरान 24 अगस्त, 2018 को लुतोका गिरमिट केंद्र आयोजित किए गए।

किरिबाती

किरिबाती ने आईएसए के फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि की और इस वर्ष पूर्ण सदस्य बन गया। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल एनर्जी मंत्री श्री रोटेक्की टेकाइरा के साथ किरिबाती के अवसंरचना एवं टिकाऊ विकास मंत्रालय के उप सचिव श्री अल्बर्ट ब्रेचफेल्ड ने 2-5 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली में आईएसए की पहली महासभा में भाग लिया।

किरिबाती में बेटियो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तरावा, में 20 जून 2018 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, 2018 बहुत उत्साह के साथ मनाया गया। राष्ट्रपति श्री तनीति मामाउ ने मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ायी और योग आसनों का प्रदर्शन भी किया।

नाउरू

नाउरू बैरन के राष्ट्रपति श्री दिवावेसी वाका ने महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रसिद्ध भजन "वैष्णव जन" गाया। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति वाका को उनके भावाभिव्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से उन्हें धन्यवाद दिया।

रक्षा राज्य मंत्री डॉ. श्री सुभाष भामरे, ने 16-18 मई 2018 को नाउरू का दौरा किया। यह भारत की ओर से नाउरू की पहली मंत्रिस्तरीय यात्रा थी। यह यात्रा भी ऐतिहासिक थी क्योंकि नाउरू ने 17 मई 2018 को अपने संविधान दिवस की 50 वीं वर्षगांठ मनाई और मंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में भाग लिया। मंत्री ने नाउरू के राष्ट्रपति और नाउरू सरकार के पूरे मंत्रिमंडल सहित नाउरू सरकार के सभी गणमान्य व्यक्तियों के साथ मुलाकात की।

उच्चायुक्त श्री विश्वास सपकाल ने 3-6 सितंबर 2018 को नाउरू में आयोजित 49 वें प्रशांत द्वीपसमूह मंच शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया और संवाद साझेदार मंच में भारत का वक्तव्य प्रस्तुत किया। इस आयोजन के मौके पर, उच्चायुक्त ने इस मंच की मेजबानी के लिए नाउरू को भारत सरकार के समर्थन के रूप में 22 महिंद्रा एसयूवी नाउरू के राष्ट्रपति को सौंप दी। वाहनों का राष्ट्रों के प्रमुखों द्वारा फोरम के दौरान उपयोग किया गया था और इससे नाउरू में ' मेड इन इंडिया' वाहनों का जबरदस्त प्रभाव पड़ा।

वाणिज्य, उद्योग और पर्यावरण सचिव श्री बेरीलिन जेरेमिया और ऑस्ट्रेलिया में नाउरू की काउंसिल जनरल सुश्री रोजी इरेडेट हैरिस ने 2-5 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली में आईएसए की पहली महासभा में भाग लिया।

नाउरू में 22 जून 2018 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2018 को बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। राष्ट्रपति श्री दिवावेसी वाका ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ायी और योग आसनों का प्रदर्शन भी किया।

नियू

नियू भारत की विकास सहायता का एक लाभार्थी है। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित चौथे टेलीकॉम प्रोजेक्ट का पहला चरण पूरा होने वाला है। नियू ने इस परियोजना में और विस्तार करने के लिए और सहायता का अनुरोध किया है। नियू में आईटी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने संबंधी कार्य प्रगति पर है।

पापुआ न्यू गिनी

भारत-पापुआ न्यू गिनी संबंध मधुर और मैत्रीपूर्ण हैं। वर्ष 2018 में भारत और पीएनजी के बीच समग्र द्विपक्षीय क्रियाकलापों में वृद्धि हुई है। राज्य मंत्री जनरल (डॉ) वीके सिंह (सेवानिवृत्त) ने अगस्त 2018 में सिंगापुर में एएमएम के दौरान पीएनजी के विदेश मंत्री श्री रिम्बिंक पाटो से मुलाकात की। एक तीन सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं, ने 25-29 नवंबर, 2018 तक पीएनजी का दौरा किया और पीएनजी में अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं (बायर-मदंग सड़क परियोजना के लिए 60 मिलियन अमरीकी डॉलर और होसकिन्स-किम्बे सड़क परियोजना के लिए 40 मिलियन अमरीकी डॉलर) के वित्तपोषण के उद्देश्य से भारत निर्यात-आयात बैंक के बीच 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण श्रृंखला संबंधी समझौते को अंतिम रूप देने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों से मिले। प्रतिनिधिमंडल ने होसकिन्स-किम्बे सड़क परियोजना स्थल का भी दौरा किया।

श्री सैम बेसिल, आईसीटी और ऊर्जा मंत्री 11 मार्च, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित आईएसए के संस्थापक सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री पतिलियास गामतो ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रक्रिया देखने के लिए 10-16 मई 2018 तक बेंगलुरु में तीन सदस्यीय पापुआ न्यू गिनी के चुनाव आयोग के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और पापुआ न्यू गिनी में स्थानीय सरकार के चुनावों के लिए ईवीएम/वीवीपैट की खरीद के बारे में बीईएल अधिकारियों के साथ बातचीत की। अक्टूबर, 2018 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की

पहली आम सभा में भाग लेने के लिए प्रबंधक, विद्युत-ऊर्जा प्रभाग, संचार, सूचना तथा प्रौद्योगिकी एवं ऊर्जा मंत्रालय और संचार मंत्रालय में प्रथम सचिव, को शामिल करके गठित दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली का दौरा किया।

भारत सरकार ने पीएनजी में भूकंप से राहत के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की। पीएनजी विश्वविद्यालय में भारत-पीएनजी सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केन्द्र (सीईआईटी) के परिसर में नवीनीकरण का काम दिसंबर 2018 तक दक्षिण-दक्षिण सहयोग के तहत भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से पूरा होने की उम्मीद है। भारत सरकार ने सीईआईटी के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा पाठ्यक्रम सामग्री और मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण प्रदान किया है।

मेसर्स केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड ने 13 सितंबर, 2018 को पीएनजी पावर लिमिटेड के साथ रामू ट्रांसमिशन सिस्टम्स रीइनफोर्समेंट परियोजना के लिए जेआईसीए जापान द्वारा वित्तपोषित 489 करोड़ (किना 227 मिलियन) अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। एस्सार प्रोजेक्ट्स (पीएनजी) लिमिटेड, जोकि एक भारतीय कंपनी है, ने किना 77.5 मिलियन (26 मिलियन अमरीकी डॉलर) मूल्य के मदंग हवाई अड्डे के उन्नयन के लिए पापुआ न्यू गिनी में एक नई परियोजना हासिल की। इस आशय का एक अनुबंध 14 नवंबर, 2018 को पोर्ट मोरेस्बी में नेशनल एयरपोर्ट कॉरपोरेशन, एचबीएस (पीएनजी) लिमिटेड और एनएसी बोर्ड के साथ हस्ताक्षर किया गया था। मौजूदा टर्मिनल के स्थान पर एक नया टर्मिनल भवन बनाने के लिए यह एडीबी द्वारा वित्त पोषित परियोजना है। पीएनजी के लिए भारत की विकास सहायता उल्लेख योग्य है। पीएनजी के चार छात्रों ने भारत में आईटीईसी प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

चौथा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 2018 को पीएनजी विश्वविद्यालय के सहयोग से मनाया गया। योग में लगभग 150 योग प्रेमियों ने भाग लिया। भारतीय संस्कृति शिक्षक (टीआईसी) ने योग सत्र आयोजित किए। श्री ससिंद्रन मुथवेल, गवर्नर, पश्चिम न्यू ब्रिटेन प्रांत, जिन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है, इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में एक दीर्घकालिक आईसीसीआर भारतीय अध्ययन पीठ स्थापित करने के लिए आईसीसीआर की ओर से उच्चायुक्त श्री विजय कुमार द्वारा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और पीएनजी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लाई के बीच एक समझौता ज्ञापन 17 अगस्त 2018 को हस्ताक्षर किया गया था।

मार्शल द्वीप समूह (आरएमआई)

वर्ष 2018 ऐतिहासिक है, क्योंकि इस वर्ष भारत की ओर से मार्शल द्वीप समूह (आरएमआई) की सर्वप्रथम मंत्रिस्तरीय यात्रा की गई। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री उपेंद्र कुशवाहा ने 10 और 11 जुलाई, 2018 को आरएमआई की यात्रा की। यात्रा के दौरान, राज्य मंत्री श्री उपेंद्र कुशवाहा ने आरएमआई के राष्ट्रपति डॉ. हिल्डा हेइन से मुलाकात की और विदेश मंत्री श्री जॉन एम सिल्क और आरएमआई के मंत्रिमंडल के कई सदस्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों और ब्लू इकोनॉमी, जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूलन-शमन प्रथाओं, आपदा तैयारियों, स्वास्थ्य, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे अन्य क्षेत्रों में संबंधों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि की।

आरएमआई की ओर से एक अनुरोध पर, भारत ने और एटोल स्थानीय सरकार के एक जल और स्वच्छता परियोजना प्रस्ताव के लिए 3,00,000 अमरीकी डॉलर का अनुदान देने का वचन दिया। इस परियोजना के लिए 1,50,000 अमरीकी डॉलर की राशि आरएमआई के लिए पहली किश्त के रूप में दी गई।

पलाऊ गणराज्य

पलाऊ के साथ भारत की विकास साझेदारी निरंतर बढ़ती जा रही है और भारत सरकार ने 2,00,000 अमरीकी डॉलर के वार्षिक पीआईएफ अनुदान के तहत पलाऊ में कई परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया है। पलाऊ सरकार द्वारा वर्ष 2017 और 2018 को क्रमशः 'परिवार वर्ष' और 'स्वास्थ्य वर्ष' घोषित किया गया था, जिसके लिए भारत द्वारा वार्षिक अनुदान प्रदान किया गया है। पलाऊ के दो प्रतिभागियों ने जयपुर के बेयरफुट कॉलेज में सोलर मामास के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त

किया। पलाऊ में भारत के राजदूत ने 1 अक्टूबर, 2018 को पलाऊ गणराज्य की 24वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया। 2 अक्टूबर, 2018 को पलाऊ के राष्ट्रपति श्री टॉमी ई. रेमेगासाऊ जूनियर और राजदूत ने पलाऊ में संयुक्त रूप से महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह की मेजबानी की। पलाऊ के राष्ट्रपति ने 21 जून 2018 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के समारोह का नेतृत्व किया।

समोआ

समोआ के साथ भारत का विकासात्मक सहयोग निरंतर बढ़ता रहा। जनजातीय कार्य मंत्रालय में रज्यमंत्री श्री जसवंतसिंह भाभोर ने 20-23 मई, 2018 तक विशेष दूत के रूप में समोआ का दौरा किया। भारत की ओर से यह समोआ की पहली मंत्रिस्तरीय यात्रा थी। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने उप प्रधान मंत्री के साथ-साथ अन्य मंत्रियों के साथ बातचीत की। चर्चा में द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया।

समोआ ने गंभीर रूप से बीमार रोगियों को भारत में इलाज के लिए भेजने के लिए भारत में अपोलो अस्पतालों के साथ एक समझौता किया। इस समझौते में समोआ के डॉक्टरों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए उनके भारत दौरे भी शामिल हैं। समोआ में सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के संबंध में कार्य प्रगति पर है।

सोलेमन द्वीप समूह

सोलोमन द्वीप समूह और भारत के संबंध मैत्रीपूर्ण रहे हैं। इस वर्ष सोलेमन द्वीप समूह के दो नागरिकों ने आईटीईसी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लिया। चौथा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सोलेमन द्वीप समूह के एक नागरिक श्री जोनाथन औना ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उत्सव के एक भाग के रूप में “वैष्णव जन तो” कविता को गाया।

टोंगा

सड़क परिवहन, राजमार्ग, पोत परिवहन, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख लाल मंडाविया ने 25 और 26 अप्रैल 2018 को टोंगा का दौरा किया। यात्रा के दौरान, मंत्री ने टोंगा के प्रधान मंत्री श्री अकिलिसी पोहिवा से मुलाकात की और ट्रॉपिकल साइक्लोन सीता के मद्देनजर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता में से 5,00,000 अमरीकी डॉलर की तत्काल राहत सहायता दी। यात्रा के दौरान, मंत्री ने उप प्रधान मंत्री और बुनियादी ढांचा मंत्री, वित्त और राष्ट्रीय योजना मंत्री के साथ-साथ टोंगा के कृषि मंत्री से भी मुलाकात की।

टोंगा ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन कार्यढाँचा समझौते की पुष्टि की और आईएसए के पूर्ण सदस्य बन गए। श्री पाओसी मटैले तई, मौसम विज्ञान, ऊर्जा, सूचना, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और संचार मंत्री के साथ-साथ श्री केओ किलाहाऊ सेफ़ाना, ऊर्जा विशेषज्ञ ने 2-5 अक्टूबर, 2018 को नई दिल्ली में आईएसए की पहली आम सभा में भाग लिया। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2018 16 जून 2018 को टोंगा में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। **स्वास्थ्य मंत्रालय, टोंगा सरकार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ऑफसिना ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया।**

तुवालु

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने 29-31 मई 2018 तक तुवालु की यात्रा की जोकि भारत की ओर से तुवालू की अभी तक की पहली मंत्रिस्तरीय यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने देश के

सभी महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों के साथ मुलाकात की जिनमें राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष तथा तुवालु मंत्रिमंडल के कई मंत्रीगण शामिल थे।

श्री मैकेंज़ी किरीटोम, कार्यवाहक विदेश मंत्री श्री फकवाए तौमिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ 2-5 अक्टूबर, 2018 को नई दिल्ली में आईएसए की पहली आम सभा में शामिल हुए। 20 जून, 2018 को तुवालु में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन तुवालु के प्रधान मंत्री श्री एनेल सोपगा ने किया।

वानुअतु

उच्चायुक्त ने 25 जुलाई, 2018 को सुवा में वानुअतु के प्रधान मंत्री श्री शार्लोट सालवाई को 2,00,000 अमरीकी डॉलर का चेक सौंपा, जो अम्बे द्वीपों पर हुए ज्वालामुखी विस्फोट के मद्देनज़र उस द्वीप के लोगों की निकासी तथा पुनर्वास के लिए भारत सरकार की ओर से अनुदान सहायता के रूप में दिया गया। प्रधानमंत्री श्री शाचार्लोट सालवाई ने इस त्रासदी के समय दी गई सहायता की सराहना की और भारत सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि “जरूरत के समय काम आनेवाला मित्र ही वास्तव में एक मित्र है”। वानुअतु ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन कार्यढाँचा करार की अभिपुष्टि की और आईएसए के पूर्ण सदस्य बन गए। श्री गैरी एरिक, प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रामीण विद्युतीकरण 2-5 अक्टूबर, 2018 तक नई दिल्ली में आईएसए की पहली आम सभा में शामिल हुए। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2018 काफी उत्साह के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन विदेश मंत्रालय, वानुअतु सरकार के कार्यवाहक निदेशक, श्री माइक मसावोवकाल द्वारा किया गया ।

‘क्लाइमेट अर्ली वार्निंग सिस्टम’ परियोजना, जिसका वित्तपोषण भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि के माध्यम से किया गया और यूएनडीपी, सुवा द्वारा कार्यान्वित किया गया, के तहत किरिबाती, मार्शल द्वीप समूह, फेडेरेटिव स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया (एफएसएम), नाउरू, सोलेमन द्वीप समूह और टोंगा के 17 अधिकारी राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की, भारत में एक माह का जल विज्ञान प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 19 जून, 2018 को रवाना हुए।

आसियान

आसियान-भारत फिल्म समारोह

मंत्रालय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से 25-30 मई, 2018 तक नई दिल्ली में पहला भारत-आसियान फिल्म महोत्सव का आयोजन किया। आसियान के सदस्य राष्ट्रों ने तैंतीस कलात्मक और समकालीन फिल्में 6 दिवसीय लंबे उत्सव के दौरान प्रदर्शित की जिनमें भारत से तीन फिल्में शामिल थीं। इसके समानांतर फिल्म निर्माण और संपादन, फिल्मों और विपणन के संयुक्त उत्पादन में सहयोग आदि विषयों पर पैनल चर्चा आयोजित की गई।

समुद्री सुरक्षा और सहयोग पर तीसरा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ साझेदारी में विदेश मंत्रालय; आरआईएस में नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन (एनएमएफ) और आसियान-इंडिया सेंटर ने 08 और 09 जून, 2018 को भुवनेश्वर में समुद्री सुरक्षा और सहयोग पर तीसरा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया जिसमें 13 ईएएस देशों के उच्च रैंकिंग अधिकारियों ने भाग लिया। सम्मेलन में समुद्री सहयोग, समुद्री सुरक्षा, समुद्री संरक्षा, अच्छी सामुद्रिक व्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी और समुद्री संसाधनों के टिकाऊ उपयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई।

समुद्री अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनॉमी) पर द्वितीय भारत-आसियान कार्यशाला

समुद्री अर्थव्यवस्था समावेशी और सतत आर्थिक विकास एवं वृद्धि हेतु तेजी से उभरती उत्प्रेरक बनती जा रही है। आसियान और भारत में, समुद्री अर्थव्यवस्था की पहचान तटीय क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के एक नए स्तंभ के रूप में की जाती है और समुद्री संसाधनों के स्थायी दोहन के माध्यम

से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने और समुद्री अर्थव्यवस्था में भारत-आसियान सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से द्वितीय भारत-आसियान समुद्री अर्थव्यवस्था कार्यशाला का आयोजन 18 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली में किया गया। कार्यशाला के प्रतिभागियों ने दस नीतिगत सिफारिशें अपनाईं, जिन्हें 19-20, जुलाई 2018 को नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली डायलॉग एक्स के उद्घाटन पूर्ण सत्र में विदेश मंत्री को सौंपा गया था।

दिल्ली संवाद एक्स

दिल्ली डायलॉग आसियान और भारत के बीच राजनीतिक-सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक वार्षिक ट्रैक 1.5 मंच है। “भारत-आसियान समुद्री सहयोग का सुदृढ़ीकरण” विषय पर दिनांक 19 और 20 जुलाई 2018 को नई दिल्ली में दिल्ली डायलॉग (डीडीएक्स) के 10वें वर्षगांठ संस्करण का आयोजन किया गया, जिसमें तीन कैबिनेट मंत्री, चार राज्य मंत्री तथा आसियान सचिवालय से उप महासचिव के अलावा आसियान सदस्य राष्ट्र देशों से एक वरिष्ठ अधिकारी ने भाग लिया। भारत और आसियान सदस्य राष्ट्रों के (एएमएस) राजनीतिक नेताओं, नीति निर्माताओं, वरिष्ठ अधिकारियों, राजनयिकों, व्यापार जगत के नेताओं, थिंक टैंकों और शिक्षाविदों तथा प्रतिनिधियों को मिलाकर कुल 400 प्रतिनिधियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने अपने संबोधन में एक ऐसे अग्रगामी एजेंडे पर जोर दिया जो हमारी साझी समुद्री विरासत को फिर से हासिल करने की कोशिश करे। कुछ ऐसे क्षेत्रों की उन्होंने पहचान की जहाँ आसियान और भारत मिलकर सहयोग कर सकते थे और समुद्री अर्थव्यवस्था, समुद्री सुरक्षा और मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर), समुद्र में आतंकवाद और समुद्री डकैती का मुकाबला करने और अंतरराष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा शामिल थे।

मेकांग गंगा सहयोग मंत्री बैठक

मेकांग गंगा सहयोग पहली और सबसे पुरानी मेकांग पहल है और भारत की एक्ट ईस्ट नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 9 अगस्त, 2018 को सिंगापुर में 9वीं मेकांग गंगा सहयोग (एमजीसी) मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की गई। विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारत और एमजीसी देशों ने पर्यटन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), शिक्षा, आपदा प्रबंधन, जल, स्वास्थ्य और कृषि आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया ।

एएसईएम शिखर सम्मेलन

उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने 18 और 19 अक्टूबर, 2018 को बेल्जियम के ब्रुसेल्स में आयोजित 12वें एएसईएम शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। शिखर सम्मेलन में उपराष्ट्रपति ने यूरोप और एशिया

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी के दूसरे शिखर सम्मेलन, 2018 में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी सदस्य राष्ट्रों के राजनेताओं के साथ प्रधानमंत्री (14 नवंबर, 2018)

के लिए मुख्य मंच के रूप में एएसईएम की भूमिका पर जोर देने के लिए बातचीत को मजबूत करने, सहयोग को बढ़ावा देने और वैश्विक चुनौतियों, जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, वैश्विक शांति और सुरक्षा, समुद्री अभिशासन, नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का संरक्षण और सुदृढ़ीकरण, और 2030 टिकाऊ विकास लक्ष्यों की दिशा में काम करने के प्रयोजनार्थ सर्वसम्मति से विश्व के नेताओं का साथ दिया। इस दौरान, उपराष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है और जो शांति और स्थिरता के लिए खतरा बना हुआ है, के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद संबंधी व्यापक अभिसमय निष्पन्न करने का आह्वान किया। उन्होंने आर्थिक अपराधियों द्वारा सार्वजनिक संपत्ति के आपराधिक दुरुपयोग से उत्पन्न चुनौतियों पर नेताओं का ध्यान आकर्षित किया और एएसईएम साझेदारों को ऐसे अपराधियों को आश्रय न देने और वित्तीय जानकारी के शीघ्र और समय पर आदान-प्रदान के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए कहा।

आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस (एडीएमएम+)

आसियान रक्षा मंत्रियों की पाँचवीं बैठक प्लस (एडीएमएम+) 20 अक्टूबर, 2018 को सिंगापुर में आयोजित की गई थी। रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। मंत्रियों ने कोरियाई प्रायद्वीप, दक्षिण चीन सागर की स्थिति, बड़े पैमाने पर विनाशकारी हथियारों के प्रसार और साइबर खतरों जैसे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में हवाई मार्गों और समुद्री गलियारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आतंकवाद के खतरे को रोकने और मुकाबला करने तथा व्यावहारिक विश्वास सृजन उपायों के संबंध में विशिष्ट संयुक्त बयान जारी किए गए।

आसियान-भारत अनौपचारिक ब्रेकफास्ट शिखर सम्मेलन

14 और 15 नवंबर, 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा मुख्य रूप से आसियान-संबंधित शिखर सम्मेलन में भाग लेने और विशेषकर 2014 में भारत द्वारा 'एक्ट ईस्ट नीति' प्रतिपादित करने के उपरांत आसियान क्षेत्र के साथ तेजी से बढ़ते संबंधों को और गति प्रदान करने के लिए थी। वर्ष 2018 में दो भारत-आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए। 25 जनवरी, 2018 को नई दिल्ली में भारत-आसियान स्मारक सम्मेलन और 15 नवंबर, 2018 को सिंगापुर में आयोजित भारत-आसियान अनौपचारिक ब्रेकफास्ट शिखर सम्मेलन में भारत-आसियान संबंधों के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला गया। सिंगापुर में भारत-आसियान अनौपचारिक ब्रेकफास्ट शिखर सम्मेलन के दौरान, सभी दस आसियान सदस्य राज्य के नेताओं ने भाग लिया, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र

सिंगापुर में 13वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के पूर्ण अधिवेशन में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्य राष्ट्रों के राजनेता के साथ प्रधानमंत्री (15 नवंबर, 2018)

सिंगापुर में आसियान-भारत अनौपचारिक ब्रेकफास्ट शिखर सम्मेलन, 2018 में आसियान देशों के राजनेताओं के साथ प्रधानमंत्री (15 नवंबर, 2018)

मोदी ने भारत की "एक्ट-ईस्ट नीति" में आसियान की एकता और केंद्रीयता की विशेषता पर जोर दिया। उन्होंने आसियान की सर्वसम्मति आधारित दृष्टिकोण की सराहना की और आसियान की केंद्रीयता पर आधारित एक खुले और समावेशी क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना की वकालत की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आसियान के साथ व्यापार और निवेश संबंधों को गहरा करने के लिए समर्थन व्यक्त किया और आसियान के साथ क्षेत्रीय संपर्क व्यवस्था को बेहतर बनाने के महत्व पर जोर दिया, जिसमें भूमि, समुद्र और डिजिटल संपर्क व्यवस्था शामिल हैं। 1 जून, 2018 को सिंगापुर में संबोधित किए गए अपने शांगरी-ला संवाद का उल्लेख करते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत-प्रशांत के संबंध में उनके द्वारा उल्लिखित सिद्धांतों को इस क्षेत्र के भीतर व्यापक स्वीकृति मिली है।

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर, 2018 को सिंगापुर में आयोजित 13वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी शामिल हुए जो भारत-प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख नेतृत्व वाला एक मंच है। नेताओं ने आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, परमाणु अप्रसार, कोरियाई प्रायद्वीप, दक्षिण चीन सागर आदि सहित वैश्विक सरोकार वाले मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने भारत-प्रशांत के संबंध में भारत के दृष्टिकोण की बात की और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान नेतृत्व वाले अन्य सुरक्षा तंत्रों जैसे एडीएमएम + के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता की बात कही। उन्होंने भारत-प्रशांत क्षेत्र की समृद्धि और सुरक्षा बढ़ाने में व्यापार और निवेश के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने सामयिक मुद्दों जैसे विदेशी आतंकवादियों तथा स्वदेश वापल लौटने वाले; समुद्री प्लास्टिक का मलबा; स्मार्ट सिटीज़; परमाणु और रेडियोधर्मी सामग्री का सुरक्षित उपयोग; आईसीटी और डिजिटल अर्थव्यवस्था के बारे में पाँच ईएएस वक्तव्यों को स्वीकार करने की दिशा में ईएएस नेताओं का साथ दिया। विशेष रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी आतंकवादियों तथा स्वदेश वापल लौटने वाले मुद्दे पर ईएएस वक्तव्य को अपनाने के लिए ईएएस की सराहना की और उम्मीद की कि सदस्य राष्ट्रों के बीच सहयोग बयानों से परे तथा और अधिक व्यावहारिक सहयोग की ओर बढ़ेगा।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) समझौता

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी एक प्रस्तावित व्यापक मुक्त व्यापार समझौता है, जिसमें दस आसियान सदस्य राष्ट्रों और उनके छह एफटीए भागीदारों अर्थात् भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, कोरिया गणराज्य और न्यूजीलैंड के बीच बातचीत की जा रही है। आरसीईपी का उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच व्यापक रूप से आर्थिक जुड़ाव को गहरा करना है। अब तक नेतृत्व स्तरीय दो शिखर बैठकें, मंत्रिस्तरीय 12 बैठकें और विशेषज्ञ स्तरीय 24 दौर की बैठकें हो चुकी हैं। 14 नवंबर, 2018 को सिंगापुर में आयोजित

आरसीईपी शिखर सम्मेलन में चल रही वार्ताओं की समीक्षा करने के लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उल्लेख किया कि आरसीईपी को शीघ्र निष्पन्न किए जाने से आर्थिक विकास और रोजगार सृजन बढ़ सकता है। उन्होंने इस प्रकार अब तक की वार्ताओं में हुई पर्याप्त प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और एक प्रभावी और व्यापक समझौते के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया, जो संतुलित, संतोषजनक और पारस्परिक रूप से लाभप्रद है।

भारत-आसियान इनोटेक शिखर सम्मेलन, 29 और 30 नवंबर 2018

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स तथा उद्योग परिसंघ के साथ नई दिल्ली में 29-30 नवंबर, 2018 को "आविष्कारी विकास की ओर तेजी लाने" विषय पर भारत-आसियान इनोटेक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत तथा आसियान क्षेत्र से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और अभिनव उत्पादों का प्रदर्शन करना था ताकि संभावित कारोबारी विनियोजन तथा गठजोड़ किया जा सके। यह शिखर सम्मेलन, जिसमें 300 से अधिक प्रतिनिधियों और 40 प्रदर्शकों ने भाग लिया, एक इंट्रैक्टिव तथा एकीकृत कार्यक्रम था, जिसने नवोन्मेषी पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े सभी हितधारकों को आपस में बातचीत करने का मंच प्रदान किया जिसमें उन्हें अपने उत्पाद संबंधी विचारों तथा सुविधाओं का संवर्धन करने के लिए आविष्कारकों द्वारा एक प्रदर्शनी आयोजित करना शामिल था ताकि वे कारोबार तथा कारोबार (बी2बी) तथा कारोबार तथा सरकार (बी2जी) के बीच बैठकें आयोजित कर सकें।

3

पूर्वी एशिया

जापान

वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान स्थापित भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में 2018 तक उल्लेखनीय प्रगति होती रही है और यह भारत की एक्ट ईस्ट नीति की आधारशिला बना हुआ है।

वर्ष 2018 में, 28 और 29 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की जापान यात्रा, इस द्विपक्षीय संबंध की मुख्य घटना है, इस यात्रा ने दो महत्वपूर्ण लोकतंत्रों के रूप में हमारे हितों और मूल्यों के बढ़ते अभिसरण का प्रदर्शन किया और हमारी भागीदारी के लिए नए रास्ते खोले। यात्रा के दौरान, जापान के प्रधानमंत्री, शिंजो आबे ने 28 अक्टूबर, 2017 को यामांशी प्रान्त में अपने पैतृक घर पर प्रधानमंत्री मोदी का आतिथ्य कर एक विशेष भाव दर्शाया। यह जापान के किसी प्रधानमंत्री द्वारा किसी विदेशी गणमान्य व्यक्ति का इस प्रकार आतिथ्य करने की पहली घटना थी।

वार्षिक शिखर सम्मेलन बहुआयामी संबंधों में हाल की प्रगति की समीक्षा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर था। शिखर सम्मेलन में भारत-जापान द्विपक्षीय सहयोग में नई उपलब्धियां रहीं जैसा कि घोषणाओं से स्पष्ट है, जापान के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) में शामिल होने, बाहरी अंतरिक्ष में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने वार्षिक अंतरिक्ष वार्ता शुरू करने के अलावा आर्थिक साझेदारी, डिजिटल और नई प्रौद्योगिकियों, स्वास्थ्य, डाक सेवाओं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शैक्षणिक आदान-प्रदान, पर्यावरण और खेल जैसे विविध क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। शिखर सम्मेलन के दौरान सरकार-से-व्यापार (जी2बी) और व्यापार-से-व्यापार (बी2बी) के समझौते और बुनियादी ढांचे, वन प्रबंधन आदि क्षेत्रों में जापान द्वारा सरकारी विकास सहायता (ओडीए) के ऋण समझौतों के लिए टिप्पणियों के आदान-प्रदान पर भी हस्ताक्षर किए गए। भारत और जापान ने

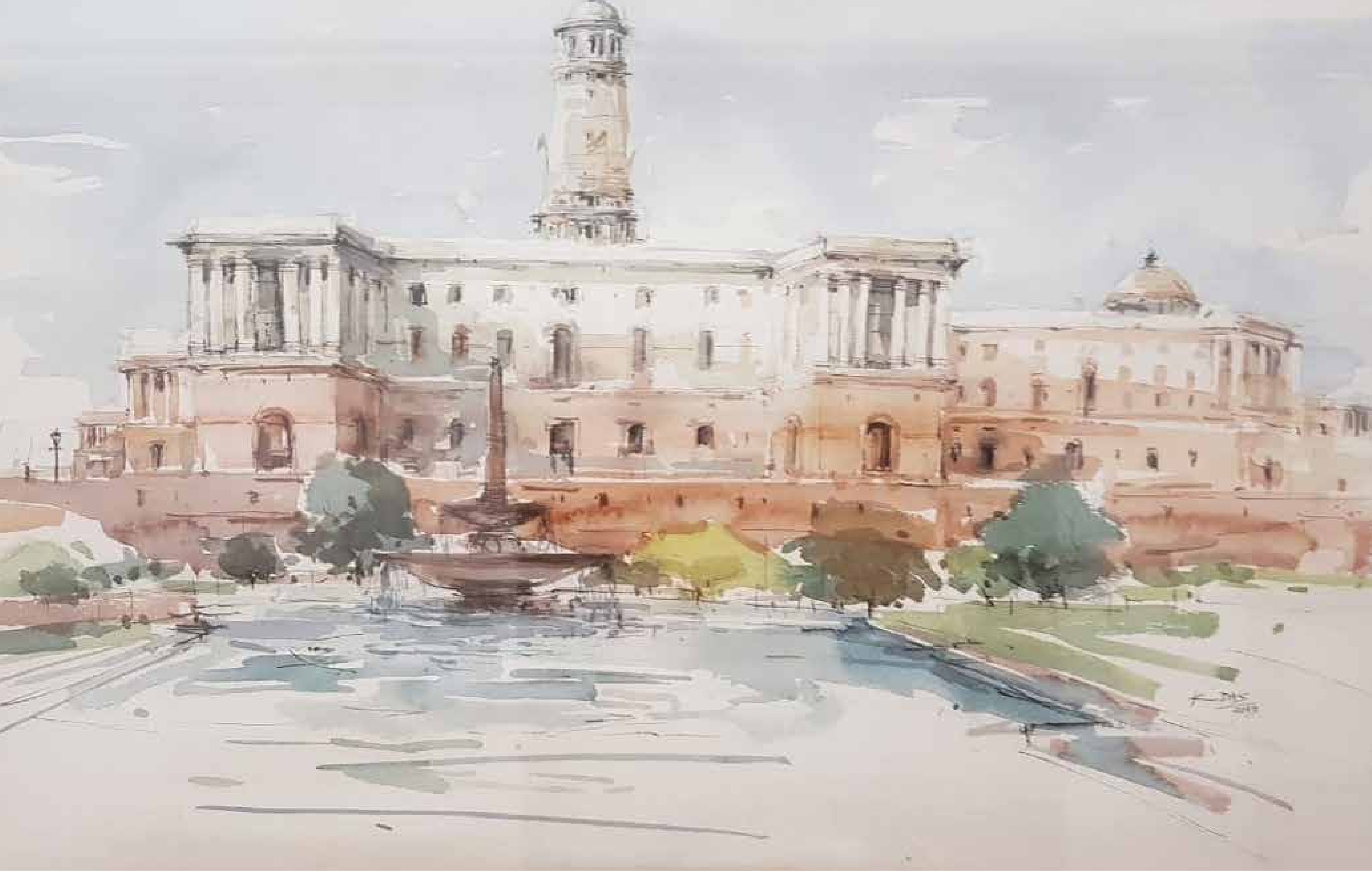

अफ्रीका सहित भारत-प्रशांत क्षेत्र में विशिष्ट संपर्क/बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सहयोग के क्षेत्रों की पहचान की और समान विचारधारा वाले देशों के साथ इस क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने की इच्छा व्यक्त की।

साझा रक्षा उद्देश्यों को पूरा करने के लिए द्विपक्षीय रक्षा संबंध भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी का एक महत्वपूर्ण घटक है। अक्टूबर 2018 में प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान विदेश और रक्षा मंत्रिस्तरीय '2+2' वार्ता, दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच अधिग्रहण और पार-सेवा समझौता वार्ता शुरू करने के निर्णय लिए गए और भारतीय नौसेना तथा जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच गहरे सहयोग की कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर करना रणनीतिक हितों में बढ़ते अभिसरण और दोनों पक्षों के बीच की आपसी समझ को दर्शाता है। जून 2018 में गुआम के तट पर यूएस के साथ मालाबार त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास के अतिरिक्त, भारत और जापान ने अपने सशस्त्र बलों के तीन घटकों के बीच द्विपक्षीय अभ्यास में एक-दूसरे को शामिल किया: अक्टूबर 2018 में विशाखापत्तनम में जापान-भारत समुद्री अभ्यास (जिमेक्स) के अलावा, नवंबर 2018 में मिजोरम में धर्म अभिभावक सेना अभ्यास और दिसंबर 2018 में आगरा में शिनियू मैत्री वायु अभ्यास पहली बार आयोजित किए गए। दोनो देशों के तट रक्षक बलों ने भी जनवरी 2018 में एक द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया।

वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद, दोनों प्रधानमंत्रियों ने नवंबर 2018 में अर्जेंटीना में जी-20 शिखर सम्मेलन के मौके पर पहली भारत-जापान-अमेरिका त्रिपक्षीय शिखर बैठक में भाग लिया।

वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले, अक्टूबर 2018 में दोनों देशों के बीच सफल और नियमित उच्च स्तरीय आदान-प्रदान द्वारा द्विपक्षीय संबंधों की गति को पूरे वर्ष बनाए रखा गया। भारत से जापान की महत्वपूर्ण यात्राओं में मार्च 2018 में नौवीं रणनीतिक वार्ता के लिए विदेश मंत्री (ईएएम) श्रीमती सुषमा स्वराज की यात्रा, अप्रैल 2018 में नीति

प्रधानमंत्री यामानाशी में जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे के साथ उनके निवास पर बातचीत करते हुए (28 अक्टूबर, 2018)

आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार की मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एमएएचएसआर) के संबंध में सातवीं संयुक्त समिति की बैठक (जेसीएम) और जुलाई 2018 में एशिया में साझा मूल्यों और लोकतंत्र पर संगोष्ठी के लिए (सामवेद की रूपरेखा के अंतर्गत)) तमिलनाडु के गवर्नर और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की यात्रा, और अक्टूबर 2018 में गृह राज्य मंत्री श्री किरन रिजीजु की जापान यात्रा शामिल थी। गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के राज्य प्रतिनिधिमंडलों ने प्रांतीय स्तर की भागीदारी और जापान से निवेश आकर्षित करने के लिए रोड शो और बैठकें करने के लिए जापान के विभिन्न शहरों का दौरा किया।

वर्ष 2018-19 में जापान से भारत की उल्लेखनीय यात्राओं में निम्नलिखित शामिल थीं: जनवरी 2019 में दिल्ली में आयोजित भारत-जापान के विदेश मंत्रियों की 10वीं रणनीतिक वार्ता के लिए विदेश मंत्री तारो कोनो की यात्रा, मई 2018 में नौवीं ऊर्जा वार्ता में भाग लेने और बेंगलुरु में भारत-जापान स्टार्टअप हब का उद्घाटन करने के लिए अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग (एमईटीआई) मंत्री श्री हिरोशिगे सेको और अगस्त 2018 में वार्षिक रक्षा मंत्रियों की बैठक के लिए जापानी रक्षा मंत्री श्री इटुनोरी ओनोडेरा, जनवरी 2019 में न्याय मंत्री श्री ताकाशी यामाशिता, जनवरी 2019 में आर्थिक पुनरुद्धार के प्रभारी मंत्री श्री तोशीमित्सु मोतेगी, अक्टूबर 2018 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार-स्तरीय संवाद के चौथे दौर के लिए प्रधानमंत्री आबे के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, श्री शोतारो याची, सितंबर 2018 में एमएएचएसआर पर आठवीं जेसीएम के लिए प्रधानमंत्री आबे के विशेष सलाहकार, डॉ.हिरो इज़ुमी, जनवरी 2019 मेंजीवंत गुजरात शिखर सम्मेलन के लिए एमईटीआई के राज्य मंत्री श्री योशिहिको इसोजाकी और सितंबर-अक्टूबर 2018 में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन (एमजीआईएससी) में भाग लेने के लिए राज्य के पर्यावरण मंत्री, श्री तादाहिको इटो, मई 2018 में एमएएचएसआर परियोजना के लिए संसदीय उप-भूमि, बुनियादी ढांचा, परिवहन और पर्यटन मंत्री, श्री मासतोशी अकीमोतो की यात्राएँ शामिल हैं।

अक्टूबर 2018 में वार्षिक शिखर सम्मेलन के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कुछ अन्य महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय इंटरैक्शन निम्नलिखित थे: डीपीडी (रक्षा नीति संवाद) का छठा संस्करण और जून 2018 में नई दिल्ली में उप-मंत्रालय स्तर के 2+2 संवाद का पाँचवां संस्करण, जुलाई 2018 में नई दिल्ली में निरस्त्रीकरण, अप्रसार और निर्यात नियंत्रण पर परामर्श का सातवां दौर, समुद्री मामलों की बातचीत का चौथा दौर और आतंकवाद प्रतिरोध पर सातवां संयुक्त कार्यकारी समूह (जेडब्ल्यूजी), सितंबर 2018 में मुंबई में परमाणु ऊर्जा सहयोग पर जेडब्ल्यूजी की दूसरी बैठक, अगस्त 2018 में नई दिल्ली में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पर जेडब्ल्यूजी का पाँचवां दौर, सितंबर 2018 में टोक्यो में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स पर जेडब्ल्यूजी का छठा दौर, अक्टूबर 2018 में नई दिल्ली में एक्ट ईस्ट फोरम की दूसरी

बैठक, जनवरी 2019 में, नई दिल्ली में तीसरी भारत-जापान पर्यटन परिषद की बैठक और चौथा भारत-जापान शिपिंग पॉलिसी फोरम।

दोनों देशों के सांसदों के बीच बातचीत जारी रही।, श्री शिनजिरो कोइज़ुमी के नेतृत्व में पाँच जापानी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अगस्त 2018 में भारत का दौरा किया। जापान के हाउस ऑफ काउंसिलर्स के अध्यक्ष श्री चुइचा डेत ने भी जनवरी 2019 में भारत आने वाले एक चार सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधियों का नेतृत्व किया।

जापान भारत के आर्थिक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भागीदार बना हुआ है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए जापानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और वर्तमान में, जापान 2000 के बाद से संचयी निवेश के मामले में प्रमुख निवेशकों में तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2018 की पहली तिमाही में जापान में 384.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के भारतीय निवेश के साथ कुल निवेश 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है। भारत में 1,441 जापानी कंपनियां (अक्टूबर 2018तक) पंजीकृत हैं, इनमें पिछले वर्ष की तुलना में 5% की वृद्धि हुई है। जापान भारत के आर्थिक विकास में तेजी लाने और विशेष रूप से बिजली, परिवहन, पर्यावरण जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में बुनियादी मानवीय जरूरतों से संबंधित परियोजनाओं के प्रयास में सबसे बड़े द्विपक्षीय साझेदारों में से एक है। 2017-18 में, जापान ने भारत में अपने विदेशी विकास सहायता (ओडीए) कार्यक्रम के अंतर्गत 389.62 बिलियन जापानी येन का वचन दिया है।

जापान ने हरियाणा, गुजरात और केरल में 3 और जापान-इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग (जेआईएम) की स्थापना के साथ 2018 में भारत में कौशल विकास को आगे बढ़ाने में अपना योगदान जारी रखा, इस प्रकार जेआईएम की कुल संख्या 8 हो गई है।

भारत-जापान साझेदारी के मूल में लोगों का परस्पर आदान-प्रदान शामिल है और दोनों पक्षों ने 2018 में सांस्कृतिक, शैक्षिक, संसदीय, शैक्षणिक और ट्रैक 1.5 सम्बद्धता का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। नई दिल्ली और फुकुओका (जनवरी 2018) और कर्नाटक और माइ (मार्च 2018) के साथ भारत के राज्यों और जापान के प्रान्तों और दोनों देशों के शहरों के बीच के संबंध को और मजबूत किया गया। वर्तमान में, भारत के सात राज्यों और भारत के तीन शहरों/क्षेत्रों ने समझौता ज्ञापन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए जापान के प्रान्तों और शहरों के साथ भागीदारी की है। द्विपक्षीय आदान-प्रदान को आगे बढ़ाने के लिए, भारत में जापानी भाषा के प्रचार के लिए नई दिल्ली में एक जापानी भाषा शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की और जापानी भाषा (जुलाई 2018) के लिए पहले शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई थी।

कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य (डीपीआरके)

दिसंबर 1973 में राजनयिक संबंधों की शुरुआत के बाद से, भारत और डीपीआरके के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) वी. के. सिंह (सेवानिवृत्त) ने डीपीआरके सरकार के निमंत्रण पर 15 और 16 मई 2018 को डीपीआरके की आधिकारिक यात्रा की। यात्रा के दौरान, राज्य मंत्री ने सुप्रीम पीपुल्स असेंबली के प्रेसिडियम के उपाध्यक्ष, श्री किम योंग डे, विदेश मंत्री, श्री री योंग हो, संस्कृति मंत्री, श्री पाक चुन नाम और डीपीआरके के उपविदेश मंत्री, श्री चोए हुई चोल के साथ दोनों देशों के बीच राजनीतिक, क्षेत्रीय, आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक सहयोग से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। भारत ने पनमुनजोम (27 अप्रैल 2018) और प्योंगयांग (18-20 सितंबर 2018) में आयोजित अंतर-कोरियाई शिखर बैठकों तथा सिंगापुर में आयोजित यूएसए-डीपीआरके शिखर बैठक (12 जून 2018) का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि इस तरह के संपर्कों से तनाव को कम करने में मदद मिलेगी और कोरियाई प्रायद्वीप में स्थायी शांति और सामंजस्य का मार्ग प्रशस्त होगा। भारत ने अपनी इस इच्छा को रेखांकित किया कि अंतर-कोरियाई मुद्दों के समाधान में प्रसार-संबंधी चिंताओं को संबोधित करना भी शामिल है।

कोरिया गणराज्य (आरओके)

वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आरओके की यात्रा के दौरान भारत-आरओके के द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया गया था। 08-11 जुलाई, 2018 को आरओके के राष्ट्रपति श्री मून जे-इन की भारत यात्रा के साथ इनकी गति में और अधिक वृद्धि हुई। यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की और लोगों, समृद्धि, शांति और भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए एक वक्तव्य जारी किया। वर्ष 2010 में हस्ताक्षरित एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के चल रहे उन्नयन को पूरा करने में अपने समर्थन को दोहराते हुए, दोनों नेताओं ने अर्ली हार्वेस्ट समझौते के निष्कर्ष का स्वागत किया और 2030 तक व्यापार को 50 बिलियन तक करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसके अलावा, दोनों नेताओं ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति और दक्षिण कोरिया की नई दक्षिणी नीति, रक्षा उद्योग में सहयोग और भविष्य की प्रौद्योगिकियों के बीच संभावित तालमेल पर चर्चा की। दोनों देशों ने सांस्कृतिक सहयोग से सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और जैव प्रौद्योगिकी तक व्यापक क्षेत्रों में ग्यारह समझौता ज्ञापनों/समझौतों का पूरा किया। दोनों नेताओं ने नोएडा में एक सैमसंग मोबाइल प्लांट के उद्घाटन में भाग लिया, जो लगभग 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ एक प्रमुख 'मेक इन इंडिया' पहल होगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर कोरिया गणराज्य की प्रथम महिला श्रीमती किम जंग-सूक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 4-7 नवंबर 2018 को भारत आईं। उन्होंने 6 नवंबर 2018 को अयोध्या में रानी सुरीरत्ना (हुह ह्वांग-ओके) के नए स्मारक के भूमि पूजन समारोह का नेतृत्व किया। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री (ईएएम) श्रीमती सुषमा स्वराज से भेंट की। ।

2018 की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं में 7-10 मार्च 2018 को आरओके की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष श्री चुंग सिय-क्युन की भारत यात्रा और 9 और 10 अगस्त 2018 को आरओके रक्षा मंत्री श्री यंग मू-सांग की भारत यात्रा शामिल है।

प्रधानमंत्री और कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति श्री मून जाई-इन सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक की विनिर्माण ईकाई के उद्घाटन के लिए दिल्ली मैट्रो से नौएडा के लिए साथ-साथ यात्रा करते हुए (9 जुलाई, 2018)

विदेश मंत्री नई दिल्ली में कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति श्री मून जई-इन से मुलाकात करते हुए (09 जुलाई, 2018)

मंगोलिया

मई 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंगोलिया की ऐतिहासिक यात्रा के समय द्विपक्षीय संबंधों को सामरिक भागीदारी में उन्नत करने के बाद से पिछले कुछ वर्षों में भारत और मंगोलिया के पारंपरिक रूप से मैत्रीपूर्ण और आत्मीय संबंधों में लगातार सुधार हुआ है। 2018 में दोनों देशों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। मंगोलिया के रक्षा मंत्री श्री एन. एनखबोल्ड ने मार्च 2018 में भारत का दौरा किया और भारत के रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) और थल सेनाध्यक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।

मंगोलिया के विदेश मंत्री श्री दामदीन सोजतबातर के निमंत्रण पर विदेश मंत्री (ईएएम) श्रीमती सुषमा स्वराज 25 और 26 अप्रैल 2018 को मंगोलिया की आधिकारिक यात्रा पर गई थीं। बयालीस वर्षों में किसी भारतीय विदेश मंत्री की यह पहली मंगोलिया यात्रा थी। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने अपनी यात्रा के समय अपने मंगोलियाई समकक्ष से बातचीत की और मंगोलिया के राष्ट्रपति, श्री कल्तमैगिन बत्तुला, प्रधानमंत्री, श्री उखनागिन खुरेलसुख और महान खुरल (मंगोलियाई संसद) के अध्यक्ष श्री मियेगोमबो एनखबोल्ड से भेंट की।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 25 अप्रैल 2018 को विदेश मंत्री श्री सोगतबातर के साथ सहयोग बैठक (आईएमजेसीसी) में छठी भारत-मंगोलिया संयुक्त समिति की सह-अध्यक्षता भी की। आईएमजेसीसी के दौरान, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और मंगोलियाई विदेश मंत्री ने राजनीतिक, रणनीतिक, व्यापार और आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने मई 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंगोलिया यात्रा के दौरान घोषित विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह 21-24 जून 2018 के दौरान मंगोलिया की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। इस

विदेश मंत्री उलानबटार में मंगोलिया के प्रधानमंत्री श्री यू.खुरेलसुख से मुलाकात करते हुए (25 अप्रैल, 2018)

यात्रा के दौरान, गृह मंत्री ने मंगोलिया के राष्ट्रपति श्री के. बतुलगा से भेंट की और प्रधानमंत्री यू. खुरलसुख, उप प्रधानमंत्री, श्री यू. एनख्तुवशिन और न्याय और गृह मामलों के मंत्री, श्री टीएस न्यामदोरज के साथ भारत और मंगोलिया के बीच आपदा में कमी, सीमा प्रबंधन और सुरक्षा क्षेत्र में क्षमता निर्माण कार्यक्रम में सहयोग सहित द्विपक्षीय हितों के व्यापक मुद्दों पर चर्चा की।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, किरेन रिजिजू 03-06 जुलाई, 2018 को आपदा जोखिम न्यूनीकरण (एएमसीडीआरआर) पर एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए ने मंगोलिया की राजधानी उलानबतार गए थे। इस यात्रा में, राज्य मंत्री (गृह मंत्रालय) ने एएमसीडीआरआर में भारत का वक्तव्य प्रस्तुत किया तथा प्रधानमंत्री, श्री यू खुरेलसुख और उप प्रधानमंत्री, श्री यू एनख्तुवशिन के साथ अलग-अलग बैठकें कीं।

4

यूरेशिया

रूसी संघ

नई दिल्ली में, 13 अप्रैल 2018 को विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा आयोजित एक सांस्कृतिक संध्या के साथ भारत-रूस राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह का समापन हुआ। दोनों देशों ने सभी स्तरों पर नियमित आदान-प्रदान और बातचीत की परंपरा जारी रखी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन ने 21 मई 2018 को रूस के सोची में अपना पहला अनौपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। इस शिखर सम्मेलन ने दोनों नेताओं को अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विनिमय का एक अवसर प्रदान किया। रूसी राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन 19वें भारत-रूस वार्षिक द्विपक्षीय सम्मेलन के लिए 4 और 5 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली आए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ आधिकारिक वार्ता की और भारत के राष्ट्रपति से भी भेंट की। शिखर सम्मेलन के हाशिये पर, दोनों नेताओं ने पहले भारत-रूस व्यापार सम्मेलन को संबोधित किया और भारत और रूस के प्रतिभाशाली बच्चों के एक समूह से बातचीत की। वर्ष के दौरान, दोनों नेताओं ने जुलाई 2018 में जोहान्सबर्ग में ब्राजील-रूस-भारत-चीन-दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) शिखर सम्मेलन में और जी20 शिखर सम्मेलन के हाशिये पर 30 नवंबर 2018 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में रूस-भारत-चीन (आरआईसी) के अनौपचारिक सम्मेलन में बातचीत की।

रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर सातवें मास्को सम्मेलन में भाग लेने के लिए 3-5 अप्रैल, 2018 को रूस गई थीं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री (सीआईएम) श्री सुरेश प्रभु, चौथे पूर्वी आर्थिक मंच (ईईएफ) में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 11 और 12 सितंबर, 2018 को व्लादिवोस्तोक गए थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री रूसी क्षेत्रों के गवर्नर/उप-गवर्नरों और सुदूर-पूर्व के रूसी क्षेत्रों - प्राइमोरी, याकूतिया, सखालिन, अमूर, मेगदान, कामचटका, खाबरोवस्क और तातारस्तान के प्रतिनिधियों से मिले तथा खनन, भूवैज्ञानिक अन्वेषण, कृषि, जल सहयोग

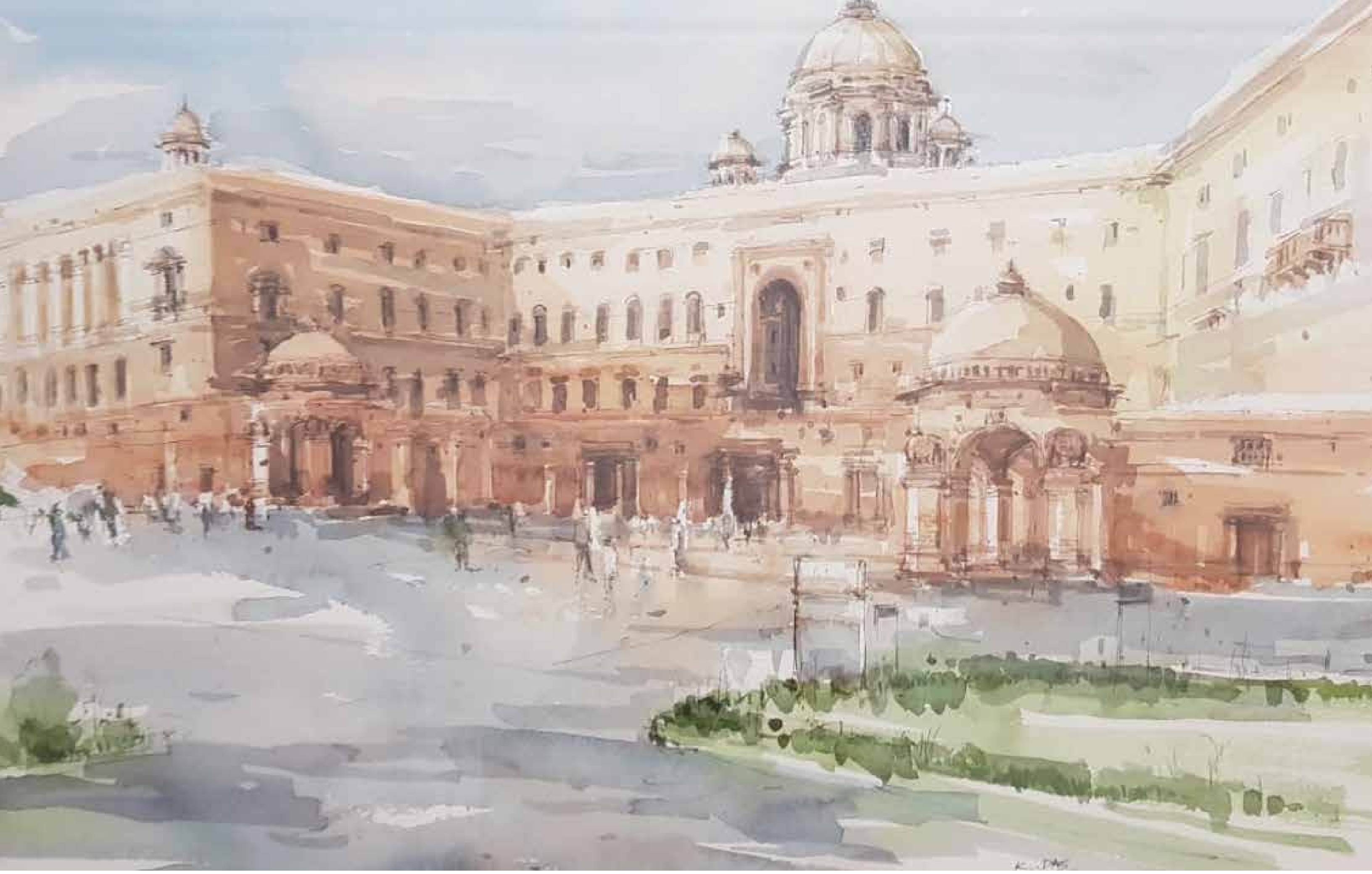

प्रधानमंत्री सोचि में रूस के राष्ट्रपति श्री ब्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करते हुए (21 मई, 2018)

और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की।

विदेश मंत्री (ईएएम) श्रीमती सुषमा स्वराज 14 और 15 सितंबर, 2018 को रूसी उप-प्रधानमंत्री श्री यूरी बोरिसोव के साथ व्यापार और आर्थिक सहयोग (आईआरआईजीसी-टीईसी) पर भारत-रूस अंतर सरकारी आयोग के 23वें सत्र की सह-अध्यक्षता के लिए मास्को गईं। यात्रा के दौरान उन्होंने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात की।

रूसी संघ की सुरक्षा परिषद के सचिव श्री निकोलाई पेत्रुशेव 6-7 दिसंबर, 2018 को भारत आए थे। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भेंट की।

रूसी संघ के राज्य ड्यूमा के अध्यक्ष श्री व्याचेस्लाव वोलोडिन के नेतृत्व में 9 और 10 दिसंबर 2018 को आए एक प्रतिनिधिमंडल की यात्रा ने रूस के साथ संसदीय संबंधों को और मजबूत किया। श्री वोलोडिन ने लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन से भेंट

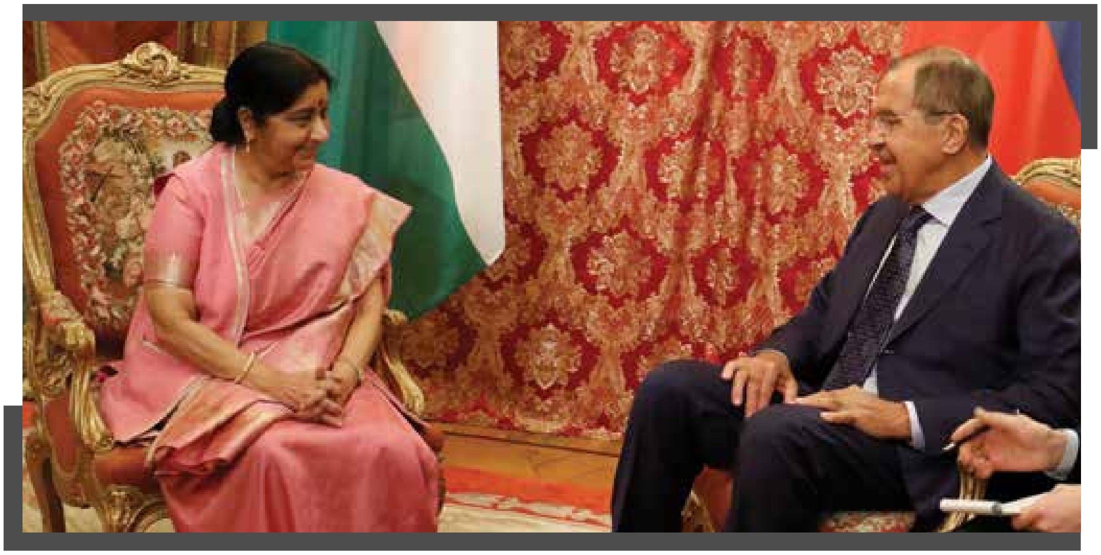

विदेश मंत्री रूसी महासंघ के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से मुलाकात करते हुए (13 सितंबर, 2018)

की। यात्रा के दौरान उन्होंने उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भी भेंट की। इस यात्रा के दौरान भारत-रूस संसदीय आयोग की 5वीं बैठक हुई।

रूसी रक्षा मंत्री श्री सर्गेई शोयगु ने रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के साथ सैन्य तकनीकी सहयोग (आईआरआईजीसी-एमटीसी) पर 18वें भारत-रूस अंतर सरकारी आयोग की सह-अध्यक्षता के लिए 12 और 13 दिसंबर 2018 को नई दिल्ली का दौरा किया।

विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) ने मास्को में आतंकवाद प्रतिरोध (जुलाई 2018) पर भारत-रूस संयुक्त कार्यदल (जेडब्ल्यूजी) की 10वीं बैठक के लिए सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। अगस्त 2018 में विदेश सचिव श्री विजय गोखले और रूसी उप विदेश मंत्री श्री सर्गेई रियाबकोव के स्तर पर बहुपक्षीय मुद्दों पर विदेश कार्यालय परामर्श मास्को में आयोजित किए गए थे।

थल सेनाध्यक्ष जनरल श्री बिपिन रावत 1-6 अक्टूबर, 2018 को आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा पर रूस गए। नौसेना स्टाफ के प्रमुख, एडमिरल श्री सुनील लांबा ने 26-29 नवंबर 2018 को रूस का दौरा किया। उन्होंने रूसी नौसेना के कमांडर-इन-चीफ के साथ चर्चा की और वल्दाई क्लब में "भारत की समुद्री सुरक्षा" पर बात की।

द्विपक्षीय व्यापार में 2016-17 की अपेक्षा 2017-18 में 21% से अधिक की वृद्धि देखी गई। 2017-18 में, द्विपक्षीय व्यापार 10.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। दोनों पक्षों ने 2025 के लिए निर्धारित 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण पहलें की। भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के हाशिए पर 5 अक्टूबर 2018 को पहला भारत-रूस व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। 19वीं द्विपक्षीय शिखर बैठक के दौरान लिए गए निर्णय के अनुसार, 26 नवंबर 2018 को सेंट पीटर्सबर्ग में भारत-रूस रणनीतिक आर्थिक वार्ता आयोजित की गई, जिसका नेतृत्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार और रूसी संघ के आर्थिक विकास मंत्री श्रीमान मैक्सिन ऑर्किन ने किया। जिन क्षेत्रों में दोनों पक्ष एक साथ काम कर सकते थे उनकी पहचान करने और उनके सहयोग को और बेहतर बनाने के लिए रणनीतिक आर्थिक वार्ता निम्नलिखित पांच मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित थी - परिवहन बुनियादी ढांचा, कृषि और कृषि-प्रसंस्करण क्षेत्र, लघु और मध्यम व्यापार समर्थन, डिजिटल परिवर्तन और सीमावर्ती प्रौद्योगिकियां और औद्योगिक और व्यापार सहयोग।

अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्मेलन के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष श्री विनय प्रभाकर सहस्रबुद्धे की 24-26 अप्रैल 2018 को मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के लिए यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंधों को प्रोत्साहन मिला।

क्रेमलिन पैलेस में 6 सितंबर 2018 को भारत समारोह का भव्य उद्घाटन किया गया था और भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले दस समूहों के प्रदर्शन के साथ 31 मार्च 2019 तक बाईस रूसी शहरों में आयोजित होने वाला यह सामारोह चल रहा है।

आर्मेनिया

भारत और आर्मेनिया के बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। येरवन में 29 अगस्त 2018 को परिवहन, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्मेन अरजिमान्यन द्वारा एक भारत-आर्मेनिया संयुक्त डाक टिकट जारी किया गया था। इसमें अर्मेनियाई "होव अरेक" लोक नृत्य और भारतीय मणिपुरी नृत्य को दर्शाया गया है। इस अवसर पर डाक टिकट संग्रह की एक संयुक्त प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। 2 अक्टूबर 2018 को 150वीं गांधी जयंती पर डाक विभाग द्वारा सात डाक टिकट जारी किए गए।

शिक्षा और विज्ञान के उप मंत्री श्री होवनेस होवनिस्यान ने 30 अक्टूबर - 1 नवंबर 2018 से नई दिल्ली में आयोजित 14वें फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

आर्मेनिया ने थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के उपचार में भारत की सहायता की सराहना की। भारत सरकार ने येरेवन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी (वाईएसएमयू) के मुरेटसन चिल्ड्रेन हॉस्पिटल की कीमोथेरेपी क्लिनिक को थैलेसीमिया की दवा दान की। दान की गई दवाएं मरीजों के दो वर्ष के उपचार के लिए पर्याप्त होंगी। 2013 और 2016 में भी वाईएसएमयू को वही दवाएं दान की गई थीं।

अज़रबैजान

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बाकू (4-6 अप्रैल, 2018) में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) की मध्यावधि मंत्रिस्तरीय बैठक में शामिल होना वर्ष 2018-19 में भारत-अजरबैजान के द्विपक्षीय संबंधों की मुख्य घटना थी। 1991 में अज़रबैजान की आजादी के बाद से यह भारत के विदेश मंत्री की पहली अज़रबैजान यात्रा थी। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से भेंट की और अपनी समकक्ष विदेश मंत्री श्रीमती एलमारममाडिरोव के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों विदेश मंत्रियों ने राजनयिकों, अधिकारियों और सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट पर एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो 6 सितंबर 2018 से लागू हुआ।

व्यापार और आर्थिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग पर भारत-अज़रबैजान अंतर-सरकारी आयोग (आईजीसी) की 5वीं बैठक 11 और 12 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु और अजरबैजान के प्राकृतिक और प्राकृतिक संसाधन मंत्री श्री मुख्तार बाबयेव ने इसकी सह-अध्यक्षता की थी। आईजीसी

विदेश मंत्री बाकू में अजरबैजान के विदेश मंत्री श्री ऐलमार मामादियारोव से मुलाकात करते हुए (04 अप्रैल, 2018)

बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने अपने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश सहयोग की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की।

अज़रबैजान की संसद की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर अज़रबैजान के मिल्लीमजलिस की सोलेमेन बैठक में भाग लेने के लिए तीन सदस्यीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने 19-22 मार्च 2018 को बाकू का दौरा किया, इस प्रतिनिधिमंडल में श्रीमती केएच मुनियप्पा (लोकसभा), श्री चिंतामणि मालवीय (लोकसभा) और श्री वी. विजयसाई रेड्डी (राज्यसभा) शामिल थे।

अजरबैजान में मानव संसाधन विकास (एचआरडी) और क्षमता निर्माण में भारत के सहयोग की काफी सराहना की गई। विदेश मंत्रालय ने अजरबैजान में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कृषि मंत्रालय की अजरबैजान ग्रामीण निवेश परियोजना (एजेडआरआईपी) द्वारा एक परियोजना के समर्थन के लिए भारतीय विशेषज्ञों की अजरबैजान यात्रा के लिए 16,000 अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की। इस परियोजना का उद्देश्य अजरबैजान ग्रामीण निवेश परियोजना द्वारा अजरबैजान के तीन अलग-अलग क्षेत्रों से चुने गए प्रतिभागियों को स्वयं सहायता समूह और माइक्रो-फाइनेंस स्थापित करने के लिए भारतीय विशेषज्ञों के ज्ञान और अनुभव को बांटना है।

भारत-अजरबैजान के द्विपक्षीय व्यापार में मजबूत वृद्धि जारी रही और वर्ष 2017-18 में यह 626 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। भारतीय प्रतिनिधियों ने अज़रबैजान पर्यटन और आतिथ्य मेले, बाकू (5-7 अप्रैल 2018), वर्ल्ड फ़ूड अजरबैजान 2018 प्रदर्शनी (16-18 मई 2018), कैस्पियन ऑयल एंड गैस 2018 प्रदर्शनी (29 मई से 1 जून 2018 तक), और अज़रबैजान अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी (एडीईएक्स) (25-27 सितंबर 2018) आदि अज़रबैजान में आयोजित विभिन्न व्यापारिक मेलों में भाग लिया।

बेलारूस

लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन के नेतृत्व में 10-13 जून 2018 के बीच एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के साथ भारत और बेलारूस के संबंधों में एक गुणात्मक अग्रगामी गति देखी गई। यात्रा के दौरान, लोक सभा और बेलारूस की राष्ट्रीय असेंबली की प्रतिनिधि सभा के बीच सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-बेलारूस अंतर-सरकारी आयोग (आईजीसी) की नौवीं बैठक 25 सितंबर 2018 को मिन्स्क में आयोजित की गई थी। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री सी. आर. चौधरी ने इसकी अध्यक्षता की। बेलारूस के उप-विदेश मंत्री श्री आंद्रेई दपकिउनास 16 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली में आयोजित भारत-बेलारूस विदेश कार्यालय परामर्श के लिए नई दिल्ली आए थे। उन्होंने विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज से भेंट की।

बेलारूस के साथ द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2016-17 के 402 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 455 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और बेलारूस की राज्य कृषि अकादमी (बीएसएए) के बीच वर्ष 2018-2020 के लिए एक कार्य योजना पर और भारत और बेलारूस के बीच भारत में संयुक्त प्रौद्योगिकी प्रदर्शन केंद्र (जेटीडीसी) के निर्माण के एक समझौते हस्ताक्षर किए गए।

जॉर्जिया

भारत-जॉर्जिया में सौहार्द और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। भारत सरकार से जॉर्जिया द्वारा सितंबर 2017 में छह महीने की अवधि के लिए उधार लिए गए जॉर्जियाई सेंट क्वीन केतवन के अवशेषों की एक प्रदर्शनी की अवधि छह महीने के लिए बढ़ा कर सितंबर 2018 तक कर दी गई थी। सेंट क्वीन केतवन का जॉर्जिया के लोगों द्वारा बहुत सम्मान किया जाता है।

भारत के राजदूत ने 16 दिसंबर 2018 को त्बिलिसी में जॉर्जिया के राष्ट्रपति सुश्री सैलोम ज़ुराबिशविलि के पदग्रहण समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया।

कज़ाकिस्तान

पूरे वर्ष कई द्विपक्षीय आदान-प्रदानों ने कज़ाकिस्तान के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण और मधुर संबंधों की गति बनाए रखी। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज 2 और 3 अगस्त 2018 को कज़ाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर गई थीं, उन्होंने कज़ाकिस्तान के विदेश मंत्री श्री कैरत अब्द्रखमानोव के साथ द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री श्री बख्शीज़ान सगिनत्येव से भेंट की।

कज़ाकिस्तान सरकार के उप-प्रधानमंत्री (डीपीएम) ने वर्ष के दौरान कज़ाकिस्तान सरकार द्वारा आरंभ की गई 'डिजिटल कज़ाकिस्तान' पहल में संभावित सहयोग के लिए डिजिटल इंडिया परियोजनाओं का अध्ययन करने के लिए 19 से 22 सितंबर 2018 तक भारत का दौरा किया। उन्होंने कानून और न्याय एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उन्होंने नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (नासकॉम) और अन्य प्रमुख आईटी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ भी मुलाकात की। कज़ाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री की भारत यात्रा की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के उपमहानिदेशक श्री दीपक चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 2-5 नवंबर 2018 के बीच कज़ाकिस्तान का दौरा किया।

रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री श्री नूरलान येरेमेबायेव एवं रक्षा और एयरोस्पेस उद्योग मंत्री श्री बेइबुत अतुलकुलोव के साथ रक्षा और सैन्य-तकनीकी सहयोग पर द्विपक्षीय वार्ता के लिए 2-4 अक्टूबर 2018 तक अस्ताना गई थीं। श्रीमती निर्मला सीतारमण और उनके कज़ाख समकक्ष ने संयुक्त रूप से कज़ाख शांति सेना के फ्लैग-ऑफ समारोह की अध्यक्षता की, जो उस महीने के बाद लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (यूएनआईएफआईएल) की भारतीय बटालियन में शामिल हुई थी। भारत और कज़ाकिस्तान ने 21 अगस्त को यूएनआईएफआईएल मिशन में भारतीय शांति रक्षक बटालियन के अंतर्गत एक कज़ाख शांति सेना की संयुक्त तैनाती पर एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया था।

राज्य मंत्री (मानव संसाधन विकास), डॉ. सत्य पाल सिंह ने अस्ताना में सातवें शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 15 से 18 अक्टूबर 2018 तक कज़ाकिस्तान गए चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए कज़ाकिस्तान के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने अस्ताना में 25 और 26 अक्टूबर 2018 को आयोजित सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और सतत विकास लक्ष्य की ओर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर अंतर्राष्ट्रीय

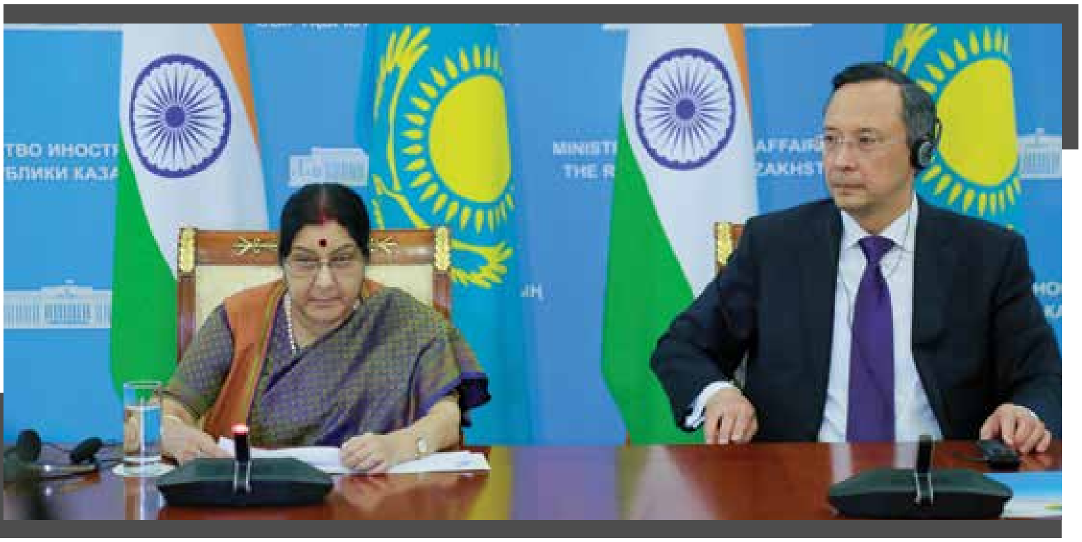

अस्ताना में भारत-कजाखस्तान द्विपक्षीय बैठक के आयोजन के दौरान विदेश मंत्री और कजाखस्तान गणराज्य के विदेश मंत्री श्री कैरात अबद्राखमानोव (03 जुलाई, 2018)

सम्मेलन में भाग लेने के लिए कज़ाकिस्तान जाने वाले तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था।

जुलाई 2018 में भारत और कज़ाकिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग पर छठी जेडब्ल्यूजी बैठक अस्ताना में आयोजित की गई थी। 2017-2018 में भारत और कज़ाकिस्तान के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 981 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था।

रक्षा सहयोग पर पाँचवीं जेडब्ल्यूजी बैठक 30 मई से 2 जून 2018 तक अस्ताना में आयोजित की गई थी। जेडब्ल्यूजी की सफल परिणति पर एक संयुक्त प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे।

अस्ताना में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र (एसवीसीसी) ने अपनी नियमित गतिविधियों को जारी रखा और कथक और बॉलीवुड नृत्य, भारतीय संगीत और योग की दैनिक कक्षाएं संचालित कीं। इसके अलावा, जुलाई 2018 में 'आरंभ करने वालों के लिए हिंदी' कक्षाएं भी शुरू की गईं। एसवीसीसी ने इस अवधि में भारतीय संगीत और नृत्य केंद्र, नज़रबायेव विश्वविद्यालय, अस्ताना में फिर से भारतीय नृत्य, संगीत और योग कक्षाएं शुरू कीं। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के हिस्से के रूप में, एसवीसीसी द्वारा कज़ाकिस्तान के राष्ट्रीय संग्रहालय, अस्ताना में 16 से 28 अक्टूबर 2018 तक पारंपरिक भारतीय वस्त्रों की एक प्रदर्शनी, 'वस्त्रम: द स्प्लेंडिड वर्ल्ड ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स' का आयोजन किया गया था।

किर्गिज गणराज्

भारत और किर्गिज़ गणराज्य में पारंपरिक रूप से सौहार्दपूर्ण और घनिष्ठ संबंध हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के अवसर पर 11 जून, 2018 को चीन के किंगदाओ में किर्गिज़ के राष्ट्रपति श्री सूरोनबे जीनबेकोव से भेंट की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ की अध्यक्षता करने के लिए राष्ट्रपति श्री जीनबेकोव को बधाई दी।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 23 अप्रैल 2018 को, एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक के मौके पर किर्गिस्तान के विदेश मंत्री श्री एर्लन अबल्देव से भेंट की और व्यापार व निवेश, सूचना प्रौद्योगिकी, रक्षा, फिल्मों, मानव संसाधन विकास, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की।

विदेश मंत्री ने 3 और 4 अगस्त 2018 को किर्गिस्तान का दौरा किया। वे किर्गिज विदेश मंत्री श्री अबल्देव से मिलीं और राष्ट्रपति श्री जीनबेकोव से भी भेंट की।

व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर किर्गिज़-भारत अंतर सरकारी आयोग की नौवीं बैठक 15 और 16 नवंबर 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई

विदेश मंत्री बिश्केक में किरगिज गणराज्य के विदेश मंत्री श्री एरलान अब्दिलदाईव से मुलाकात करते हुए (03 जुलाई, 2018)

थी। भारतीय पक्ष से आईजीसी का नेतृत्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा किया गया था। किर्गिज़ प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किर्गिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री ने किया। 2017-18 में भारत और किर्गिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 59.53 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, किर्गिस्तान में भारत से 28.59 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात और किर्गिस्तान से 30.94 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात हुआ।

ताजिकिस्तान

भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की 7-9 अक्टूबर 2018 की ताजिकिस्तान यात्रा से भारत-ताजिकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों में एक उत्साह उत्पन्न हुआ। उन्होंने ताजिक राष्ट्रपति श्री इमोमाली रहमोन के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने ताजिक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और भारतीय समुदाय के छात्रों और विद्वानों को संबोधित किया। यात्रा के दौरान आठ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। 9 जून 2018 को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चीन के किंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के अवसर पर ताजिक राष्ट्रपति श्री इमोमाली रहमोन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कनेक्टिविटी, व्यापार और निवेश और अफगानिस्तान जैसे कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 11 और 12 अक्टूबर 2018 को दुशांबे में आयोजित सरकार प्रमुखों की 17वीं एससीओ बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक के हाशिये पर, उन्होंने अफगान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डॉ. अब्दुल्ला अब्दुल्ला से भेंट की और ताजिक विदेश मंत्री श्री सिरोजिद्दीन मुहरिद्दीन के साथ बैठक की। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने स्थानीय भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया।

पूर्व विदेश राज्य मंत्री (एमओएस) श्री एम. जे. अकबर 1-5 मई 2018 को आतंकवाद के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए ताजिकिस्तान गए थे। उन्होंने ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और ताजिक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव से भेंट की।

केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 'इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन: वॉटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 2018-2028' पर 20-22 जून 2018 को दुशांबे में आयोजित सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

रक्षा सचिव श्री संजय मित्रा ने 26 जून 2018 को दुशांबे में आयोजित भारत-ताजिक रक्षा सहयोग पर सातवीं जेडब्ल्यूजी बैठक के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

राष्ट्रपति दुशान्बे में ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति श्री एमोमाली रहमॉन से मुलाकात करते हुए (08 अक्टूबर, 2018)

तुर्कमेनिस्तान

भारत और तुर्कमेनिस्तान में सौहार्द और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। दोनों पक्षों के लिए एक प्रमुख क्षेत्र हाइड्रोकार्बन सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों का सहयोग चल रहा है।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज और तुर्कमेनिस्तान के उप प्रधानमंत्री श्री रशीद मेरेडोव ने 2 अगस्त 2018 और 13 सितंबर 2018 को श्रीमती सुषमा स्वराज की तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबात से पारगमन के दौरान दो बार मुलाकात की।

तुर्कमेन शिक्षा मंत्री, श्री मम्मेत्मिरत गेल्डिनेयाज़ोव ने 30 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन (एमजीआईएससी) में भाग लिया।

दूरदर्शन की महानिदेशक सुश्री सुप्रिया साहू ने 30 सितंबर से 5 अक्टूबर 2018 तक अश्गाबात में 55वें एशिया-पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन (एबीयू) महासभा की बैठकों की अध्यक्षता की।

दोनों पक्षों के व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों के बीच कई आदान-प्रदान हुए। 8-12 जुलाई 2018 से तुर्कमेन ऑटोमोबाइल सेक्टर के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली और पुणे का दौरा किया। पंद्रह भारतीय दवा कंपनियों ने 20-23 जुलाई 2018 से अश्गाबात में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एक्सपो 2018 में भाग लिया। छब्बीस सदस्यीय फार्ममेक्ससिल प्रतिनिधिमंडल ने फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिए 24-28 नवंबर, 2018 तक अश्गाबात का दौरा किया। गेल के एक प्रतिनिधिमंडल ने 23वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और 'तुर्कमेनिस्तान का तेल और गैस -2018' प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए 20 नवंबर को अश्गाबात का दौरा किया।

वर्ष 2017-18 के लिए भारत-तुर्कमेनिस्तान द्विपक्षीय व्यापार लगभग 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

तुर्कमेनिस्तान के संस्कृति मंत्रालय द्वारा अप्रैल में अश्गाबात में आयोजित उत्सव 'एनसियेन्ट क्रैडल ऑफ म्यूजिकल आर्ट्स' में भाग लेने वाले तीन सदस्यीय तबला समूह की यात्रा ने तुर्कमेनिस्तान के साथ सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत किया। तुर्कमेनिस्तान के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए योग एक सबसे शक्तिशाली कड़ी है। 11 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान स्थापित योग और पारंपरिक चिकित्सा केंद्र 2,800 से अधिक पंजीकृत योग अभ्यास करने वालों के साथ बहुत लोकप्रिय रहा है, जिनमें से लगभग 2,100 साप्ताहिक आधार पर योग का अभ्यास कर रहे हैं। भारतीय योग शिक्षकों की मदद से राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय में 'योग उपचार' के दो क्रेडिट कोर्स आयोजित किये जा रहे हैं।

नवंबर 2018 तक 11,735 वीजा जारी किए जाने के साथ तुर्कमेनिस्तान से भारत में चिकित्सा पर्यटन बढ़ रहा है, 2013 में केवल 2,047 वीजा जारी किए गए थे।

यूक्रेन

भारत और यूक्रेन के बीच के द्विपक्षीय संबंध सभी क्षेत्रों में सौहार्दपूर्ण बने रहे। मई 2018 में कीव-दिल्ली सेक्टर पर यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइन (यूआईए) द्वारा सीधी उड़ानों के शुभारंभ के बाद लोगों के बीच आपसी संपर्क में एक प्रबलता दिखाई दी। भारतीय छात्रों में यूक्रेनी चिकित्सा विश्वविद्यालयों की लोकप्रियता काफी अधिक रही, यूक्रेन में विदेशी छात्रों की संख्या के मामले में भारत शीर्ष स्थान पर रहा।

यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के पहले उप सचिव श्री ओलेह ह्लादकोवस्की ने भारत के चेन्नई में आयोजित डेफ़एक्सपो 2018 में भाग लेने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। श्री ओलेह ने डेफएक्सपो के हाशिए पर रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के साथ एक बैठक की। भारत और यूक्रेन के बीच रक्षा सहयोग पर पहली जेडब्ल्यूजी बैठक 4-6 जून 2018 सेको कीव में आयोजित की गई थी।

आयुर्वेद उत्पादों और सेवा के क्षेत्र में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के एक बारह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 9 से 11 अप्रैल 2018 तक यूक्रेन का दौरा किया। एक संबंधित विकास में, सितंबर 2018 में आयुर्वेद-योग का एक यूक्रेनी एसोसिएशन बनाया गया था, जिसका उद्देश्य यूक्रेन में नीति-निर्माताओं का ध्यान आयुर्वेद को वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में स्वीकार करने पर आकर्षित करना था। एक

बहु-क्षेत्रीय सीआईआई व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने यूक्रेन में व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिए यूक्रेनी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आयोजित एक भारत-यूक्रेन बिजनेस फोरम में भाग लेने के लिए 7 और 8 जून 2018 को यूक्रेन का दौरा किया।

2015 से हर वर्ष जून में आयोजित किया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह यूक्रेन के लोगों में योग, शांति, दोस्ती और भारतीय संस्कृति के प्रसार के लिए एक मानक बन गया है। 27 और 28 अक्टूबर, 2018 को यूक्रेन के विभिन्न शहरों के 250 से अधिक प्रतिभागियों के साथ कीव में "रिदम ऑफ जॉय" नामक 18वें वार्षिक ऑल-यूक्रेनी इंडियन डांस फेस्टिवल आयोजित किया गया था। यह वार्षिक आयोजन दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

उज़्बेकिस्तान

इस वर्ष 30 सितंबर और 1 अक्टूबर 2018 को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति श्री शौकत मिर्जियोयेव की भारत की राजकीय यात्रा के साथ भारत-उज्बेकिस्तान संबंध और मजबूत हुए हैं। यह राष्ट्रपति श्री मिर्जियोयेव की पहली भारत यात्रा थी। यात्रा के दौरान, कानून, पर्यटन, सैन्य शिक्षा, कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वाणिज्य और उद्योग, फार्मास्युटिकल, राष्ट्रीय सुरक्षा और अवैध तस्करी के क्षेत्रों में सत्रह समझौतों/ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने सामाजिक क्षेत्र में उज्बेकिस्तान की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक ऋण की घोषणा की और साथ ही लाइन ऑफ क्रेडिट और क्रेता के क्रेडिट के रूप में आगे 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने की संभावना है।

वर्ष के दौरान अन्य द्विपक्षीय यात्राओं में निम्नलिखित शामिल थीं:

विदेश मंत्री श्री कामिलोव ने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की। श्री कामिलोव और विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने अप्रैल 2018 में बीजिंग में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक के मौके पर द्विपक्षीय बैठक की। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 4 और 5 अगस्त 2018 को उज्बेकिस्तान की आधिकारिक यात्रा की। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने श्री कामिलोव, राष्ट्रपति श्री शौकत मिर्जियोयेव, प्रधानमंत्री श्री अब्दुल्ला अरिपोव और उजबेकिस्तान के ओलीमजलिस (संसद) के विधान चैंबर के अध्यक्ष श्री नूरदीनजोइस्माइलोव से मुलाकात की। उन्होंने ताशकंद के भारतीय समुदाय, उज़्बेक वैज्ञानिकों, हिंदी विद्वानों, भारतीय सांस्कृतिक संबंध

उज्बेकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति श्री शॉवकट मिरजियोयेव राष्ट्रपति भवन में अपने स्वागत समारोह के दौरान सम्मान गारद का निरीक्षण करते हुए (01अक्टूबर, 2018)

परिषद (आईसीसीआर) के पूर्व छात्रों और भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) के छात्रों से बातचीत की।

व्यापार और आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी सहयोग पर अंतर-सरकारी आयोग का 11वां सत्र 16 अगस्त 2018 को आयोजित किया गया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु और उज़्बेकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री श्री सुखबरकादुरोव के साथ सत्र की सह-अध्यक्षता की। वर्ष 2017-18 में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 324 मिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र भारत द्वारा व्यापार और निवेश दोनों के लिए एक प्रमुख क्षेत्र है। हाल में भारत में चिकित्सा पर्यटन में तेजी से वृद्धि हुई है।

पूर्व विदेश राज्य मंत्री (एमओएस) श्री एम. जे. अकबर ने 14 और 15 सितंबर, 2018 को समरकंद में पाँचवीं भारत-मध्य एशिया वार्ता के लिए उज़्बेकिस्तान का दौरा किया, जिसे संयुक्त रूप से वैश्विक मामलों की भारतीय परिषद (आईसीडब्ल्यूए) और ताशकंद के सामरिक और क्षेत्रीय अध्ययन संस्थान द्वारा आयोजित किया गया था। उन्होंने 14 सितंबर 2018 को ताशकंद में आयोजित प्राचीन से आधुनिक समय तक भारत-उजबेकिस्तान संबंधों पर संगोष्ठी में भाग लिया।

रक्षा सहयोग में, सैन्य चिकित्सा, उच्च ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र और प्रशिक्षण के क्षेत्र में आदान-प्रदान हुआ। उज़्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री मेजर जनरल अब्दुस्सलोम अजिज़ोव ने 4-7 सितंबर 2018 को भारत का दौरा किया।

वर्ष के दौरान भारत-उज्बेक सांस्कृतिक संबंध बढ़ते रहे। 18-20 अगस्त 2018 को मॉरीशस में आयोजित 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में, दक्षिण एशियाई भाषाओं के विभाग के प्रमुख और निदेशक, महात्मा गांधी सेंटर फॉर इंडोलॉजिकल स्टडीज, ताशकंद अध्ययन संस्थान, डॉ. उल्फतमुखिबोवा ने उजबेकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया। सम्मेलन में “मंत्र उच्चारण” के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा केंद्रीय हिंदी संस्थान की पूर्व छात्रा सुश्री ज़िलोलासोबिरोवा को चुना गया था।

शंघाई सहयोग संगठन

भारत ने अप्रैल से नवंबर 2018 तक शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की विभिन्न उच्च-स्तरीय बैठकों में भाग लिया जिसमें राज्याध्यक्षों और शासनाध्यक्षों की बैठकें शामिल हैं।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने, बीजिंग में आयोजित विदेश मंत्रियों की एससीओ परिषद की बैठक (23 और 24 अप्रैल 2018) में भाग लिया। रक्षा मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने बीजिंग में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया (24 और 25 अप्रैल 2018)। पर्यटन-नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ एक राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने वुहान, चीन (7-11 मई 2018) में एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक में भाग लिया और संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) 15-18 मई 2018 को आयोजित 15वें शंघाई सहयोग संगठन के संस्कृति मंत्रियों की बैठक के लिए सान्या, चीन गए। कानून और न्याय मंत्रालय की अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री पिंकी आनंद ने ताजिकिस्तान (20 सितंबर 2018) में सोलहवें एससीओ अभियोजन पक्ष की आम बैठक में भाग लिया।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 9 और 10 जून, 2018 को चीन के किंगदाओ में आयोजित एससीओ के राष्ट्र प्रमुखों के शिखर सम्मेलन के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक की अध्यक्षता पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अध्यक्ष श्री शी जिनपिंग ने की। शिखर सम्मेलन में कज़ाकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति श्री नूरसुल्तान नज़रबायेव, किर्गिज़ गणराज्य के राष्ट्रपति श्री सूरोनबे जीनबेकोव, इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री ममनून हुसैन, रूसी संघ के अध्यक्ष श्री व्लादिमीर पुतिन, तजाकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति श्री इमोमाली रहमोन और उज्बेकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति श्री शौकत मिर्ज़ियोयेव ने भाग लिया।

शिखर बैठक में इस्लामी गणतंत्र अफगानिस्तान के अध्यक्ष श्री अशरफ गनी, बेलारूस गणराज्य के राष्ट्रपति श्री अलेक्जेंडर लुकाशेंको, इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति श्री हसन रूहानी और मंगोलिया के राष्ट्रपति श्री कतलमागीन बत्तुला जैसे पर्यवेक्षक देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी भाग लिया।

शिखर सम्मेलन में, संयुक्त संवाद और 'अपील टू यूथ' सहित कुल बाईस परिणामी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए थे। हस्ताक्षर किए गए अन्य दस्तावेज नशीले पदार्थों के दुरुपयोग, पर्यावरण संरक्षण, महामारी के खतरे के खिलाफ लड़ाई, व्यापार सुविधा, मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम (एमएसएमई) और सीमा शुल्क और पर्यटन से संबंधित हैं।

विदेश मंत्री की बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों के साथ सामूहिक फोटो(24 अप्रैल, 2018)

2018-2022 के लिए दीर्घकालिक अच्छे पड़ोस, मित्रता और सहयोग पर एससीओ संधि की कार्य योजना और एससीओ-अफगानिस्तान संपर्क समूह के प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किए गए।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 11 और 12 अक्टूबर 2018 को एससीओ शासनाध्यक्षों (एससीओ-एचओजी) की बैठकों में भाग लिया। पार-सीमा और एपीज़ोटिक रोगों पर संयुक्त प्रतिबंध और नियंत्रण के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

एससीओ के महासचिव श्री रशीद कुतबिद्दीनोविच अलीमोव 7 और 8 मई 2018 को भारत आए थे। श्री अलीमोव ने यात्रा के दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री और संस्कृति मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज से भेंट की।

वर्ष 2019 में भारत में आयोजित की जाने वाली शंघाई सहयोग संगठन के संयुक्त शहरी भूकंप बचाव अभ्यास के साथ-साथ आपातकालीन स्थिति के लिए एससीओ मंत्रियों की अगली बैठक के पहले भारत ने 1 और 2 नवंबर, 2018 को

शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव श्री राशिद अलीमोह किंगडाओ, चीन में प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हुए (09 जून, 2018)

नई दिल्ली में एससीओ संयुक्त शहरी भूकंप बचाव अभ्यास के लिए प्रारंभिक विशेषज्ञों की बैठक की मेजबानी की।

भारत 21-24 फरवरी, 2019 से शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) संयुक्त भूकंप प्रतिक्रिया बचाव अभ्यास और 24 फरवरी 2019 को एससीओ सदस्य राज्यों के संबंधित मंत्रालयों/एजेंसियों की प्रारंभिक विशेषज्ञ बैठक की मेजबानी करेगा। 25 फरवरी 2018 को नई दिल्ली में आपातकालीन स्थितियों की रोकथाम और उन्मूलन के लिए जिम्मेदार शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के प्रमुखों की बैठक के बाद विशेषज्ञ बैठक होगी। उपर्युक्त आयोजन विदेश मंत्रालय के समन्वय से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाएंगे।

5

खाड़ी और पश्चिम एशिया

बहरीन

भारत एवं बहरीन में उत्कृष्ट, गहन और ऐतिहासिक संबंध हैं और बहरीन में बड़े पैमाने पर भारतीय समुदाय की उपस्थिति बहरीन के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों की आधारशिला बनी हुई है। वर्ष 2017-18 में द्विपक्षीय व्यापार में 30% की वृद्धि दर्ज की गई जो वर्ष 2016-17 के 761.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2017-18 में 987.94 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई।

विदेश मंत्री (ईएएम) श्रीमती सुषमा स्वराज बहरीन में आयोजित भारत और बहरीन के बीच दूसरे उच्च संयुक्त आयोग (एचजेसी) की बैठक की सह-अध्यक्षता करने के लिए 14 और 15 जुलाई, 2018 को बहरीन गई थीं। दोनों पक्षों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष सहयोग, पर्यटन, तेल और गैस, पेट्रोकेमिकल्स, सुरक्षा, रक्षा, खाद्य सुरक्षा, साइबरस्पेस और ऊर्जा आदि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के आदान-प्रदान में सहयोग का विस्तार करने के तरीकों और

विदेश मंत्री और बहरीन के विदेश मंत्री शेख खालिद बिन अहमद बिन खलीफा ने मनामा में भारतीय राजदूतावास का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया (14 जुलाई, 2018)

साधनों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने (i) स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन (ii) नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन और राजनयिक और विशेष/आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा आवश्यकता से छूट के समझौते पर हस्ताक्षर किए। यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री, श्रीमती सुषमा स्वराज ने भारतीय दूतावास के न्यू चांसरी कॉम्प्लेक्स का उद्‌घाटन किया।

दोनों देशों द्‌वारा अंतरिक्ष सहयोग के मसौदे पर सहमति व्यक्त की जाने पर वर्ष के दौरान अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया गया। बहरीन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान एजेंसी (एनएसएसए) के सीईओ डॉ. मोहम्मद अल असीरी के नेतृत्व में तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 'बेंगलुरु स्पेस एक्सपो' में भाग लिया और सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के साथ विचार-विमर्श किया।

बहरीन के तेल मंत्री, शेख मोहम्मद बिन खलीफा अल खलीफा ने 10-12 अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच (आईईएफ) की 16वीं मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। साइबर सुरक्षा पर बहरीन के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 23 और 24 अप्रैल, 2018 को दोनों देशों के बीच साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के आगे के रास्ते पर चर्चा करने के लिए भारत का दौरा किया।

ईरान

ईरान के राष्ट्रपति, डॉ. हसन रूहानी की 14-18 फरवरी 2018 को भारत यात्रा वर्ष 2018-19 में भारत-ईरान द्‌विपक्षीय संबंधों की मुख्य सुर्खी रही। भारत और ईरान के बीच नौ समझौता ज्ञापनों/समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस यात्रा ने मई 2016 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के बाद द्‌विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान किया। वर्ष 2018 में द्‌विपक्षीय और वाणिज्यिक आदान-प्रदान में सभी स्तरों पर वृद्धि देखी गई।

प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति और ईरान इस्लामिक गणराज्य के राष्ट्रपति डॉ. हसन रूहानी राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य स्वागत समारोह में (17 फरवरी, 2018)

उच्च स्तरीय दौरे

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर, ईरान के राष्ट्रपति डॉ. हसन रूहानी ने 14-18 फरवरी 2018 को भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा की। राष्ट्रपति रूहानी के साथ आए उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल में विदेश मंत्री श्री जावद ज़रीफ़, सड़क और परिवहन मंत्री डॉ. अब्बास आख़ूंदी, पेट्रोलियम मंत्री श्री बिजान जंगनेह, आर्थिक मामलों और वित्त मंत्री मसूद करबासियन और अन्य लोग शामिल थे। यात्रा के समापन पर, "अधिक संपर्क के माध्यम से समृद्धि की ओर" शीर्षक से एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया था।

ईरान के सड़क और शहरी विकास मंत्री, डॉ. अब्बास आख़ूंदी ने 9-12 जनवरी 2018 के बीच भारत का दौरा किया। उन्होंने सड़क परिवहन और राजमार्ग, शिपिंग और जल संसाधन मंत्री, श्री नितिन गडकरी और वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री सुरेश प्रभु से मुलाकात की और चाबहार बंदरगाह के विकास सहित परस्पर रुचि के द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की।

ईरान के पेट्रोलियम मंत्री श्री बिजान जंगनेह नई दिल्ली में आयोजित 16वें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच में भाग लेने के लिए 11 अप्रैल 2018 को भारत आए थे। यात्रा के दौरान, जंगनेह, ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठक की और विशेष रूप से ऊर्जा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की।

विदेश मंत्री श्री जावद ज़रीफ ने 28 मई 2018 को भारत का दौरा किया और विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के साथ आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा की। दोनों पक्षों ने राष्ट्रपति रूहानी की भारत यात्रा के दौरान लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन का सकारात्मक आकलन किया। इनमें संपर्क, ऊर्जा, व्यापार और लोगों के परस्पर संपर्क को बढ़ावा देने के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग शामिल थे।

ईरान के सड़क और शहरी विकास मंत्री, डॉ. अब्बास आख़ूंदी 6 सितंबर 2018 को दो दिवसीय यात्रा पर भारत आए। इस यात्रा के दौरान, श्री आख़ूंदी ने अपने भारतीय समकक्ष श्री नितिन गडकरी के साथ बैठक की, जिसमें दोनों पक्षों ने अन्य विषयों के साथ, चाबहार बंदरगाह के विकास पर हस्ताक्षर किए गए समझौतों के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

चाबहार समझौते की समन्वय परिषद में भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच पहली त्रिपक्षीय बैठक 23 अक्टूबर 2018 को तेहरान में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री टी.एस. तिरुमूर्ति, सचिव (आर्थिक संबंध) ने किया। अफगान और ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संबंधित परिवहन उप-मंत्रियों ने किया। तीन पक्षों में चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पारगमन और परिवहन के लिए त्रिपक्षीय समझौते के पूर्ण परिचालन पर विस्तृत चर्चा हुई। इस विचार

पर सभी पक्षों की सहमति रही कि त्रिपक्षीय चाबहार पहल के पूर्ण परिचालन से अफगानिस्तान और इस क्षेत्र के संपर्क और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। समन्वय परिषद की अगली बैठक 2019 की पहली छमाही में भारत में आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

विदेश कार्यालय परामर्श

राजनीतिक मामलों के उप विदेश मंत्री डॉ. अब्बास अराघाची अपने भारतीय समकक्ष विदेश सचिव श्री विजय गोखले के साथ विदेश कार्यालय परामर्श के 15वें दौर के लिए 16 जुलाई 2018 को नई दिल्ली आए थे। दोनों पक्षों ने फरवरी 2018 में ईरान के राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान लिए गए निर्णयों, विशेष रूप से संपर्क बढ़ाने और व्यापार और आर्थिक मुद्दों में सहयोग तथा लोगों के आपसी आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के कार्यान्वयन में प्रगति का सकारात्मक मूल्यांकन किया। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विनिमय किया गया, जिसमें विभिन्न पक्षों द्वारा संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओए) पर उठने वाले मुद्दों को हल करने के प्रयास भी शामिल हैं।

संसदीय आदान-प्रदान

ईरानी मजलिस के ईरान-भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों ने अपने अध्यक्ष श्री नज़र अफसाली के नेतृत्व में, मजलिस के सदस्यों के साथ फरवरी 2018 में भारत का दौरा किया। यात्रा के दौरान, उन्होंने विदेश मंत्री से भेंट की और ऊर्जा पर संसदीय स्थायी समिति के साथ चर्चा की। ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने इस यात्रा के समय, एक इंटरेक्टिव सत्र के लिए नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा कैम्पस का दौरा किया।

द्विपक्षीय व्यापार

भारत-ईरान द्विपक्षीय व्यापार 2016-17 के 12.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 13.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुँच गया। द्विपक्षीय व्यापार में 2016-17 की तुलना में 6.8% की वृद्धि देखी गई। 2017-18 के दौरान, भारतीय निर्यात में 11.4% की वृद्धि हुई और 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा, जबकि ईरान से आयात 5.8% बढ़ कर 11.11 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

संस्कृति

भारत ने 15 मई 2018 को यूनेस्को तेहरान क्लस्टर कार्यालय द्वारा आयोजित 'वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट 2018' में भाग लिया, जिसमें भारतीय पुस्तक प्रदर्शनी, भारतीय संगीत प्रदर्शन, भारतीय भोजन और नाश्ते वितरण शामिल था। भारतीय संस्कृति केंद्र (एसवीसीसी) और केन्द्रीय विद्यालय स्कूल तथा संबद्ध योग सोसायटी द्वारा योग कक्षा के प्रदर्शन के साथ तेहरान में 21 जून 2018 को चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया।

विदेश मंत्री ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ से नई दिल्ली में मुलाकात करते हुए (28 मई, 2018)

राजनयिक संबंध

भारत और ईरान के बीच संयुक्त कांसुलर समिति की वार्ता 16 जनवरी 2018 को, तेहरान में आयोजित की गई। संयुक्त सचिव (सीपीवी) ने भारत-ईरान कांसुलर वार्ता के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक में राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए आगमन पर वीजा देने, ई-वीजा और वीजा-छूट की सुविधा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। ये पहले कार्यान्वित कर दी गई हैं।

इराक

इराक से भारत के लंबे ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध रहे हैं और यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भागीदार बना हुआ है। पिछले वित्तीय वर्ष में यह भारत के लिए कच्चे तेल के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा और इस वर्ष में भी इस स्थिति को बनाए रखने के लिए तैयार है। वर्ष 2017-18 के दौरान इराक से भारत का द्विपक्षीय व्यापार 19.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें 17.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर का तेल आयात शामिल था।

आईएसआईएस पर इराक की जीत के बाद, भारत सरकार ने इराक में कई मानवीय और विकासात्मक परियोजनाओं को शुरू करने की मंजूरी दी, जिसमें युद्ध प्रभावित सिंजर क्षेत्र में पानी के काम की बहाली, इराक के शहीद फाउंडेशन को उपकरणों की आपूर्ति, मोसुल विश्वविद्यालय के लिए इंजीनियरिंग पुस्तकों की आपूर्ति शामिल है। 24 नवंबर 2018 से, इराक में 500 युद्ध पीड़ितों को कृत्रिम अंग लगाने के लिए जयपुर स्थित संगठन के सहयोग से कर्बला में चालीस दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया था।

इराक के उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री डॉ. अब्दुल रज्जाक अल-इसा, 3-6 अक्टूबर 2018 के बीच नई दिल्ली में आयोजित शिक्षा और कौशल एवं प्रदर्शनी पर भारत-एशियाई शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इराक के शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के उप मंत्री डॉ. फाउद कासिम मोहम्मद ने 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2018 तक नई दिल्ली में आयोजित 14वें उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) द्वारा आयोजित एक व्यापार बैठक में भी हिस्सा लिया।

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (एफआईईओ) के नेतृत्व में लगभग चालीस भारतीय कंपनियों ने 10-19 नवंबर, 2018 के बीच आयोजित बगदाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लिया। इस उद्देश्य के लिए मेला मैदान में एक 'इंडिया पैवेलियन' की स्थापना की गई थी।

एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (टीपीसीआई) के नेतृत्व में 26-30 नवंबर 2018 से इराक (बगदाद, कर्बला, नजफ और एरबिल) का दौरा किया। इसमें खाद्य और कृषि क्षेत्र की कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग पच्चीस व्यवसायी शामिल थे। भारतीय उद्योग परिसंघ के भारतीय व्यापारियों की एक अन्य टीम ने 16-20 दिसंबर 2018 से बगदाद और एरबिल का दौरा किया और व्यवसाय के विकल्प तलाशने और विकासात्मक परियोजनाएं आरंभ करने के लिए काम किया। इराक में तेल और इस्पात क्षेत्र में निवेश में रुचि बढ़ी है।

भारत इराक के लोगों के लिए चिकित्सा उपचार और उच्च शिक्षा प्राप्त करने का पसंदीदा स्थान बना रहा। बगदाद में 21 जून, 2018 को बहुत उत्साह के साथ चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस आयोजन में 250 से अधिक इराकी युवाओं ने भाग लिया।

इजराइल

पिछले वर्ष भारत-इजरायल संबंधों की 25वीं वर्षगांठ के समारोह के बाद (जिसमें दोनों देशों के शासनाध्यक्षों की परस्पर यात्राएं शामिल थीं), वर्ष 2018 में मंत्री/मुख्यमंत्री स्तर पर कई महत्वपूर्ण यात्राओं के साथ यह रुझान जारी रहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री, श्री मनोहर लाल खट्टर, उत्तराखंड और महाराष्ट्र के कृषि मंत्रियों और पंजाब के एक वरिष्ठ आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ, तेल अवीव में आयोजित नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों - एग्रीटेक पर त्रिवार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने विज्ञान मंत्रियों के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए 27-29 मई 2018 तक इज़राइल का दौरा किया, इस यात्रा के दौरान उन्होंने अपने

इज़राइली समकक्ष, ओफर अकुनिस से भेंट की। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी ने 26 जून से 1 जुलाई 2018 तक इज़राइल में अधिकारियों के एक बड़े प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस यात्रा के दौरान कृषि, जल, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में कई इजरायली कंपनियों के साथ सोलह समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री अमरिंदर सिंह ने 21-25 अक्टूबर 2018 तक इज़राइल में पंजाब के वरिष्ठ अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। यात्रा के दौरान शैक्षिक सहयोग और जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्रों में चार समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

पिछले चार वर्षों की परंपरा को ध्यान में रखते हुए, जुलाई-अगस्त 2018 में, सरदार पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीएनपीए) हैदराबाद से 2016 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) प्रोबेशनर्स के पूरे बैच ने इजराइल में अपना सप्ताह भर का विदेशी प्रशिक्षण पूरा किया। सितंबर 2018 में, औद्योगिक संवर्धन और नीति विभाग (डीआईपीपी) के नेतृत्व में और निवेश भारत द्वारा समन्वित आठ राज्य सरकारों के सोलह अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने वार्षिक तेल अवीव इनोवेशन फेस्टिवल 2018 में भाग लेने के लिए इज़राइल का दौरा किया। भारत और इज़राइल के बीच सीमा प्रबंधन पर संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की चौथी बैठक 25-29 नवंबर, 2018 को इज़राइल में संपन्न हुई।

दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच नियमित आदान-प्रदान जारी रखते हुए, वायु सेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल श्री बी.एस. धनोआ ने 21-24 मई 2018 तक अंतर्राष्ट्रीय वायु सेना कमांडरों के सम्मेलन के दूसरे संस्करण में भाग लिया। तटरक्षक बल के महानिदेशक श्री राजेंद्र सिंह ने तटीय सुरक्षा और समुद्री कानून प्रवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग की क्षमता का पता लगाने के लिए 9-11 जुलाई 2018 को इज़राइल का दौरा किया। भारत-इज़राइल जेडब्ल्यूजी की 14वीं बैठक रक्षा सचिव के नेतृत्व में 3 जुलाई 2018 को नई दिल्ली में हुई। कमांडेंट वाइस एडमिरल श्रीकांत के नेतृत्व में इंडियन नेशनल डिफेंस कॉलेज के एक उन्नीस सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अगस्त 2018 के अंतिम सप्ताह में एक रणनीतिक पड़ोस के अध्ययन दौरे के लिए इज़राइल का दौरा किया, जबकि कॉलेज ऑफ़ डिफेंस मैनेजमेंट के इक्कीस अधिकारी अपने अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक प्रबंधन दौरे के हिस्से के रूप में अक्टूबर में आए थे। इजरायल में स्थित भारतीय दूतावास द्वारा हाइफा नगरपालिका के सहयोग से हाइफा की लड़ाई के शताब्दी वर्ष को एक विशेष समारोह के रूप में चिह्नित किया गया था, जिसमें मेजर जनरल श्री डोगरा और अधिकारियों तथा 61वीं कैवेलरी के रैंक के नेतृत्व में भारतीय सेना के एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल ने भी भाग लिया था। अंत में, अपनी सात महीने की विदेश यात्रा के हिस्से के रूप में, भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण जहाज, आईएनएस तरंगिनी ने 27-30 सितंबर 2018 से हाइफा में एक पोर्ट कॉल किया।

तेल अवीव नगर पालिका के सहयोग से तेल अवीव बंदरगाह में एक हजार से अधिक लोगों की भागीदारी के साथ सार्वजनिक कार्यक्रम के रूप में चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून 2018) मनाया गया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के समारोह 2 अक्टूबर 2018 को दूतावास में एक कार्यक्रम के साथ शुरू किए गए, जिसमें भारत द्वारा जारी किए गए स्मारक डाक टिकट को जारी करना शामिल था। नवंबर 2018 में गोवा में आयोजित 49वें आईएफएफआई के लिए इज़राइल पर ध्यान केंद्रित किया गया था, इस उत्सव के दौरान दस इजरायली फिल्मों का प्रदर्शन किया गया था।

जॉर्डन

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 9 और 10 फरवरी, 2018 की अम्मान यात्रा और 27 फरवरी से 1 मार्च 2018 के बीच किंग अब्दुल्ला की भारत की राजकीय यात्रा के बाद, भारत और जॉर्डन के बीच द्विपक्षीय संबंध आत्मीयता और सौहार्दपूर्ण बने रहे।

जॉर्डन के ऊर्जा मंत्री श्री सालेह खरबशाह ने 12 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री श्री आसिफ इब्राहिम के विशेष दूत ने जॉर्डन के अकाबा में अप्रैल 2018 में आयोजित दक्षिण-पूर्व एशिया-द्वितीय पर अकाबा प्रक्रिया बैठक में भाग लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) की आठ सदस्यीय टीम ने 30 अप्रैल से 7 मई 2018 तक किंग अब्दुल्ला द्वितीय विशेष संचालन प्रशिक्षण केंद्र, अम्मान में आयोजित 10वीं वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय योद्धा प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें पच्चीस मित्र देशों से चालीस टीमों को शामिल किया गया था। भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य स्वागत समारोह में राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने जॉर्डन नरेश महामहिम अब्दुल्लाह II अल-हुसैन से मुलाकात की (01 मार्च, 2018)

एक पुराने विमान डकोटा टेल सं. 905 ने 20-22 अप्रैल, 2018 को कोवेंट्री (इंग्लैंड) से भारतीय हवाई अड्डे आने के रास्ते में अकाबा, जॉर्डन को पार किया।

इकतीस भारतीय कंपनियों ने इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (ईईपीसी इंडिया) के त्वावधान में अम्मान में 9-12 अप्रैल 2018 को आयोजित जॉर्डन अंतर्राष्ट्रीय मशीनरी और इलेक्ट्रो-मैकेनिकल प्रदर्शनी (जिमेक्स-2018) में भाग लिया। भारतीय दूतावास ने 14 अक्टूबर, 2018 को अकाबा में अकाबा स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन अथॉरिटी और एक राज्य सुगमता कोष गतिविधि, "गोवा - एक परफेक्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन" के सहयोग से 14 अक्टूबर 2018 को अकाबा में एक व्यापार प्रोत्साहन सम्मेलन, "इंडिया-सर्जिंग अहेड 2018" का आयोजन किया। 11 सितंबर 2018 को जॉर्डन टूरिज्म बोर्ड के निमंत्रण पर भारतीय फिल्म उद्योग के एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने जॉर्डन का दौरा किया। गोवा पर्यटन के प्रतिनिधियों ने जॉर्डन का दौरा किया और 10 अक्टूबर 2018 को अम्मान में पर्यटन उद्योग के हितधारकों के साथ रोड शो किया।

भारतीय दूतावास ने 150वीं जयंती के समारोह के साथ, 2 अक्टूबर 2018 को एक शानदार तरीके से गांधीजी का स्मरणोत्सव मनाया।

कुवैत

भारत और कुवैत के बीच के ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण और बहुआयामी संबंध विभिन्न दिशाओं में बढ़ते रहे हैं। वर्ष के दौरान कई उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय बातचीत हुई। लगभग 9.5 लाख के भारतीय कार्यबल के साथ कुवैत में भारतीय समुदाय सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय बना हुआ है। वर्ष के दौरान कुवैत में भारतीय समुदाय की चिंताओं से संबंधित मुद्दों पर अच्छी प्रगति हुई।

व्यापार, विशेष रूप से तेल व्यापार, भारत-कुवैत संबंधों में ऐतिहासिक रूप से एक महत्वपूर्ण घटक रहा है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में कुवैत एक विश्वसनीय स्रोत बना रहा। द्विपक्षीय व्यापार बड़े पैमाने पर, कुवैत के पक्ष में रहा, 2017-18 में यह 8.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। 2017-18 के दौरान, कुवैत भारत का नौवाँ सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता था और इसने भारत की ऊर्जा जरूरतों का लगभग 4.63% पूरा किया, जिसकी कुल मात्रा 12.85 मिलियन बैरल की आपूर्ति और कीमत 5.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। गैर-तेल द्विपक्षीय व्यापार भी बढ़ता रहा। भारत और कुवैत के बीच कुल गैर-तेल द्विपक्षीय व्यापार 2017-18 में 2,405.40 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि कुवैत में भारत का गैर-तेल निर्यात 2017-18 में 1,361.06 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

श्रम, रोजगार और जनशक्ति विकास पर भारत और कुवैत संयुक्त श्रम समूह की छठी बैठक 25 और 26 अप्रैल 2018 को कुवैत में आयोजित की गई थी। श्री मनीष गुप्ता, संयुक्त सचिव, प्रवासी भारतीय मामलों के प्रभाग-I, विदेश मंत्रालय और श्री सामी अब्दुल अजीज अल-हमद, वाणिज्य मामलों के सहायक विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय, कुवैत राज्य ने बैठक की सह-अध्यक्षता की। यह बैठक श्रम, रोजगार और जनशक्ति विकास के क्षेत्र में सहयोग और समन्वय को मजबूत करने पर केंद्रित थी। भारतीय इंजीनियरों, नर्सों और घरेलू कर्मचारियों की भर्ती के मुद्दे को बड़े पैमाने पर उठाया गया और इस पर विस्तार से चर्चा की गई।

चौथा विदेश कार्यालय परामर्श 1 और 2 अगस्त 2018 को कुवैत में हुआ। भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (खाड़ी) डॉ. टी वी नागेंद्र प्रसाद और कुवैती प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एशियाई मामलों के मंत्री, विदेश मंत्री (एएफएम), विदेशी मामले, कुवैत राज्य, श्री अली सुलेमान अल-सईद ने किया। बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने पारस्परिक हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा की।

कुवैत के सामाजिक मामलों और श्रम मंत्री, सुश्री हेंद बकर अल सुबैह, ने 26 अक्टूबर 2018 को भारत का दौरा किया और विदेश राज्य मंत्री (एमओएस) विदेश राज्य मंत्री (डॉ.) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) के साथ चर्चा की। बैठक के दौरान, लंबित मामलों, विशेष रूप से खराफी राष्ट्रीयता के भारतीय श्रमिकों, भारतीय इंजीनियरों, अस्सी भारतीय नर्सों की भर्ती और भारतीय घरेलू श्रमिकों पर समझौता ज्ञापन से संबंधित मामलों के बारे में चर्चा की गई, जिससे उनके हितों की रक्षा की जा सके।

विदेश मंत्री (ईएएम) श्रीमती सुषमा स्वराज ने 30 और 31 अक्टूबर 2018 को कुवैत की आधिकारिक यात्रा की। नवंबर 2013 में कुवैत के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के बाद यह उनकी पहली कुवैत यात्रा और पहली उच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने कुवैत के अमीर शेख सब-अल-अहमद अल-जबर अल-सबा, और कुवैत के प्रधान मंत्री, शेख जाबेर अल-मुबारक अल-हमद अल-सबा से भेंट की। बाद में विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने उप-प्रधानमंत्री और कुवैत के विदेश मंत्री के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया। दोनों मंत्रियों ने व्यापार और निवेश, रक्षा और श्रम मुद्दों के क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। दोनों पक्ष तेल व्यापार से आगे बढ़ने की आवश्यकता तथा व्यापार और निवेश के लिए भी रास्ते तलाशने पर सहमत हुए। इस यात्रा ने राजनयिक, आधिकारिक और विशेष पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा में छूट और घरेलू कामगारों की भर्ती पर समझौते सहित दो महत्वपूर्ण समझौतों को पूरा किया गया।

दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी बढ़ता रहा है। भारत ने कुवैत दूतावास, दिल्ली में रक्षा अताशे का कार्यालय खोलने की स्वीकृति दी। दोनों पक्षों के बीच रक्षा सहयोग पर मसौदा समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान हुआ।

लेबनान

लेबनान में संसदीय चुनाव नौ वर्ष बाद, 6 मई 2018 को हुए। राष्ट्रपति श्री मिशेल एउन द्वारा प्रधानमंत्री और फ्यूचर आंदोलन के नेता, श्री साद हरीरी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया था। श्री नबीह बेरी को फिर से संसद का अध्यक्ष चुना गया। नए मंत्रिमंडल के गठन को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

भारत और लेबनान के बीच ऐतिहासिक रूप से मैत्रीपूर्ण संबंधों और बहुआयामी सहयोग में कुछ उल्लेखनीय विकास हुए, जिनमें मई 2018 में चुनावों के बाद भारत के लिए लेबनानी संसदीय मैत्री समूह का पुनर्गठन; 12-14 सितंबर 2018 तक फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (एफआईईओ), भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई), और इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट काउंसिल (ईईपीसी) के नेतृत्व में अड़तालीस सदस्यीय बहु-क्षेत्रीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल की बेरूत यात्रा; इंडिया रजिस्टर ऑफ शिपिंग (आईआरक्लास) और एक्सेप्शनल ऑपरेशन क्लासीफिकेशन-सैल (एक्सओक्लास) के बीच प्रबंधन, सर्वेक्षण और जहाजों के वर्गीकरण के लिए लेबनानी बाजार को विकसित करने के लिए एक संयुक्त प्रयास में एक एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर; बेरुत में एक प्रमुख व्यापार प्रदर्शनी में दस भारतीय कंपनियों की भागीदारी; भारत और लेबनान के बीच आने वाले पेशेवरों और व्यापारियों की संख्या में और वृद्धि आदि शामिल हैं। भारत ने लेबनान के नागरिक और रक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण देना जारी रखा है। 2018-19 के लिए असैनिक भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग

(आईटाईसी) स्लॉट की संख्या साठ से बढ़ा कर पचहत्तर कर दी गई है।

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती सहित महत्वपूर्ण अवसरों पर स्थानीय भागीदारों के सहयोग से दूतावास द्वारा सार्वजनिक समारोह आयोजित किए गए; भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रदर्शनों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों और स्कूलों में चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 'भारत दिवस' का आयोजन किया गया। दक्षिण लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (लेबनान) के भारतीय बटालियन के मुख्यालय में राजदूत द्वारा प्रसिद्ध लेबनानी गायक अबीरनेहम द्वारा प्रस्तुत भजन "वैष्णव जन तो तेने कहिए जे" का वीडियो जारी किया गया।

ओमान

वर्ष के दौरान, भारत और ओमान ने द्विपक्षीय भागीदारी जारी रखी। दोनों देशों ने पारंपरिक रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे है, जिसे ऐतिहासिक समुद्री व्यापार संबंधों के रूप में देखा जा सकता है। ओमान में रहने वाले लगभग आठ लाख भारतीय वहाँ का सबसे बड़ा प्रवासी समूह हैं।

वर्ष 2017-18 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था जिसमें भारत का निर्यात 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर और आयात 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल हैं। भारत के वाणिज्य और उद्योग एवं नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने 15-18 जुलाई 2018 को भारत-ओमान संयुक्त आयोग की बैठक (जेसीएम) के आठवें सत्र और संयुक्त परिषद (जेबीसी) के नौवें सत्र की सह-अध्यक्षता की। भारत-ओमान संयुक्त व्यापार परिषद के ओमानी सह-अध्यक्ष पंकज खिमजी के नेतृत्व में ओमान के इकतीस युवा व्यापारियों के एक दल ने भारत का दौरा किया और 16 मई 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी के सारस्वत के नेतृत्व में एक दल ने भारत और ओमान के बीच खनन क्षेत्र में सहयोग का पता लगाने के लिए 8 और 9 अप्रैल 2018 को ओमान का दौरा किया।

ओमानी पक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने में रुचि व्यक्त की। ओमान के पर्यावरण और जलवायु मामलों के मंत्री श्री मोहम्मद बिन सलीम अल तोबी भारतीय महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) अक्षय ऊर्जा की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली आम सभा में भाग लेने के लिए 1-5 अक्टूबर 2018 से नई दिल्ली आए थे।

रक्षा सहयोग में, ओमान के रक्षा मामलों के मंत्री श्री सैय्यद बद्रबिन सऊद बिन हरीब अल-बसैदी ने 25-27 सितंबर 2018 को भारत का दौरा किया। रक्षा सचिव, श्री संजय मित्रा 27-29 नवंबर, 2018 को भारत-ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग समिति (जेएमसीसी) की दसवीं बैठक की सह-अध्यक्षता करने के लिए ओमान गए। भारत से 14 सदस्यीय एनडीसी प्रतिनिधिमंडल ने 26-29 अगस्त 2018 को ओमान का दौरा किया। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट (सीडीएम) के बीस अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 21-26 अक्टूबर 2018 के दौरान 'अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक प्रबंधन यात्रा' के लिए ओमान का दौरा किया।

भारत और ओमान रणनीतिक वार्ता के पांचवें दौर की सह-अध्यक्षता के लिए उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) श्री राजिंदर खन्ना की 11 और 12 अप्रैल, 2018 की ओमान यात्रा से भारत और ओमान के बीच सुरक्षा सहयोग और मजबूत हुआ।

फिलिस्तीन

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की, 10 फरवरी 2018 की फिलिस्तीन की पहली ऐतिहासिक यात्रा के दौरान घोषित 42.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए गए।

भारत और फिलिस्तीन के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर संयुक्त कार्य दल (जेडब्ल्यूजी) की पहली बैठक 16 और 17 जुलाई 2018 को फिलिस्तीन के रामल्ला में आयोजित की गई थी; और एक पचास सदस्यीय फिलिस्तीनी युवा प्रतिनिधिमंडल ने 1-7 अक्टूबर 2018 से भारत का दौरा किया।

कतर

कतर के साथ भारत के गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। दोनों देशों के नेताओं के बीच हाल की उच्च स्तरीय सम्बद्धता द्वारा प्रदान किए गए उत्कृष्ट ढांचे के अंतर्गत कतर के साथ बहुमुखी जुड़ाव बढ़ रहा है। फरवरी 2018 में कतर में भारतीय प्रवासियों की आबादी 6,91,539 है और यह कतर में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। भारतीय समुदाय कतर की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लगा हुआ है और इस देश के समग्र विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

लोगों के आपसी संपर्क को बढ़ाने के एक और कदम में, भारत ने कतर के नागरिकों के लिए ई-वीजा की सुविधा प्रदान की है। 2017-18 के दौरान कतर को भारतीय निर्यात में 87% की वृद्धि दर्ज की गई। 2017-18 के दौरान कुल व्यापार 9.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17% की वृद्धि दर्ज करता है।

पूर्व विदेश राज्य मंत्री श्री एम. जे. अकबर ने 15-17 अप्रैल 2018 को कतर का दौरा किया और कतर राष्ट्रीय पुस्तकालय के आधिकारिक उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कतर के अपने समकक्ष सुल्तान बिन साद अल मुरैखी के साथ बैठक की और द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से सामुदायिक कल्याण, व्यापार और निवेश, संस्कृति और लोगों के परस्पर संपर्क के क्षेत्र पर चर्चा की।

विदेश मंत्रालय के महासचिव, डॉ. अहमद हसन अल हमादी ने 20 अप्रैल 2018 को राजनीतिक परामर्श के लिए भारत का दौरा किया। भारत और कतर के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का तीसरा दौर 23 सितंबर 2018 को दोहा में आयोजित किया गया था, जहां भारतीय पक्ष का नेतृत्व श्री टी.एस. तिरुमूर्ति, सचिव (ईआर) ने किया था। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की।

विदेश मंत्री (ईएएम) श्रीमती सुषमा स्वराज 28-30 अक्टूबर, 2018 को कतर की आधिकारिक यात्रा पर गई थीं। किसी भारतीय विदेश मंत्री की यह पहली कतर यात्रा थी। उन्होंने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की और आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने कतर के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री श्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी के साथ प्रतिनिधि-स्तरीय वार्ता की। दोनों पक्षों ने विदेश/विदेश मामलों के मंत्री के स्तर पर एक संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने कतर की कंपनियों को पेट्रोकेमिकल्स, बुनियादी ढाँचे, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया।

सऊदी अरब

भारत और सऊदी अरब के बीच के घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हाल के वर्षों में एक मजबूत और पारस्परिक रूप से लाभप्रद साझेदारी में परिवर्तित हो गए हैं। 2.7 मिलियन से अधिक भारतीय प्रवासियों का मेजबान राज्य इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। पिछले वर्ष प्रतिष्ठित जनाद्रियाह महोत्सव में अतिथि के रूप में भारत की उपस्थिति और वित्त मंत्री द्वारा संयुक्त आयोग की 12वीं बैठक (जेसीएम) की सह-अध्यक्षता से भारत और सऊदी अरब के बीच के द्विपक्षीय संबंधों का प्रक्षेपवक्र वर्ष 2018-19 के दौरान ऊपर की ओर बढ़ा है।

29 नवंबर 2018 को ब्यूनस आयर्स में जी20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बैठक बहुत ही फलप्रद रही, दोनों नेता द्विपक्षीय बैठकों को गहराई और विविधता देने पर सहमत हुए। सऊदी क्राउन प्रिंस ने भारत के राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (एनआईएफ) में सार्वजनिक निवेश कोष (पीआईएफ) के निवेश को अंतिम रूप देने और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में भाग लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।

बढ़ते आर्थिक संबंधों के साथ, सऊदी अरब आज हमारा चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार (चीन, अमेरिका और यूएई के बाद) और ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। हम सऊदी अरब भारत की कुल आवश्यकता के लगभग19% कच्चे तेल का आयात करते हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान, हमारे द्विपक्षीय व्यापार ने 2016-17 के 25.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 27.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचकर 9.57% की वृद्धि दर्ज की है।

प्रधान मंत्री ब्यूनस आयर्स में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के साथ मुलाकात करते हुए (29 नवंबर, 2018)

क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के अधीन सऊदी सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप (एससीआईएसपी) ने अपने व्यापार और निवेश संबंधों को बेहतर बनाने के लिए भारत सहित आठ देशों की पहचान की है। एससीआईएसपी और नीति आयोग के बीच पहली प्रारंभिक बैठक 26 जुलाई 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

सऊदी के ऊर्जा, उद्योग और खनिज संसाधन मंत्री श्री खालिद अल फलीह ने 10 -11 अप्रैल, 2018 को 16वें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच (आईईएफ) की मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए और नई दिल्ली में 14-16 अक्टूबर 2018 को आयोजित भारत ऊर्जा मंच में भाग लेने के लिए दो बार भारत का दौरा किया। आईईएफ की 16वीं मंत्रिस्तरीय बैठक के अवसर पर, सऊदी अरामको ने रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, रत्नागिरी और महाराष्ट्र में 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विकास करने के लिए भारतीय कंसोर्टियम (आईओसी, बीपीसीएल और एपपीसीएल) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। (बाद में, यूएई के एडीएनओसी ने जून 2018 में आरमको के साथ उक्त परियोजना के विकास में भाग लेने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।)

ओडिशा के उद्योग मंत्री श्री अनंत दास ने नवंबर 2018 में 'मेक इन ओडिशा' शिखर सम्मेलन का प्रचार करने के लिए सऊदी अरब का दौरा किया। इसी तरह, 'वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन 2019' का प्रचार करने के लिए गुजरात से एक प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब का दौरा किया। इसके अलावा, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (टीपीसीआई), फ्रामेक्सिल और एपीईडीए आदि के प्रतिनिधिमंडलों ने रियाद का दौरा किया था।

दस सऊदी कैडेट (दिसंबर 2017 में पांच कैडेट और जून 2018 में पांच कैडेट) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए), पुणे में शामिल हुए और छह सदस्यीय रक्षा प्रतिनिधिमंडल ने डीईईएफ एक्सपीओ 2018 में भाग लिया। आईएनएस तरंगिनी 4-6 मई 2018 तक जेद्दा बंदरगाह पर गया था। एक भारतीय तोपखाने के प्रतिनिधिमंडल ने 22-25 अक्टूबर 2018 के बीच इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिलरी, रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस, खामिसमुसायत का दौरा किया।

नवंबर 2017 में योग को आधिकारिक तौर पर 'खेल गतिविधि' के रूप में मान्यता दी गई थी। भारत के दूतावास ने 21 जून 2018 को, 'स्वास्थ्य और कल्याण के लिए योग' नामक एक सत्र आयोजित कर चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, जो राज्य में पहला आउटडोर योग कार्यक्रम था।

सीरिया

भारत ने सीरिया के बारे में अपने दृष्टिकोण बनाए रखा है - सीरिया में संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता और सभी पक्षों को बातचीत की मेज पर लाकर संकट के व्यापक और शांतिपूर्ण समाधान के लिए आह्वान किया है; सीरिया के लोगों की वैध आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक समाधान एक सीरियाई नेतृत्व वाली प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए। भारत ने संकट को हल करने के लिए जिनेवा और अस्ताना प्रक्रिया सहित विभिन्न पहलों का समर्थन किया।

भारत ने अप्रैल 2018 में सीरिया को खाद्य पदार्थों और दवाओं के रूप में 15 करोड़ रुपये से अधिक की मानवीय सहायता प्रदान की।

भारत ने आईटीईसी और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) की छात्रवृत्तियों के अलावा, शैक्षणिक वर्ष 2018-19 से शुरू होने वाली चार वर्ष की अवधि के लिए "स्टडी इन इंडिया" कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में अध्ययन के लिए 400 सीरियाई छात्रों को तकनीकी सहायता दी। सीरियाई छात्रों ने कार्यक्रम के अंतर्गत मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय द्वारा चिह्नित विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रवेश लिया है।

एफआईईओ, सीआईआई, फिक्की और ईईपीसी के नेतृत्व में भारतीय कंपनियों के एक बहु-उत्पाद व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने 7-11 सितंबर 2018 के बीच सीरिया का दौरा किया। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने जनशक्ति की सूचना और प्रशिक्षण के आदान-प्रदान के लिए फेडरेशन ऑफ सीरियाई चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सीरिया में एक ट्रैक्टर प्लांट स्थापित करने के लिए मैसर्स सोनालिका ट्रैक्टर कंपनी और मैसर्स सीरियन मॉडर्न ट्रैक्टर कंपनी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

संयुक्त अरब अमीरात

वर्ष के दौरान उच्चतम स्तर पर यात्राओं के नियमित आदान-प्रदान और व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए संबंधों के उन्नयन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की गति को बनाए रखा गया था।

भारत से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की उच्च-स्तरीय यात्राओं में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान की 11-15 मई 2018 तक की यात्रा शामिल थी। उन्होंने संयुक्त मैंगलोर में भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) की कंदरा के लिए संयुक्त अरब अमीरात से तेल की खेप ले जाने वाले जहाज को हरी झंडी भी दिखाई। श्री प्रधान ने अबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन (एडीआईपीईसी) में भाग लेने के लिए 12-15 नवंबर 2018 से फिर से संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया, उस समय संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (एडीएनओसी) ने पाडुर की कंदरा में कच्चा तेल भरने के लिए आईएसपीआरएल के साथ एक और समझौते पर हस्ताक्षर किए।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर भारत-संयुक्त अरब अमीरात जेसीएम के 12वें सत्र की सह-अध्यक्षता करने के लिए 3-5 दिसंबर 2018 को अबू धाबी का दौरा किया, उन्होंने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस से भेंट की और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री के साथ संयुक्त रूप से महात्मा गांधी और शेख जायद पर एक डिजिटल संग्रहालय का शुभारंभ किया। यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने संयुक्त रूप से अफ्रीका में विकासात्मक परियोजनाओं के लिए मुद्रा विनिमय और समझौता ज्ञापन के समझौते पर हस्ताक्षर किए।

संयुक्त अरब अमीरात से, ऊर्जा सुरक्षा, संक्रमण, प्रौद्योगिकी और निवेश मंत्री, श्री सुहैल मोहम्मद अल मज़रोई 16वें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच (आईईएफ) की मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए 10-12 अप्रैल 2018 को भारत आए थे। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री, शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान 24-30 जून 2018 को विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज से मिले और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने भारत के विदेशी सेवा संस्थान और अमीराती डिप्लोमैटिक अकादमी के

विदेश मंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्लाह बिन जाएद अल नाहयान ने अबु धाबी में गाँधी-जाएद डिजिटल संग्रहालय का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया (4 दिसंबर, 2018)

बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा सऊदी अरब के अरामको के साथ संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (एडीएनओसी) ने भी रत्नागिरी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स में निवेश के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान वे अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु भी गए। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के शाही दरबार के अध्यक्ष और अबू धाबी निवेश प्राधिकरण (एडीआईए) के प्रबंध निदेशक, शेख हमीद ने 14-15 अक्टूबर 2018 को भारत में संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, तथा मुंबई में 15 अक्टूबर को निवेश पर उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल (एचएलटीएफआई)की छठी बैठक की सह-अध्यक्षता की। संयुक्त अरब अमीरात के मंत्रीमंडल के राज्य मंत्री और एडीएनओसी के ग्रुप सीईओ डॉ. सुल्तान अहमद अल जाबेर ने 15 अक्टूबर 2018 को ग्लोबल ऑयल एंड गैस लीडर्स के साथ प्रधानमंत्री की वार्षिक अंतरराष्ट्रीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मामलों के राज्य मंत्री, श्री मोहम्मद अहमद अल बोउर्दी रक्षा मंत्री के निमंत्रण पर 14-18 अक्टूबर 2018 को भारत आए थे। संयुक्त अरब अमीरात के नेशनल डिफेंस कॉलेज की सोलह सदस्यीय टीम ने 17-23 नवंबर 2018 तक एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भारत का दौरा किया। संयुक्त अरब अमीरात के फेडरल नेशनल काउंसिल के राज्य अवर-सचिव के नेतृत्व में आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कार्यकारिणी और विधायिका अधिकारियों के बीच समन्वय और संसदीय कार्य के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करने के लिए 12 से 14 दिसंबर 2018 तक भारत का दौरा किया।

शारजाह की अमीरात ने जनवरी 2019 में आयोजित नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में एक अतिथि देश के रूप में भाग लिया। पुस्तक मेले में शारजाह के शासक ने शारजाह मंडप का उद्घाटन किया। नेशनल बुक ट्रस्ट अप्रैल 2019 में अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भी भाग लेगा।

हैदराबाद में एक और महावाणिज्य दूतावास स्थापित करने के संयुक्त अरब अमीरात के अनुरोध को जुलाई 2018 में मंजूरी दी गई थी। 29 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली में भारत-संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त कांसुलर समिति का तीसरा सत्र आयोजित किया गया था। दोनों देशों के बीच सुरक्षा मामलों में अधिक से अधिक सहयोग किया जाता रहा है। वर्ष के दौरान, संयुक्त अरब अमीरात ने अमेरिकी वीजा या ग्रीन कार्ड धारक और यूरोपीय संघ या यूके के वीजा धारक भारतीय नागरिकों के लिए के लिए उदारीकृत वीजा योजना की घोषणा की। संयुक्त अरब अमीरात ने अगस्त से दिसंबर 2018 की अवधि के लिए अवैध प्रवासियों के लिए आम माफ़ी योजना की घोषणा की, इस दौरान भारतीय नागरिकों को भारत लौटने के लिए बड़ी संख्या में आपातकालीन प्रमाणपत्र जारी किए गए थे। कुछ योग्य मामलों में, उन्हें भारतीय सामुदायिक कल्याण निधि से वापसी हवाई टिकट भी जारी किए गए थे।

यमन

भारत और यमन में लोगों से लोगों के करीबी और ऐतिहासिक संपर्क का एक लंबा इतिहास रहा है। यमन में राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति बिगड़ने के कारण, 14 अप्रैल 2015 से यमन के भारतीय दूतावास को अस्थायी रूप से जिबूती में स्थानांतरित कर दिया गया है। दूतावास यमन में भारतीय नागरिकों के लिए अपनी सहायता जारी रखे हुए है।

यमन के बिजली और ऊर्जा मंत्री श्री अब्दुल्ला मोहसिन अल-अकवा ने एक बार मार्च 2018 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) शिखर सम्मेलन के लिए और उसके बाद अक्टूबर 2018 में आईएसए की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक के लिए भारत का दौरा किया।

भारत ने यमन को चिकित्सा सहायता देना जारी रखा है और दिसंबर 2017 में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता की घोषणा की थी। अप्रैल 2018 में उन्हें हैजा के 7,000 टीके एयरलिफ्ट करके पहुँचाए गए जबकि शेष दवाइयां मई और जुलाई 2018 में जहाज द्वारा दो खेप में अदन पहुंचाई गईं।

6

अफ्रीका

अंगोला

वर्ष के दौरान, मंत्रिस्तरीय और आधिकारिक स्तर की यात्राओं का नियमित आदान-प्रदान हुआ। अंगोला की ओर से, उनके भूविज्ञान और खान राज्य मंत्री ने 26 मार्च से 3 अप्रैल 2018 तक भारत का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ने 5-10 जुलाई 2018 को भारत का दौरा किया। भारतीय पक्ष से, नाबार्ड और नाबाकॉन के अध्यक्ष के नेतृत्व में 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए 19-23 नवंबर 2018 तक अंगोला का दौरा किया। भारत मुख्य रूप से थोक कच्चे तेल की खरीद के आधार पर अंगोला का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार (लगभग 10% अंगोला बाहरी व्यापार) बन गया है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु के 29-30 जनवरी 2019 तक अंगोला जाने की संभावना है।

बेनिन

बेनिन ने इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के संस्थापक सम्मेलन और 11 मार्च 2018 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले सौर सम्मेलन और 2 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली में आईएसए की पहली महासभा में भाग लिया। बेनिन ने 3-5 अक्टूबर 2018 से नई दिल्ली में आयोजित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन (एमजीआईएससी) में वरिष्ठ आधिकारिक स्तर पर भी भाग लिया। इन यात्राओं ने वर्ष के दौरान दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी बनाने में मदद की। भारत 2017-18 में बेनिन के वैश्विक व्यापार का लगभग 17% हिस्से और

703 मिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ बेनिन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। इस वर्ष पहले से चल रही एलओसी परियोजनाओं के अलावा, भारत ने सौर संबंधित परियोजनाओं के लिए ईबीआईडी [पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय (ईसीओडब्ल्यूएएस) बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट] के माध्यम से 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रियायती ऋण दिया। भारत ने कृषि विविधीकरण के माध्यम से युवाओं और महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भारत-यूएनडीपी विकास साझेदारी निधि के अंतर्गत बेनिन को 300,000 अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता भी प्रदान की। सांस्कृतिक मोर्चे पर, नरसिंह मेहता द्वारा लिखे "वैष्णव जन तो" और एक लोकप्रिय बेनिनी गायक सुश्री ज़ेनब हबीब द्वारा गाए भजन को बेनीनी लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया था। बेनेन के स्वास्थ्य मंत्री के 25-26 फरवरी 2019 (विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से) नई दिल्ली में आयोजित होने वाले वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य भागीदारी के चौथे शिखर सम्मेलन और 27 फरवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य संगोष्ठी में भाग लेने के लिए भारत आने की संभावना है।

बोत्सवाना

बोत्सवाना के उपराष्ट्रपति श्री स्लम्बर सोगवने के निमंत्रण पर, उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 2018 तक बोत्सवाना की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। उनके साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, दो संसद सदस्य, श्री के. सुरेश और श्री वी. मुरलीधरन और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल थे।

यात्रा के दौरान, उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने 13वें वार्षिक ग्लोबल एक्सपो बोत्सवाना का उद्घाटन किया और भारत-बोत्सवाना के सीईओ गोलमेज को संबोधित किया। उन्होंने बोत्सवाना के राष्ट्रपति डॉ. मासीसी से भेंट की और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। राजनयिक पासपोर्ट के धारकों के लिए वीजा की आवश्यकता से छूट और द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक संयुक्त समुदाय पर एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू की यात्रा आपसी चिंता के निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए विशिष्ट सम्मान के साथ रिश्ते को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के महत्वपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम थी: भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) के अंतर्गत बोत्सवाना रक्षा बल को प्रशिक्षित करने के लिए भारतीय सेना प्रशिक्षण दल (आईएटीटी) की तैनाती; अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए बोत्सवाना का परिग्रहण; एक चांसरी निर्माण परियोजना; न्यायिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन (समझौता ज्ञापन), बोत्सवाना राजनयिकों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण; व्यापार और लोगों के आपसी संपर्क को बढ़ावा देने के लिए वीजा और वर्क परमिट के मुद्दे; एसएमई, लॉजिस्टिक्स, फार्मास्युटिकल, माइनिंग, एग्रीकल्चर, रिटेल और कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में व्यापार और निवेश सहयोग; चिकित्सा पर्यटन, दवाओं, पारंपरिक दवाओं, जेनेरिक दवाओं, आयुर्वेद/योग और बोत्सवाना में भारत अफ्रीका डायमंड इंस्टीट्यूट (आईएडीआई) की जल्द से जल्द स्थापना के क्षेत्र में सहयोग।

उप राष्ट्रपति और बोत्सवाना के उप राष्ट्रपति स्लंबर सोगवेन ने बोत्सवाना में आयोजित 13वें ग्लोबल एक्सपो का साथ मिलकर उद्घाटन किया (31 अक्टूबर, 2018)

बोत्सवाना के, जल और स्वच्छता सेवाओं के सहायक मंत्री श्री इटुमेलेंग मोईपीसी ने 29 सितंबर-2 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली में आयोजित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। यह दौरा स्वच्छ भारत मिशन की ओर से पेयजल और स्वच्छता मंत्री श्रीमती उमा भारती के निमंत्रण पर था। वर्ष 2017-18 (भारत द्वारा मुख्य रूप से हीरे का आयात) में 26% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि के साथ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। क्षमता निर्माण में भारत की सहायता हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है। प्रशिक्षण वर्ष 2018-19 में बोत्सवाना द्वारा आईटीईसी/इंडिया अफ्रीका फोरम समिट (आईएएफएस)/भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) और अन्य योजनाओं के अंतर्गत अब तक 160 छात्रवृत्ति स्लॉटों का उपयोग किया गया है। मिशन ने योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस और महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के स्मारक के कार्यक्रम आयोजित किए। स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों और भारतीय समुदाय के सदस्यों की भारी भागीदारी के अलावा, बोत्सवाना की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष सुश्री ग्लेडिस टीटी कोकोरवे ने इन घटनाओं में

भाग लिया। 8 अक्टूबर 2018 को, मिशन ने एक व्यापार-सह-सांस्कृतिक कार्यक्रम, 'गुजरात पर संगोष्ठी 'का आयोजन किया, जिसे बोत्सवाना के खनिज संसाधन, हरित प्रौद्योगिकी और ऊर्जा सुरक्षा मंत्री श्री एरिक मोल्ले ने संबोधित किया।. मिशन ने विभिन्न भारतीय संघों के सहयोग से, भारतीय संस्कृति और लोगों के आपसी संपर्क को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक प्रदर्शनों और खाद्य उत्सवों सहित 10 से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन किया।

पहली बार बोत्सवाना के राष्ट्रपति डॉ. मोकेगसेसी मासी ने जुलाई 2018 में जोहान्सबर्ग में आयोजित 10वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने समावेशी विकास की अपनी खोज में अफ्रीका के लिए ब्रिक्स की प्रासंगिकता पर जोर दिया।

दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय (एसएडीसी) के मंत्रियों ने 29 और 30 अप्रैल 2018 को जोहान्सबर्ग में आयोजित भारत-दक्षिण अफ्रीका व्यापार सम्मेलन में भाग लिया इस अवसर पर, वाणिज्य, उद्योग और नागरिक विमानन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने 30 अप्रैल, 2018 को बोत्सवाना की निवेश, व्यापार और उद्योग मंत्री सुश्री बोगोलोकेनवेडो के साथ विचार-विमर्श किया और द्विपक्षीय भागीदारी बढ़ाने के लिए आगे की पहल पर सहमति व्यक्त की।

बुर्किना फासो

भारत और बुर्किना फासो के बीच आत्मीय और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं, जो 11 मार्च 2018 को नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) शिखर सम्मेलन के संस्थापक सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुर्किनाबे के राष्ट्रपति श्री रोच मार्क क्रिश्चियन काबे के आने से और मजबूत हुए। पूर्व विदेश राज्य मंत्री श्री एम. जे. अकबर, 11-13 जुलाई 2018 को औऱकडौगौ में आयोजित चौथे भारत-बुर्किना फासो संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता करने के लिए बुर्किना फासो गए। 29 सितंबर -2 अक्टूबर 2018 से नई दिल्ली में आयोजित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन में शामिल होने के लिए बुर्किनाबे के जल, जल प्रणाली और स्वच्छता मंत्री एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आए। बुर्किना फासो के व्यापार महानिदेशालय में आर्थिक सलाहकार के साथ औद्योगिक विकास महानिदेशक ने 8-9 अक्टूबर 2018 को नाइजीरिया के अबूजा में आयोजित सीआईआई-एक्जिम बैंक इंडिया-वेस्ट अफ्रीका रीजनल कॉन्क्लेव में भाग लिया। भारत और बुर्किना फासो के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2016-17 में 371.36 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2017-18 में 780.92 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। नेशनल

प्रधान मंत्री की नई दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की बैठक के अवसर पर बुर्किना फासो के राष्ट्रपति महामहिम रॉक मार्क क्रिश्चियन काबोर से मुलाकात (11 मार्च, 2018)

बिल्डिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनबीसीसी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर के लिए भारत की अनुदान सहायता के संबंध में बुर्किना फासो का दो बार दौरा किया। 23 जून 2018 को बुर्किना फासो में चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया।

बुरूंडी

बुरुंडी को 2018-19 के लिए दस आईसीसीआर स्लॉट आवंटित किए गए थे। बुरुंडी को 30 आईटीईसी स्लॉट भी आवंटित किए गए थे, आज तक उनमें से अठारह स्लॉटों का उपयोग किया गया है। अब तक बुरुंडी द्वारा चार आईएएफएस प्रशिक्षण स्लॉटों का उपयोग किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) समारोह 24 जून 2018 को बुजुम्बुरा में आयोजित किया गया था।

कैमरून

वरिष्ठ आधिकारिक स्तर पर 29 सितंबर -2 अक्टूबर 2018 से नई दिल्ली में आयोजित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन (एमजीआईएससी) में कैमरून का प्रतिनिधित्व किया गया था। कैमरून की अर्थव्यवस्था की मामूली बहाली के साथ, भारत और कैमरून के बीच द्विपक्षीय व्यापार इस वर्ष के पहले छह महीनों में 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचा, जबकि पिछले साल यह 406 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। सांस्कृतिक मोर्चे पर, 12-सदस्यीय हरियाणा लोक नृत्य मंडली ने नवंबर 2018 में कैमरून का दौरा किया और डौला में प्रदर्शन किया। अप्रैल 2018 में संगोष्ठी के आयोजन और जून 2018 में योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के साथ लोगों से लोगों के आपसी संपर्क बढ़े हैं। श्री मासोमा जोसेफ के नेतृत्व में नरसिंह मेहता के भजन "वैष्णव जन तो" को एक लोकप्रिय कोरस समूह द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे कैमरून के लोगों ने खूब सराहा।

केप वर्डे

केप वर्डे के उद्योग, व्यापार और ऊर्जा मंत्री ने पहली आईएसए असेंबली और में 3-5 नवंबर 2018 को ग्रेटर नोएडा में दूसरे पुनर्निवेश में भाग लिया। केप वर्डे के क्षेत्रीय एकीकरण उप मंत्री ने 8 और 9 अक्टूबर 2018 को अबूजा में आयोजित सीआईआई-एक्जिम बैंक इंडिया-वेस्ट अफ्रीका रीजनल कॉन्क्लेव में भाग लिया। वित्तीय वर्ष 2017-18 में वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 36% बढ़कर 4.30 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। भारतीय दूतावास, डकार ने 22 जून 2018 को केप वर्डे के प्राया में चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में काफी लोग उपस्थित थे और गणमान्य व्यक्तियों में प्राया के महापौर और प्रधानमंत्री के सलाहकार शामिल थे।

केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य

वर्ष के दौरान केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य (सीएआर) की सरकार के साथ बातचीत बहुत सीमित थी, जिसका कारण मोटे तौर पर सीएआर में राजनीतिक अनिश्चितता थी। ऊर्जा मंत्री ने 29 सितंबर-2 अक्टूबर 2018 को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। सीएआर ने सभी अंतरराष्ट्रीय/संयुक्त राष्ट्र निकायों में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है।

चाड

चाड के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों ने वर्ष के दौरान अपनी गति को बनाए रखा है। चाड के प्रधानमंत्री श्री पाहिमी पडके अल्बर्ट ने 11 मार्च 2018 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के संस्थापक सम्मेलन और सौर शिखर सम्मेलन में भाग लिया। चाड ने 29 सितंबर -2 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली में आयोजित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन (एमजीआईएससी) में पर्यावरण, जल संसाधन और मत्स्य पालन मंत्री के स्तर पर भाग लिया। चाड ने नई दिल्ली में 2 अक्टूबर 2018 को होने वाली आईएसए की पहली महासभा में वरिष्ठ आधिकारिक स्तर पर भाग लिया। इन मंत्रिस्तरीय यात्राओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया है। चाड भारत के लिए कच्चे तेल के आपूर्तिकर्ता के रूप में भी उभर रहा है, इस वर्ष सितंबर 2018 तक आयात 290 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचा, जबकि पिछले साल 141 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात हुआ था। आईएसए के संस्थापक सम्मेलन के बाद, भारत सरकार ने एन'जमेना में एक सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल विनिर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए 27.45 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एलओसी प्रदान किया। सांस्कृतिक मोर्चे पर, याराना एसोसिएशन, भारत और चाड के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने वाले एक चाडियन एनजीओ के सदस्यों द्वारा गाए गए"वैष्णव जन तो" भजन को प्रतिपादन चाड के लोगों द्वारा खूब सराहा गया। चाड के माइंस, इंडस्ट्रियल प्रमोशन, ट्रेड एंड प्रमोशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर के मंत्री के अहमदाबाद में "जीवंत गुजरात अफ्रीका दिवस" में भाग लेने के लिए 18-20 जनवरी 2019 तक भारत आने की संभावना है।

कोटे डी आइवर

वर्ष के दौरान कोटे डी'वायर के साथ संबंधों को और मजबूत किया गया। उनके उपराष्ट्रपति डैनियल कबलान डंकन ने 11 मार्च 2018 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के संस्थापक सम्मेलन में कोटे डी आइवर का प्रतिनिधित्व किया। पेट्रोलियम, ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आइवरियन ने अक्टूबर 2018 में नई दिल्ली में आईएसए की पहली महासभा में भाग लिया। भारत और कोटे डी आइवर के बीच द्विपक्षीय व्यापार 511.75 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात और 441.70 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आयात के साथ 2017-18 में 953,45 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा।

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य

वर्ष के दौरान कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी) के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे। डीआरसी के विदेश मंत्री ने 11 मार्च 2018 को दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संस्थापक सम्मेलन में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। ऊर्जा और हाइड्रोलिक संसाधन मंत्री आईएसए की पहली महासभा के लिए 1 से 6 अक्टूबर 2018 तक नई आए थे। भारत ने, विशेष रूप से भारत-अफ्रीका फोरम समिट (एएएफएस) और आईटीईसी क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के अंतर्गत, इस देश को क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करना जारी रखा है। वर्ष के दौरान, सत्तर आईटीईसी स्लॉट और डीआरसी को दी जाने वाली दस आईसीसीआर छात्रवृत्ति का पूर्ण उपयोग किया गया है। वर्ष के दौरान, भारत सरकार (जीओआई) ने, बंदुडु प्रांत में 9.3 मेगावाट काकोबो हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एलओसी परियोजना का समर्थन किया, इसे अक्टूबर 2018 में पूरा किया गया।

इक्वेटोरियल गिनी

द्विपक्षीय संबंधों में एक प्रमुख उपलब्धि 7-9 अप्रैल 2018 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा इक्वेटोरियल गिनी (ईजी) की पहली यात्रा रही। यात्रा के दौरान, पारंपरिक दवाओं और औषधीय पौधों के क्षेत्र में सहयोग पर दो समझौता ज्ञापन और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) में सहयोग पर एक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रपति को इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति द्वारा इक्वेटोरियल गिनी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ग्रैन कॉलर डी ला इंडिपेंडेनिया का पदक से सम्मानित किया गया। यात्राओं की गति को बनाए रखते हुए, पूर्व राज्य मंत्री (एमओएस) श्री एम. जे. अकबर इस देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ में भाग लेने के लिए 11-13 अक्टूबर, 2018 को इक्वेटोरियल गिनी गए।

राष्ट्रपति मालाबो, इक्वेटोरिया गिनी में अपने आगमन पर आयोजित स्वागत समारोह के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर की निगरानी करते हुए (07 अप्रैल, 2018)

इथियोपिया

इथियोपिया और भारत के बीच द्वितीय संयुक्त आयोग की बैठक 9 मई 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इथियोपिया के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री डॉ. वर्कनेहगेबेहु ने और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री (ईएएम) श्रीमती सुषमा स्वराज ने किया। दूतावास ने 16 जून 2018 को अदीस अबाबा में चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इथोपिया सरकार का प्रतिनिधित्व मुख्य अतिथि के रूप में विदेश मामलों के राज्य मंत्री प्रो अफ्वेल कसू द्वारा किया गया था। विदेश मामलों की राज्य मंत्री श्रीमती हीरुत ज़ेमेने, संसद सदस्य, कई राजदूत और राजनयिकों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लिया। इथियोपिया के महान धावक और युवा आइकन श्री हैले गेब्रसेलेसी ने भाग लिया और इस अवसर पर अपना संदेश दिया। 19 जुलाई 2018 को, के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की यात्रा के दौरान इथियोपिया की सरकार 1000 मीट्रिक टन चावल के दान की घोषणा की गई। राष्ट्रीय आपदा और जोखिम प्रबंधन आयोग के उपायुक्त श्री डेमेनेदरुता ने प्रतीकात्मक रूप से इथियोपिया सरकार की ओर से खेप स्वीकार की।

भारत के दूतावास ने 15-23 सितंबर 2018 से इटैलियन कल्चरल सेंटर, अदीस अबाबा में एशिया पैसिफिक देशों के 12 मिशनों के एक समूह द्वारा आयोजित एशिया पैसिफिक फिल्म फेस्टिवल में भाग लिया, जिसमें हिंदी फिल्म "पूर्णा: साहस की कोई सीमा नहीं" प्रदर्शित की गई थी। कृषि और

विदेश मंत्री ने इथियोपिया के विदेश मंत्री डॉ. वर्कनेह गेबेयेहु से नई दिल्ली में मुलाकात की (09 मई, 2018)

किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने 4-6 सितंबर 2018 तक अदीस अबाबा का दौरा किया। यह यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा कृषि सहयोग के साथ-साथ आगे के सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए थी। राज्य मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने पशुधन और मत्स्य पालन राज्य मंत्री डॉ गेब्रेयो हैंन्स के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इंडिया बिजनेस फोरम में भी भाग लिया। 2 अक्टूबर 2018 को मिशन ने चांसरी परिसर में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई। अफ्रीमा-2018 के लिए छह नामांकन प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध इथियोपियाई गायक बेट्टी जी द्वारा गाये भजन 'वैष्णव जन तो' का वीडियो दिखाया गया, स्टूडियो ऑफ़ प्रोडक्शन आरटीडी, जिबूती के कलाकारों द्वारा गाए 'वैष्णव जन तो' का एक अन्य वीडियो जारी किया गया। महात्मा गांधी पर डाक विभाग, भारत सरकार द्वारा भेजे गए स्मारक डाक टिकट जारी किए गए। गांधीजी पर एक विशेष फिल्म का एलईडी प्रक्षेपण भी किया गया था। 31 अक्टूबर 2018 को, मिशन ने सरदारवल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई। सरदार पटेल के जीवन पर एक लघु फिल्म और स्टैचू ऑफ यूनिटी पर एक लघु वीडियो क्लिपिंग भी प्रदर्शित की गई थी।

गैबॉन

वर्ष के दौरान गैबॉन के साथ राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरह के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत किया गया। गैबॉन के विदेश मंत्री श्री रेगिस इमोगॉल्ट ने 24-30 नवंबर, 2018 को नई दिल्ली का दौरा किया और विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के साथ विस्तारित चर्चा की। जुलाई 2018 में मैंगनीज अयस्क क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल ने गैबॉन का दौरा किया, इसके बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए नवंबर 2018 में भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय से एक यात्रा की गई। दूसरी ओर, नेशनल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स गैबॉन उर्वरक संयंत्र परियोजना (यूरिया प्लांट) में हिस्सेदारी हासिल करने की संभावना तलाश रहा है। पिछले कुछ वर्षों

विदेश मंत्री ने गैबोन के विदेश मंत्री इमॉनगॉल्ट जिन यूडेस रेजिस से नई दिल्ली में मुलाकात की (30 नवंबर, 2018)

में, पच्चीस से अधिक भारतीय कंपनियों को गैबॉन के विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में इकाइयां स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है। बहुत सी भारतीय कंपनियाँ लिबास निर्माण के क्षेत्र में काम कर रही हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार के उद्यम और गैबॉन में एक तटवर्ती अन्वेषण ब्लॉक के ऑपरेटर ने तेल की खोज गतिविधि जारी रखी।

गाम्बिया

जाम्बिया के पेट्रोलियम और ऊर्जा के मंत्री ने 11 मार्च 2018 को नई दिल्ली में आईएसए के संस्थापक सम्मेलन में भाग लिया। जाम्बिया के स्वास्थ्य और समाज कल्याण के मंत्री ने 29 सितंबर -2 अक्टूबर 2018 से महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन (एमजीआईएससी) में भाग लिया। पेट्रोलियम और ऊर्जा मंत्री ने 3-5 अक्टूबर 2018 से नई दिल्ली में पहली आईएसए महासभा और दूसरे पुन: निवेश में भाग लेने के लिए फिर से नई दिल्ली का दौरा किया। वित्तीय वर्ष 2017-18 में वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 70% की वृद्धि दर्ज करते हुए 178.90 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। एक भारतीय कंपनी को 53.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से बंजुल में जाम्बिया विश्वविद्यालय (यूटीजी) फरबा परिसर के निर्माण का अनुबंध दिया गया है। बीस जाम्बियन राजनयिकों ने विदेशी सेवा संस्थान, नई दिल्ली द्वारा 20 जून से 20 जुलाई 2018 तक विदेशी राजनयिकों के लिए निर्मित पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया।

घाना

वर्ष के दौरान, कई महत्वपूर्ण यात्राओं से भारत और घाना के बीच के पारंपरिक रूप से आत्मीय और सौहार्दपूर्ण संबंधों को मजबूत किया गया, जिसमें घाना के राष्ट्रपति श्री नाना एडो डंकवा अकुफो-एडो की यात्रा शामिल है, जिन्होंने 11 मार्च 2018 को नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संस्थापक सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। घाना के विदेश मंत्री और क्षेत्रीय एकीकरण मंत्री (वह पहले मार्च में अपने राष्ट्रपति के साथ गए थे) ने 16-18 जुलाई 2018 तक भारत की आधिकारिक यात्रा की और विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के साथ द्विपक्षीय बैठक की। यात्रा के दौरान, 2018-2022 की अवधि के लिए सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम (सीईपी) और भारतीय मानक ब्यूरो और घाना मानक प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। स्वच्छता और जल संसाधन मंत्री ने 29 सितंबर -2 अक्टूबर 2018 से नई दिल्ली में आयोजित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन में घाना के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। ऊर्जा मंत्री ने 2-5 अक्टूबर 2018 से नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली महासभा में दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। व्यापार और उद्योग के उप मंत्री ने 8-9 अक्टूबर 2018 से नाइजीरिया के अबूजा में आयोजित सीआईआई-एक्जम बैंक इंडिया-वेस्ट अफ्रीका रीजनल कॉन्क्लेव में भाग लिया।

दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में तेजी देखी गई है और 2016-17 के 2620.82 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2017-18 में यह 3345.83 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने घाना के राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्राधिकरण के निमंत्रण पर 24-27 अप्रैल 2018 तक घाना का दौरा किया। ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एक अन्य दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 25-26 मई 2018 को घाना के डाउनस्ट्रीम तेल क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने के लिए घाना का दौरा किया। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने 14 मई से 1 जून 2018 तक 38 भारतीय कंपनियों की भागीदारी के साथ अकारा में 14वीं पश्चिम अफ्रीकी खनन और बिजली प्रदर्शनी वेम्पैक्स 2018 में "इंडिया पैवेलियन" का आयोजन किया। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (एफआईईओ) ने घाना इंटरनेशनल ट्रेड फेयर सेंटर, अकरा में 6-8 सितंबर 2018 से पॉवरेलेक, ऑटो पार्ट्स और कंस्ट्रक्शन घाना के तीसरे संस्करण में 55 भारतीय कंपनियों की भागीदारी का समर्थन किया। जून 2016 में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की पहली राजकीय यात्रा के

दौरान की गई घोषणा, आईसीटी (एआईटीआई-केएसीई) में भारत-घाना कोफी अन्नान सेंटर फॉर एक्जीलेंस को एक मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता प्रदान की गई थी और यह अनुदान महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिह्नित करने के लिए दो साल के लंबे समारोह के शुभारंभ में 2 अक्टूबर 2018 को संसद के स्पीकर और संचार मंत्री की उपस्थिति में केंद्र को जारी किया गया था। 37 सैन्य अस्पताल, अकरा के "गांधी वार्ड" प्रसूति विंग को ओवर द काउंटर दवाओं के साथ एक पानी की टंकी भेंट की गई। पूर्व राष्ट्रपति श्री जॉन कुफूर ने महात्मा गांधी के जीवन और शिक्षाओं पर एक भाषण दिया और इंडिया हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में डाक विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए महात्मा गांधी के स्मारक टिकटों का विमोचन किया। घाना के स्वच्छता और जल संसाधन मंत्री ने 5-7 दिसंबर 2018 से नई दिल्ली में आयोजित तीसरे भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन के लिए दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। आईटीईसी प्रशिक्षण कार्यक्रम लोकप्रिय हैं और घाना में इनकी मांग की जाती है। 2017-18 की अवधि के दौरान, घाना ने 110 आईटीईसी स्लॉट्स का उपयोग किया, जिनमें आईएएफएस निर्णय के अंतर्गत उनतीस स्लॉट्स और आईसीसीआर छात्रवृत्ति के अंतर्गत इसे आवंटित किए गए बीस स्लॉटों में से ग्यारह स्लॉट शामिल हैं। घाना के पांच वैज्ञानिकों को 2017-18 के दौरान सीवी रमन रिसर्च फेलोशिप से सम्मानित किया गया। अप्रैल-अक्टूबर 2018 की अवधि के दौरान, छत्तीस आईटीईसी स्लॉट का उपयोग किया गया है। घाना के साथ रक्षा सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है और 2018-19 की अवधि के लिए आईटीईसी के अंतर्गत घाना के सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए सत्ताईस प्रशिक्षण स्लॉट आवंटित किए गए हैं।

गिनी

भारत और गिनी के बीच सौहार्द और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। गिनी के विदेश मंत्री श्री ममादियौरे ने मार्च 2018 में नई दिल्ली में आईएसए के संस्थापक सदस्यों के सम्मेलन में गिनी का प्रतिनिधित्व किया। मार्च 2018 में निवेश के प्रभारी राज्य मंत्री डॉ. इब्राहिम कासोरीफोना ने नई दिल्ली में आयोजित 13वें सीआई-एक्जिम बैंक के इंडिया-अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए मार्च 2018 में भारत का दौरा किया। गिनी के ऊर्जा और हाइड्रोलिक्स मंत्री ने अक्टूबर 2018 में नई दिल्ली में आईएसए की पहली आमसभा में भाग लिया। भारत और गिनी के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2017-18 में 892.57 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें 377.94 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात और 514.63 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात शामिल था। भारत शीघ्र ही कॉनक्री में अपने राजनयिक मिशन को फिर से खोल रहा है।

गिनी बिसाऊ

गिनी बिसाऊ के ऊर्जा, उद्योग और प्राकृतिक संसाधनों के मंत्री ने नई दिल्ली में 29 सितंबर -2 अक्टूबर 2018 से महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन में भाग लिया। मंत्रिमंडल के ऊर्जा, उद्योग और प्राकृतिक संसाधनों के प्रमुख ने 8-9 अक्टूबर 2018 से अबूजा में भारत-पश्चिम अफ्रीका परियोजना भागीदारी पर सीआईआई-एक्जिम बैंक क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लिया। वित्तीय वर्ष 2017-18 में वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार 266.89 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12.5% अधिक था। गिनी-बिसाऊ की निर्यात आय का 90% से अधिक काजू की फसल से आता है और काजू की लगभग पूरी फसल (लगभग 98%) प्रसंस्करण के लिए भारत को निर्यात की जाती है। भारत ने गिनी बिसाऊ को आपातकालीन खाद्य सहायता के रूप में 1000 टन चावल की आपूर्ति की।

केन्या

भारत-केन्या संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) की आठवीं बैठक 22-25 अगस्त 2018 से केन्या के नैरोबी में आयोजित की गई थी। इस बैठक की सह-अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु और केन्या सरकार के उद्योग, व्यापार और सहकारिता के लिए कैबिनेट सचिव (मंत्री) पीटर मुन्या ने की। संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के मौके पर भारत-केन्या संयुक्त व्यापार परिषद की बैठक हुई। वाणिज्य मंत्री ने भारतीय प्रवासी सदस्यों से भी बातचीत की।

लेसोथो

लेसोथो के जल मामलों के मंत्री, श्री सामो न्येन ईजेकील नत्सेकेले, जल आयुक्त श्रीमोकेमोजकिसेन के साथ भारत में 29 सितंबर-2 अक्टूबर 2018 से महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन (एमजीएसआईसी) में भाग लेने के लिए भारत आए थे।

लेसोथो के स्वास्थ्य मंत्री, श्री नकाकु काबी ने 30 जून-6 जुलाई 2018 को भारत का दौरा किया और सुश्री मंथाबिसेंग आर्किलिया फोलली, स्वास्थ्य उप मंत्री, लेसोथो सरकार ने 2 सितंबर 2018 को अपोलो अस्पताल भारत और स्वास्थ्य मंत्रालय, लेसोथो सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत का दौरा किया। सामाजिक विकास मंत्री सुश्री माटेबात्सो डोती ने अक्टूबर 2018 के दूसरे सप्ताह के दौरान कमजोर वृद्धों के लिए सहयोग और बच्चों और विकलांग लोगों के लिए समर्थन के क्षेत्र में चर्चा करने के लिए भारत का दौरा किया।

लाइबेरिया

वर्ष के दौरान, द्विपक्षीय संबंधों को नियमित यात्राओं द्वारा चिह्नित किया गया था। राज्य मंत्री (एमओएस) ने 1-2 मार्च 2018 से लाइबेरिया का दौरा किया। यात्रा के दौरान, भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र और परिवहन वाहनों और दमकल वाहनों के लिए अनुदान सहायता की पेशकश की। लाइबेरिया के विदेश मंत्री ने मार्च 2018 में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संस्थापक सम्मेलन में भाग लिया। भारत और लाइबेरिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2017-18 में 294.22 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा साथ किया गया, जिसमें 257.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात और 36.76 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात हुआ।

मलावी

उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू 4-5 नवंबर 2018 को मलावी की यात्रा पर गए थे। उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू के साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता के राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर और दो सांसद भी गए थे। उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने मलावी के राष्ट्रपति प्रो. आर्थर पीटर मुथारिका से भेंट की और इस कार्यक्रम के लिए पहचाने गए 18 देशों में से पहले देश मलावी में 'इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी' कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यात्रा के दौरान तीन समझौता ज्ञापनों (i) राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा से छूट; (ii) प्रत्यर्पण संधि और (iii) रेडियो-सक्रिय/परमाणु खनिज और दुर्लभ खनिज सामग्री के खनन को विनियमित करने में क्षमता निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।। यात्रा के दौरान घोषित अनुदानों में निम्नलिखित शामिल हैं: भाभाट्रॉन कैंसर उपचार उपकरण का उपहार; दवाएँ, दस एम्बुलेंस, 1,00,000 एनसीईआरटी पुस्तकें, ट्रस्ट ऑफ़ फर्स्ट लेडी ऑफ़ मलावी द्वारा संचालित "ब्यूटीफुल मालवी" को 10,000 अमेरिकी डॉलर। जल परियोजनाओं के लिए 215.68 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के नए ऋणों की भी घोषणा की गई।

उप राष्ट्रपति ने मलावी के राष्ट्रपति आर्थर पीटर मुथारिका से लिलॉंगवे में मुलाकात की (05 नवंबर, 2018)

स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्री श्री अतूपुले मुलुजी, 29 सितंबर से 2 अक्टूबर 2018 तक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे और उद्योग, व्यापार और पर्यटन मंत्री श्री हेनरी मुसा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली महासभा (आईएसए) में भाग लेने के लिए 2-6 अक्टूबर 2018 को आए थे। भारत और मलावी के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में पहला संयुक्त कार्य समूह 21 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

माली

माली के राष्ट्रपति, इब्राहिम बोकैकर केटिया, मार्च 2018 में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संस्थापक सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आए थे। दोनों देशों के बीच साझा ऐतिहासिक संबंधों की खोज करने के उद्देश्य से, 14 मई से 6 जून, 2018 तक राष्ट्रीय संग्रहालय में भारत में टिम्बकटू, माली की प्राचीन पांडुलिपियों की एक प्रदर्शनी - "ताजमहल टिम्बकटू से मिलता है" का आयोजन किया गया था।. 2017-18 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 237.74 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2016-17 से लगभग 15% तक अधिक है।

मॉरिटानिया

वर्ष 2018 के दौरान कोई उच्च-स्तरीय आधिकारिक यात्रा नहीं हुई। 2018-19 के दौरान मॉरिटानिया को पांच आईटीईसी स्लॉट और तीन आईसीसीआर छात्रवृत्तियों का प्रस्ताव किया गया है। 2017-2018 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 88.61 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि 2016-2017 में यह 76.93 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।

नामिबिया

एक भारतीय कंपनी केजीके डायमंड्स ने विंडहोक में हीरे काटने और पॉलिश करने की एक इकाई खोली, जिसका उद्घाटन 13 अप्रैल 2018 को खान और ऊर्जा मंत्री श्री टॉम अलवेन्डो ने किया था। मिशन ने 30 अप्रैल 2018 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित भारत-दक्षिण अफ्रीका व्यापार शिखर सम्मेलनमें 19 नामीबियाई कंपनियों की भागीदारी की सुविधा

प्रदान की। फेडरेशन ऑफ इंडियन ग्रेनाइट एंड स्टोन इंडस्ट्री (एफआईजीएसआई) के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 9-11 जुलाई 2018 को नामीबिया का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने खान और ऊर्जा मंत्रालय में खनन आयुक्त से मुलाकात की और द्वारा ग्रेनाइट खदान का दौरा किया, साथ ही वाल्विस बे में एक पत्थर काटने और पॉलिशिंग प्लांट का भी दौरा किया। भारत के विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (सीएसई) के सहयोग से नामीबिया के पर्यावरण और पर्यटन मंत्रालय ने 6 अगस्त 2018 को विंडहोक में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन विनियमों पर 2 दिवसीय अफ्रीकी राष्ट्रों के अनुभव साझाकरण कार्यशाला का आयोजन किया। इसका उद्घाटन पर्यावरण और पर्यटन मंत्री, श्री पोहांबाशिता द्वारा किया गया था और इसमें 14 अफ्रीकी देशों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और नीति-निर्माताओं ने भाग लिया था। नामीबिया में निर्माणाधीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सीडीएसी) के छह महीने के प्रशिक्षण के लिए नामीबिया के चार मास्टर ट्रेनरों ने 21 अगस्त 2018 को भारत का दौरा किया। यह केंद्र भारत की प्रतिबद्धता है और इसे 2019 में आरंभ किए जाने की उम्मीद है।

मिशन ने 29 अगस्त 2018 को एक बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट का आयोजन किया जिसमें भारत-नामीबिया चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (आईएनसीसीआई) और भारतीय और नामीबिया की कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नामीबिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट (एनआईपीएएम) और लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (एलबीएसएनएए) के बीच सार्वजनिक अधिकारियों के क्षमता निर्माण के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन पर 4 सितंबर 2018 को विंडहोक में हस्ताक्षर किए गए। नामीबिया ने 25 जून 2018 को इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के लिए अपना एक्सेस दस्तावेज जमा किया और 25 जुलाई 2018 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया। 21 अप्रैल 2018 को मिशन द्वारा एक योग प्रदर्शन-सह-अभ्यास सत्र का आयोजन किया गया था। नेशनल काउंसिल ऑफ नामीबिया की अध्यक्ष और खोमसाल्ड निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य, सुश्री मार्गेट मेन्सा विलियम्स ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। 5 जून 2018 को मिशन द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। मिशन ने 23 जून 2018 को विंडहोक में योग के चौथे अंतर्राष्ट्रीय दिवस (आईडीवाई) का आयोजन किया। अंतरराष्ट्रीय संबंध और सहयोग उप मंत्री, क्रिस्टीन होएबस, विंडहोक के महापौर मिसे कज़ापुआ, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता सुश्री हेलिया जोहान्स ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। मिशन द्वारा 2 अक्टूबर 2018 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान, स्थानीय कलाकार सैली बॉस मैडम द्वारा प्रस्तुत भजन 'वैष्णव जन तो' को महात्मा गांधी पर डाक टिकट के साथ जारी किया गया और महात्मा गांधी पर एक वृत्तचित्र का प्रदर्शन किया गया।

नाइजर

राष्ट्रपति श्री महामदौ इस्सौफ़ ने मार्च 2018 में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के संस्थापक सम्मेलन में भाग लिया। 17-19 सितंबर 2018 ka राष्ट्रपति के विशेष सलाहकार की नई दिल्ली यात्रा के दौरान, 35.484 मिलियन अमेरिकी डॉलर की गोई अनुदान सहायता के साथ नीमी में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर (एमजीआईसीसी) की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। जल विज्ञान और स्वच्छता मंत्री ने 29 सितंबर -2 अक्टूबर 2018 से नई दिल्ली में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन में भाग लिया। नाइजर के ऊर्जा मंत्री ने 3 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली महासभा में भाग लिया। 2017-18 में नाइजर द्वारा आईटीईसी के अंतर्गत 160 में से 154 स्लॉटों, पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्स के लिए आईसीसीआर अफ्रीका स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत 8 में से 2 स्लॉट और अफ्रीकी अध्येताओं के भारत में पोस्ट-डॉक्टोरल रिसर्च के लिए 1 सीवी रमन इंटरनेशनल फेलोशिप का उपयोग किया गया था।

नाइजीरिया

वर्ष 2018 भारत और नाइजीरिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का वर्ष है क्योंकि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के साठ वर्ष पूरे हुए हैं। भारत ने नाइजीरिया की स्वतंत्रता से दो साल पहले नवंबर 1958 में लागोस में अपने राजनयिक घर की स्थापना की थी। अफ्रीका में सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, नाइजीरिया ने वर्ष के दौरान करीबी राजनीतिक और वाणिज्यिक संबंध बनाए रखे।

विश्व स्तर पर नाइजीरिया के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को चलाने के लिए पर्याप्त आर्थिक साझेदारी जारी है, और नाइजीरिया अफ्रीका में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। नाइजीरिया के साथ द्विपक्षीय व्यापार 2017-18 में 11.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया। इस साल के पहले छह महीनों में, द्विपक्षीय व्यापार 6.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुँच गया, जिसमें आयात में लगभग 3.5% और निर्यात में लगभग 20% वृद्धि हुई है। नाइजीरिया भारत की ऊर्जा सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कच्चे तेल का 5 वाँ सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। भारत की कच्चे तेल की वार्षिक जरूरत का लगभग 10% नाइजीरिया से आयात किया जाता है। दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच लगातार आदान-प्रदान के साथ दोनों देशों में जीवंत रक्षा संबंध हैं। भारत नाइजीरियाई लोगों के लिए एक प्रमुख स्वास्थ्य पर्यटन स्थल बना हुआ है, जबकि नाइजीरिया प्रबंधकीय और विशेषज्ञ स्तर के पदों में 50,000 से अधिक भारतीय नागरिकों के लिए रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है।

वर्ष में नाइजीरिया से तीन और भारत से दो मंत्रिस्तरीय यात्राएं हुईं। मार्च 2018 में नई दिल्ली में नाइजीरिया के बिजली, निर्माण और आवास और पर्यावरण राज्य मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) और सौर शिखर सम्मेलन के संस्थापक सम्मेलन में भाग लिया। अक्टूबर 2018 में नई दिल्ली में आयोजित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन (एमजीआईएससी) में नाइजीरिया के जल संसाधन मंत्री अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शामिल हुए। पूर्व विदेश मंत्री श्री एम. जे. अकबर और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री (सीआरएस) श्री सी. आर. चौधरी ने एक साथ द्विपक्षीय यात्रा पर नाइजीरिया का दौरा किया और अबूजा में 8 से 9 अक्टूबर 2018 को आयोजित सीआई-एक्जिमबैंक इंडिया-वेस्ट अफ्रीका रीजनल कॉन्क्लेव में भाग लिया था। कॉन्क्लेव में 300 से अधिक भारतीय और अफ्रीकी उद्योग के नेताओं और सीईओ ने भाग लिया, भारत और पंद्रह देशों के आर्थिक समुदाय के पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों (ईसीओडब्ल्यूएएस) के बीच आर्थिक साझेदारी को तीव्र और गहरा करने के लिए एक रोडमैप और बहु-आयामी कार्य योजना के रूप में इसका समापन हुआ। करीब 500 परियोजनाओं पर चर्चा की गई।

इस नवीकृत संबंध में पहली बार, जुलाई 2018 में नई दिल्ली स्थित विदेशी सेवा संस्थान (एफएसआई) में भारत द्वारा प्रस्तावित एक विशेष पाठ्यक्रम में 22 नाइजीरियाई राजनयिकों की भागीदारी देखी गई। अप्रैल 2018 में चेन्नई में आयोजित होने वाले डिफेंस एक्सपो में नाइजीरियाई वायु सेना और नाइजीरियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो (डीआरडीबी) के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया; मई 2018 में डीआरडीओ, भारत में रक्षा पर अध्यक्ष सीनेट समिति के नेतृत्व में छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा और जुलाई 2018 में नाइजीरियाई चीफ ऑफ नवल स्टाफ की भारत की यात्रा ने दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद रक्षा सहयोग को मजबूत किया।

आईएसए के संस्थापक सम्मेलन के दौरान, भारत ने दो सौर परियोजनाओं के लिए 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रियायती ऋण की घोषणा की। यह नाइजीरिया के लिए पहले से प्रस्तुत 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एलओसी के अलावा है, जिसमें से कडूना और क्रॉस रिवर में 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं।

आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत, नाइजीरियाई भारत में नागरिक असैनिक और रक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। वर्ष 2018-19 में नाइजीरिया को 200 नागरिक आईटीईसी स्लॉट और 115 रक्षा आईटीईसी स्लॉट की पेशकश की गई थी. भारतीय उच्चायुक्त और विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री की उपस्थिति में अक्टूबर 2018 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ उमरु मूसा यारदुआ विश्वविद्यालय में

नाइजीरिया में प्रथम आईसीसीआर संस्कृत चेयर की स्थापना की गई थी। सांस्कृतिक स्तर पर, 12 सदस्यीय हरियाणा लोक नृत्य समूह ने नवंबर 2018 में नाइजीरिया का दौरा किया और लागोस, अबूजा और कानो शहरों में प्रदर्शन किया। गांधी जी की 150वी जयंती के समारोहों के हिस्से के रूप में, मिशन ने नाइजीरियाई गायकों के एक समूह द्वारा नरसिंह मेहता द्वारा लिखे गए "वैष्णव जन तो" भजन के लिए व्यवस्था की।

मुंबई में आयोजित होने वाले 2019 ग्लोबल एविएशन समिट में भाग लेने के लिए नाइजीरियाई राज्य मंत्री ने 15 और 16 जनवरी 2019 को दौरा किया जहां द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते (बीएएसए) पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। अतिरिक्त सचिव रैंक के अधिकारी की अगुवाई में 5 वें संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक की अध्यक्षता रक्षा प्रतिनिधिमंडल ने 17-18 जनवरी को नई दिल्ली में की। नाइजीरियाई विदेश मंत्री ने 18-20 जनवरी 2019 को "जीवंत गुजरात अफ्रीका दिवस" में भाग लिया। नाइजीरियाई स्वास्थ्य मंत्री से 25-27 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य भागीदारी के चौथे शिखर सम्मेलन में भाग लेने और 27 फरवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य संगोष्ठी में भाग लेने की उम्मीद है।

कांगो गणराज्य

भारत सरकार की तीन क्रेडिट लाइनों के अंतर्गत कांगो गणराज्य के ब्रेज़ावेल और पॉइंट नायर में 89.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की शहरी परिवहन प्रणाली परियोजना; 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ग्रीनफील्ड 600 टन प्रति दिन (टीपीडी) रोटरी भट्ठा-आधारित सीमेंट प्लांट परियोजना; और 69.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना पर कार्यान्वयन की प्रक्रिया चल रही है। कार्य प्रगति पर है। गुजरात राज्य उर्वरक निगम (जीएसएफसी) कांगो गणराज्य में अमोनिया-यूरिया उर्वरक संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर रहा है। वर्ष 2018-19 के लिए आरओसी को प्रस्तावित किए गए 10 आईटीईसी स्लॉट में से अब तक सात का उपयोग किया जा चुका है।

रवांडा

भारत और रवांडा के बीच पहला विदेशी कार्यालय परामर्श 3 मई 2018 को किगाली में आयोजित किया गया था। रवांडा गणराज्य के राष्ट्रपति श्री पॉल कागमे के निमंत्रण पर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 23-24 जुलाई 2018 को रवांडा गणराज्य की राजकीय यात्रा की। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहली रवांडा यात्रा थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में रवांडा के राष्ट्रपति के साथ एक से एक वार्ता, द्विपक्षीय प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता, भारतीय समुदाय के साथ बातचीत और एक व्यावसायिक कार्यक्रम को संबोधित करना शामिल था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गिजोजी नरसंहार स्मारक भी गए और तुत्सी के खिलाफ 1994 के नरसंहार के पीड़ितों के स्मारक पर माल्यार्पण किया।. 24 जुलाई 2018 को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ''गिरींकप्रोग्राम'', एक गाय - एक परिवार की सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत किगली के बाहर रिवरू मॉडल गाँव में एक कार्यक्रम में भाग लिया और योजना के लिए भारत के एक योगदान के रूप में 2,00,000 अमेरिकी डॉलर मूल्य की 200 गायें उपहार में दीं। रक्षा सहयोग, द्विपक्षीय व्यापार, डेयरी सहयोग, चमड़ा सहयोग, सांस्कृतिक विनिमय, कृषि और पशु संसाधनों और पर छह समझौता ज्ञापनों; औद्योगिक पार्कों और कृषि परियोजना योजनाओं के विकास के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं में निम्नलिखित शामिल हैं- डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में एक टास्क फोर्स का गठन, जिसमें एक ई-लाइब्रेरी का प्रावधान, 1,00,000 पुस्तकों का उपहार देना और डिजिटलाइजेशन और शिक्षा की किताबों की ऑनलाइन पहुंच और संबंधित शिक्षा सामग्री के लिए सहायता प्रदान करना शामिल है, उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना, डेयरी उत्पादन और प्रसंस्करण के क्षेत्र में अल्पकालिक प्रशिक्षण के लिए पूरी तरह से वित्त पोषित पच्चीस स्लॉट, किगाली में गिज़ोजी नरसंहार स्मारक में 10,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान और रवांडा की प्रथम महिला द्वारा संचालित इमब्यूटो फाउंडेशन में बालिकाओं की शिक्षा के लिए 10,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान।

प्रधान मंत्री ने अपनी रवांडा यात्रा के दौरान रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे से मुलाकात की (23 जुलाई, 2018)

साओ टोम और प्रिंसिपे

साओ टोम और प्रिंसिपे (एसटीपी) के विदेश मामलों और समुदायों के मंत्री ने 7 और 8 सितंबर 2018 को नई दिल्ली का दौरा किया और विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के साथ बातचीत के अलावा, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में सहयोग पर फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किये।

सेनेगल

वर्ष के दौरान, भारत-सेनेगल संबंधों को और मजबूत किया गया। सेनेगल के पेट्रोलियम और ऊर्जा मंत्री ने 11 मार्च 2018 को नई दिल्ली में आईएसए संस्थापक सम्मेलन में भाग लिया। जलगति विज्ञान और स्वच्छता मंत्री ने 29 सितंबर से 2 अक्टूबर 2018 तक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन (एमजीआईएससी) में भाग लिया। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए भारत और सेनेगल के बीच द्विपक्षीय व्यापार पहली बार 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है और पिछले वर्ष की तुलना में 35.7% की मजबूत छलांग दर्ज करते हुए 1289.05 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंचा है। विभिन्न एलओसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में वर्ष के दौरान उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इनमें चावल आत्मनिर्भरता कार्यक्रम के लिए लिफ्ट सिंचाई के पहले चरण के लिए 62.95 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एलओसी; ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के दूसरे चरण के लिए 27.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर; सार्वजनिक परिवहन के लिए 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर और स्वास्थ्य सेवा के उन्नयन और पुनर्वास के लिए 24.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एलओसी शामिल था। एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट (एनईआईए) के अंतर्गत सेनेगल में टैंबाकौंडा-कोल्डा-ज़िगुइंचोर को जोड़ने वाली ट्रांसमिशन लाइन और सेनेगल में नेटवर्क के विस्तार और पुनर्वास के लिए 200 मिलियन का एलओसी का ऋण दिया। भारत ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से किए गए सेनेगल के राष्ट्रपति मिक्कीसॉल के अनुरोध का जवाब देते हुए, लीथियम आयन बैटरी वाले 250 ई-रिक्शा की आपूर्ति की।

सियरा लिओन

भारत और सिएरा लियोन आत्मीय और सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों हैं। 12 मई 2018 को फ्रीटाउन में नए राष्ट्रपति श्री जूलियस माडा बायो के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व उच्चायुक्त ने किया। सिएरा लियोन के स्वास्थ्य और स्वच्छता मंत्री 29 सितंबर -2 अक्टूबर 2018 से नई दिल्ली में आयोजित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन में शामिल हुए। वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने 8-9 अक्टूबर 2018 को नाइजीरिया के अबूजा में सीआईआई-एक्जिमबैंक इंडिया-वेस्ट अफ्रीका रीजनल कॉन्क्लेव के लिए दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 2016-17 के 105.94 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2016-18 में 117.68 अमेरिकी डॉलर मिलियन हो गया। आईटीईसी प्रशिक्षण कार्यक्रम सिएरा लियोन में लोकप्रिय हैं और 2017-18 में उनचालीस स्लॉटों का उपयोग किया गया था। अप्रैल-अक्टूबर 2018 की अवधि के दौरान, बेलीफूट कॉलेज, तिलोनिया में ग्रामीण सौर विद्युतीकरण में प्रशिक्षित दस सोलर मैमों सहित इकतीस आईटीईसी स्लॉटों का उपयोग किया गया था। हैदराबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के आईटी विंग के राष्ट्रीय डिजिटल अपराध संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र (एनडीसीआरटीसी) के पांच विशेषज्ञों ने 1-13 अप्रैल 2018 से सिएरा लियोन पुलिस के साइबर अपराध ब्यूरो को प्रशिक्षण प्रदान किया। 23 जून 2018 को फ्रीटाउन में चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया।. बेसिक और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ 10-14 दिसंबर 2018 को नई दिल्ली में मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य पर पार्टनर्स फोरम 2018 में भाग लिया।

दक्षिण अफ्रीका

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25-27 जुलाई 2018 को 10वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका की आधिकारिक यात्रा की। यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए: दक्षिण अफ्रीका में कारीगर कौशल के लिए गांधी-मंडेला विशेषज्ञता केंद्र की स्थापना; भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी (सानसा) के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में सहयोग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और कृषि अनुसंधान और शिक्षा में सहयोग दक्षिण अफ्रीकी कृषि अनुसंधान परिषद (सार्क)। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किए।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 3-7 जून 2018 तक दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 4 जून 2018 को प्रिटोरिया में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक और आईबीएसए विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने राष्ट्रपति श्री सिरिल रामफोसा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री सुश्री लिंडवे सिसुलु और ग्रामीण विकास और भूमि सुधार मंत्री सुश्री माइट नोकाना-मशाबेन के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने भारतीय प्रवासियों से भी बातचीत की, 1904 में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित फीनिक्स बस्ती का और इनंडा के रामकृष्ण अबालंडी होम दौरा किया। पीटरमैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी के साथ हुई "घटना" के 125 वें वर्ष के उपलक्ष्य में, दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री लुवेली लैंडर्स के साथ विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने पीटरमैरिट्ज़बर्ग रेलवे स्टेशन पर 10-15 मिनट की एक प्रतीकात्मक ट्रेन की सवारी की। स्टेशन और महात्मा गांधी की एक दो-तरफा बस्ट और एक डिजिटल संग्रहालय का अनावरण किया। इस अवसर पर सत्याग्रह, स्मारक सिक्के और स्मारक डाक टिकटों की 125वीं वर्षगांठ पर एएनसी स्टालवार्ट ओलिवर रेजिनाल्ड टैम्बो और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर एक कॉफी टेबल बुक जारी की गई। वाणिज्य और उद्योग और भारत के नागर विमानन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने 29-30 अप्रैल 2018 को जोहान्सबर्ग के सैंडटन में आयोजित भारत-दक्षिण अफ्रीका व्यापार शिखर सम्मेलन(आईएसएबीएस) 2018 के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। व्यापार और उद्योग मंत्री डॉ. रॉब डेविस, श्री प्रवीण गोरधन, सार्वजनिक

प्रधान मंत्री और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा भारत-दक्षिण अफ्रीका संस्मारक डाक टिकट जारी करते हुए (26 जुलाई, 2018)

उद्यम मंत्री और लघु व्यवसाय उद्यम मंत्री, सुश्री लिंडवे ज़ुलु ने शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीकी सरकार का प्रतिनिधित्व किया। गौतेंग प्रांत के प्रमुख श्री डेविड मखुरा ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। शिखर सम्मेलन के दौरान सीआईएम और दक्षिण अफ्रीकी व्यापार और उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री के बीच द्विपक्षीय बैठकें हुईं। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय व्यवसायों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को उजागर करने वाला एक श्वेत पत्र जारी किया गया था और निवेश भारत और निवेश दक्षिण अफ्रीका के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। सम्मेलन के दौरान विख्यात प्रवासी पत्रकार फकीर हसन की द रेड फोर्ट डिक्लेरेशन - द लिगेसी 20 ईयर्स शीर्षक एक किताब लोकार्पित की गई। इंडिया-साउथ अफ्रीका व्यापार शिखर सम्मेलन में 12 और 13 नवंबर, 2018 को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में संभावित दक्षिण अफ्रीकी निवेशकों को निवेश और व्यापार के अनुकूल न्यू इंडिया के साथ परिचित करने के लिए जून 2018 को सैंडटन कन्वेंशन सेंटर, जोहान्सबर्ग में एक इन्वेस्ट इन इंडिया बिजनेस फोरम (आईआईबीएफ) आयोजित किया गया था। वाइस एडमिरल श्रीकांत, कमांडेंट एनडीसी की अध्यक्षता में नेशनल डिफेंस कॉलेज के प्रतिनिधियों ने, 20-27 मई 2018 से पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया। आईएनएस तारकेश और कोलकाता ने 1-13 अक्टूबर 2018 से केपटाउन का दौरा किया और छठे आईबीएसए समुद्री अभ्यास (आईबीएसएएमएआर) में भाग लिया। जुलाई 2018 में, भारत सरकार, दक्षिण अफ्रीका सरकार और डेनियल एसओसी लिमिटेड के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, जिसके बाद भारत सरकार ने डेनियल पर लगाए गए प्रशासनिक प्रतिबंध हटा दिए थे। इसके बाद प्रिटोरिया में आयोजित अफ्रीका एयरोस्पेस एंड डिफेंस एक्जिबिशन (एएडी) 2018 में भाग लेने के लिए 16-20 सितंबर 2018 को डीजी अधिग्रहण के नेतृत्व में एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की दक्षिण अफ्रीका यात्रा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार और डेनियल एसओसी लिमिटेड के साथ भी विचार-विमर्श किया।

दक्षिण अफ्रीकी नौसेना के प्रमुख, वाइस एडमिरल एमएस हलोंगेन ने 12 से 16 नवंबर, 2018 तक भारत का दौरा किया और हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की 10वीं वर्षगांठ समारोह के भाग के रूप में आयोजित स्मारक सेमिनार में भाग लिया। उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण मंत्री सुश्री नलदेई पंडोर की उपस्थिति में 8 अक्टूबर 2018 को प्रिटोरिया में गांधी-मंडेला सेंटर ऑफ़ स्पेशलाइज़ेशन ऑफ़ आर्टिसन स्किल्स का सॉफ्ट लॉन्च हुआ। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गईं और 24-27 जून 2018 से जोहान्सबर्ग में अफ्रीका बिग सेवन/साइटेक्स और अन्य बैठकों में शामिल हुईं। सीईओ के फोरम की चौथी बैठक 26 अप्रैल 2018 को 29-30 अप्रैल 2018 से भारत-दक्षिण अफ्रीका व्यापार शिखर सम्मेलन के मार्जिन में

सैंडटन, जोहान्सबर्ग में आयोजित की गई थी। आईटीईसी के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में, दक्षिण अफ्रीका को सत्तर स्लॉट आवंटित किए गए थे, जिनमें से अब तक पंद्रह स्लॉट का उपयोग किया गया है। आईसीसीआर ने 2018-19 में दक्षिण अफ्रीका को कुल पचास स्लॉट दिए, जिसमें से तेईस का उपयोग किया गया।

स्वाज़ीलैंड

राजा मस्वाती-तृतीय (केएम-तृतीय) के निमंत्रण पर, राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने 9 और 10 अप्रैल, 2018 को किंगडम ऑफ एस्वातिनी का राजकीय दौरा किया, जो एक भारतीय राष्ट्रपति द्वारा एस्वातिनी की पहली यात्रा बन गई। उनके साथ प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद, सड़क परिवहन, राजमार्ग और शिपिंग, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया और दो संसद सदस्य, डॉ. पोन्नुसामी वेणुगोपाल और डॉ. यशवंत सिंह तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी थे। एक विशेष समारोह में, राजा ने राष्ट्रपति को एस्वातिनी के सर्वोच्च सम्मान, 'ऑर्डर ऑफ द लायन' को सम्मानित किया और उन्हें संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करने का विशेष सम्मान दिया गया। राष्ट्रपति द्वारा की गई घोषणाओं में निम्नलिखित शामिल हैं - नए संसद भवन के निर्माण के लिए सहायता, 'आपदा रिकवरी साइट' की स्थापना के लिए 10.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन, सिंचाई के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 4,00,000 अमेरिकी डॉलर का अनुदान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी (एनडीएमए) के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नकद अनुदान और 700 टन चावल और 300 टन बीन्स का दान, दवाओं की आपूर्ति और इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड फाइनेंस (आईएनजीएएफ), नई दिल्ली में पचास स्वाज़ी अधिकारियों के लिए सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में एक पूर्णतया भारतीय वित्त पोषित विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। स्वास्थ्य और वीजा छूट पर दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत के महावाणिज्य दूतावास, जोहान्सबर्ग के सहयोग से 21 जून 2018 को सोवतो में चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया गया।

राष्टपति स्वाजीलैंड पहुँचने पर स्वागत समारोह के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर की निगरानी करते हुए (09 अप्रैल, 2018)

तंजानिया

व्यापार, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत-तंजानिया संयुक्त आयोग ने विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज और तंजानिया के विदेश और पूर्वी अफ्रीकी सहयोग मंत्री डॉ ऑगस्टीन पी महिगा के नेतृत्व में 15 और 16 अक्टूबर,

2018 को अपना 9वां सत्र आयोजित किया। संयुक्त आयोग के दौरान, दोनों देशों ने भारत के विदेशी सेवा संस्थान और सेंटर फॉर फॉरेन रिलेशंस, डार एस सलाम के बीच सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास सहयोग और तंजानिया के औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास संगठनों के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया। भारत के साथ संबंधों को लेकर तंजानिया के दृष्टिकोण पर भारतीय मंत्री ने विश्व मामलों की नई परिषद, नई दिल्ली में अधिकारियों और विद्वानों को संबोधित किया और समुद्री संपर्क और विकास के आदान-प्रदान के लिए राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन का दौरा किया।

विदेश मंत्री और तंजानिया के विदेश तथा पूर्वी अफ्रीकी सहयोग मंत्री ऑगस्टीन पी. माहिगा नई दिल्ली में करारों का आदान-प्रदान करते हुए (16 अक्टूबर, 2018)

टोगो

नई दिल्ली में 11 मार्च 2018 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संस्थापक सम्मेलन में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति फुरन ग्नसिंगबे की यात्रा ने भारत और टोगो के बीच के सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत किया। स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा मंत्री ने 16 मई 2018 को मुंबई में चौथे भारत-अफ्रीका स्वास्थ्य मंच में भाग लिया। जल स्वच्छता और ग्राम जल विज्ञान मंत्री ने 29 सितंबर-2 अक्टूबर 2018 से नई दिल्ली में आयोजित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन में भाग लेने के लिए पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। खान और ऊर्जा मंत्री ने नई दिल्ली में 2-5 अक्टूबर 2018 से आयोजित आईएसए की पहली महासभा में भाग लेने के लिए तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। टोगो के वरिष्ठ अधिकारियों ने 8-9 अक्टूबर 2018 से नाइजीरिया के अबूजा में आयोजित सीआई-एक्जिमबैंक इंडिया-वेस्ट अफ्रीका रीजनल कॉन्क्लेव में भाग लिया। भारत टोगो के शीर्ष व्यापारिक भागीदारों में से एक है। दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 2016-17 में 454.12 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2017-2018 में 572.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

युगांडा

युगांडा के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2018 में युगांडा की राजकीय यात्रा की। उन्होंने युगांडा के राष्ट्रपति के साथ एक-से-एक विचार-विमर्श किया जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई और

उनके सम्मान में एक राजकीय भोज आयोजित किया गया। उन्होंने युगांडा में भारतीय समुदाय के 10000 से अधिक सदस्यों की एक बड़ी सभा को संबोधित किया और सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और युगांडा के राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से एक व्यापार कार्यक्रम को संबोधित किया। पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने युगांडा की संसद को संबोधित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में अफ्रीका के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया और महाद्वीप के साथ जुड़ने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, आधिकारिक और राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकता से छूट, सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम और युगांडा में क्षेत्रीय सामग्री प्रयोगशाला की स्थापना पर समझौता ज्ञापनों/समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, बिजली लाइनों के निर्माण के लिए 141 मिलियन अमेरिकी डॉलर और कृषि और डेयरी उत्पादन के लिए 64 मिलियन अमेरिकी डॉलर के दो ऋणों की पेशकश की। यह भी तय किया गया कि भारत जिंजा में महात्मा गांधी सम्मेलन/ विरासत केंद्र स्थापित करेगा, यहां महात्मा गांधी की राख विसर्जित की गई थी; विभिन्न भारतीय सेना प्रशिक्षण संस्थानों में युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्स के अतिरिक्त प्रशिक्षण की भी घोषणा की गई। इसके अलावा, वर्तमान में युगांडा की अध्यक्षता में पूर्वी अफ्रीकी समुदाय (ईएसी) के लिए वित्तीय सहायता भी घोषित की गई थी। भारत ने युगांडा पीपुल्स डिफेंस फोर्सेज और युगांडा सरकार द्वारा नागरिक उपयोग के लिए वाहनों; युगांडा कैंसर संस्थान को भाभाट्रॉन कैंसर थेरेपी मशीन; युगांडा के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए एनसीईआरटी की किताबें; और कृषि के विकास में मदद करने के लिए सौर ऊर्जा सिंचाई पंप के दान की भी घोषणा की। भारत और युगांडा के बीच पहला विदेशी कार्यालय परामर्श अप्रैल 2018 में कंपाला में आयोजित किया गया था।

नेशनल डिफेंस कॉलेज, नई दिल्ली के 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 20-26 मई 2018 को युगांडा का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने युगांडा के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री से भेंट की और विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। इसने वरिष्ठ कमांड और स्टाफ कॉलेज, किमका और वायु सेना मुख्यालय के साथ भी बातचीत की।

भारत सरकार की आटीईसी पहल के अंतर्गत, युगांडा को वर्ष 2018-19 के लिए 125 प्रशिक्षण स्लॉट की पेशकश की गई थी, जिसमें से आज तक 94 स्लॉट्स का उपयोग किया गया है। युगांडा को भारतीय रक्षा संस्थानों में बाईस वायु सेना प्रशिक्षण स्लॉट की भी पेशकश की गई थी। विभिन्न क्षेत्रों में आईएएफएस-III प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए युगांडा से आठ लोग अब तक भारत की यात्रा कर चुके हैं। युगांडा के एक नागरिक ने 2018-19 में विशेष कृषि फैलोशिप का लाभ उठाया है। 'स्टडी इन इंडिया' अभियान के अंतर्गत, युगांडा के कुल सात छात्रों ने योजना के अंतर्गत

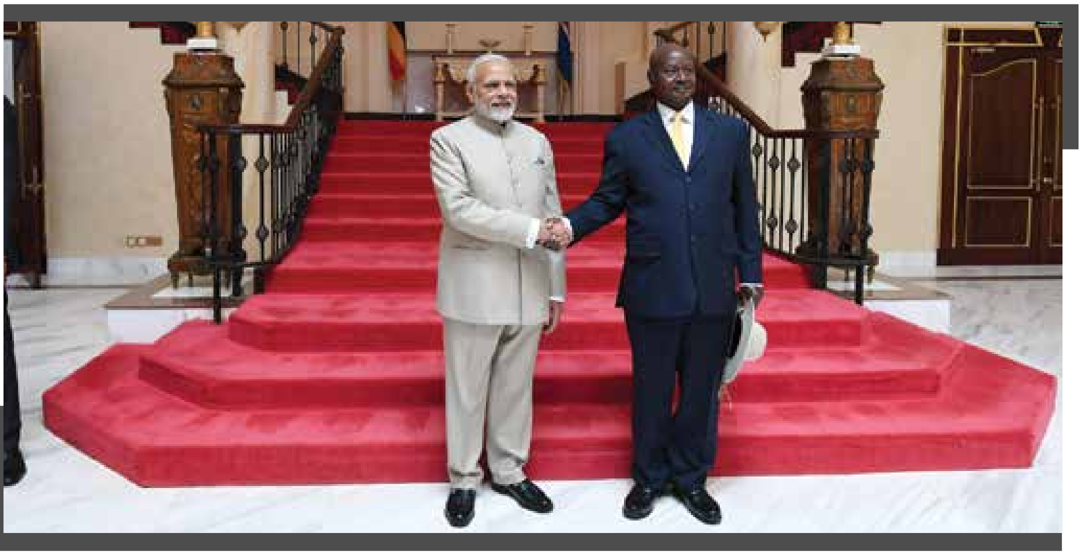

प्रधान मंत्री युगांडा की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान वहाँ के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी से मुलाकात करते हुए (24 जुलाई, 2018)

दी जाने वाली छात्रवृत्ति का लाभ उठाया है। प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम (एसपीडीसी) योजना के अंतर्गत युगांडा के एक छात्र का चयन किया गया है और वर्तमान में वह भारत में शिक्षा प्राप्त कर रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को कोलोआ एयरस्ट्रिप, कंपाला के ऐतिहासिक “इंडिपेंडेंस ग्राउंड” में मनाया गया, जहाँ सभी उम्र के 3000 से अधिक योग प्रेमियों ने भाग लिया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए, मिशन ने 2 अक्टूबर 2018 को एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में एक गांधीवादी और अफ्रीका में सबसे कम उम्र के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, श्री विक्टर ओचेन भी शामिल थे। उच्चायुक्त ने भी जिन्जा का दौरा किया और नदी के उद्गम स्थल पर स्थित गांधी मैदान में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने जिन्जा में एक शांति मार्च में भी भाग लिया जिसमें कई युगांडा और भारतीयों ने भाग लिया। एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया ने भारत से वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के ऋण का विस्तार करने के लिए युगांडा डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड (यूडीबीएल) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यूडीबीएल द्वारा युगांडा के एसएमई को मध्यम और दीर्घकालिक विकास वित्त प्रदान करने के लिए इस क्रेडिट सुविधा का उपयोग किया जाएगा। युगांडा की एक सांस्कृतिक मंडली ने भारत सरकार द्वारा आमंत्रण और वित्त पोषण पर मई 2018 में दिल्ली में अफ्रीका महोत्सव में भाग लिया। युगांडा के राष्ट्रपति जनरल योवेरी कागुता मुसेवेनी ने 23 नवंबर, 2018 को स्टेट हाउस, एंतेबे में दिवाली समारोह की मेजबानी की, जिसमें भारतीय समुदाय के प्रमुख सदस्यों ने भाग लिया। उच्चायोग ने भारत के राज्यों के समृद्ध इतिहास, संस्कृति, परंपराओं, खानपान और पर्यटन की संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना के राज्य दिवस (राज्य दिवस) की एक श्रृंखला का आयोजन किया।

जाम्बिया

भारत और ज़ाम्बिया का द्विपक्षीय व्यापार 2017-2018 (1388.29 अमेरिकी डॉलर) के दौरान पहली बार 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है।

जाम्बिया के राष्ट्रपति श्री एडगर चगवालुंग के निमंत्रण पर, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी और रासायनिक और उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख एल. मंडाविया, दो संसद सदस्य और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ जाम्बिया गए। 10-12 अप्रैल 2018 से जाम्बिया की राजकीय यात्रा का भुगतान किया। दोहरे कराधान से बचाव, उद्यमशीलता सहकारी विकास केंद्र की स्थापना, राजनयिक पासपोर्ट पर वीजा की आवश्यकता में छूट और न्यायिक सहयोग पर चार समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर के निर्माण में भारत की सहायता और दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के उपहार के साथ-साथ महात्मा गांधी प्राथमिक विद्यालय के नवीकरण के लिए 100,000 डॉलर के अनुदान की भी घोषणा की। भारत के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति एडगर चगवालुंग द्वारा संयुक्त रूप से लुसाका रोड्स डी-कंजेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। ऊर्जा मंत्री श्री मैथ्यू मखुवा 10-12 अप्रैल, 2018 से नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच (आईईएफ) की

राष्ट्रपति जाम्बिया गणराज्य के राष्ट्रपति श्री एडगर चागवा लुंगू से स्टेट हाउस, जाम्बिया गणराज्य में मुलाकात करते हुए (11 अप्रैल, 2018)

16वीं अंतर्राष्ट्रीय मंत्रिस्तरीय बैठक में शामिल हुए। जल विकास और स्वच्छता मंत्री डॉ. डेनिस मुसुकु वानचिंग 29 सितंबर से 7 अक्टूबर 2018 तक महात्मा गांधी स्वच्छता सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली आए थे। जाम्बिया ने

अप्रैल 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। मिशन ने ज़ांबियाई छात्रों को स्व-वित्तपोषण के आधार पर उच्च अध्ययन करने के लिए लगभग 150 वीजा जारी किए। अब तक भारत में लगभग 3500 असैनिक जाम्बिया विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षित हो चुके हैं। जाम्बिया में 650 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रो की स्थापना कार्यान्वयन के अग्रिम चरण में है, भारत सरकार की एलओसी द्वारा 68 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि का समर्थन दिया गया है।

ज़िम्बाब्वे

उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने 2-4 नवंबर, 2018 से जिम्बाब्वे का दौरा किया। पिछले दो वर्षों में भारत की जिम्बाब्वे के लिए यह पहली उच्च स्तरीय यात्रा थी। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति श्री ई. डी. मन्नगग्वा से सौजन्यता भेंट की और जिम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति श्री केम्बो मोहदी के नेतृत्व में जिम्बाब्वे के प्रतिनिधिमंडल के साथ द्विपक्षीय चर्चा की। यात्रा के दौरान, पांच समझौता ज्ञापनों और आईसीटी पर एक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के उपराष्ट्रपतियों ने संयुक्त रूप से भारत-जिम्बाब्वे बिजनेस फोरम को संबोधित किया और सात बी2बी समझौता ज्ञापनों/समझौतों पर हस्ताक्षर किए। उपराष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। यात्रा के दौरान, उपराष्ट्रपति ने हवांगे थर्मल पावर स्टेशन के उन्नयन के लिए 310 मिलियन अमेरिकी डॉलर एलओसी की घोषणा की, बुलेवेओ थर्मल पावर प्लांट के पुनर्वास के लिए अतिरिक्त 23 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एलओसी और डेका पंपिंग और नदी जल उपयोग प्रणाली के लिए अतिरिक्त 19.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट; महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए अनुदान, इंडो-जिम टेक्नोलॉजी सेंटर के उन्नयन के लिए 2.93 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान और 10 भारतीय निर्मित एम्बुलेंस, जीवन रक्षक दवाओं का उपहार और पांच विशेष क्षेत्रों में विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति की घोषणा की गई।

जिम्बाब्वे के भूमि, कृषि, जल, जलवायु और ग्रामीण निपटान उप-मंत्री श्री वेंगेलिस पीटर हरितातोस 29 सितंबर-2 अक्टूबर 2018 से महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए और ऊर्जा और ऊर्जा विकास मंत्री, मैग्ना मुडियवा ने अक्टूबर 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली महासभा में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। उद्योग और वाणिज्य मंत्री श्री राज मोदी, 23 और 24 नवंबर, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित इंडिया गोल्ड एंड ज्वैलरी समिट के दूसरे संस्करण में भाग लेने के लिए भारत आए।

उप राष्ट्रपति जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति ई.डी. मनानगागवा से हरारे में मुलाकात करते हुए (03 नवंबर, 2018)

जिम्बाब्वे सरकार के आमंत्रण पर, एक आठ सदस्यीय चुनाव प्रेक्षक मिशन ने जुलाई 2018 में 30 जुलाई 2018 को होने वाले चुनावों का निरीक्षण करने के लिए जिम्बाब्वे का दौरा किया।

सीआईआई के नेतृत्व में एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने 24-28 सितंबर 2018 से जिम्बाब्वे का दौरा किया और जिम्बाब्वे मंत्रालय के सूचना संचार प्रौद्योगिकी और कूरियर सेवाओं और जिम्बाब्वे-भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर आयोजित भारत-जिम्बाब्वे आईसीटी सम्मेलन 'जिम्बाब्वे-इंडिया: ब्रिजिंग द डिजिटल गैप' में भाग लिया। उसी प्रतिनिधिमंडल ने 26-28 सितंबर 2018 से तुलावे में आयोजित सीजेडआई वार्षिक कांग्रेस और अंतर्राष्ट्रीय निवेश फोरम में भी भाग लिया।

इस अवधि के दौरान 125 आईटीईसी स्लॉट, पांच रक्षा आईटीईसी स्लॉट और नौ आईसीसीआर छात्रवृत्ति का उपयोग किया गया है। मिशन द्वारा आयोजित चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आठ स्थानों -मटारे (2 जून 2018), रुसेप (3 जून 2018), क्वेके (9 जून 2018), जीवरू (10 जून 2018), विक्टोरिया फॉल्स (16 जून 2018), हरारे (17 जून 2018), बुलावायो (23 जून 2018) और जिम्बाब्वे के यूएनडीपी में मनाया गया।

सितंबर 2018 में दूतावास द्वारा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए 10 दिनों के 'इंडिया इन सनशाइन सिटी' उत्सव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया था। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के जश्न के हिस्से के रूप में, मिशन ने युवा, खेल, कला और मनोरंजन, खेल और मनोरंजन आयोग, जिम्बाब्वे के राष्ट्रीय एथलेटिक्स एसोसिएशन और हिंदू सोसायटी के सहयोग 7 अक्टूबर 2018 को 'शांति और सद्भाव के लिए एक महात्मा गांधी दौड़' का आयोजन किया।

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन संस्थापना सम्मेलन की सामूहिक तस्वीर (11 मार्च, 2018)

7

यूरोप और यूरोपीय संघ

पश्चिमी यूरोप

अंडोरा

भारत और अंडोरा की रियासत के बीच संबंध सौहार्द और मैत्रीपूर्ण रहे। इस्पात राज्य मंत्री श्री विष्णु देव साई, अप्रैल 2018 में अंडोरा का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री बने और अंडोरा की विदेश मंत्री सुश्री मारिया उबाख से मिले तथा बहुपक्षीय मुद्दों में द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने अंडोरा में रहने वाले भारतीय समुदाय से भी भेंट की। मंत्री ने यात्रा के दौरान हुई सहमति के अनुसार, अंडोरा के एक वरिष्ठ राजनयिक ने नई दिल्ली स्थित विदेश सेवा संस्थान में एशिया-यूरोप (एएसईएम) राजनयिकों के लिए चौथे विशेष पाठ्यक्रम में भाग लिया।

बेल्जियम

सितंबर 1947 में स्वतंत्र भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय देशों में से एक बेल्जियम और भारत के संबंधों को वर्ष में होने वाले उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान द्वारा चिह्नित किया गया था। भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू 18-19 अक्टूबर2018 को यूरोपीय संघ द्वारा आयोजित 12वीं एशिया-यूरोप बैठक (एएसईएम) के लिए ब्रुसेल्स की यात्रा पर गए। उन्होंने बेल्जियम के राजा से भेंट की और उत्कृष्ट द्विपक्षीय

सहयोग तथा बेल्जियम और भारत के बीच साझा हितों के समकालीन मुद्दों पर चर्चा की।

इससे पहले, विदेश मंत्री (ईएएम) श्रीमती सुषमा स्वराज ने 20 से 22 जून, 2018 के दौरान बेल्जियम का दौरा किया था और श्री डिडिएर रेयंडर्स, उप प्रधानमंत्री और बेल्जियम के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और भारत-बेल्जियम के बीच चल रहे द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की।. नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएनसी) के सुधारों, विकास सहयोग, आतंकवाद और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने प्रतिष्ठित ललित कला केंद्र (बोजर) में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की।

भारत-बेल्जियम उद्घाटन विदेश कार्यालय परामर्श ब्रसेल्स में 2 मई 2018 को श्रीमती रूचि घनश्याम, सचिव (पश्चिम) और बेल्जियम के संघीय लोक सेवा विदेश मामलों, विदेश व्यापार और विकास सहयोग के महासचिव श्री डर्क अचटेन के बीच हुआ। दोनों पक्षों ने 2017 में राजा और रानी की बेल्जियम की राजकीय यात्रा पर अनुवर्ती कार्रवाई सहित पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा की, पारस्परिक कानूनी सहायता संधि, राजनयिक और अधिकारियों के लिए वीजा छूट समझौता, भारत-बेल्जियम आर्थिक और व्यापार संबंध और क्षेत्रीय महत्व के अन्य मुद्दों पर बातचीत की।

पारंपरिक रूप से व्यापार और निवेश भारत-बेल्जियम द्विपक्षीय संबंधों का केंद्रीय स्तंभ रहा है। भारत, बेल्जियम का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य और यूरोपीय संघ के बाहर तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। हीरों का व्यापार द्विपक्षीय व्यापार पर हावी है जो 2017-18 के दौरान 12.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अप्रैल से सितंबर 2018 की अवधि के लिए व्यापार पहले ही 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है।. अप्रैल 2000 से जून 2018 की अवधि

के लिए भारत में बेल्जियम द्वारा समेकित एफडीआई 1.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

वर्ष 1997 में स्थापित भारत-बेल्जियम-लक्ज़मबर्ग-ईयू संयुक्त आयोग (भारत-बीएलईयू जेसीएम) आर्थिक और वाणिज्यिक मुद्दों का मुख्य मंच है। भारत-बीएलईयू संयुक्त आयोग की बैठक (जेसीएम) की मध्यावधि समीक्षा बैठक 3 मई 2018 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। पिछले वर्षों की तरह, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) ने 24-26 अप्रैल, 2018 को ब्रसेल्स में आयोजित ग्लोबल सीफूड एक्सपो में भाग लिया, जिसमें भारत के समुद्री भोजन के तीस निर्यातक शामिल थे। कृषि मंत्री डॉ.प्रेम कुमार के नेतृत्व में बिहार के एक प्रतिनिधिमंडल ने केले की रोग प्रतिरोधी किस्मों की संभावित सोर्सिंग पर चर्चा करने के लिए 15-17 अप्रैल 2018 को बेल्जियम का दौरा किया।इस बीमारी के नियंत्रण के लिए यह दौरा नीतिगत विकास में भी उपयोगी था।

फ्रांस

भारत और फ्रांस ने 1998 में स्थापित अपनी रणनीतिक साझेदारी के बीस वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह संबंध एक करीबी और बढ़ते द्विपक्षीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों के अभिसरण द्वारा चिह्नित है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग, अंतरिक्ष सहयोग और असैनिक परमाणु सहयोग के क्षेत्र सामरिक भागीदारी के प्रमुख आधार हैं। सहयोग के इन पारंपरिक क्षेत्रों के अलावा, भारत और फ्रांस हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) सहित जलवायु परिवर्तन और अन्य स्थायी विकास और विकास सहयोग के नए क्षेत्रों में तेजी से लगे हुए हैं।

भारत और फ्रांस में कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक रूप से अभिसरण है। फ्रांस ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और संयुक्त राष्ट्र के सुधारों के लिए भारत के दावे का समर्थन करना जारी रखा है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (एमटीसीआर), वासेनार व्यवस्था (डब्ल्यूए) और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप (एजी) के लिए भारत की पहुँच में फ्रांस का समर्थन महत्वपूर्ण था, जबकि फ्रांस ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी) के लिए भारत के दावे का समर्थन करना जारी रखा है।

आर्थिक क्षेत्र में, फ्रांसीसी व्यापार और उद्योग, इसकी पूंजी और प्रौद्योगिकियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के विकास लक्ष्यों के साथ संबंध बनाए हैं। लोगों के बीच संपर्क बढ़ने के साथ जीवंत द्विपक्षीय सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंध मौजूद हैं। महानगरीय फ्रांस और उसके विदेशी विभागों/क्षेत्रों में भारतीय प्रवासियों की एक बड़ी उपस्थिति है।

उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने विश्व युद्ध-I आर्मिस्टिस शताब्दी के स्मारक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया और पेरिस में 11 नवंबर 2018 को उद्घाटन पेरिस शांति मंच में भी भाग लिया। उन्होंने 10 नवंबर 2018 को विलर्स गुइस्लैन में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के स्मारक का उद्घाटन किया।

विदेश मंत्री (ईएएम) श्रीमती सुषमा स्वराज ने 18 और 19 जून 2018 को पेरिस का दौरा किया और अपने समकक्ष, फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री श्री जीन-यवेस ले ड्रियन के साथ बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री (ईएएम) श्रीमती सुषमा स्वराज ने 18 जून 2018 को फ्रांसीसी राष्ट्रपति से भेंट की। बाद में, उन्होंने पेरिस में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र के नामकरण समारोह में भाग लिया जिसे 'विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय केंद्र' का नाम दिया गया है और छात्रों और भारतीय प्रवासियों से बातचीत की। उनकी यात्रा के दौरान पूर्व-ऐतिहासिक गुफाओं पर सहयोग के लिए एक द्विपक्षीय आशय पत्र (एलओएल) का भी आदान-प्रदान किया गया था।

रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण अपने समकक्ष, सशस्त्र बलों के लिए फ्रांस की मंत्री सुश्री फ्लोरेंस पार्ली के साथ पहली द्विपक्षीय मंत्री स्तरीय वार्षिक रक्षा वार्ता के लिए 11 और 12 अक्टूबर, 2018 को पेरिस गईं। यात्रा के दौरान, रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने फ्रांस के प्रधानमंत्री श्री एडुअर्ड फिलिप से भी भेंट की, फ्रेंच मिलिट्री कॉलेज के इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक रिसर्च (आईआरएसईएम) में एक भाषण दिया और प्रमुख फ्रांसीसी रक्षा उद्योग के प्रमुखों के साथ बातचीत भी की।

अन्य मंत्रिस्तरीय दौरों में सेलोन इंटरनेशनल डी एल अग्रिकल्चर (एसआईएएल) एग्रो-फेयर के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्री (अक्टूबर2018) श्रीमती हरसिमरत कौर

राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन का नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य स्वागत समारोह में स्वागत करते हुए (10 मार्च, 2018)

बादल की यात्रा; वाणिज्य, उद्योग और नागरिक उड्डयन (मई-जून 2018) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) मंत्री सम्मेलन के लिए श्री सुरेश प्रभु; और पेरिस में 'आतंक के लिए कोई पैसा नहीं' बहुपक्षीय सम्मेलन के लिए पूर्व राज्य मंत्री (एमओएस) श्री एम. जे. अकबर (25 और 26 अप्रैल 2018) की यात्रा शामिल है।) फ्रांस की ओर से, हाल ही में भारत की मंत्री स्तरीय यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (अक्टूबर 2018) की पहली महासभा के लिए पारिस्थितिक और संक्रमण राज्य मंत्री की सचिव सुश्री ब्रुनेपोरसन की यात्रा का उल्लेख किया जा सकता है।

भारत और फ्रांस कई नियमित संस्थागत संवाद तंत्र को साझा करते हैं। भारत-फ्रांस सामरिक वार्ता दोनों पक्षों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (एनएसए) के बीच होती है। आखिरी रणनीतिक वार्ता पेरिस में 19 जुलाई 2018 को श्री अजीत डोवाल, एनएसए और फ्रांसीसी राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार श्री फिलिप एटिने के बीच आयोजित की गई थी। विदेश सचिव श्री विजय गोखले ने 18 जून 2018 को पेरिस में फ्रांसीसी विदेश विभाग के महासचिव, श्री मौरिस गौरल्ड्ट-मोंटगिन के साथ विचार-विमर्श किया। 14 जून 2018 को पेरिस में समुद्री सहयोग पर तीसरा द्विपक्षीय संवाद उप-एनएसए, श्री राजिंदर खन्ना और राजदूत ल्यूक हॉलडे के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जो हिंद महासागर में क्षेत्रीय सहयोग के लिए फ्रांस के राजदूत और वाइस एडमिरल हेव बोनावेंचर, कार्यवाहक महानिदेशक (डीजी) हैं। पिछली बार मई 2018 में इसे नई दिल्ली में समुद्री सुरक्षा समन्वयक, सशस्त्र बलों के फ्रांसीसी मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त सचिव [संयुक्त सचिव (संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक)/ संयुक्त सचिव (संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक), विदेश मंत्रालय (एमईए)] के सह-नेतृत्व में आयोजित किया गया था।

फ्रांसीसी राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रों की भारत (मार्च 2018) की यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने मंत्रिस्तरीय स्तर पर एक वार्षिक रक्षा वार्ता बनाने का निर्णय लिया, जिसमें से पहली वार्ता अक्टूबर 2018 में आयोजित की गई थी। नियमित द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण दो चरणों में मार्च-मई 2018 के दौरान गोवा में और रीयूनियन द्वीप, फ्रांस में हुआ। रक्षा संबंधी प्रमुख परियोजनाओं में राफेल विमान और पी-75 स्कॉर्पीयन परियोजना की खरीद शामिल है।

नागरिक अंतरिक्ष के क्षेत्र में ऐतिहासिक संबंधों का निर्माण के लिए भारत और फ्रांस दोनों ने फ्रांस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा (मार्च 2018) के दौरान "अंतरिक्ष सहयोग के लिए संयुक्त विजन" जारी किया। पहचान की गई परियोजनाओं के संबंध में कार्यान्वयन चल रहा है। संयुक्त रूप से विकसित मेघा-ट्रोपिक्स उपग्रह जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर बादलों और पानी के वाष्प का निरीक्षण करता है, अच्छा स्वास्थ्य और मूल्यवान वैज्ञानिक डेटा प्रदान करता है। एक संयुक्त के-बैंड प्रसार प्रयोग भी कार्यान्वयन के अंतर्गत है। फ्रांस भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए घटकों और उपकरणों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति की भारत

यात्रा (मार्च 2018) के दौरान, भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम (एनपीसीआईएल) और इलेक्ट्रीसाइट डी फ्रांस (ईडीएफ) के बीच भविष्य के लिए एक औद्योगिक करार संपन्न हुआ। ईडीएफ और एनपीसीआईएल के बीच परियोजना को शीघ्र साकार करने के उद्देश्य से चर्चा चल रही है।

भारत और फ्रांस दोनों के महत्वपूर्ण द्विपक्षीय निवेश और व्यापार और वाणिज्यिक सहयोग हैं। लगभग 1000 फ्रांसीसी कंपनियां भारत में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल कारोबार के साथ मौजूद हैं और लगभग 300,000 लोगों को रोजगार दे रही हैं। अप्रैल 2000 से जून 2018 तक 6.30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संचयी निवेश के साथ फ्रांस भारत में नौवां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। फ्रांस में, लगभग 120 भारतीय कंपनियां € 1 बिलियन के अनुमानित निवेश स्टॉक के साथ मौजूद हैं और 7000 लोगों को रोजगार दे रही हैं। अप्रैल 2017 से मार्च 2018 की अवधि में, माल में भारत फ्रांस द्विपक्षीय व्यापार 11.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.26% की वृद्धि थी। फ्रांस को भारत का निर्यात 6.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 6.66% कम था। इसी अवधि के दौरान भारत में फ्रांसीसी निर्यात 14.30% बढ़ कर 6.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया। हालाँकि, द्विपक्षीय व्यापार की कुल मात्रा फ्रांस के भारत से निर्यात के साथ कम है, जो फ्रांस के कुल आयात का 0.99% है। जनवरी से अगस्त 2018 तक वर्तमान व्यापार 8.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

वर्ष 2016 से 2018 की अवधि के लिए एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम कार्यान्वयन के अंतर्गत है। भारत सरकार ने फ्रांसीसी नागरिकों को भारत में संस्कृत के अध्ययन के लिए पांच छात्रवृत्तियों का प्रस्ताव किया है। 16 जून 2018 को पेरिस और फ्रांस के अन्य शहरों में भारत के दूतावास द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसे व्यापक प्रशंसा और प्रेस कवरेज मिली है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, नई दिल्ली स्थित 1987 में स्थापित उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत-फ्रांसीसी केंद्र (सीईएफआईपीआरए) विज्ञान में अनुसंधान के लिए संयुक्त प्रस्तावों और मौजूदा शोध परियोजनाओं का मूल्यांकन करने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। 2016 में स्थापित एक भारत-फ्रांसीसी मंत्री स्तरीय संयुक्त समिति विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित कई अन्य द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम मौजूद हैं, जिनकी पहली बैठक जून 2018 में नई दिल्ली में हुई थी।

फ्रांस में लगभग 6000 भारतीय छात्रों के होने का अनुमान है। उच्च शिक्षा के फ्रांसीसी संस्थानों में अंग्रेजी माध्यम में पाठ्यक्रमों के प्रस्ताव से प्रोत्साहित, विशेष रूप से व्यवसाय प्रबंधन के क्षेत्र में, हर वर्ष लगभग 3,000 भारतीय छात्र फ्रांस जाते हैं। दोनों पक्षों का लक्ष्य 2020 तक 10,000 छात्रों की संख्या तक पहुंचने का है।

जर्मनी

भारत और जर्मनी के बीच उच्च स्तरीय यात्राओं ने 2018 में द्विपक्षीय संबंधों में गति बनाए रखने में मदद की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2018 में जर्मनी की यात्रा की। जर्मनी के संघीय राष्ट्रपति डॉ. फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर ने मार्च 2018 में भारत की अपनी पहली यात्रा की। दोनों ओर से केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर नियमित रूप से द्विपक्षीय दौरे हुए और व्यापार और निवेश, विनिर्माण, कौशल विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, बुनियादी ढाँचा, नवाचार, रक्षा सहयोग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा आदि विविध क्षेत्रों में परस्पर सहयोग जारी रहा।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और चांसलर सुश्री एंजेला मर्केल द्वारा साझा किए गए आपसी विश्वास और समझ को वर्ष के दौरान हुई कई बैठकों और फोन वार्तालापों में प्रकट किया गया। सुश्री एंजेला मर्केल के चांसलर के रूप में अपना चौथा कार्यकाल शुरू करने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 21 मार्च 2018 को टेलीफोन पर बातचीत के दौरान उन्हें बधाई दी। चांसलर सुश्री एंजेला मर्केल के निमंत्रण पर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 अप्रैल 2018 को लंदन में कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन (सीएचओजीएम) से वापस आते समय रास्ते में बर्लिन गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और चांसलर सुश्री एंजेला मार्केल ने 9 नवंबर 2018 को एक टेलीफोन पर बातचीत की, जिसके तुरंत बाद 1 दिसंबर 2018 को ब्यूनस आयर्स में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन के मौके पर एक बैठक हुई।

प्रधान मंत्री ब्यूनस आयर्स में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर जर्मनी की चांसलर सुश्री एंजेला मर्केल से मुलाकात (01 दिसंबर, 2018)

संघीय राष्ट्रपति डॉ. फ्रेंक-वाल्टर स्टीनमीयर ने एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ 22-27 मार्च 2018 के दौरान भारत में 5 दिवसीय राजकीय यात्रा की। उन्होंने राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री (ईएएम) श्रीमती सुषमा स्वराज के साथ भेंट की। वे दिल्ली के अलावा वाराणसी और चेन्नई भी गए।

कौशल विकास और उद्यमिता और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20-23 जून 2018 के दौरान जर्मनी का दौरा किया और बर्लिन में जर्मन संघीय शिक्षा और अनुसंधान मंत्री सुश्री अंजा कार्लाइसेक से भेंट की।उन्होंने बर्लिन और स्टटगार्ट में कौशल विकास केंद्रों स्टटगार्ट के पास एक जैव-संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) संयंत्र का दौरा किया। जर्मन विदेश राज्य मंत्री श्री नील एलेन ने 17 और 18 जुलाई 2018 को नई दिल्ली का दौरा किया और केंद्रीय वित्त मंत्री और रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल, पूर्व राज्य मंत्री (एमओएस) श्री एम.जे. अकबर और विदेश सचिव श्री विजय गोखले से भेंट की। यात्रा के दौरान विचार-विमर्श भारत-जर्मनी द्विपक्षीय संबंधों पर केंद्रित था।

संस्कृति और मीडिया के लिए जर्मन संघीय आयुक्त प्रो. मोनिका ग्रुइटर्स ने 17 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति मंत्री डॉ. महेश शर्मा और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। नेताओं ने सांस्कृतिक जुड़ाव को पुनर्जीवित करने पर सहमति व्यक्त की।

भारत से, संसदीय कार्य, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में एक सद्भावना संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने 17-19 अक्टूबर 2018 के दौरान जर्मनी का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से आठ संसद सदस्य (सांसद) शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने बुंडेस्टैग के उपाध्यक्ष (जर्मन संसद के निचले सदन) श्री वोल्फगैंग कुबिकी, विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष डॉ. नॉर्बर्ट रोएटजेन और डिजिटलाइजेशन कमेटी के उपाध्यक्ष हंज़ोउर दूर्ज़ से भेंट की।

जर्मन फेडरल कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स पॉलिसी एंड ह्युमैनिटेरियन एड डॉ. बेरबेलकोफ़लर ने 21-26 अक्टूबर 2018 को दिल्ली, मुंबई, झारखंड और गुजरात की यात्रा की। उन्होंने सरकारी अधिकारियों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट के साथ बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन और न्यायमूर्ति मदन भीमराव लोकुर के नेतृत्व में एक न्यायिक प्रतिनिधिमंडल 16-23 जून 2018 को जर्मनी के संघीय न्यायालयों के न्यायाधीशों के साथ विशेषज्ञ चर्चा में भाग लेने के लिए जर्मनी गया। यह यात्रा भारत-जर्मन न्यायिक

वार्ता की निरंतरता में थी, जो पहली बार 2015 में भारत में शुरू हुई थी।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉ. के. सिवन ने 21-22 जून 2018 को जर्मनी का दौरा किया और जर्मन एयरोस्पेस सेंटर (डीएलआर) और जर्मनी की एक प्रमुख एयरोस्पेस कंपनी एमटी एयरोस्पेस पर चर्चा की। डीएलआर और भारत के बीच सहयोग 1971 से शुरू हुआ था, जब परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष अनुसंधान के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। आर्थिक मामलों और ऊर्जा के लिए जर्मन संघीय मंत्रालय के संसदीय राज्य सचिव श्री क्रिश्चियन हिर्ते ने 8 अगस्त 2018 को भारत का दौरा किया और वाणिज्य मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और दिल्ली में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों के साथ भेंट की। उन्होंने श्री नलिन कोहली के साथ भारत में “कानूनी सहयोग के लिए इंडो-जर्मन एसोसिएशन” भी लॉन्च किया।

ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी (आईएनएनओटीआरएएनएस) मेले के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेने और विभिन्न सरकारी अधिकारियों और व्यवसायों के साथ बैठकें आयोजित करने के लिए 18-21 सितंबर, 2018 को भारतीय रेलवे, रेलवे बोर्ड (सीआरबी) के अध्यक्ष श्री अश्वनी लोहानी ने बर्लिन का दौरा किया। यात्रा के दौरान, उन्होंने राज्य सचिव, जर्मन संघीय परिवहन और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर श्री गेरहार्ड शुल्ज से भेंट की, जिन्होंने सीआरबी को चेन्नई-बैंगलोर-मैसूर खंड के लिए हाई-स्पीड रेल स्टडी रिपोर्ट सौंपी।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, डॉ. रेनुस्वरुप “ग्रैंड चैलेंज मीटिंग” में भाग लेने के लिए 14-19 अक्टूबर 2018 को बर्लिन गए। उन्होंने जर्मन संघीय शिक्षा और अनुसंधान के राज्य सचिव डॉ. जॉर्ज शुट्टे के साथ भेंट की और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और जर्मनी के भविष्य के कार्यक्रमों पर चर्चा की।

जर्मनी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2017 में जर्मनी के वैश्विक व्यापार में भारत 26वें स्थान पर था। द्विपक्षीय व्यापार (2017-18) बढ़कर 21.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, इसमें 17.15% की वृद्धि हुई। 2017-18 में, जर्मनी को भारत का निर्यात 8.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर और जर्मनी से आयात 13.29 बिलियन यूएस डॉलर था। जर्मनी भारत में 7वां सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक है। अप्रैल 2000 से जून 2018 तक जर्मनी का कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) भारत में 10.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत में 1700 से अधिक जर्मन कंपनियां सक्रिय हैं और 600 से अधिक इंडो-जर्मन संयुक्त उद्यम काम कर रहे हैं। मिशन का “मेक इन इंडिया मित्तलस्टैंड” (एमआईआईएम) कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य जर्मन मित्तलस्टैंड कंपनियों को भारतीय बाजार में प्रवेश करने में सहायता करना है, वर्ष 2018-19 में जारी रहा। एमआईआईएम को भारत में निवेश करने की योजना बना रही जर्मन कंपनियों के लिए ‘स्थानीय फास्ट ट्रैक’ के रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 2015 के अंत से नवंबर 2018 तक शुरू होने के बाद से, कार्यक्रम ने 870 मिलियन यूरो से अधिक के घोषित निवेश के साथ 123 जर्मन एसएमई का समर्थन किया है।

वर्ष 2018 ने साठ वर्षों के द्विपक्षीय विकास सहयोग को चिह्नित किया। जर्मनी 1958 से एक महत्वपूर्ण विकास सहयोग भागीदार रहा है। 1958 से कुल द्विपक्षीय तकनीकी और वित्तीय सहयोग, 16.98 बिलियन यूरो की राशि का रहा है। ऊर्जा, सतत आर्थिक विकास, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन विकास सहयोग के अंतर्गत प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। भारत के साथ जर्मन विकास सहयोग की अनूठी विशेषता यह है कि यह स्थानीय परियोजनाओं पर कम और संरचनात्मक प्रभाव वाले कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। ये कार्यक्रम भारत के अपने प्रयासों और सुधार कार्यक्रमों पर आधारित हैं। वे मॉडल समाधान प्रदर्शित करते हैं और स्वतंत्र रूप से परियोजनाओं को जारी रखने और विस्तारित करने के लिए भाग लेने वाले भागीदारों को अर्हता प्रदान करते हैं।

जर्मनी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए फंडिंग के माध्यम से ट्रांसमिशन लाइनों के नेटवर्क को अपग्रेड करने में भी भारत की मदद कर रहा है। यह परियोजना नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (जैसे सौर, पवन और जल विद्युत) से उत्पन्न होने वाली बिजली को राष्ट्रीय ग्रिड में सुधारने के साथ-साथ ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और बिजली संचरण के नुकसान को कम करने में मदद करेगी। कृषि के क्षेत्र में, जर्मनी भारत सरकार के मिट्टी के संरक्षण और खाद्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों का समर्थन कर रहा है। व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में जर्मनी भी भारत का प्रमुख भागीदार है। जर्मनी के वर्तमान प्रयासों का उद्देश्य युवा आबादी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और मध्यम आकार के व्यवसायों की प्रतिस्पर्धा में सुधार करने में मदद करने के लिए अभ्यास-

प्रधान मंत्री नई दिल्ली स्थित सुंदर नर्सरी में जर्मनी संघीय गणराज्य के राष्ट्रपति डॉ. फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर के साथ (24 मार्च, 2018)

उन्मुख व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली स्थापित करना है।

भारत-जर्मनी द्विपक्षीय विकास सहयोग परामर्श 2018 नई दिल्ली में 3 मई 2018 को आर्थिक मामलों के विभाग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय और भारत/दक्षिण एशिया के प्रमुख, आर्थिक सहयोग और विकास के लिए संघीय मंत्रालय डॉ, वुल्फराम क्लेन के नेतृत्व में आए जर्मन प्रतिनिधिमंडल के बीच आयोजित किया गया था। बैठक के दौरान ऊर्जा, सतत शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण और संसाधन संरक्षण के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भविष्य के सहयोग पर चर्चा की गई।

रक्षा पक्ष में, जर्मन नौसेना के प्रमुख ने 15 से 18 अक्टूबर 2018 तक भारत का दौरा किया। उन्होंने तीन सेवा प्रमुखों और रक्षा सचिव के साथ भेंट की। रियर एडमिरल श्री अधीर अरोड़ा, एनएम, जॉइंट चीफ हाइड्रोग्राफर ने 14-17 मई 2018 के दौरान हाइड्रोग्राफिक सर्विसेज एंड स्टैंडर्ड्स कमेटी (एचएसएससी) की 10वीं बैठक में भाग लेने के लिए जर्मनी के रोस्टॉक का दौरा किया। नेशनल डिफेंस कॉलेज (एनडीसी) के एक 18-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 27 मई से 1 जून 2018 तक 58वें राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज पाठ्यक्रम के विदेशी अध्ययन दौरे पर जर्मनी का दौरा किया। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, सिकंदराबाद के तेईस सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय सामरिक प्रबंधन यात्रा के हिस्से के रूप में 22-26 अक्टूबर, 2018 के दौरान जर्मनी का दौरा किया। जर्मन नौसेना के निदेशक संचालन और उप फ्लीट कमांडर ने 12-14 नवंबर, 2018 के दौरान कोच्चि में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (आईओएनएस) की 10वीं वर्षगांठ में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया।

द्विपक्षीय वार्षिक रक्षा सहयोग कार्यक्रम 2018: जर्मन संघीय सशस्त्र बल उड़ान सुरक्षा के निदेशक के नेतृत्व में तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 10-12 सितंबर 2018 के दौरान उड़ान सुरक्षा (विशेषज्ञ वार्ता/सूचना यात्रा) (आईएनडी-जे-007-18), द्विपक्षीय वार्षिक सहयोग कार्यक्रम 2018 के हिस्सा के रूप में भारत का दौरा किया। लेफ्टिनेंट जनरल श्री अमरजीत सिंह बेदी और सीडीआर श्री आशुतोष सारंगी ने सैन्य खुफिया सूचना यात्रा (आईएनडी-जे -003-18), द्विपक्षीय वार्षिक सहयोग कार्यक्रम 2018 के भाग के लिए 12-14 सितंबर 2018 के दौरान जर्मन संघीय रक्षा मंत्रालय का दौरा किया।

प्रशिक्षण, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एणएसडीई) के महानिदेशक और इंडो-जर्मन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईजीसीसी) के महानिदेशक ने भारतीय युवाओं को दोहरी व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए 18 सितंबर 2018 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने वाले छात्रों को एक प्रमाण पत्र मिलेगा जिसे भारत के साथ-साथ जर्मनी में भी मान्यता प्राप्त है।

जर्मन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (डीजीयूवी) ने कर्मचारियों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में आगे सहयोग के लिए 13 नवंबर, 2018 को

निदेशालय जनरल फैक्ट्री सलाह सेवा और श्रम संस्थानों (डीजीएफएएसएलआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

मिशन द्वारा जर्मन राज्य थुरिंगिया की सरकार के सहयोग से, थुरिंगिया की राजधानी एरफर्ट में 18 जून 2018 को "भारत-थुरिंगिया साझेदारी दिवस" का आयोजन किया गया। एरफ़र्ट के स्कूली बच्चों ने राजदूत से बातचीत की और बच्चों को योग, भारतीय नृत्य और संगीत सहित विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति से अवगत कराया गया। एरफर्ट विश्वविद्यालय में, पूरे थुरिंगिया के विश्वविद्यालय के छात्रों ने भारत के संबंध में चर्चा की। इस अवसर पर थुरिंगियन कंपनियों के लिए एक व्यावसायिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मिशन द्वारा 10 जून 2018 को चांसरी में एक "भारतीय खाद्य महोत्सव" आयोजित किया गया था। जर्मनी में भारतीय सामुदायिक संघों द्वारा एक दर्जन से अधिक फूड स्टॉल लगाए गए थे, जो विभिन्न भारतीय राज्यों और व्यंजनों का प्रतिनिधित्व करते थे। इस आयोजन में भारतीय समुदाय के सदस्यों सहित 4,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया।

आयरलैंड

भारत और आयरलैंड के बीच निरंतर द्विपक्षीय राजनीतिक और आर्थिक संबंध बने रहे। राष्ट्रपति माइकल डी. हिगिंस 16 अगस्त 2018 को पूर्व पीएम वाजपेयी के निधन पर शोक संवेदना पुस्तिका पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे। अपनी टिप्पणी में, राष्ट्रपति हिगिंस ने "एक महान राजनेता और कवि" के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की।

वर्ष 2017-18 में भारत-आयरलैंड व्यापार कारोबार 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। भारत में समेकित आयरिश निवेश जून 2018 तक 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ छोड़ने के फैसले ने आयरलैंड को भारत जैसे देशों के प्रति अपनी निर्यात और व्यापार रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया है, जो एक बड़ी क्षमता पेश करते हैं। मुंबई में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने का आयरलैंड का निर्णय इसी दिशा में एक कदम है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के सहयोग से दूतावास ने 13 सितंबर 2018 को डबलिन के प्रतिष्ठित हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इस विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया। फिनटेक, स्वास्थ्य और बायो-फार्मा तथा एग्रीटेक क्षेत्र में काम कर रही कई भारतीय कंपनियों- आईडीएफसी बैंक, मोदी-मुंडीफार्मा और गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (अमूल) और अन्य ने 25 अप्रैल 2018 को डबलिन में आयोजित एशिया- प्रशांत सम्मेलन 'विकास की जड़' में हिस्सा लिया।

डबलिन सिटी काउंसिल के सहयोग से 16 जून 2018 को डबलिन में चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) मनाया गया। इस कार्यक्रम में डबलिन के हर्बर्ट पार्क में विभिन्न क्षेत्रों के 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। 21 जून 2018 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हिल ऑफ़ तारा के आइकॉनिक स्थल पर समर सोलस्टाइस के साथ भी मनाया गया, जो प्राचीन आयरिश हाई किंग्स की जगह थी, इसमें लगभग पचास लोग शामिल हुए थे।

येट्स के जन्मदिन पर, 13 जून 2018 को सैंडमाउंट, डबलिन में आयरिश साहित्यकार डब्ल्यू. बी. येट्स और भारतीय कवि गुरुदेव टैगोर के बीच की दोस्ती का उत्सव मनाया गया। इंटरनेशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस (इस्कॉन) द्वारा 28 जुलाई 2018 को वार्षिक डबलिन रथयात्रा महोत्सव (रथों का त्योहार) का आयोजन किया गया था। डबलिन में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान के सहयोग से दूतावास ने 17 मई, 2018 को श्री पैट्रिक बोवे, एक प्रसिद्ध लेखक, परिदृश्य डिजाइनर और स्थापत्य इतिहासकार द्वारा 'भारत के उद्यान' पर एक वार्ता आयोजित की गई। 2 अक्टूबर 2018 को सिटी काउंसिल के साथ सेंट पैट्रिक कैथेड्रलिन के सहयोग से गांधी जी की 150वीं जयंती पर एक प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आयरलैंड का नौवां भारतीय फिल्म महोत्सव डबलिन में 23-25 नवंबर 2018 से आयोजित किया गया था।

आयरलैंड में प्रवासी आबादी लगभग 34,000 है, जिनमें से लगभग 20,500 भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) हैं और लगभग 13,500 अनिवासी भारतीय (एनआरआई) हैं। समुदाय के अधिकांश लोग स्वास्थ्य सेवा (डॉक्टर और नर्स), आईटी, इंजीनियरिंग और वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर है। दूतावास ने सरकार की विभिन्न नीतियों को रेखांकित करने के लिए 31 जुलाई 2018 को एक प्रवासी कार्यक्रम का आयोजन

किया। मिशन ने विभिन्न आयरिश शिक्षण संस्थानों में आने वाले छात्रों के लिए स्वागत समारोह का भी आयोजन किया। मिशन ने 2 सितंबर 2018 को डबलिन के फीनिक्स पार्क में चौथे भारत दिवस का भी आयोजन किया, जिसमें आयरलैंड के कई उच्च-स्तरीय गणमान्य लोगों ने भाग लिया।

इटली

वर्ष 2018-19 भारत-इटली संबंधों के लिए एक विशेष वर्ष था। दोनों देशों ने भारत और इटली में वर्ष भर के उत्सवों के साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मनाई। पूर्व इतालवी प्रधानमंत्री श्री पाओलो जेंटिलोनी की यात्रा के ठीक एक वर्ष बाद अक्टूबर 2018 में प्रधानमंत्री श्री ग्यूसेप कोंटे की आधिकारिक यात्रा से संबंधों को और प्रोत्साहन मिला। जून 2018 में कार्यभार ग्रहण करने के बाद यह प्रधानमंत्री श्री ग्यूसेप कोंटे की एशिया की पहली यात्रा थी। उन्होंने भारतीय उद्योग प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी-परिसंघ (डीएसटू) - (सीआईआई) के 24वें संस्करण में इतालवी आधिकारिक-सह-व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, इटली इस सम्मेलन का भागीदार देश था।

यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री श्री ग्यूसेप कोंटे के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। नेताओं ने संयुक्त रूप से प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया, जिसमें इटली के 150 सहित 700 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दोनों पक्षों ने एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय, राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इसने सीईओ फोरम के संविधान सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत-इटली संबंधों को मजबूत करने और दो तरफा निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक फास्ट-ट्रैक तंत्र की स्थापना करने और दोनों देशों के व्यापारों के सामने आने वाले मुद्दों को तेजी से हल करने के तरीके को आगे बढ़ाया। डिजाइन में इटली की प्रसिद्ध विशेषज्ञता को देखते हुए, दोनों पक्षों ने लाइफस्टाइल एक्सेसरीज़ डिज़ाइन (एलएडी) में सहयोग का पता लगाने का फैसला किया, जिसमें चमड़ा क्षेत्र, परिवहन और ऑटोमोबाइल डिज़ाइन (टीएडी) पर विशेष ध्यान दिया गया। भारत और इटली ने सूक्ष्म विद्युत-यांत्रिक प्रणालियों, संज्ञानात्मक तंत्रिका विज्ञान, भौतिक विज्ञान, नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण जैसे क्षेत्रों में अपने दीर्घकालिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की।

प्रधान मंत्री और इटली के प्रधान मंत्री ज्यूसेप कोंटे नई दिल्ली में आयोजित भारत-इटली प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुए (30 अक्टूबर, 2018)

विदेश मंत्री इटली के विदेश मंत्री एंजो मोआवेरो मिलानेसी से रोम में मुलाकात करते हुए (18 जून, 2018)

17 जून 2018 को विदेश मंत्री (ईएएम) श्रीमती सुषमा स्वराज की इटली की यात्रा, इटली की नई सरकार के साथ पहला बड़ा राजनीतिक आदान-प्रदान था। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री श्री ग्यूसेप कोंटे से भेंट की और इटली की नवनिर्वाचित सरकार को भारत सरकार की बधाई दी और इटली के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की भारत की इच्छा को दोहराया। उन्होंने इटली के नए विदेश मंत्री श्री एनजो मोवरोमिल्नेसी के साथ द्विपक्षीय चर्चा की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। मंत्रियों ने नियमित उच्च-स्तरीय संपर्क और द्विपक्षीय संवाद तंत्र को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया और राजनीतिक परामर्श, व्यापार और वाणिज्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों से लोगों को जोड़ने के लिए एक मजबूत और व्यापक साझेदारी बनाने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने समकालीन वैश्विक मुद्दों पर बढ़ते भारत-इटली अभिसरण का स्वागत किया और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

अक्टूबर 2018 में इटली के विदेश मंत्रालय के तत्वावधान में नौ भारतीय राजनयिकों के पहले बैच ने रोम में एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया, दोनों देशों के विदेशी सेवा संस्थानों के बीच अक्टूबर 2017 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

एक सद्भावना संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने 15-17 अक्टूबर 2018 को इटली का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसदीय मामलों और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प के राज्य मंत्री ने किया, प्रतिनिधिमंडल में श्री अर्जुन राम मेघवाल और विभिन्न राजनीतिक दलों के संसद सदस्य शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने संसद के संबंधों और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए इटली के मंत्री, रिकार्डो फ्रॉकारो से भेंट की और चेंबर ऑफ डेप्युटीज के विदेशी मामलों के आयोग के सदस्यों के साथ-साथ इतालवी सीनेट से भी बातचीत की। दोनों पक्षों ने आईटी, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन के साथ-साथ सांस्कृतिक और युवा आदान-प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। इतालवी पक्ष ने अच्छी तरह से एकीकृत, शांतिप्रिय और मेहनती भारतीय समुदाय की सराहना की। दिसंबर 2011 में इटली-भारत संसदीय मैत्री संघ द्वारा सात वर्ष के अंतराल के बाद की गई भारत की यात्रा ने दोनों पक्षों के सांसदों को एक-दूसरे के देशों के लिए अपनी समझ और सद्भावना बढ़ाने का एक अवसर प्रदान किया।

वर्ष में दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई गति देखी गई। यूरोपीय संघ में इटली भारत का पांचवा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। द्विपक्षीय व्यापार 2016-17 में 8.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर में 18.4% की वृद्धि के साथ वर्ष 2017-18 में 10.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया, जिसमें 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार अधिशेष के साथ भारत के पक्ष में था। अप्रैल-सितंबर 2018 के 5.23 बिलियन के व्यापार के 2018-19 में उच्च स्तर तक पहुंचने का अनुमान है। इटली भारत से कॉफी का सबसे बड़ा आयातक बनकर उभरा। मेक इन इंडिया में इतालवी कंपनियों की भागीदारी बढ़ रही है। एक इतालवी सुपर-बाइक कंपनी ने भारत में पड़ोसी देशों को निर्यात करने की योजना के साथ एक नया विनिर्माण संयंत्र भी खोला। इतालवी कंपनियों ने भारत में प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भी प्राप्त की हैं। एक भारतीय कंपनी ने इटली में एक प्रमुख इस्पात संयंत्र का अधिग्रहण किया।

अप्रैल 2018 में अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर मेले के दौरान मिलान में डिजाइन पर इंडो-इटैलियन हाई-लेवल फोरम लॉन्च किया गया, जहां भारतीय इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट और फर्नीचर निर्माताओं ने भाग लिया। भारत ने 19-27 अक्टूबर 2018 के दौरान रोम में ऑडियो-विजुअल एंटरटेनमेंट उद्योग

से संबंधित प्रदर्शनी, वीडियोसिट्टा के पहले संस्करण में एक साझेदार देश के रूप में भाग लिया। इंडिया पैवेलियन ने भारतीय फिल्मों की विरासत, भारत में फिल्म की शूटिंग और खूबसूरत शूटिंग स्थानों की सुविधा, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, विभिन्न क्षेत्रों के भारतीय सिनेमा, भारत और इटली के बीच ऑडियो विजुअल सह-निर्माण का प्रदर्शन किया। भारतीय सांस्कृतिक प्रदर्शन और योग प्रदर्शन भी आयोजित किए गए थे। वर्ष के दौरान, दूतावास ने इटली में एक प्रमुख व्यापार साझेदार और एक निवेश गंतव्य के रूप में भारत को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न वाणिज्यिक कार्यक्रमों के आयोजन/भागीदारी के अलावा इटली में प्रमुख व्यावसायिक मेलों में भारतीय व्यापारियों की भागीदारी की सुविधा प्रदान की।

भारत-इटली प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के अलावा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) में मजबूत सहयोग जारी रहा। अक्टूबर 2018 में भारत में हुई संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, जीवन विज्ञान और भू-अभिलेख जैसे आपसी ताकत के चयनित क्षेत्रों में इंडो-इटैलियन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को बढ़ावा देने और सुविधा के लिए विज्ञान और नवाचार का इटली भारत मंच स्थापित करने का निर्णय लिया। उन्नत अनुसंधान के भारत-ट्रेंटो कार्यक्रम (आईटटीपीएआर) का चौथा चरण 19 जून 2018 को शुरू किया गया था। आईटीपीएआर की संयुक्त वैज्ञानिक समिति की बैठक 18 और 19 जून 2018 को हुई थी, समिति ने (i) माइक्रोसिस्टम्स (ii) दूरसंचार (iii) संज्ञानात्मक तंत्रिका विज्ञान (iv) नवीकरणीय ऊर्जा और (iv) क्वांटम भौतिकी के क्षेत्रों में अगले तीन वर्षों के लिए संयुक्त गतिविधियों की सिफारिश की। दोनों पक्षों ने कैमरिनो में 17-19 सितंबर 2018 तक "अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों" पर एक कार्यशाला आयोजित की, जिसमें छह भारतीय वैज्ञानिकों ने भाग लिया।

इटली के साथ रक्षा संबंध तेज हुआ है और आठ वर्ष के अंतराल के बाद रोम में 14-15 मई 2018 को 9 वीं संयुक्त रक्षा समिति की बैठक के आयोजन के साथ इसे एक ताजा प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। भारत-इटली सैन्य सहयोग समूह की नौवीं बैठक 11 और 12 अक्टूबर 2018 को रोम में आयोजित की गई थी, जहां दोनों पक्षों ने वर्ष 2019 के लिए द्विपक्षीय सहयोग योजना पर सहमति व्यक्त की, जिसने द्विपक्षीय गतिविधियों को आठ से बढ़ाकर अठारह कर दिया। आईएनएस तरंगिनी ने दक्षिणी इटली के पालेर्मो बंदरगाह की सद्भावना यात्रा की। इटली में नौ वर्ष के अंतराल के बाद एक सेना उच्च कमांड पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवधि के दौरान नाटो संहिताकरण द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो रक्षा उपकरणों के निर्यात के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को लाभकर स्थिति में लाते हैं।

दूतावास ने संस्कृति, प्रदर्शन कला और योग के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। भारत और इटली के बीच 70 वर्षों के राजनयिक संबंधों का स्मरणोत्सव इस अवधि के सार्वजनिक समारोहों का मुख्य आकर्षण था। आईसीसीआर द्वारा प्रायोजित एक मंडली ने रोम के प्रतिष्ठित टेट्रो अर्जेंटीना और दक्षिणी इटली के कैसर्टा पैलेस में कथक नृत्य "विवर्था" प्रस्तुत किया। प्रसिद्ध पियाजा डेल कैंपिडोग्लियो में हस्ताक्षर कार्यक्रम के साथ बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। नए संवाद के लिए भारत-यूरोप फाउंडेशन (एफआईएनडी) द्वारा एक वार्षिक ग्रीष्मकालीन मेला महोत्सव का आयोजन किया गया था। यह कार्यक्रम जून-जुलाई 2018 के दौरान आयोजित किया गया था और इसमें प्रख्यात भारतीय और इतालवी कलाकारों ने भाग लिया था। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर मंत्रालय की वैश्विक स्मृति में शामिल होकर, रोम की नगर परिषद की सीट प्रतिष्ठित पालाजो सेनेटोरियो को 2 अक्टूबर 2018 को गांधीजी के संदेश और शिक्षाओं के एक एलईडी प्रक्षेपण के साथ प्रकाशित किया गया था। इस वर्ष भी इतालवी सीनेट और दूतावास परिसर में इतालवी हिंदू संघ, इस्कॉन इटालिया, ब्रह्म कुमारियों व अन्य के सहयोग से दीपावली/दीवाली का त्यौहार आधिकारिक रूप से मनाया गया।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली की मुक्ति के लिए ब्रिटिश सेना के साथ लड़ने वाले भारतीय सैनिकों की भूमिका और बलिदान की काफी सराहना की जाती है। सक्रिय प्रयासों से दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान इटली में अपने जीवन का बलिदान देने वाले भारतीय सेना के दो सैनिकों के अवशेषों के औपचारिक दफन के मामले में तेजी आई है। समारोह 25 अप्रैल 2019 को होगा। दूतावास समय-समय पर कांसुलर शिविरों का आयोजन करके रोम से दूर-दराज के इलाकों में भारतीय समुदाय तक अपनी पहुंच बनाता रहा। दूतावास द्वारा प्रत्येक बुधवार को एक ओपन हाउस भी शुरू किया गया है जिसमें लोग वरिष्ठ दूतावास के अधिकारियों के साथ पूर्व नियुक्ति के बिना अपने कांसुलर मामलों पर चर्चा कर सकते हैं। वर्ष 2017 में दूतावास के सहयोग से स्थापित

किया गया भारतीय सामुदायिक केंद्र, बुकिन, भारतीय प्रवासियों को स्थानीय अधिकारियों के साथ से संपर्क करने में मदद कर रहा है, जिसमें समुदाय से संबंधित विभिन्न मुद्दों जैसे कि इतालवी भाषा की कक्षाएं आयोजित करना, भारतीयों को कानूनी मार्गदर्शन, भारतीय संस्कृति, भोजन और आध्यात्मिक विरासत को बढ़ावा देना आदि शामिल है।

लक्ज़ेमबर्ग

वर्ष 2018 भारत-लक्ज़ेमबर्ग द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष था। दोनों पक्षों द्वारा उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान से वर्ष को चिह्नित किया गया था। दोनों देश 1948 में अपने बीच स्थापित राजनयिक संबंधों की सत्तरवीं वर्षगांठ मना रहे हैं।

विदेश मंत्री ने लक्जमबर्ग के ग्रैंड ड्यूक हेनरी अल्बर्ट गेब्रियल फेलिक्स मारि गिलॉमे से मुलाकात की (20 जून, 2018)

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 19 और 20 जून 2018 को लक्ज़ेमबर्ग की यात्रा की। यह यात्रा भारत के किसी विदेश मंत्री द्वारा लक्ज़ेमबर्ग की पहली यात्रा थी। अपनी यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने लक्ज़ेमबर्ग के ग्रैंड ड्यूक, हेनरी अल्बर्ट गेब्रियल फ़ेलिक्स मैरी गुइल्यूम और लक्ज़ेमबर्ग के प्रधानमंत्री श्री जेवियर बेटटेल से भेंट की। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने अपने समकक्ष विदेश मंत्री और यूरोपीय मामलों के मंत्री, श्री जीन एस्सेलबॉर्न के साथ वार्ता की, जिसमें दोनों पक्षों ने भारत-लक्ज़ेमबर्ग राजनीतिक द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर परामर्श किया। यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री ने लक्ज़ेमबर्ग में ग्रैंड ड्यूक जीन म्यूज़ियम ऑफ़ मॉडर्न आर्ट (एमयूडीयूएम) में भारतीय समुदाय से बातचीत की।

लक्ज़ेमबर्ग के वित्त मंत्री श्री पियरे ग्रामेना ने 25 और 26 जून 2018 को एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तीसरी वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए मुंबई का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने तत्कालीन कार्यवाहक वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल से भेंट की।

भारत और लक्ज़ेमबर्ग के बीच माल का द्विपक्षीय व्यापार, 2017-18 के दौरान 64 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। लक्जेमबर्ग से भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) अप्रैल 2000 से जून 2018 के बीच 2.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

मोनाको

मोनाको, दुनिया के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है और वेटिकन के बाद दूसरा सबसे छोटा राज्य है। यह एक संवैधानिक राजतंत्र है जो हाउस ऑफ ग्रिमाल्डी के राजकुमार अल्बर्ट द्वितीय द्वारा शासित है। भारतीय गणतंत्र और मोनाको की रियासत ने आधिकारिक रूप से 21 सितंबर 2007 को राजनयिक संबंध स्थापित किए। दोनों देशों के बीच 30 सितंबर, 1954 से कांसुलर संबंध हैं। भारत और मोनाको ने सौहार्दपूर्ण संबंधों का आनंद लिया है और दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने संबंधों को धीरे-धीरे विकसित किया है। व्यापार, पर्यटन और कराधान मामले में सहयोग कुछ प्रमुख क्षेत्रों में हैं।

वित्त और जहाजरानी राज्य मंत्री श्री पोन. राधा कृष्णन ने 21 और 22 मई 2018 को मोनाको का दौरा किया और श्री जीन कास्टेलिनी, वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्री और श्री गिल्स टोनेली, विदेश और सहकारिता मंत्री के साथ बैठकें कीं।

नीदरलैंड

वर्ष 2018 भारत और नीदरलैंड के बीच प्राकृतिक तालमेल की निरंतरता का गवाह बना। डच प्रधानमंत्री श्री मार्क रुटे ने 24 और 25 मई 2018 को भारत में एक व्यापार मिशन का नेतृत्व किया। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा डच व्यापार मिशन था। बुनियादी ढांचा और जल प्रबंधनमंत्री, उप प्रधानमंत्री और कृषि, प्रकृति और खाद्य गुणवत्ता मंत्री, विदेश व्यापार और विकास सहयोग मंत्री, चिकित्सा देखभाल मंत्री, हेग शहर के मेयर भी इस व्यापार मिशन का हिस्सा थे। यात्रा के दौरान आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में सहयोग सहित कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर रचनात्मक चर्चा हुई। द्विपक्षीय चर्चा में जल और अपशिष्ट प्रबंधन, स्थानिक योजना, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, लोगों से लोगों और कनेक्टिविटी के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस यात्रा ने जून 2017 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों की आई गति को आगे बढ़ाया। ब्यूनस आयर्स में जी20 के अवसर पर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2018 को डच प्रधानमंत्री श्री मार्क रुटे और नीदरलैंड की रानी मैक्सिमा से भेंट की।

नीदरलैंड भारत के आर्थिक विकास में एक स्वाभाविक भागीदार है। दोनों पक्ष इंडो-डच आर्थिक जुड़ाव में चल रहे विस्तार को बनाए रखने के इच्छुक हैं। द्विपक्षीय व्यापार

प्रधान मंत्री और नीदरलैंड्स के प्रधान मंत्री मार्क रुट्टे हैदराबाद हाउस, नई दिल्ली में आयोजित भारत-नीदरलैंड्स सीईओ गोलमेज बैठक में भाग लेते हुए (24 मई, 2018)

2017-2018 में 8.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। 2017 में, नीदरलैंड्स को भारतीय निर्यात 14.7% बढ़ा, जबकि भारतीय आयात 18.2% बढ़ा। चालू वित्त वर्ष के दौरान, वित्त वर्ष 2018-2019 (अप्रैल से सितंबर) में कुल दो-तरफा व्यापार 6.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। 2017-2018 में नीदरलैंड भारत में तीसरे सबसे बड़े निवेशक के रूप में उभरा, जिसमें सेवा क्षेत्र, व्यापार, ऑटोमोबाइल उद्योग, किण्वन उद्योग, रसायन और जल प्रबंधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कुल मिलाकर 2.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ। वर्ष 2017 में 83,500 करोड़ रुपये (लगभग 12.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के निवेश के साथ, सिंगापुर के बाद यह भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा गंतव्य था। यूके, जर्मनी और बेल्जियम के बाद यूरोपीय संघ में नीदरलैंड भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। भारत और नीदरलैंड के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक जुड़ाव में पिछले एक दशक में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है।

वर्ष 2018 ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) में भारत-डच सहयोग की दसवीं वर्षगांठ को चिह्नित किया। नीदरलैंड 2019 में इंडिया टेक शिखर सम्मेलन के लिए साझेदार देश है। भारत और नीदरलैंड के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल, पानी, बिग डेटा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर) सहित विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान व सफल द्विपक्षीय सहयोग जारी है। अंतरिक्ष, कृषि, स्थानिक योजना, गतिशीलता प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, भारत और नीदरलैंड ने एक-दूसरे की वैश्विक पहलों में सहयोग और समर्थन जारी रखा। नीदरलैंड मई 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया। भारत अक्टूबर 2018 में नीदरलैंड द्वारा शुरू किए गए, अनुकूलन केंद्र पर ग्लोबल सेंटर का सह-संयोजक बना।

वर्ष 2018 में अन्य उच्च-स्तरीय दौरे भी हुए थे। मई 2018 में, नीदरलैंड की रानी मिक्सिमा ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में समावेशी वित्त के विकास के विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा की। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भेंट की और भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर चर्चा की। वे विदेश मंत्री (ईएएम) श्रीमती सुषमा स्वराज से भी मिलीं और 2014 में भारत की अपनी पिछली यात्रा के बाद से वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भारत द्वारा की गई प्रगति हासिल पर चर्चा की। आयुष मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक 1-4 सितंबर 2018 को नीदरलैंड गए। उन्होंने चौथे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस और स्वास्थ्य मेले (आईएवीसी) में भाग लिया और आयुर्वेद सहित "स्वास्थ्य देखभाल में भारत - नीदरलैंड सहयोग" पर एक संगोष्ठी को भी संबोधित किया। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने 4-6 सितंबर 2018 से नीदरलैंड का दौरा किया। यात्रा 1-4 नवंबर, 2019 से आयोजित होने वाले वर्ल्ड फूड इंडिया (डब्ल्यूएफआई) 2019 को बढ़ावा देने और नीदरलैंड को भागीदारी के लिए आमंत्रित करने पर केंद्रित थी। पाँचवां भारत-नीदरलैंड विदेशी कार्यालय परामर्श 4 मई 2018 को हेग में आयोजित किया गया था।

2018 में, भारत और नीदरलैंड के बीच दो समझौता ज्ञापनों अर्थात् स्थानिक योजना, जल प्रबंधन, और गतिशीलता प्रबंधन (अप्रैल 2018) के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर समझौता ज्ञापन का विस्तार; और विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, नीदरलैंड (23 मई 2018) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।।

स्थानिक नियोजन, जल प्रबंधन और गतिशीलता प्रबंधन के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर तीसरा संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) 2 मई 2018 को नीदरलैंड के हेग में आयोजित किया गया था। शहरी नियोजन और स्मार्ट सिटी विकास, किफायती आवास और अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे सहयोग के लिए एक संयुक्त कार्य योजना तैयार की गई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग पर समझौता ज्ञापन के अंतर्गत छठी जेडब्ल्यूजी का आयोजन 28 नवंबर 2018 को नई दिल्ली में किया गया। आतंकवाद प्रतिरोध पर भारत-नीदरलैंड पहला साइबर संवाद और दूसरी जेडब्ल्यूजी बैठक 14 दिसंबर 2018 को हेग में हुई। स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र पर जेडब्ल्यूजी की दूसरी बैठक 17 और 18 दिसंबर 2018 को नई दिल्ली में हुई। भारत-नीदरलैंड विदेश कार्यालय परामर्श का छठा संस्करण फरवरी 2019 में आयोजित किया जाएगा।

अगस्त 2015 से, नीदरलैंड में सफलतापूर्वक इलेक्ट्रॉनिक टूरिज्म वीज़ा (ईटीवी) लागू किया गया है, जिससे व्यापार और पर्यटन प्रवाह में वृद्धि हुई है और दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ रहे हैं। 2015 में एक सीधी उड़ान से, भारत और नीदरलैंड के बीच दैनिक गैर-रुके उड़ानों

की संख्या 2018 में बढ़कर पांच हो गई, जो एम्स्टर्डम को दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से जोड़ती है। इससे भारत और नीदरलैंड के बीच कनेक्टिविटी और यात्रा में बहुत आसानी हुई है।

17 जून 2018 को चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एम्स्टर्डम के सबसे प्रतिष्ठित स्थल म्यूजिप्लिन में मनाया गया। पहली बार द हेग के बाहर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में पूरे दिन कल्याण उत्सव में भाग लेने वाले लोगों की एक बड़ी भीड़ देखी गई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन डच इन्फ्रास्ट्रक्चर और जल प्रबंधन मंत्री, सुश्री कोरा वान नीवेनहुइज़न और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर द्वारा किया गया था। योग प्रदर्शनों को एक भव्य समापन 'द सोल शांति कॉन्सर्ट' में योग की विशेषता के साथ दिन भर नृत्य और संगीत के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को जोड़ा गया था, जिसमें भारतीय वायलिन वादक डॉ. एल. सुब्रमण्यम और बॉलीवुड पार्श्व गायिका श्रीमती कविता कृष्णमूर्ति शामिल थे। द नीदरलैंड्स में राजदूत के निवास, इंडिया हाउस में 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। दूसरी बार, इस कार्यक्रम का आयोजन एक खुले तौर पर किया गया था और इसमें 600 से अधिक लोग शामिल हुए थे, जिसमें भारतीय प्रवासी और भारत के मित्र भी शामिल थे।

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और अहिंसा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, को यूट्रेक्ट, द हेग, ज़ोएटर्मीयर और एम्स्टर्डम सहित चार शहरों में छह घटनाओं द्वारा चिह्नित किया गया था। भारतीय डाक विभाग द्वारा 150वीं जयंती पर जारी विशेष स्मारक टिकटों को पूर्व विदेश मंत्री और कार्नेगी फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. आर. बर्नार्ड बॉट को पीस पैलेस में एक समारोह में प्रस्तुत किया गया। नीदरलैंड के चार बड़े शहरों - हेग, एम्स्टर्डम, रॉटरडैम और उट्रेच के रेलवे स्टेशनों सहित सार्वजनिक स्थानों पर "समकालीन दुनिया में बापू के संदेश की प्रासंगिकता" पर एलईडी प्रोजेक्शन किया गया था। मिशन ने 'फॉलो द महात्मा' अभियान के भाग के रूप में, 30 सितंबर को, द हेग में शांति पैलेस से ग्रोट केर्क, द हेग तक गांधी मार्च का आयोजन किया। ग्रोट केर्क में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मार्च का समापन किया गया, जहां महात्मा गांधी के जीवन और कार्यों पर एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। इसके अलावा, "फॉलो द महात्मा" नामक एक आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें 100 से अधिक स्वयंसेवक अहिंसा का संदेश फैलाने और महात्मा गांधी के जीवन के बारे में बताने के लिए नीदरलैंड के बीस स्कूलों में गए थे।

पुर्तगाल

भारत और पुर्तगाल के बीच मधुर, मैत्रीपूर्ण संबंध, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच के संबंधों पर आधारित हैं, दोनों देशों ने पूरक तालमेल में काम करने और मजबूत रणनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और लोगों से लोगों का संबंध बनाने में लगे हैं। भारत और पुर्तगाल के बीच संबंधों में नए सिरे से तेजी देखी गई और 2017 में छह महीनों के भीतर दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा यात्राओं के अभूतपूर्व आदान-प्रदान, 6-12 जनवरी 2017 को भारत में पुर्तगाली प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा की राज्य यात्रा और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 24 जून 2017 को पुर्तगाल की आधिकारिक यात्रा से बीस से अधिक समझौतों और परिणामों को लागू करना किया गया - जिसके परिणामस्वरूप रक्षा, अंतरिक्ष, नवीकरणीय ऊर्जा, महासागरों, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, स्टार्टअप, उच्च शिक्षा और अनुसंधान, कराधान, लोक प्रशासन, संस्कृति, वीजा, युवा और खेल, तीसरा देश सहयोग, और व्यापार और वाणिज्य जैसे कई प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में समझौते हुए।

जनवरी 2017 में प्रधानमंत्री श्री एंटोनियो कोस्टा की गोवा यात्रा के दौरान हुई चर्चाओं के बाद, पर्यावरण मंत्री श्री जोओ पेड्रो माटोस फर्नांडीस, पाँच सदस्यीय पुर्तगाली प्रतिनिधिमंडल के साथ, 28 और 29 सितंबर, 2018 को गोवा आए और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) गोवा और डेगास द पार्तुगाल के बीच जल प्रबंधन में तकनीकी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्री श्री जोआओ माटोस फर्नांडीस ने नई दिल्ली में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन में भाग लिया और पेयजल और स्वच्छता मंत्री उमा भारती, संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ. महेश शर्मा, और संसदीय मामलों, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प के राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। मंत्री के दौरे से पहले पीडब्ल्यूडी गोवा और इमेजिन पणजी स्मार्ट सिटी परियोजना के साथ जल प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा करने के लिए 28 मई से 1 जून 2018 तक एडीपी

के तीन सदस्यीय पुर्तगाली प्रतिनिधिमंडल ने गोवा का दौरा किया था।

अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए पुर्तगाली राज्य सचिव डॉ. इरिकोब्रीहेल्टे डायस, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए 24-25 जून 2018 को मुंबई आए थे। उन्होंने दिल्ली का दौरा किया और जहाजरानी, राजमार्ग, जल संसाधन और गंगा कायाकल्प मंत्री नितिन गडकरी, वाणिज्य और उद्योग एवं नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु और पूर्व राज्य मंत्री श्री एम. जे. अकबर के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। स्टेट डायस के सचिव एक पुर्तगाली व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ आए थे और उन्होंने मुंबई में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ व्यापारिक बैठकें भी कीं। पंजाब सरकार में राजस्व, खनन, जल संसाधन और सिंचाई मंत्री, श्री सुखबिंदर सिंह सरकारिया, पुर्तगाल में पंजाबी प्रवासियों के साथ 1 नवंबर को पंजाब राज्य दिवस मनाने के लिए 30 नवंबर - 2 नवंबर 2018 को पुर्तगाल गए थे।

पुर्तगाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान सार्वजनिक प्रशासन और शासन सुधारों पर समझौता ज्ञापन के अनुपालन में, प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक प्रशासन विभाग (डीएआरपीजी) के सचिव, श्री के.वी. इपन की अगुवाई में चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने लिस्बन का दौरा किया। 8 और 9 मई 2018 और ई-गवर्नेंस और डिजिटल नागरिक-अनुकूल सेवा वितरण प्रणालियों से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ परामर्शदात्री निकाय की पहली बैठक आयोजित की गई।

. रक्षा क्षेत्र में, पुर्तगाली प्लेटफार्म फॉर डिफेंस इंडस्ट्रीज (आईडीडी) के नेतृत्व में सोलह सदस्यीय पुर्तगाली प्रतिनिधिमंडल ने कांचीपुरम में 11-14 अप्रैल 2018 को डेन्फेक्सपो-2018 में भाग लिया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सचिव, भारतीय रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों (पीएसयू) सहित भारतीय रक्षा अधिकारियों के साथ बातचीत की और फिक्की द्वारा आयोजित बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) बैठकों में भाग लिया। 4-7 जून 2018 से आईएनएस तरंगिनी द्वारा लिस्बन के दूसरे अनुकूल पोर्ट विजिट के अवसर पर एक राजनयिक स्वागत समारोह आयोजित किया गया था। एयर मार्शल श्री कुलदीप शर्मा ने 2-7 सितंबर 2018 के दौरान लिस्बन का दौरा किया पुर्तगाली एयरोस्पेस कंपनी ओजीएमए के साथ भारतीय एम्ब्रीयर विमानों के रखरखाव मरम्मत ओवरहाल (एमआरओ) सुविधा के बारे में चर्चा की और मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत व्यावसायिक अवसरों की खोज में रुचि रखने वाले पुर्तगाली रक्षा कंपनियों के साथ बात की। रक्षा उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 17 जुलाई 2018 को फिक्की और आईडीडी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जवाहरलाल नेहरू केंद्र (जेएनसीएएसआर) और भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) के भारतीय वैज्ञानिकों के सात-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 15-17 अक्टूबर 2018 से, ब्रागा, पुर्तगाल में अंतर्राष्ट्रीय अरबियन नैनो टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी (आईएनएल) में नैनो तकनीक पर एक कार्यशाला में भाग लिया। इसरो के अध्यक्ष श्री के. सिवन ने 2-5 अक्टूबर 2018 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस के मौके पर जर्मनी में पुर्तगाली, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मैनुअल हेइटर से भेंट की। संयुक्त वैज्ञानिक अनुसंधान और सहयोग के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और पुर्तगाली विज्ञान और प्रौद्योगिकी फाउंडेशन (एफसीटी) के बीच जून 2017 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पुर्तगाल यात्रा के दौरान घोषित 4 मिलियन यूरो के एक समझौता ज्ञापन को संचालन के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है। खाद्य नीति और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और पुर्तगाली खाद्य और सुरक्षा प्राधिकरण (एएसएई) के बीच 6 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

आर्थिक मोर्चे पर, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) और फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो) द्वारा एक बहु-क्षेत्रीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने पुर्तगाल के चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (सीसीआईपी) लिस्बन में, और पुर्तगाली उद्यमी संघ (एईपी) के साथ पोर्टो में बी2बी बैठकों के लिए 26 और 27 नवंबर, 2018 को पुर्तगाल का दौरा किया गया। यह यात्रा 30 मई 2017 को लिस्बन में संयुक्त आर्थिक समिति की बैठक में व्यापार मिशनों के आदान-प्रदान के लिए फिक्की और सीसीआईपी के बीच समझौता ज्ञापन के ढांचे के अंतर्गत हुई। जनवरी 2017 में पुर्तगाली प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान इन्वेस्ट इंडिया और स्टार्टअप पुर्तगाल के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के लिए, दस भारतीय स्टार्टअप का चयन करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं जो यूरोपीय संघ के बाजार से परिचित होने के लिए पुर्तगाली इनक्यूबेटरों

में शामिल होंगे। 5 सितंबर 2018 को, प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने पुर्तगाली प्रौद्योगिकी कंपनी विज़न-बॉक्स और केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, बेंगलुरु के बीच यात्री-अनुकूल, बायोमेट्रिक सिस्टम डिजाइन करने के लिए अनुबंध-हस्ताक्षर समारोह में भाग लिया। भारत ने 12 अक्टूबर 2018 को सांता मारिया दे फिरा में खादी और एसएमई बिज़फोरम को बढ़ावा देने के लिए 26 और 27 सितंबर 2018 को पोर्टो में मोदतिसिमो वस्त्र मेले में भाग लिया।

गोवा में वर्षगांवकर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन के बारह छात्रों के एक दूसरे बैच ने लोगों के करीबी आपसी संपर्क को बढ़ावा देते हुए आतिथ्य क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए 20 मई से 2 जून 2018 तक पुर्तगाल का दौरा किया। सेंट मार्क्स सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली के लगभग पंद्रह भारतीय छात्रों ने दो स्कूलों के बीच एक छात्र विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत एग्रुपेंटो डी एसकोलास डे कैनेकास पुर्तगाल के एस्कोला सिकंदरिया का दौरा किया। एक पुस्तक, हिस्टोरियोसैक्वी ई डाली '(यहाँ और यहाँ से परे की कहानियां'), गोवा के ऑक्जिलियम हाई स्कूल और सिंट्रा के अल्बर्टा मेनरेस स्कूल से 400 स्कूली छात्रों के साथ लिस्बन में 14 मई 2018 को जल प्रदूषण पर एक सहयोगी परियोजना शुरू की गई। आईसीसीआर के समर्थन के साथ 17 और 18 अप्रैल 2018 को लिस्बन विश्वविद्यालय में भारतीय अध्ययन के लिए केंद्र में 'ग्लोबल कनेक्शन हिंद महासागर' पर भारत से प्रतिष्ठित वक्ताओं के साथ एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ओरिएंट फाउंडेशन के सहयोग से कार्नेगी इंडिया ने 7 और 8 जून 2018 को पुर्तगाल के अर्राबिडा मठ में भारत रणनीति समूह सम्मेलन का आयोजन किया।

भारतीय कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया, जिसमें 21 जून 2018 को प्रतिष्ठित बेलम टॉवर में लगभग 200 प्रतिभागियों सहित पुर्तगाली योग परिसंघ के साथ चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस; 24 जून 2018 को पोर्टो के रामलडे स्पोर्ट्स पार्क में एक सामूहिक योग कार्यक्रम; और 10 नवंबर 2018 को नक्षत्र प्रोडक्शंस के साथ ओरिएंट फाउंडेशन में नृत्य का जिया महोत्सव शामिल है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का दो वर्ष का समारोह लिस्बन के महापौर की मौजूदगी में महात्मा गांधी की छवियों और संदेशों के एलईडी प्रोजेक्शन के माध्यम से लिस्बन के ऐतिहासिक प्राकोसा कॉमरेडिया चौक पर आयोजित किया गया और लिस्बन विश्वविद्यालय में भारत अध्ययन केंद्र महात्मा गांधी पर सम्मेलन सत्य वार्ता आरंभ की गई। प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने महात्मा गांधी के अवसर पर मानव विद्या के लिए एक लेख लिखा, वे विश्व स्तर पर स्मारक की घटनाओं को आयोजित करने के लिए गठित समिति के सदस्य हैं। जाने-माने पुर्तगाली बांसुरी वादक श्री राओकाओ ने महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में गांधीजी के पसंदीदा भजन 'वैष्णव जन तो' को प्रस्तुत किया। 15 अगस्त 2018 को, भारत के स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए बेलम में वास्को डी गामा उद्यानों में एक समारोह का आयोजन किया गया था। 7,000 से अधिक आगंतुकों ने भारतीय नृत्य और संगीत, भोजन, खादी उत्पादों, योग, आयुर्वेद, मेंहदी, रंगोली, सुलेख, बॉलीवुड, भारतीय उत्पादों और एक भारत प्रश्नोत्तरी की विविधता का आनंद लिया। आईसीसीआर द्वारा प्रायोजित भारतीय संस्कृति के एक शिक्षक (टीआईसी) 30 अप्रैल 2018 को भारतीय दूतावास में शामिल हुए और पुर्तगाल में योग को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहे हैं।

पुर्तगाल बहुपक्षीय मंचों में भारत का लगातार समर्थन करता रहता है। 26 सितंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र को संबोधित करते हुए, पुर्तगाली गणराज्य के राष्ट्रपति डॉ. मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

सैन मरीनो

सैन मैरिनो के साथ संबंध सौहार्द और मैत्रीपूर्ण बने हुए हैं। वर्ष 2017 में द्विपक्षीय व्यापार में 2016-17 की अपेक्षा 27.87% की वृद्धि हुई और यह 0.78 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। हालांकि भारत से सैन मैरिनो के निर्यात में 39.15% की कमी आई और यह 0.14 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जबकि सैन मैरिनो से आयात 66.5% बढ़कर यूएस 0.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।. सैन मैरिनो के चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ 23 जनवरी 2018 को गोल मेज वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें भारत और सैन मैरिनो के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने की क्षमता पर चर्चा की गई थी।

इस वर्ष 22-23 जून को बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। विदेश, राजनीतिक मामलों और न्याय के मंत्री, श्री निकोला रेनज़ी और संस्कृति और खेल मंत्री, श्री मार्को पोदेस्की ने भी सैन मैरिनो में एक प्रतिष्ठित स्थान पर आयोजित योग दिवस समारोह में भाग लिया।

22 जून 2018 को एक दिवसीय फिल्म महोत्सव भी आयोजित किया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म 'क्वीन' प्रदर्शित की गई और सैन मैरिनो की जनता द्वारा उत्साह से इसका स्वागत किया गया।

स्पेन

मई **2017** में प्रधानमंत्री की स्पेन की आधिकारिक यात्रा द्वारा दी की गई प्रेरणा के बाद, उच्च स्तरीय बैठकों की आवृत्ति में वृद्धि से द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए। उप राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने अक्टूबर **2018** में ब्रसेल्स में एशिया यूरोप मीटिंग **(एएसईएम)** शिखर सम्मेलन के अवसर पर स्पेन के प्रधानमंत्री श्री पेड्रो सांचेज़ से भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 दिसंबर 2018 को ब्यूनस आयर्स में जी20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर भी स्पेन के प्रधानमंत्री से भी भेंट की। विदेश मंत्री (ईएएम) श्रीमती सुषमा स्वराज ने सितंबर 2018 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर स्पेन के विदेश मंत्री के साथ भेंट की।

स्पेनिश विदेश राज्य मंत्री श्री इल्डेफोंसो कास्त्रो भारत-स्पेन विदेश कार्यालय परामर्श के लिए 3 अप्रैल, 2018 को दिल्ली आए थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की स्पेन यात्रा के दौरान जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य में हुई सहमति के अनुसार अप्रैल 2018 में मैड्रिड में एक रक्षा उद्योग सम्मेलन आयोजित किया गया था; मई 2018 में मैड्रिड में पर्यटन पर विशेषज्ञ पैनल की पहली बैठक हुई; अहमदाबाद और वलाडोलिड शहरों के बीच जुड़ाव समझौते पर जुलाई 2018 में हस्ताक्षर किए गए थे; शहरी परिवहन के क्षेत्र में एक तकनीकी सहयोग समझौते पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम और एडीआईएफ, स्पैनिश सार्वजनिक क्षेत्र की रेलवे अवसंरचना कंपनी के बीच हस्ताक्षर किए गए थे, और रक्षा आरएंडडी पर अतिरिक्त समझौते तथा व्हाइट शिपिंग पर तकनीकी समझौते पर बातचीत संपन्न हुई।

वाणिज्यिक क्षेत्र में, पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में अप्रैल-सितंबर 2018 की छह महीने की अवधि के दौरान द्विपक्षीय व्यापार में 9.6% की वृद्धि हुई और यह 3.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। इस अवधि के दौरान भारत का स्पेन में निर्यात 8% बढ़कर 2.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि स्पेन से भारत का आयात 15% बढ़ गया और 0.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुँचा। मैड्रिड

विदेश मंत्री स्पेन के विदेश मंत्री जोसेप बोरेल फॉंटेलेस से नई दिल्ली में मुलाकात करते हुए (8 जनवरी, 2019)

में 18 जनवरी 2018 को आर्थिक सहयोग पर भारत-स्पेन संयुक्त आयोग का 11वां दौर आयोजित हुआ और इसमें द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों, बाजार पहुंच मुद्दों और वित्तीय सहयोग पर चर्चा हुई। पर्यटन राज्य मंत्री (आई/सी) श्री अल्फोंस कन्ननथनम ने अप्रैल 2018 में सैन सेबेस्टियन में आयोजित संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के 108वें कार्यकारी परिषद सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने सितंबर 2018 में स्पेन का दौरा किया और भारत में व्यवसायों के लिए सरकार की सुधार पहलों और अवसरों को प्रस्तुत किया तथा खाद्य प्रसंस्करण और मेगा फूड पार्कों में सहयोग को मजबूत किया।

राज्यों की सुविधा के प्रयासों के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, थोक बाजारों और सहकारी समितियों में सहयोग के लिए हरियाणा, उत्तराखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्यों से मंत्रिस्तरीय और आधिकारिक-सह-व्यापार प्रतिनिधिमंडल का आयोजन किया गया। रक्षा, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा, वस्त्र, चमड़ा और आईटी में व्यापार प्रतिनिधिमंडल, क्रेता-विक्रेता बैठकें और व्यापार सम्मेलन आयोजित किए गए। भारत ने स्पेन में आयोजित फिटुर 2018 पर्यटन मेले में 'साथी देश' के रूप में भाग लिया और इंटर गिफ्ट, एलेमेंटेरिया, फूडटेक, जीपीईएक्स और गैस्टेक, डिजिटल एंटरप्राइज शो, सीपीएचआई वर्ल्डवाइड और स्मार्ट सिटी एक्सपो वर्ल्ड कांग्रेस आदि व्यापार मेलों समर्पित भारत मंडप के साथ भागीदारी की।

चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईवाईडी), 16 जून 2018 को प्रतिष्ठित कॉनकेड ड्यूक कल्चरल सेंटर में मनाया गया, इसके बाद बार्सिलोना, टेनेरिफ़, ग्रेनेडा, वलाडोलिड जैसे सत्रह प्रमुख शहरों और साथ ही अंडोरा की रियासत में आईवाईडी कार्यक्रम हुए, जिनमें लगभग 4500 प्रतिभागी शामिल थे। मिशन ने गंगा नदी का प्रतिनिधित्व करते हुए कॉर्डोबा में रियोमुंडी विश्व नदियों महोत्सव में भाग लिया। कॉन्सर्ट में भारत के पाँचवें संस्करण का आयोजन मैड्रिड की टीट्रोसडेल नहर में किया गया। महानिदेशक आईसीसीआर, सुश्री रीवा गांगुली दास ने जुलाई 2018 में कासा डी ला इंडिया बोर्ड की बैठक के लिए व्लाडोलिड का दौरा किया। मिशन ने जुलाई से सितंबर 2018 तक हिंदी के लिए एक ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम आयोजित किया। सितंबर 2018 में मैड्रिड और वलाडोलिड में भारत की स्वतंत्र फिल्मों का एक फिल्म समारोह आयोजित किया गया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का उत्सव 2 अक्टूबर 2018 को बापू@150 क्विज़ के शुभारंभ, स्मारक टिकटों की जारी, फोटो प्रदर्शनी, लघु फिल्म के एलईडी प्रदर्शन और कंडेनसेयलो अल्फोंसो क्वायर द्वारा गाये गए "वैष्णव जन" मेडले के साथ शुरू हुआ। दिवाली मेला का दूसरा संस्करण मैड्रिड में नगर परिषद और स्थानीय भारतीय समुदाय के सहयोग से आयोजित हुआ। मिशन ने राष्ट्रीय एकता दिवस के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल पर डॉक्यूमेंट्री और क्विज़ की स्क्रीनिंग का आयोजन किया। अहमदाबाद और केरल के प्रतिनिधिमंडलों ने वलाडोलिड में सांस्कृतिक विरासत के एआर एंड पीए बेनेले में भाग लिया।

यूनाइटेड किंगडम

भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी को 18 अप्रैल 2018 की प्रधानमंत्री की लंदन यात्रा से नया प्रोत्साहन प्राप्त मिला, जो प्रधानमंत्री के स्तर पर तीन वर्ष की अवधि में तीसरी यात्रा थी। यात्रा के दौरान साइबर संबंध फ्रेमवर्क, गंगा नदी का कायाकल्प, कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा, सुरक्षित परमाणु ऊर्जा उपयोग, पशुपालन, मत्स्य पालन और सहयोग, आपराधिक रिकॉर्ड साझा करने, न्यूटन-भाभा कार्यक्रम के अंतर्गत मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान और आयुर्वेद और पारंपरिक भारतीय चिकित्सा में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने जैसे विभिन्न क्षेत्रों में दस समझौता ज्ञापनों/समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच व्यापक और रचनात्मक बातचीत हुई, भारत-ब्रिटेन प्रौद्योगिकी साझेदारी को आगे बढ़ाने और व्यापार, निवेश और वित्त के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया गया।. नासाकॉम और टेक यूके के बीच भारत-यूके टेक एलायंस के आरंभ, यूके-इंडिया टेक हब की स्थापना, यूके-इंडिया टेक क्लस्टर साझेदारी का विकास, भारत में एक उन्नत विनिर्माण केंद्र की स्थापना और भारत के एस्पिरेशनल हेल्थ डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल में सहयोग के माध्यम से टेक पार्टनरशिप के कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई थी।

प्रधान मंत्री लंदन में फ्रांसीस क्रिस्क इंस्टीट्यूट में आयोजित यूके-भारत सीईओ मंच में भाग लेते हुए (18 अप्रैल, 2018)

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान घोषित अन्य पहलों में निवेश और फिनटेक पर नए भारत-यूके संवाद, एक बहुपक्षीय भारत-यूके व्यापार संवाद और व्यापार के लिए बाधाओं को दूर करने के लिए एक सेक्टर-आधारित रोडमैप शामिल थे। 18 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान भारत-यूके सीईओ फोरम का गठन किया गया, जिसमें तकनीकी सहयोग, डेटा संरक्षण और व्यापार करने में आसानी पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वेल्स के राजकुमार ने संयुक्त रूप से 18 अप्रैल 2018 को एक नए आयुर्वेद उत्कृष्टता केंद्र के लिए एक पट्टिका का अनावरण किया जिसने योग और आयुर्वेद पर साक्ष्य-आधारित अनुसंधान के समन्वय के लिए एक नए नेटवर्क के शुभारंभ को चिह्नित किया। ब्रिटेन इस यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में भी शामिल हुआ।

अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद, दोनों पक्षों की कई मंत्रिस्तरीय यात्राओं के साथ द्विपक्षीय सहयोग में गति पूरे वर्ष बनी रही। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने जुलाई 2018 में नासाकॉम और टेक यूके द्वारा समन्वित भारत-यूके टेक एलायंस को आगे बढ़ाने के लिए लंदन का दौरा किया। इस अवसर पर भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए साझा दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से कानून और न्याय के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. टी. गहलोत ने 23 और 24 जुलाई 2018 को लंदन में वैश्विक विकलांगता शिखर सम्मेलन में भाग लिया। विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, श्री आर.के. सिंह, सितंबर 2018 में शून्य उत्सर्जन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बर्मिंघम गए थे। उन्होंने 13 सितंबर 2018 को लंदन में व्यापार, ऊर्जा और औद्योगिक रणनीति विभाग के सचिव श्री ग्रेग क्लार्क के साथ यूके-इंडिया एनर्जी फॉर ग्रोथ डायलॉग की सह-अध्यक्षता की।

यूके के विदेश और राष्ट्रमंडल कार्यालय में दक्षिण एशिया के राज्य मंत्री, श्री मार्क फील्ड, ने टेक पार्टनरशिप और टिकाऊ ऊर्जा पर व्यापक वार्ता के लिए 7 और 8 मई 2018 को भारत का दौरा किया। गृह मंत्रालय में अतिवाद को रोकने की मंत्री श्रीमती बरोनेस विलियम्स ने 11 जून 2018 को चरमपंथ से निपटने में निकट सहयोग विकसित करने पर द्विपक्षीय चर्चा करने के लिए भारत का दौरा किया। ट्रेजरी के चांसलर श्री फिलिप हैमंड ने एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए 25 और 26 जून 2018 को मुंबई का दौरा किया और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में जोन स्टार्टअप्स एक्सेलेरेटर में कुछ युवा भारतीय उद्यमियों से भी भेंट की। विश्वविद्यालय और विज्ञान मंत्री, श्री सैम गिमा, 26 जुलाई 2018 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन के साथ नई दिल्ली में आयोजित विज्ञान और नवाचार परिषद की बैठक की सह-अध्यक्षता करने के लिए 25 से 27 जुलाई 2018 तक भारत यात्रा पर आए थे।

आवास, समुदाय और स्थानीय सरकार विभाग के राज्य सचिव, श्री जेम्स ब्रोकेन्सशायर, भारत और ब्रिटेन के मिडलैंड्स क्षेत्र के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 4-6 अक्टूबर 2018 से वेस्ट मिडलैंड्स के मेयर, मिस्टर एंडी स्ट्रीट के साथ भारत आए। लंदन शहर के लॉर्ड मेयर, श्री चार्ल्स बोमन, भारत के साथ आर्थिक और व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए 7 से 12 अक्टूबर 2018 तक एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल और फिनटेक फर्मों के प्रतिनिधियों के साथ भारत आए। स्कॉटलैंड के प्रथम उपमंत्री श्री जॉन स्वाइन ने व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने और शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी पर ध्यान देने के साथ व्यापार और स्कॉटिश विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधिमंडल के साथ 23-29 नवंबर 2018 तक दिल्ली और बेंगलुरु का दौरा किया।

भारत की राज्य सरकारों ने यूनाइटेड किंगडम में आउटरीच जारी रखा और भारत में निवेश करने के लिए अपने प्रोत्साहन और शक्तियों को बढ़ावा दिया। इस संबंध में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, तमिलनाडु के उद्योग मंत्री श्री एम. सी. संपत और उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों ने क्रमशः मई 2018, अक्टूबर 2018 और जुलाई 2018 में ब्रिटेन का दौरा किया।

भारत-यूके साइबर संवाद का एक और दौर 20 जून 2018 को नई दिल्ली में हुआ, जिसमें साइबर डिप्लोमेसी, साइबर क्राइम, घटना प्रतिक्रिया, डिजिटल अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत उप-समूहों और नामित विभागों/एजेंसियों में और नोडल बिंदु के माध्य से क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में साइबर से संबंधित मुद्दों पर सहयोग करने का निर्णय लिया गया। डेटा गोपनीयता मुद्दों पर एक अलग संरचित संवाद शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। आतंकवाद-प्रतिरोध पर भारत-ब्रिटेन संयुक्त कार्यदल की 12वीं बैठक 16 नवंबर, 2018 को नई दिल्ली में हुई। आगामी चर्चाओं में जोखिम मूल्यांकन के बंटवारे, कट्टरपंथ और उग्रवाद का मुकाबला करने, पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) और प्रत्यर्पण मामलों, विशेष बलों के बीच सहयोग और विमानन और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में चर्चा हुई।

वर्ष 2017-18 में वस्तुओं में यूनाइटेड किंगडम के साथ द्विपक्षीय व्यापार 14.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर और सेवाओं में लगभग 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत ने यूके में चौथे सबसे बड़े निवेशक के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखा और 105,000 से अधिक नौकरियां उत्पन्न करने वाली भारतीय कंपनियों के साथ दूसरे सबसे बड़े रोजगार निर्माता के रूप में उभरा। अप्रैल 2000 से जून 2018 तक यूके, 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संचयी इक्विटी निवेश, भारत में सभी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का लगभग 7% के साथ भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक था। ब्रिटेन में सक्रिय 800 भारतीय कंपनियों के कुल समेकित राजस्व 46 बिलियन पाउंड को छूने वाले कुल पूंजीगत व्यय निवेश के साथ 46.4 बिलियन पाउंड था। भारतीय कंपनियों ने 2017-18 में यूके में 120

प्रधान मंत्री लंदन में सीएचओजीएम शिखर सम्मेलन के औपचारिक उद्घाटन समारोह में शासनाध्यक्षों के साथ। (19 अप्रैल, 2018)

एफडीआई परियोजनाएं बनाईं और 532 नौकरियों की सुरक्षा करते हुए 5,659 नई नौकरियां सृजित कीं।

रक्षा सचिव और रक्षा मंत्रालय के स्थायी सचिव के बीच नई दिल्ली में 27 सितंबर 2018 को 19वें रक्षा सलाहकार समूह की बैठक के माध्यम से रक्षा के क्षेत्र में शीर्ष स्तर का सहयोग जारी रहा। चर्चाओं में रक्षा क्षमता साझेदारी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास में संयुक्त सहयोग और मेक-इन-इंडिया ढांचे के अंतर्गत विनिर्माण शामिल थे। 26 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में आयोजित अतिरिक्त सचिव-स्तर पर रक्षा उपकरण उप-समूह की बैठक में रक्षा उपकरणों और रखरखाव के मुद्दों पर चर्चा हुई। भारतीय नौसेना-रॉयल नेवी (24 जुलाई 2018) और भारतीय वायु सेना-रॉयल एयर फोर्स (25-27 सितंबर 2018) के बीच कार्यकारी संचालन समूह की बैठकों ने पिछले रक्षा सलाहकार समूह बैठकों में दोनों पक्षों के बीच लिए गए द्विपक्षीय सहयोग के निर्णयों और कार्यान्वयन को आगे बढ़ाया। भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी के बीच कैरियर ऑपरेशंस पर क्षमता साझेदारी विकसित करने के लिए रियर एडमिरल के नेतृत्व में पांच सदस्यीय रॉयल नेवी प्रतिनिधिमंडल ने 25-29 जून 2018 तक भारत का दौरा किया।

द्विपक्षीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कोंकण का आयोजन 28 नवंबर से 6 दिसंबर 2018 तक गोवा में किया गया, जिसमें भारतीय नौसेना विध्वंसक आईएनएस कोलकाता ने भाग लिया। भारतीय सेना के 2/8 गोरखा राइफल्स की एक टीम ने 15-17 अक्टूबर 2018 से यूके में एक्सरसाइज कैंब्रियन पैट्रोल 2018 में भाग लिया और रजत पदक जीता।अपनी नाविका सागर परिक्रमा के दौरान, भारतीय नौसेना नौकायन पोत तारिणी ने छह सदस्यों के एक महिला-चालक दल के साथ फॉकलैंड द्वीप समूह (दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ब्रिटेन का एक प्रवासी क्षेत्र) पोर्ट स्टेनली का दौरा किया। आईएनएस तरंगिनी ने 12-14 जुलाई 2018 तक दस अधिकारियों, तीस प्रशिक्षु कैडेटों और चौंतीस नाविकों के चालक दल के साथ ब्रिटेन के संडरलैंड का दौरा किया।

लंदन में 21-23 अप्रैल 2018 के दौरान आयोजित भारत-ब्रिटेन विज्ञान और नवाचार नीति संवाद के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग जारी रहा, जिसकी सह-अध्यक्षता विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव और यूके के व्यापार विभाग, ऊर्जा और औद्योगिक रणनीति के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार ने की। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ) और रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (डीएसटीएल) के बीच भारत-यूके विज्ञान और प्रौद्योगिकी उप-समिति की छठवीं संचालन समिति की बैठक 30 अप्रैल 2018 को आयोजित की गई और सितंबर 2018 में डीआरडीओ और डीएसटीएल के बीच लंदन में एक अन्य कार्यदल-स्तरीय बैठक हुई। ।

मध्य यूरोप

अल्बानिया

आपसी विश्वास और समझदारी पर आधारित द्विपक्षीय संबंध मैत्रीपूर्ण हैं। भारत और अल्बानिया बहुपक्षीय मंचों में एक मुद्दा आधारित दृष्टिकोण पर सहयोग करते हैं।

इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नेतृत्व में एक कंसोर्टियम के अल्बानिया में 70 मिलियन यूरो (79.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य के 100 मेगावाट के सौर पार्क के निर्माण के लिए एक टेंडर जीतने नवंबर 2018 में द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग को बढ़ावा मिला।

ऑस्ट्रिया

यूरोप, एकीकरण और विदेश मामलों के ऑस्ट्रियाई संघीय मंत्री सुश्री करिन कनीसल ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से न्यूयॉर्क में, सितंबर 2018 में द्विपक्षीय बैठक के लिए विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज से भेंट की।

ऑस्ट्रियाई राज्य के वित्त सचिव डॉ. ह्यूबर्ट फुच्स ने 23 जून 2018 को एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वार्षिक बैठक के लिए मुंबई का दौरा किया।

पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान 7वीं ओपेक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने के लिए ने 19 से 20 जून 2018 तक वियना की आधिकारिक यात्रा की।

केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा ने मई 2018 में अपनी वियना यात्रा के दौरान, ऑस्ट्रिया में भारतीय वस्त्रों के प्रचार के लिए भविष्य के रोडमैप पर चर्चा की।

पूर्व विदेश मंत्री श्री एम. जे. अकबर ने 15 मई, 2018 को वियना में यूरोप, एकीकरण और विदेश मामलों की विदेश मंत्री सुश्री करिन कनिस्ल से भेंट की।

आयुष और मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ ग्राज़ के सहयोग से 25-27 सितंबर 2018 को आयुर्वेद, योग और ध्यान और सक्रिय और स्वस्थ बुढ़ापे के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। आयुर्वेद और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ़ ग्राज़ के वाइस रेक्टर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

बोस्निया और हर्ज़ेगोविना

बोस्निया और हर्ज़ेगोविना के विदेश व्यापार और अर्थव्यवस्था मंत्रालय के उप मंत्री श्री माटो फ्रांजिसविक द्वारा मोस्टार में 21वें अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मेले (10-14 अप्रैल 2018) में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया गया था। ट्रेड फेयर के मौके पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सेंटर फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मोस्टार (सीआईआरपी) और फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी (एफआईपीए) द्वारा हर्जेगोविना की निवेश संभावनाओं पर आयोजित सम्मेलन में भाग लिया।

एक 15 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 25-26 अप्रैल 2018 को साराजेवो बिजनेस फोरम का दौरा किया, जिसमें श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, (एसआरएमसी), चेन्नई और श्री सुहास मंत्री, मुंबई में बीआईएच के मानद महावाणिज्यदूत शामिल थे।

फ्रैंकफर्ट में भारत सरकार के पर्यटन कार्यालय ने 24-26 अक्टूबर 2018 से 40वें साराजेवो पर्यटन महोत्सव में भाग लिया। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री श्री डेनिस ज़विज़्डिक और फेडरेशन ऑफ बिह के अन्य मंत्रियों ने भाग लिया।

बुल्गारिया

राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने 4-6 सितंबर 2018 तक बुल्गारिया की राजकीय यात्रा की। अपनी यात्रा के समय, सोफिया में बड़ी संख्या में कंपनियों की भागीदारी के साथ भारत-बुल्गारिया व्यापार मंच आयोजित किया गया था और भारत और बुल्गारिया के राष्ट्रपतियों द्वारा इसे संबोधित किया गया था। गांधीजी की 150वीं वर्षगांठ समारोह की पूर्व संध्या पर बल्गेरियाई मूर्तिकार इवान रुसेव द्वारा बनाई गई महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का भारत और बुल्गारिया के राष्ट्रपतियों द्वारा अनावरण किया गया था। यात्रा के दौरान निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, असैन्य परमाणु ऊर्जा, पर्यटन और सोफिया विश्वविद्यालय में हिंदी चेयर की स्थापना के क्षेत्र में सहयोग पर पांच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर संयुक्त कार्य समूह की नौवीं बैठक अगस्त 2018 में सोफिया में आयोजित की गई थी, जिसमें 2018-2021 के लिए सहयोग के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया था।

वस्त्र राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा ने 8-11 मई 2018 तक बुल्गारिया का दौरा किया और बल्गेरियाई अर्थव्यवस्था मंत्री से भेंट की।

भारत ने 24-29 सितंबर, 2018 के दौरान 74वें अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मेले प्लोवदीव में भाग लिया, जिसमें 47 भारतीय कंपनियों के साथ एसोचैम ने भी भाग लिया।

क्रोएशिया

क्रोएशिया गणराज्य की विदेश और यूरोपीय मामलों की मंत्री सुश्री मारिजा पाजिनकोविच बुरिक ने 22 अक्टूबर 2018 को भारत का दौरा किया। उन्होंने विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज और लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन से भेंट की। यात्रा के दौरान वर्ष 2019-2022 के लिए सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम (सीईपी) और राजनयिक मिशनों या कांसुलर पदों के सदस्यों के परिवार के सदस्यों के लिए लाभकारी व्यवसाय पर समझौते सहित दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

क्रोएशिया गणराज्य के पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रालय के राज्य सचिव, श्री मारियो सिलजेग ने 29 सितंबर - 02 अक्टूबर 2018 से महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन में भाग लिया।

साइप्रस

राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने 2-4 सितंबर 2018 को साइप्रस की राजकीय यात्रा की। उन्होंने साइप्रस के राष्ट्रपति, श्री निकोस अनास्तासीड्स, प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष, श्री डेमेट्रीस सिलेरियस से भेंट की और प्रतिनिधि सभा के वेशेष सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने साइप्रस के विश्वविद्यालय में रवीन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। दो समझौता ज्ञापनों (पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग और भारत के एफआईयू और साइप्रस के मोकास के बीच धन शोधन पर सूचना के आदान-प्रदान) पर हस्ताक्षर किए गए।

चेक गणराज्य

राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने 6-9 सितंबर 2018 तक चेक गणराज्य की राजकीय यात्रा की और राष्ट्रपति श्री मिलो जोमैन से भेंट की। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री लेडी बाबिस, स्पीकर राडकोवंड्रैक से भी भेंट की और चेक-इंडियन बिजनेस फोरम को संबोधित किया।

यात्रा के दौरान आठ समझौतों/समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए - जिनमें डिप्लोमैटिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट; चेक एकेडमी ऑफ साइंसेज और सीएसआईआर के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग पर समझौता ज्ञापन; डीएसटी और एम/ओ युवा, शिक्षा और खेल के बीच संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं पर कार्य योजना; टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और ईएलआई बीमलाइन के बीच लेजर अनुसंधान पर समझौता; हिसार कृषि विश्वविद्यालय और चेक यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेज के बीच समझौता ज्ञापन; भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) और टाटरा ट्रकों के बीच समझौता ज्ञापन, पीएचडीसीसीआई और एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज़ एंटरप्राइजेज एंड क्राफ्ट्स सीजेड और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के संकाय, यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स प्राग और आईआईएम, बैंगलोर के बीच समझौता ज्ञापन शामिल हैं।

वाणिज्य और उद्योग और उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के राज्य मंत्री, श्री सी आर चौधरी, ने 22-23 अक्टूबर, 2018 से प्राग में आयोजित भारत-चेक गणराज्य संयुक्त आर्थिक आयोग (जेसीईसी) के 11वें सत्र के लिए चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। व्यापार और उद्योग मंत्री, सुश्री मार्टा नोवाकोवा के साथ एक संयुक्त प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों तरफ निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों, इन्वेस्ट इंडिया और चेकइनवेस्ट के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए थे।

चेन्नई में इंडिया इंटरनेशनल सोर्सिंग फेयर (आईईएसएस) 2018 के अवसर पर नई दिल्ली में 8 मार्च 2018 को भारी उद्योग पर 5वें जेडब्ल्यूजी का आयोजन किया गया। बैठक की सह-अध्यक्षता श्री एन शिवानंद, संयुक्त सचिव एमओएचआई और पीई, और चेक की तरफ से उद्योग और व्यापार मंत्रालय के वरिष्ठ महानिदेशक रिचर्ड हलवट ने की।

वोक्सवैगन समूह ने नई परियोजना इंडिया 2.0 में 1 बिलियन यूरो के निवेश की घोषणा की, जिसका स्कोडा ऑटो कंपनी द्वारा पर्यवेक्षण किया जाएगा, ताकि पुणे के संयंत्र से भारतीय बाजार के लिए विशेष रूप से नए मॉडल विकसित किए जा सकें।

भारत और चेक गणराज्य के बीच कांसुलर परामर्श का चौथा दौर 22 अप्रैल 2018 को प्राग में आयोजित किया गया था।

उद्योग और व्यापार मंत्री श्री टॉमस हूनर के नेतृत्व में 35 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 13 कंपनियों के साथ दिल्ली में इंडिया-ईयू 29 बिजनेस फोरम और चेन्नई में इंडिया इंजीनियरिंग सोर्स शो में भाग लेने के लिए, 4-10 मार्च 2018 तक भारत का दौरा किया, चेक गणतंत्र इसमें एक भागीदार देश था।

व्यापार और उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ महानिदेशक श्री रिचर्ड हलवट ने बेंगलुरु में चेक इंडस्ट्रियल क्लस्टर (सीआईसी) के शुभारंभ के लिए 25 नवंबर से 1 दिसंबर 2018 तक भारत में एक औद्योगिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

चेक सरकार ने भारत में 1 अक्टूबर 2018 से 'विशेष योग्यताओं के लिए विशेष प्रक्रियाएँ' नाम की एक विशेष परियोजना शुरू की है, जहाँ अधिमानतः 500 आवेदन के वार्षिक कोटा के साथ भारत से अत्यधिक कुशल श्रमिकों के रोजगार परमिट के लिए आवेदन पत्र प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार किए जाएंगे।

चेक गणराज्य ने भारत में बेंगलुरु और चेन्नई में (दिल्ली में अपने दूतावास के अलावा और मुंबई और कोलकाता में दो मानद वाणिज्य दूतावासों में) दो नए मानद वाणिज्य दूतावास खोले।

डेनमार्क

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 17 अप्रैल 2018 को स्टॉकहोम में भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान डेनमार्क के प्रधानमंत्री श्री लार्स लोके रस्मुसेन से भेंट की। नौ वर्ष के अंतराल के बाद प्रधानमंत्री स्तर पर यह पहली बैठक थी। बैठक के दौरान पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में सहयोग पर; सतत और स्मार्ट शहरी विकास के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन; कृषि अनुसंधान और शिक्षा में सहयोग पर समझौता ज्ञापन और खाद्य सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन, कुल चार समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया।

डेनमार्क के विदेश मंत्री, श्री एंडर्स सैमुअलसेनमेट उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने 19 अक्टूबर 2018 को ब्रुसेल्स में 12वें एएसईएम शिखर सम्मेलन के अवसर पर बैठक की।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कोपेनहेगन में आयोजित 9वें स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय (सीईएम 9) और माल्मो (स्वीडन) में आयोजित तीसरे मिशन नवाचार मंत्री स्तरीय (एमआई3) में भाग लेने के लिए 21-24 मई 2018 के दौरान डेनमार्क का दौरा किया।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल 30 अगस्त से 01 सितंबर 2018 तक विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए डेनमार्क गईं। मंत्री ने उद्योग, व्यापार और वित्तीय मामलों के मंत्री, श्री रासमस जारलोव और पर्यावरण और खाद्य मंत्री, श्री जैकब एलेमन-जेन्सेन से भेंट की।

महाराष्ट्र विधान परिषद के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र विधान परिषद के अध्यक्ष, श्री रामराजे नाइक निम्बालकर के नेतृत्व में 18-19 अप्रैल 2018 के दौरान कोपेनहेगन का दौरा किया।

श्री गोपाल कृष्ण, सचिव (नौवहन) ने 28-31 मई 2018 तक दौरा किया। यात्रा के दौरान शिपिंग पर पहले संयुक्त कार्य समूह का आयोजन किया गया था।

सड़क परिवहन और राजमार्ग के सचिव श्री युधवीर सिंह मलिक ने 1-2 नवंबर 2018 से दौरा किया।

श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, सचिव, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 21 से 23 नवंबर 2018 तक दौरा किया। यात्रा के दौरान शहरी विकास पर संयुक्त कार्य समूह आयोजित किया गया।

श्री मनीष गुप्ता, संयुक्त सचिव (ओआईए-I) 8-9 अगस्त 2018 को कोपेनहेगन में श्रम गतिशीलता पर संयुक्त कार्य समूह के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

इस अवधि के दौरान भारत और डेनमार्क के बीच संयुक्त कार्य समूह की निम्नलिखित बैठकें हुईं- i) कृषि और पशुपालन पर संयुक्त कार्य समूह (दिल्ली में 16 मई 2018); ii) खाद्य प्रसंस्करण पर संयुक्त कार्य समूह (दिल्ली में 17 मई 2018); iii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर संयुक्त कार्य समूह (कोपेनहेगन में 22 मई 2018); iv) शिपिंग पर संयुक्त कार्य समूह (कोपेनहेगन में 28-31 मई 2018); v) श्रम गतिशीलता पर संयुक्त कार्य समूह (कोपेनहेगन में 8-9

प्रधान मंत्री स्टॉकहोम में आयोजित प्रथम भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में स्वीडन, डेनमार्क, आईसलैंड, नॉर्वे तथा फिनलैंड से नॉर्डिक प्रधान मंत्रियों के साथ (17 अप्रैल, 2018)

अगस्त 2018); vi) नवीकरणीय ऊर्जा पर दूसरा संयुक्त कार्य समूह (दिल्ली में 4 अक्टूबर 2018); vii) पर्यावरण पर संयुक्त कार्य समूह (कोपेनहेगन में 29-31 अक्टूबर 2018); और viii) शहरी विकास पर संयुक्त कार्य समूह (कोपेनहेगन में 21-23 नवंबर 2018)।

एस्तोनिया

कर्नाटक के आईटी, बीटी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री के जे जॉर्ज ने 26-27 अगस्त, 2018 को एस्टोनिया का दौरा किया।

तेलंगाना और एस्टोनिया सरकार ने अक्टूबर 2018 में डिजिटल प्रथाओं, ई-गवर्नेंस और संबंधित क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

फिनलैंड

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 17 अप्रैल, 2018 को स्वीडन के स्टॉकहोम में पहले भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री श्री जुहासिपिला से भेंट की।

फ़िनलैंड के ऊर्जा, आवास और पर्यावरण मंत्री किमो टिलिकेनन ने 18 से 21 अप्रैल 2018 तक भारत का दौरा किया।

लोकसभा अध्यक्ष, श्रीमती सुमित्रा महाजन ने छह संसद सदस्यों के साथ 17 से 18 जून 2018 तक फिनलैंड का दौरा किया।

ग्रीस (यूनान)

राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने 16 से 19 जून 2018 तक हेलेनिक गणराज्य की एक राजकीय यात्रा की और ग्रीक राष्ट्रपति श्री प्रोकोपियोस पावलोपोलोस से भेंट की। उन्होंने यूनानी राष्ट्रपति पावलोपोलोस और प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास से भेंट की। विपक्ष के नेता, श्री कायरकोस मित्सोटाकिस ने राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद से भेंट की। यात्रा के दौरान मानकीकरण के क्षेत्र में सहयोग; वर्ष 2018-2020 के लिए राजनयिक प्रशिक्षण में सहयोग और सांस्कृतिक सहयोग के कार्यक्रम के तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने

भारत-ग्रीस बिजनेस फोरम और हेलेनिक फ़ाउंडेशन फ़ॉर यूरोप एंड फॉरेन पॉलिसी (ईएलआईएएमईपी) को संबोधित किया। उन्होंने थिस्सलोनिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 के लिए भारत को "सम्मानित देश" के रूप में आमंत्रित करने के लिए ग्रीस को धन्यवाद दिया।

उपराष्ट्रपति, श्री एम. वेंकैया नायडू ने 18 अक्टूबर 2018 को ब्रसेल्स में एएसईएम शिखर सम्मेलन 2018 के मौके पर ग्रीक प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास के साथ भेंट की।

कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने 17-19 अप्रैल 2018 को ग्रीस की आधिकारिक यात्रा की और ग्रीक के कृषि विकास और खाद्य मंत्री, श्री इवांजेलोस ऑपोस्तोपोलोस और हेलेनिक संसद के अध्यक्ष श्री निकोस वाउटीस से भेंट की।

होली सी

यह वर्ष भारत और द होली सी के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है।

हंगरी

पूर्व विदेश राज्य मंत्री श्री एम. जे. अकबर ने 4 मई 2018 को 'आतंकवाद प्रतिरोध और हिंसात्मक कट्टरता को रोकने' पर उच्च-स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के मौके पर, विदेश मामलों के मंत्री, श्री पीटर सज्जिजर्तो और हंगरी के व्यापार मंत्री से दुशांबे में भेंट की।

भारत के राज्यों को बढ़ावा देने के लिए- उनकी आर्थिक, पाक और पर्यटन क्षमता पर एक कार्यक्रम 12 मई 2018 को आयोजित किया गया था। आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हैदराबाद, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के राज्यों और उनकी ''मेक इन इंडिया'' क्षमता का प्रदर्शन किया गया।

15 जून 2018 को, गुड़गांव स्थित बहुराष्ट्रीय समूह एसआरएफ लिमिटेड ने जसज़फेनज़ारू (बुडापेस्ट के पास) शहर में एक पैकेजिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की।

हंगरी के 22 शहरों में 23-24 जून 2018 से "गंगा-डेन्यूब कल्चरल फेस्टिवल ऑफ इंडिया" का तीसरा संस्करण मनाया गया। उत्सव में योग, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, संगीत, लोक कला, फिल्मों और गैस्ट्रोनॉमी का प्रदर्शन किया गया।

भारत के ईयू चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स (सीईयूसीसीआई) की परिषद और हंगेरियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एचसीसीआई) के बीच भविष्य में सहयोग पर 25 जून 2018 को, बुडापेस्ट में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

ईएलटीई विश्वविद्यालय में हिंदी चेयर की निरंतरता के लिए आईसीसीआर और बुडापेस्ट के ईएलटीई विश्वविद्यालय के बीच 19 सितंबर 2018 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) की एक पहल वर्ल्ड स्किल्स इंडिया के एक प्रतिनिधिमंडल ने 24-29 सितंबर, 2018 को हंगरी का दौरा किया, जो हेंगज़ेपो के यूरोस्किल्स कार्यक्रमों में एक अतिथि देश के रूप में भाग लेने और विश्व कौशल प्रतियोगिता के लिए खुद को तैयार करने के लिए गई थी।

बुडापेस्ट के पुस्किन सिनेमा में 4-10 अक्टूबर, 2018 से पाँचवें भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया।

भारत और हंगरी के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए, विदेश मंत्रालय और हंगरी के व्यापार ने 13 नवंबर 2018 को बुडापेस्ट में पहले हंगेरियन इंडियन फिल्म एंड टूरिज्म सिम्पोजियम का आयोजन किया। संगोष्ठी का उद्घाटन विदेश मंत्रालय और व्यापार मंत्रालय में उप राज्य सचिव सुश्री सीसिलिया स्ज़िलस द्वारा किया गया था।

हंगरी के विदेश मंत्री, श्री पीटर स्ज़िजार्तो ने यूफ्लेक्स इंडिया लि की सहायक कंपनी मेसर्स फ्लेक्स फिल्म्स यूरोपा द्वारा 21 नवंबर 2018 को 71.50 मिलियन यूरो के ग्रीनफील्ड निवेश की घोषणा की गई। कंपनी रेत्साग में एक लचीली पैकेजिंग सामग्री का उत्पादन संयंत्र स्थापित करेगी।

आइसलैंड

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 17 अप्रैल, 2018 को स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित भारत - नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान आइसलैंड के प्रधान मंत्री, सुश्री कैटरीन जैकोब्स्दोतिर से भेंट की।

आइसलैंड विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा के लिए आईसीसीआर अध्यक्ष की स्थापना के लिए 12 अप्रैल 2018 को आईसीसीआर और आइसलैंड विश्वविद्यालय द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 17 अप्रैल, 2018 को स्वीडन के स्टॉकहोम में भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भारत और आइसलैंड के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान हुआ।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री श्री एस एस अहलूवालिया ने 5-8 जून 2018 को आइसलैंड का दौरा किया। यात्रा के दौरान, मंत्री ने आइसलैंड के राष्ट्रपति श्री गुदनी थ. जोहानिसन से भेंट की और पर्यटन, उद्योग और नवाचार मंत्री सुश्री थोरोडिसकोलब्रनगिलफैडॉटिर; वित्त और आर्थिक मंत्री श्री बंजनी बेनेडिकटसन और परिवहन और आइसलैंड की स्थानीय सरकार के मंत्री श्री सिग्रुदुरिंजी जोहानसन से भेंट की ।

रेकजाविक में 19-21 अक्टूबर 2018 से आयोजित पाँचवीं आर्कटिक सर्कल सभा में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डॉ विजय कुमार, वैज्ञानिक जी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया था।

लिकटेंस्टीन

भारत और लिकटेंस्टीन इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना की 25 वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।

वंशानुगत राजकुमार, श्री अलोइस ने भारत का दौरा किया और 12 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद से तथा 10 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री से भेंट की।

वादुज, लिकटेंस्टीन में 11 अक्टूबर 2018 को भारतीय गणराज्य और लिकटेंस्टीन की रियासत के बीच वित्तीय खाता सूचना के स्वचालित विनिमय के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

लिथुआनिया

भारत और लिथुआनिया में सौहार्दपूर्ण संबंध हैं, जो करीबी सांस्कृतिक संबंधों द्वारा चिह्नित है। लिथुआनियाई विश्वविद्यालयों में इंडोलॉजी के अध्ययन की एक मजबूत परंपरा मौजूद है।

भारतीय निवेश (इंडोरामा समूह) 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। सितंबर 2018 में एक समर्पित भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की गई।

लातविया

लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन के नेतृत्व में 12 सदस्यीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने 13 से 17 जून 2018 तक लातविया का दौरा किया। उन्होंने लातविया के प्रधानमंत्री श्री माक्रसुकिंस्किन से भेंट की।

जून 2018 में लातविया विश्वविद्यालय में एक आयुर्वेद चेयर स्थापित किया गया है।

ग्लोबल नेटवर्क के श्री जगत शाह के नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जनवरी 2019 में होने वाले वाइब्रेंट गुजरात समिट के 9वें संस्करण का प्रचार करने के लिए 17 से 22 अक्टूबर 2018 तक रीगा, लातविया का दौरा किया।

मैसेडोनिया

वस्त्र राज्य मंत्री, श्री अजय टम्टा ने 6-8 मई 2018 तक मैसिडोनिया का दौरा किया। उन्होंने मैसेडोनिया के अर्थव्यवस्था मंत्री श्री कृशनिक बेक्तेशी के साथ विचार-विमर्श किया।

भारतीय कंपनी इंडस मेडिका ने 14 नवंबर 2018 को स्कोप्जे में 3 मिलियन यूरो के निवेश के साथ एक उच्च तकनीकी चिकित्सा प्रयोगशाला खोली, जो इस वर्ष मैसेडोनिया में सबसे बड़ा भारतीय निवेश है। कंपनी अपने बेस के रूप में मैसेडोनिया के साथ बाल्कन क्षेत्र में 5 और निवेश की योजना बना रही है।

माल्टा

द्वितीय भारत-माल्टा विदेश कार्यालय परामर्श 20 अप्रैल 2018 को माल्टा में आयोजित किए गए थे। पूर्व विदेश राज्य मंत्री श्री एम जे अकबर 8-10 जुलाई 2018 से माल्टा की एक आधिकारिक यात्रा पर गए थे, उन्होंने विदेश मंत्री श्री कारमेलो अबेला से भेंट की। उन्होंने माल्टा की राष्ट्रपति सुश्री मैरी लुईस कोलेरोप्राइका और माल्टा के प्रधानमंत्री डॉ जोसेफ मस्कट से भेंट की। भारत के उपराष्ट्रपति, श्री एम वेंकैया नायडू, ने 16-18 सितंबर 2018 तक माल्टा की आधिकारिक यात्रा की और माल्टा की राष्ट्रपति, सुश्री मैरी लुईस कोलेरोप्राइका से भेंट की। उपराष्ट्रपति ने प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष डॉ. एंजेलो फारुगिया, कार्यवाहक प्रधानमंत्री और अर्थव्यवस्था के मंत्री डॉ. क्रिश्चियन सोनोना के साथ बैठकें कीं। विपक्ष के नेता डॉ. एड्रियन डेलिया ने उपराष्ट्रपति से भेंट की। यात्रा के दौरान भारत के नौवहन मंत्रालय और माल्टा के परिवहन, इन्फ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल प्रोजेक्ट्स के बीच समुद्री सहयोग; विदेशी सेवा संस्थान, भारत और भूमध्यसागरीय अकादमी के राजनयिक अध्ययन, माल्टा विश्वविद्यालय के बीच पारस्परिक सहयोग और भारत और माल्टा के बीच पर्यटन सहयोग पर तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

स्थानीय सरकार और माल्टा के संसदीय सचिव श्री सिल्वियो पर्निस ने 29 सितंबर से 2 अक्टूबर 2018 तक नई दिल्ली में आयोजित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता (एमजीआईएस) सम्मेलन में मालदीव प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

मालडोवा

विदेश मामलों और मोल्दोवा के यूरोपीय एकीकरण के मंत्री श्री टुडोर उलियानोव्स्की ने 11 से 15 अगस्त 2018 तक भारत की आधिकारिक यात्रा की और 14 अगस्त 2018 को विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज से भेंट की। उन्होंने वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री सुरेश पी प्रभु और कृषि और किसान कल्याण मंत्री, श्री राधा मोहन सिंह से भी भेंट की।

मोंटेनेग्रो

मोंटेनेग्रो के साथ भारत के घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और मोंटेनेग्रो में भारत के लिए मित्रता की सद्भावना है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन 25 जून, 2018 को मोंटेनेग्रो में किया गया था और मोंटेनेग्रो के अधिकारियों और पॉडगोरिका में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में बहुत अच्छी उपस्थिति थी।

नॉर्वे

भारत और नॉर्वे के प्रधानमंत्री 17 अप्रैल 2018 को भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के मौके पर स्टॉकहोम में मिले थे। महाराष्ट्र विधान परिषद के अध्यक्ष श्री रामराजे नाइक निंबालकर के नेतृत्व में 11 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा

प्रतिनिधिमंडल 19-21 अप्रैल को एक अध्ययन यात्रा पर ओस्लो का दौरा किया।

भारतीय नौसेना के एक सेल ट्रेनिंग शिप, आईएनएस तरंगिनी ने हार्लिंगन से स्टवान्गर तक 'लंबे जहाजों की दौड़ 2018' की रेस 2 में भाग लेने के 26 से 29 जुलाई 2018 तक नॉर्वे में स्टवान्गर गया था।

सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव, श्री युधवीर सिंह मलिक के नेतृत्व में 5-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 28 से 30 अक्टूबर, 2018 को नॉर्वे में सुरंग तकनीक के एक अध्ययन दौरे पर नॉर्वे का दौरा किया।

भारतीय कानूनी विद्वान डॉ. तरुणाभ खेतान को भेदभाव और असमानता के खिलाफ उनके काम के लिए नोकिया 2 मिलियन का पहला नॉर्वेजियन लेटन्ट पुरस्कार एक दिया गया था।

पोलैंड

आठवां एफओसी 19 जनवरी 2018 को आयोजित किया गया था, इसकी सह अध्यक्षता पोलैंड की ओर से उप विदेश मंत्री और भारत की ओर से सचिव (पश्चिम) द्वारा की गई।

बिहार से एक तीन सदस्य मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी के नेतृत्व में और पश्चिम बंगाल से एक दो सदस्य प्रतिनिधिमंडल विद्युत एवं गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री श्री शोभन देब चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में 14-15 मई 2018 को यूरोपीय आर्थिक कांग्रेस में भाग लेने के लिए कटोविस गया था ।

पोलैंड की वित्त मंत्री सुश्री टेरेसा जेरविंस्का ने एशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश बैंक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के 25-26 से जून 2018 मुंबई का दौरा किया। सुश्री जेरविंस्का ने अपनी यात्रा के दौरान वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली से भेंट की।

पर्यावरण मंत्रालय के राज्य सचिव और सीओपी 24 के अध्यक्ष श्री मिशल कुर्तिका ने 10-11 सितंबर 2018 को भारत का दौरा किया और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन से भेंट की।

भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद (टीपीसीआई) के अध्यक्ष ने 14-15 जनवरी 2019 को ग्रेटर नोएडा में भारत एक्सपो मार्ट में आयोजित होने वाले टीपीसीआई की प्रमुख घटना 'इंडसफूड-द्वितीय' के दूसरे संस्करण के प्रचार के लिए 13-14 सितंबर 2018 से वारसॉ का दौरा किया।

पादप स्वास्थ्य के मुख्य निरीक्षणालय और बीज निरीक्षण के प्रतिनिधि श्री अलेक्जेंडर हैंकविज़ ने 25 सितंबर 2018 को पादप स्वास्थ्य पर यूरोपीय यूनियन कार्य समूह में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के सचिव श्री सी. के. मिश्रा ने दिसंबर 2018 में सीओपी24 की तैयारी में 22-24 अक्टूबर, 2018 को क्राको में आयोजित सीओपी24 से पहले के सम्मेलन के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। सचिव (एमओईएफसीसी) ने अपने पोलिश समकक्ष पर्यावरण मंत्री और सीओपी 24 के अध्यक्ष मिशल कुर्तिका, से भेंट की।

भारत पर्यटन कार्यालय, फ्रैंकफर्ट ने 22-24 नवंबर 2018 से वारसा में टीटी वारसॉ पर्यटन व्यापार मेले में भाग लिया।

रोमानिया

उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने 18 - 20 सितंबर 2018 को रोमानिया का दौरा किया। उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चैंबर ऑफ डेप्युटीज़ ऑफ पार्लियामेंट के अध्यक्ष सहित रोमानियाई नेताओं से भेंट की। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने एक आयुष सूचना प्रकोष्ठ का उद्घाटन किया और आयुर्वेद पर एक पुस्तक का विमोचन भी किया। यात्रा के दौरान पेट्रोलियम-गैस विश्वविद्यालय, प्लियोस्टी और पंडित दीन दयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, गांधीनगर के बीच पर्यटन पर सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए तथा बुखारेस्ट चैंबर ऑफ कॉमर्स ने सीआईआई, एसोकैम और पीएचडीसीसीआई प्रत्येक के साथ 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए

रोमानिया के विदेश मंत्री श्री टेओडोर मेलेस्कैनु 24-27 नवंबर 2018 को भारत आए थे। उन्होंने विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री पंकज सरन से भेंट की।

सर्बिया

भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू 14-16 सितंबर 2018 को सर्बिया की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। यात्रा के दौरान, उन्होंने सर्बिया के राष्ट्रपति श्री अलेक्जेंडर वूसिक, सर्बिया के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष, सुश्री मेजा गोजकोविक और प्रधानमंत्री सुश्री एना ब्रैनबिक से भेंट की। agreement. यात्रा के दौरान पादप संरक्षण और संगरोध और संशोधित हवाई सेवा समझौते के दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। यात्रा के दौरान, सर्बिया पोस्ट और भारतीय डाक विभाग ने संयुक्त रूप से राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सर्बियाई वैज्ञानिक और आविष्कारक, निकोला टेस्ला और स्वामी विवेकानंद पर स्मारक डाक टिकट जारी किए।

सर्बिया की प्रथम उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री श्री इविका डैसिक ने 1-4 मई 2018 को भारत की आधिकारिक यात्रा की और विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज से भेंट की। संस्कृति, कला, युवा, खेल और मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के एक समझौते पर दोनों मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए।

रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अप्रैल 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा (एमसीआईएस 2018) के सातवें मास्को सम्मेलन के मौके पर सर्बिया के रक्षा मंत्री श्री अलेक्जेंडर वुलिन से भेंट की।

भारत 9-13 अक्टूबर 2018 से नृवंशविज्ञान संग्रहालय बेलग्रेड द्वारा आयोजित नृवंशविज्ञान फिल्म के 27वें अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में 'ध्यान केंद्रित देश' था।

स्लोवाक गणराज्य

पूर्व विदेश राज्य मंत्री श्री एम जे अकबर एक वक्ता के रूप में ग्लोबसेक 2018 ब्रातिस्लावा फोरम में भाग लेने और श्री रिचर्ड रासी, निवेश और संचार के उप प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री श्री पीटर गजडोस; विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्री श्री मिरोस्लाव लजाक, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 72वें अध्यक्ष और विदेशी और यूरोपीय मामलों के मंत्रालय में राज्य सचिव श्री लुकास परिजेक के साथ आयोजित बैठकों में भाग लेने के लिए 17-19 मई 2018 को ब्रातिस्लावा का दौरा किया।

नितारा में भारत के टाटा समूह के स्वामित्व वाले जगुआर लैंड रोवर ऑटोमोबाइल विनिर्माण संयंत्र ने 25 अक्टूबर, 2018 को अपना उत्पादन शुरू किया। स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री श्री पीटर पेलेग्रिनी द्वारा आधिकारिक तौर पर संयंत्र का उद्घाटन किया गया था।

स्लोवेनिया

जुलाई 2018 में, दो भारतीय महिला पायलटों, केथिर मिसक्विटा और आरोही पंडित ने एक छोटे से स्लोवेनिया निर्मित पिपिस्ट्रेल साइनस लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट में विश्व की यात्रा करते हुए स्लोवेनिया में दो दिन रुकी थीं ।

21- 23 सितंबर 2018 से एकीकृत चिकित्सा के लिए 11 वीं यूरोपीय कांग्रेस के एक भाग के रूप में अल्मा मेटर यूरोपिया, एक स्थानीय विश्वविद्यालय, एकीकृत चिकित्सा की यूरोपीय कांग्रेस (ईसीआईएम) और आयुष मंत्रालय ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया।

स्वीडन

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लगभग तीन दशकों के अंतराल के बाद 16-17 अप्रैल 2018 तक स्वीडन की आधिकारिक यात्रा की। भारत और स्वीडन ने स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड के नॉर्डिक नेताओं के साथ संयुक्त रूप से पहली बार 'भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन' की मेजबानी की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजा कार्ल सोलहवें गुस्ताफ से भेंट की। भारत और स्वीडन के बीच स्थायी भविष्य पर भारत-स्वीडन नवाचार भागीदारी और एक संयुक्त कार्य

योजना के दो दस्तावेजों पर सहमति बनी। दोनों प्रधानमंत्रियों ने शीर्ष स्वीडिश सीईओ के साथ एक गोलमेज बैठक को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने स्टॉकहोम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में स्वीडिश पीएम श्री स्टीफन लोफवेन ने भी भाग लिया। विपक्ष के नेता और स्वीडिश संसद में मॉडरेट पार्टी के नेता, श्री उल्फ़ क्रिस्टर्ससन ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भी भेंट की।

श्री हरिभाऊ बैगड, अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान परिषद सहित एक 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र विधान परिषद श्री रामराजे नाईक निंबालकर के नेतृत्व में 23 अप्रैल 2018 को स्वीडन का दौरा किया।

श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, सचिव, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सह संचालन पर इंडो-स्वीडिश समझौता ज्ञापन के अंतर्गत आयोजित इंडो-स्वीडिश संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक में भाग लेने के लिए 2-4 मई 2018 तक स्वीडन का दौरा किया था।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 22-23 मई 2018 को स्वीडन से मिशन इनोवेशन-3 मंत्रिस्तरीय और नौवीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया और उद्यम और नवाचार के स्वीडिश मंत्री मिकेल डेमबर्ग से भेंट की।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव, श्रीमती रेणु स्वरूप के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की स्वीडन यात्रा के समय हस्ताक्षरित संयुक्त घोषणा के अनुसार स्वीडिश अनुसंधान परिषद नवाचार इनक्यूबेटर साझेदारी और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास के लिए रणनीति विकसित करने के लिए विन्नोवा के साथ बैठक करने के उद्देश्य से 20-22 अगस्त 2018 को स्वीडन का दौरा किया।

श्री सी पी गुरनानी, सीईओ, टेक महिंद्रा के नेतृत्व में सीआईआई के एक 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत-स्वीडन व्यापार जगत के नेताओं की गोलमेज के डिजिटलीकरण पर (आईएसबीएलआरटी) जेडब्ल्यूजी के लिए 22-23 से अगस्त 2018 को स्वीडन का दौरा किया।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव श्रीमती प्रीति सूदन के नेतृत्व में 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने स्टॉकहोम में मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य (पीएमएनसीएच) बोर्ड रिट्रीट में भाग लेने के लिए 28-30 अगस्त 2018 तक स्वीडन का दौरा किया।

भारत और स्वीडन के बीच साइबर सुरक्षा के संयुक्त कार्य बल की स्थापना की संभावना का पता लगाने के लिए भारत के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक श्री (डॉ) गुलशन राय के नेतृत्व में 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 2-5 सितंबर 2018 तक स्वीडन का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने स्वीडिश प्रधानमंत्री के राज्य सचिव श्री हंस डाहलग्रेन से भेंट की।

प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. श्री के. विजय राघवन ने 2-4 सितंबर 2018 से स्टॉकहोम टेक फेस्ट 2018 में भाग लेने के लिए 10 स्टार्टअप के एक इन्वेस्ट इंडिया प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

स्विट्जरलैंड

स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री डॉ. इग्नाजियो कैसिस ने 8 से 12 अगस्त 2018 तक भारत का दौरा किया और विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के साथ भेंट की।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा ने 19 मई 2018 को स्विट्जरलैंड का दौरा किया और ज्यूरिख में स्विस स्वास्थ्य और दवा उद्योग के प्रमुख हितधारकों के साथ एक बैठक की।

विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) ने 26 नवंबर 2018 को बर्न का दौरा किया।

महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल के दो अलग-अलग प्रतिनिधियों ने फरवरी और अप्रैल 2018 में स्विट्जरलैंड का दौरा किया।

स्विस सांसद श्री निकलॉस शमूएल दुगेर और मेयर जीन फिलिप पिंटो ने नई दिल्ली में 9 जनवरी 2018 को आयोजित पहली पीआईओ सांसद सम्मेलन में भाग लिया।

भारत-स्विट्जरलैंड कॉन्सुलर संवाद का चौथा दौर 11 मई 2018 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

तुर्की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति श्री रिसेप तईप एरडोगन ने 25-27 जुलाई 2018 को जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स प्लस बैठक के समय एक दूसरे के साथ बातचीत की।

इस्तांबुल में ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क द्वारा 16-18 अप्रैल 2018 को आयोजित ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप कांग्रेस में नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत के नेतृत्व में तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया और तुर्की के विकास मंत्री श्री लुत्फी एलवान से भी भेंट की।

यूरोपीय संघ

यूरोपीय संघ (ईयू) अट्ठाईस देशों की, एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति का एक ब्लॉक है और 16.4 खरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के सकल घरेलू उत्पाद के साथ सबसे बड़े एकल बाजार अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। यह भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार (सेवाओं में शामिल) है जिसका मूल्य पिछले वित्तीय वर्ष में 136 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। माल का कुल व्यापार 101 बिलियन अमेरिकी डॉलर और सेवाओं में कुल व्यापार 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। यूरोपीय संघ भारत में 91 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अप्रैल 2000 से जून 2018 तक) के समेकित निवेश के साथ भारत में सबसे बड़े एफडीआई प्रवाह का स्रोत भी है। 2017-18 में भारत यूरोपीय संघ का नौवां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार था।

यूरोपीय संघ और भारत ने, लोकतंत्र, बहुलवाद, मानवाधिकार, कानून के शासन, बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता और एक नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय आदेश और विविध लोगों की यूनियनों के कई समानताएं होने के आधार पर, 2004 में एक रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया। इन वर्षों में, भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों का विस्तार हुआ है और इनकी ताकत तक बढ़ी है।

भारत ने "भारत पर यूरोपीय संघ की रणनीति के तत्व - स्थायी आधुनिकीकरण और नियमों पर आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए साझेदारी" शीर्षक के साथ यूरोपीय आयोग की 2018 की रणनीति का स्वागत किया, जिसमें अगले दस से पंद्रह वर्षों में द्विपक्षीय संबंध को शामिल किया गया है - 2004 के पिछले ऐसे संचार पर निर्माण करते हुए और यूरोपीय संसद की सितंबर 2017 की सिफारिशों "भारत के साथ राजनीतिक संबंधों पर संकल्प" को प्रतिबिंबित किया गया है ।

यह रणनीति दोनों पक्षों की प्राथमिकता के आधार पर भारत-यूरोपीय संघ की साझेदारी का निर्माण और संवर्द्धन करना चाहती है, जिसमें भारत में स्थायी आधुनिकीकरण और जलवायु परिवर्तन, वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, संसाधन दक्षता, आपदा जोखिम में कमी, महासागर शासन और वैश्विक आम वस्तुओं की सुरक्षा जैसे वैश्विक मुद्दों पर भारत के साथ अधिक सक्रिय भागीदारी शामिल है। यूरोपीय संघ ने भारत-यूरोपीय संघ के अनुसंधान और तकनीकी सहयोग, ऊर्जा के नवीकरणीय और वैकल्पिक स्रोतों के कुशल उपयोग, खाद्य सुरक्षा, एजेंडा 2030 के कार्यान्वयन और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी), जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण के संरक्षण, आपदा जोखिम में कमी और अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए बहुपक्षीय मंचों में सहयोग को भी रेखांकित किया है।

वर्ष 2018-19 को उच्च-स्तरीय संपर्कों और उपलब्धियों की एक श्रृंखला द्वारा चिह्नित किया गया है, जो द्विपक्षीय और वैश्विक दोनों संदर्भ में, भारत और यूरोपीय संघ के बीच पारस्परिक सहयोग और सकारात्मक सहयोग को बढ़ाने में योगदान देता है। भारत-यूरोपीय संघ की अनौपचारिक रणनीतिक साझेदारी की पहली समीक्षा का नेतृत्व सचिव (पश्चिम) श्रीमती रुचि घनश्याम और यूरोपीय विदेश कार्रवाई सेवा (ईईएएस) के उप महासचिव, श्री क्रिश्चियन लेफ़लर ने 2 मई 2018 को ब्रसेल्स में किया था, जहाँ भारत और यूरोपीय संघ के बीच द्विपक्षीय सहयोग के पूर्ण परिदृश्य को पुनर्जीवित किया गया और अगले कदमों पर चर्चा की गई। 17 मई 2018 को नई दिल्ली में नौवीं वार्षिक "भारत-यूरोपीय संघ मैक्रो आर्थिक वार्ता और वित्तीय सेवा विनियम पर वार्ता" का आयोजन किया गया।

विदेश मंत्री (ईएएम) श्रीमती सुषमा स्वराज ने 20-23 जून 2018 के दौरान बेल्जियम का दौरा किया। भारत-यूरोपीय संघ की पाँचवीं मंत्रिस्तरीय बैठक 22 जून 2018 को यूरोपीय संघ की उच्च प्रतिनिधि/ उपाध्यक्ष सुश्री फेडेरिका मोघेरिनी

प्रधान मंत्री ने ब्यूनस आयर्स में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ के अध्यक्ष डोनल्ड टस्क और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जीन-क्लॉड जुंकर से मुलाकात की (01 दिसंबर, 2018)

के साथ आयोजित की गई। यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री (ईएएम) श्रीमती सुषमा स्वराज ने 20 जून 2018 को यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष श्री जीन क्लाउड जुनकर और यूरोपीय संसद अध्यक्ष श्री एंटोनियो ताजानी से भी भेंट की। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने "जलवायु, शांति और सुरक्षा" पर यूरोपीय आयोग द्वारा आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित किया और 21 जून 2018 को यूरोपीय संसद में चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समारोह मनाया।

पर्यावरण, समुद्री मामलों और मत्स्य पालन के लिए यूरोपीय संघ के आयुक्त, श्री कर्मेनु वेला ने 3-7 सितंबर 2018 के दौरान भारत में "परिपत्र अर्थव्यवस्था मिशन" का नेतृत्व किया। 21 सितंबर 2018 को ब्रसेल्स में "भारत-यूरोपीय संघ समुद्री सुरक्षा" पर दूसरी अनौपचारिक बैठक हुई। डॉ. पंकज शर्मा, संयुक्त सचिव (निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के प्रभाग (डीईएसए), विदेश मंत्रालय ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का और श्री पेल हर्कज़िनस्की, सुरक्षा नीति निदेशक, यूरोपीय बाहरी कार्रवाई सेवा (ईईएएस) ने यूरोपीय संघ का नेतृत्व किया। फार्मास्यूटिकल्स बायोटेक्नोलॉजी और मेडिकल डिवाइसेज पर भारत-यूरोपीय संघ के संयुक्त कार्यकारी समूह की नौवीं बैठक 27 और 28 सितंबर 2018 के दौरान आयोजित की गई थी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण और यूरोपीय खाद्य सुरक्षा एजेंसी के बीच 14 सितंबर 2018 को एक समझौता ज्ञापन (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए गए।

ग्यारहवीं भारत-यूरोपीय संघ आतंकवाद प्रतिरोध वार्ता 12 नवंबर 2018 को ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। भारत और यूरोपीय संघ ने हिंसक चरमपंथ, कट्टरपंथीकरण और रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (सीबीआरएन) खतरों का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक साथ काम करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र के लिए अपने समर्थन को रेखांकित करते हुए, वैश्विक आतंकवाद प्रतिरोध मंच और पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाले आतंकवाद के खतरे को संबोधित करने के लिए समर्पित अन्य बहुपक्षीय, एक बहुपक्षीय मंच बनाने पर एक फलदायी आदान-प्रदान किया।

भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने 18 और 19 अक्टूबर 2018 को यूरोपीय संघ द्वारा ब्रुसेल्स में आयोजित 12वीं एशिया-यूरोप मीटिंग समिट (एएसईएम) में भाग लिया। उपराष्ट्रपति ने 19 अक्टूबर 2018 को शिखर सम्मेलन में पूर्णसत्र और रिट्रीट सत्र को संबोधित किया। शिखर सम्मेलन में अपने हस्तक्षेप में, उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत एएसईएम को एक ऐसे मंच के रूप में महत्व देता है जो विचारों के आदान-प्रदान और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए एशिया और यूरोप के नेतृत्व को एक साथ लाता है।

8

अमेरिका

उत्तरी अमेरिका

कनाडा

भारत और कनाडा के बीच साझा मूल्यों, साझा हितों और लोगों के बीच मजबूत आपसी संपर्कों की एक रणनीतिक साझेदारी है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अप्रैल 2015 में कनाडा की यात्रा ने फिर से मजबूत किया और द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। 17-24 फरवरी 2018 से कनाडा के प्रधानमंत्री श्री जस्टिन ट्रूडो की भारत यात्रा से यह गति जारी रही।

प्रधानमंत्री श्री जस्टिन ट्रूडो की यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने दोनों देशों की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के मूल सिद्धांत के आधार पर कनाडा-भारत संबंधों के विस्तार और दायरे की पुष्टि की। दोनों पक्षों ने लोकतंत्र, विविधता, बहुलवाद और कानून के साझा मूल्यों के आधार पर रणनीतिक साझेदारी के चल रहे विविधीकरण और विकास की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

प्रधानमंत्री श्री जस्टिन ट्रूडो छह संघीय मंत्रियों और चौदह सांसदों के साथ आए थे। यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने निम्नलिखित समझौतों पर हस्ताक्षर किए:

- विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग के बारे में भारत गणराज्य के परमाणु ऊर्जा विभाग और कनाडा के प्राकृतिक संसाधन विभाग के बीच समझौता ज्ञापन।
- उच्च शिक्षा में सहयोग के संबंध में कनाडा सरकार और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन।
- भारत-कनाडा मंत्रिस्तरीय ऊर्जा वार्ता के संदर्भ की शर्तें।
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सहयोग पर भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और कनाडा सरकार के नवाचार, विज्ञान और आर्थिक विकास विभाग के बीच आशय की संयुक्त घोषणा।

- कनाडा के विरासत विभाग (खेल कनाडा) और भारत सरकार के गणराज्य, युवा मामलों और खेल मंत्रालय के बीच खेल में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, भारत (डीआईपीपी) और कनाडा के बौद्धिक संपदा कार्यालय के बीच बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) पर सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन।

राष्ट्रपति भवन में कनाडा के प्रधान मंत्री, जस्टिन ट्रूडो के स्वागत समारोह के दौरान प्रधान मंत्री उनकी अगवानी करते हुए (23 फरवरी, 2018)

प्रधानमंत्री श्री जस्टिन ट्रूडो की यात्रा से पहले, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार ने 14 फरवरी 2018 को भेंट की और द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग के बारे में चर्चा की। दोनों पक्ष ने 14 फरवरी 2018 को आतंकवाद प्रतिरोध और हिंसक चरमपंथ पर भारत और कनाडा के बीच सहयोग के लिए एक रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए।

प्रधानमंत्री श्री जस्टिन ट्रूडो की यात्रा के हाशिये पर, 22 फरवरी 2018 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री (ईएएम) श्रीमती सुषमा स्वराज और कनाडा के विदेश मामलों की मंत्री सुश्री चिस्टेरिया फ्रीलैंड की अध्यक्षता में विदेश मंत्री स्तरीय रणनीतिक वार्ता आयोजित की गई थी।

वर्ष के दौरान कनाडा के साथ अन्य उच्च-स्तरीय दौरे निम्नलिखित थे:

- **भारत से दौरे**
  - o महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फड़नवीस ने 10-13 जून 2018 को अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच द्वारा आयोजित सम्मेलन डे मॉन्ट्रियल में भाग लेने के लिए मॉन्ट्रियल, क्यूबेक का दौरा किया।
  - o मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर 8-13 जुलाई 2018 को विश्व संस्कृत सम्मेलन 2018 में भाग लेने के लिए वैंकूवर गए।
- **कनाडा से दौरे**
  - o अल्बर्टा में विपक्ष के नेता और अलबर्टा में यूनाइटेड कंजरवेटिव पार्टी के नेता 17-22 सितंबर 2018 को भारत आए। यात्रा के दौरान श्री केनी ने विदेश मंत्री (ईएएम) श्रीमती सुषमा स्वराज, सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्री नितिन गडकरी और खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल से भेंट की। उन्होंने चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री श्री अमरिंदर सिंह से भी भेंट की।
  - o श्री एंड्रयू स्कीर, कनाडा के महामहिम के वफादार विपक्ष के नेता और कनाडा के कंज़र्वेटिव पार्टी के नेता 6-14 अक्टूबर 2018 को भारत आए। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली और आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री (एमओएस) से भेंट की। उन्होंने चंडीगढ़ की यात्रा के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री श्री अमरिंदर सिंह से भी भेंट की।
  - o सस्केचेवान के प्रमुख श्री स्कॉट रेयान मो ने 24-30 नवंबर 2018 तक भारत का दौरा किया।
  - o अंतर्राष्ट्रीय विकास मंत्री की संसदीय सचिव, सुश्री कमल खेरा ने 10-13 दिसंबर 2018 तक नई दिल्ली में मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य पर 2018 पार्टनर्स फोरम में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया।
  - o कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री, श्री स्टीफन हार्पर, 6-13 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में रायसीना वार्ता में भाग लेने के लिए भारत आए थे। संवाद के हाशिये पर, श्री हार्पर ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ईएएम श्रीमती सुषमा स्वराज, वित्त मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री से भेंट की। मिस्टर हार्पर मुंबई भी गए।

द्विपक्षीय व्यापार

द्विपक्षीय व्यापार वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 7.23 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और अप्रैल-सितंबर 2018 की अवधि के लिए यह 2.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इस अवधि में कनाडा को भारत का निर्यात 1.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर और कनाडा से आयात 1.549 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

अप्रैल 2000 से अब तक, कनाडाई पेंशन फंड ने भारत में लगभग 12.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है और भारत को दीर्घकालिक निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में देख रहा है। 400 से अधिक कनाडाई कंपनियों की भारत में उपस्थिति है, और 1,000 से अधिक कंपनियां भारतीय बाजार में सक्रिय रूप से कारोबार कर रही हैं।

कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विविधीकरण के मंत्री श्री जिम कैर और वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु (सीआईएम) ने 14 नवंबर, 2018 को सिंगापुर में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के हाशिये पर भेंट की और विभिन्न क्षेत्रों, आर्थिक विकास और पारस्परिक हित के बहुपक्षीय क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की।

कृषि

जनवरी 2009 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत और कनाडा के बीच कृषि सहयोग में स्थिर प्रगति हुई है। अनाज के भंडारण और दालों के भंडारण के लिए कनाडा के सिस्टम दृष्टिकोण का आकलन करने के लिए कृषि मंत्रालय की एक विशेषज्ञ टीम ने 10-13 सितंबर 2018 तक कनाडा का दौरा किया।

ऊर्जा

कनाडा विविधीकृत, स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा आपूर्ति की भारत की खोज में ऊर्जा आपूर्ति का प्रमुख स्रोत हो सकता है। फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री श्री जस्टिन ट्रूडो की यात्रा के दौरान ऊर्जा क्षेत्र में क्षमता को ध्यान में रखते हुए, मंत्रिस्तरीय स्तर की ऊर्जा वार्ता के दायरे का विस्तार किया गया इसके अलावा बिजली, ऊर्जा दक्षता और नवीकरण भी वार्ता में शामिल थे।

आईओसी के पास ब्रिटिश कोलंबिया में पेट्रोनास एलएनजी परियोजना के नेतृत्व में एक कंसोर्टियम प्रोग्रेस एनर्जी कनाडा लिमिटेड (जिसे अब पेट्रोनास कनाडा के रूप में जाना जाता है) के एकीकृत शेल प्रोजेक्ट में 10% हिस्सेदारी है। आईओसी ने परियोजना में अब तक 1.61 बिलियन डॉलर (सितंबर 2018 तक) का निवेश किया है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आयोजित पेट्रोटेक 2019 के 13 वें संस्करण में भाग लेने के लिए कनाडा के प्राकृतिक संसाधन मंत्री श्री अमरजीत सोही के भारत आने की आशा है।

असैनिक परमाणु सहयोग

अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कनाडा यात्रा के दौरान, परमाणु ऊर्जा विभाग और मैसर्स केमको इंक, कनाडा ने 2015-2020 में भारत को 3000 मीट्रिक टन यूरेनियम अयस्क की केंद्रित आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दिसंबर 2018 तक यूरेनियम के छह खेपें प्राप्त हुई हैं।

दोनों पक्ष भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग और कनाडा के प्राकृतिक संसाधन विभाग के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन में परिकल्पित संयुक्त कार्य समूह पर काम कर रहे हैं।

विज्ञान और तकनीक

भारत-कनाडा संयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति द्वारा 14 नवंबर 2017 को अंतिम रूप दी गई, 2017-19 के लिए कार्य योजना को दोनों पक्षों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। भारत-कनाडा अभिनव सामुदायिक परिवर्तन और स्थिरता के लिए अभिनव बहु-विषयक भागीदारी के केंद्र के अंतर्गत, सुरक्षित और सतत अवसंरचना, ऊर्जा संरक्षण और एकीकृत जल प्रबंधन के क्षेत्रों में दस परियोजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। भारत-कनाडा के संयुक्त औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 2018 के लिए प्रस्तावों का आह्वान 14 नवंबर 2017 को शुरू किया गया था। उन्नत सामग्री और उन्नत विनिर्माण, जल प्रौद्योगिकी, स्मार्ट शहर और खाद्य और कृषि प्रौद्योगिकी विशेष ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र थे। अब तक कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता के लिए तीन परियोजनाओं की संयुक्त रूप से सिफारिश की गई है।

अंतरिक्ष

इसरो और प्राकृतिक संसाधन कनाडा (एनआरकैन) ने 10 अप्रैल 2018 को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से एक बैठक की और आपदा प्रबंधन और फसल पूर्वानुमान और कॉम्पैक्ट सेंसर के विकास और डिजाइन के लिए माइक्रोवेव उपग्रह डेटा जैसे संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की। 27 जून 2018 को, इसरो और कनाडा सेंटर फॉर मैपिंग एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन (सीसीएमईओ) ने आपदा प्रभावित बुनियादी ढांचे के लिए रडारसैट नक्षत्र मिशन (आरसीएम) और रडारसैट-2 के उपयोग; भूस्खलन और शहरी बाढ़ और भारत के भविष्य रीसैट और निसार में अनुसंधान - कैलिब्रेशन और एस-बैंड विशेषज्ञता का आदान-प्रदान जैसे संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की। इसरो की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एंट्रिक्स) ने अब तक पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (पीएसएलवी) में सह-यात्री उपग्रहों के रूप में कनाडा से 13 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसमें हाल ही में पीएसएलवी -सी43 मिशन द्वारा 29 नवंबर 2018 को लॉन्च किया गया केपलर (सीएएसई) उपग्रह शामिल है।

उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा में सहयोग के लिए 2010 में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) को फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री श्री जस्टिन ट्रूडो की यात्रा के दौरान नवीनीकृत किया गया था। दोनों पक्ष सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए समझौता

ज्ञापन में संयुक्त कार्य समूह की स्थापना के लिए काम कर रहे हैं।

कनाडा भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र सुधार लाने के उद्देश्य से संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 25अक्टूबर 2018 को शुरू की गई एक पहल शैक्षणिक संवर्धन एवं अनुसंधान सहयोग (स्पार्क) स्कीम के अंतर्गत शामिल 28 देशों में से एक है। स्पार्क के अंतर्गत, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), रोपड़ को कनाडा के संस्थानों के साथ सहयोग के लिए केंद्रीय संस्थान के रूप में नामित किया गया है।

शास्त्री इंडो-कनाडियन इंस्टीट्यूट (एसआईसीआई)

इस वर्ष अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है। 1968 में अपनी स्थापना के बाद से, एसआईसीआई उच्च शिक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए कनाडाई और भारतीय सरकारों के उद्देश्यों का समर्थन करने में लगा हुआ है और दोनों देशों के लिए सकारात्मक परिणामों के साथ काफी संख्या में जैव राष्ट्रीय अनुसंधान अध्ययन पूरे हुए हैं।

लोगों के परस्पर संपर्क

कनाडा में भारतीय मूल के 1.4 मिलियन से अधिक व्यक्तियों (पीआईओ) का निवास है, जो देश की जनसंख्या के 3% से अधिक है। वर्तमान में कनाडा में पढ़ रहे 125,000 से अधिक भारतीय छात्रों के साथ, यह भारतीय छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के लिए सबसे पसंदीदा स्थलों में से एक बन गया है।

भारत-कनाडा ट्रैक 1.5 संवाद

भारत के विदेश मंत्रालय और कनाडा के वैश्विक मामलों के मंत्रालय के सहयोग से, गेटवे हाउस, मुंबई और सेंटर फॉर इंटरनेशनल गवर्नेंस इनोवेशन (सीआईजीआई), कनाडा के बीच नवाचार, विकास और समृद्धि पर पहला भारत-कनाडा ट्रैक 1.5 संवाद ओटावा में 29 और 30 अक्टूबर 2018 को आयोजित हुआ था। दोनों पक्षों के विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों और व्यापार जगत के नेताओं ने रणनीतिक, सुरक्षा सहित साइबर सुरक्षा, आर्थिक संबंध, भू-संरक्षण, जलवायु नेतृत्व, सेवाओं में व्यापार और ऊर्जा के पारंपरिक और गैर-पारंपरिक रूपों में भविष्य के सहयोग की संभावना का पता लगाया।

संयुक्त राज्य अमरीका

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका (यू. एस.) के बीच साझा मूल्यों, रणनीतिक दृष्टिकोणों में बढ़ते अभिसरण और मजबूत जन संपर्कों पर आधारित मजबूत और बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी है। दोनों देश विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी एक साथ काम कर रहे हैं। वर्ष के दौरान, भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध एक व्यापक तरीके से विकसित हुए, जिसमें सुरक्षा, आर्थिक संबंध, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और लोगों से लोगों के संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग शामिल है।

उच्च-स्तरीय सहभागिता

- उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने 8-9 सितंबर 2018 को अमेरिका का दौरा किया और शिकागो में द्वितीय विश्व हिंदू सम्मेलन को संबोधित किया। यात्रा के दौरान, उन्होंने अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय के सदस्यों से बात की।
- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 नवंबर 2018 को पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के समय, संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति श्री माइकल आर पेंस से सिंगापुर में भेंट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की और आपसी हित के द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की।
- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर, 2018 को ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में भारत, जापान और अमेरिका के नेताओं की पहली त्रिपक्षीय बैठक के लिए राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड जे. ट्रम्प और प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे से भेंट की। तीनों नेताओं ने भारत-प्रशांत पर विचारों का आदान-प्रदान किया, आसियान की केंद्रीयता पर जोर दिया और समुद्री और कनेक्टिविटी मुद्दों पर प्रयासों के समन्वय के लिए सहमत हुए।
- प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 8 जनवरी 2019 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने नए साल की शुभकामनाएं दीं, 2018 में रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और इसे

जारी रखने के लिए सहमत हुए। भारत-अमेरिका 2019 में द्विपक्षीय संबंध को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे।

2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद

- अमेरिकी विदेश मंत्री श्री माइकल आर. पोम्पेओ और तत्कालीन अमेरिकी रक्षा सचिव श्री जेम्स एन. मैटिस ने विदेश मंत्री (ईएएम) श्रीमती सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के साथ भारत-अमेरिका के 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद के उद्घाटन के लिए 6 सितंबर 2018 को भारत का दौरा किया। यात्रा के दौरान, सचिव श्री माइकल आर. पोम्पेओ और तत्कालीन सचिव श्री जेम्स एन. मैटिस ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से एक संयुक्त भेंट की। उन्होंने क्रमशः विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें कीं। 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद की शुरूआत भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी और रणनीतिक और सुरक्षा प्रयासों में तालमेल को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक, दूरंदेशी दृष्टि प्रदान करने के लिए नेताओं के बीच साझा प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है।
- यात्रा के दौरान एक संचार संगतता और सुरक्षा समझौता (सीओएमसीएएसए) पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह उन्नत रक्षा प्रणालियों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा

ब्यूनस आयर्स में भारत-अमरीका-जापान त्रिपक्षीय बैठक के दौरान अमरीका के राष्ट्रपति, डोनाल्ड ट्रंप और जापान के प्रधान मंत्री शिन्जो अबे के साथ प्रधान मंत्री (30नवंबर, 2018)

और भारत को अपने मौजूदा अमेरिकी मूल मंचों का बेहतर उपयोग करने में सक्षम करेगा। दोनों पक्ष एक नए त्रि-सेवा अभ्यास के लिए सहमत हुए। अमेरिकी नौसेना बल मध्य कमान और भारतीय नौसेना के बीच बातचीत बढ़ाने पर भी सहमति हुई। संवाद की पूर्व संध्या पर संयुक्त राज्य अमेरिका की रक्षा नवप्रवर्तन इकाई और भारतीय रक्षा नवोन्मेष संगठन -नवोन्मेष के लिए रक्षा उत्कृष्टता के बीच एक समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ।

विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री नई दिल्ली में अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेन्स से मुलाकात करते हुए (06 सितंबर, 2018)

मंत्री-स्तरीय आदान-प्रदान:

- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और अमेरिकी ऊर्जा सचिव श्री रिक पेरी ने 17 अप्रैल 2018 को, दिल्ली में भारत-अमेरिका नई रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी (एसईपी)उद्घाटन बैठक की सह-अध्यक्षता की। दोनों पक्ष जून 2017 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन डीसी की यात्रा के दौरान एसईपी स्थापित करने पर सहमत हुए थे। भारत और अमेरिका ऊर्जा भागीदारी को बढ़ाने, ऊर्जा और नवाचार लिंकेज का विस्तार करने, रणनीतिक संरेखण का विस्तार करने और इस भागीदारी के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र में उद्योग और हितधारक जुड़ाव को बढ़ाने की सुविधा चाहते हैं। एक भारत-अमेरिका एसईपी के अंतर्गत प्राकृतिक गैस टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसकी पहली बैठक 6 दिसंबर 2018 को नई दिल्ली में हुई।
- पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री के. जे. अल्फोंस ने अप्रैल 2018 में अमेरिका का दौरा किया। यात्रा के दौरान, उन्होंने भारत में आने वाले पर्यटन पर न्यूयॉर्क में टूर ऑपरेटरों और मीडिया के साथ बातचीत की।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री विजय सांपला ने अप्रैल 2018 में न्यूयॉर्क का दौरा किया और भारतीय समुदाय से भेंट की।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने जून 2018 में अपने अमेरिकी वार्ताकारों के साथ बैठकों के लिए अमेरिका का दौरा किया। यात्रा के दौरान, उन्होंने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि श्री रॉबर्ट ई. लाइताइज़र, वाणिज्य सचिव श्री विल्बर एल रॉस और कृषि सचिव श्री सन्नी पेरडू के साथ विचार-विमर्श किया। उन्होंने इंडिया कॉकस सह-अध्यक्ष सीनेटर श्री मार्क रॉबर्ट वार्नर और सीनेटर श्री जॉन कॉर्निन के साथ एक संयुक्त बैठक भी की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों पर चर्चा हुई और दोनों पक्षों की चिंताओं को दूर करने के लिए आगे का रास्ता खोजने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री के. जे. अल्फोंस ने जून 2018 में अमेरिका में 'अतुल्य भारत' रोड शो की श्रृंखला में भाग लिया। अमेरिका के कई प्रमुख शहरों में रोड शो आयोजित किए गए थे, जिनमें न्यूयॉर्क, शिकागो, सेंट लुइस और ह्यूस्टन शामिल थे।
- संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी स्थायी प्रतिनिधि, अमेरिकी राजदूत निक्की हेली ने जून 2018 में भारत का दौरा किया। यात्रा के दौरान, उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज से भेंट की।
- नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा ने जुलाई 2018 में अमेरिका का दौरा किया। यात्रा के दौरान, उन्होंने वाशिंगटन डीसी में अमेरिका- भारत रणनीतिक साझेदारी मंच के वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया और शिकागो और न्यूयॉर्क में रोड शो में भाग लिया।
- वस्त्र राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा कपड़ा और सहायक उपकरण के एक मेले में भाग लेने के लिए, अगस्त 2018 में लास वेगास और सैन फ्रांसिस्को गए।
- इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और कानून और न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने अगस्त 2018 में सैन फ्रांसिस्को का दौरा किया। उन्होंने क्षेत्र में स्थित प्रमुख आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स फर्मों के सीईओ और प्रतिनिधियों से भेंट की और अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों से भारत में अधिक निवेश और सहयोग का अनुरोध किया।
- राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल ने सितंबर 2018 में अमेरिका का दौरा किया और अमेरिकी विदेश मंत्री श्री माइकल आर. पोम्पेओ, तत्कालीन अमेरिकी रक्षा सचिव श्री जेम्स एन. मैटिस और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन आर बोल्टन से भेंट की।
- रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सिंगापुर में अक्टूबर 2018 में आसियान रक्षा मंत्रियों की 5वीं बैठक [एडीएमएम-प्लस] के समय तत्कालीन अमेरिकी रक्षा मंत्री श्री जेम्स एन. मैटिस से भेंट की। मंत्रियों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में प्रगति की समीक्षा की और आपसी हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।
- रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल अक्टूबर 2018 में पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय में 2018 कार्नोट पुरस्कार के सिलसिले में एक पुरस्कार समारोह में भाग लेने के लिए अमेरिका गए थे।
- विदेश राज्य मंत्री (डॉ.) वी. के. सिंह (सेवानिवृत्त) ने 24 नवंबर 2018 को वाशिंगटन डीसी में भारत के दूतावास में पासपोर्ट सेवा परियोजना का उद्घाटन किया। उन्होंने 21 नवंबर 2018 को न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य

दूतावास और 25 नवंबर 2018 को अटलांटा में भारत के महावाणिज्य दूतावास में इसी तरह की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। यात्रा के दौरान, उन्होंने न्यूयॉर्क, बाल्टीमोर और वाशिंगटन डीसी में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ अलग-अलग बातचीत की।

- रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 2-7 दिसंबर 2018 को अमेरिका का दौरा किया। उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स एन. मैटिस से भेंट की और भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी पर चर्चा की। पारस्परिक हित के द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया। रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने रेनो, नेवादा का दौरा किया और अमेरिका में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भेंट की। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को और होनोलूलू का भी दौरा किया।

भारत में राज्यों के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों ने अमेरिका का दौरा किया।

- अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू अप्रैल 2018 में आईआईएम अहमदाबाद द्वारा आयोजित ई-गवर्नेंस नेतृत्व प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में सैन फ्रांसिस्को गए थे।
- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फड़नवीस ने जून 2018 में न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी और सैन फ्रांसिस्को का दौरा किया। उन्होंने महाराष्ट्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट स्टडीज, वर्ल्ड बैंक, यू.एस.-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम और संभावित निवेशकों के साथ बैठकों में भाग लिया।
- केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनारायी विजयन ने जुलाई 2018 में अमेरिका का दौरा किया और भारतीय प्रवासियों के साथ सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लिया।
- आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू ने सितंबर 2018 में स्थायी कृषि के वित्तपोषण पर एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका का दौरा किया। यात्रा के दौरान, उन्होंने राज्य के साथ व्यापार करने वाले संभावित निवेशकों और कंपनियों के साथ बातचीत की।

संसदीय आदान-प्रदान

अमेरिकी कांग्रेस के साथ पारस्परिक आदान-प्रदान और बातचीत भारत-अमेरिका की सामरिक भागीदारी के मजबूत द्विदलीय समर्थन को दर्शाती है। वर्ष के दौरान कई आदान-प्रदान हुए थे:

- हाउस आर्म्ड सर्विस कमेटी के अध्यक्ष विलियम “मैक” थॉर्नबेरी के नेतृत्व में एक कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल और तीन अन्य प्रतिनिधियों ने मई 2018 में नई दिल्ली का दौरा किया।
- अप्रैल 2018 में सात सदस्यीय अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली का दौरा किया।
- कैलिफोर्निया राज्य सीनेट के आठ सीनेटरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने नवंबर 2018 में भारत का दौरा किया।प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्य सीनेट अध्यक्ष प्रो टेम्पोर सुश्री टोनी एटकिंस ने किया।
- दिसंबर 2018 में कैलिफोर्निया राज्य विधानसभा के छह सदस्यों वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया।

अन्य प्रमुख आदान-प्रदान

- विदेश सचिव श्री विजय गोखले और रक्षा सचिव श्री संजय मित्रा ने मार्च 2018 में अमेरिका के दौरे पर गए और अमेरिकी अधिकारियों से भेंट की।
- वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, श्री सुभाष चंद्र गर्ग ने विश्व बैंक और आईएमएफ की 2018 स्प्रिंग मीटिंग के समय अपने समकक्ष अमेरिका के ट्रेजरी के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अवर सचिव श्री डेविड मलगेज़ के साथ अप्रैल 2018 में वाशिंगटन डीसी में द्विपक्षीय बैठक की।
- गोवा सरकार के मुख्य सचिव श्री धर्मेन्द्र शर्मा ने मई 2018 में शिकागो का दौरा किया।
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के सचिव श्री रमेश अभिषेक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मई 2018 में भारत में “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” सुधारों पर विश्व बैंक के साथ विचार-विमर्श के लिए वाशिंगटन डी.सी. का दौरा किया।

- विदेश मंत्रालय के सचिव (सीवीपी और ओआईए) श्री ज्ञानेश्वर एम. मुले ने जून 2018 में सैन फ्रांसिस्को का दौरा किया।
- परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव श्री शेखर बसु ने जून 2018 में फिलाडेल्फिया में अमेरिकन न्यूक्लियर सोसायटी (एएनएस) की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका का दौरा किया।
- विदेश सचिव श्री विजय गोखले ने अगस्त 2018 में भारत-अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद की तैयारियों के लिए अमेरिका का दौरा किया।
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने जुलाई 2018 में न्यूयॉर्क में सतत विकास पर उच्च-स्तरीय राजनीतिक मंच (एचएलपीएफ) से संबंधित घटनाओं में भाग लेने के लिए अमेरिका का दौरा किया।
- वित्त मंत्रालय में निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव श्री अतनु चक्रवर्ती ने अगस्त 2018 में अमेरिका का दौरा किया।
- अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क के सेंट्रल बोर्ड के अध्यक्ष श्री एस. रमेश ने सितंबर 2018 में अमेरिका का दौरा किया।
- अंतरिक्ष विभाग के सचिव और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष डॉ. के. सिवन ने अक्टूबर 2018 में लॉस एंजिल्स के पासादेना का दौरा किया।
- अमेरिकी नौसेना के सचिव श्री रिचर्ड वी स्पेंसर ने दिसंबर 2018 में भारत का दौरा किया और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट की।
- अमेरिकी पुनर्निर्माण के विशेष प्रतिनिधि, ज़ाल्मे खलीलज़ाद ने जनवरी 2019 में भारत का दौरा किया और विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव से भेंट की।

परामर्श/संवाद तंत्र:

भारत और अमेरिका ने विभिन्न वरिष्ठ आधिकारिक स्तर और विशेषज्ञ स्तर के संवाद तंत्र के माध्यम से वाणिज्य और व्यापार, रक्षा प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, कृषि अनुसंधान और नागरिक उड्डयन सहित कई क्षेत्रों को शामिल करते हुए अपने संपर्क जारी रखे। वर्ष के दौरान इन संस्थागत संवाद तंत्र के अंतर्गत प्रमुख द्विपक्षीय आदान-प्रदान/पहलों में निम्नलिखित शामिल थे:

सुरक्षा/सामरिक:

- भारत-अमेरिका आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की 15वीं बैठक का आयोजन 27 मार्च 2018 को नई दिल्ली में किया गया। कार्य समूह ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सीमा पार से आतंकवाद सहित दुनिया भर के आतंकवादी समूहों और अपने संबंधित क्षेत्रों में उत्पन्न खतरों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने जानकारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता की और क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवादी संगठनों के वित्तपोषण और संचालन का मुकाबला करने के प्रयासों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
- भारत-अमेरिका समुद्री सुरक्षा संवाद का तीसरा दौर गोवा में 30 अप्रैल और 1 मई 2018 को आयोजित किया गया। संवाद के दौरान, दोनों पक्षों ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री डोमेन के विकास पर चर्चा की और द्विपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
- भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 4 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली में संयुक्त सचिव/महानिदेशक/सहायक सचिव स्तर पर नौवीं त्रिपक्षीय बैठक की और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। अधिकारियों ने कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के विकास; प्रसार विरोध; आतंकवाद विरोध; समुद्री सुरक्षा, समुद्री डोमेन जागरूकता और एचएडीआर के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए व्यावहारिक कदमों की खोज की। अधिकारियों ने फरवरी 2018 में वाशिंगटन में हुए त्रिपक्षीय बुनियादी ढांचा कार्य समूह की बैठक के परिणामों की समीक्षा की।
- भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने सिंगापुर में 7 जून 2018 को आसियान-केंद्रित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में भारत-प्रशांत क्षेत्र में सामान्य हित के मुद्दों पर परामर्श के लिए बैठक की। इसी प्रारूप में एक और बैठक 15 नवंबर 2018 को सिंगापुर में आयोजित की गई थी। कनेक्टिविटी, सतत विकास, आतंकवाद, अप्रसार और समुद्री और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। प्रतिभागियों ने एक मुक्त, खुले और समावेशी भारत-

प्रशांत की आधारशिला के रूप में आसियान केंद्रीयता की पुष्टि की।

- भारत-अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 18 जुलाई 2018 को नई दिल्ली में हुई।
- उद्घाटन भारत-अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक 11 जनवरी, 2019 को दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों ने भारत-अमेरिका मंत्रिस्तरीय 2 + 2 संवाद के दौरान लिए गए निर्णयों और पारस्परिक हित के रक्षा और विदेश नीति के मुद्दों पर द्विपक्षीय सहयोग पर प्रगति करने के तरीकों पर चर्चा की।

रक्षा

o रक्षा सहयोग भारत-अमेरिका द्विपक्षीय रणनीतिक सहयोग का एक प्रमुख स्तंभ है। दोनों पक्षों ने सैन्य संबंधों के साथ-साथ रक्षा व्यापार के विस्तार की दिशा में काम करना जारी रखा। सह-विकास और सह-उत्पादन परियोजनाएं भी विचाराधीन हैं। भारत को लाइसेंस छूट के रणनीतिक व्यापार प्राधिकरण टीयर- I (एसटीए-I) की अधिसूचना 3 अगस्त 2018 को अमेरिकी संघीय रजिस्टर में प्रकाशित की गई थी।

अभ्यास और सैन्य सहयोग

- भारत और अमेरिका तीनों सेवाओं से जुड़े द्विपक्षीय अभ्यास करते हैं और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय/बहुपक्षीय अभ्यास में भी भाग लेते हैं। 2018 में, निम्नलिखित प्रमुख संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किए गए:
  - o वर्ष 2018-19 के लिए अभ्यास वज्र प्रहार 19 नवंबर -2 दिसंबर 2018 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। यह भारतीय और अमेरिकी विशेष बलों के बीच आयोजित एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
  - o भारत के रानीखेत के चौबटिया में 16-29 सितंबर 2018 को व्यायाम युद्धाभ्यास का 14 वां संस्करण आयोजित किया गया। व्यायाम युद्ध अभ्यास भारतीय और अमेरिकी सेना के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है।अभ्यास का उद्देश्य सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना और अशांति और आतंकवाद विरोधी अभियानों में सामरिक कौशल को सीखना है।
  - o भारतीय और अमेरिकी वायु सेनाओं के बीच एक्सरसाइज कोप इंडिया का चौथा संस्करण 3-14 दिसंबर 2018 को पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा और पानागढ़ में आयोजित किया गया था।
  - o मालाबार अभ्यास का 22 वां संस्करण 4-15 जून 2018 को गुआम द्वीप के तट पर आयोजित किया गया था। इस त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास में भारत, अमेरिकी और जापान की नौसेना के बल शामिल हैं।
  - o भारत ने रिमपैक 2018 में भाग लिया, जिसकी मेजबानी यूनाइटेड स्टेट्स इंडोपाकैम द्वारा 25 जून -3 अगस्त 2018 को हवाई के तट से दूर 'द रिम ऑफ पैसिफिक' (रिमपैक) में की गई, जो एक द्विवार्षिक अभ्यास है, यह वर्तमान में दुनिया में आयोजित सबसे बड़ा बहुपक्षीय अभ्यास है।
- रक्षा खरीद और उत्पादन समूह (डीपीपीजी) की 13वीं बैठक 6-9 जून 2018 को वाशिंगटन डीसी में आयोजित की गई थी। बैठक ने विदेशी सैन्य बिक्री (एफएमएस) मामलों की प्रगति की समीक्षा की और कार्यान्वयन के अंतर्गत खरीद के मामलों में तेजी लाने के उपायों पर चर्चा की।
- भारतीय वायु सेना-अमेरिकी वायु सेना ईएसजी की 21वीं बैठक 14-16 मार्च 2018 को भारत में आयोजित की गई थी। द्विपक्षीय नौसैनिक सहयोग पर 21वें कार्यकारी संचालन समूह की बैठक 12 दिसंबर 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। सेवा-से-सेवा सहयोग की सुविधा के लिए सेवा-से-सेवा कार्यकारी संचालन समूह (ईएसजी) प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं।
- अध्यक्ष, संयुक्त सेनाध्यक्ष जनरल जोसेफ एफ. डनफोर्ड जूनियर ने सितंबर 2018 में भारत का दौरा किया और अपने समकक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें कीं। उन्होंने भारत-अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद में भी भाग लिया।
- स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष और नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने अमेरिकी नौसेना द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सीपॉवर सिम्पोजियम (आईएसएस) के 23वें संस्करण में भाग लेने के लिए सितंबर 2018 में अमेरिका का दौरा किया और अमेरिकी पक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठके की।

- डिप्टी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (ऑपरेशंस) एयर मार्शल पी एन प्रधान ने अक्टूबर 2018 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित हिंसक अतिवादी संगठनों के प्रतिरोध के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया।
- अमेरिकी प्रशांत वायु सेना के कमांडर जनरल चार्ल्स ब्राउन ने दिसंबर 2018 में भारत का दौरा किया।
- कमांडर, अमेरिकी इंडो-पैसिफिक कमान, एडमिरल फिलिप एस. डेविडसन ने जनवरी 2019 में भारत का दौरा किया। उन्होंने रायसीना वार्ता में भाग लिया और कई द्विपक्षीय बैठकें कीं।

रक्षा प्रौद्योगिकी

- रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल (डीटीटीआई) समूह की 7वीं बैठक 18 जुलाई 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई और रक्षा मंत्रालय के सचिव (रक्षा उत्पादन) डॉ. अजय कुमार और सुश्री एलेन एम लॉर्ड, रक्षा और निरंतरता के लिए रक्षा सचिव, अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा इसकी सह-अध्यक्षता की गई। बैठक में रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग में चल रहे सहयोग की समीक्षा की गई।
- भारत-अमेरिका रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल के तत्वावधान में अन्य प्रणालियों (ओएस) पर संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठक 9 और 10 अक्टूबर 2018 को एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट (एडीई), बेंगलुरु में हुई।
- डीटीटीआई के अंतर्गत संयुक्त कार्य समूह भूमि प्रणाली (जेडब्ल्यूजी एलएस) की पहली बैठक 9 मई 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसके बाद 21-24 अगस्त 2018 को मिशिगन, संयुक्त राज्य अमेरिका में जेडब्ल्यूजी एलएस की दूसरी बैठक हुई।
- रक्षा विभाग द्वारा भारत के रक्षा मंत्रालय और अमेरिकी रक्षा विभाग के बीच अनुसंधान और विकास सूचना के आदान-प्रदान से संबंधित मास्टर सूचना विनिमय समझौते (एमआईईए) को 15 वर्षों के एक और कार्यकाल के लिए, फरवरी 2034 तक बढ़ाया गया।
- भारत- अमेरिका संयुक्त तकनीकी समूह (जेटीजी) की बीसवीं बैठक 14 अगस्त 2018 को सीएआईआर, बेंगलुरु में आयोजित की गई।

वाणिज्य और व्यापार

- अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार (माल और सेवाएँ संयुक्त) है। अमेरिकी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2017 में द्विपक्षीय व्यापार 126 बिलियन तक पहुंचा और इसमें 10% से अधिक की वृद्धि हुई। 2017 में दोनों तरफ का व्यापारिक व्यापार 74.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। 2018 के पहले नौ महीनों के दौरान, भारत के पक्ष में 19.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार संतुलन के साथ द्विपक्षीय व्यापार 105.54 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। दोनों पक्ष आपसी हित के मुद्दों को सुलझाने और आर्थिक संबंधों के विस्तार में लगे हुए हैं।
- मुंबई में 11 और 12 अप्रैल 2018 को भारत-अमेरिका पशु और पादप स्वास्थ्य संवाद आयोजित किया गया था। यह वार्ता व्यापार नीति फोरम के तत्वावधान में आयोजित की जाती है। बैठक के दौरान पशु और पौध स्वास्थ्य प्रणालियों, विनियामक उपायों और द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों से संबंधित आपसी चिंता के कई मुद्दों पर चर्चा की गई।
- नागरिक विमानन मंत्रालय और अमेरिकी व्यापार और विकास एजेंसी द्वारा छठा द्विवार्षिक विमानन शिखर सम्मेलन भारत-अमेरिकी विमानन सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत 9 से 11 मई 2018 को मुंबई में आयोजित किया गया था। इसने दोनों देशों में उद्योग को भारत के विमानन क्षेत्र की तीव्र वृद्धि का समर्थन करने के लिए विमानन साझेदारी को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्रदान किया।
- अमेरिकी ऊर्जा विभाग में अवर सचिव मार्क मेनेजेस ने दिसंबर 2018 में भारत का दौरा किया और भारत-अमेरिका गैस टास्क फोर्स सहित कई बैठकों में भाग लिया।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग

- टीकाकरण एक्शन प्रोग्राम लीडरशिप की 30वीं बैठक 16 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इंडो-यूएस वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय एलर्जी और संक्रामक रोग संस्थान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (एनआईएच), संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय कार्यक्रम है।

- भारत और अमेरिका ने समुद्र विज्ञान और जलवायु विज्ञान के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अपना सहयोग जारी रखा। चेन्नई में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा एक संयुक्त शोध परियोजना के अंतर्गत, शोधकर्ताओं की एक अमेरिकी टीम ने जून 2018 में बंगाल की खाड़ी में यू.एस. नेवी आर/वी थॉमस जी थॉम्पसन पर मानसून अध्ययन के लिए भारतीय शोधकर्ताओं के साथ शामिल हुए।

विचार मंच विनिमय

- विदेश मंत्रालय ने अनंत एस्पेन केंद्र के साथ मिलकर 7 और 8 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली में दूसरा भारत-अमेरिका फोरम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में भारत-अमेरिका संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए सरकार, राजनीति, चिंतकों, विश्वविद्यालय, उद्योग और मीडिया के प्रमुख व्यक्तित्वों को एकजुट किया गया था।
- विदेश मंत्रालय के छह-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने विचार मंच का समर्थन किया, सेंटर फॉर कंटेम्परेरी चाइनीज स्टडीज (सीसीसीएस) ने 29 जुलाई-4 अगस्त 2018 को विचार मंच और अमेरिका के सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वाशिंगटन डीसी और सैन फ्रांसिस्को का दौरा किया।

लोग के परस्पर संपर्क

- भारत और अमेरिका के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास में लोगों के आपसी संपर्क ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस बातचीत का विकास वर्ष भर जारी रहा। अमेरिका में लगभग 4 मिलियन का मजबूत भारतीय प्रवासी समुदाय है और यह विकसित हो रहा है। दोनों देश 2017 में अमेरिका में विभिन्न पाठ्यक्रमों में शामिल 200,000 से अधिक भारतीय छात्रों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक संबंधों का आनंद लेते हैं।
- सातवां भारत-यूएस कांसुलर संवाद 23 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। वीजा और कांसुलर मामलों से संबंधित कई मुद्दों, जिनमें रोजगार वीजा [एच1बी और एल-1] शामिल हैं, और अमेरिका में भारतीय नागरिकों के लिए कांसुलर अधिसूचना और पहुंच पर चर्चा की गई।
- सांस्कृतिक संबंध भारत-अमेरिकी द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण घटक है। अमेरिका में स्थित भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने वर्ष के दौरान विभिन्न घटनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा देना जारी रखा। विभिन्न संगठनों के सहयोग से 16 जून 2018 को वाशिंगटन में यू.एस. कैपिटल वेस्ट लॉन में आयोजित चौथे अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर 2500 से अधिक लोगों की उत्साही भागीदारी में भारतीय संस्कृति और परंपराओं में रुचि परिलक्षित हुई।
- यू.एस. के भारतीय राजदूत और श्री कीथ रोथफस, श्री अमी बेरा और श्री राजा कृष्णमूर्ति सहित कई कांग्रेसियों की उपस्थिति में 14 नवंबर 2018 को कैपिटल हिल पर दिवाली समारोह मनाया गया। 5 नवंबर 2018 को, राज्य विभाग के दक्षिण एशियाई अमेरिकी कर्मचारी संघ के सहयोग से राज्य विभाग में एक दिवाली कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अमेरिका में भारतीय राजदूत को 13 नवंबर 2018 को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड जे. ट्रम्प द्वारा आयोजित दिवाली समारोह में एक अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था।

जनवरी - मार्च 2019 में अपेक्षित कार्यक्रम

- भारत-अमेरिका आतंकवाद-रोधी कार्य समूह की 16वीं बैठक फरवरी 2019 में आयोजित होने की आशा है।
- भारत-अमेरिका आतंकवाद-रोधी नामित संवाद के फरवरी 2019 में आयोजित होने की आशा है।
- भारत - अमेरिकी सूचना संचार प्रौद्योगिकी कार्य समूह के फरवरी 2019 में मिलने की आशा है।
- भारत-अमेरिका वाणिज्यिक संवाद फरवरी 2019 में आयोजित होने की आशा है
- भारत-अमेरिका विदेश सचिव के स्तर पर विदेश कार्यालय परामर्श के फरवरी-मार्च 2019 में आयोजित होने की आशा है।
- दोनों पक्ष फरवरी 2019 में होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग मंत्रीस्तरीय बैठक आयोजित करने की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं।
- भारत-अमेरिका रणनीतिक सुरक्षा वार्ता फरवरी-मार्च 2019 में आयोजित होने की आशा है।
- भारत-अमेरिका अंतरिक्ष सुरक्षा वार्ता के फरवरी-मार्च 2019 में आयोजित होने की आशा है।

लैटिन अमेरिका

अर्जेंटीना

जी-20 के अध्यक्ष के रूप में अर्जेंटीना ने 30 नवंबर 1 दिसंबर 2018 को नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए शिक्षा, रोजगार, व्यापार और निवेश, वित्त, कृषि, महिला, व्यवसाय व उद्यमिता और कानून और व्यवस्था सहित विभिन्न विषयों को आवृत करते हुए पचास से अधिक बैठकों का आयोजन किया। इन बैठकों में मंत्री और अधिकारियों दोनों के स्तर पर भारत के विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया, जिनमें श्री शक्तिकांत दास, भारत के लिए जी20 शेरपा, आर्थिक मामलों के सचिव श्री सुभाष चंद्र गर्ग, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे, राज्य मंत्री (एमओएस) [आईसी] श्री संतोष कुमार गंगवार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, कृषि राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम रुपाला, वाणिज्य विभाग की आर्थिक सलाहकार सुश्री रूपा दत्ता और सुश्री अनु पी मथाई, राज्य मंत्री (एमओएस) पर्यटन के लिए श्री के जे अल्फोंस शामिल थे।

प्रधान मंत्री ब्यूनस आयर्स में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, मौरिसियो मैक्री से मुलाकात करते हुए (01 दिसंबर, 2018)

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर और 1 दिसंबर 2018 को ब्यूनस आयर्स में जी20 के नेताओं के शिखर सम्मेलन 2018 में भाग लेने के लिए अर्जेंटीना गए थे। यात्रा के दौरान, उन्होंने 1 दिसंबर, 2018 को अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, श्री मौरिसियो मैकरी और चिली और जमैका के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 29 नवंबर, 2018 को आर्ट ऑफ़ लिविंग, अर्जेंटीना द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम 'योग फॉर पीस' में भी भाग लिया, जिसमें 4000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इससे पहले, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई 2018 को जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर अर्जेंटीना के राष्ट्रपति से भेंट की थी। बैठकों के दौरान, दोनों नेताओं ने कृषि, अंतरिक्ष, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, तेल और गैस, आदि क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।

वाणिज्य और उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु 14-17 सितंबर 2018 से जी20 व्यापार और निवेश मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए एर्जेंटीना गए। यात्रा के दौरान, उन्होंने बैठक के मौके पर अर्जेंटीना के विदेश मंत्री श्री जॉर्ज फॉरी से भेंट की और द्विपक्षीय व्यापार और निवेशों में विविधता लाने और इन्हें बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। उन्होंने 15 सितंबर 2018 को अर्जेंटीना के भारत के दूतावास में काम करने वाले युवा भारतीय पेशेवरों के साथ भी बातचीत की।

लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में 30 अक्टूबर-2 नवंबर 2018 से आयोजित संसदीय मंच और अध्यक्षों के जी20 देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 13-सदस्यीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने कार्यक्रम के मौके पर भारत-अर्जेंटीना संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत की।

विदेश मंत्री जनरल (डॉ) वी के सिंह (सेवानिवृत्त), 19-22 मई 2018 को ब्यूनस आयर्स में जी20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अर्जेंटीना गए। बैठक के मौके पर, उन्होंने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति और अर्जेंटीना के विदेश मामलों के मंत्री से भेंट की। उन्होंने अर्जेंटीना के कृषि मंत्री से भी भेंट की।

अन्य यात्राएं स्टील की क्षमता पर ग्लोबल फोरम की स्टीयरिंग समूह की बैठक, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीशों के चौदहवें द्विवार्षिक सम्मेलन के संदर्भ में थीं; हरियाणा के कृषि मंत्री श्री ओ.पी. धनखड़ के यात्रा में अर्जेंटीना के कृषि-उद्योगों के अधिकारियों से भेंट की और भारतीय और स्थानीय कृषि उद्यमियों के साथ बातचीत की। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) के एक प्रतिनिधिमंडल ने मई 2018 में अर्जेंटीना का दौरा किया। विकास साझेदारी प्रशासन (डीपीए-II) प्रभाग, विदेश मंत्रालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)-कानपुर के अधिकारियों और विशेषज्ञों के एक तकनीकी प्रतिनिधिमंडल और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस कंप्यूटिंग (सी-डीएसी) ने 5-12 मई 2018 को अर्जेंटीना का दौरा किया ब्यूनस आयर्स में आईटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के तरीकों पर चर्चा की गई।

अर्जेंटीना के चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड सर्विसेज ने 27 सितंबर 2018 को ब्यूनस आयर्स में 'भारत के साथ निवेश और व्यापार के अवसरों' पर एक सेमिनार का आयोजन किया। अर्जेंटीना के विदेश और उपासना मंत्रालय के सहयोग से इंटर अमेरिकन बैंक फॉर डेवलपमेंट ने 7 जून 2018 को ब्यूनस आयर्स में 'भारत और लैटिन अमेरिका के बीच सहयोग का भविष्य' विषय पर एक लैटइंडिया संगोष्ठी का आयोजन किया। एक अर्जेण्टीनी व्यापार प्रतिनिधिमंडल, 'अर्जेंटीना हेकिया एल मुंडो' 13-25 अप्रैल 2018 में भारत का दौरा किया। यात्रा के दौरान, आर्थिक परिसंघ (एफईसी), ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एफईसी और मिलेनियल इंडिया इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स के बीच एक और समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए।

भारत और अर्जेंटीना के बीच संयुक्त आयोग की 5 वीं बैठक 14 जनवरी, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

अर्जेंटीना के राष्ट्रपति श्री मौरिसियो मैक्री ने 18 फरवरी, 2019 को भारत की राजकीय यात्रा की। यात्रा के दौरान रक्षा, नवीकरणीय, कृषि, दवा और संस्कृति सहित विविध क्षेत्रों में सहयोग समझौतों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग (बीएपीए+ 40) पर दूसरा उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 20-22 मार्च 2019 को ब्यूनस आयर्स में आयोजित किया जाएगा; भारत का प्रतिनिधित्व एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

बेलिज़

श्री सुदर्शन भगत, राज्य मंत्री (जनजातीय मामले) ने 14-16 मई 2018 से सरकार के आउटरीच कार्यक्रम के तहत बेलीज का दौरा किया। भारत सरकार के बीच राजनयिक/आधिकारिक पासपोर्ट रखने वाले व्यक्तियों के लिए वीजा माफी समझौता 30 अप्रैल 2018 से लागू हुआ।

बोलीविया

रेल राज्य मंत्री (एमओएस) श्री राजेन गोहेन ने 20 और 21 अप्रैल, 2018 को बोलीविया की आधिकारिक यात्रा की। उन्होंने बोलीविया के विदेश मंत्री और बोलिवियाई अधिकारियों के एक समूह के साथ बातचीत की, जिसमें विदेश व्यापार और एकीकरण, बिजली और ऊर्जा और सार्वजनिक निर्माण और आवास के उप मंत्रियों के साथ-साथ ला पाज़ के अन्य मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ बातचीत हुई। मंत्री की व्यस्तताओं में मी टेलीफेरिको - केबल कार प्रणाली और ला पाज़ में भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से बातचीत शामिल है।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 26 सितंबर, 2018 को 73वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के अवसर पर न्यूयॉर्क में बोलीविया के नए विदेश मंत्री श्री डिएगो पैरी रोड्रिग्ज के साथ द्विपक्षीय बैठक की। रेल मंत्रालय, इंडियन पोर्ट रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और चेन्नई और दिल्ली के मेट्रो निगमों के विशेषज्ञों ने सितंबर/अक्टूबर, 2018 में ला पाज़ में केबल कार सिस्टम पर 4-दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया। एक्जिम बैंक के एक प्रतिनिधिमंडल ने अक्टूबर 2018 में ला पाज़ का दौरा किया।

ब्राज़ील

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2018 में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर राष्ट्रपति श्री मिशेल टेमर से भेंट की। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 27 सितंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के समय ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान ब्राजील के विदेश मंत्री श्री अलॉयसियो न्यूनस फेर्रेरा फिल्हो से भेंट की। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 4 जून 2018 को प्रिटोरिया में भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए) की अनौपचारिक बैठक के लिए अपने देश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे ब्राज़ील के विदेश मामलों के उप मंत्री श्री मार्कोस बीज़र्रा एबॉट गाल्वा से भी भेंट की।

एयर चीफ मार्शल श्री बी.एस. धनोआ 4-8 जून 2018 से सद्भावना यात्रा पर गए थे। प्रो.लक्ष्मण कुमार बेहरा, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान और प्रो. हर्ष पंत, किंग्स कॉलेज लंदन ने 23-25 अक्टूबर, 2018 को नवल वार कॉलेज, रियो डी जनेरियो में आयोजित 'सिम्पोजियम ऑन इंडिया' में भाग लिया। बीसीएएस के महानिदेशक श्री कुमार राजेश चंद्र के नेतृत्व में दो-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 5-7 जून, 2018 से ब्रासीलिया का दौरा किया और आईसीएओ यात्री पहचान कार्यक्रम (आईसीएओ टीआरआईपी) की क्षेत्रीय संगोष्ठी और ब्रासीलिया में प्रदर्शनी में भाग लिया। ब्राजील से, ब्राजील के वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राउल मोटेलो के नेतृत्व में दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 6-10 अगस्त 2018 तक भारत का दौरा किया। ब्राजील के रक्षा उत्पाद विभाग के प्रमुख एयर वाइस मार्शल पाउलो चा के नेतृत्व में एक रक्षा प्रतिनिधिमंडल 10-13 अप्रैल 2018 को बेंगलुरु में आयोजित डेफएक्सपो 2018 में भाग लेने के लिए भारत आया था। ब्राज़ील इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड स्पेस के निदेशक ब्रिगेडियर एन्हेनहेरो ऑगस्टो लुइज़ डी कास्त्रो ओटेरो 6-8 सितंबर 2018 को बेंगलुरु स्पेस एक्सपो-2018 में भाग लेने के लिए भारत आए थे।

श्री एस. के. जायसवाल, महानिदेशक, सीएजी ने 6-17 अगस्त 2018 को ब्रासीलिया में सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस (एसएआई) ऑडिट प्रोफेशनल की सर्टिफिकेशन पायलट मीटिंग में भाग लेने के लिए ब्रासीलिया गए। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के कुमार भारतीय विभाग के प्रमुख डॉ.राजगोपाल एस ने 9-11 नवंबर, 2018 को साओ पाउलो में आयोजित एनकांत्रो लातीनी अमेरिकनो डी आयुर्वेद (ईएलएए) में भाग लेने के लिए ब्राजील का दौरा किया, जिसका उद्देश्य ब्राजील में आयुर्वेद को बढ़ावा देना था।

22 मई, 2018 को साओ पाउलो में आयोजित, संपूर्ण लैटिन अमेरिका में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए समाधान, उत्पाद, सेवाओं, प्रौद्योगिकी, नवाचारों और उपकरणों की सबसे बड़ी प्रदर्शनी, 'अस्पताल 2018' में फिक्की द्वारा एक इंडिया मंडप की स्थापना की गई थी, जहां स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की लगभग 50 भारतीय कंपनियों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) ने साओ पाओलो में 28-30 अगस्त 2018 से आयोजित सौर ऊर्जा उद्योग की छठी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन "इंटरसोलर-साउथ अमेरिका" में इंडिया पवेलियन का आयोजन किया, जहां लगभग 35 प्रमुख भारतीय कंपनियों ने ऊर्जा और संबंधित क्षेत्रों के प्रदर्शन में भाग लिया। बेसिक केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स एंड डाइज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (केमेक्सिल) ने साओ पाउलो में 28-30 अगस्त 2018 से आयोजित 32 वें डाई + केम ब्राज़ील इंटरनेशनल एक्सपो - 2018 में भाग लिया, इस प्रदर्शनी में लगभग 25 प्रमुख भारतीय कंपनियों ने भाग लिया।

हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ के नेतृत्व में एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने कृषि में अवसरों की पहचान करने के लिए अप्रैल 2018 से रियो डी जनेरियो का दौरा किया। राष्ट्रीय जूट बोर्ड (एनजेबी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर स्थायी बाजार संपर्क स्थापित करने और खाद्य ग्रेड गुणवत्ता जूट के निर्यात को बढ़ाने के लिए 18 अप्रैल 2018 को साओ पाउलो में भारत ब्राजील चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ भेंट की। भारत-ब्राजील चैंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से मिशन ने 14 नवंबर 2018 को रियो डी जनेरियो में एक सम्मेलन 'डूइंग बिजनेस विद इंडिया' का आयोजन किया।

साओ पाउलो में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र ने साओ पाउलो में प्रतिष्ठित यूनिब्स कल्चरल सेंटर में एक 'एक्सपीरियंस इंडिया' कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्यों और अन्य प्रचलित सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का उत्सव शामिल था।

चिली

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2018 में राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिएनेरा इचनीक से, एक बार सिंगापुर में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में और फिर ब्यूनस आयर्स में जी 20 में भेंट की। राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) ने 22 और 23 मई 2018 को और 1 और 2 अक्टूबर 2018 को दौरे किए। मई 2018 की यात्रा में, राज्य मंत्री ने भारत और चिली के बीच एक उच्च-स्तरीय संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर

प्रधान मंत्री ब्यूनस आयर्स में जी-20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर चिली के राष्ट्रपति, सेबस्टियन पिनेरा से मुलाकात करते हुए (30 नबंवर,2018)

फिदेल कास्त्रो, कार्लोस मैनुअल डी सेस्पेडेस के स्मारक और सैंटियागो में सांता इफेजेनिया सिमेट्री में मरियाना ग्रेजेल्स के स्मारक पर राष्ट्रपति श्रद्धांजलि देते हुए (21 जून, 2018)

किए। अक्टूबर 2018 की यात्रा के दौरान, राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) वी. के. सिंह (सेवानिवृत्त) ने आठवें सीआईआई इंडिया-एलएसी बिजनेस कॉन्क्लेव में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। चिली से, कृषि मंत्री एंटोनियो वॉकर 29 और 30 अक्टूबर 2018 को भारत आए।

कोलम्बिया

विदेश मंत्री (ईएएम) श्रीमती सुषमा स्वराज ने 24 सितंबर 2018 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के समय कोलंबिया के विदेश मंत्री श्री कार्लोस होम्स ट्रूजिलो से भेंट की।

एमओएस जनरल (डॉ.) वी. के. सिंह (सेवानिवृत्त) ने 3-5 अक्टूबर 2018 को कोलंबिया का दौरा किया और विदेश मंत्री कार्लोस होम्स ट्रूजिलो के साथ व्यापक वार्ता की। यात्रा के दौरान, भारत की पारंपरिक प्रणालियों, पर्यटन विकास और द्विपक्षीय निवेश समझौते के संवर्धन और संरक्षण पर संयुक्त व्याख्यात्मक घोषणापत्र पर सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

दूतावास की पहल पर, वाणिज्य, शिक्षा, आईटीईएस, पर्यटन में सहयोग का पता लगाने के लिए कोलम्बिया, कैलडास की विधानसभा से 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 4-7 सितंबर 2018 से भारत का दौरा किया, इस प्रतिनिधिमंडल में प्रांतीय विधानसभा के सदस्य, गवर्नर कार्यालय के प्रतिनिधि, चैंबर ऑफ कॉमर्स, कॉफी किसानों, गैर सरकारी संगठनों आदि के सदस्य शामिल थे।

29 नवंबर 2018 को, इसरो ने कोलंबियाई वायु सेना के पीएसएलवी-सी43/एचवाईएसएलएस मिशन पर एफएसीएसएटी 1 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह कोलंबियाई वायु सेना का पहला नैनोसेटेलाइट था। यह द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक अवसर था जो अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करता था।

दूतावास द्वारा मेडेलिन के चैंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से एक "मेक इन इंडिया" व्यापार और निवेश संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें कोलम्बियाई और भारतीय कंपनियों के 50 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

सीआईआई द्वारा भारतीय व्यापार मंच के 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 25-26 अप्रैल 2018 को कोलंबिया का दौरा किया।

बोगोटा में लेबोर और पोर्ट फ़ोलियो ग्रुप द्वारा 26 अप्रैल 2018 को आयोजित तीसरी बिग डेटा वर्ल्ड मीटिंग 2018 इवेंट में, भारत को बोगोटा में आयोजित होने वाले चौथी बिग डेटा वर्ल्ड मीटिंग 2019 के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर देश के रूप में आमंत्रित किया गया था।

न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान विदेश मंत्री की कोलंबिया के विदेश मंत्री कार्लोस होम्स ट्रूजिलो से मुलाकात (24 सितंबर, 2018)

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के एमडी और सीईओ, श्री नरेंद्र कुमार वर्मा ने कोलंबिया और इक्वाडोर में कंपनी के मौजूदा संचालन और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा करने के लिए कोलंबिया का दौरा किया।

एक सोलह सदस्यीय केमेक्सिल प्रतिनिधिमंडल ने 3 सितंबर 2018 को बोगोटा का दौरा किया।

आठ वर्ष के अंतराल के बाद ईईपीसी के आईएनडीईई के बैनर तले फेरिया इंटरनेशियल डी बोगोटा में साझेदार देश के रूप में भारत की प्रभावशाली उपस्थिति थी। पचहत्तर से अधिक भारतीय कंपनियों ने मेले में भाग लिया और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर के साथ एक उत्कृष्ट प्रतिक्रिया प्राप्त की।

कोलंबिया के तीसरे सबसे बड़े वित्तीय समूह, कोलंबिया के ग्रुपो बोलिवर के वरिष्ठ अधिकारियों का एक समूह ने अक्टूबर के मध्य में ने दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई का दौरा किया और वित्तीय समावेशन, डिजिटल अर्थव्यवस्था, विमुद्रीकरण और बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में आईसीटी से भारत के अनुभवों को जाना।

यूनिटेक विश्वविद्यालय में 16 अक्टूबर 2018 से एक भारतीय सप्ताह का आयोजन किया गया था।

जेएनयू में स्पेनिश, पुर्तगाली, इतालवी और लैटिन अमेरिकी अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर राजीव सक्सेना ने कोलंबिया का दौरा किया और 4 मई 2018 को बोगोटा में राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मिशन पर एक व्याख्यान दिया।

कोस्टा रिका

राजदूत द्वारा 29 अगस्त 2018 को परिचय पत्र की प्रस्तुति के बाद आयोजित चर्चा के दौरान, कोस्टा रिका के नए राष्ट्रपति ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षाविदों और ऐसे अन्य क्षेत्रों में भारत के साथ मजबूत संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुकता दिखाई।

इक्वाडोर

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 24 सितंबर को न्यूयॉर्क में यूएनजीए के हाशिए पर विदेश मंत्री श्री जोस सैमुअल वालेंसिया अमोरेस से भेंट की।

विदेश मंत्री सुश्री मारिया फ़र्नान्डा एस्पिनोसा ने 4 और 5 अप्रैल, 2018 को बाकू में आयोजित गुट निरपेक्ष आंदोलन के मध्य अवधि के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के मौके पर विदेश

न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान विदेश मंत्री की इक्वेडोर के विदेश मंत्री जोस वालेंसिया अमोरेस से मुलाकात (24 सितंबर, 2018)

मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज से भेंट की।

हाइड्रोकार्बन मंत्री कार्लोस पेरेज़ ने नई दिल्ली में 10-12 अप्रैल 2018 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम में भाग लिया।

अल साल्वाडोर

अल साल्वाडोर ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए।

ग्रेनेडा

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने 13-15 मई, 2018 तक ग्रेनाडा की आधिकारिक यात्रा की, उन्होंने गवर्नर जनरल डॉ. कैसिल ला ग्रेनेड, प्रधानमंत्री श्री कीथ मिशेल, विदेश मंत्री श्री पीटर डेविड और ग्रेनेडा के स्वास्थ्य मंत्री श्री निकोलस स्टील से भेंट की।

सुश्री शादेल नैक कॉम्पटन ने 30 अप्रैल 2018 को, ग्रेनाडा को भारत के पहले मानद महावाणिज्यदूत के रूप में नियुक्ति का साधन प्रदान किया।

गुयाना

मानव संसाधन और विकास (एचआरडी), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प राज्य मंत्री डॉ. सत्य पाल सिंह ने 8-11 मई 2018 को गुयाना का दौरा किया। जनस्वास्थ्य मंत्री डॉ. करेन कमिंग्स, लिम्फैटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने के लिए ग्लोबल एलायंस की 10वीं बैठक में जून में नई दिल्ली आए थे। गुयाना के प्रधान मंत्री, डॉ. मूसा नागामुटू, ने पुडुचेरी में विश्व तमिल आर्थिक सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए एक निजी यात्रा की।

भारत को जानो कार्यक्रम के अंतर्गत गुयाना के 19 नागरिकों ने भारत का एक परिचय दौरा किया। वर्ष के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने 4 मई 2018 को भारतीय आगमन दिवस की 180वीं वर्षगांठ मनाई; यहाँ रक्षाबंधन (27 अगस्त 2018) जैसे भारतीय त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनमें गरबा नृत्य (18 अक्टूबर 2018) और राष्ट्रीय राजधानी दिवस (31 अक्टूबर 2018) शामिल हैं।

ग्वाटेमाला

उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू 6-8 मई 2018 को ग्वाटेमाला गए थे। यह ग्वाटेमाला में किसी भारतीय उपराष्ट्रपति की पहली यात्रा थी। विदेश सेवा संस्थानों के बीच सहयोग और भारत में ग्वाटेमाला के अंग्रेजी शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

फार्मास्युटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (फार्मेक्सिल) के नेतृत्व में 22 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने ग्वाटेमाला का दौरा किया।

भारत ने जून 2018 में ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी फुएगो के विस्फोट के बाद आपदा राहत के लिए 100,000 अमेरिकी डॉलर का दान दिया।

होंडुरस

जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री श्री सुदर्शन भगत ने 10-13 मई 2018 को होंडुरास का दौरा किया, उन्होंने कार्यवाहक विदेश मंत्री श्रीमती मारिया डोलोरेस अग्योरो और कृषि और पशुधन मंत्री से भेंट की।

फार्मेक्सिल ने सैन पेड्रो सुला के लिए 22 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

उप राष्ट्रपति की ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति, जिमी मोरालेस से मुलाकात (07 मई, 2018)

निकारागुआ

राज्य मंत्री (एमओएस) [ग्रामीण विकास और भूमि संसाधन] श्री राम कृपाल यादव 13-16 मई 2018 को निकारागुआ गए, उन्होंने निकारागुआ के विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और उत्पादन, उपभोग और व्यापार के लिए राष्ट्रीय प्रणाली के सदस्यों के साथ बैठकें कीं। निकारागुआ के विकास, उद्योग और व्यापार मंत्री श्री ऑरलैंडो डेलगाडिलो ने 1-2 अक्टूबर 2018 को चिली के सेंटियागो में सीआईआई द्वारा आयोजित इंडिया-लाक कॉन्क्लेव में भाग लिया और राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) वीके सिंह (सेवानिवृत्त) के साथ बातचीत की।

पनामा

उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू 8-10 मई 2018 को पनामा गए थे। इस अवसर पर, भारत ने जैव विविधता और ड्रग डिस्कवरी का एक केंद्र स्थापित करने के लिए पनामा को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर और नवाचार और प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर के दो ऋणों की घोषणा की। राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट पर वीजा की छूट पर भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

पनामा द्वारा भारतीय व्यापार और अन्य आवेदकों के लिए पांच वर्षीय कई प्रवेश वीजा की सुविधा शुरू की गई थी।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने सितंबर 2018 में यूएनजीए के समय पनामा के उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री के साथ भेंट की।

भारत-पनामा विदेश कार्यालय परामर्श भारत में 11 सितंबर 2018 को आयोजित किया गया था।

निकारागुआ के विदेश मामलों और उपासना मंत्री, डेनिस मोनकाडाकोलिंड्रेस 1 मार्च, 2019 को दिल्ली में विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा आयोजित की जा रही भारत एसआईसीए विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में भाग लेने के लिए पनामा और कोस्टा रिका के विदेश मंत्रियों को भी निमंत्रण भेजे गए हैं और उनकी पुष्टि की प्रतीक्षा की जा रही है।

पनामा के राष्ट्रपति श्री जुआन कार्लोस वरेला की भारत की यात्रा मार्च/अप्रैल 2019 के लिए प्रस्तावित की गई है और यह मंत्रालय के विचाराधीन है।

उप राष्ट्रपति पनामा में पनामा के राष्ट्रपति, श्री जुआन कार्लोस वरेला रोड्रिगेज के साथ पनामा नहर पर (09 मई, 2018)

पैराग्वे

कोयला और खान राज्य मंत्री श्री हरिभाई पराथीभाई चौधरी 8-10 मई 2018 को पैराग्वे का दौरा किया। उन्होंने पैराग्वे के विदेश मामलों के मंत्री श्री इलादियो लोइज़गा से भेंट की।

पेरू

उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू 10-12 मई 2018 को पेरू गए थे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति ने पेरू के राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री और कई अन्य मंत्रियों के साथ व्यापक चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस के अध्यक्ष और पेरू-भारत संसदीय मैत्री लीग के अध्यक्ष के साथ भी बातचीत की। भारतीय समुदाय के साथ बातचीत, भारत और पेरू के बीच कूटनीतिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ का उत्सव अन्य प्रमुख कार्यक्रम थी। इस यात्रा में दोनों सरकारों के बीच नई और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

भूविज्ञान और खनिज संसाधनों में सहयोग पर जेडब्ल्यूजी की दूसरी बैठक 13 सितंबर 2018 को लीमा में आयोजित की गई थी। खान मंत्रालय के सचिव श्री अनिल मुकीम और खान मंत्रालय के उपाध्यक्ष श्री लुइस मिगुएल इनकाउस्टेगुइज़ेवैलोस ने अपने-अपने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

भारत और पेरू के बीच व्यापार समझौते पर वार्ता का दूसरा दौर 9-12 अप्रैल 2018 को लीमा में आयोजित किया गया था और भारत-पेरू व्यापार समझौते पर तीसरा दौर 4-7 दिसंबर 2018 से नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। भारत से कई प्रतिनिधिमंडलों ने पेरू दौरा किया है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल ने अप्रैल में लीमा का दौरा किया और एक क्रेता विक्रेता मीट (बीएसएम) का आयोजन किया, एसआरटीईपीसी ने जुलाई में "सोर्स इंडिया 2018" पर एक रोड शो किया, एक खनन प्रतिनिधिमंडल ने एक्सपो मीना पेरू 2018 में भाग लिया, गोल्ड फर्मों के एक बड़े प्रतिनिधिमंडल ने अक्टूबर में लीमा में व्यापक व्यापार परामर्श आयोजित किया, काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स (सीएलई) के प्रतिनिधिमंडल ने अक्टूबर में एक बीएसएम और एसआरटीईपीसी और आईसीआईसी के समन्वय के अंतर्गत 26 भारतीय कपड़ा कंपनियों ने नवंबर में इंडिया

पविलियन की स्थापना करके एक्सपो टेक्सिल 2018 में भाग लिया। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (आईटीपीओ) के तत्वावधान में लीमा में 21-25 मार्च 2019 से एक बहु-उत्पाद व्यापार मेला "इंडिया शो 2019" आयोजित होगा।

उप राष्ट्रपति लीमा, पेरू में प्रेजिडेंशियल प्लेस में पेरू के राष्ट्रपति श्री मार्टिन विजकारा के साथ (11 मई, 2018)

उरुग्वे

विकास साझेदारी प्रशासन (डीपीए-II) प्रभाग, विदेश मंत्रालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-कानपुर और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस कंप्यूटिंग (सी-डीएसी) के अधिकारियों और विशेषज्ञों के एक तकनीकी प्रतिनिधिमंडल ने मोंटेवीडियो में आईटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के तरीकों पर चर्चा करने के लिए 7-11 मई, 2018 से उरुग्वे का दौरा किया।

वेनेजुएला

वेनेजुएला भारत के कच्चे तेल के छठे सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। दूतावास ने एक भारतीय चाय प्रदर्शनी और चाय-का स्वाद लेने (अप्रैल 2018), भारतीय प्लास्टिक की प्रदर्शनी (मई 2018), भारतीय घरों में प्लास्टिक का जादू' (अगस्त 2018) पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया।

कैरिबियन देश

एंटीगुआ और बारबुडा

राज्य मंत्री (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और वाणिज्य और उद्योग), श्री सी आर चौधरी ने 23-25 अप्रैल 2018 को एंटीगुआ और बारबुडा का दौरा किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के समय, विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा

स्वराज ने 26 सितंबर, 2018 को एंटीगुआ और बारबुडा के विदेश मंत्री श्री चेत ग्रीन से भेंट की।

सितंबर 2017 में विनाशकारी तूफान के बाद, हन्ना थॉमस अस्पताल और बारबुडा डाक घर के पुनर्वास के लिए, भारत ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के माध्यम से भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि से 100,000 अमेरिकी डॉलर और 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक और नकद सहायता दी। इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के माध्यम से 4,00,000 अमेरिकी डॉलर के अनुदान पर स्वास्थ्य केंद्रों और स्कूलों में सौर पैनलों की स्थापना का काम चल रहा है।

बारबाडोस

विधि और न्याय और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री पी. पी. चौधरी ने विदेश मंत्रालय के आउटरीच कार्यक्रम 'अभिनव पहल' के अंतर्गत 25-28 अप्रैल 2018 से बारबाडोस का दौरा किया और 26 अप्रैल 2018 को एक सामुदायिक स्वागत के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री फ्रंडेल स्टुअर्ट से मिले। उन्होंने अटॉर्नी जनरल और गृह मामलों के मंत्री श्री एड्रिएल डी. ब्रैथवेट क्यूसी, उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य और लघु व्यवसाय विकास मंत्री श्री डोनविलइनिस, विदेश मामलों और विदेश व्यापार मंत्री सुश्री मैक्सिन मैक्लेन, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री और श्री डाकोस्टा जोन्स जेपी के साथ विस्तृत द्विपक्षीय चर्चा की।

बहामा

बहामा सरकार ने अप्रैल 2018 में घोषणा की कि बहामा जाने वाले भारतीयों को आगमन पर वीजा जारी किया जाएगा। बाद में इसने भारतीय आगंतुकों की अतिरिक्त सुविधा चयन श्रेणी शुरू की। इसके अलावा, 29 नवंबर 2018 को डिप्लोमैटिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की माफी के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

डोमिनिका का कॉमनवेल्थ

भारत की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने 'अभिनव पहल' आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत 11 और 12 मई 2018 को डोमिनिका का दौरा किया। वहाँ उन्होंने राष्ट्रपति और कार्यकारी प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से भेंट की।

क्यूबा

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की जून 2018 में क्यूबा की पहली यात्रा के साथ भारत-क्यूबा द्विपक्षीय संबंध ने नई गति प्राप्त की। उनके साथ इस्पात राज्य मंत्री और दो संसद सदस्य भी थे। अपने समकक्ष के साथ एक बैठक आयोजित करने के अलावा, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने महात्मा गांधी, क्यूबा के राष्ट्रीय नायक जोस मार्टी और क्रांतिकारी नेता फिदेल कास्त्रो को श्रद्धांजलि अर्पित की।

उन्होंने प्रसिद्ध क्यूबा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का दौरा किया और हवाना विश्वविद्यालय में "भारत और वैश्विक दक्षिण" पर विद्वानों और राजनयिकों को संबोधित किया। राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस फ्रेमवर्क समझौते के अंतर्गत क्यूबा में 100 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एलओसी की भारत की प्रस्ताव की घोषणा की।

जैव प्रौद्योगिकी और बीआईआरएसी (जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद) विभाग के एक प्रतिनिधिमंडल ने 20-23 जून 2018 को क्यूबा का दौरा किया और चर्चा की और बीआईआरएसी, कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ टेक्नोलॉजी (केआईएचटी) और 'बायो क्यूबा फार्मा' के बीच एक त्रिपक्षीय पत्र पर हस्ताक्षर किए।

भारत ने 29 अक्टूबर -2 नवंबर 2018 से हवाना (एफआईएचएवी) 2018 के 36वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लिया, जिसमें 45 भारतीय कंपनियां मौजूद थीं। क्यूबा के एस्कॉर्ट्स और कृषि मंत्रालय के बीच एक आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए गए थे।

भारत ने क्यूबा की सांस्कृतिक पर्यटन एजेंसी पैराडिसो द्वारा आयोजित पहले गैस्ट्रोकेट 2019 में भाग लिया। इस आयोजन के दौरान, 8 जनवरी 2019 को "भारत दिवस" के रूप में मनाया गया जिसमें दो भारतीय रसोइयों ने भारतीय व्यंजनों का प्रदर्शन किया।

मार्च 2019 में भारतीय एलओसी के अंतर्गत निर्मित थोक सम्मिश्रित उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया गया।

आईटीईसी दिवस: भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (I आईटीईसी) दिवस 6 दिसंबर 2018 को इंडिया हाउस में मनाया गया। इस कार्यक्रम में आईटीईसी के लगभग 100 पूर्व छात्रों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि व्यापार और विदेश निवेश के कार्यकारी उपाध्यक्ष विल्मा सांचेज सेम्पे थे, विदेश मंत्रालय में एशिया डिवीजन के महानिदेशक भी उपस्थित थे।

गास्त्रोकल्ट: जून 2018 में भारत के राष्ट्रपति की क्यूबा यात्रा के दौरान की गई प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, भारत क्यूबा सांस्कृतिक पर्यटन एजेंसी पैराडिसो द्वारा आयोजित किए जा रहे भारत के पहल गास्त्रोकल्ट 2019 में भाग लेगा। गास्त्रोकल्ट 2019 का पहला संस्करण भारत को समर्पित किया जाएगा। भारत, मैक्सिको, पेरू, स्पेन और क्यूबा पांच देशों के विशेषज्ञ शेफों ने 8 से 10 जनवरी तक बातचीत की। गास्त्रोकल्ट 2019 शैक्षणिक कार्यक्रम भी भारत को समर्पित होगा और 8 जनवरी को "भारत दिवस" के रूप में मनाया जाएगा, भारत के दो अनुभवी शेफ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के पूरक सहित भारतीय व्यंजनों का प्रदर्शन करेंगे।

पीबीडी: मिशन 2019 प्रवासी भारतीय दिवस और सत्य वार्ता का आयोजन करेगा। कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। गुरु नानक की 550वीं जयंती भी मनाई जाएगी।

क्यूबा के सीआईटी के मंत्री की भारत यात्रा: प्रथम उप मंत्री श्री गोंजालेज विडाल विल्फ्रेडो 4 और 5 फरवरी 2019 को हैदराबाद, तेलंगाना में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जिसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे और वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय आईटी प्रदर्शनी और सम्मेलन इंडिया सॉफ्ट और इंडिया एक्सपो (आईएनडीईई) के 19वें संस्करण में भाग लेंगे। ।

उर्वरक संयंत्र: भारत के 2.712 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि के एलओसी के साथ बनाये जा रहे थोक सम्मिश्रण उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन फरवरी-मार्च 2019 में किया जाएगा। 15 जनवरी 2019 तक काम पूरा हो जाएगा, ताकि संयंत्र 28 फरवरी 2019 तक चालू हो जाए। इस अवसर पर क्रांति के कमांडर रामिरो वल्डेस के उपस्थित रहने की संभावना है।

डोमिनिकन गणराज्य

भारत ने सेंटो डोमिंगो में एक मानद महावाणिज्यदूत नियुक्त किया।

हाइती

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री विजय सांपला ने 18-21 अप्रैल, 2018 को आउटरीच कार्यक्रम 'अभिनव पहल' के अंतर्गत हाइती का दौरा किया। यात्रा के दौरान, विदेश राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री जैक गाई लाफोंटेंट, श्री जोवेनियल मोइज़, हैती गणराज्य के राष्ट्रपति श्री एंटोनियो रोड्रिग्यु और हाइती गणराज्य के विदेश मंत्री के साथ बैठकें कीं।

जमाइका

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जमाइका के प्रधानमंत्री श्री एंड्रयू होल्नेस ने अप्रैल 2018 में लंदन में सीएचओजीएम, जुलाई 2018 में जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन; और ब्यूनस आयर्स में नवंबर 2018 में जी 20 शिखर सम्मेलन के समय भेंट की। जमाइका सरकार ने सीनेटर ऑबिन हिल को किंग्स्टन में निवास के साथ भारत में जमाइका का उच्चायुक्त नियुक्त किया।

मेक्सिको

मैक्सिकन सांसद और आईपीयू के अध्यक्ष सुश्री गैब्रियला क्यूवास बैरोन ने 11 दिसंबर 2018 को दिल्ली में उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू से भेंट की। मेक्सिको की ऊर्जा मंत्री, सुश्री रोशियो नाहले 10-12 फरवरी को पेट्रोटेक 2019 में भाग लेने के लिए भारत आई थीं।

अध्ययन दौरे के हिस्से के रूप में, 16-सदस्यीय राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज टीम ने मई 2018 में मैक्सिको का दौरा किया। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स (आईसीडब्ल्यूए) के निमंत्रण पर, मैक्सिको के राजदूत एडुआर्डो रोल्डन ने मई 2018 में ब्रासीलिया में भारत-एलएसी साझेदारी पर द्वितीय आईसीडब्ल्यूए-एलएसी सम्मेलन में भाग लिया।

डुरंगो राज्य के आर्थिक विकास सचिव, विदेश व्यापार के सचिव, श्री जुआन कार्लोस बेकर और क्विरोगा, ऊर्जा मंत्रालय के सचिव, डॉ. एल्डो फ्लोरेस ने भारत का दौरा किया। पार्ले ने मैक्सिको में पश्चिमी गोलार्ध में अपना पहला विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया और टेक महिंद्रा ने अगुस्कालिएंट्स राज्य में अपना दूसरा कार्यालय खोला। मेक्सिको के सेमेक्स ने भारत में अपनी निवेश योजना की घोषणा की। भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद (एफ एवं बी क्षेत्र में चालीस कंपनियां और निर्माण क्षेत्र में पैंतालीस कंपनियां), नेशनल जूट बोर्ड, सिंथेटिक और रेयन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल(निर्माण क्षेत्र में पैंतीस कंपनियां) और चमड़ा निर्यात परिषद (नौ कंपनियां) ने भारतीय उद्योग परिसंघ के तत्वावधान में कई भारतीय कंपनियों ने प्रमुख व्यापारिक प्रदर्शनियों में भाग लिया। पीडब्ल्यूसी मेक्सिको के सहयोग से दूतावास ने एक प्रकाशन " डूइंग बिजनेस इन मेक्सिको: ए गाइड फॉर इंडियन इनवेस्टर्स" प्रकाशित किया, ताकि भारत के साथ व्यापारिक जुड़ाव आसान हो सके।

भारत ने 10-28 अक्टूबर 2018 से पहली बार, गुआनाजुआतो में कर्वेटिनो अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के 46वें संस्करण में ´सम्मानित अतिथि´ देश के रूप में भाग लिया। मालविका सारुकाई (भरतनाट्यम) और मणिपुरी जागोई मरुप समूह (मणिपुरी), शाहिद परवेज खान (सितार), रश्मि अग्रवाल (सूफी और भक्ति), ओजोन राग (फ्यूजन) और समंदर खान मंगनियार (राजस्थानी लोक) सहित कई नृत्य समूहों ने भाग लिया। भारत ने खाद्य उत्सवों, फिल्म शो, योग प्रदर्शनों, प्रदर्शनियों (वस्त्र, गुड़िया और तस्वीरें), कार्यशालाओं और शैक्षणिक सम्मेलनों में भी भाग लिया। आईसीसीआर ने गुआनाजुआतो के नगर पालिका को महात्मा गांधी की एक प्रतिमा दान की।

नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया (एनबीटी) और फेरिया इंटरनेशियल डी लिब्रो ग्वाडलजारा ने जुलाई 2018 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार भारत ग्वाडलजारा में 2019 अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के लिए अतिथि देश होगा।

सूरीनाम

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 19-21 जून, 2018 को सूरीनाम की पहली राजकीय यात्रा की, जिसमें शामिल था, जिसमें इस्पात राज्य मंत्री श्री विष्णु देव साई भी शामिल थे। भारत और सूरीनाम के बीच आईसीटी में सेंटर ऑफ एक्जीलेंस, चुनाव अधिकारियों के बीच सहयोग, राष्ट्रीय अभिलेखागार, राजनयिक संस्थानों के बीच सहयोग और दोनों देशों के राजनयिक कर्मियों के आश्रितों के पारिश्रमिक रोजगार के क्षेत्रों में पांच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। यात्रा के दौरान 27.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए ईबीएस ट्रांसमिशन लाइन और चेतक हेलीकॉप्टरों के रखरखाव के लिए 3.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के दो एलओसी समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा भारत के राष्ट्रपति को आईएसए के अनुसमर्थन के उपकरण सौंपने के बाद सूरीनाम के गांवों के ग्रामीण विद्युतीकरण की दिशा में आईएसए परियोजना के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक एलओसी की घोषणा भी की गई थी।

उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने 9 सितंबर, 2018 को शिकागो में विश्व हिंदू कांग्रेस के हाशिये पर गणराज्य सूरीनाम के उपाध्यक्ष श्री अश्विन अधीन से भेंट की। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 26 सितंबर, 2018 को

न्यूयॉर्क में 73वें यूएनजीए के समय सूरीनाम के विदेश मंत्री सुश्री यल्दिज़ पोलाक बेइगल के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

आईसीसीआर द्वारा 27 मई -7 जून 2018 के दौरान सूरीनाम में भारतीय आगमन की 145वीं वर्षगांठ में भाग लेने के लिए डॉ. राधिका चोपड़ा के नेतृत्व में चार सदस्यीय संगीत समूह को प्रायोजित किया गया था। 18-23 जून 2018 से परमारिबो में विरासत और दासता पर आधारित श्रम सम्मेलन में भारत के पांच विद्वानों ने भाग लिया।

राष्ट्रपति सूरीनाम में राष्ट्रपति भवन में उनके स्वागत समारोह के दौरान सम्मान गारद का निरीक्षण करते हुए (20 जून, 2018)

उप राष्ट्रपति शिकागो में द्वितीय विश्व हिंदू कांग्रेस के दौरान सूरीनाम के उप राष्ट्रपति, अश्विन अधिन से मुलाकात करते हुए (09 सितंबर, 2018)

सेंट किट्स एंड नेविस

राज्य मंत्री (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और वाणिज्य और उद्योग), श्री सी. आर. चौधरी ने आउटरीच कार्यक्रम 'अभिनव पहल' के अंतर्गत 25-28 अप्रैल 2018 को सेंट किट्स एंड नेविस का दौरा किया।

सेंट लूसिया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 अप्रैल 2018 को लंदन में सीएचओजीएम के समय सेंट लूसिया के प्रधानमंत्री श्री एलन चैस्टरनेट से भेंट की।

सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस

कानून और न्याय एवं कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री पी पी चौधरी ने 22-24 अप्रैल 2018 को आउटरीच कार्यक्रम 'अभिनव पहल' के अंतर्गत सेंट विन्सेंट और ग्रेनेडाइंस का दौरा किया, यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री डॉ. राल्फ गोंसाल्वेस और विदेश मंत्रालय में स्थायी सचिव श्रीमती सैंडी पीटर्स-फिलिप्स के साथ भेंट की।

त्रिनिडाड और टोबैगो

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 अप्रैल 2018 को सीएचओजीएम सम्मेलन के अवसर पर लंदन में त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री डॉ कीथ राउली से भेंट की।

एक आईसीसीआर प्रायोजित 8 सदस्य कव्वाली समूह ने उस्ताद शाहिद नियाजी के नेतृत्व में 12-15 जुलाई 2018 तक टी एंड टी का दौरा किया। अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट, संस्कृति विभाग, यूपी सरकार द्वारा प्रायोजित एक 18 सदस्यीय रामलीला समूह ने 17-23 जनवरी 2018 को "कैरिबियन में रामलीला यात्रा" के हिस्से के रूप में त्रिनिदाद और टोबैगो का दौरा किया। 90 वर्ष से अधिक आयु के 110 बुजुर्ग पीआईओ को विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा हस्ताक्षरित फोटो-फ्रेमयुक्त पत्र प्रस्तुत किए गए। आयोजन के लिए खादी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा विशेष रूप से अंगवस्त्रम भी प्रस्तुत किए गए। हथकरघा आयुक्त, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित, भारत के पांच प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कारीगरों के एक समूह ने 28 अक्टूबर से 5 नवंबर 2018 तक त्रिनिदाद और टोबैगो का दौरा किया और नेशनल काउंसिल फॉर इंडियन कल्चर (एनसीआईसी) द्वारा आयोजित वार्षिक दिवाली नगर महोत्सव में भाग लिया।

9

संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं कानूनी और संधियाँ प्रभाग

संयुक्त राष्ट्र महासचिव की यात्रा

संयुक्त राष्ट्र महासचिव (यूएनएसजी), श्री एंटोनियो गुटेरेस ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में नई दिल्ली में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन में भाग लिया, कन्वेंशन में पचास से अधिक देशों के नेताओं ने भाग लिया, जिसमें यूएनएसजी ने कहा कि 'स्वच्छ भारत अभियान' के अंतर्गत "खुले में शौच मुक्त समाज" पर भारत में चल रहा काम वैश्विक स्वच्छता आँकड़ों को तेजी से बदल रहा है।

महासचिव ने अपनी भारत यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शासी निकाय की पहली बैठक को चिह्नित करने के लिए एक कार्यक्रम में भाग लिया।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी [फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ] को चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिल्ली में 3 अक्टूबर को एक विशेष समारोह में, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पुरस्कार प्रदान किया। वे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली महासभा में भाग लेने के लिए भारत आए थे।

निर्वाचन

सभी अठारह उम्मीदवार देशों में से सबसे अधिक वोट (193 में से 188) प्राप्त करने पर भारत को 2019-2021 की अवधि के लिए मानव अधिकार परिषद (एचआरसी) के लिए चुना गया था। भारत 1 जनवरी 2019 से शुरू होने वाले तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए एचआरसी पर काम करेगा।

एशिया-प्रशांत समूह और लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन समूह (जीआरयूएलएसी) में चुनाव लड़ी जाने वाली सभी सीटों में सबसे अधिक वोट (चौवन में से छियालीस) के साथ भारत को 2019-2022 की अवधि के लिए गैर-सरकारी संगठनों (सीएनजीओ) की समिति में फिर से चुना गया था। भारत 1 जनवरी 2019 से चार वर्ष के कार्यकाल के लिए सीएनजीओ पर काम करेगा।

भारत को पाँच संयुक्त राष्ट्र निकायों 2019-21 की अवधि के लिए अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय पर आयोग (सीसीपीसीजे); 2019-2021 की अवधि के लिए यूएनडीपी/यूएनएफपीए/यूएनओपीएस के कार्यकारी बोर्ड; संयुक्त राष्ट्र महिला (यूएन-वुमन के कार्यकारी बोर्ड) 2019-2021 के लिए; सीपीडी (जनसंख्या और विकास पर आयोग) 16 अप्रैल 2018 से 2021 तक; और 16 अप्रैल 2018 से 2021 तक सीएसओसीडी (सामाजिक विकास आयोग) के लिए भी चुना गया।

29 अक्टूबर से 16 नवंबर, 2018 तक दुबई में आईटीयू प्लीनिपोटेंसरी कांफ्रेंस में हुए चुनावों में भारत को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ परिषद (आईटीयू) के सदस्य के रूप में फिर से

प्रधान मंत्री ब्यूनस आयर्स में जी-20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महा सचिव, एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात करते हुए (29 नवंबर, 2018)

चुना गया।भारत 1869 से आईटीयू का सदस्य रहा है और 1952 से नियमित रूप से आईटीयू परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है।

राजदूत प्रीति सरन को 5 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार समिति (सीईएससीआर) की संयुक्त समिति की एशिया-प्रशांत सीट पर 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2022 तक के लिए निर्विरोध चुना गया।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (एचआरसी)

भारत को 2019-2021 के लिए मानवाधिकार परिषद का सदस्य निर्वाचित किया गया, भारत ने अक्टूबर 2018 में परिषद के लिए चुने गए सभी सदस्यों के बीच सबसे अधिक वोट प्राप्त किए।भारत ने ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में फरवरी से सितंबर 2018 के बीच आयोजित परिषद के तीन नियमित सत्रों में रचनात्मक भूमिका निभाना जारी रखा।

भारत ने यूनिवर्सल आवधिक समीक्षा प्रक्रिया के तीसरे चक्र में अपनी सक्रिय भागीदारी जारी रखी, 2018 में की गई समीक्षा में बयालीस में से उनतीस सदस्य राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप किया गया।

प्रवासन पर वैश्विक कम्पैक्ट

सुरक्षित, सुव्यवस्थित और नियमित प्रवासन के लिए वैश्विक कॉम्पैक्ट पर अंतर-सरकारी सहमति वाला पाठ जुलाई 2018 में अठारह महीने की बातचीत के बाद संपन्न हुआ।नियमित रूप से कानूनी प्रवास के सकारात्मक पहलुओं सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लाभों और चुनौतियों को रेखांकित करते हुए, भारत वार्ता में प्रमुख साझेदार था, इसने एक संतुलित और बारीक दृष्टिकोण के लिए बहस की। दिसंबर 2018 में मोरक्को में अंतर-सरकारी सम्मेलन में और उसके बाद 73वें यूएनजीए में सहमत पाठ को अपनाया जाएगा।

2030 एजेंडा और एसडीजी

जुलाई 2018 में उच्च-स्तरीय राजनीतिक फोरम में, आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र-हैबिटैट के शासी निकाय के अध्यक्ष की अपनी क्षमता में भाग लिया और शहरीकरण पर एसडीजी -11 पर विचार-विमर्श का नेतृत्व किया।

विकास के लिए वित्त पोषण पर अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा के संदर्भ में, भारत ने अपने नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए संयुक्त राष्ट्र टैक्स ट्रस्ट फंड में योगदान करने वाला पहला देश बन गया, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों को संयुक्त राष्ट्र कर समिति की चर्चाओं में भाग लेने में मदद करना है।

मध्य-अवधि की समीक्षा के लिए भारत ने न्यूनतम विकसित देशों (एलडीसी), भूमि से घिरे विकासशील देश (एलएलडीसी) और छोटे द्वीपीय विकासशील देश (एसआईडी) (ओएचआरएलएलएस) के लिए उच्च प्रतिनिधि के कार्यालय को 2019 में एलएलडीसी के लिए एक्शन ऑफ वियना प्रोग्राम का कार्यान्वयन की मध्यावधि समीक्षा हेतु 250,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है ।

संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली सुधार

भारत ने संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रस्तावों का समर्थन किया। यूएनएसजी के प्रस्ताव के आधार पर, महासभा ने संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली (यूएनडीएस) को पुनः तैनात करने पर एक प्रस्ताव अपनाया।यूएनडीएस सुधार रणनीति के केंद्र में नई रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर (आरसी) प्रणाली है, जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों को काम करने में मदद करना है।

सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे (यूनेस्को)

कार्यकारी बोर्ड का 204 वां सत्रः भारत ने 4-17 अप्रैल 2018 से पेरिस में आयोजित यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड (ईएक्सबी) के 204वें सत्र में भाग लिया, जिसकी कार्यसूची में तैंतीस मद थे। भारत के कार्यकारी बोर्ड के प्रतिनिधि, प्रोफेसर जे एस राजपूत ने सत्र में अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि यूनेस्को ने रणनीतिक परिवर्तन के बारे में बात की और महात्मा गांधी की विरासत के **150 वर्ष पूरे होने और गांधीवादी दर्शन के बारे में भी बताया।**

विज्ञान की लोकप्रियता के लिए यूनेस्को-कलिंग पुरस्कार (पिक्सेल): यूनेस्को- कलिंग पुरस्कार सबसे पुराना यूनेस्को पुरस्कार है और इसे 1951 में स्थापित किया गया था। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, उड़ीसा सरकार और कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित है। यूनेस्को ने वित्तीय योगदान और पुरस्कार की राशि 20,000 डॉलर से 40,000 डॉलर करने के लिए भारत सरकार और दाताओं का आभार व्यक्त किया।

28 से 30 मई, 2018 तक बच्चों के लिए न्याय पर विश्व कांग्रेस: यूनेस्को के संरक्षण में, 28-30 मई 2018 को बच्चों के लिए न्याय पर विश्व कांग्रेस आयोजित किया गया था। इस आयोजन में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मदन सिंह लोकुर के नेतृत्व में चौदह उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ने भाग लिया। जस्टिस लोकुर मंच पर पैनल वक्ता भी थे।

अंतर्राष्ट्रीय जल विज्ञान कार्यक्रम (आईएचपी) के अंतर सरकारी परिषद का 23वां सत्र: 11-15 जून 2018 को पेरिस में आयोजित किया गया था। आईएचपी परिषद के सभी छत्तीस सदस्यों द्वारा जल और स्वच्छता (एसडीजी 6) के सतत विकास लक्ष्य पर बेहतर संवाद और समन्वय की आवश्यकता को मान्यता दी गई थी।

4 पेरिस में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (आईसीएच) की सुरक्षा के कन्वेंशन के लिए राष्ट्रीय पक्षों की सातवीं महासभा - 6 जून 2018: ग्यारह राज्यों ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कन्वेंशन की पुष्टि की, जिसमें चार एएसपीएसी सदस्य, अर्थात् कुक आइलैंड्स, थाईलैंड, तिमोर-लेस्ते और तुवालु शामिल थे। भारत 2018 में आईसीएच समिति के चार निवर्तमान सदस्यों में से एक था जिसमें अफगानिस्तान, मंगोलिया और कोरिया गणराज्य भी शामिल थे।

<u>वैश्विक विरासत समिति का 42वां सत्र:</u> 24 जून - 4 जुलाई 2018 को मनामा, बहरीन में वैश्विक विरासत समिति के 42वें सत्र के दौरान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में "मुंबई के विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको एन्सेम्बल" को नामांकित किया गया। इस साइट का शिलालेख यूनेस्को सूची में भारत की 37वीं प्रविष्टि है।

<u>यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का 205वां सत्र:</u> ईएक्सबी का 205वां सत्र 3 से 17 अक्टूबर, 2018 तक पेरिस में आयोजित किया गया था। कार्यकारी बोर्ड के कार्यक्रम और बाहरी संबंध (पीएक्स) आयोग ने "महात्मा गांधी की विरासत को याद करते हुए" पर मद अट्ठाईस की जांच की, जिसे बिना किसी बहस के प्रस्तावित किया गया था। आयोग को भारत सरकार की योजना के बारे में भी सूचित किया गया था जो इस आइकन के उत्सव में आने वाले वर्ष भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू करेगी। महात्मा गांधी के जीवन पर एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई।

डिजिटल सहयोग

यूएनएसजी ने मेलिंडा गेट्स और जैक मा की सह अध्यक्षता में डिजिटल सहयोग पर एक बीस सदस्यीय उच्च स्तरीय पैनल की स्थापना की गई है। पैनल के अप्रैल 2019 में एक रिपोर्ट और सिफारिशें पेश करने की आशा है। राजदूत अमनदीप सिंह गिल पैनल के सचिवालय में कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)

भारत ने 13 मार्च 2018 को दिल्ली में ट्यूबरकुलोसिस की समाप्ति (टीबी) शिखर सम्मेलन का आयोजन किया।इसे भारत सरकार, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय (एसईएआरओ) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक टीबी को समाप्त करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और सभी भागीदारों, सार्वजनिक और निजी लोगों की मदद की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि भारत में टीबी को समाप्त करने के लिए, इस क्षेत्र में और विश्व स्तर पर एकजुट हुआ जा सके। शिखर सम्मेलन में डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ने भाग लिया।

तपेदिक पर संयुक्त राष्ट्र की पहली उच्च स्तरीय बैठक 26 सितंबर, 2018 को 73वें संयुक्त राष्ट्र संघ के उच्च-स्तरीय सप्ताह के दौरान आयोजित हुई, जिसने "तपेदिक को समाप्त करने के लिए एकजुटताः एक वैश्विक महामारी के लिए एक तत्काल वैश्विक प्रतिक्रिया" विषय पर एक राजनीतिक घोषणा को अपनाया, टीबी को समाप्त करने और रोकथाम और देखभाल के साथ सभी प्रभावित लोगों तक पहुंचने के प्रयासों में तेजी लाने की प्रतिबद्धता की राजनीतिक पुष्टि की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा ने बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। 2030 के वैश्विक लक्ष्य से पांच वर्ष पहले 2025 तक भारत में तपेदिक को खत्म करने के लक्ष्य पर प्रकाश डाया गया था।

गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की रोकथाम और नियंत्रण पर संयुक्त राष्ट्र की तीसरी उच्च स्तरीय बैठक 27 सितंबर, 2018 को आयोजित की गई, जिसने 'समय पर पहुंचानाः वर्तमान और भावी पीढ़ियों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए गैर-संचारी रोगों के लिए हमारी प्रतिक्रिया को तेज करना'' पर एक राजनीतिक घोषणा को अपनाया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा ने बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

इकहत्तरवीं विश्व स्वास्थ्य सभा का सत्र 21-26 मई 2018 को जिनेवा में हुआ। भारत का प्रतिनिधित्व स्वास्थ्य मंत्री श्री जे.पी. नड्डा ने किया। सत्र के दौरान डिजिटल हेल्थ पर एक संकल्प अपनाया गया था, जिसे भारत द्वारा शुरू किया गया था। स्वास्थ्य मंत्री ने भारत की विधानसभा की "आयुष्मान भारत" की नई पहल से भी अवगत कराया, जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य में भारत का योगदान होगा। इस मौके पर, स्वास्थ्य मंत्री ने जेनेवा में राष्ट्रमंडल के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भी भाग लिया। बैठक का विषय था "एनसीडी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को बढ़ाना: जागरूकता बढ़ाना, संसाधन जुटाना और सार्वभौमिक वैश्विक कवरेज तक पहुंच सुनिश्चित करना"।

अल्मा-अता की घोषणा की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर, 25-26 अक्टूबर 2018 को कजाकिस्तान के अल्माटी में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर एक वैश्विक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन को कजाकिस्तान की सरकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ द्वारा सह-आयोजित किया गया था। सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व स्वास्थ्य मंत्री श्री जे.पी. नड्डा ने किया। सम्मेलन में बोलते हुए, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत वर्ष 2020 तक अपने सभी जिलों में एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस स्थापित करने का लक्ष्य रखता है, ताकि कागज-आधारित डेटा संग्रह, रिकॉर्डिंग और भंडारण के बोझ को कम किया जा सके।

चिकित्सा उत्पादों तक पहुंच के लिए दूसरा विश्व सम्मेलन - 2030 तक एसडीजी प्राप्त करना नई दिल्ली में 9-11 अक्टूबर 2018 को आयोजित किया गया था। सम्मेलन का आयोजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू), भारत सरकार द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से किया गया था। भारत ने नवंबर 2017 में नई दिल्ली में पहले विश्व सम्मेलन का भी आयोजन किया था।

मई 2018 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तंबाकू उत्पादों पर अवैध व्यापार को खत्म करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल के अंतर्गत प्रोटोकॉल को स्वीकार करने की मंजूरी दे दी।

भारत की अध्यक्षता में तंबाकू नियंत्रण के लिए डब्ल्यूएचओ फ्रेमवर्क कन्वेंशन (एफसीटीसी) के लिए पक्षों का सम्मेलन एक मध्यम अवधि के रणनीतिक ढांचे (एमटीएसएफ) को अपनाने के बाद वैश्विक तंबाकू नियंत्रण एजेंडा के लिए एक नई कार्य योजना की रूपरेखा तैयार कर रहा है।

महासागरों और समुद्र के कानून

भारत ने 11-14 जून 2018 को यूएनएचक्यू में आयोजित समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) की 28वीं बैठक; 8 से 13 जुलाई को किंग्स्टन, जमैका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के 24 वां सत्र; 18-22 जून को आयोजित “एन्थ्रोपोजेनिक पानी के नीचे शोर” पर महासागरों और समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र की ओपन एंडेड अनौपचारिक परामर्श प्रक्रिया की 19 वीं बैठक; 28 फरवरी - 1 मार्च 2018 को आयोजित सामाजिक-आर्थिक पहलुओं सहित समुद्री पर्यावरण की स्थिति की वैश्विक रिपोर्टिंग और मूल्यांकन के लिए नियमित प्रक्रिया पर पूरे समय के तदर्थ कार्य समूह की 10 वीं बैठक और 23 और 24 अगस्त 2018 को आयोजित सामाजिक-आर्थिक पहलुओं सहित समुद्री पर्यावरण की स्थिति की वैश्विक रिपोर्टिंग और मूल्यांकन के लिए नियमित प्रक्रिया पर पूरे तदर्थ के कार्य समूह की 11वीं बैठक में भाग लिया था

भारत ने अप्रैल और सितंबर 2018 में यूएनसीएलओएस के अंतर्गत आयोजित राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के मुद्दे (बीबीएमजे) पर हुई बैठकों में भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (यूएनसीआईटीआरएएल)

भारत ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों में कार्यकारी समूह-I (12-16 मार्च 2018); विवाद निपटान पर कार्य समूह-II (5-9 फरवरी 2018); निवेशक-राज्य विवाद निपटान सुधार पर कार्य समूह -III (23-27 अप्रैल 2018); इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पर कार्य समूह- IV (16-20 अप्रैल 2018); दिवाला कानून पर कार्य समूह -V (7-11 मई 2018); सुरक्षा हितों पर कार्य समूह-VI (30 अप्रैल - 4 मई 2018); और यूएनसीआईटीआरएएल के 51वें वार्षिक सत्र (25 जून - 13 जुलाई 2018) में भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (आईएचएल)

भारत अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (आईएचएल) के सम्मान को मजबूत करने के लिए अंतर-सरकारी प्रक्रिया में सह-सुविधाकर्ताओं - स्विट्जरलैंड और रेड क्रॉस (आईसीआरसी) की अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा आयोजित बैठकों में सक्रिय

रूप से शामिल है।यह प्रक्रिया दिसंबर 2015 में रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अनुवर्ती कार्रवाई है।

भारत ने 2018 में जिनेवा में आयोजित पांच औपचारिक अंतर सरकारी सत्रों के दौरान यह दृष्टिकोण बनाए रखा ताकि लक्ष्य हासिल करने के लिए मौजूदा अंतरराष्ट्रीय तंत्र की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ)

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार ने 28 मई से 8 जून, 2018 तक जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) के 107वें सत्र के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारत के प्रमुख नियोक्ता और श्रमिक समूहों के प्रतिनिधि भी आईएलसी में शामिल हुए।

वर्ष भर में, भारत ने विभिन्न आईएलओ तकनीकी समितियों के विचार-विमर्श में भाग लिया, जिसमें मानक समीक्षा तंत्र त्रिपक्षीय कार्य समूह (एसआरएम-टीडबल्यूजी) की चौथी बैठक और समुद्री श्रम कन्वेंशन, 2006 की विशेष त्रिपक्षीय समिति की तीसरी बैठक शामिल है।

भारत ने मार्च, जून और अक्टूबर-नवंबर 2018 में क्रमशः आईएलओ के शासी निकाय (जीबी) के 332वें, 333वें और 334वें सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत आईएलओ में चल रही सुधार प्रक्रिया में शामिल रहा, जिसमें इसकी शासन संरचनाओं से संबंधित, आईएलओ पर्यवेक्षी तंत्रों की समीक्षा और आईएलओ की शताब्दी (वर्ष 2019) पहल के हिस्से के रूप में मानक समीक्षा तंत्र शामिल हैं।

अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू)

डॉ. एम. जी. थंबीदुरई, उपसभापति, लोकसभा ने 4-28 मार्च 2018 से जिनेवा में अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 138वीं सभा में "प्रवासियों और शरणार्थियों के लिए वैश्विक शासन को मजबूत करना: प्रमाण-आधारित नीति समाधानों की आवश्यकता" विषय पर सदस्यों के भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के संसद सदस्यों ने भाग लिया था।

जिनेवा में 14-18 अक्टूबर 2018 से "नवाचार और तकनीकी परिवर्तन के युग में शांति और विकास को बढ़ावा देने में संसदीय नेतृत्व" विषय पर, अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 139वीं सभा में, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन द्वारा किया गया था। प्रतिनिधिमंडल में श्री हरिवंश, उपसभापति, राज्यसभा और श्री थम्बी दुरई, उपसभापति, लोकसभा के साथ-साथ लोकसभा और राज्यसभा के संसद सदस्य भी शामिल थे।

व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी)

उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के केंद्रीय मंत्री श्री राम विलास पासवान ने 9 जुलाई 2018 को जिनेवा में तीसरे अंतर सरकारी समूह, उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति के विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व किया।

भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष

भारत ने जून 2017 में स्थापित दक्षिण-दक्षिण सहयोग (यूएनओएसएससी) के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में स्थित भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष में अगले 10 वर्षों के दौरान 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान करने की प्रतिबद्धता स्वीकार की है। अप्रैल 2018 में, कोष में 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कॉमनवेल्थ भाग जोड़ा गया। कोष 2030 के एजेंडे और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के सिद्धांतों के साथ देश के नेतृत्व वाली परियोजनाओं का समर्थन करता है।

भारत में अध्ययन यात्रा

मिशन ने 21-28 अगस्त 2018 तक न्यूयॉर्क में स्थित बारह देशों के चुनिंदा स्थायी प्रतिनिधियों के लिए एक अध्ययन यात्रा का आयोजन किया। वे नाइजर, इक्वेटोरियल गिनी, मार्शल आइलैंड्स, माल्टा, सेंट लूसिया, ग्रेनेडा, जाम्बिया, डोमिनिका, एस्वेटनी, कोमोरोस, सेंट किट्स और नेविस और किरिबाती से थे। प्रतिनिधिमंडल ने विदेश मंत्री (ईएएम) श्रीमती सुषमा स्वराज से भेंट की। यात्रा के कार्यक्रम में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), चुनाव आयोग और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी), आदि शामिल थे।

संयुक्त राष्ट्र में अन्य महत्वपूर्ण बैठकें और दौरे

भारत के स्थायी मिशन ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र में कई आयोजन किए। इनमें योग शिक्षकों के साथ योग सत्र (20 जून), शामति के लिए योग पर योग शिक्षकों से बातचीत (21 जून) और योग पर प्रदर्शनी (18-22 जून) शामिल हैं। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र सचिवालय भवन को योग मुद्राओं से प्रकाशित किया गया।

भारत ने 24 अक्टूबर 2018 को बावन वर्षों के अंतराल के बाद संयुक्त राष्ट्र में प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र दिवस समारोह को प्रायोजित किया। संगीत कार्यक्रम का विषय 'परंपराओं की शांति और अहिंसा' था और महात्मा गांधी को उनकी 150वीं वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि दी गई। सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान ने इस अवसर पर रिफ्यूजी ऑर्केस्ट्रा प्रोजेक्ट के साथ प्रदर्शन किया।

डॉ. बी आर अंबेडकर की 127वीं जयंती को चिह्नित करने के लिए 13 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन द्वारा 'लीविंग नो वन बिहाइंड' नामक एक उच्च स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के प्रशासक श्री अचिम स्टेनर ने मुख्य भाषण दिया, जिसके बाद इस विषय पर एक पैनल चर्चा हुई।

भारत ने 22 और 23 अक्टूबर को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कानून सप्ताह के दौरान संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के विदेश मंत्रालयों के कानूनी सलाहकारों की बैठक में भाग लिया।

भारत ने 24 अक्टूबर को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कानून सप्ताह के दौरान ब्रिक्स के कानूनी सलाहकारों की अनौपचारिक बैठक में भाग लिया।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के क्योटो प्रोटोकॉल के लिए दोहा संशोधन के औचित्य का साधन संयुक्त राष्ट्र में 8 अगस्त को जमा किया गया था।

बुध पर मिनमाता कन्वेंशन के लिए परिशोधन का साधन, 2013 संयुक्त राष्ट्र महासचिव के समक्ष 18 जून को जमा किया गया था।

2012 में तम्बाकू में अवैध व्यापार को खत्म करने के प्रोटोकॉल के लिए उपयोग का साधन, 5 जून को संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पास जमा किया गया था।

भारत ने कमजोर समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों पर समुद्र तल की मछली पकड़ने पर टिकाऊ मछली पालन संकल्पों के कार्यान्वयन पर दीर्घकालिक मछली पालन प्रभाव और गहरे समुद्र में मछली स्टॉक के दीर्घकालिक स्थिरता पर 6-13 नवंबर 2018 को आयोजित अनौपचारिक परामर्श में सक्रिय रूप से भाग लिया।

सर्वेयर जनरल के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने जुलाई-अगस्त 2018 के दौरान वैश्विक भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन (जीजीआईएम) पर संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञों की समिति के आठवें सत्र में भाग लिया।

भारत दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र के दूसरे सम्मेलन के लिए अंतर-सरकारी रूप से सहमत परिणाम दस्तावेज के लिए वार्ता में सक्रिय रूप से संलग्न है, जिसे बीएपीए + 40 (ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन को अपनाने के चालीस वर्ष बाद) कहा जाता है।

"सीआरपीडी के पूरे कार्यान्वयन के माध्यम से किसी को पीछे नहीं छोड़ना" विषय पर विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन के लिए राज्य दलों का 11वां सम्मेलन 12-14 जून 2018 से न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग के सचिव ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का

नेतृत्व किया और राष्ट्रीय वक्तव्य दिया, जिसमें पिछले वर्ष लागू विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया।

बुढ़ापे पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप का नौवां सत्र 23-26 जुलाई 2018 से संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया गया था। न्यायमूर्ति श्री एच. एल. दत्तू की अध्यक्षता में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था (एएचआरआई) की अपनी स्वतंत्र क्षमता में बैठक में भाग लिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इंडिया ने 'दीर्घकालिक देखभाल और उपशामक देखभाल' पर लिखित रूप से कार्य समूह की चर्चा में योगदान दिया।

भारत के स्थायी मिशन ने मई 2018 में संयुक्त राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भाग लिया।

भारत के स्थायी मिशन ने मई 2018 में 'जयपुर फुट' पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया।

भारत ने **नौरोज** के अंतरराष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय **वेसक** दिवस, **दिवाली** और **विश्व शौचालय दिवस** को कई अन्य देशों के साथ मनाया।

खाद्य और कृषि संगठन

भारत ने एफएओ परिषद के सदस्य के रूप में खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) में भाग लेना जारी रखा। यह मत्स्य पालन समिति, वानिकी समिति, खाद्य सुरक्षा समिति और कृषि संबंधी समिति जैसी विभिन्न समितियों के सदस्य के रूप में भी काम करता रहा।

भारत को पारिवारिक खेती के लिए अपने समर्थन की मान्यता में एशिया ग्रुप के दो सदस्यों में से **पारिवारिक खेती 2019-2028** के लिए **इंटरनेशनल स्टियरिंग कमेटी (आईएससी)** के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। आईएससी कार्य कार्यक्रम के विकास और सुसंगत कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। भारत दो वर्ष यानी 2019 -2020 तक आईएससी पर रहेगा। दिसंबर 2017 में यूएनजीए द्वारा पारिवारिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय निर्णय को अपनाया गया और (एफएक्यू) और अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष (आईएफएडी) अन्य प्रासंगिक हितधारकों के साथ मिलकर दशक के कार्यान्वयन का नेतृत्व करेगा।

रोम में 1-5 अक्टूबर 2018 से आयोजित खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ), समिति के 26वें सत्र के द्वारा 2023 में मिलेट्स के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया गया था।

विश्व खाद्य सुरक्षा पर समिति का 45वां सत्र 15-19 अक्टूबर 2018 को एफएओ में आयोजित किया गया था। **ग्रामीण महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस** के उद्घाटन के अवसर पर, जाला शारदाबेन फतेसिंह, छोटे किसान और भारतीय स्व-रोजगार महिला संघ (एसईडब्ल्यूए) की कार्यकारी समिति के सदस्यों को मुख्य भाषण देने का विशेषाधिकार दिया गया।

विश्व में पहला कार्बनिक राज्य होने के लिए सिक्किम को 15 अक्टूबर 2018 को रोम में खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) में आयोजित एक समारोह में विश्व भविष्य नीति गोल्ड अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया।

21-23 नवंबर, 2018 को एफएओ में आयोजित पारिवारिक किसानों के लिए **कृषि नवाचार पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में,** प्रो अनिल गुप्ता, संस्थापक, हनीबी नेटवर्क इंडिया को मुख्य भाषण के साथ संगोष्ठी आरंभ करने का विशेषाधिकार दिया गया। तेलंगाना में **रायथु बंधु बीमा योजना** को नवाचार की बीस सफल कहानियों में से एक के रूप में चुना गया था और श्री सी. पार्थ सारथी, कृषि उत्पादन आयुक्त और सचिव, सरकारी कृषि और सहकारिता (बागवानी और सेरीकल्चर) विभाग, तेलंगाना सरकार, ने संगोष्ठी में भाग लिया और प्रतिभागियों को बीमा योजना के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी दी।

कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष (आईएफएडी)

आईएफएडी में भारत की मजबूत प्रतिबद्धता और भागीदारी इस वर्ष आईएफएडी 11 की बैठक में परिलक्षित हुई थी जब भारत ने पिछली अवधि में 37 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अपने योगदान को काफी बढ़ा कर 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वादा किया था। भारत आईएफएडी कार्यकारी बोर्ड में भी काम करता रहा।

संयुक्त राष्ट्र ईएससीएपी

यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक (यूएन-ईएससीएपा) का 74वां वार्षिक आयोग सत्र 11-16 मई 2018 को बैंकॉक में आयोजित किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार सुश्री अनुराधा मित्रा ने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (एसओएम) में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और राजदूत श्री भगवंत सिंह बिश्नोई राजदूत सेगमेंट के प्रमुख थे। 74वें सत्र का विषय 'स्थायी विकास के 2030 के एजेंडा के युग में असमानता' था। राजदूत बिश्नोई ने इस संबंध में भारत सरकार की पहल पर प्रकाश डालते हुए देश का वक्तव्य दिया। आयोग के दौरान ग्यारह प्रस्तावों को अपनाया गया था। सत्र के दौरान, विकास के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के एशियाई और प्रशांत प्रशिक्षण केंद्र की शासी परिषद (एपीसीआईसीटी) और सतत कृषि यंत्रीकरण केंद्र (सीएसएएम) की शासी परिषद का चुनाव भी हुआ। भारत को दोनों शासी परिषदों के लिए फिर से चुना गया।

एशिया-प्रशांत ऊर्जा मंच

दूसरा एशिया-प्रशांत ऊर्जा मंच बैंकॉक में 03-05 अप्रैल को आयोजित किया गया था। सदस्य देशों ने एक मंत्रिस्तरीय घोषणा को अपनाया, जिसने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को आगे बढ़ाने, सीमा पार बुनियादी ढांचे और ऊर्जा व्यापार को सुविधाजनक बनाने और ऊर्जा के सतत उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कई कार्यों को पूरा किया।मंत्रिस्तरीय घोषणा में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को संयुक्त राष्ट्र के अन्य प्रासंगिक मंचों के साथ स्वच्छ ऊर्जा के लिए एक मंच के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सुश्री प्रिया नायर, निदेशक (आर्थिक कूटनीति), विदेश मंत्रालय, मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल हुईं। थाई सरकार की ओर से, विदेश मामलों के उप-मंत्री वीरसाकडी फ़ुटरकुल ने 4 अप्रैल को टिप्पणी दी। इस बैठक में अफगानिस्तान, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, चीन, लाओस, कोरिया गणराज्य और रूस सहित सोलह मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों के साथ एशिया और प्रशांत के पचास से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बैंकॉक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018 (बीसीसीसी)

बैंकाक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018 (4-9 सितंबर 2018) की पूर्व-सत्रीय बैठक 30 अगस्त को बैंकॉक में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुई। बीसीसीसी में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया था।सम्मेलन का आयोजन पेरिस समझौते के कार्य कार्यक्रम (पीएडब्ल्यूपी) को समय पर पूरा करने की सुविधा के लिए किया गया था, जो सम्मेलन 2018 की पक्षों के 24वें सत्र में काटोविस, पोलैंड में दिसंबर 2018 में होना था। यूएन-ईएससीएपी द्वारा सदस्य राज्यों के लिए यूएनएफसीसीसी की कार्यकारी सचिव पेट्रीसिया एप्सिनोसा द्वारा एक ब्रीफिंग का आयोजन किया गया था। 6 सितंबर को ब्रीफिंग में दूतावास के अधिकारियों ने भाग लिया।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर क्षेत्रीय परामर्श (एसएससी)

यूएन-ईएससीएपी द्वारा संयुक्त राष्ट्र के दक्षिण-दक्षिण सहयोग (यूएनओएसएससी) और थाईलैंड सरकार के सहयोग से 27-29 जून से बैंकॉक में दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर क्षेत्रीय परामर्श का आयोजन किया गया था। बैठक का उद्देश्य मार्च 2019 के लिए निर्धारित ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन की 40वीं वर्षगांठ (बीएपीए + 40) के लिए तैयारी करना था। निदेशक (संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक), विदेश मंत्रालय ने बैठक में भाग लिया। भारत ने एसएससी के संबंध में अपना अनुभव साझा किया। भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष की प्रशंसा की गई थी और बैठक के दौरान कई बार इसका उल्लेख किया गया था।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग दिवस

संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन केंद्र बैंकॉक में 12 सितंबर को दक्षिण-दक्षिण सहयोग दिवस मनाया गया। यह कार्यक्रम एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएन-ईएससीएपी), दक्षिण-दक्षिण सहयोग के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओएसएससी) और थाई विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इस घटना ने विकासशील देशों (बीएपीए) के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने और लागू करने के लिए दक्षिण-दक्षिण सहयोग की एक रूपरेखा- ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन को अपनाने की 40वीं वर्षगांठ को चिह्नित किया।

विदेशी मामलों के मंत्री का प्रतिनिधित्व करने वाले थाईलैंड के विदेश मामलों के मंत्रालय के सलाहकार विजावत इसाराभाकडी ने अपने संबोधन में भागीदारी के महत्व पर जोर दिया, जो दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग की भावना है। यूएनईएससीएपी के उप-कार्यकारी सचिव केव जाहेदी, संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर सुश्री देयरेड बॉयड और थाईलैंड में यूएनडीपी के रेजिडेंट रिप्रजेंटेटिव, राजदूतों और बांग्लादेश, चीन, फिजी, भारत, इंडोनेशिया और थाइलैंड सहित इस क्षेत्र में दक्षिण-दक्षिण सहयोग देशों के अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने बीएपीए + 40 सम्मेलन से पहले, अतीत की उपलब्धियों और भविष्य पर साझा दृष्टिकोण का आकलन किया।

श्री अब्बागानी रामू, चार्ज डी'अफेयर (सी'डीए), भारत के बैंकॉक दूतावास ने विकासशील देशों के साथ विकास साझेदारी का विस्तार करने के लिए भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष की स्थापना सहित एसएससी पर भारत की विभिन्न पहलों को साझा किया। इस कोष के अंतर्गत, भारत ने दस वर्षों की अवधि में दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने की प्रतिबद्धता स्वीकार की है।

यूएनईएससीएपी में अन्य महत्वपूर्ण बैठकें

भारत के दूतावास, बैंकॉक और यूएनईएससीएपी ने संयुक्त रूप से 2 अक्टूबर 2018 को यूएनईएसएपी में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया। यूएनईएससीएपी के प्रभारी उप-कार्यकारी सचिव और अधिकारी श्री हॉन्ग्जू हाहम ने शुरुआती टिप्पणियां दीं। इसके बाद श्री अब्बागानी रामू, सी'डीए, भारतीय दूतावास, बैंकॉक ने टिप्पणी दी। कई राजदूत और राजनयिक समुदाय, संयुक्त राष्ट्र के निकायों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों ने अहिंसा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस में भाग लिया।

एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास के लिए अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर तीसरा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 8-10 अक्टूबर से बैंकॉक में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन केंद्र (यूएनसीसी) में आयोजित किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिक सचिव श्री पी जी दिवाकर ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। सम्मेलन के दौरान सतत विकास के लिए भू-स्थानिक सूचना और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के उपयोग पर मंत्रिस्तरीय घोषणा को अपनाया गया। सम्मेलन ने एशिया-प्रशांत योजना पर कार्रवाई के लिए अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए सतत विकास (2018-2030) पर सहमति व्यक्त की, यह एक क्षेत्रीय-समन्वित खाका है, जो विशेष रूप से विशेष आवश्यकताओं वाले देशों को 2030 के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) एजेंडा को प्राप्त करने में समर्थन देने के लिए अंतरिक्ष अनुप्रयोगों और डिजिटल नवाचारों का दोहन करता है।

जनसंख्या और विकास पर एशियाई और प्रशांत मंत्रिस्तरीय घोषणा की मध्यावधि समीक्षा 26-28 नवंबर 2018 से यूएनसीसी, बैंकॉक में आयोजित की गई थी।बैठक का आयोजन एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (ईएससीएपी) और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) द्वारा किया गया था, जनसंख्या विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मध्यावधि समीक्षा (आईसीपीडी) ने प्रतिभागियों की समीक्षा की प्रगति और 1994 में अपनाये गये काहिरा में महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अंतराल को देखा।आगे बढ़ते हुए, प्रतिनिधियों ने जनसंख्या संबंधी चुनौतियों के एक व्यापक सेट को संबोधित करने के लिए प्राथमिकता कार्यों के साथ ही नए और उभरते रुझानों की भी की पहचान की। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बैठक में लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय कानून

संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति (कानूनी)

छठी समिति, महासभा में कानूनी सवालों पर विचार करने के लिए प्राथमिक मंच होने के नाते, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों को अंतरराष्ट्रीय कानून से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श और सिफारिश करने का अवसर प्रदान करती है। कानूनी और संधियाँ प्रभाग छठी समिति के कार्य का अनुसरण करता है।

छठी समिति की बैठक महासभा के सत्रहवें सत्र के दौरान 3 अक्टूबर से 13 नवंबर 2018 तक हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के सत्र के मुख्य भाग के दौरान, छठी समिति ने निम्नलिखित विषयों /मुद्दों पर विचार किया:-

- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून का नियम;
- मिशन पर संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों और विशेषज्ञों की आपराधिक जवाबदेही;
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून का नियम;
- 1949 के जिनेवा सम्मेलनों के अतिरिक्त प्रोटोकॉल और सशस्त्र संघर्षों के पीड़ितों की सुरक्षा से संबंधित स्थिति;
- इसके पचासवें सत्र के काम पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की रिपोर्ट;
- शिक्षण, अध्ययन, प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्यापक प्रशंसा में सहायता का संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम;
- अपने 70 वें सत्र के कार्य पर अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की रिपोर्ट;
- बाहरी तत्वों का निष्कासन;
- संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और संगठन की भूमिका को मजबूत करने पर विशेष समिति की रिपोर्ट;
- सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार के सिद्धांत का दायरा और अनुप्रयोग;
- संधियों पर सशस्त्र संघर्षों का प्रभाव;
- अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जिम्मेदारी;
- अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को खत्म करने के उपाय;
- महासभा के कार्य का पुनरुद्धार;
- संयुक्त राष्ट्र में न्याय का प्रशासन;
- मेजबान देश के साथ संबंधों पर समिति की रिपोर्ट।

छठी समिति के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र की आम बहस के दौरान आतंकवाद और इससे संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए कानूनी व्यवस्था को मजबूत करना चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना रहा। आम बहस में, आतंकवाद की कड़ी निंदा करने के अलावा, सदस्य राज्यों ने आतंकवाद के हर कृत्य से प्रभावी ढंग से निपटने पर जोर दिया और साथ ही इससे निपटने के लिए पर्याप्त कानूनी उपायों को सुनिश्चित किया।

इस संदर्भ में, आतंकवाद के खतरे को रोकने के लिए एक वैश्विक आदर्शवादी दस्तावेज होना आवश्यक है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को खत्म करने के उपाय छठी समिति (मद 111) के एजेंडे में जारी रहे। इस संबंध में, प्रगति हुई क्योंकि सत्तर के दशक के सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों को आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए प्रभावी उपायों पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के आह्वान पर "अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को खत्म करने के उपाय" और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर विस्तृत कन्वेंशन (सीसीआईटी) के मसौदा प्रस्ताव को अपनाया गया।

छठी समिति ने निम्नलिखित विषयों को आवृत करने वाले तीन समूहों/भागों में अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग (आईएलसी) की रिपोर्ट पर विचार किया और बहस भी की:

- आपदाओं की स्थिति में व्यक्तियों का संरक्षण;
- विदेशी आपराधिक क्षेत्राधिकार से राष्ट्र के अधिकारियों की प्रतिरक्षा;
- संधियों के अनंतिम आवेदन;
- प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून का गठन और साक्ष्य;
- संधियों की व्याख्या के संबंध में बाद के बाद की समझौते और अभ्यास;
- प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून की पहचान;
- सशस्त्र संघर्षों के संबंध में पर्यावरण की सुरक्षा;

- सशस्त्र संघर्षों के संबंध में पर्यावरण की सुरक्षा;
- वायुमंडल की सुरक्षा;
- राष्ट्र की जिम्मेदारी के संबंध में राज्यों का उत्तराधिकार;
- सामान्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुल्लंघनीय मानदंड (जुस कॉजेंस।)

भारत ने तीनों हिस्सों पर बयान दिए। इसके अलावा, छठी समिति ने भी निम्नलिखित को पर्यवेक्षक का दर्जा देने के अनुरोधों पर विचार किया है (i) नया विकास बैंक (ब्रिक्स देशों द्वारा प्रस्तुत), (ii) समुद्र की खोज के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद (नॉर्वे द्वारा प्रस्तुत), (iii) यूरोपीय सार्वजनिक कानून संगठन (पुर्तगाल द्वारा पेश), (iv) एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (चीन द्वारा प्रस्तुत और भारत द्वारा समर्थित) और (v) इंटरनेशनल थिंक टैंक फॉर लैंडलॉकड डेवलपिंग कंट्रीज (मंगोलिया द्वारा प्रस्तुत)। छठी समिति में विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप अनुरोधों को मंजूरी देने की सिफारिश हुई, जिसे बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपनाया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय कानून सप्ताह

इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क में 22 से 26 अक्टूबर 2018 तक अंतर्राष्ट्रीय कानून सप्ताह मनाया गया। विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और कानूनी सलाहकार डॉ. वी. डी. शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय कानून सप्ताह के दौरान कार्यक्रमों में भाग लिया। इस अवधि के दौरान, छठी समिति ने अंतर्राष्ट्रीय कानून आयोग (आईएलसी) की रिपोर्ट पर बहस की। भारत ने बहस में भाग लिया, आईएलसी द्वारा विचार किए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून विषयों की जांच की और बयानों में टिप्पणी की।

संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के विदेश मंत्रालय के कानूनी सलाहकारों की बैठक 22 और 23 अक्टूबर, 2018 को आयोजित की गई थी। पोलैंड इस वर्ष कानूनी सलाहकारों की बैठक का मुख्य समन्वयक था। बैठक में छठी समिति के विशेषज्ञों, अंतर्राष्ट्रीय कानून शिक्षाविदों और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने भी भाग लिया। भारत के कानूनी सलाहकारों के अलावा संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, कनाडा, मैक्सिको और स्वीडन ने इस कार्यक्रम के आयोजन में पोलैंड की सहायता की। इस घटना में अत्याचार के अपराधों की रोकथाम और सजा के लिए समर्पित तीन चर्चा पैनल शामिल थे; एक व्यावहारिक संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गलत कृत्यों के लिए राष्ट्रो की जिम्मेदारी; और संधि के कानून पर वियना कन्वेंशन के प्रकाश में समझौता ज्ञापन। भारतीय कानूनी सलाहकार ने कानूनी सलाहकारों की बैठकों के विचार-विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय कानून सप्ताह के दौरान, ब्रिक्स सदस्य देशों के कानूनी सलाहकारों की अनौपचारिक बैठक भी हुई।

दक्षिण अफ्रीका इस वर्ष के अनौपचारिक ब्रिक्स कानूनी सलाहकारों की बैठक का अध्यक्ष बन रहा है, एडवांसिया डी वेट, मुख्य राज्य कानून सलाहकार (अंतर्राष्ट्रीय कानून), दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग विभाग ने 24 अक्टूबर 2018 को अंतर्राष्ट्रीय कानून सप्ताह के दौरान ब्रिक्स देशों के कानूनी सलाहकारों के लिए दोपहर के भोजन का आयोजन किया। बैठक में अनौपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के समक्ष विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया, जिसमें आयोग के कामकाज के तरीके और आवेदन के दायरे में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत आत्मरक्षा के सिद्धांत शामिल थे।

अंतर्राष्ट्रीय कानून सप्ताह के दौरान, यूएनजीए के पूर्ण सत्र में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) की रिपोर्ट पर भी बहस हुई। डॉ. वी. डी. शर्मा, अतिरिक्त सचिव (एलएंडटी) और कानूनी सलाहकार ने आईसीजे की रिपोर्ट पर यूएनजीए में एक बयान दिया।

महासागरों और समुद्र के कानून

भारत ने 16-18 अप्रैल 2018 से संगठनात्मक मामलों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार (आईजीसी - बीबीएनजे) से परे क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता पर अंतर सरकारी सम्मेलन की संगठनात्मक बैठक में भाग लिया, जिसमें उपकरण के शून्य मसौदे की प्रक्रिया भी शामिल है।

भारत ने आईजीसी बीबीएनजे के पहले सत्र में भी भाग लिया

था, जिसे संकल्प 72/249 के अंतर्गत 4-17 सितंबर 2018 को आयोजित किया गया था, और 2011 में सहमत संकुल में पहचाने गए विषयों अर्थात् संरक्षण और टिकाऊ राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे के क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता का उपयोग, विशेष रूप से, एक साथ और एक समग्र रूप में, समुद्री आनुवंशिक संसाधन, लाभ के बंटवारे पर सवाल सहित, क्षेत्र आधारित प्रबंधन उपकरण, समुद्री संरक्षित क्षेत्रों सहित, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, और क्षमता निर्माण और समुद्री प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण जैसे उपायों को संबोधित किया गया था। सम्मेलन के अध्यक्ष सम्मेलन के दूसरे सत्र की तैयारी के हिस्से के रूप में, केंद्रित चर्चा और पाठ-आधारित बातचीत को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से एक दस्तावेज तैयार करेंगे, जिसमें संधि की भाषा होगी और संकुल के चार तत्वों से संबंधित विकल्पों को दर्शाया जाएगा।

सागर पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 1982 के कानून में राज्यों की पार्टियों की 28 वीं बैठक में भारत ने भाग लिया था, जो 11-14 जून 2018 से आयोजित किया गया था। प्रतिनिधिमंडल ने कन्वेंशन के अंतर्गत स्थापित संस्थानों, कांटिनेंटल शेल्फ की सीमा पर आयोग, अर्थात्, अंतर्राष्ट्रीय सीबेड प्राधिकरण और सागर के कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल द्वारा किए गए कार्यों पर विचार किया।

भारत ने किंग्स्टन, जमैका में अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी के 24वें सत्र में भाग लिया, जिसमें गहरे समुद्र में खनन पर मसौदा नियम; ठेकेदारों के गैर-अनुपालन मुद्दे; एंटरप्राइज़ का संभावित परिचालन; 2019-2023 के लिए एक रणनीतिक योजना; एसजी की वार्षिक रिपोर्ट; और 2019-2020 के लिए प्रस्तावित बजट सहित एक वित्तीय भुगतान प्रणाली के लिए मॉडल पर विचार किया गया।

संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महासागरों और समुद्रों से संबंधित अन्य बैठकों में कानून और संधियां प्रभाग ने भाग लिया:

- 18-22 जून 2018 से, महासागरों के “खुले में अनौपचारिक परामर्श प्रक्रिया” की 19वीं बैठक और “एन्थ्रोपोजेनिक पानी के नीचे शोर” पर समुद्र के कानून;
- सामाजिक पर्यावरण सहित वैश्विक पर्यावरण के लिए रिपोर्टिंग और मूल्यांकन की नियमित प्रक्रिया पर 23 और 24 अगस्त, 2018 को महासभा के प्रस्ताव 72/73 के अनुच्छेद 330 के अनुसार बुलाई गई पूरे समय के तदर्थ कार्य समूह की 11वीं बैठक।
- भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 1-4 अक्टूबर 2018 और 14-20 नवंबर 2018 के दौरान महासागरों और समुद्र के कानून (ओमिनिबस) पर अनौपचारिक परामर्श पर विचार-विमर्श में सक्रिय रूप से योगदान दिया।
- भारत ने 6-13 नवंबर 2018 से कमजोर समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों पर समुद्र तल में मछली पकड़ने के प्रभाव पर टिकाऊ मछली पालन प्रस्तावों के कार्यान्वयन और गहरे समुद्र में मछली स्टॉक के दीर्घकालिक स्थिरता के प्रभाव पर अनौपचारिक परामर्श में सक्रिय रूप से भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (यूएनसीआईटीआरएएल)

भारत ने निम्नलिखित कार्य समूहों में भाग लिया:

- न्यूयॉर्क में 12-16 मार्च 2018 से कार्य समूह-I (सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम) इस समूह ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के पूरे जीवन चक्र और, विशेष रूप से, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में कानूनी बाधाओं को कम करने के उद्देश्य से कानूनी मानकों की तैयारी का काम जारी रखा।
- न्यूयार्क में 5-9 फरवरी 2018 से आयोजित कार्य समूह-II (पंचाट और सुलह/विवाद निपटान), (68वां सत्र) ने मध्यस्थता से उत्पन्न अंतरराष्ट्रीय निपटान समझौतों पर एक मसौदा सम्मेलन की तैयारी पर अपने काम को अंतिम रूप दिया अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक सम्मेलन पर मॉडल कानून में संशोधन किया गया।
- न्यूयॉर्क में 23-27 अप्रैल 2018 से कार्य समूह-III (निवेशक-राज्य विवाद निपटान) ने निवेशक-राज्य विवाद निपटान के संभावित सुधार पर अपना काम जारी रखा।
- न्यूयॉर्क में 16-20 अप्रैल 2018 से कार्य समूह-IV (इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स) ने क्लाउड कंप्यूटिंग के संविदात्मक पहलुओं के साथ-साथ पहचान प्रबंधन और विश्वास सेवाओं से संबंधित कानूनी मुद्दों पर अपने विचार जारी रखे।

- न्यूयॉर्क में 7-11 मई 2018 से कार्य समूह-V (दिवाला कानून), अपने पैंतालीसवें सत्र में आयोग के निर्णय के अनुरूप, कार्य समूह ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सीमा-पार इन्सॉल्वेंसी को सुविधाजनक बनाने के उपायों और उद्यम समूहों और विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के दिवाला उपचार को संबोधित करने के लिए तंत्र सहित दिवालियेपन से संबंधित निर्णयों की मान्यता और प्रवर्तन पर मसौदा मॉडल कानून पर अपना विचार-विमर्श जारी रखा।
- न्यूयॉर्क में 30 अप्रैल से 4 मई 2018 तक कार्य समूह -VI (सिक्योरिटी इंट्रेस्ट) ने सुरक्षित लेनदेन पर यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल लॉ के लिए एक प्रैक्टिस गाइड तैयार करने के लिए अपना काम जारी रखा।

यूएनसीआईटीआरएएल के 25वें वार्षिक सत्र (25 जून -13 जुलाई 2018) ने दिवाला-संबंधित न्याय की मान्यता और विभिन्न कानूनी और आर्थिक प्रणालियों के साथ विभिन्न राज्यों की राष्ट्रीय प्रक्रियात्मक और न्यायिक प्रणालियों का सम्मान करने के साथ प्रवर्तन पर मॉडल कानून को अपनाने और सीमा पार से दिवालिया होने पर कानून को नुकसान पहुंचाने में मदद करने के लिए इसके गाइड पर विचार किया।

एशियाई-अफ्रीकी कानूनी सलाहकार संगठन (एएएलसीओ)

कानूनी और संधियों के प्रभाग जापान के टोक्यो में 8-12 अक्टूबर 2018 को आयोजित एशियाई-अफ्रीकी कानूनी सलाहकार संगठन (एएएलसीओ) के 57वें वार्षिक अधिवेशन में ने भाग लिया। सत्र में एएएलसीओ के सैंतीस सदस्य देशों ने भाग लिया।

उद्घाटन सत्र 9 अक्टूबर 2018 को आयोजित किया गया था। जापान के विदेश मंत्री श्री तारो कोनो और जापान के न्याय मंत्री श्री ताकाशी यमाशिता, उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि थे। भारत ने एएएलसीओ के 55वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की और डॉ. वी.डी. शर्मा, एएस (एल एंड टी) 55वें सत्र के अध्यक्ष थे। एएस (एल एंड टी) की अनुपस्थिति में, मिशन के उप प्रमुख, भारत के दूतावास ने, ए एस (एल एंड टी) की ओर से उद्घाटन सत्र में धन्यवाद ज्ञापन किया।

सत्र के दौरान निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय कानूनी विषयों पर चर्चा की गई: अंतर्राष्ट्रीय कानून आयोग के एजेंडा पर विषय; सागर का कानून; फिलिस्तीन में अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन; अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश कानून; साइबरस्पेस में अंतर्राष्ट्रीय कानून; और विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा। इसके अतिरिक्त, संगठन के संगठनात्मक और वित्तीय मामलों पर भी चर्चा की गई।

सामान्य वक्तव्य के अलावा, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून आयोग के एजेंडे के विषयों सागर का कानून; साइबरस्पेस में अंतर्राष्ट्रीय कानून; और विवादों का शांतिपूर्ण निपटारे पर वक्तव्य दिए।

निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून पर हेग सम्मेलन (एचसीसीएच)

25-28 सितंबर, 2018 को द हेग में आयोजित पेरेंटेज/सरोगेसी प्रोजेक्ट पर विशेषज्ञों के समूह की चौथी बैठक, सामान्य रूप से कानूनी अभिभावकता के आसपास के निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुद्दों पर केंद्रित थी। विशेषज्ञ समूह ने चौथी बैठक के दौरान निम्नलिखित मामलों पर चर्चा की:

- कानूनी अभिभावकता पर विदेशी सार्वजनिक दस्तावेजों को स्वीकार करने की संभावना;
- जहां कोई न्यायिक निर्णय नहीं है वहाँ विदेशों में स्थापित कानूनी अभिभावकता को मान्यता देने की संभावना;
- क्या इसकी कोई आवश्यकता है, और, यदि हाँ, तो क्या यह कानूनी अभिभावकता पर लागू समान कानून नियमों से समझौते तक पहुंचना संभव है, जिसमें सार्वजनिक दस्तावेजों के साथ इस तरह के किसी भी नियम को कैसे संचालित किया जा सकता है; तथा
- क़ानून संचालन के संबंध में कानूनी प्रावधानों के संबंध में विदेशी न्यायिक निर्णयों की, सीमा-पार मान्यता के बारे में परिष्कृत प्रावधान।

अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (आईएचएल)

कानून और संधियों के प्रभाग ने तेहरान में 17-19 नवंबर, 2018 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून पर आठवें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लिया गया, जिसमें 'नई प्रौद्योगिकियों और आईएचएल' पर चर्चा हुई।

इसके अतिरिक्त, प्रभाग ने आईएचएल के कई पहलुओं पर दस्तावेजों/प्रस्तावों/प्रश्नों की जांच की और इसमें मंत्रालय के यूएनईएस प्रभाग को सलाह दी।

प्रत्यर्पण

वर्ष 2018 के दौरान, कानून और संधियों के प्रभाग ने कई प्रत्यर्पण अनुरोधों की जांच की और उसमें कानूनी सलाह दी। घरेलू और विदेशी न्यायालयों से आपराधिक और नागरिक मामलों से संबंधित अन्य अनुरोधों की भी जांच की गई और उन पर सलाह दी गई।

भारत को शामिल करने वाले अंतर्राष्ट्रीय विवाद का समाधान

क. **एनरिका लेक्सी मामला (इटली और भारत):** इटली ने जून 2015 में भारत को "आर्टिकल 287 और एनेक्स VII, यूएनसीएलओएस के अंतर्गत अधिसूचना" भेज कर मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की थी। भारत ने रजिस्ट्री के साथ अपनी लिखित दलीलों की फाइलिंग पूरी कर ली है। 16 फरवरी 2018 को इटली ने अपना उत्तर प्रस्तुत करते हुए दोनों पक्षों की लिखित दलीलें पूरी कर लीं। अंतिम मौखिक सुनवाई जो अक्टूबर - नवंबर 2018 में होने वाली थी, ट्रिब्यूनल के मध्यस्थों में से एक के आकस्मिक निधन के कारण आयोजित नहीं की जा सकी। अब, मौखिक सुनवाई को फिर से जुलाई 2019 निर्धारित किया गया है।

ख. **कुलभूषण जाधव केस (भारत बनाम पाकिस्तान):** जाधव के मामले में, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में अपने स्मारक के अलावा, 17 अप्रैल 2018 को पाकिस्तान के जवाबी स्मारक पर अपना जवाब दाखिल किया। पाकिस्तान ने 17 जुलाई, 2018 को एक पत्युत्तर दायर किया। इसके साथ ही दोनों पक्षों का लिखित दलीलों को प्रस्तुत करना पूरा हो गया। योग्यता पर पार्टियों की मौखिक सुनवाई आईसीजे द्वारा 18-21 फरवरी 2019 से हेग में होनी निर्धारित की गई है।

ग. **निवेश से संबंधित मध्यस्थता मामले:** स्थायी पंचाट न्यायालय (पीसीए) के तत्वावधान में गठित विभिन्न पंचाट न्यायाधिकरणों ने भारत गणराज्य के खिलाफ लाए गए निम्नलिखित निवेश संधि विवादों पर फैसला सुनाया।

- 8 अक्टूबर 2018 को, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने भारत-यूके और भारत-मॉरीशस द्विपक्षीय निवेश संधियों के अंतर्गत गठित एस्ट्रो ऑल एशिया नेटवर्क्स लिमिटेड और साउथ एशिया एंटरटेनमेंट होल्डिंग्स लिमिटेड में भारत के पक्ष में दो निर्णय दिए। दावे भारत में दावेदारों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही से उत्पन्न हुए। दावेदारों और इसके अधिकारियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध का आरोप लगाया गया था और यह मामला दूसरी विशेष अदालत के समक्ष लंबित था। मध्यस्थता की कार्यवाही में, दावेदारों ने दावा किया कि उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही के संबंध में भारत का आचरण भारत-यूके और भारत-मॉरीशस द्विपक्षीय निवेश संधियों के अंतर्गत भारत के महत्वपूर्ण दायित्वों और प्रतिबद्धताओं के उल्लंघन के कारण था, और उनके निवेश में नुकसान हुआ था। भारत के खिलाफ निवेशकों के दावे अंततः पक्षपात के साथ वापस ले लिए गए, और भारत (इसके अंगों, एजेंसियों, उपकरण, एजेंसियों और प्रतिनिधियों सहित) को हमेशा के लिए निवेशकों के दावों, शिकायतों और कार्रवाई के कारणों से छुट्टी दे दी गई। भारत को इन कार्यवाहियों में अपना बचाव करने की पूरी लागत भी दी गई जिसमें न्यायाधिकरण का शुल्क और व्यय और परामर्श शुल्क शामिल थे।

- 11 सितंबर 2018 को, भारत- फ्रांस द्विपक्षीय निवेश संधि के अंतर्गत लुइस ड्रेफस आर्मेटर्स (एलडीए) में, भारत के पक्ष में निर्णय पारित किया गया। एलडीए हल्दिया बल्क टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (एचबीटी) के साथ इस संयुक्त उद्यम में एक भागीदार था। यह दावा हल्दिया बल्क टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अनुबंध की समाप्ति के कारण बढ़ते नुकसान, बर्थ 2 और 8 को कार्गो के गैर-आवंटन का हवाला देकर और कानून और व्यवस्था के मुद्दों की गिरावट जैसे अन्य कारकों के कारण उत्पन्न हुआ। एकाधिक मुकदमे दायर किए गए। इस फैसले में कहा गया है कि एचबीटी में एलडीए का अप्रत्यक्ष निवेश फ्रांस-भारत बीआईटी के अंतर्गत संरक्षण का हकदार नहीं है क्योंकि फ्रांस-भारत बीआईटी सुरक्षा अप्रत्यक्ष निवेश के दायरे से बाहर है जिसमें एक निवेशक, वह जहाँ भी स्थित है मध्यवर्ती निवेश वाहन का 51% से कम का स्वामित्व रखता है, । ट्रिब्यूनल ने भारत द्वारा दावा की गई लागत का हिस्सा भी दिया।
- डर्चे टेलीकॉम बनाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया के बीच विवाद में स्थायी न्यायालय ऑफ आर्बिट्रेशन (पीसीए) के तत्वावधान में गठित ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए पंचाट को भारत-जर्मनी के बीच विवाद के कारण दिसंबर 2017 में जेनेवा में संघीय न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और अदालत ने भारत की चुनौती के खिलाफ फैसला सुनाया और न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा।
- भारतीय गणतंत्र में दावस बनाम भारत गणराज्य की चुनौती के मामले में भारत गणराज्य के अंतर्गत भारतीय गणतंत्र- मॉरीशस बीआईटी, हेग में जिला अदालत ने भारत की चुनौती के खिलाफ फैसला सुनाया और न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा।

भारत-मॉरीशस बीएपीए के अंतर्गत खेतान होल्डिंग्स मॉरीशस लिमिटेड बनाम भारत गणराज्य के बीच विवाद में, पंचाट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (पीसीए) के तत्वावधान में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का भी गठन किया गया है।

संधि वार्ताएं

क. पर्यावरण: कानून एवं संधियां प्रभाग के प्रतिनिधि ने पोलैंड के कैटोविस में 2-14 दिसंबर 2018 से यूनाइटेड किंगडम फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) के 24वें सम्मेलन में भाग लिया।

ख. निवेश: कानूनी और संधियों के प्रभाग ने ईरान, स्विट्जरलैंड, यूक्रेन, यूएई और मोरक्को के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौतों से संबंधित दस्तावेजों की बातचीत और जाँच की प्रक्रिया में भाग लिया।

ग. नागरिक और आपराधिक मामले: कानून और संधियाँ प्रभाग ने मई 2018 और सितंबर के महीने में भारत और मोरक्को के बीच राबत में आपराधिक मामलों में प्रत्यर्पण और पारस्परिक कानूनी सहायता पर संधियों की बातचीत में भाग लिया और भारत और मोरक्को के बीच नागरिक और वाणिज्यिक में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि की नई दिल्ली में बातचीत हुई और तीनों संधियों पर नवंबर, 2018 में मोरक्को से वीआईपी यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा, सितंबर के महीने में, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने मिन्स्क में भारत और बेलारूस के बीच नागरिक और वाणिज्यिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता वार्ता में भाग लिया। कानून और संधियों के प्रभाग ने नागरिक और आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता पर समझौते और सजा प्राप्त व्यक्तियों के स्थानांतरण के लिए विभिन्न द्विपक्षीय वार्ताओं में भाग लिया। उनमें से पोलैंड, बेलारूस और मोरक्को के साथ संधियाँ उल्लेखनीय हैं।

कानून और संधियां प्रभाग ने अगस्त में बांग्लादेश के ढाका में आयोजित आतंकवाद और आतंकवाद विरोधी अपराध पर आठवीं बिम्सटेक संयुक्त कार्य समूह में भाग लिया और नवंबर 2018 में काठमांडू, नेपाल में कानूनी और कानून प्रवर्तन मुद्दों की बिम्सटेक उप-समूह की आठवीं बैठक में भी भाग लिया।

घ. वाह्य अंतरिक्ष: कानून और संधियां प्रभाग ने विएना में 9-20 अप्रैल 2018 के बीच बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर कानूनी उप-समिति के 57 वें सत्र में भाग लिया

ङ. साइबर अपराध: कानून और संधियां प्रभाग ने 3-5 अप्रैल 2018 से वियना में आयोजित साइबर अपराध

पर एक व्यापक अध्ययन करने के लिए ड्रग्स एंड क्राइम (यूएनओडीसी) की चौथी राष्ट्रीय कार्यालय में भाग लिया। बैठक के दौरान विचार-विमर्श काफी हद तक विधान और रूपरेखा से संबंधित था जो साइबर अपराध की रोकथाम और सामना करने के कानूनी उपायों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा, साइबर अपराध की धारणाओं से संबंधित अध्ययन में पहचाने गए चौदह कार्यों के प्रकाश में उपलब्ध राष्ट्रीय कानून के आधार पर आपराधीकरण के अध्याय की जांच की गई।

ऑनलाइन संधि डेटाबेस

कानून और संधियाँ प्रभाग विदेश मंत्रालय (एमईए) की वेबसाइट पर भारतीय संधि डेटाबेस के अंतर्गत संधियों/ समझौतों/समझौता ज्ञापनों और अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों के एक समर्पित वेब मॉड्यूल का रखरखाव कर रहा है। 1950 से 2017 तक की अवधि के लिए अन्य देशों से भारतीय गणराज्य की सरकार की संधियों को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया गया है। इस डेटाबेस को नियमित आधार पर अद्यतन करने के लिए कानून और संधियाँ प्रभाग लगातार काम कर रहा है। वर्तमान में, डेटाबेस में 3000 से अधिक संधियाँ हैं।

संधियों की परीक्षा/ पुनरीक्षण

कानून और संधियां प्रभाग ने अंतर्राष्ट्रीय संधियों/ मझौतों से संबंधित कई अंतर्राष्ट्रीय कानून मुद्दों की जांच की और कानूनी राय प्रदान की। इसने अन्य के साथ, रक्षा सहकारिता, रेलवे, सार्क (क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ), स्वास्थ्य, जैव प्रौद्योगिकी, बाहरी अंतरिक्ष मुद्दों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ब्रिक्स (ब्राजील, रूस भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का समूह) और बंगाल की खाड़ी में बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (बिम्सटेक), शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ), अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित समझौते, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी/नशीले पदार्थों के लिए पहल; गोपनीयता पर समझौते; हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करना; गैस और ऊर्जा; सांस्कृतिक सहयोग, दृश्य-श्रव्य, सड़क परिवहन, व्यापार और निवेश, परियोजनाओं, शिक्षा, पर्यटन, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा पर द्विपक्षीय समझौते; जल संसाधन; जैव-विविधता; सौर गठबंधन; ओजोन क्षयकारी पदार्थ; हाइड्रोग्राफी, ट्विनिंग/साथी सिटी समझौते और सीमा शुल्क सहयोग समझौते, आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में संधि, समझौतों, समझौता ज्ञापनों का पुनरीक्षण किया।

संधियों की सूची

भारत ने वर्ष 2018 के दौरान विदेशी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ कई बहुपक्षीय/द्विपक्षीय संधियों/समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। एक व्यापक सूची **परिशिष्ट-I** में दी गई है। वर्ष **2018** के दौरान जारी किए गए इंस्ट्रूमेंट ऑफ रैटिफिकेशन/एक्सेसेशन **(37)** की सूची **परिशिष्ट-II** में है और वर्ष **2018** के दौरान जारी किए गए पूर्ण शक्तियों **(16)** के साधन की सूची **परिशिष्ट-III** में है। यह देखा जा सकता है कि भारत ने 2018 के दौरान 250 से अधिक बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संधियों पर हस्ताक्षर किए और/या उन पर निर्णय लिए हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा का 73वां सत्र

संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) का 73वां सत्र 'संयुक्त राष्ट्र को सभी लोगों के लिए प्रासंगिक बनाना: वैश्विक नेतृत्व और शांतिपूर्ण, समान और स्थायी समाज के लिए साझा जिम्मेदारियां' विषय 18 सितंबर 2018 को न्यूयॉर्क में आरंभ हुआ। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र के उच्च-स्तरीय खंड के समय 25

सितंबर से 1 अक्तूबर 2018 तक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। 28-29 सितंबर 2018 को दौरान विदेश मंत्री के साथ विदेश राज्य मंत्री श्री एम. जे. अकबर भी थे।

विदेश मंत्री ने 29 सितंबर 2018 को 73वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय खंड में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य दिया। विदेश मंत्री ने 21 देशों (एंटीगुआ और बारबुडा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, आर्मेनिया, बोलीविया, चिली, साइप्रस, कोलंबिया, इक्वाडोर, एस्टोनिया, यूरोपीय संघ, जर्मनी, ईरान, जापान, लिकटेंस्टीन, मंगोलिया, मोरक्को, नेपाल, पनामा, स्पेन, सीरिया और सूरीनाम) के अपने समकक्षों के साथ-साथ 3 शासनाध्यक्षों (फिजी, मॉरीशस और नेपाल) से द्विपक्षीय चर्चा की। विदेश मंत्री ने बांग्ला देश, इक्वेटोरियल गिनी, इटली, कुवैत, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, सिंगापुर और श्रीलंका के मंत्रियों के साथ भी बैठक की। विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा आयोजित जलवायु परिवर्तन पर विशेष कार्यक्रम, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा आयोजित ग्लोबल कॉल फॉर एक्शन ऑन वर्ल्ड ड्रग प्रॉब्लम और नेल्सन मंडेला पीस समिट में आयोजित विशेष कार्यक्रम में भी भाग लिया। विदेश मंत्री ने फिलिस्तीन, जी-4, आईबीएसए, ब्रिक्स और सार्क पर एनएएम समिति की बैठकों में भी भाग लिया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र में संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दौरा

एक दस सदस्यीय बहु-दलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल (श्री शरद त्रिपाठी, श्री प्रेम दास राय, श्री अरविन्द गणपत सावंत, श्री एन. के. प्रेमचंद्रन, सुश्री सुष्मिता देव, श्री विष्णु दयाल राम, श्री नरेश गुजराल, सुश्री कनिमोझी अरविन्थन, श्री सुखेन्दु शेखर रे, डॉ. नरेंद्र दामोदर जाधव सहित) 6-20 अक्तूबर 2018 से संयुक्त राष्ट्र संघ के 73वें सत्र में भारत के अनाधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के रूप में न्यूयॉर्क गया था। सांसदों ने इस यात्रा के दौरान महासभा और उसकी समितियों में संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न बैठकों/सत्रों में भाग लिया। संसद सदस्यों (सांसदों) ने विभिन्न अवसरों पर संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थिति पर चर्चा करते हुए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी), मानव बस्तियां और आवास, महिलाओं की उन्नति, बच्चों के अधिकार, सतत विकास के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकीविद् (आईसीटी), वैश्वीकरण और अन्योन्याश्रय, परमाणु हथियार और गरीबी उन्मूलन जैसे विभिन्न विषयों पर वक्तव्य दिए।

संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष का दौरा

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र की चयनित अध्यक्ष और इक्वाडोर की पूर्व विदेश मंत्री, सुश्री मारिया एस्पिनोसा 10-14 अगस्त 2018 को नई दिल्ली आई थीं। यात्रा के दौरान, उन्होंने प्रधानमंत्री से भेंट की। विदेश मंत्री ने उनके साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इन बैठकों में संयुक्त राष्ट्र में भारत के मूल हितों से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जिनमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार, अंतर-सरकारी वार्ता (आईजीएन) और आतंकवाद प्रतिरोध (सीसीआईटी) पर व्यापक सम्मेलन शामिल हैं। वे दिल्ली हाट देखने गईं और सतत विकास के क्षेत्र में लगे विभिन्न गैर सरकारी संगठनों से मिलीं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार

संयुक्त राष्ट्र में जी-4 और एल69 जैसे सुधार उन्मुख समूहों के साथ भारत की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के प्रयास जारी रहे। विदेश मंत्री ने XXXX पर संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में अपने भाषण में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला, उन्होंने कहा कि "संयुक्त राष्ट्र को यह स्वीकार करना चाहिए कि इसे मौलिक सुधार की आवश्यकता है। सुधार प्रसाधन नहीं हो सकता। हमें संस्थान के सिर और हृदय दोनों को बदलना होगा ताकि इसे समकालीन वास्तविकता के अनुकूल बनाया जा सके। सुधार आज शुरू होना चाहिए, कल तक बहुत देर हो सकती है।" एल69 समूह ने, भारत सहित अपने सभी सदस्यों के

योगदान के साथ, पिछले 25 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत तैयार किए गए सभी दस्तावेजों को संकलित करते हुए 'सुरक्षा परिषद सुधारों पर पुस्तिका: पर्यालोचना के 25 वर्ष' तैयार की।

जी-4 के विदेश मंत्रियों (भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान सहित) ने 25 सितंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार की प्रगति की समीक्षा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र के अवसर पर न्यूयॉर्क में अपनी वार्षिक बैठक आयोजित की। बैठक के अंत में जारी एक संयुक्त प्रेस बयान में, जी-4 के मंत्रियों ने परिषद के शीघ्र सुधार की आवश्यकता की पुष्टि की, जिसमें इसकी वैधता, प्रभावशीलता और प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए सदस्यता की स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों का विस्तार शामिल है। मंत्रियों ने 73वें सत्र के दौरान आईजीएन में पाठ-आधारित वार्ता शुरू करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

भारत और शांति स्थापना

भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सबसे बड़ा संचयी योगदान जारी रखा, भारत ने 1950 से 200,000 से अधिक सैनिक और पुलिस कर्मी प्रदान किए हैं। भारत, 31 अक्तूबर 2018 को नौ शांति अभियानों में तैनात 6,608 कर्मियों के साथ सबसे बड़ी सैन्य टुकड़ी का योगदान करने वाले देशों (टीसीसी) में चौथे स्थान पर है। आज तक, संयुक्त राष्ट्र मिशनों में सेवा करते हुए 163 भारतीय शांति सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है।

भारत ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (यूएनआईएफआईएल) में अपनी टुकड़ी के हिस्से के रूप में कजाकिस्तान से 120 सैनिक टुकड़ियों की सह-तैनाती का सफलतापूर्वक संचालन किया। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में इस तरह की सह-तैनाती पहली बार हो रही है।

भारत ने, बदलती वास्तविकताओं को संबोधित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार की कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव की पहल के अंतर्गत शांति व्यवस्था पर साझा प्रतिबद्धताओं की घोषणा का समर्थन किया।

संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए अंडर-सेक्रेटरी जनरल श्री जीन-पियरे लैक्रोइक्स ने जून 2018 में भारत का दौरा किया और रक्षा मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट की। उन्होंने नई दिल्ली में शांति स्थापना के संयुक्त राष्ट्र केंद्र (सीयूएनपीके) का दौरा किया और विश्व मामलों की भारतीय परिषद (आईसीडब्ल्यूए) में एक इंटरैक्टिव भाषण दिया।

भारत ने शांति स्थापना में क्षमता निर्माण पर अन्य देशों को समर्थन देना जारी रखा। शांति स्थापना के संयुक्त राष्ट्र केंद्र ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जुलाई 2018 के दौरान अफ्रीकी साझेदारों (यूएनपीसीएपी) के लिए तृतीय संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना पाठ्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कुल 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया। फ्रैंकोफ़ोन अफ्रीकी देशों के लाभ के लिए पहली बार फ्रांसीसी में पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए गए थे। फरवरी 2018 में जाम्बिया में प्रायोगिक आधार पर संयुक्त मोबाइल प्रशिक्षण टीम (जेएमटीटी) का शुभारंभ शांति स्थापना भारत-अमेरिका सहयोग की एक अन्य मुख्य बात थी।

यौन शोषण और दुर्व्यवहार (एसईए) की घटनाओं के प्रति शून्य सहिष्णुता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए, प्रधान मंत्री ने सितंबर 2018 में यौन शोषण और दुर्व्यवहार की रोकथाम और प्रतिक्रिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के अभियान "महासचिव के नेतृत्व के सर्किल का सामूहिक वक्तव्य" का समर्थन किया।

संयुक्त राष्ट्र में विचार-विमर्श के समय, भारत ने जनादेश तैयार करने में टीसीसी के साथ गंभीर और संस्थागत परामर्श की आवश्यकता; जनादेश को प्राथमिकता देने और कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त संसाधनों के आवंटन की आवश्यकता; निष्पादन में बाधा बनने वाले सभी राष्ट्रीय विरोधों को हटाने की आवश्यकता; 'मजबूत जनादेश' के मुद्दे पर उचित सावधानी और आक्रामक अभियानों में सैनिकों के लिए कानूनी सुरक्षा उपाय किए जाने पर बल दिया

संयुक्त राष्ट्र / बहुपक्षीय मुद्दों पर भारत फ्रांस परामर्श

नई दिल्ली में, 11 मई 2018 को संयुक्त राष्ट्र/बहुपक्षीय मुद्दों पर द्वितीय भारत-फ्रांस परामर्श आयोजित किया गया था। दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार, आईजीएन, आतंकवाद, 1267 समिति सूचीकरण, शांति स्थापना और संयुक्त राष्ट्र से संबंधित अन्य मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

आतंकवाद

भारत ने संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयास को अधिक प्राथमिकता दिए जाने पर जोर देना जारी रखा। इस बात पर बार-बार प्रकाश डाला गया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अपने कानूनी ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है, जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद (सीसीआईटी) पर व्यापक कन्वेंशन के समझौते पर पहुंचकर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी सहयोग का समर्थन करता है और संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न आतंकवाद प्रतिरोधों सहित सुरक्षा परिषद द्वारा गठित विभिन्न समितियों में संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद प्रतिरोध की पारदर्शिता और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करता है और संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक एकीकृत तरीके से आतंकवाद से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए अधिक से अधिक संस्थागत समन्वय की दिशा में काम करता है।

विदेश मंत्री ने 29 सितंबर 2018 को 73वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देते हुए आतंकवाद को मानवता के अस्तित्व के लिए दूसरा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के दानव ने अब दुनिया को चौंका दिया है। उन्होंने आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने के लिए अन्य देशों से सीसीआईटी का समर्थन करने की अपील की।

गृह मंत्रालय के विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) के नेतृत्व में चार सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 28-29 जून 2018 को न्यूयॉर्क में आयोजित आतंकवाद प्रतिरोधी एजेंसियों के प्रमुखों के पहले संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय सम्मेलन में भाग लिया।

अप्रैल 2018 में, संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद प्रतिरोधी केंद्र के परामर्श मंडल में भारत की सदस्यता को 3 साल की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया। भारत ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र और सदस्य राज्यों के साथ काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए रियाद में आयोजित परामर्श मंडल की 17वीं बैठक में भाग लिया।

भारत ने आतंकवाद का मुकाबला करने से संबंधित परियोजनाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद रोधी संगठन (यूएनओसीटी) के लिए 550,000 अमरीकी डॉलर का स्वैच्छिक योगदान दिया।

भारत ने 1267 अल-कायदा प्रतिबंध समिति सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति के साथ भी काम करना जारी रखा और साथ ही, प्रतिबंध व्यवस्था के सदस्य राज्यों द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अल-कायदा और तालिबान निगरानी टीम के साथ भी काम किया।

संयुक्त राष्ट्र में हिंदी

न्यूयॉर्क में भारत का स्थायी मिशन संयुक्त राष्ट्र सचिवालय द्वारा हिंदी में निर्मित सामग्री की मात्रा और आवृत्ति बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। परिणामस्वरूप, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय ने हिंदी में ऑडियो, वीडियो और पाठ सामग्री को बढ़ाया है और सूचनाओं के प्रसार के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के हिंदी संस्करण आरंभ किए हैं।

गुट निरपेक्ष आंदोलन

विदेश मंत्री ने 3-6 अप्रैल 2018 के बीच बाकू में आयोजित गुट निरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) के 18वें मध्यावधि मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक के दौरान, विदेश मंत्री ने उल्लेख किया कि एनएएम हमेशा

अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और सतत विकास पर हमारे पारस्परिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक पसंदीटा मंच होगा। विदेश मंत्री ने बैठक के अवसर पर, इक्वाडोर, घाना और वेनेजुएला के अपने समकक्षों से भेंट की।

कॉमनवेल्थ

प्रधानमंत्री ने लंदन में 19-20 अप्रैल 2018 को आयोजित राष्ट्रमंडल के शासनाध्यक्षों की बैठक (सीएचओजीएम) में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित प्रमुख घोषणाएं की गई थीं (i) तकनीकी सहयोग के कॉमनवेल्थ कोष (सीएफटीसी) में भारत के योगदान को 1 मिलियन पाउंड से बढ़ाकर 2 मिलियन पाउंड करना; (ii) 5 वर्षों में 50 मिलियन अमरीकी डॉलर की अतिरिक्त धनराशि के साथ भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में 'राष्ट्रमंडल उप खिड़की' खोलना; (iii) न्यूयॉर्क और जेनेवा में कॉमनवेल्थ स्मॉल स्टेट्स ऑफ़िस के लिए भारत द्वारा योगदान, क्रमशः 1,00,000 से 2,50,000 अमरीकी डॉलर और 80,000 से 1,50,000 अमरीकी डॉलर तक बढ़ाया गया; (iv) राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा में महासागर और समुद्री विकास क्षेत्रों में क्षमता निर्माण कार्यक्रम और (v) राष्ट्रमंडल देशों के लिए भारत में बीसीसीआई सुविधाओं में 30 लड़कों और 30 लड़कियों (16 वर्ष से कम) के लिए क्रिकेट में प्रशिक्षण योजना।

एशियाई संसदीय सभा

भारत के संसद सदस्यों द्वारा एशियाई संसदीय सभा (एपीए) की विभिन्न समितियों और वर्ष भर आयोजित की जाने वाली बैठकों में प्रतिनिधित्व किया जाता रहा, जिसमें 25 से 28 जुलाई, 2018 तक साइप्रस में आर्थिक और सतत विकास पर एपीए स्थायी समिति, राजनैतिक मामलों पर एपीए स्थायी समिति (एससीपीए) और 29-31 अक्तूबर 2018 से पाकिस्तान के ग्वादर में विशेष संसद के निर्माण के लिए समिति (एससीसीएपी) की बैठक और, 28 नवंबर -3 दिसंबर 2018 के इस्तांबुल, तुर्की में हुई एपीए की दूसरी कार्यकारी परिषद की 11वीं पूर्ण बैठक आदि में भाग लेना शामिल है।

लोकतांत्रिक पहलें

भारत ने 14 सितंबर 2005 को आरंभ की गई संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र निधि (यूएनडीईएफ) के लिए अपना समर्थन जारी रखा। भारत ने दिसंबर 2018 तक यूएनडीईएफ में लगभग 32 मिलियन अमरीकी डॉलर का योगदान दिया है। भारत ने 25-26 जून 2018 को सैंटियागो, चिली में कम्युनिटी ऑफ डेमोक्रेसीज की गवर्निंग काउंसिल और कार्यकारी समिति की बैठकों में भाग लिया। भारत ने कम्युनिटी ऑफ डेमोक्रेसीज गवर्निंग काउंसिल में अपनी सदस्यता का नवीनीकरण भी किया। कम्युनिटी ऑफ डेमोक्रेसीज (सीओडी) लोकतांत्रिक नियमों का समर्थन करने और दुनिया भर में लोकतांत्रिक मानदंडों और संस्थानों को मजबूत करने के एक साझा लक्ष्य की तलाश में सरकारों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र को एकजुट करने के लिए राष्ट्रों का एक वैश्विक अंतर-सरकारी गठबंधन है।

10

निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले

वैश्विक शांति और सुरक्षा एक मजबूत निरस्त्रीकरण, अप्रसार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की संरचना पर टिकी है। भारत निरस्त्रीकरण, अप्रसार और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रूप से लगा हुआ है और उसने विभिन्न क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर अपने अनुभवों और व्यस्तताओं के आधार पर एक मजबूत और विश्वसनीय संवाद विकसित किया है। निरस्त्रीकरण के मुद्दों पर भारत का रुख अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों और अंतर्राष्ट्रीय भू-भाग के साथ घनिष्ठ जुड़ाव की परंपरा के कारण एक बदलते भू-स्थानिक वातावरण में वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सहकारी प्रयासों को बढ़ावा देने की ओर निर्देशित था।

वर्ष 2018 में, भारत ने सार्वभौमिक और गैर-भेदभावपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के साथ-साथ सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के लिए अपनी प्रतिबद्धता के अनुसरण में निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर विभिन्न बहुपक्षीय मंचों में सक्रिय भूमिका निभाना जारी रखा।

संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली समिति

भारत ने 8 अक्टूबर से 9 नवंबर, 2018 के दौरान न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली समिति के 73 वें सत्र में वैश्विक, गैर-भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

"आतंकवादियों को बड़े पैमाने पर विनाश के हथियार प्राप्त करने से रोकने के उपाय" नामक भारत का संकल्प, जिसे पहली बार 2002 में पेश किया गया था, उसे इस वर्ष फिर से आम सहमति से अपनाया गया। 90 देशों द्वारा सह-प्रायोजित किया गया, यह संकल्प, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों से आतंकवादियों को सामूहिक विनाश के हथियार प्राप्त करने से रोकने और इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करने के उद्देश्य से उपाय करने का आहवान करता है।

किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियारों के उपयोग या खतरे को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन पर बातचीत शुरू करने के लिए निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन में “परमाणु हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध” पर भारत के प्रस्ताव को दोहराया गया। यह संकल्प 20 देशों द्वारा सह-प्रायोजित था और विपक्ष में 50 मत और 15 के मतदान में भाग न लेने के मुकाबले पक्ष में दिए जाने वाले 120 वोटों से इसे अपनाया गया था।

“परमाणु खतरे को कम करने” पर भारत के संकल्प ने परमाणु सिद्धांतों की समीक्षा और परमाणु हथियारों के जानबूझकर या आकस्मिक उपयोग के जोखिम को कम करने के लिए तत्काल कदम की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जिसमें उनको अक्षम और लक्ष्य हीन करना शामिल हैं। इस प्रस्ताव को पक्ष में दिए जाने वाले 127 मतों से अपनाया गया, विपक्ष में 49 मत दिए गए और 10 ने मतदान में भाग नहीं लिया, इसे 21 देशों द्वारा सह-प्रायोजित किया गया।

“अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और निरस्त्रीकरण के संदर्भ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका” पर भारत का संकल्प सर्वसम्मति से अपनाया गया था और इसे 19 देशों द्वारा सह-प्रायोजित किया गया था। पिछले वर्ष के संकल्प द्वारा अनिवार्य की गई, यूएनएसजी की रिपोर्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हाल की घटनाक्रमों पर प्रकाश डालती है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऑटोनॉमस सिस्टम, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, उन्नत मिसाइल और मिसाइल रक्षा प्रौद्योगिकियां, अंतरिक्ष-आधारित प्रौद्योगिकियां, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रौद्योगिकियां और पदार्थ प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। संकल्प ने इस महत्वपूर्ण विषय पर संबंधित हितधारकों के बीच संवाद की सुविधा प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण अनुसंधान (यूएनआईडीआईआर) के साथ जिनेवा में एक दिवसीय केंद्रित संगोष्ठी आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है।

संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग (यूएनडीसी)

यूएनडीसी ने 2 से 20 अप्रैल 2018 के दौरान न्यूयॉर्क में अपना वार्षिक मूल सत्र आयोजित किया, 2018-2020 चक्र के लिए इसके एजेंडा को अपनाया और अपने दो एजेंडा मदों, अर्थात् (i) परमाणु निरस्त्रीकरण और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सिफारिशें; और (ii) बाहरी अंतरिक्ष गतिविधियों में पारदर्शिता और विश्वास निर्माण उपाय (टीसीबीएम) पर सरकारी विशेषज्ञों के समूह (जीजीई) की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के अनुसार, बाहरी अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ रोकने के लिए बाहरी अंतरिक्ष गतिविधियों में टीसीबीएम के व्यावहारिक कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशों की तैयारी के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया। भारत ने यूएनडीसी की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन (सीडी)

निरस्त्रीकरण (सीडी) पर सम्मेलन ने 2018 में 22 जनवरी से 30 मार्च, 14 मई से 29 जून और 30 जुलाई से 14 सितंबर तक अपने सत्र आयोजित किए। सीडी ने अपनी कार्यसूची की पांच वस्तुओं पर पांच सहायक निकायों की स्थापना की: (i) हथियारों की दौड़ और परमाणु निरस्त्रीकरण की समाप्ति, (ii) सभी संबंधित मामलों सहित परमाणु युद्ध की रोकथाम (iii) बाहरी अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ को रोकना (पीएआरओएस) (iv) परमाणु हथियारों के उपयोग या खतरे के खिलाफ गैर-परमाणु हथियार सम्पन्न राज्यों को आश्वस्त करने के लिए प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था (एनएसए); तथा (v) सामूहिक विनाश के हथियारों नए प्रकार और ऐसे हथियारों की नई प्रणाली; रेडियोलॉजिकल हथियार, निरस्त्रीकरण का व्यापक कार्यक्रम, शस्त्रीकरण में पारदर्शिता, उभरते और सम्मेलन के मूल कार्य से संबंधित अन्य मुद्दे। भारत ने सीडी कार्यसूची के सभी चार मुख्य मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण साझा किया, जिसमें परमाणु निरस्त्रीकरण, विखंडनीय सामग्री में कमी पर संधि (एफएमसीटी), पीएआरओएस और एनएसएएस शामिल हैं। इसके साथ ही, भारत ने ठोस वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए सीडी द्वारा कार्य के कार्यक्रम को अपनाने का आह्वान किया। भारत ने परमाणु निरस्त्रीकरण को प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप सीडी में एक गैर-भेदभावपूर्ण और अंतरराष्ट्रीय रूप से सत्यापित एफएमसीटी की बातचीत शुरू करने के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी)

यूएनएससी संकल्प 1540 (2004) के अनुसार भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति के साथ समन्वय स्थापित कर रहा है जो राज्यों, अंतर-देशों को किसी भी तरह से गैर-राष्ट्र पक्षों को परमाणु, रासायनिक या जैविक हथियारों के विकास, अधिग्रहण, विनिर्माण, रखने, परिवहन, स्थानांतरण या स्थानांतरित करने और उनके वितरण प्रणाली का उपयोग करने से रोकने के लिए बाध्य करता है।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अंतर्गत अप्रैल 2017 में एक आदेश जारी करने और अक्टूबर 2017 और मार्च 2018 में संशोधन के माध्यम से सुरक्षा परिषद के डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया से संबंधित प्रासंगिक प्रस्तावों को लागू किया। उपरोक्त पर भारत की राष्ट्रीय कार्यान्वयन रिपोर्ट संकल्प 1718 समिति को प्रस्तुत की गई थी।

भारत ने जर्मनी और संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण मामलों के कार्यालय (यूएनओडीए) द्वारा समर्थित अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाने के लिए 16-17 अप्रैल, 2018 को 'यूएनएससी संकल्प 1540 के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में सरकार-उद्योग की नीतियों के माध्यम से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा' पर भारत-विस्बाडन सम्मेलन आयोजित किया। इसका उद्देश्य वैश्विक अंतर-निर्भरता के प्रति सचेत रहते हुए क्षेत्र की विशिष्टताओं के लिए विस्बाडन प्रक्रिया को अनुकूलित करना था। 'अनुभवों और सीखे गए सबक पर भारत-जर्मनी संयुक्त परिणामी दस्तावेज़' निरस्त्रीकरण मामलों पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है।

जैविक और विषाक्त हथियार सम्मेलन (बीटीडब्ल्यूसी)

भारत ने 2017 में सफलतापूर्वक बीडब्ल्यूसी के लिए राष्ट्रीय पक्षों की बैठक (एमएसपी) की अध्यक्षता की थी, जो अंतर-सत्रीय कार्यक्रम को अपनाने का कारण बना था। भारत ने 7 से16 अगस्त 2018 तक जेनेवा में आयोजित विशेषज्ञों की पांच बैठकों और 4-7 दिसंबर 2018 से राष्ट्रीय पक्षों की वार्षिक बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत दो कार्य पत्र प्रस्तुत किए - (i) संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ "बीडब्ल्यूसी के तृतीय अनुच्छेद के कार्यान्वयन को मजबूत बनाना" और (ii) फ्रांस के साथ "बीडब्ल्यूसी के सातवें अनुच्छेद के ढांचे में सहायता के लिए एक डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव"। विशेषज्ञों की बैठक के मौके पर, भारत ने "उभरते संक्रामक रोग: जांच, प्रतिक्रिया, सहायता और चुनौतियां" पर एक पक्षीय-कार्यक्रम आयोजित किया।

रासायनिक हथियार सम्मेलन (सीडब्ल्यूसी)

भारत ने रासायनिक हथियारों के निषेध (ओपीसीडब्ल्यू) के लिए संगठन की कार्यकारी परिषद (ईसी) के एक सदस्य के रूप में, रासायनिक हथियारों के विनाश, उद्योग निरीक्षण, राष्ट्रीय कार्यान्वयन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहायता के मुद्दों में योगदान दिया। पिछले वर्षों की तरह, भारत ने पूरे वर्ष ईसी के विभिन्न सत्रों में राष्ट्रीय पक्षों को शामिल कर एक सक्रिय भूमिका निभानी जारी रखी। 26-27 जून, 2018 राष्ट्रीय पक्षों के सम्मेलन (सीएसपी) के चौथे विशेष सत्र का आयोजन; 19-20 नवंबर 2018 के दौरान आयोजित सीएसपी का 23वां सत्र और नीदरलैंड्स के हेग में 21-30 नवंबर, 2018 के दौरान रासायनिक हथियार सम्मेलन (सीडब्ल्यूसी) का चौथा समीक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत ने ओपीसीडब्ल्यू में आरोपण तंत्र स्थापित करने के लिए सीएसपी के चौथे विशेष सत्र के निर्णय के खिलाफ मतदान किया क्योंकि यह भारत की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता था।

भारत ने ओपीसीडब्ल्यू के मेंटरशिप कार्यक्रम के अंतर्गत, अफगानिस्तान को मेंटर करने का प्रस्ताव किया है।

कुछ पारंपरिक हथियारों पर सम्मेलन (सीसीडब्ल्यू)

भारत ने 11-13 जून, 2018 तक जिनेवा में संशोधित प्रोटोकॉल-II के विशेषज्ञों और सीसीडब्ल्यू के प्रोटोकॉल-V की बैठकों में भाग लिया। भारत ने 21-23 नवंबर, 2018 को सीसीडब्ल्यू के लिए उच्च अनुबंध वाले दलों की वार्षिक बैठक के दौरान और साथ ही 19 और 20 नवंबर 2018 को क्रमशः संशोधित प्रोटोकॉल-द्वितीय और प्रोटोकॉल-पाँच के वार्षिक सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। स्विट्ज़रलैंड के साथ, भारत ने "विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास पर विचार" नामक एक कार्यपत्र प्रस्तुत किया जो सीसीडब्ल्यू के कार्य के लिए प्रासंगिक हो सकता है।

भारत ने 9-13 अप्रैल 2018 और 27-31 अगस्त 2018 को जिनेवा में घातक स्वायत्त शस्त्र प्रणाली (एलएडब्ल्यूएस) पर सरकारी विशेषज्ञों के समूह (जीजीई) की बैठक की सफलतापूर्वक अध्यक्षता की। जीजीई घातक स्वायत्त शस्त्र प्रणाली के क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित संभावित मार्गदर्शक सिद्धांतों को, सर्वसम्मति से अपनाने में सफल रहा। अगस्त 2018 में अंतिम बैठक में एक रिपोर्ट को अपनाया गया जिसमें निष्कर्ष और सिफारिशों का एक समूह शामिल था जिसमें सीसीडब्ल्यू को उच्च संपर्क दलों की वार्षिक बैठक द्वारा समर्थन दिया गया था। घातक स्वायत्त शस्त्र प्रणाली पर जीजीई, जेनेवा 2019 में मैसेडोनिया के पूर्व यूगोस्लाव गणराज्य की अध्यक्षता में सात दिनों तक अपने जनादेश को पूरा करना जारी रखेगा।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पर संगोष्ठी

ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) के साथ साझेदारी में निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन के लिए भारत के स्थायी मिशन ने आईटीयू के "एआइ फॉर गुड समिट" के समय "कृत्रिम बुद्धिमत्ता: वर्तमान नीति प्रतिबिंब और भविष्य की रणनीतियाँ" पर 18 मई 2018 को जिनेवा में एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास, उपयोग और प्रचार के एक पार-क्षेत्रीय विनिमय पर केंद्रित था।

मानव-विरोधी सुरंग प्रतिबंध कन्वेंशन (एपीएमबीसी)

भारत ने नवंबर 2018 से जिनेवा में आयोजित एपीएमबीसी की राष्ट्रीय पक्षों की 17वीं बैठक में एक पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया।

छोटे हथियार और हल्के हथियार

जुलाई 2001 में अपनाया गया संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई का कार्यक्रम (यूएनपीओए) अपने सभी पहलुओं में छोटे आयुधों और हल्के हथियारों में अवैध व्यापार को रोकने, उसका मुकाबला करने और हटाने के लिए अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक उपायों का एक व्यापक सेट प्रदान करता है। भारत ने यूएनपीओए और अंतर्राष्ट्रीय अनुरेखण साधन के कार्यान्वयन की दिशा में प्रगति जारी रखी है। भारत ने 18-29 जून 2018 से न्यूयॉर्क में एसएएलडब्ल्यू पर तीसरे समीक्षा सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लिया।

सरकारी विशेषज्ञों के समूह में भागीदारी (जीजीई)

वर्ष 2018 में, भारत ने तीन जीजीई में भाग लिया - (i) जिनेवा में एइएमसीटी पर 28 मई से 8 जून तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ तैयारी समूह (ii) 14-18 मई और 12-16 नवंबर को जिनेवा में परमाणु निरस्त्रीकरण सत्यापन (एनडीवी) पर जीजीई और (iii) 6-17 अगस्त को जिनेवा में बाहरी अंतरिक्ष में शस्त्रों की होड़ को रोकना (पीएआरओएस)।

निरस्त्रीकरण मामलों पर यूएनएसजी का सलाहकार मंडल (एबीडीएम)

भारत के प्रतिनिधि ने 23 से 26 जनवरी 2018 तक और न्यूयॉर्क में और 27-29 जून 2018 को जिनेवा में आयोजित यूएनएसजी के एबीडीएम के 69वें और 70वें सत्र में भाग लिया।

परमाणु अनुसंधान के लिए यूरोपीय संगठन (सीईआरएन)

भारत 2017 में सीईआरएन का एसोसिएट सदस्य बन गया और 2018 के दौरान इसने सर्न काउंसिल, वित्त समिति और वैज्ञानिक नीति समिति के सत्रों में भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए)

भारत ने 17-21 सितंबर, 2018 के दौरान वियना में आयोजित आईएईए जनरल कॉन्फ्रेंस के 62वें सत्र में भाग लिया। पिछले वर्षों की तरह, भारत ने मार्च, जून, सितंबर और नवंबर, 2018 में आयोजित बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स की बैठकों में राष्ट्रीय पक्षों के साथ मिल कर एक सक्रिय भूमिका निभाना जारी रखा। भारत ने 7-11 मई के दौरान आयोजित

कार्यक्रम और बजट समिति की बैठक (पीबीसी) और 19-20 नवंबर, 2018 के दौरान आयोजित तकनीकी सहायता और सहयोग समिति (टीएसीसी) में भी भाग लिया।

भारत ने पूरे वर्ष वियना में आयोजित कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके अतिरिक्त, भारत ने 22-27 अक्टूबर को गांधीनगर, भारत में आयोजित 27वें आईएईए संलयन ऊर्जा सम्मेलन में भी भाग लिया।

परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर 28-30 नवंबर, 2018 के दौरान आयोजित आईएईए मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में लगभग 1100 प्रतिभागियों के साथ, 137 राज्यों और 15 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 54 कार्य वृत्त सहित उच्च-स्तरीय अधिकारियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। महानिदेशक ने एक बयान दिया और भारत ने सम्मेलन से पहले मंत्रिस्तरीय घोषणा से पहले वार्ता में सक्रिय रूप से भाग लिया।

समुद्री मामले

भारत ने 2018 में ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ वार्षिक समुद्री सुरक्षा संवाद आयोजित किया। इसके अलावा, यूरोपीय संघ के साथ समुद्री सुरक्षा पर अनौपचारिक परामर्श किया गया। संवादों में आपसी हित के मुद्दों को शामिल किया गया, जिसमें भारत-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा विकास पर दृष्टिकोण का आदान-प्रदान और साथ ही द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की संभावनाएं शामिल हैं।

समुद्री क्षेत्र की जागरूकता में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने कई देशों के साथ व्हाइट शिपिंग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं जिनकी गिनती 18 तक पहुँच गई है। इसके अलावा, भारत ने पार-क्षेत्रीय समुद्री नेटवर्क (टी-आरएमएन) के लिए एक आरोहण समझौते पर भी हस्ताक्षर किया, जिसमें 30 देशों का एक बहुपक्षीय गठन शामिल है। इसके अलावा, भारत ने 21 दिसंबर 2018 को सूचना संलयन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र (आईएफसी-आईओआर) का शुभारंभ किया।

मलक्का और सिंगापुर के जलडमरूमध्य (एसओएमएस)

भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ के) के अंतर्गत 2007 में स्थापित "प्रमुख नौवहन मार्गों की सुरक्षा" पहल के अंतर्गत मलक्का और सिंगापुर के जलडमरूमध्य (एसओएमएस) के सहकारी तंत्रों का सक्रिय सदस्य रहा है। पहले के योगदान के आधार पर, भारत ने मई और सितंबर 2018 में मलेशिया में आयोजित नेविगेशन फंड की सहायता (एएनएफ) समिति की 20वीं और 21वीं बैठक में भाग लिया। भारत ने एएनएफ के लिए 30 लाख रुपये की राशि का योगदान दिया, जो सहकारी यांत्रिकी के लिए एक कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है और नौवहन की चिन्हित सहायता के नियोजित रखरखाव के लिए एक बजट प्रदान करता है।

सोमालिया के तट पर समुद्री डकैती पर संपर्क समूह (सीजीपीसीएस)

भारत ने 12-13 जुलाई, 2018 को नैरोबी में कोमालिया (सीजीपीसीएस) के तट पर डकैती पर आयोजित संपर्क समूह के 21वें पूर्ण सत्र में भाग लिया। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात और सेशेल्स के साथ, "सागर में संचालन" पर कार्य समूह की सह-अध्यक्षता की।

एशिया में सहभागिता और विश्वास निर्माण उपायों पर सम्मेलन (सीआईसीए)

भारत ने पूरे वर्ष सीआईसीए कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया। विदेश मंत्री श्रीमती श्रीमती सुषमा स्वराज ने 24 सितंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क में विदेश मामलों के सीआईसीए मंत्रियों की विशेष बैठक में भाग लिया।

आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) और एडीएमएम प्लस

भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के अनुरूप, भारत ने एआरएफ के तत्वावधान में आयोजित सभी अंतर-व्यावसायिक बैठकों (आईएसएम) और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों (एसओएम) में सक्रिय रूप से भाग लिया। विदेश राज्य मंत्री जनरल डॉ. वी. के. सिंह (सेवानिवृत्त) 4 अगस्त 2018 को सिंगापुर में एआरएफ की 25वीं मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल हुए।

भारत म्यांमार के साथ मिलिट्री मेडिसिन पर एडीएमएम प्लस विशेषज्ञों के कार्य समूह का सह-अध्यक्ष है और इसने एडीएमएम प्लस के तत्वावधान में आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं और कार्यक्रमों में भाग लेने के साथ-साथ अंतर सत्रीय बैठक (आईएसएम) में अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। रक्षामन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 20 अक्टूबर 2018 को सिंगापुर में आयोजित वार्षिक एडीएमएम प्लस संवाद के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

परमाणु सुरक्षा संपर्क समूह (एनएससीजी)

एनएससीजी परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन प्रक्रिया का एक परिणाम है और भारत ने 2018 में आयोजित समूह की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत ने 3-7 दिसंबर 2018 के दौरान वियना में आयोजित रेडियोधर्मी सामग्री की सुरक्षा: पता लगाने और रोकथाम के लिए आगे की राह पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी भाग लिया।

निर्यात नियंत्रण

वासेनार व्यवस्था (डब्ल्यूए) के 42वें राज्य के रूप में, भारत ने अप्रैल और सितंबर 2018 में विशेषज्ञों के समूह (ईजी) की बैठकों, मई और अक्टूबर 2018 में जनरल वर्किंग ग्रुप (जीडब्ल्यूजी) और दिसंबर 2018 में पूर्ण सत्र की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेना जारी रखा। वासेनार व्यवस्था का उद्देश्य पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाले सामान और प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है।

भारत जनवरी 2018 में, 43वें भागीदार के रूप में ऑस्ट्रेलिया समूह (एजी) का सदस्य बना, जिससे भारत को रासायनिक और जैविक हथियारों के अप्रसार के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान मिला है।

परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में भारत की सदस्यता के लिए आवेदन पर विचार चल रहा है, भारत ने परमाणु सामग्री और प्रौद्योगिकी के निर्यात पर नियंत्रण के लिए एनएसजी दिशानिर्देशों को अद्यतित और कार्यान्वित करना जारी रखा है। भारत जून 2016 में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (एमटीसीआर) में शामिल हुआ और एमटीसीआर की बैठकों में भाग लेता रहा है, जिसमें मार्च और नवंबर 2018 में आइसलैंड में आयोजित तकनीकी विशेषज्ञ समूह की बैठकें शामिल हैं।

चार बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं: वासेनार व्यवस्था, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, एमटीसीआर और ऑस्ट्रेलिया समूह के दिशानिर्देश और नियंत्रण सूची के साथ सामंजस्य बनाने के लिए वर्ष के दौरान, भारत की विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी (एससीओएमईटी) की निर्यात नियंत्रण सूची को मार्च और जुलाई 2018 में

अद्यतित किया गया था। 2018 में युद्ध-सामग्री के निर्यात के लिए प्राधिकरण जारी करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया को भी संशोधित किया गया था।

हेग आचार संहिता

भारत ने जून 2016 में हेग कोड ऑफ़ कंडक्ट (एचसीओसी) में शामिल हुआ/इसकी सदस्यता ली। पारदर्शिता और विश्वास निर्माण उपायों पर प्रतिबद्धताओं के अनुपालन में, भारत ने नियमित रूप से अपनी बैलिस्टिक मिसाइल और अंतरिक्ष प्रक्षेपणों की पूर्व-लॉन्च सूचनाओं के बारे में एचसीओसी को अधिसूचित किया और वियना में 28-29 मई 2018 के दौरान आयोजित एचसीओसी की 17वीं नियमित बैठक में भाग लिया।

भारत ने 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपनी वार्षिक घोषणा भी प्रस्तुत की।

वाह्य अंतरिक्ष:

भारत ने वियना में बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोगों पर संयुक्त राष्ट्र समिति और उसकी उपसमितियों की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया। जून 2018 में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यूनिस्पेस+50 के लिए वियना में इकट्ठा हुआ, जिसने बाहरी अंतरिक्ष की खोज और शांतिपूर्ण उपयोग पर पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पचासवीं वर्षगांठ मनाई। यूनिस्पेस+50 पहल के हिस्से के रूप में, भारत ने “उन्नति” नाम के छोटे उपग्रह बोध पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम की घोषणा की, जो इसरो द्वारा यूनिस्पेस नैनोसेटेलिक संयोजन और प्रशिक्षण को दर्शाता है तथा विकासशील देशों को छोटे उपग्रह के संयोजन, एकीकरण और परीक्षण में क्षमताओं को मजबूत करने के लिए उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। कार्यक्रम तीन वर्ष की अवधि के लिए है, जिससे 45 देशों के 90 उम्मीदवारों को लाभ होगा। पहला पाठ्यक्रम 15 जनवरी 2018 को बेंगलुरु में शुरू हुआ जिसमें 18 देशों के 30 प्रतिभागी शामिल हैं।

“बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ को रोकने के लिए और अधिक व्यावहारिक उपाय” नामक यूएनजीए संकल्प 72/250 को अपनाने के परिणामस्वरूप 24 दिसंबर 2017 को 25 सदस्य राज्यों की सदस्यता के साथ, सरकारी विशेषज्ञों के एक समूह (जीजीई) का गठन किया गया, तथा उसे बाहरी अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ को रोकने के साथ-साथ अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती पर रोक लगाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन के पर्याप्त तत्वों पर विचार करने और सिफारिश करने का काम सौंपा गया। भारत भी इस जीजीई का हिस्सा है और 6-17 अगस्त 2018 (दो सप्ताह) से जिनेवा में होने वाले यूएनजीजीई के पहले भाग में भाग लिया है। अंतिम बैठक मार्च 2019 में होने वाली है।

11

बहुपक्षीय आर्थिक संबंध

ब्रिक्स

दसवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

दसवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 25-27 जुलाई 2018 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था, जिसका विषय था "अफ्रीका में ब्रिक्स: समावेशी विकास और चौथी औद्योगिक क्रांति में साझा समृद्धि के लिए विकासशील देशों के साथ सहयोग"। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति श्री सिरिल रामफोसा ने शिखर सम्मेलन की कार्यवाही की अध्यक्षता की। ब्राजील के राष्ट्रपति श्री मिशेल टेमर, चीन के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के अपने-अपने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

जोहान्सबर्ग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में, नेताओं के प्रतिबंधित सत्र, पूर्ण सत्र, ब्रिक्स व्यापार परिषद के साथ बैठक, ब्रिक्स नेताओं के रिट्रीट के अलावा आउटरीच/ब्रिक्स प्लस खंडों का आयोजन किया गया। शिखर सम्मेलन में, नेताओं ने बहुपक्षवाद को मजबूत करने, कानून और वैश्विक शासन के नियम; वैश्विक शांति और सुरक्षा; आर्थिक और वित्तीय सुदृढ़ता को मजबूत करने और चौथी औद्योगिक क्रांति पर चर्चा की। लीडर्स रिट्रीट "साझा समृद्धि और समावेशी विकास के भविष्य के लिए संयुक्त सहयोग का एक दशक और सहयोग पर विचार" विषय पर आयोजित किया गया था।

शिखर सम्मेलन के परिणामों में **जोहान्सबर्ग घोषणा** शामिल थी जिसमें ब्रिक्स नेताओं द्वारा आतंकवाद पर कठोर विचार व्यक्त किए गए थे। ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में इसकी निंदा की। उन्होंने सभी राष्ट्रों को आतंकवादी नेटवर्कों का वित्तपोषण और अपने क्षेत्रों से आतंकवादी कार्रवाई को रोकने की उनकी जिम्मेदारी की याद दिलाई।

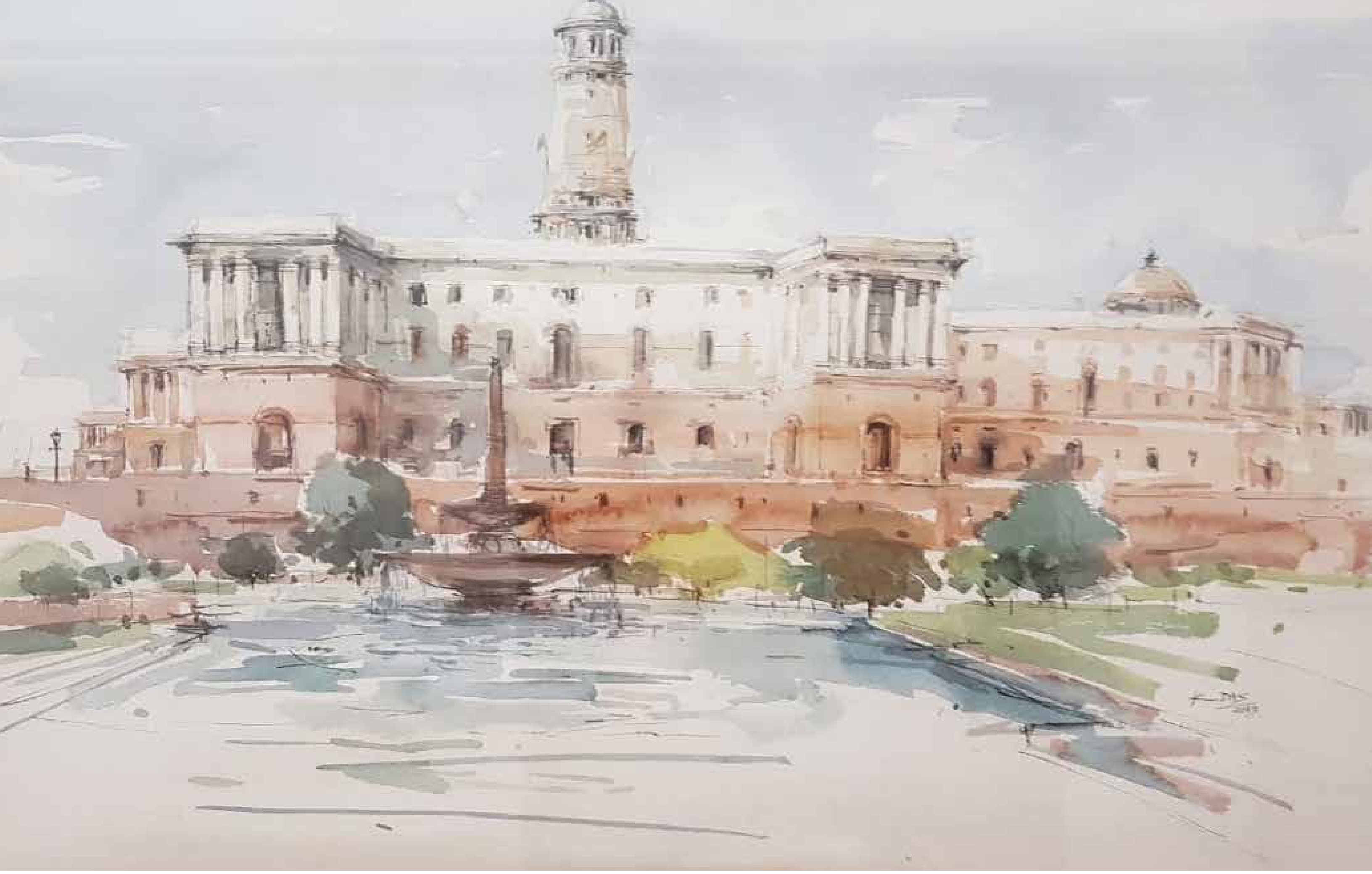

नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद (सीसीआईटी) पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने तथा कट्टरवादी बनाने, भर्ती और विदेशी आतंकवादी लड़ाकों की यात्रा पर एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की मांग की। नेताओं ने आतंकवादी वित्त के स्रोतों को अवरुद्ध करने, हथियारों की आपूर्ति, आतंकवादी ठिकानों को खत्म करने और इंटरनेट का दुरुपयोग रोकने का आहवान किया। नेताओं ने आतंकवाद और प्रसार के वित्तपोषण पर वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) मानकों को लागू करने का भी आहवान किया।

जोहान्सबर्ग घोषणा के अन्य तत्व थे (i) सतत विकास और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए 2030 एजेंडा को पूरी तरह से लागू करने की प्रतिबद्धता (ii) आपसी सम्मान, संप्रभु समानता, लोकतंत्र, समावेशिता और मजबूत सहयोग के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता (iii) पक्षों के 24वें सम्मेलन (यूएनएफसीससी सीओपी 24) की दिशा में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीससी) की वार्ता को पूरा करने के लिए काम करना (iv) 2019 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के सुधार को पूरा करना (v) महिला सांसदों के मंच को मजबूत बनाना; (vi) नई दिल्ली में ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच (एआरपी) को मजबूत करना (vii) कानून प्रवर्तन, भगोड़ों के प्रत्यर्पण, आर्थिक और भ्रष्टाचार के अपराधी और संपत्ति की वसूली में सहयोग (viii) संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के व्यापक सुधार की आवश्यकता (ix) बहुपक्षवाद को समर्थन (x) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की केंद्रीयता आदि।

जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में चौथी औद्योगिक क्रांति पर दिए गए विशेष ध्यान को याद करते हुए, शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स भागीदारी, नई औद्योगिक क्रांति (पार्टएआईआर),

जोहान्सबर्ग में दसवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में बिक्स राष्ट्रों के नेताओं का समूह फोटो (26 जुलाई, 2018)

ब्रिक्स वैक्सीन अनुसंधान केंद्र, ब्रिक्स नेटवर्क ऑफ साइंस पार्क्स और ब्रिक्स ऊर्जा अनुसंधान मंच पर शुरू किए गए। इसके अलावा, शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय उड्डयन में सहयोग पर ब्रिक्स समझौता ज्ञापन और पर्यावरण पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा, सामाजिक और श्रम क्षेत्र में सहयोग पर ब्रिक्स समझौता ज्ञापन और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास के संदर्भ में वितरित लेजर और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर सहयोगात्मक अनुसंधान पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आउटरीच की ब्रिक्स परंपरा की निरंतरता में, दक्षिण अफ्रीका ने आउटरीच का आयोजन किया जिसमें रवांडा (अध्यक्ष अफ्रीकी संघ), सेनेगल (अध्यक्ष - अफ्रीका के विकास के लिए नई भागीदारी (एनईपीएडी), गैबोन (मध्य अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय के अध्यक्ष), युगांडा (चेयर पूर्वी अफ्रीकी समुदाय के अध्यक्ष), इथियोपिया (अंतर सरकारी प्राधिकरण विकास के अध्यक्ष), टोगो (पश्चिम अफ्रीका राज्यों के आर्थिक समुदाय के अध्यक्ष), जाम्बिया (पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के लिए सामान्य बाजार के नए अध्यक्ष), नामीबिया (दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय के नए अध्यक्ष), अंगोला (अध्यक्ष - दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय (एसएडीसी) और अफ्रीकी संघ आयोग के अध्यक्ष को आमंत्रित किया गया था। मॉरीशस, लेसोथो, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, सेशेल्स, तंजानिया, मोजाम्बिक, मलावी और मेडागास्कर के एसएडीसी नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था। दक्षिण अफ्रीका ने शिखर सम्मेलन में अर्जेंटीना (अध्यक्ष जी20), मिस्र (अध्यक्ष जी77 + चीन), जमाइका (कैरेबियन समुदाय के नए अध्यक्ष (कैरिकॉम) और तुर्की (ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (ओआईसी)के नए अध्यक्ष) को भी आमंत्रित किया था।

ब्यूनस आयर्स जी20 शिखर सम्मेलन के हाशिये पर ब्रिक्स नेताओं की बैठक

अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में जी20 शिखर सम्मेलन के हाशिए पर 30 नवंबर, 2018 को ब्रिक्स नेताओं की एक पारंपरिक अनौपचारिक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति श्री सिरिल रामफोसा ने की। नेताओं ने जी20 शिखर सम्मेलन एजेंडा पर व्यापक चर्चा की और जी20 में ब्रिक्स देशों के वैश्विक और पारस्परिक हित के मुद्दों को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। बैठक के एजेंडे के अलावा, चर्चा में वैश्विक राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक, और वैश्विक प्रशासन के मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर विचारों का आदान-प्रदान शामिल था।

यूएनजीए के हाशिए पर ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक

न्यूयॉर्क शहर में 27 सितंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 73वें सत्र के समय विदेश मंत्री (ईएएम) श्रीमती सुषमा स्वराज ने प्रथागत ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान, ब्रिक्स मंत्रियों ने वैश्विक राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा महत्व के मामलों पर विचार विनिमय किया।

ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक, प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 4 जून, 2018 को प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक में भाग लिया। दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री, सुश्री लिंडीवे सिसुलु ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें रूसी संघ के विदेश मंत्री श्री सर्गेई लावरोव, चीन के लोकतांत्रिक गणराज्य के विदेश मंत्री श्री वांग यी और ब्राजील के संघीय गणराज्य के विदेशी संबंधों के उप-मंत्री श्री मार्कोस बीज़र्रा एबॉट गैलोवा भी शामिल हुए। ब्रिक्स मंत्रियों ने वैश्विक राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा महत्व के मामलों पर विचार विनिमय किया।

ब्रिक्स शेरपाओं की बैठक, डरबन, दक्षिण अफ्रीका

ब्रिक्स शेरपाओं की सातवीं और अंतिम बैठक दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में 4-5 दिसंबर, 2018 को डरबन में आयोजित की गई थी। बैठक का एजेंडा ब्राजील को अध्यक्षता (2019 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष) सौंपना और 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए अध्यक्षों की प्राथमिकताओं पर चर्चा करना था। अगली ब्रिक्स शेरपा/सूस-शेरपा बैठक 13-15 मार्च 2019 को होने की संभावना है, स्थल की पुष्टि बाद में की जाएगी।

जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स आउटरीच कार्यक्रम में ब्रिक्स राष्ट्राध्यक्षों का समूह फोटो (27 जुलाई, 2018)

तेरहवां जी20 शिखर सम्मेलन

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर और 01 दिसंबर 2018 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में तेरहवें जी20 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। शिखर सम्मेलन का विषय था "निष्पक्ष और सतत विकास

के लिए सहमति बनाना"। शिखर सम्मेलन में जी20 की पूरी कार्यसूची में काम के भविष्य, विकास के लिए बुनियादी ढांचे, स्थायी खाद्य भविष्य और लिंग को मुख्यधारा में लाने की रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया गया।

शिखर सम्मेलन में सतत, संतुलित और समावेशी विकास पर विशेष बल दिया गया। जी20 लीडर्स रिट्रीट 30 नवंबर 2018 को 'एक न्यायसंगत और स्थायी भविष्य' पर आयोजित किया गया था।

ब्यूनस आयर्स घोषणा ने मजबूत वैश्विक आर्थिक विकास का स्वागत किया, पर इस बात को भी मान्यता दी कि इसे देशों के बीच कम समन्वित किया गया है। घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित शामिल हैं (i) मजबूत, स्थायी, संतुलित और समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए सभी नीतिगत उपकरणों का उपयोग करना (ii) मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मौद्रिक नीति का उपयोग (iii) नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सुधार के लिए प्रतिबद्धता (iv) सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को पोर्टेबल बनाना (v) कौशल विकास और गुणवत्ता विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा (vi) डिजिटल अंतर को दूर करना (vii) एक परिसंपत्ति वर्ग के रूप में बुनियादी ढाँचा (viii) खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ कृषि (ix) अधिक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली, एचआईवी/एड्स, तपेदिक और मलेरिया को समाप्त करना, पारंपरिक दवाओं का उपयोग (x) आपदा रोकने के लिए लचीला बुनियादी ढांचा (xi) विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के मद्देनजर आम लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए पेरिस समझौते को लागू करना; (xii) ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा गरीबी उन्मूलन द्वारा सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंच (xiii) 2019 तक आईएमएफ कोटा के 15वीं सामान्य समीक्षा (जीआरक्यू) सुधार (xiv) आर्थिक अपराधों से निपटना, अपराधियों की वापसी और संपत्ति की वसूली में सहयोग।

ब्यूनस आयर्स नेताओं के घोषणापत्र में धन शोधन रोकने के लिए क्रिप्टो-संपत्ति का विनियमन, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) मानकों के अनुरूप आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करना, आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में इसकी कड़ी निंदा और आतंकवाद का मुकाबला करने पर हैम्बर्ग जी20 लीडर्स स्टेटमेंट के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए आह्वान, आतंकवादी और प्रसार वित्तपोषण और धन शोधन से लड़ने के प्रयास और आतंकवादी उद्देश्यों के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया के शोषण से लड़ने के प्रयासों को भी प्रमुखता से दर्शाया गया है।

ब्यूनस आयर्स में जी-20 शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र में प्रधान मंत्री और जी 20 सदस्यों का समूह फोटो (30 नवंबर, 2018)

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जी20 लीडर्स रिट्रीट में 'एक निष्पक्ष और टिकाऊ भविष्य' पर एक प्रमुख हस्तक्षेप किया। उन्होंने शिखर सम्मेलन के बाद के सत्रों में भी हस्तक्षेप किया और विभिन्न मुद्दों पर भारत की बात को प्रभावी ढंग से रखा।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दस वर्षों में जी20 द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने आईएमएफ के

कोटा की 14वीं सामान्य समीक्षा में जी20 द्वारा निभाई गई भूमिका, आधार के क्षय और लाभ के स्थानांतरण (बीईपीएस) का संचालन किया और कर मामलों पर जानकारी का स्वत: आदान-प्रदान के बारे में बात की। उन्होंने जी 20 सहयोग द्वारा निभाई गई भूमिका पर भी प्रकाश डाला जिसके परिणामस्वरूप 2008 के बाद की बहाली और पुनरुद्धार हुआ।

वैश्विक अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तेल की कीमत में उतार-चढ़ाव, व्यापार तनाव में वृद्धि के बारे में बात की जो कम विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की संपार्श्विक क्षति का कारण बनता है। उन्होंने मुख्य रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की मौद्रिक नीतियों और विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं के पुनरुद्धार की असमान गति से उत्पन्न होने वाली वित्तीय कमजोरियों के खतरे पर भी प्रकाश डाला।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक सक्रिय और सुधारित बहुपक्षवाद की आवश्यकता पर जोर देते हुए, आईएमएफ, एफएटीएफ, संयुक्त राष्ट्र और जी20 जैसे विभिन्न बहुपक्षीय चैनलों को सक्रिय करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बजटीय और वित्तीय संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डाला है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि विश्व व्यापार संगठन में सुधार केवल महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि व्यापार और सेवाओं पर बातचीत को आगे बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में वैश्विक मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि सभी देशों को समय के भीतर स्वचालित विनिमय में शामिल होना चाहिए और जानकारी साझा करना शुरू करना चाहिए, भारत पहले से ही साठ से अधिक न्यायालयों के साथ जानकारी साझा कर रहा है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ वैश्विक सहयोग के लिए नौ-सूत्री एजेंडे को प्रस्तुत किया। आतंकवाद पर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में एक अद्वीतीय दस्तावेज़ के रूप में हैम्बर्ग घोषणा के एक भाग के रूप में जारी आतंकवाद के खिलाफ ग्यारह सूत्री एजेंडा को पूरी तरह से लागू और संचालित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल के वर्षों में भारत द्वारा किए गए सबका साथ, सबका विकास, डिजिटल पहल और कौशल विकास कार्यक्रमों जैसे मजबूत और समावेशी विकास नीति के हस्तक्षेप, सुधार और पहलों के बारे में बताया। उन्होंने रोबोटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, शिक्षा प्रौद्योगिकी, वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) उद्योग आदि परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों के दोहन के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयासों पर भी प्रकाश डाला।

जी-20 के विदेश मंत्रियों की बैठक

अर्जेंटीना गणराज्य ने 2018 के लिए जी20 प्रेसीडेंसी का आयोजन किया और 20 और 21 मई 2018 को ब्यूनस आयर्स में जी-20 के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (एमओएस) जनरल (डॉ.) वी. के. सिंह (सेवानिवृत्त) ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद, वैश्विक शासन, निष्पक्ष और सतत विकास, भविष्य का काम, बुनियादी ढांचा विकास और स्थायी भोजन भविष्य जैसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

जी20 शेरपाओं की पहली बैठक 19-20 जनवरी 2019 को टोक्यो में आयोजित किए जाने की संभावना है।

आईबीएसए (भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका)

आईबीएसए के विदेश मंत्रियों की बैठक, प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका

विदेश मंत्री (ईएएम) श्रीमती सुषमा स्वराज ने आईबीएसए के विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक के लिए 04 जून 2018 को प्रिटोरिया में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों से भेंट की। मंत्रियों ने वर्ष के दौरान आईबीएसए

सहयोग को आगे बढ़ाने, विकास सहयोग और दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर विचारों का आदान-प्रदान किया, जिसमें इसके बहुपक्षीय मिशनों के माध्यम से ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन+40 (बीएपीए+40) घटनाएं शामिल थीं। इस अवसर पर, उन्होंने वैश्विक दक्षिण के एक आम प्रयास के रूप में विकास सहयोग की अधिक समझ में योगदान करने के लिए दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर आईबीएसए घोषणा जारी की।

आईबीएसए त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय आयोग की नौवीं बैठक, न्यू यॉर्क

आईबीएसए त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय आयोग की नौवीं बैठक 27 सितंबर 2018 को न्यूयॉर्क शहर में आयोजित की गई। विदेश मंत्री (ईएएम) श्रीमती सुषमा स्वराज ने बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक के दौरान, मंत्रियों ने पिछले एक वर्ष में आईबीएसए सहयोग की समीक्षा की और आईबीएसए सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचारों का आदान-प्रदान किया। मंत्रियों ने शांति, सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला करने, विकास सहयोग और दक्षिण-दक्षिण सहयोग सहित वैश्विक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर विचार विनिमय किया। मंत्रियों ने बीएपीए+40 आयोजनों में दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर समन्वय जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। मंत्रियों ने बहुपक्षीय मंचों पर आईबीएसए सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। मंत्रियों ने आईबीएसए की पंद्रहवीं वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए 2018-19 के लिए नियोजित आईबीएसए आयोजनों पर भी चर्चा की। मंत्रियों ने इन कार्यक्रमों को तीनों देशों के साथ-साथ बहुपक्षीय कार्यक्रमों के हाशिये पर आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की।

पहला गांधी मंडेला स्वतंत्रता भाषण 25 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी)

भारत ने "लिमिटेड सेक्टोरल एंगेजमेंट" की अपनी घोषित नीति के तहत ओईसीडी के साथ जुड़ना जारी रखा।

व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी)

भारत ने यूएनसीटीएडी की विभिन्न बैठकों में अपनी सम्बद्धता जारी रखी।

12

(सार्क) और (बिम्सटेक)

सार्क

विदेश मंत्री (ईएएम) श्रीमती सुषमा स्वराज ने 27 सितंबर 2018 को न्यूयॉर्क में 73वें यूएनजीए सत्र के मौके पर आयोजित सार्क मंत्री परिषद की एक अनौपचारिक बैठक में भाग लिया। 4 मई 2018 को फिलीपींस के मनीला में एडीबी की वार्षिक बैठक के मौके पर सार्क के वित्त मंत्रियों की 12वीं अनौपचारिक बैठक में आर्थिक मामलों के सचिव ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारत ने क्षेत्रीय केंद्र/विशेष निकाय और क्षेत्रीय बैठकों सहित सार्क की अन्य आधिकारिक और तकनीकी स्तर की बैठकों में भाग लिया।

सार्क प्रोग्रामिंग समिति का 55वां सत्र नेपाल की अध्यक्षता में 6 जुलाई 2018 को काठमांडू में आयोजित किया गया था। बैठक में वर्ष 2018 के लिए सार्क सचिवालय के बजट पर चर्चा हुई और इसे अंतिम रूप दिया गया। प्रोग्रामिंग समिति का 56वां सत्र दिसंबर 2018 में काठमांडू में आयोजित किया गया।

भारत अपने पड़ोस में समान विचारधारा वाले देशों के साथ तकनीकी प्रगति के लाभों को साझा करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद और श्रीलंका के दूरसंचार और डिजिटल अवसंरचना मंत्री, श्री हरिन फर्नांडो द्वारा 15 जनवरी 2018 को श्रीलंका में इसके विस्तार के पहले चरण के उद्घाटन के साथ भारत की अपने राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का दक्षिण एशिया के देशों के लिए विस्तार करने की एकतरफा पहल आगे बढ़ी है। भाग लेने वाले अन्य सार्क देशों में विस्तार पर काम चल रहा है।

मई 2017 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका की भागीदारी के साथ दक्षिण एशिया उपग्रह (एसएएस) के लिए कक्षीय आवृत्ति संशोधन समझौते जैसे सभी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद

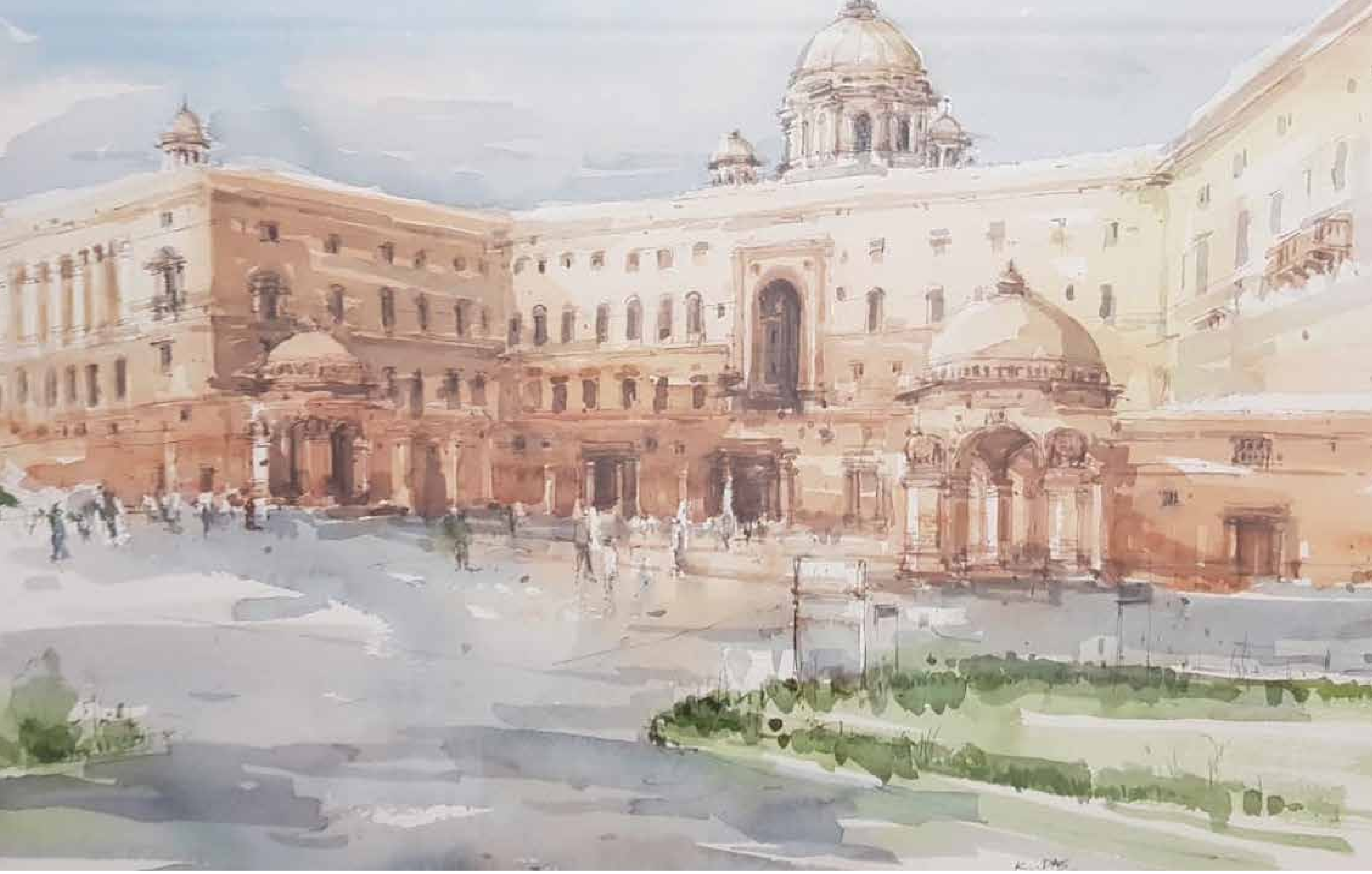

प्रत्येक प्रतिभागी सदस्य राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं पर विचार-विमर्श करने और एसएएस के इष्टतम उपयोग के लिए उपयोग योजनाओं को इष्टतम बनाने के लिए 11 दिसंबर 2018 को नई दिल्ली में एक उपयोगिता कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।

भारत ने, उत्कृष्टता केंद्र के रूप में भारत में स्थापित दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (एसएयू) के लिए अपना समर्थन जारी रखा। एसएयू का तीसरा दीक्षांत समारोह 7 जून 2018 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें 176 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई (इसमें छह पीएचडी छात्रों का पहला बैच शामिल है)। भारत विश्वविद्यालय की पूंजीगत लागत का 100% पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसके स्थायी परिसर का निर्माण चल रहा है।

सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र (आईयू), गांधीनगर को भारत द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया जा रहा है और सार्क सदस्य राज्यों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए बुनियादी ढांचा क्षेत्र, सार्क क्षेत्र में हीट वेव के लिए तैयारी और उसकी प्रतिक्रिया, सार्क क्षेत्र में आपदाओं में कमी और देखभाल, आपदाओं के समय बच्चों की सुरक्षा और भागीदारी जैसे आपदा प्रबंधन क्षेत्रों में कार्यशालाएं/प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है।

बिम्सटेक

बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) भारत की 'पड़ोस सबसे पहले' और 'एक्ट ईस्ट' की प्रमुख विदेश नीति की प्राथमिकताओं को पूरा करता है। काठमांडू में 30 और 31 अगस्त 2018 को आयोजित चौथे बिम्सटेक सम्मेलन में बिम्सटेक को एक महत्वपूर्ण अग्रगति प्राप्त हुई। प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। सम्मेलन ने परिणामोन्मुख तरीके से विभिन्न क्षेत्रों

में क्षेत्रीय सहयोग को तेज करने और बिम्सटेक के संस्थागत तंत्र को मजबूत करने के लिए भविष्य की रूपरेखा प्रदान की। शिखर सम्मेलन में बिम्सटेक ग्रिड इंटरकनेक्शन पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने डिजिटल कनेक्टिविटी, अर्थव्यवस्था और व्यापार, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, समुद्र के पारिस्थिक तंत्र को सुरक्षित रखते हुए बेहतर आजीविक, रोजगार और आर्थिक विकास के लिए महासागरीय संसाधनों के निरंतर उपयोग, कृषि और स्वास्थ्य के साथ-साथ सांस्कृतिक और युवा संपर्कों को बढ़ावा देने के लिए विविध क्षेत्रों में बिम्सटेक सहयोग और क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए कई पहलों की घोषणा की।

शिखर सम्मेलन को भारत द्वारा अक्टूबर 2016 में गोवा में आयोजित बिम्सटेक आउटरीच शिखर सम्मेलन की बुनियाद पर आगे बढ़ाया गया था। मार्च 2018 में ढाका में बिम्सटेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की दूसरी बैठक के आयोजन के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को प्रोत्साहन मिला। भारत ने क्षेत्रीय संपर्क और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बिम्सटेक समझौतों और समझौता ज्ञापनों पर चर्चा करने के लिए संयुक्त कार्य समूह की बैठकें आयोजित कीं।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 27 सितंबर 2018 को न्यूयॉर्क में 73वें यूएनजीए सत्र के मौके पर आयोजित सार्क मंत्री परिषद की एक अनौपचारिक बैठक में भाग लिया। भारत ने शांति और सुरक्षा के वातावरण की आवश्यकता और सार्थक क्षेत्रीय सहयोग के लिए विभिन्न सार्क मंचों पर की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने पर जोर दिया। भारत ने क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए अपनी आर्थिक और तकनीकी प्रगति के लाभों को अपने पड़ोस के साथ साझा करना जारी रखा। 15 जनवरी 2018 को श्रीलंका में भारत के राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के दक्षिण एशियाई देशों के लिए विस्तार की परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया गया। दक्षिण एशिया उपग्रह के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए 11 दिसंबर 2018 को नई दिल्ली में सभी भागीदार देशों को शामिल कर एक कार्यशाला आयोजित की जा रही है। नई दिल्ली में दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के नए परिसर का निर्माण भी प्रगति पर है, जिसका व्यय पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

विदेश मंत्रियों की 16वीं बैठक (29 अगस्त, 2018) और वरिष्ठ अधिकारियों की 19वीं बैठक (28 अगस्त, 2018) से पहले चौथा बिम्सटेक शिखर सम्मेलन, 30 और 31 अगस्त 2018 को काठमांडू में आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन में बिम्सटेक के सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों और शासनाध्यक्षों ने भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया और इसमें राज्य मंत्री (एमओएस) जनरल (डॉ.) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त), विदेश सचिव और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। शिखर सम्मेलन का विषय था “एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और टिकाऊ बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की ओर”। शिखर सम्मेलन में अपनाई गई काठमांडू घोषणा सुरक्षा और आतंकवाद, आपदा प्रबंधन, संपर्क

बिम्स्टेक सम्मेलन के हस्ताक्षर समारोह में प्रधानमंत्री (31 अगस्त, 2018)

और व्यापार, ऊर्जा, कृषि और गरीबी उन्मूलन, विज्ञान और तकनीक, संस्कृति, पर्यटन और लोगों के आपसी संपर्क के प्रमुख क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग को तेज करने का प्रयास करती है। चौथे शिखर सम्मेलन में बिम्सटेक के संस्थागत और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने, संगठन के चार्टर के प्रारूपण के लिए निर्देश प्रदान कर, सचिवालय को मजबूत करने और बिम्सटेक स्थायी कार्य समिति का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिखर सम्मेलन ने बिम्सटेक गृह मंत्रियों की बैठक का एक तंत्र स्थापित कर आतंकवाद-रोधी और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया। शिखर सम्मेलन में बिम्सटेक ग्रिड इंटरकनेक्शन पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

शिखर सम्मेलन से पहले, शिखर सम्मेलन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए 11 अगस्त 2018 को काठमांडू में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (एसओएम) का एक विशेष सत्र आयोजित किया गया था। स्थायी बिम्सटेक सचिवालय की स्थापना और सचिवालय के प्रशासनिक और संस्थागत मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए संयुक्त कार्य समूह की आठवीं बैठक 10 जुलाई 2018 को कोलंबो में आयोजित की गई थी।

ढाका में 21 मार्च 2018 को आयोजित बिम्सटेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की दूसरी बैठक ने आतंकवाद-रोधी और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के महत्वपूर्ण क्षेत्र में बिम्सटेक के अंतर्गत सहयोग को आगे बढ़ाया। बैठक में इस क्षेत्र और इस क्षेत्र में छह उप-समूहों में अब तक हुई प्रगति पर विचार किया गया। आतंकवाद-रोधी और अंतर्राष्ट्रीय अपराध पर बिम्सटेक संयुक्त कार्य दल की 8वीं बैठक 13-14 अगस्त 2018 को बांग्लादेश के ढाका में आयोजित की गई थी। धन शोधन प्रतिरोध और के वित्तपोषण का मुकाबला बिम्सटेक उप-समूह आतंकवाद (एसजीएएमएलL-सीएफटी) की 10वीं बैठक 19-20 नवंबर 2018 पर काठमांडू, नेपाल में आयोजित की गई थी। भारत ने 5-7 दिसंबर 2018 से आईडीएसए, नई दिल्ली में बिम्सटेक क्षेत्रीय साइबर सुरक्षा संवाद का आयोजन किया।

प्रथम बिम्सटेक सैन्य अभ्यास (बिम्सटेक मिलएक्स-2018) आतंकवाद विरोध के विषय पर 10-16 सितंबर 2018 से पुणे में आयोजित किया गया। मिलएक्स के समय बिम्सटेक सेना प्रमुखों की एक सभा भी आयोजित की गई। समापन समारोह में बिम्सटेक के महासचिव, राजदूत एम शाहिदुल इस्लाम ने भी भाग लिया।

बिम्सटेक के अंतर्गत कनेक्टिविटी पर नए सिरे से ध्यान देने की बात को ध्यान में रख कर भारत ने कार्यसूची को आगे बढ़ाने विशेष रूप से परिवहन और कनेक्टिविटी और व्यापार सुविधा लिए कई पहलों का प्रस्ताव किया, जिसमें पारगमन, परिवहन सहयोग और वाहनों के आवागमन पर बिम्सटेक समझौते की रूपरेखा पर विचार करने के लिए कार्य समूह की पहली बैठक (9-10 अप्रैल 2018) आयोजित करना और सीमा शुल्क पर बिम्सटेक समझौते पर विचार करने के लिए कार्य समूह की पहली बैठक (10-11 मई 2018) शामिल है। बिम्सटेक परिवहन कनेक्टिविटी योजना में तेजी लाने के उद्देश्य से, दूसरे मसौदे पर चर्चा करने और परिवहन कनेक्टिविटी पर बिम्सटेक की मुख्य योजना के अंतिम मसौदे की तैयारी के लिए इनपुट प्रदान करने के लिए 7-18 सितंबर 2018 को बैंकॉक में एक कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए बिम्सटेक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी वर्किंग ग्रुप (बीटीसीडब्ल्यूजी) की तीसरी बैठक 2019 के आरंभ में नई दिल्ली में आयोजित होने वाली है, जो सभी सदस्य राज्यों द्वारा आंतरिक प्रक्रियाओं के पूरा होने पर निर्भर है। डिजिटल कनेक्टिविटी और आईसीटी अनुप्रयोगों के क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए, 25-27 अक्टूबर 2018 को 'न्यू डिजिटल होराइजंस कनेक्ट, क्रिएट, इनोवेट' विषय पर भारतीय मोबाइल कांग्रेस आयोजित की गई थी, जिसका लक्ष्य नवीन विचारों पर निर्माण करना, स्थायी उद्योग संबंध बनाना है, इसी अवसर पर बिम्सटेक मंत्रीस्तरीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, जिसमें बिम्सटेक देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी स्तर के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया था।

बिम्सटेक व्यापार वार्ता समिति (टीएनसी) की 21वीं बैठक और संबंधित कार्यदल की बैठकें 18-19 नवंबर, 2018 को ढाका, बांग्लादेश में आयोजित की गईं। बिम्सटेक मुक्त व्यापार क्षेत्र पर संरचनात्मक समझौते के घटक समझौतों और चर्चा को अंतिम रूप देने के लिए सदस्य देशों के बीच समझ बनाने में यह बैठक महत्वपूर्ण रही।

इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करने में सहयोग को गहरा करने के लिए, भारत द्वारा 30-31 जुलाई 2018 को नोएडा में बिम्सटेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की पहली गवर्निंग बोर्ड मीटिंग भी आयोजित की गई।

सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने और क्षेत्र में क्षमता निर्माण की दृष्टि से, भारत ने 26-30 मार्च 2018 से बिम्सटेक के सदस्य देशों के चुनाव अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। संविधान दिवस मनाने के लिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने बिम्सटेक के सदस्य राज्यों से न्यायपालिका के प्रमुखों को आमंत्रित किया, जिन्होंने 25 नवंबर 2018 को आयोजित बिम्सटेक देशों की न्यायपालिका के प्रमुखों की पहली गोल मेज बैठक में भाग लिया और नई दिल्ली में 26 नवंबर 2018 को संविधान दिवस समारोह मनाया।

बिम्सटेक की 20वीं वर्षगांठ का उत्सव मनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे, जिसमें चिंतकों, शिक्षा और व्यापार समुदाय की भागीदारी के साथ लोगों के आपसी संपर्क को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। 13-14 नवंबर 2018 को नई दिल्ली में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा 'क्षत्रीय सुरक्षा पर बिम्सटेक चिंतकों' का संवाद आयोजित किया गया था। बिम्सटेक की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए:

- इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा 23-24 अप्रैल 2018 को सिक्किम के गंगटोक में "इंटीग्रेटिंग बिम्सटेक - 2018" नामक सम्मेलन आयोजित किया गया था।
- बिम्सटेक सचिवालय द्वारा 20 मार्च, 2018 को ढाका में "अपने 20 पर बिम्सटेक: एक बंगाल की खाड़ी समुदाय की ओर" नामक सम्मेलन का आयोजन किया गया।
- नई दिल्ली (अप्रैल 2018), यंगून (जून 2018) और कोलंबो (अगस्त 2018) में दिल्ली नीति समूह द्वारा एडवांसिंग बिम्सटेक सहयोग नामक एक सम्मेलन आयोजित किया गया था।
- फिक्की ने एक सम्मेलन आयोजित किया और नई दिल्ली में 26 अप्रैल 2018 को 'बिम्सटेक को पुनर्जीवित करना: अगले दशक के लिए उद्योग का एक दृष्टिकोण' पर एक ज्ञान पत्र जारी किया।

काठमांडू में 30 और 31 अगस्त 2018 को आयोजित चौथे शिखर सम्मेलन के अंत में श्रीलंका बिम्सटेक का अध्यक्ष बना है अतः बिम्सटेक स्थायी कार्य समिति (बीपीडब्ल्यूसी) की पहली बैठक 17-18 जनवरी 2019 को कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित होने वाली है। बिम्सटेक नेताओं के निर्देश पर चौथे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में बिम्सटेक नेशनल फोकल पॉइंट्स से युक्त बीपीडब्ल्यूसी गठित की गई है और यह बिम्सटेक ढांचे के अंतर्गत प्रमुख समन्वयक निकाय है, जो बिम्सटेक के अंतर्गत संस्थागत प्रक्रियाओं/तंत्र के साथ काम करेगी और वित्तीय तथा प्रशासनिक मामलों सहित सभी गतिविधियों का समन्वय करती है। बीपीडब्ल्यूसी, बिम्सटेक के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के विचार के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

आतंकवाद प्रतिरोध और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को गहरा करने के लिए भारत द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में 18 फरवरी -1 मार्च 2019 तक बिम्सटेक देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों के लिए आतंकवाद प्रतिरोध, साइबर आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध प्रतिरोध पर एक पाठ्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्रीय क्षमता का निर्माण करना और आतंकवाद, अंतरराष्ट्रीय अपराध, धन शोधन, साइबर हमलों की चुनौतियों से निपटने के लिए क्षेत्रीय कार्यप्रणाली पर चर्चा करना है।

13

विकास सहयोग

विकास भागीदारी प्रशासन (डीपीए)

विकास साझेदारी भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख साधन है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के विकास सहायता के क्षेत्र और पहुंच में काफी विस्तार हुआ है। भारत के स्थायी भू-राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक हितों और भारत के सहायता कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से वितरित करने की आवश्यकता ने विकासशील देशों के साथ, विशेष रूप से विकास सहायता के मोर्चे पर अधिक से अधिक जुड़ाव उत्पन्न किया है। इसकी मान्यता में, भारत की विकास सहायता परियोजनाओं को अवधारणा, आरंभ, निष्पादन और पूर्णता के चरणों के माध्यम से प्रभावी ढंग से संभालने के लिए विकास साझेदारी प्रशासन (डीपीए) बनाया गया था। डीपीए मंत्रालय में प्रादेशिक प्रभागों के साथ निकट समन्वय में कार्य करता है, जो उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं की पहचान करने में भागीदार देशों के साथ प्रमुख वार्ताकार बने रहते हैं। डीपीए विभिन्न क्षेत्रों और प्रदेशो में परियोजना मूल्यांकन, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के चरणों के माध्यम से परियोजनाओं को संभालने के लिए उत्तरोत्तर आवश्यक विशेषज्ञता विकसित कर रहा है।

भारत की विकास साझेदारी भागीदार देशों की जरूरतों पर आधारित है और इन देशों से प्राप्त तकनीकी और वित्तीय रूप से व्यवहार्य कई अनुरोधों का उत्तर देने के लिए तैयार है। भारत की विकास सहायता के मुख्य साधनों में लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी), अनुदान सहायता, लघु विकास परियोजनाएं (एसडीपी), तकनीकी परामर्श, आपदा राहत और मानवीय सहायता, साथ ही भारतीय तकनीकी और नागरिक प्रशिक्षण के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम शामिल हैं। विकास सहायता में भारत के पड़ोस और अफ्रीका के देशों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, हालांकि भारत दक्षिण-पूर्व एशिया, कैरिबियन,

लैटिन अमेरिका, मंगोलिया, प्रशांत द्वीप देशों आदि में भी अपनी विकास सहायता का विस्तार कर रहा है।

विकास साझेदारी प्रशासन कार्यात्मक रूप से तीन स्तंभों में विभाजित है जो तीन अलग-अलग प्रभागों के अनुरूप हैं। डीपीए-I, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस) के अंतर्गत ऋण परियोजनाओं की लाइनों की देखभाल करता है। व्यापार आवंटन नियमों के अंतर्गत बांग्लादेश, नेपाल और भूटान विदेश मंत्रालय के दायरे में हैं। डीपीए-I इन देशों से संबंधित एलओसी के तरीकों को भी संभालता है। डीपीए-II एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सहकारी और आर्थिक सामाजिक विकास के लिए भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग की कोलंबो योजना (आईटीईसी) कार्यक्रम के अंतर्गत रक्षा कर्मियों और नागरिक प्रशिक्षण द्वारा क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पर केंद्रित है। भागीदार देशों के अनुरोध के आधार पर विभिन्न विषयों में अनुकूलित पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं। इसके अलावा, यह मानवीय सहायता भी प्रदान करता है। डीपीए-III का कार्य भारत सरकार के पड़ोस में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, मॉरीशस, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका में अनुदान सहायता परियोजनाओं के कार्यान्वयन को संभालने के लिए भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों और एजेंसियों के परामर्श करना है।

पड़ोसी देशों में विकास परियोजनाएं

हाल में, भारत के विकास सहायता के दायरे और पहुंच में और विस्तार हुआ है। तत्काल पड़ोस, दक्षिण-पूर्व एशिया और अफ्रीका भारत की विकास सहायता का पारंपरिक और मजबूत केंद्र रहे है। भारत के तत्काल और विस्तारित पड़ोस के देशों के साथ विकास सहयोग भारत की 'पड़ोस सबसे पहले' और 'एक्ट ईस्ट' नीति को पुष्ट करता है। यह इन देशों

के साथ घनिष्ठ और बहुआयामी संबंधों के आयाम को बढ़ता है। अफ्रीकी देश लंबे समय से विकास साझेदार हैं जो भारत के इन देशों के साथ संयुक्त रूप से की जाने वाली विकास परियोजनाओं की समृद्ध सूची में परिलक्षित है। इसके अलावा, कैरेबियाई, लैटिन अमेरिका, पूर्वी एशिया, मध्य एशिया और प्रशांत द्वीप देशों में सहयोगी देशों के साथ भी भारत के विकास सहयोग कार्यक्रम मजबूत और विस्तारित हैं।

भारत की विकास परियोजनाओं को अनुदान सहायता के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसमें सड़कों और पुलों, जलमार्गों, पारेषण लाइनों, बिजली उत्पादन और जलविद्युत क्षमता से लेकर क्षमता निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, और सामुदायिक विकास जैसे बड़े बुनियादी ढांचे के निर्माण तक कई तरह के क्षेत्र शामिल हैं।

भारत ने सितंबर 2017 में अफगानिस्तान के साथ एक 'नई विकास भागीदारी' की है और दोनों देशों के बीच करीब विकास सहयोग को समेकित किया गया है। भारत मुश्किल सुरक्षा वातावरण के बावजूद अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और राष्ट्रीय विकास में एक स्थायी भागीदार रहा है। अफगानिस्तान को विकास सहायता संस्था और क्षमता निर्माण और परिसंपत्तियों के निर्माण पर केंद्रित है जो आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में अफगान लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई प्रमुख ऐतिहासिक परियोजनाएं पूरी हुई हैं, जिनमें दिसंबर 2015 में काबुल में नए संसद भवन और जून 2016 में अफगान-भारत मैत्री बांध (जिसे पहले सलमा बांध के रूप में जाना जाता था) का निर्माण शामिल है।

भारत ने अफगानिस्तान की मानवीय जरूरतों के लिए भी तेजी से प्रतिक्रिया की है। भारत ने अफगानिस्तान में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए, अक्टूबर 2017 और अप्रैल 2018 के बीच चाबहार बंदरगाह के माध्यम से कई खेपों में 1.7 लाख टन गेहूं की आपूर्ति की। इसके अलावा, चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान को 2000 टन चना दाल (दलहन) की भी आपूर्ति की गई थी।

भारत सरकार (जीओआई) द्वारा वित्तपोषित सैकड़ों उच्च प्रभावी सामुदायिक विकास परियोजनाएं (एचआईसीडीपी) पूरे अफगानिस्तान में चल रही हैं, जो खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, पेयजल, नवीकरणीय ऊर्जा, बाढ़ नियंत्रण, माइक्रो-हाइड्रो पावर और खेल के क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर पहचानी हुई जरूरतों को पूरा करती है।

क्षमता निर्माण के अंतर्गत, भारत 2018 से अफगानों के लिए वार्षिक औसतन 1200 स्लॉटों के साथ एक बहुत बड़ा छात्रवृत्ति कार्यक्रम चलाता है, जिसमें अफगान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बलों (एएनडीएसएफ) के शहीदों के बच्चों/आश्रितों के लिए समर्पित छात्रवृत्तियां शामिल है। भारत द्वारा भारत के प्रमुख कृषि संस्थान, भारत कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ आपसी साझेदारी के माध्यम से कंधार में स्थापित अफगानिस्तान कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एएनएएसटीयू) को भी सक्रिय समर्थन प्रदान किया जा रहा है ।

म्यांमार के साथ, कनेक्टिविटी बढ़ाने, आर्थिक विकास और विकास को गति देने के उद्देश्य से सीमा पार परियोजनाओं के कार्यान्वयन सहित विकास सहयोग में निरंतर गति बनी हुई है। इन परियोजनाओं में भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच त्रिपक्षीय राजमार्ग के निर्माण शामिल हैं, जिसके अंतर्गत भारत तामू - कायगोन - कालिवा खंड में अड़सठ पुलों का निर्माण और कालवा-यार्गी खंड में 120 किलोमीटर सड़क के उन्नयन का कार्य कर रहा है। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना एक अन्य बड़ी कनेक्टिविटी पहल है जो भारत के पूर्वी सीबोर्ड और म्यांमार के सिटवे बंदरगाह पर बंदरगाहों को जोड़ेगी, और उसके बाद मिजोरम में भारत-म्यांमार सीमा पर जाएगी। बंदरगाहों और अंतर्देशीय जल टर्मिनलों के मूल जलमार्ग घटक को पूरा कर लिया गया है और शेष सड़क बुनियादी ढांचे का निष्पादन चल रहा है।

कनेक्टिविटी के अलावा, भारत म्यांमार में सहायक क्षमता निर्माण में लगा हुआ है जिसमें आईटी, कृषि और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रमुख पहलों में मांडले में म्यांमार इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (एमआईआईटी) की स्थापना, नाय पेई ताव में एक उन्नत कृषि अनुसंधान और शिक्षा केंद्र (एसीएआरई) और हाल ही में नाय पेई ताव में राइस बायो-पार्क की स्थापना शामिल है। ये परियोजनाएं जनसंख्या को कम करने, उपज और उत्पादकता बढ़ाने और आजीविका के अवसरों में सुधार करने में मदद करती हैं। यांगून चिल्ड्रन हॉस्पिटल और सिटवे जनरल अस्पताल में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति और कमीशनिंग भी पूरी की गई है।

नेपाल के साथ, भारत की दीर्घकालिक विकास साझेदारी ने गति पकड़ ली है और कई महत्वपूर्ण संयुक्त विकास पहलें पूरी हो गई हैं। अप्रैल 2018 में नेपाल के बीरगंज में सीमा

पार एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) का उद्‌घाटन किया जाएगा जो आर्थिक और लोगों के लाभांश को पूरा करेगा। इसी प्रकार, भारत द्वारा नेपाल के बिराटनगर में आईसीपी का विकास चल रहा है। भारत नेपाल में सीमा पार नेपालगंज और भैरहवा में भी आईसीपी विकसित करेगा। भारत ने अगस्त 2018 में, काठमांडू में नेपाल-भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला का निर्माण पूरा कर लिया है, जिसमें दोनों देशों को जोड़ने वाले सांस्कृतिक संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। भारत में जयनगर से नेपाल में जनकपुर और कुर्था और भारत में जोगबनी से नेपाल में नेपाल सीमा शुल्क यार्ड तक दो सीमा-पार रेल लाइनें दिसंबर 2018 में पूरी हो चुकी हैं। नेपाल में इन लिंकों के शेष हिस्सों पर भी काम किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

श्रीलंका में, लोगों और श्रीलंका सरकार की प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए भारत की विकास परियोजनाओं को वहाँ की सरकार के साथ घनिष्ठ परामर्श के आधार पर आरंभ किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने डिकोया में अस्पताल का निर्माण और मन्नार में थिरुकेथीश्वरम मंदिर का जीर्णोद्धार पूरा कर लिया है। भारत, अन्य परियोजनाओं में, वर्तमान में जाफना में एक अत्याधुनिक सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण में सहायता कर रहा है।

मालदीव में, संयुक्त विकास परियोजनाएं निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। माफ़िलाफ़ुशी द्वीप में समग्र प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना अगस्त 2015 में पूरी हुई। इसी तरह, माले में इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल का नवीनीकरण जून 2017 में पूरा हुआ। भारत वर्तमान में इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट स्टडीज (आईएसएलईएस) के निर्माण में सहायता कर रहा है। निकट भविष्य में और अधिक परियोजनाएं शुरू होने की आशा है।

मॉरीशस में, भारत का विकास कार्य बहुत सक्रिय दौर में है। भारत अपनी प्रमुख राष्ट्रीय परियोजनाओं के निष्पादन में मॉरीशस को वित्तीय और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान कर रहा है। ऐसी परियोजनाओं में पहली बार हल्की रेल पारगमन मेट्रो एक्सप्रेस लिंक शामिल की गई है, इसके सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को परिवर्तित करने की अपेक्षा है, मॉरीशस की न्यायपालिका के लिए एक नया सर्वोच्च न्यायालय भवन, लगभग 1000 इकाइयों की कम आय वाली आवास परियोजना, एक विशेष ईएनटी अस्पताल परियोजना के साथ-साथ अर्ली डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत 26,800 प्राथमिक विद्यालय के छात्रों और उनके शिक्षकों को शिक्षा के लिए टेबलेट प्रदान किया गया है। इसकी सफलता पर, कार्यक्रम को अन्य ग्रेडों तक भी बढ़ाया जा रहा है।

लाइन ऑफ क्रेडिट

भारत की विदेश नीति में विकास साझेदारी एक महत्वपूर्ण उपकरण है। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में रियायती शर्तों पर लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी) का विस्तार भारत की विकास सहयोग नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। वर्ष 2005-06 से, साठ से अधिक देशों में विभिन्न क्षेत्रों में कुल 26.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर की 269 एलओसी का विस्तार किया गया है, जिनमें से 11.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर अफ्रीकी देशों के लिए और 14.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर एशियाई देशों के लिए आवंटित किए गए हैं, शेष 0.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर लैटिन अमेरिका, ओशिनिया और स्वतंत्र राज्यों (सीआईएस) देशों के राष्ट्रमंडल के लिए हैं। मुख्य रूप से द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, एलओसी लेने वाले देशों को भारत से वस्तुओं और सेवाओं को आयात करने में सक्षम बनाती है और उनकी विकास संबंधी प्राथमिकताओं के अनुसार बुनियादी ढाँचे के विकास और क्षमता निर्माण के लिए परियोजनाएँ शुरू की जाती हैं। इस प्रक्रिया में, यह भारतीय कंपनियों और व्यापार उद्यमों को नए बाजारों का दोहन करने में मदद करती है और भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देती है।

एलओसी 7 दिसंबर 2015 को भारत सरकार द्वारा संशोधित और जारी किए गए आईडीईएएस दिशानिर्देशों द्वारा शासित होते हैं। एलओसी कार्यान्वयन प्रक्रिया में सुधार के कई क्षेत्रों को अनिवार्य विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआरएस), पूर्व-योग्यता (पीक्यू) सहित परामर्शदाताओं और ठेकेदारों के चयन की प्रक्रिया, एक विस्तृत निगरानी तंत्र के संस्थानीकरण और कार्यान्वयन तथा भारतीय परामर्श फर्मों और ईपीसी के ठेकेदारों के साथ पेश किया गया है। एक्ज़िम बैंक ने विभिन्न क्षेत्रों में 111 परामर्श फर्मों का काम पूरा कर लिया है। कुल 109 फर्मों को ईपीसी ठेकेदारों के रूप में रखा गया है। उल्लेख किया जा सकता है कि यह एक सतत प्रक्रिया

है जिसके माध्यम से कंपनियां पंजीकृत हो रही हैं। अप्रैल से नवंबर 2018 के बीच, 1.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल मूल्य के साथ ग्यारह एलओसी को अनुमोदित किया गया है। 2018-19 (अप्रैल से नवंबर 2018) में 101.13 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल नौ परियोजनाएं पूरी हुई हैं।

नई क्रेडिट लाइनें

वर्तमान वर्ष (अप्रैल 2018-जनवरी 2019) में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित नई एलओसी का विस्तार किया गया है:

- गितेगा में नई संसद और बुजुंबुरा और बुरुंडी में दो मंत्री भवनों के निर्माण के लिए बुरुंडी सरकार को 161.36 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एलओसी दी गई।
- मेकेले इंडस्ट्रियल पार्क 400 केवी पॉवर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए इथियोपिया सरकार को 147.43 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एलओसी दी गई।
- इथियोपिया और जिबूती के बीच एक नये 230 केवी इंटरकनेक्शन, 230 केवी कॉम्बोलेचा II - सेमेरा, नागद और कॉम्बोल्चा II में संबद्ध सबस्टेशन एक्सटेंशन के साथ सेमरा ट्रांसमिशन लाइन के लिए इथियोपिया की सरकार को 133.70 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एलओसी दी गई।
- रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए मॉरीशस सरकार को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एलओसी दी गई।
- दो विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास और किगाली विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के विस्तार के लिए रवांडा सरकार को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एलओसी दी गई।
- तीन कृषि परियोजना स्कीमों अर्थात् (i) वारुफ़ु बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, (ii) मुगीसेरा सिंचाई परियोजना, और (iii) न्यामुकाना सिंचाई परियोजना के लिए रवांडा सरकार को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एलओसी दी गई।
- कृषि और डेयरी क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए युगांडा सरकार को 64.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एलओसी दी गई।
- ग्रिड सुदृढीकरण और विस्तार परियोजना के लिए युगांडा सरकार को 141.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एलओसी दी गई।
- जिम्बाब्वे में डेका पंपिंग स्टेशन और नदी जन इनटेक प्रणाली के दूसरे चरण के उन्नयन के लिए जिम्बाब्वे सरकार को 19.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एलओसी दी गई।
- बुलावायो ताप विद्युत संयंत्र के उन्नयन के लिए जिम्बाब्वे सरकार को 23 मीलियन अमेरिकी डॉलर की एलओसी दी गई।
- मोजाम्बिक में 1600 छोटी जल प्रणालियों के साथ हैंड-पंपों और 1600 बोरवेलों के निर्माण के लिए मोजाम्बिक सरकार को 38 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एलओसी दी गई।
- लोकोमोटिव, कोच और वैगनों सहित रेलवे रोलिंग स्टॉक की खरीद के लिए मोज़ाम्बिक सरकार को 95 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एलओसी दी गई।
- करावा, प्रांत- उत्तर उबांगी में पंद्रह मेगावाट सौर फोटो-वोल्टेइक बिजली परियोजना के वित्तपोषण के लिए कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की कांगो सरकार को 33.29 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एलओसी दी गई।
- लुसांबो, प्रांत-सांकुरु में दस मेगावाट सौर फोटो-वोल्टेइक बिजली परियोजना के वित्तपोषण के लिए कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की सरकार को 25.27 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एलओसी दी गई।
- मबंडाका, प्रांत - इक्वेटोर में दस मेगावाट सौर फोटो-वोल्टेइक बिजली परियोजना के वित्तपोषण के लिए कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो सरकार को 33.29 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एलओसी दी गई।
- आवास एवं सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए उज़्बेकिस्तान सरकार को 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एलओसी दी गई।

पूरी हो चुकी एलओसी परियोजनाएं

- राजमार्ग, हवाई अड्डों, पुलों और सिंचाई परियोजनाओं जैसी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 2010-11 में 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एलओसी दी गई थी। इस एलओसी के अंतर्गत कुल तेईस परियोजनाओं को शामिल किया गया है, जिसमें उन्नीस सड़क परियोजनाएं, तीन ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाएं और एक पनबिजली परियोजना शामिल हैं। उन्नीस सड़क परियोजनाओं में से तीन हाल ही में पूरी हुई हैं। ये निम्नलिखित हैं:

(i) सनफेबर-मार्ताडी सड़क का बरजुगढ़-मार्ताडी खंड (27.70 किमी)

(ii) बरदाघाट-पलडांडा-त्रिवेणी सड़क खंड (12.5 किमी)

(iii) भरतपुर-रामपुर-मेघौली मार्ग का भरतपुर-चनौली खंड (16 किमी)

- ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए बुर्किना फासो को 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एलओसी
- बुर्किना फासो को ईबीआईडी एलओसी के अंतर्गत 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बसों की आपूर्ति
- नाइजर में 34.54 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एलओसी के अंतर्गत 30 गाँवों में सौर विद्युतीकरण और 7 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली
- अर्ध-शहरी और ग्रामीण समुदायों के लिए पीने योग्य पानी के लिए नाइजर को 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एलओसी
- म्यांमार में रिह-मिडैट दूरसंचार नेटवर्क परियोजना के लिए 6.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एलओसी
- टोगो को 13.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एलओसी के अंतर्गत कृषि उपकरण और इनपुट की आपूर्ति।

नई एलओसी परियोजनाओं का उद्घाटन/आरंभ

भारत के गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मंगोलिया के प्रधान मंत्री श्री उखनागिन खुरेलसुख के साथ 21 जून 2018 को भारत सरकार की 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एलओसी के अंतर्गत मंगोलिया में पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी प्रोजेक्ट के शिलान्यास समारोह में भाग लिया।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर 2018 को संयुक्त रूप से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के साथ भारत सरकार की 862 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एलओसी के अंतर्गत पुनरुद्धार किए गए बांग्लादेश रेलवे के कुलौरा-शहबाज़पुर सेक्शन का उद्घाटन किया।

भारत सरकार की 862 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एलओसी के अंतर्गत बांग्लादेश रेलवे परियोजना पर सिग्नलिंग कार्यो सहित, ढाका-टोंगी खंड के बीच 3 जी और 4 जी दोहरे गेज ट्रैक का निर्माण और टोंगी-जयदेवपुर खंड के बीच दोहरे गेज ट्रैक का दोहरीकरण का 18 सितंबर 2018 को प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधान मंत्री सुश्री शेख हसीना द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया।

नेपाल के प्रधान मंत्री, श्री केपी शर्मा ओली ने 4 जनवरी, 2019 को प्रांत-1 के पंचथर जिले के रबीबाजार में भदेतर-रबी-रांके सड़क की आधारशिला रखी। परियोजना की कुल लंबाई 100.367 किमी और कुल लागत 32.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसे नेपाल को 550 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एलओसी के अंतर्गत बनाया जा रहा है। यह सड़क कोसी राजमार्ग पर धनकुटा जिले में भदेतर शहर को नौ मीटर चौड़ी मोटर योग्य सड़क के साथ इलाम और पंचथर जिले से जोड़ेगी।

सभी देशों के साथ रोटेशन के आधार पर चल रही निगरानी के अंतर्गत, एलओसी परियोजनाओं की द्विपक्षीय समीक्षा की गई। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में चल रही परियोजनाओं की प्रगति की स्थिति रिपोर्ट भारतीय मिशनों और एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया से भी प्राप्त हुई थी।

अन्य परियोजनाएं जिनके 2018-19 में पूरा होने की संभावना है:

बांग्लादेश सड़क परिवहन निगम (बीआरटीसी) के लिए 500 ट्रकों और 600 बसों की खरीद की परियोजना: दिसंबर 2018 में 16.2 टन ट्रकों का पहला बैच भेजा गया है और जनवरी 2019 में सिंगल डेकर नॉन एसी बसों का पहला बैच भेजा जा रहा है। पूरी परियोजना को मार्च-अप्रैल 2019 तक समय से पहले पूरा कर लेने की आशा है।

श्रीलंका को बीस कंटेनर कैरियर वैगन और तीस ईंधन टैंक वैगनो की आपूर्ति की परियोजना: फरवरी 2019 में दस कंटेनर कैरियर वैगनों और पांच ईंधन टैंक वैगनों से युक्त पहली खेप भेजे जाने की आशा है।

श्रीलंका को छह डीएमयू और दस इंजनों की आपूर्ति की परियोजना: पहल डीएमयू और लोकोमोटिव (प्रोटोटाइप) दिसंबर 2018 में श्रीलंका रेलवे को राइट्स लिमिटेड द्वारा निर्धारित समय से पहले दिया गया। जनवरी 2019 में ट्रायल रन शुरू होने हैं। दो डीएमयू और दो इंजनों का अगला सेट मार्च-अप्रैल 2019 के आसपास वितरित किए जाने की उम्मीद है।

अन्य एलओसी पहलें:

भारत सरकार द्वारा एक एलओसी परियोजना की मंजूरी की अभूतपूर्व गति: भारत सरकार को मोज़ाम्बिक सरकार से 12 दिसंबर 2018 को रेलवे परियोजना के लिए 95 मिलियन अमरीकी डॉलर की एलओसी का एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। मोजाम्बिक के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऋण के लिए कोटा सीमा के कारण, एलओसी को मंजूरी देनी पड़ी और 31 दिसंबर 2018 तक एलओसी समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ा। तत्काल कदम उठाते हुए और विदेश मंत्रालय (एमईए) और वित्त मंत्रालय के साथ-साथ एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी विस्तृत मंजूरी प्रक्रिया पर तेजी से अमल करते हुए, एलओसी को 27 दिसंबर 2018 को मंजूरी दी गई और 31 दिसंबर 2018 को एक्जिम बैंक और मोजाम्बिक सरकार के बीच एलओसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसलिए, आमतौर पर कुछ महीनों में होने वाली प्रक्रिया को दो सप्ताह के भीतर पूरा किया गया। यह एलओसी कार्यक्रम की स्थापना के बाद से सबसे तेजी से हुई एलओसी मंजूरी और हस्ताक्षर प्रक्रिया है।

14वीं भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय समीक्षा बैठक: बैठक नई दिल्ली में 12 और 13 दिसंबर 2018 को आयोजित की गई थी। रेलवे, बंदरगाह, सड़क, बिजली और ट्रांसमिशन लाइन, शिपिंग, अस्पतालों आदि विभिन्न क्षेत्रों में फैली सैंतालीस परियोजनाओं के लिए भारत सरकार ने बांग्लादेश को 7.862 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एलओसी दी है। इस बैठक से दोनों पक्षों को महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने, परियोजना के कार्यान्वयन में संभावित बाधाओं की पहचान करने और लंबित मुद्दों को हल करने में मदद मिली।

भारत सरकार की लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत सौर परियोजनाओं के लिए व्यापार आउटरीच कार्यक्रम: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) और एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से विदेश मंत्रालय ने 7 अगस्त 2018 को भारत में सौर ऊर्जा क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों को भारत सरकार द्वारा एलओसी के अंतर्गत उपलब्ध व्यापार के अवसरों के बारे में अवगत कराने के लिए एक व्यापार आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया। विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) वी.के.सिंह (सेवानिवृत्त) कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और उन्होंने मुख्य भाषण दिया था।

चल रही एलओसी परियोजनाओं की निगरानी के अंतर्गत, रोटेशन के आधार पर कई देशों के साथ द्विपक्षीय समीक्षा की गई। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में चल रही परियोजनाओं की प्रगति की स्थिति रिपोर्ट भारतीय मिशनों और एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया से भी प्राप्त हुई थी।

परियोजना तैयार करने की सुविधा (पीपीएफ)

भारत सरकार द्वारा नि:शुल्क भारतीय परामर्श सहायता प्रदान करने के लिए परियोजना की तैयारी सुविधा (पीपीएफ) नामक एक नया तंत्र स्थापित किया गया है, जो भारत सरकार की क्रेडिट लाइन (एलओसी) के लिए अनुरोध करने

वाली सरकारों को परियोजनाओं के निर्माण और डिजाइन तैयारी के लिए प्रदान की जा सकती है। किसी भी देश के इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अनुरोध करने पर, विदेश मंत्रालय कार्यान्वयन के लिए इसे एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया को सौंपता है। विकास भागीदारी प्रशासन (डीपीए) को इस तंत्र पर एक बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। आज तक मिस्र, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, नाउरू, मॉरीशस, सेशेल्स, रवांडा, लेसोथो के राज्य, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, किरिबाती गणराज्य, स्वाज़ीलैंड, मलावी, श्रीलंका, म्यांमार, माली और सूरीनाम से निष्पादन के लिए पीपीएफ अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

पड़ोसी देशों में अनुदान सहायता के साथ विकास परियोजनाएं

भारत सरकार द्वारा पड़ोसी देशों में अनुदान सहायता के साथ की जा रही विकास परियोजनाओं में बुनियादी ढाँचे का विकास, निर्माण, सड़क और पुल, जलमार्ग और पारेषण लाइनों से लेकर बिजली उत्पादन, कृषि, क्षमता निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास आदि कई क्षेत्र शामिल हैं।

श्रीलंका हाउसिंग प्रोजेक्ट

श्रीलंका के साथ भारत की विकास साझेदारी एक परामर्शात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है, जो श्रीलंका सरकार की प्राथमिकताएं एक कारक हैं। श्रीलंका में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) के पुनर्वास के लिए 50,000 घरों के निर्माण से संबंधित चल रही आवासीय परियोजना में अच्छी प्रगति हुई है।

- 1000 घरों के निर्माण की प्रायोगिक परियोजना पहले ही पूरी हो चुकी है।
- उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में 44,666 घरों के पूरा होने के साथ एक मालिकाना चालित प्रक्रिया के अंतर्गत 45,000 घरों का निर्माण और मरम्मत लगभग पूरा हो गया है।
- श्रीलंकाई सरकार द्वारा 1134 घरों के लिए भूमि की पहचान की प्रक्रिया के पूरा होने के बाद वृक्षारोपण क्षेत्र में कार्यरत भारतीय मूल के तमिलों के लिए केंद्र और उवा प्रांत में 4,000 घरों का निर्माण भी शुरू हो चुका है। 1134 घरों के पहले समूह का निर्माण अक्टूबर 2016 में शुरू हुआ था। 30 नवंबर 2018 तक, 1134 में से 854 घरों का निर्माण पूरा हो चुका है और 1903, 1102 और 941 लाभार्थियों को क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी किस्त भी जारी की गई है। शेष 2866 घरों के लिए अनुमान लगाए गए हैं और श्रीलंका सरकार द्वारा भूमि/लाभार्थियों की पहचान की प्रक्रिया चल रही है। 2866 लॉट में घरों का निर्माण चरणों में शुरू हुआ है।
- मई 2017 में श्रीलंका की यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्रीलंका के मध्य और उवा प्रांतों में भारतीय मूल तमिलों के लिए अतिरिक्त 10,000 घरों के निर्माण की घोषणा की गई थी। श्रीलंका सरकार उपर्युक्त 10,000 घरों के लिए लाभार्थियों और भूमि की पहचान करने की प्रक्रिया में है।

अफ्रीका में विकास परियोजनाएं

अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी सहयोग का एक सलाहकार मॉडल, विकास के अनुभवों को साझा करने पर आधारित है और यह अफ्रीकी देशों की प्राथमिकताओं और जरूरतों को संबोधित करने पर केंद्रित है। विभिन्न विकास साझेदारी पहलों के माध्यम से अफ्रीकी देशों के साथ जुड़ाव ने पिछले दशक में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2008, 2011 और 2015 में तीन भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलनों [आईएएफएस I, II और III] ने इस महाद्वीप के साथ विकास साझेदारी को और मजबूत किया है। आईएएफएस -II के अंतर्गत चिन्हित परियोजनाओं में ग्रामीण विकास में भू-सूचना विज्ञान अनुप्रयोग (सीजीएआरडी) पर केंद्रों की स्थापना और ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना का कार्य चल रहा है। आईएएफएस-III में, भारत ने रियायती ऋण (एलओसी) में अतिरिक्त 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर

और 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करके अफ्रीकी देशों के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।

अफ्रीका के इकतालीस देशों में, बिजली संयंत्र, पनबिजली, विद्युत पारेषण और वितरण नेटवर्क, बांध, सड़क, रेलवे, बंदरगाह, कृषि और सिंचाई, औद्योगिक इकाइयां, कौशल विकास, नागरिक निर्माण आदि विभिन्न क्षेत्रों में 11.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर के 189 ऋण प्रदान किये गए हैं। सौर ऊर्जा परियोजनाओं और रक्षा जैसे नए क्षेत्रों को भी भारत सरकार की एलओसी के अंतर्गत शामिल किया गया है।

अफ्रीका में अनुदान सहायता के अंतर्गत विभिन्न देशों को दिए गए उल्लेखनीय समर्थन में नौ अफ्रीकी देशों में प्रतिष्ठित महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर के निर्माण की परियोजनाएं शामिल हैं। अन्य परियोजनाओं में दक्षिण अफ्रीका में कारीगर कौशल के लिए गांधी-मंडेला सेंटर ऑफ स्पेशलाइजेशन की स्थापना, सेनेगल में उद्यमी और तकनीकी विकास केंद्र का उन्नयन और आधुनिकीकरण, तंजानिया में बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना, माली और तंजानिया को एंबुलेंस की आपूर्ति, सोमालिया को मिनीबस की आपूर्ति और लाइबेरिया में चिकित्सा उपकरण और सीटी स्कैन मशीनों की आपूर्ति शामिल हैं।

इन एलओसी और अनुदान परियोजनाओं ने अफ्रीकी देशों के साथ मजबूत विकास साझेदारी का नेतृत्व किया है जो हमारे साझा इतिहास और सांस्कृतिक संबंधों की समर्थक और पूरक है।

भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के माध्यम से क्षमता निर्माण

भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम भारत की भूमिका और दक्षिण-दक्षिण सहयोग में योगदान का एक दृश्य प्रतीक है, जो एशिया, अफ्रीका, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन के साथ ही प्रशांत और छोटे द्वीप देशों के 161 साझेदार देशों के पदचिह्न के साथ क्षमता निर्माण साझेदारी का गठन करता है। यह भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के प्रमुख स्तंभों में से एक है। आईटीईसी कार्यक्रम में भारत द्वारा अफ्रीका के लिए विशेष राष्ट्रमंडल सहायता कार्यक्रम (एससीएएपी) और कोलंबो योजना (सीपी) के अंतर्गत विस्तारित क्षमता निर्माण भी शामिल है। इसने नए साझेदार संस्थानों को शामिल करने के साथ दायरे और पहुँच को मजबूत करना जारी रखा है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान जैसे उत्कृष्टता के अधिक संस्थानों के साथ भागीदारी करके हमारी ताकत दिखाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नैनो तकनीक, पेट्रोलियम, फोरेंसिक जैसे उभरते क्षेत्रों में अग्रिम पाठ्यक्रम आरंभ किए गए हैं। दुनिया भर में बदलती जरूरतों और तकनीकी प्रगति के साथ इसकी लोकप्रियता और प्रासंगिकता को देखते हुए, इस साल उच्च स्तरीय व्यापक समीक्षा के हिस्से के रूप में आईटीईसी के क्षेत्र में ई-आईटीईसी और आईटीईसी-ऑन साइट जैसे नए तौर-तरीकों को शामिल किया गया है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, पूरे भारत के विभिन्न संस्थानों में विभिन्न अल्पकालिक और मध्यम अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए 161 भागीदार देशों के लिए आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत 11051 नागरिक प्रशिक्षण स्लॉट प्रस्तावित किए गए थे। पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा प्रायोजित असैनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि, खाद्य और उर्वरक जैसे कौशल और बैंकिंग, वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा; शिक्षा; इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी; अंग्रेजी भाषा; पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन; सरकारी कामकाज; स्वास्थ्य और योग; मानव संसाधन विकास और योजना; सिंचाई और जल संसाधन; आईटी और व्यावसायिक अंग्रेजी; पत्रकारिता; प्रबंधन और नेतृत्व; बिजली, नवीकरणीय और वैकल्पिक ऊर्जा; परियोजना प्रबंधन; ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन; एसएमई और उद्यमिता; सतत विकास और दक्षिण-दक्षिण सहयोग; दूरसंचार; कपड़ा; व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार; शहरी नियोजन और महिला सशक्तिकरण आदि विषयों की एक विस्तृत और विविध श्रेणी में काम कर रहे पेशेवरों के लिए 85 से अधिक प्रमुख संस्थानों में 370 से अधिक पाठ्यक्रमों का संचालन करता है।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग की मांग से प्रेरित होने के कारण, विशेष पाठ्यक्रमों पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जिन्हें भागीदार देशों की सरकारों के अनुरोध पर प्रशिक्षण के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए अनुकूलित किया गया है। वर्ष 2018 में ही, चालीस विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन पाठ्यक्रमों में नागरिक सेवा के कर्मचारियों के लिए क्षेत्र प्रशासन में मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम और न्यायिक अधिकारियों, सीमा

शुल्क अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, अंग्रेजी संचार, योग और संग्रहालय जैसे क्षेत्रों के कार्यक्रम शामिल हैं।

तीसरे भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (आईएएफएस-III) के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं के अलावा, अफ्रीकी देशों में क्षमता निर्माण प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके लिए एक परामर्श तंत्र के आधार पर महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गई है। अफ्रीकी देशों को आवंटित आईटीईसी स्लॉटों में आईएएफएस-तृतीय के पहले 2015-16 में 3382 के आंकड़े से 2018-19 में 4790 की मात्रात्मक वृद्धि देखी गई है। इसके अतिरिक्त मार्च 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के संस्थापन समारोह के दौरान हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, आईएसए सदस्य देशों के 165 मास्टर ट्रेनरों को आईटीईसी के अंतर्गत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

पाठ्यक्रमों और संस्थानों की अद्यतित सूची आईटीईसी पोर्टल (www.itecgoi.in) पर उपलब्ध है।

पिछले वर्षों की तरह, इस कार्यक्रम ने नागरिकों और रक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत, सरकारी और निजी क्षेत्रों के कुछ, भारतीय संस्थानों द्वारा संचालित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों को शामिल किया। आईटीईसी पोर्टल की ऑनलाइन प्रक्रियाओं ने आईटीईसी प्रतिभागियों, मिशनों/पोस्टों और भागीदार संस्थानों की आवश्यकताओं को सुगम बना दिया है, जिससे संस्थानों और अनुमोदित पाठ्यक्रमों आदि से संबंधित विवरणों तक पहुंचना आसान हो सके। आईटीईसी पोर्टल और अन्य सामाजिक नेटवर्किंग उपकरणों के माध्यम से और विदेशों में स्थित मिशनों और भारत के आईटीईसी पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों में आयोजित होने वाले वार्षिक 'आईटीईसी दिवस' समारोहों के माध्यम से पूर्व छात्रों के नेटवर्क के साथ जुड़ाव और माध्यम से मजबूत हो रहा है। आईटीईसी ने उन महाद्वीपों में पूर्व छात्रों का एक बड़ा नेटवर्क बनाया है जो अपने-अपने देशों में आईटीईसी के मशाल वाहक बन गए हैं और इस प्रक्रिया में, भारत और संबंधित देश के बीच एक शक्तिशाली सांस्कृतिक पुल विकसित किया है। आईटीईसी ने विकास साझेदारी के क्षेत्र में एक मजबूत ब्रांड नाम हासिल कर लिया है।

रक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2018-19 के दौरान, भागीदार देशों को 2196 रक्षा प्रशिक्षण स्लॉट आवंटित किए गए थे। पाठ्यक्रम सामान्य और विशेष दोनों प्रकृति के थे, जिसमें सुरक्षा और रणनीतिक अध्ययन, रक्षा प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, समुद्री जल सर्वेक्षण, जवाबी कार्रवाई और जंगल युद्ध शामिल थे, इनके अलावा तीनों सेवाओं में युवा अधिकारियों के लिए बुनियादी पाठ्यक्रम भी शामिल थे। नेशनल डिफेंस कॉलेज, नई दिल्ली और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज (डीएसएससी), वेलिंगटन जैसे प्रमुख संस्थानों के पाठ्यक्रम काफी लोकप्रिय रहे और स्व-वित्तपोषण के आधार पर विकसित देशों के अधिकारियों को भी आकर्षित किया।

विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति और अध्ययन यात्राएं

आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति ने भारतीय विशेषज्ञता को विकासशील देशों के साथ बांटने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम किया है। वर्ष 2018-19 (नवंबर 2018 तक) में, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और दूरसंचार, आपदा प्रबंधन, पुरातत्व, आयुर्वेद/सिद्धा, साइबर क्षमता निर्माण आदि विभिन्न क्षेत्रों में कुल बावन विशेषज्ञों को भागीदार देशों में प्रतिनियुक्त किया गया है। भागीदार देशों में आईटीईसी के रक्षा विशेषज्ञों को भी प्रतिनियुक्त किया गया है। भागीदार देशों के लिए भारतीय विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति मुख्य रूप से हमारे सहयोगी देशों की मांग से प्रेरित है। विशेषज्ञों के लिए सेवा अनुरोध में तेजी लाने के लिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के साथ मिलकर अंग्रेजी शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया है और संचार और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ इसी तरह की चर्चा चल रही है।

मंत्रालय मांगों के आधार पर, एक्सपोज़र देने और प्रासंगिक क्षेत्रों में भारत की उपलब्धि को प्रदर्शित करने के लिए,

भागीदार देशों के विशेषज्ञों और पेशेवरों को अध्ययन यात्राओं की सुविधा प्रदान करता है। 2018-19 के दौरान, युगांडा से लघु, मध्यम उद्यम (एसएमई) और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक छह सदस्यीय टीम ने अध्ययन दौरा किया था।

परियोजनाएं

वर्ष 2018-19 के दौरान, अन्य विकास परियोजनाओं में, भारत ने अपनी विशेषज्ञता और अनुभव को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के माध्यम से कंबोडिया में टा-प्रोहम, लाओ पीडीआर में वात फू और वियतनाम में मंदिरों के मैसन समूह में जैसी दक्षिण-पूर्व एशिया की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत स्मारकों और मंदिरों की बहाली और संरक्षण के लिए विस्तारित किया है। आईटी के क्षेत्र में भारत की ताकत आईटी देशों में उत्कृष्टता के विभिन्न केंद्रों की स्थापना के माध्यम से और मिस्र, मोरक्को, तंजानिया, गुयाना, नामीबिया, जॉर्डन और प्रशांत द्वीप देशों सहित भागीदार देशों को प्रशिक्षण प्रदान करने के माध्यम से साझा की जा रही है। कैरिबियन समुदाय (कैरीकॉम) सचिवालय के मौजूदा आईटी प्रणालियों के उन्नयन के अलावा उन्हें तकनीकी जानकारी, अपेक्षित आईटी अवसंरचना और विशेषज्ञ भी उपलब्ध कराये गए हैं। वर्ष के दौरान, बेलभ्यू, ग्रेनाडा में एक सड़क का निर्माण किया गया और जंजीबार में और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (वीटीसी) परियोजना और मलावी में बिजनेस इन्क्यूबेटर सेंटर (बीआईसी) परियोजना में काफी प्रगति दर्ज की गई, जबकि मेजबान देश के अनुरोध पर बेलीज़ में भारतीय सहयोग से अतीत में स्थापित अन्य वीटीसी परियोजनाओं का उन्नयन आरंभ किया गया।

आपदा राहत

भारत द्वारा आपदा से प्रभावित देशों से मानवीय आधार पर सहयोग किया गया था। इसमें मोजाम्बिक, सीरिया, यमन, सोमालिया, युगांडा, तंजानिया, मेडागास्कर, स्वाज़ीलैंड और केन्या को अन्य वस्तुओं के साथ दवाएं उपलब्ध कराई गईं। बांग्लादेश और सीरिया को खाद्य सामग्री और अन्य राहत सामग्री की आपूर्ति की गई थी।

14

आर्थिक कूटनीति

आर्थिक कूटनीति (ईडी) और राज्य प्रभाग ने, देश की विदेश नीति के आर्थिक कूटनीति आयाम को एक केंद्रित दिशा देने के प्रयासों के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कई पहलें कीं। भारत के निर्यात की पहुंच का विस्तार करने, विदेशों में भारतीय उद्यमों के लिए नए व्यापार के अवसर खोलने, तत्काल पड़ोस और उससे आगे आर्थिक वृद्धि करना, अधिक निवेश आकर्षित करने, पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने और भारत को एक आकर्षक व्यवसाय स्थल बनाने के उद्देश्य से विदेश मंत्रालय, केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, व्यापार मंडलों और विदेशों में स्थित मिशनों/पोस्टों के बीच अधिक से अधिक समन्वय सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए।

भारतीय मिशनों/पोस्टों को अपने मान्य देशों के साथ अपने आर्थिक जुड़ाव को तेज करने के लिए ईडी और स्टेट्स प्रभाग ने अपनी "बाजार विस्तार गतिविधियों" के बजट के अंतर्गत वित्तपोषण बढ़ा कर 16 करोड़ रुपए कर दिया है। वित्तपोषण का उपयोग कैटलॉग शो और क्रेता-विक्रेता की बैठकों के माध्यम से भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने, बाजार अध्ययन तैयार करने के लिए सलाहकारों को संलग्न करना, विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के लिए व्यापार सेमिनार आयोजित करने और विदेशों में व्यापार के अवसरों की तलाश करने वाले भारतीय उद्यमों के हितों को बढ़ावा देने के लिए उनकी वकालत के काम करने के लिए किया गया है। इसके अलावा, ईडी प्रभाग भी भारत में शीर्ष व्यापार कक्षों द्वारा भारत में विशिष्ट व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने की गतिविधियों का समर्थन करने के लिए ₹ 6 करोड़ तक के प्रस्तावों को संसाधित किया है।

द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी)

ईडी प्रभाग द्विपक्षीय निवेश संधियों (बीआईटी) के मुद्दे पर आर्थिक मामलों के विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा है। प्रभाग ने दिसंबर 2015 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित भारत के नए मॉडल पाठ पर आधारित बीआईटी पर विभिन्न दौर की वार्ताओं में भाग लिया। मौजूदा वर्ष में, प्रभाग ने स्विट्जरलैंड, मोरक्को, ईरान और यूएई के साथ इन वार्ताओं में भाग लिया है। इस प्रभाग द्वारा आदानों और अनुवर्ती कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। ब्राजील के साथ बीआईटी का समापन हो गया है और इस मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को सलाह दी है कि ब्राजील में नई सरकार के आने के बाद बीआईटी पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

सामाजिक सुरक्षा समझौते (एसएएएस)

विदेश मंत्रालय के अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय एसएएएस पर वार्ता शुरू और समाप्त करने के लिए विदेश मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी के रूप में ईडी प्रभाग ने "व्यापक" सामाजिक सुरक्षा समझौतों (एसएएएस) पर हस्ताक्षर किए और इन्हें कार्यान्वित किया है। आज तक, भारत ने अठारह देशों - ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, जापान, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और दक्षिण कोरिया के साथ एसएसएएस पर हस्ताक्षर किए और इन्हें कार्यान्वित किया है। भारत ने कनाडा के क्यूबेक प्रांत के साथ भी एसएसए पर हस्ताक्षर किए हैं, जो संचालन की प्रक्रिया में है। 28 जून 2017 को प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान, 2009 में दोनों देशों के बीच किए गए एसएसए में संशोधन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए

गए थे। संशोधन प्रोटोकॉल ने एसएसए में "निवास का देश" सिद्धांत को शामिल किया जिससे एसएसए में इक्विटी और निष्पक्षता का तत्व आया। भारत-दक्षिण कोरिया एसएसए में गैर-योगदान अवधि को वर्तमान पांच वर्षों से बढ़ाकर कुल आठ वर्ष कर दिया गया है।

जारी वार्ताएँ

भारत और चीन के बीच एसएसए पर पहली तकनीकी बैठक मई 2018 में हुई थी। (पहला पी-5 देश, दोनों देशों के लिए पारस्परिक रूप से फायदेमंद, 2019 में फिर से शुरू करने के लिए औपचारिक पाठ आधारित वार्ता)।

विदेश मंत्रालय एसएसए वार्ता के लिए "सक्षम प्राधिकारी" के रूप में, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस, थाईलैंड, मेक्सिको, पेरू, साइप्रस आदि कई अन्य देशों के साथ एसएसए में प्रवेश करने की योजना बना रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सर्व शिक्षा अभियान/समग्रता पर अनौपचारिक विचार-विमर्श चल रहे हैं।

औद्योगिक आउटरीच

उद्योग के क्षेत्र में, प्रभाग ने निम्नलिखित घटनाओं को वित्तपोषित और सह-आयोजित किया:

- अबू धाबी निवेश प्राधिकरण (एडीआईए) टीम की विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ जेएनबी, नई दिल्ली में 9 अप्रैल 2018 को बैठक।
- सैंटियागो, चिली में 1 और 2 अक्टूबर, 2018 को भारतीय उद्योग संघ (सीआईआई) के साथ भारत-लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन कॉन्क्लेव।
- नई दिल्ली में 7 अक्टूबर 2018 को इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स काउंसिल (आईआईसी) के साथ प्रभाव 2018 ।
- अबूजा (नाइजीरिया) में 8 और 9 अक्टूबर 2018 को सीआईआई के साथ भारत-पश्चिम अफ्रीका क्षेत्रीय कॉन्क्लेव।
- मलेशिया के कुआलालंपुर में 27 नवंबर 2018 को आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल (एआईबीसी) के साथ आसियान -इंडिया बिजनेस समिट के लिए रात्रि भोज और आसियान- इंडिया अचीवमेंट एंड एक्सीलेंस अवार्ड्स नाइट।
- सऊदी अरब में 27 और 28 नवंबर 2018 को बुनियादी ढांचा एवं आवासन क्षेत्र पर एक टीपीसीआई के प्रतिनिधिमंडल का दौरा।
- सूरत, गुजरात में 28 और 29 नवंबर 2018 को दक्षिणी गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसजीसीसीआई) के साथ इंडो आसियान बिजनेस कॉन्क्लेव (आईएबीसी)।

प्रभाग ने निम्नलिखित को लोगो समर्थन और अन्य सुविधा भी प्रदान की:

- 12-16 मार्च 2019 तक आयोजित होने वाले इंडिया स्मार्ट यूटिलिटी वीक 2019 के लिए भारत स्मार्ट ग्रिड फोरम को लोगो समर्थन।
- 20-29 मई 2019 को आयोजित वैश्विक प्राकृतिक संसाधनों के लिए नेटवर्क 18 को लोगो समर्थन।
- नई दिल्ली में 16 नवंबर 2019 को दक्षिण एशिया पावर समिट के आयोजन के लिए सीआईआई को लोगो का समर्थन।
- ताज डिप्लोमैटिक एन्क्लेव, नई दिल्ली में 9 और 10 अक्टूबर 2018 को खनिज और धातु आउटलुक 2030 पर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लोगो का समर्थन।

यह प्रभाग विदेश मंत्रालय की राजनीतिक मंज़ूरी प्रदान करने की सुविधा के लिए सत्रह व्यापारिक कार्यक्रमों के समन्वय प्रभाग के लिए अपना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया।

व्यापार मंच

16 दिसंबर, 2018 को नई दिल्ली में शीर्ष मंडलों के साथ मालदीव के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान एक व्यापार मंच का आयोजन किया गया था। एक सीईओ मंच भी आयोजित किया गया था, जिसमें 30 से अधिक अग्रणी भारतीय कंपनियों के सीईओ ने भाग लिया और एक से एक के आधार पर विचार-विमर्श किया ।

सभी प्रमुख व्यापार मंडलों के सहयोग से 25 जनवरी, 2019 को मॉरीशस के प्रधानमंत्री की यात्रा के मुंबई चरण के दौरान एक व्यापार मंच का आयोजन किया गया था। मॉरीशस के प्रधान मंत्री एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं और व्यापार मंच का नियोजन पर्यटन, बुनियादी ढांचे आदि जैसे क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए किया गया।

ईडी एंड स्टेट्स प्रभाग ने 25 जनवरी, 2019 को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान एक व्यावसायिक कार्यक्रम की भी मेजबानी की। इस आयोजन का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत करना है और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आमंत्रितों में ऐसे व्यवसायी/निवेशक शामिल किए जाएंगे, जो संभावित क्षेत्रों में निवेश और व्यापार विकास को आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक होंगे।

दिल्ली और मुंबई में 18-19 फरवरी, 2019 को अर्जेंटीना के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान व्यावसायिक कार्यक्रमों की योजना है। व्यापार मंच सभी संभावित क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच निवेश/व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चर्चा करेगा और बी2बी की सम्बद्धता पर ध्यान केंद्रित करेगा।

जीवंत गुजरात शिखर सम्मेलन, 2019

नौवां जीवंत गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 18-20 जनवरी, 2019 को गुजरात के गांधीनगर में होने वाला है। शिखर सम्मेलन का उदघाटन माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा।

शिखर सम्मेलन में 19 जनवरी, 2019 को 'अफ्रीका दिवस' भी होगा जिसमें विदेश मंत्री भी उपस्थित रहेंगी। ईडी और राज्य प्रभाग जीवंत गुजरात कार्यक्रम के सफल आयोजन में सक्रिय रूप से शामिल है और अफ्रीका दिवस सहित व्यापार संवर्धन से संबंधित घटनाओं का नेतृत्व कर रहा है।

गांधी नगर, गुजरात में 9वें वाइब्रेन्ट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रधान मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति (18 जनवरी, 2019)

प्रवासी भारतीय दिवस, 2019

ईडी और राज्य प्रभाग प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल है। यह तैयारी के लिए संचालन समिति का हिस्सा है और आयोजन के दौरान दो पैनल चर्चाएं आयोजित कर रहा है।

चेन्नई में सौर संगोष्ठी

आर्थिक कूटनीति और राज्य प्रभाग, एक्जिम बैंक के साथ मिलकर 8 फरवरी 2019 को चेन्नई में एक सौर संगोष्ठी का आयोजन करेगा, जिसका उद्देश्य भारत में सौर ऊर्जा हितधारकों को एलओसी तंत्र के बारे में सूचित करना है। कार्यक्रम में 200 से अधिक सौर कंपनियों की भागीदारी रहेगी।

कुवैत में भारतीय चिकित्सा पर्यटन

कुवैत में भारत का दूतावास मार्च, 2019 में सीआईआई, एसईपीसी और आईडीएफ, आईबीपीसी जैसे स्थानीय साझेदार संघों के सहयोग से कुवैत में भारतीय चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक आयोजन कर रहा है। ईडी एवं राज्य प्रभाग ने बजट शीर्षक 'बाजार विस्तार गतिविधियाँ' के अंतर्गत इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए ईओआई, कुवैत को 5 लाख रुपए की एक अतिरिक्त राशि आवंटित की है।

आयुष

ईडी एवं राज्य प्रभाग ने अपने आईपी एवं पी बजट से फरवरी/मार्च, 2019 के महीने में आयुष को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम की योजना बना रहा है। यह कार्यक्रम एक भारतीय राज्य में आयोजित किया जाएगा जो परंपरागत रूप से जाना जाता है और जिसके पास आयुष के माध्यम से इलाज/चिकित्सा के लिए बहुत अच्छी सुविधा बनाई गई है।

ऊर्जा

ईडी प्रभाग अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के साथ भारत के संयुक्त सहयोग का समन्वय करता है। प्रभाग ने भारत और आईईए के बीच विकसित द्विवार्षिक कार्य कार्यक्रमों में योगदान दिया है, जिसमें संयुक्त वक्तव्य और 2015-17 के लिए संयुक्त कार्रवाई (जेएस एवं एसजेए) की अनुसूची, नीति आयोग और आईईए के बीच आशय का बयान (एसओआई) साथ ही आईईए और भारत सरकार के बीच 2018-2021 का संयुक्त कार्य कार्यक्रम शामिल है। ईडी प्रभाग आईईए के साथ भारतीय ऊर्जा मंत्रालयों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने वाली प्राथमिक समन्वय एजेंसी भी है।

ईडी प्रभाग बहुपक्षीय मंच पर भारत की ऊर्जा भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के अलावा, लाइन मंत्रालयों के समूह का एक हिस्सा भी है, जो विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय ऊर्जा संवाद को आगे बढ़ाने में शामिल है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए)

ईडी प्रभाग ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के मसौदा फ्रेमवर्क समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में काम किया और भावी सदस्य देशों से समर्थन हासिल करने के प्रयासों को गति दी। आईएसए को संधि-आधारित संगठन के रूप में स्थापित करने का प्रयास करने वाला आईएसए फ्रेमवर्क

समझौता, 7-18 नवंबर2016 से मोरक्को के माराकेच में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (सीओपी -22) में पक्षों के 22वें सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था।

आईएसए संस्थापक सम्मेलन 11 मार्च 2018 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रों के अलावा, इक्कीस राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों, छह उप-राष्ट्रपतियों और उप-प्रधानमंत्रियों, प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के रूप में उन्नीस मंत्रियों, बहुपक्षीय बैंकों के प्रमुखों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के शीर्ष प्रतिनिधियों, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा, कॉर्पोरेट समाज, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के कॉर्पोरेट क्षेत्र और दुनिया भर के चिंतकों ने सम्मेलन में भाग लिया। प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की क्रेडिट लाइन (एलओसी) का विस्तार करने की भारत की प्रतिबद्धता की घोषणा की जो पंद्रह देशों में सत्ताईस परियोजनाओं को शामिल करेगी। इन परियोजनाओं में सौर पीवी बिजली संयंत्र की स्थापना, मिनी ग्रिड और ऑफ ग्रिड उपयोग, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, स्ट्रीट लाइटिंग, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए सौर ऊर्जा, स्वास्थ्य, अस्पतालों, कॉलेजों, स्कूलों, सरकारी प्रतिष्ठानों, कम आय वाले परिवारों आदि शामिल होगी।

इकहत्तर देशों ने आईएसए के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि इनमें से अड़तालीस देशों ने फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि भी की है। गठबंधन ग्रामीण और विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों, किफायती वित्त, द्वीप और गांव के सोलर मिनी ग्रिड, रूफटॉप इंस्टॉलेशन और सौर ई-मोबिलिटी प्रौद्योगिकियों तक पहुंच पर ध्यान केंद्रित करेगा। आईएसए का उद्देश्य सदस्य देशों को संगठित करना, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रतिबद्धताओं की तलाश करना और व्यवसाय और निजी क्षेत्र की समिति का गठन कर निजी क्षेत्र को गतिशील करना है। आईएसए सदस्य देशों में सौर प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों और संसाधन केंद्र के अंतर्गत सौर संसाधन केंद्रों का एक नेटवर्क बनाकर सौर ऊर्जा अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगा, प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करेगा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी विकसित करेगा, और सौर पुरस्कार व फैलोशिप आरंभ करेगा। आईएसए एक आम गारंटी तंत्र बनाकर और परियोजना डेवलपर्स और निवेशकों को एक साथ लाने के लिए एकल खिड़की मंच के विकास की सुविधा के द्वारा नई सौर ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण का भी समर्थन करेगा।

आईएसए की पहली आम सभा 2-5 अक्टूबर 2018 से नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। महासभा के दौरान आईएसए को सभी देशों के लिए खोलने का प्रस्ताव पेश किया गया था। जो देश कर्क रेखा और मकर रेखा के बाहर आते हैं, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं और फ्रेमवर्क समझौते में दिए गए उद्देश्यों और गतिविधियों में योगदान करने के लिए तैयार और सक्षम हैं उन्हें एक भागीदार देश का दर्जा दिया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने आईएसए को संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) के अंतर्गत अधिसूचित किया है।

नागर विमानन

नागरिक विमान के क्षेत्र में, प्रभाग ने नागरिक विमानन मंत्रालय के साथ मिलकर द्विपक्षीय हवाई सेवा वार्ता पर काम किया। विदेश मंत्रालय इन मुद्दों पर और पर्यटन को बढ़ावा देने तथा द्विपक्षीय/बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए उड़ान संचालन या कोड शेयर की आवश्यकता पर भी इनपुट प्रदान करता है।

नागरिक विमानन मंत्रालय ने 15 और 16 जनवरी 2019 को मुंबई में आयोजित होने वाले ग्लोबल एविएशन समिट की योजना बनाई है, उन्होंने मंत्रियों और नागर विमानन प्राधिकरणों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। विदेश मंत्रालय ने विदेशों में अपने मिशनों के माध्यम से निमंत्रण भेजने और ऐसे अधिकारियों से पुष्टि प्राप्त करने के संदर्भ में पर्याप्त सहायता प्रदान की है। इसके अलावा, विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में नागर विमानन और वाणिज्य मंत्री के निवास पर आयोजित कार्यक्रम के लिए विदेशी निवासी मिशनों के प्रमुखों की उपस्थिति की सुविधा प्रदान की।

विदेश मंत्रालय ने मोरक्को, फिलीपींस, सर्बिया, इंडोनेशिया, यूएई और फ्रांस के साथ द्विपक्षीय हवाई सेवा वार्ता में भाग लिया। सर्बिया और मोरक्को के साथ हवाई सेवा समझौते संपन्न किए गए।

प्रवासी आउटरीच

ईडी प्रभाग ने नई दिल्ली में 14 जुलाई 2018 को 'किफायती अपशिष्ट प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण में भारतीय प्रवासियों की भूमिका' विषय पर एक दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) पैनल चर्चा का समन्वय किया। प्रवासी भारतीयों और प्रमुख नीति निर्माताओं ने प्रवासी भारतीयों को भारत के विकास से जोड़ने की रणनीति पर चर्चा की। विदेश मंत्री (ईएएम) श्रीमती सुषमा स्वराज ने पैनल की अध्यक्षता की और पेयजल और स्वच्छता मंत्री श्रीमती उमा भारती एक दिवसीय पैनल चर्चा की सम्मानित अतिथि थीं, कई महत्वपूर्ण विचार/सुझाव प्राप्त हुए, जो भारत के विकास के प्रयासों में प्रवासी भारतीयों की सक्रिय भागीदारी के लिए प्रवासी भारतीयों को जोड़ने में मदद कर सकते हैं। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित सिफारिशें आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं।

एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड इंवेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) की तीसरी वार्षिक बैठक

ईडी प्रभाग ने अंतर-मंत्रालयी समिति के सदस्य के रूप में, 22-27 जून 2018 के बीच, मुंबई में एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड इनवेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) की तीसरी वार्षिक बैठक का सह-आयोजन किया। बैठक एशिया में समृद्धि और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसकी उधार देने की क्षमता बढ़ाने के लिए आशावादी टिप्पणी पर संपन्न हुई। बैठक का विषय था : इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए वित्त जुटाना: नवाचार और सहयोग'। इसका प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया और एआईआईबी के छियासी सदस्य देशों से 3,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया।

निर्यात-विदेशी मुद्रा अर्जन परियोजनाएँ

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) ट्रस्ट के अंतर्गत क्रेडिट इंश्योरेंस कवर के लिए ईसीजीसी लिमिटेड से प्राप्त प्रभाग प्रक्रिया के मामलों को ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा प्रशासित किया जाता है। यह कोष परियोजनाओं/अनुबंधों की आपूर्ति सहित बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भारतीय निर्यातकों का समर्थन करने के लिए स्थापित किया गया है। एनईआईए की ओर से ऐसे मध्यम और बड़े परियोजना निर्यात को सहायता दी जाती है जो एग्जिम बैंक और ईसीजीसी लिमिटेड की हामीदारी क्षमता से परे हैं। इस तरह के प्रस्तावों की मंजूरी और निगरानी वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता वाली निर्देश समिति (सीओडी) द्वारा की जाती है। विदेश मंत्रालय भी सीओडी का सदस्य है और विदेश मंत्रालय में सीओडी और ईडी एवं राज्य प्रभाग के इस विषय को संभालते हैं। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, विदेश मंत्रालय का भारतीय कंपनियों द्वारा सुरक्षित 965 करोड़ रुपए के आठ विदेशी अनुबंधों के लिए, राजनीतिक कोण से अनापत्ति दी गई थी, जिनमें दो परियोजनाएं अफगानिस्तान में और शेष मुख्य रूप से अफ्रीकी देशों में थीं। प्रभाग ने इस अवधि के दौरान आयोजित दो सीओडी बैठकों में विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया और देश की आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों पर पर्याप्त जानकारी प्रदान की तथा इन देशों के साथ हमारे संबंधों पर भी विचार दिए ताकि परियोजनाओं के लिए आवश्यक क्रेडिट/बीमा कवर सहायता प्रदान करने पर एक संतुलित दृष्टिकोण लिया जा सके।

अधिशेष चीनी का निर्यात

पिछले सत्रों में चीनी के अधिशेष उत्पादन और अक्टूबर 2018 से शुरू हुए चालू मौसम से अनुमानित अधिशेष के साथ, चीनी के निर्यात से चीनी मिलों की तरलता संकट को कम करना आवश्यक हो गया है जिससे उन्हें किसानों को

गन्ने की बकाया रकम का समय पर भुगतान करने में सक्षम बनाया गया है। एक बैठक के बाद, तीन प्रतिनिधिमंडलों का गठन किया गया था जो विभिन्न समयों पर संबंधित देशों में अधिकारियों के साथ बैठक करने के लिए इंडोनेशिया और मलेशिया, चीन और कोरिया और बांग्लादेश जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने यात्रा की सुविधा प्रदान की, संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकें तय कीं और फलदायक चर्चाएँ हुईं। विदेश मंत्रालय लगातार विभिन्न संबंधित मंत्रालयों के संपर्क में है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव समर्थन प्रदान कर रहा है कि भारत से चीनी निर्यात को अधिकतम किया जा सके। इस प्रभाग ने अन्य देशों में भारतीय मिशनों/पोस्टों से संचार प्राप्त किया है, जो भारत से चीनी आयात करने के इच्छुक हैं।

भारत-संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग का 12वां सत्र

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 3 और 4 दिसंबर, 2018 को अबू धाबी में आयोजित भारत-संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आर्थिक, व्यापार और तकनीकी सहयोग आयोग के 12 वें सत्र की सह-अध्यक्षता के लिए संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। जेसीएम ने आर्थिक, व्यापार और निवेश, कांसुलर, वीजा, रोजगार और आव्रजन के क्षेत्रों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ हमारे सहयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

ईडी वेबसाइट

ईडी प्रभाग अपनी वेबसाइट `www.indbiz.gov.in' (http://164.100.163.203 पर सुलभ) के नवीनीकरण की प्रक्रिया में लगा रहा है। संशोधित वेबसाइट का उद्देश्य विदेशी उद्यमों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यापारिक वातावरण के साथ-साथ विदेशों में जाने वाले भारतीय व्यवसायों और भारतीय मिशनों और पोस्टों के लिए भारत की सभी सूचनाओं का एक स्रोत होना है। यह भारत के फायदों, भारत की एक सामान्य, आर्थिक, राजनीतिक और जनसांख्यिकी प्रोफ़ाइल, भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जानकारी, क्षेत्रीय अवसरों और सफलता की कहानियों, राज्य के प्रमुख लाभों, राज्य एजेंसियों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अद्यतन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की असंख्य रेटिंगों को उपलब्ध कराता है। वेबसाइट अब निकट भविष्य में आरंभ से पहले अंतिम मंज़ूरी प्राप्त करने के चरण में है।

संसाधनों का वैश्विक मानचित्रण

ईडी प्रभाग ने मिशनों से प्राप्त जानकारी के आधार पर जून 2018 में सामग्री, खनिज, प्रौद्योगिकी और कौशल के वैश्विक मानचित्रण के लिए एक अभ्यास किया था। इस अभ्यास को राज्य सरकारों के लिए और अधिक प्रासंगिक बनाने की दिशा में एक दृष्टिकोण के साथ परिष्कृत किया गया है, ताकि उन्हें संभावनाओं के प्रति सचेत किया जा सके और उनकी ताकत और रुचियों का मिलान किया जा सके, साथ ही साथ इसमें विदेशों में कृषि निर्यात और रोजगार के अवसरों की संभावनाओं को भी शामिल किया जा सके।

डाक के बुनियादी ढांचे के डिजिटलीकरण पर दर्पण परियोजना

ईडी प्रभाग ने टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) और रिकोह (इंडिया) लिमिटेड (आरआईएल) द्वारा डाक के बुनियादी ढांचे के डिजिटलीकरण पर दर्पन परियोजना के निष्पादन के लिए डाक विभाग (डीओपी) के साथ काम किया।

नौवेले गैबॉन खनन एसए (एनओजीए) में MOIL इक्विटी भागीदारी

प्रभाग ने मैंगनीज अयस्क इंडिया लिमिटेड (एमओआईएल) को गैबॉन में एक मिलियन मीट्रिक टन फेरोलाइल स्मेल्टर कॉम्प्लेक्स के विकास के लिए नौवेले गैबॉन माइनिंग एसए (एनओजीए) में इक्विटी भागीदारी के इसके प्रस्ताव में सहायता प्रदान की।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून (यूएनसीआईटीआरएएल) पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के कार्य समूह- III का 35वां सत्र

प्रभाग ने निवेशक-राज्य विवाद निपटान (आईएसडीएस) के संभावित सुधार पर 23-27 मई 2018 से संयुक्त राष्ट्र आयोग के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून (यूएनसीआईटीआरएएल या आयोग) के कार्यकारी समूह- III में भाग लिया।

सॉफ्टवेयर उत्पादों पर औद्योगिक नीति और राष्ट्रीय नीति

प्रभाग ने प्रस्तावित औद्योगिक नीति और सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति - 2018 में सहयोग किया, जो दो प्रस्तावित नीतियों के विकास के लिए एक रणनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण प्रदान करता है।

सीएलएमवी क्षेत्र के लिए भारत की रणनीतिक और आर्थिक कार्यसूची

इस प्रभाग ने अप्रैल 2018 में सीएलएमवी क्षेत्र के लिए भारत की रणनीतिक और आर्थिक कार्यसूची पर सीआईआई संवाद में भाग लिया और सीआईआई अफ्रीका समिति 2018-19 और दिसंबर 2018 में एसोचैम भारत-अफ्रीका संवाद में संबंधित क्षेत्रों के लिए भारत की आर्थिक रणनीति को रेखांकित किया।

भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव के अंतर्गत एक अंतर-विभागीय समिति (आईडीसी) का गठन किया गया है, जो भारत में परिचालन की तलाश कर रहे विदेशी बैंकों और विदेश में कार्यालय खोलने के इच्छुक भारतीय बैंकों के प्रस्तावों की जांच करती है। ये प्रस्ताव आरबीआई द्वारा सरकार के विचार के लिए आगे लाए गए हैं। विदेश मंत्रालय समिति में सदस्य है। चालू वित्त वर्ष में, विदेश मंत्रालय ने राजनैतिक कोण से छह प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी जिसमें विदेशी बैंको से चार और विदेश में अपने कार्यालय स्थापित करने के लिए एसबीआई से दो प्रस्ताव शामिल हैं। इस मंत्रालय ने भारत में अपनी शाखा स्थापित करने के लिए बैंक ऑफ चाइना को अनुमति दिलाने के लिए जानकारी और पक्षपोषण के मामले में पर्याप्त योगदान दिया। यह प्रस्ताव लंबे समय से बिना किसी निर्णय के लंबित था।

इस प्रभाग ने मौजूदा संपर्क कार्यालय (एलओ)/शाखा कार्यालय (बीओ)/ परियोजना कार्यालय (पीओ) आदि के नियमित/नियमितीकरण के सोलह प्रस्तावों के लिए राजनीतिक कोण से मंजूरी की सुविधा प्रदान की। प्रभाग ने ऐसे मामलों की मंजूरी की प्रगति की निगरानी के लिए आरबीआई की त्रैमासिक बैठकों में भी भाग लिया। प्रभाग द्वारा दी गई जानकारी से मामलों के शीघ्र निर्णय में मदद मिली है।

विभिन्न बोर्डों/समितियों की टिप्पणियाँ

अतिरिक्त सचिव (ईडी और राज्य) ईओयू और सेज के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीईएस) (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय), परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद (पीईपीसी), इंडिया ट्रेड प्रमोशन संगठन (आईटीपीओ), इन्वेस्ट इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड (आईआईएफटी), इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी), डब्ल्यूएपीसीओएस आदि कई बोर्डों/समितियों में सदस्य/निदेशक के रूप में विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हैं। ईडी एवं स्टेट्स प्रभाग के अन्य अधिकारी भी मत्स्य समितियों, कोल प्रिपरेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया (सीपीएसआई), दालों के कार्टेलिजेशन/होर्डिंग पर गठित समूह, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव (एमएआई) जैसी समितियों में विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन बोर्डों/समितियों के भाग के रूप में, ईडी और राज्य प्रभाग नियमित रूप से इनकी बैठकों में भाग लेते हैं और विदेश मंत्रालय को आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

कार्यक्रमों का प्रचार

ईडी प्रभाग ने उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2018, फार्मा मेडिकल डिवाइस एक्सपो जैसे कार्यक्रमों का प्रचार किया और इन कार्यक्रमों में हितधारकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इंडिया स्टील एक्सपो 2019 जैसे कार्यक्रमों का प्रचार करना जारी रखा है।

मध्यस्थता के मामले

विदेशी निवेशकों द्वारा विभिन्न द्विपक्षीय निवेश संरक्षण समझौतों (बीआपीएएस) के अंतर्गत भारत सरकार (जीओआई) के खिलाफ दो दर्जन कानूनी विवाद/मध्यस्थताएं उठाई गईं, जिनमें भारत 1990 और 2000 की शुरुआत में विभिन्न देशों के साथ शामिल हुआ था। विदेश मंत्रालय के सचिव (ईआर) इन मामलों से निपटने के लिए गठित अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) के सदस्य हैं, ईडी प्रभाग ने इन बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया है और साथ ही अन्य बैठकों में भारत सरकार के बयान की तैयारी और अंतिम रूप देने पर विचार किया है।

प्रभाग ने भारत-नीदरलैंड बीआईपीए के अंतर्गत वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स; भारत-ब्रिटेन बीआपीए के अंतर्गत वोडाफोन; भारत- ब्रिटेन बीआईपीए के अंतर्गत केयर्न एनर्जी और वेदांत दोनों; भारत-जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के अंतर्गत निसान मोटर्स; भारत-फ्रांस बीआईपीए के अंतर्गत लुई ड्रेफस एमेटर्स; भारत-यूएई बीआईपीए के अंतर्गत रास-अल-खैमाह निवेश प्राधिकरण; भारत-मॉरीशस बीआईपीए के अंतर्गत खेतान होल्डिंग्स; भारत-मॉरीशस बीआईपीए के अंतर्गत कैरिसा इनवेस्टमेंट्स एलएलसी; भारत-पुर्तगाल बीआईपीए के अंतर्गत मैस्करेनहास के संबंध में ऐसी बैठकों में भाग लिया है।

ईडी प्रभाग ने यूएनसीआईटीआरएएल द्वारा किए गए निवेशक-राज्य विवाद निपटान तंत्र में सुधार में भी योगदान दिया ।

15

राज्य

शहरों/ राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों व विदेशी सरकारों के बीच जुड़वां शहर/ जुड़वां राज्य और अन्य समझौते के हस्ताक्षर की सुगमता।

राज्य प्रभाग ने 9 अप्रैल, 2018 को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बार्कले एवं अरूणाचल प्रदेश राज्य के बीच समझौता पर हस्ताक्षर का समन्वय किया।

इस प्रभाग ने दिल्ली और सियोल (सियोल मेट्रोपोलिटन सरकार) के बीच समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए दिनांक 18 मई, 2018 को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की सहायता की।

इस प्रभाग ने पणजी (गोवा) और विक्टोरिया (सेसेल्स) के बीच युग्म समझौता पर हस्ताक्षर करने के लिए 22 जून, 2018 को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय को सहायता दी।

राज्य प्रभाग ने विश्व बैंक की सहायता से असम राज्य सड़क परियोजना फेज-।। के कार्यान्वयन के लिए असम सरकार के प्रस्ताव पर अनुमति देने में वित्ती मंत्रालय के साथ समन्वय किया।

विभाग ने संबंधित प्रादेशिक प्रभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद 5 अक्टूबर, 2018 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और मास्को के बीच एक समझौता विस्तार पर हस्ताक्षर को सुकर बनाया है।

प्रभाग ने पशुपालन एवं पशुचिकित्सा विभाग, मेघालय सरकार तथा वेलोनिया के पशु उतपाद के संवर्धन-प्रोआनिवल, वालोनिया क्षेत्र, बेल्जियम राज्य के बीच समझौता किए जाने वाले प्रस्तावित एमओयू के संबंध में मेघालय सरकार की सहायता की।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न समझौतों/एमओयू पर कार्रवाई की जा रही है। इनमें से कुछेक पर राज्य सरकार से अनुमति की प्रतीक्षा है।

राज्यों की बाहरी पहुंच को सुकर बनाना।

राज्य प्रभाग ने 1 फरवरी, 2018 को नई दिल्ली में जम्मू और कश्मीर का 'पर्यटन सड़क शो' के आयोजन को सुकर बनाया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पर्यटन राज्य मंत्री श्री के. जे. अल्फोंज द्वारा किया गया था और इसका लक्ष्य जम्मू व कश्मीर तथा लद्दाख के बौद्ध सर्किट की पर्यटन क्षमता में दिल्ली/ राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र (एनसीआर) के प्रमुख पर्यटन आपरेटरों में रूचि जगाना तथा साथ हीं, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार का प्रदर्शन गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इस प्रभाग ने सड़क शो में भागीदारी करने के लिए विदेशी मिशनों को आमंत्रित करते हुए उनके विभिन्न मिशन प्रमुखों को लिखित रूप में लिखते हुए इस कार्यक्रम को प्रचारित किया।

प्रभाग ने गुवाहाटी में 3 एवं 4 फरवरी, 2018 को आयोजित 'वैश्विक निवेशकर्ता सम्मेलन- असम के लिए लाभकारी' कार्यक्रम में भाग लिया। इस सम्मेलन और प्रदर्शनी का लक्ष्य असम की आर्थिक और निर्माण मजबूती को प्रदर्शित करना था। इस प्रभाग ने इस मंत्रालय के विभिन्न प्रादेशिक प्रभागों के साथ परामर्श कर विभिन्न विदेशी राजनयिकों को संबोधित आमंत्रण पत्रों को भेजकर इस कार्यक्रम को सुकर बनाया।

इस प्रभाग ने मुम्बई में 18-20 फरवरी, 2018 को 'वैश्विक निवेशक सम्मेलन, मैग्नेटिक महाराष्ट्र: अभिसरण 2018' में विदेश मंत्रालय (एमईए) का प्रतिनिधित्व किया। इस सम्मेलन की योजना भावी उद्योग, रोजगार, अवसंरचना और धारणीयता के चार प्रमुख स्तंभों के लिए बनाया गया और इसका लक्ष्य महाराष्ट्र को विश्व स्तरीय गंतव्य के रूप में बनाने के संबंध में उद्योग कैप्टन और प्रबुद्ध वर्ग के विचार जानने के लिए एक मंच के रूप इस्तेमाल करना था।

इस प्रभाग ने आंध्र प्रदेश- भारत उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के 24वें संस्करण में भाग लिया जिसका आयोजन 24-26 फरवरी, 2018 को विशाखापतनम में किया गया। इस साझेदारी सम्मेलन का विषय ''चार्टिंग इंडियाज ग्लोबल इंटेग्रेशन स्ट्रेटेजी'' था तथा इसका उप विषय विश्व व्यापार, व्यापार सुगमता, भारत सरकार के ध्वजरोधक कार्यक्रम, उद्योग 4.0 एयरोस्पेस और रक्षा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, अवसंरचना वित्तपोषण, कौशल विकास और स्टार्टअप में भारत की भूमिका थी।

राज्य प्रभाग ने 3 मई, 2018 और 11 मई, 2018 को पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस)- अंतर मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की सभी बैठकों में हिस्सा लिया जिसका आयोजन पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) के सचिव की अध्यक्षता में किया गया था।

इस प्रभाग ने विदेश मंत्रालय के विदेश संपर्क पहल के तहत 30 अगस्त, 2018 को गांधी नगर में हुए चौथे विदेश मंत्रालय राज्य पहुंच सम्मेलन में भागीदारी की।

इस प्रभाग ने विदेश मंत्रालय के विदेश संपर्क पहल के तहत 24 सितम्बर, 2018 को 5वें एमईए राज्य पहुंच सम्मेलन में भाग लिया।

इस प्रभाग ने विश्व तमिल आर्थिक प्रतिष्ठान द्वारा 1-15 अक्टूबर, 2018 को आयोजित पांडिचेरी वैश्विक आर्थिक सम्मेलन में विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया।

राज्य प्रभाग के अधिकारियों ने एमईए राज्य पहुंच कार्यक्रम के भाग के रूप में और 8 दिसम्बर, 2018 को भुवनेश्वर, ओडिशा का दौरा किया।

नई दिल्ली में विदेशी कूटनीतिज्ञों के साथ राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के सरकारों के साथ परस्पर बातचीत।

राज्य प्रभाग ने 24 मई, 2018 को जवाहरलाल नेहरू भवन (जेएनबी), नई दिल्ली में एक बैठक का आयोजन किया जिसकी अध्यक्षता भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के महानिदेशक द्वारा की गयी थी और के विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से ईकतीस निवासी आयुक्तों/अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। इस बातचीत का प्रमुख ध्यान आईसीसीआर के समक्ष आने वाली कठिनाईयों पर था जबकि भारत के विभिन्न भागों में विदेशी छात्रों के लिए ग्रीष्मकालीन/ शीतकालीन शिविरों का आयोजन किया गया।

इस प्रभाग ने एचओएम द्वारा राज्यों के दौरों के रिपोर्टों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न राज्यों और राज्य निवासी आयुक्तालयों के प्रतिनिधियों के लिए भारतीय मिशन प्रमुख (एचओएम) के बीच प्रवासी भारतीय केन्द्र में 30 जून, 2018 को एक बैठक का आयोजन भी किया।

प्रभाग ने जेएनबी, नई दिल्ली में 12 अक्टूबर, 2018 को कार्बनिक और मिलेट के लिए कर्नाटक राज्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (जिसका आयोजन 18-20 जनवरी 2019 को हुआ था) के संबंध में एक संक्षिप्त बैठक का आयोजन किया जिसमें नई दिल्ली में विदेशी मिशनों के प्रमुख और कर्नाटक सरकार के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

राज्य प्रभाग ने बंगलुरू में 18-20 जनवरी, 2019 के दौरान अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला- जैविक और मिलेट 2019 में भाग लेने के लिए विदेशी राजदूतों को आमंत्रित करने में कर्नाटक सरकार के साथ समन्वय किया और उनसे अनुरोध किया है कि वे अपने संबंधित राष्ट्रों से व्यापारिक/ कारोबारी शिष्टमंडल भेजें।

प्रभाग ने झारखंड के मुख्य मंत्री के साथ 9 अक्टूबर, 2018 को बैठक और रात्रि भोज कार्यक्रम के लिए विदेशी राजदूतों को आमंत्रित करने में झारखंड सरकार के साथ समन्वय भी किया। यह जेएनबी, नई दिल्ली में 19 सितम्बर, 2018 को वैश्विक कृषि और खाद्य सम्मेलन 2018 के संबंध में नई दिल्ली में झारखंड राज्य के अधिकारियों और विभिन्न विदेशी कूटनीतिज्ञों की बैठक के राज्य प्रभाग के पूर्व सुविधा के क्रम में था।

इस प्रभाग ने 6 नवम्बर, 2018 को जेएनबी, नई दिल्ली में 3-5 फरवरी, 2019 के दौरान अनुसूचित 23वें अंतरराष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला (आईईटीएफ) 2019 के संबंध में एक संक्षिप्त बैठक का आयोजन किया जिसमें नई दिल्ली में स्थिति विभिन्न विदेशी मिशनों के प्रमुखों, भारतीय उद्योग संघ (सीआईआई) के अधिकारियों ने भाग लिया।

भारत में दुर्दशा में विदेशी नागरिकों को सहायता।

'दुर्दशा में विदेशी नागरिकों को सहायता' के अंतर्गत राज्य प्रभाग महाराष्ट्र में विदेशी नागरिकों के संबंध में पुलिस से रिपोर्ट लेने तथा उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए अधिकारियों के तत्काल संपर्क में रहा जब एक ब्रिटिश नागरिक की 22 जनवरी, 2018 को मुम्बई हवाई अड्डे पर कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया गया तथा उत्तर प्रदेश में जब दो स्विस नागरिकों का आगरा में कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया गया। 27 जनवरी, 2018 को एक नाईजीरियाई नागरिक को कानपुर में गिरफ्तार किया गया; 03 जनवरी, 2018 को वाराणसी में एक स्पेनिश नागरिक को लूट लिया गया; 05 जनवरी, 2018 को एक युक्रेनी नागरिक की मृत्यु हो गयी; 23 जनवरी, 2018 को उपचार के दौरान वृंदावन में एक थाईलैंड नागरिक की जान चली गयी; 8 फरवरी, 2018 को वाराणसी में एक जापानी नागरिक को लूट लिया गया; 13 दिसम्बर, 2018 को वाराणसी में एक सिंगापुर नागरिक को कथित रूप से लूट लिया गया; 29 जनवरी, 2018 को उपचार के दौरान एक मारिशस नागरिक की मृत्यु हो गयी; 12 फरवरी, 2018 को वृंदावन में एक ईरानी नागरिक की मृत्यु हो गयी; 18 फरवरी, 2018 को मथुरा में एक ब्रिटिश नागरिक को विकट स्थिति में अस्पताल में भर्ती किया गया। यह प्रभाग हरियाणा में विदेशी नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए भी अधिकारियों के साथ संपर्क किया जब एक दक्षिण कोरियाई महिला के साथ गुरूग्राम में 10 फरवरी, 2018 को लोगों के एक समूह द्वारा कथित रूप से दुर्व्यहार और यौन उत्पीड़न किया गया।

इसने केरल में लातिवियाई नागरिक लिगा स्क्रोमने द्वारा सहायता के लिए विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज की सहायता लेने के लिए पीड़ित के परिवार के सदस्यों द्वारा ट्विट किया गया तो उनके गुम हो जाने के मुद्दे पर केरल राज्य सरकार के साथ समन्वय किया। बाद में 3 अप्रैल, 2018 को संयुक्त सचिव (आर्थिक कूटनीति और राज्य) ने इस मामले पर चर्चा करने के लिए केरल का दौरा किया और उसके बाद राज्य के पुलिस महानिदेशक द्वारा इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया तथा गुमशुदा लातिवियाई नागरिक के बारे में सूचना देने के लिए 2 लाख रूपए के ईनाम की घोषणा की।

इसके अतिरिक्त, राज्य प्रभाग ने मंत्रालय में संबंधित प्रादेशिक प्रभागों को विदेशी नागरिकों के संबंध में राज्यों से प्राप्त सूचना पुलिस को अग्रेषित करने तथा याचिकाओं के निपटान के लिए राज्य प्राधिकारियों को विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज को संबोधित कई याचिकाएं भी अग्रेषित की।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में उनके दौरे के दौरान भारत में अवस्थित विदेशी मिशन प्रमुखों/ कूटनीतिज्ञों को सुविधा प्रदान करना।

प्रादेशिक प्रभागों, राज्य रेजिडेंट आयोगों और राज्यप्राधिकारियों के साथ निकट सहयोग के साथ प्रभाग ने भारत स्थित डेनमार्क, फ्रांस, घाना, जापान, कजाखस्तान, न्यूजीलैंड, युनाइटेड किंग्डम, ऑस्ट्रेलिया, चीन, साइप्रस, गेवोरोन, ग्रीस, इंडोनेशिया, इस्राइल, मलेशिया, नीदरलैंड और रूस के विदेशी दूतावासों से कूटनीतिज्ञों का विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में दौरे को सुकर बनाया।

विदेशी शिष्टमंडलों के राज्यों के दौरे को सुकर बनाना।

प्रादेशिक प्रभागों, राज्य रेजिडेंट आयोगों और राज्य प्राधिकारियों के निकट सहयोग के साथ इस प्रभाग ने अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर, बेल्जियम, भूटान, कनाडा, यूरोपीय संघ, श्रीलंका, स्वीडन, थाइलैंड, नोर्डिक देशों व यूएई के राष्ट्रपतियों/ उपराष्ट्रपतियों/ प्रधानमंत्रियों/ मंत्रियों/ राज्यपालों/ मेयरों और अन्य गण्यमान्यों को भारत के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में दौरे को सुकर बनाया।

प्रत्यायन के अपने संबंधित राज्य में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के संवर्धन के लिए मिशनों/ पोस्टों के लिए 'राज्य सुविधा विदेशी' निधि।

राज्य प्रभाग ने विदेश स्थित विभिन्न मिशनों/ पोस्टों से इनपुटों को ध्यान में रखते हुए तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में 'विदेश स्थित राज्य सुविधा' शीर्षक के अंतर्गत निधियों की उपलब्ध्ता को ध्यान में रखते हुए 30 मई, 2018 को राज्य विशिष्ट गतिविधियों को करने के लिए 5 करोड़ रूपए की राशि विदेश स्थित 105 भारतीय मिशनों/पोस्टों को जारी की।

प्रभाग ने असम को एक निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए दिनांक 12 और 13 अगस्त, 2018 को असम सरकार के मंत्री श्री चंद्र मोहन पोटावरी का ग्वांगजोउ, चीन के दौरे को सुकर बनाया।

इसने आंध्र प्रदेश के शिष्टमंडल के साथ यहां के मुख्य मंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू का दिनांक 25 और 26 सितम्बर, 2018 को न्यूयार्क का दौरा सुकर बनाया बनाया जिन्होंने संभावित निवेशकों और कंपनियों के साथ बातचीत की जो न्यूयार्क राज्य में कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने दिनांक 26 सितम्बर, 2018 को आंध्र प्रदेश सरकार, अमेरिका-भारत कारोबार परिषद् तथा भारतीय उद्योग संगठन (सीआईआई) द्वारा आयोजित उद्योग गोल मेज वार्ता में भी हिस्सा लिया।

इस प्रभाग ने 1 अक्टूबर, 2018 को शिकागो में श्री अरविंद अग्रवाल (अपर मुख्य सचिव (वित्त)) की अगुवाई वाले गुंजायमान गुजरात शिष्टमंडल के दौरे को भी सुकर बनाया। अमेरिका-भारत नीतिगत साझेदारी मंच (यूएसआईएसपीएफ) के सहयोग से शिकागो में हमारे वाणिज्य दूतावास ने गुंजायमान गुजरात वैश्विक सम्मेलन, 2019 के लिए एक अग्रदूत के रूप में एक बहुक्षेत्रीय सड़क शो का आयोजन किया। इस आयोजन में लगभग 150 लोगों ने हिस्सा लिया।

व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रभाग ने खारतूम, सूडान में 18 नवम्बर, 2018 को चौथे सूडानी अंतरराष्ट्रीय तिलहन सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुख्यत: गुजरात/ कर्नाटक/ महाराष्ट्र से कंपनियों की भागीदारी को सुकर बनाया।

राज्यों में आयोजित दौरों/ घटनाओं और कार्यक्रमों को सुकर और सहायता के लिए राज्य सुविधा व ज्ञान सहायता कोष।

इस प्रभाग ने 'राज्य विशिष्ट क्रियाकलापों' के संबंध में 06 मई, 2018 को हैदराबाद में एक दिवसीय 'आर्थिक, कूटनीतिक, विकास और विकेन्द्रीकृत सहयोग संबंधी सम्मेलन' के आयोजन के लिए शाखा सचिवालय, हैदराबाद के लिए 6.5 लाख रूपए की राशि जारी की, इस सम्मेलन का उद्घाटन विदेश राज्य मंत्री जेनरल (डॉ.) वी. के. सिंह (सेवानिवृत्त) द्वारा किया गया ।

इस प्रभाग ने 'राज्य विशिष्ट क्रियाकलापों' को करने के लिए शाखा सचिवालय प्रमुख, गुवाहाटी को 10 लाख रूपए तथा पासपोर्ट कार्यालय, रांची को 50,000 रूपए की राशि संस्वीकृत की।

इस प्रभाग ने 11-15 अक्टूबर, 2018 को पांडिचेरी वैश्विक आर्थिक सम्मेलन, 2018 तथा पांचवें विश्व तमिल सम्मेलन को आयोजित करने के लिए विश्व तमिल आर्थिक प्रतिष्ठान को 12 लाख रूपए की राशि संस्वीकृत की। इस प्रभाग ने इस कार्यक्रम में मंत्रालय का भी प्रतिनिधित्व किया।

इस प्रभाग ने अहमदाबाद में 14 सितम्बर, 2018 को 12वें वैश्विक एफएडी 2018-प्रौद्योगिकी -निवेश- सुरक्षा हेतु खाद्य प्रसंस्करण, कृषि कारोबार, डेयरी के संबंध में कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए भारत के एसोसिएट चैम्बर आफ कॉमर्स (एसोचेम) को पांच लाख रूपए की राशि संस्वीकृत की।

प्रभाग ने 20 नवम्बर, 2018 को मैसर्स प्रैक्टिस स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को मूल विषय वस्तु सृजन, इंफोग्राफिक डिजाइन, डेवलपिंग और ईडी एवं राज्य प्रभाग की वेबसाइट की मेजबानी के लिए क्यू 3 के भुगतान, प्रथम वर्ष (जनवरी-मार्च, 2018) और क्यू 4, प्रथम वर्ष (अप्रैल-जून, 2018) के लिए 62,51,700 रूपए की राशि संस्वीकृत की।

आईएफएस अधिकारियों की राज्य पहचान/ विशेषता

प्रभाग ने मिशन प्रमुख सम्मेलन, 2018 के समक्ष 27-28 जून, 2018 को भारत के विभिन्न राज्यों के लिए भारतीय मिशन प्रमुखों के पहचान दौरों को सुकर बनाया। राज्यों से अनुरोध किया गया था कि वे (एक) भारतीय मिशन प्रमुख (एचओएम) के दौरों को सुकर बनाने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करे; (दो) स्वागत, आवास सुविधा और परिवहन सुविधा की व्यवस्था करें; और (तीन) राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के साथ भ्रमणकारी भारतीय एचओएम हेतु नियुक्ति निर्धारित करे। राज्यों में विभिन्न विभागों के मुख्य सचिवों के साथ राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक आयोजित करने का भी अनुरोध किया गया था।

प्रभाग ने विभिन्न भारतीय मिशनों/ विदेश स्थित पोस्टों के साथ कठिनाई में रह रहे भारतीयों को वापस भेजने के लिए राज्य अधिकारियों से प्राप्त अनुरोधों का समन्वयन किया और साथ हीं विदेश में कार्यरत गुम हुए भारतीयों का पता लगाने तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने व उन्हें सुरक्षित घर लाने के लिए उनके साथ संपर्क भी किया।

प्रभाग ने हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश के राज्य प्राधिकारियों को एजेंटों के अधम कृत्यों के बारे में बताया जो एजेंट जहाजों पर नाविकों को नौकरी देने के बहाने उनकी भर्ती कर रहे थे। राज्य प्राधिकारियों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे ऐसे एजेंटों के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई करें ताकि ऐसे गैर कानूनी कृत्यों को भविष्य में दुहराया न जा सके।

16

आतंकवाद रोध

इन वर्षों के दौरान विश्व के विभिन्न भागों में हुए विभिन्न आतंकी घटनाओं के कारण सभी स्तरों पर विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया। ऐसी सभी पारस्परिक क्रियाओं के दौरान भारत ने वैश्विक रूप से आतंकवाद की घटनाओं से निपटने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दुहराया तथा आतंकवाद के सभी रूपों और प्रत्यक्षीकरण की कठोर निंदा की। आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहनशीलता का आह्वान, किसी प्रकार की आतंकी कार्रवाई के लिए किसी भी औचित्य को निरस्त करना, आतंकवाद को धर्म से अलग करना, आतंकवाद से लड़ने के लिए सभी देशों को एकजुट होने की आवश्यकता जैसी चीजों को अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अधिक स्वीकार्यता प्राप्त हुई और विभिन्न देशों के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक व क्षेत्रीय व बहुपक्षीय मंचों पर जारी कई परिणामी दस्तावेजों में परिलक्षित होता है।

भारत ने विभिन्न साझेदार देशों के साथ संयुक्त आतंकवाद रोधी कार्य समूह (जेडब्लूजी-सीटी) के माध्यम से संरचित परामर्श करना जारी रखा है। वर्तमान में भारत जेडब्लूजी-सीटी के तंत्र के माध्यम से तेईस राष्ट्रों और तीन बहुपक्षीय समूहों के वरिष्ठ माध्यस्थों के साथ संबद्ध है। जेडब्लूजी-सीटी बैठक आतंकवाद रोधी सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है जिससे यह सूचना, अनुभव और सीमापार आतंकवाद सहित वैश्विक आतंकवाद के संबंध में मूल्यांकन को साझा करने में समर्थ बनाता है, संगत प्रौद्योगिकी और उपकरण सहित क्षमता वर्धन और प्रशिक्षण प्राप्त होता है, आतंकवाद व आतंकी वित्तपोषण के विरूद्ध युद्ध में बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूती प्राप्त होती है, परस्पर कानूनी सहायता अनुरोधों में शीघ्रता आती है, एजेंसी-दर-एजेंसी सहयोग को सुकर बनाता है और संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के तत्वावधान में व्यापक अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद अभिसमय (सीसीआईटी) के शीघ्र अनुकूलन के महत्व पर जोर डाला जाता है। वर्ष 2018 के दौरान भारत ने आस्ट्रेलिया, कनाडा, मिस्र, फ्रांस, इंडोनेशिया, रूस, ट्युनिशिया, यूके, अमेरिका, उजबेकिस्तान, नीदरलैंड और यूरोपीय संघ, ब्रिक्स तथा बिम्सटेक के साथ आतंकवाद रोधी वार्ता की।

भारत वैश्विक आतंकवाद-रोधी प्रयासों का अगुआ रहा है और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के विरूद्ध सभी प्रमुख प्रयासों में भाग लिया। आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने के भारत की सतत प्रतिबद्धता तथा आतंकवाद रोधी (ओसीटी) के लिए नव स्थापित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के कार्य के समर्थन के रूप 550,000 अमेरिकी डॉलर के एक स्वैच्छिक योगदान की घोषणा की गयी थी। वैश्विक आतंकवाद रोधी मंच (जीसीटीएफ), जिसकी स्थापना वर्ष 2011 में की गयी थी, के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत ने मार्च, 2018 में टोक्यो और सितम्बर, 2018 में न्यूयार्क में हुई जीसीटीएफ समन्वय समिति की तेरहवीं और चौदहवीं बैठक में तथा 27 सितम्बर, 2018 को जीसीटीएफ मंत्रालय की 9वीं पूर्ण बैठक में वरिष्ठ स्तर पर भा लिया। भारत वित्तीय कृतक बल (एफएटीए) बैठकों में भी नियमित रूप से भाग लेता रहा है जिसमें भारत वर्ष 2010 से ही सदस्य है। विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने जून और अक्टूबर, 2018 में पेरिस में आयोजित एफएटीई की बैठकों में हिस्सा लिया।

विदेश राज्य मंत्री जेनरल (डॉ.) वी. के. सिंह (सेवानिवृत्त) की अगुवाई वाले एक शिष्टमंडल ने 25 और 26 अप्रैल, 2018 को पेरिस में आयोजित दायेश और अल कायदा के वित्तपोषण से निपटने संबंधी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। विदेश राज्यमंत्री जेनरल (डॉ.) वी. के. सिंह (सेवानिवृत्त) ने दसन्वे में 4 मई, 2018 को आयोजित आतंकवाद रोधी एवं अतिवादी हिंसा को रोकने संबंधी उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने 22 और 23 मार्च, 2018 को सिंगापुर में आयोजित पारदेशीय संगठित अपराध और आतंकवाद पहल के बीच गठजोड़ संबंधी क्षेत्रीय बैठक में भी हिस्सा लिया; 3 और 4 सितम्बर, 2018 को मास्को में आयोजित अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने के संबंध में गैरकानूनी अस्त्र तस्करी से निपटने संबंधी सम्मेलन में भाग लिया; और 7 और 8 मई, 2018 को बाली, इंडोनेशिया में आयोजित विदेशी आतंकवादी लड़ाकुओं के परिवारों को वापस करने संबंधी चुनौती के समाधान पर जीसीटीएफ पहल की दूसरी बैठक में हिस्सा लिया।

17

वैश्विक साइबर मुद्दा

विदेश मंत्रालय के भीतर साइबर कूटनीति प्रभाग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय साइबर मुद्दों से निपटता है। ऐसे अनुबंधों का मुख्य उद्देश्य बहुपणधारक दृष्टिकोण को अपनाते हुए भारत के साइबर हितों की सुरक्षा करना है।

संयुक्त राष्ट्र के एक मुख्य सदस्य के रूप में भारत ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) प्रथम महासभा समिति में दो संकल्पों -एक यूएनजीजीई (संयुक्त राष्ट्र सरकारी विशेषज्ञ समूहों के समूह), और दूसरा सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में विकास संबंधी एक नए मुक्त समूह की स्थापना को अपनाने में शीर्ष चर्चाओं में हिस्सा लिया। इन समूहों से आशा की जाती है कि वे इन मुद्दों का अध्ययन करना जारी रखे ताकि सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में सामान्य समझ, विद्‌यमान और संभावित खतरों को समझा जा सके एवं इनके समाधान के लिए संभावित सहयोग उपाए किए जा सकें और यह भी पता लगाया जा सके कि किस प्रकार अंतरराष्ट्रीय कानून राष्ट्रों के जिम्मेदार व्यवहार के मानकों, नियमों और सिद्धांतों, विश्वास बहाली उपायों और क्षमता वर्धन द्वारा सूचना और संचार प्रौद्‌योगिकी के इस्तेमाल पर लागू होते हैं।

भारत के बहु पणधारक दल के रूप में विदेश मंत्रालय ने अक्टूबर, 2018 को बार्सिलोना में आयोजित 63वीं बैठक में समनुदेशित नाम और संख्या संबंधी इंटरनेट सहयोग (आईसीएएनएन) में भाग लिया। भारत ने वर्ष 2018 में ब्राजील और युनाइटेड किंग्डम के साथ द्विपक्षीय साइबर वार्ता आयोजित की तथा स्वीडन के साथ साइबर सुरक्षा संबंधी संयुक्त कृतक बल गठित किया। भारत और अमेरिका ने साइबर सुरक्षा मुद्दों में सहयोग करने के लिए अपने समझौते का नवीकरण किया। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए मोरक्को किंग्डम और सेशेल्स के साथ द्विपक्षीय समझौता किया।

दिसम्बर, 2018 में भारत ने ब्रुसेल्स में आयोजित पांचवीं भारत-ईयू साइबर वार्ता में भाग लिया और हेग में आयोजित प्रथम भारत-नीदरलैंड वार्ता में भाग लिया। फरवरी, 2019 में भारत बीजिंग में अंतरराष्ट्रीय सूचना सुरक्षा संबंधी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के विशेषज्ञ समूहों की अगले दौर की बैठक, नई दिल्ली में तीसरे भारत-आस्ट्रेलिया साइबर वार्ता और अंतरराष्ट्रीय साइबर मुद्दों संबंधी 5वीं भारत-जर्मन परामर्शदात्री बैठ में भाग लेगा।

18

सीमा प्रकोष्ठ

सीमा प्रकोष्ठ समुद्री सीमाओं सहित भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित विभिन्न अंतर मंत्रालयी और संयुक्त सीमा बैठकों में भाग लिया। सीमा प्रकोष्ठ में वर्गीकृत और संवेदनशील सूचना के संबंध में रिकार्डों तक पहुंच के लिए अनुसंधान विद्वानों द्वारा किए गए अनुरोधों को देखता है।

यह प्रकोष्ठ सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) से जुड़े प्रश्नों का भी उत्तर देता है। यह प्रकोष्ठ बजट अनुदान की समेकित संपूर्ण आवश्यकताओं को भी तैयार करता है तथा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को बरकरार रखने, रेखांकन और सीमांकन के संबंध में इसकी निगरानी करता है।

19

नीति नियोजन और अनुसंधान

नीतिगत योजना और अनुसंधान प्रभाग ने इस मंत्रालय के लिए विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के संबंध में हमारी सैद्धांतिक विदेशी नीतिगत उद्देश्यों के सतत विश्लेषण करने तथा अनुसंधान आधारित परिप्रेक्ष्यों के लिए अधिदेश देना जारी रखा। इसे विभिन्न भारतीय प्रबुद्ध वर्गों और अनुसंधान संगठनों के लिए इन हाउस और अग्रसक्रिय पहुंच के माध्यम से किया गया था।

इस प्रभाग ने भारत में मंच विकसित करने के उद्देश्य से प्रमुख प्रबुद्ध वर्ग और अकादमी संस्थाओं के साथ साझेदारी में सम्मेलनों का भी आयोजन किया जहां विश्व के शीर्ष रणनीतिक विशेषज्ञों व नीति निर्धारकों के बीच समकालीन विदेश नीति पर चर्चा हो सके।

इस प्रभाग ने दीर्घकालिक नीतिगत योजना और प्राथमिकताओं के संबंध में विचारों के आदान-प्रदान के लिए हमारे महत्वपूर्ण कूटनीतिक साझेदारों के साथ नीतिगत योजना के संबंध में संस्थागत विचारों को भी विकसित किया। भारत के परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करने तथा ऐसे सम्मेलनों में विशेषज्ञों व नीति निर्धारकों के बीच ऐसे विचारों के आदान-प्रदान से लाभ प्राप्त करने के लिए भारत और विदेश में महत्वपूर्ण कूटनीतिक सम्मेलनों में भारत की भागीदारी का भी आयोजन किया गया।

अनुसंधान शोधपत्र और नीतिगत संक्षिप्तियां

नीति और अनुसंधान के क्षेत्र में प्रभाग ने कई अध्ययन कार्यों को किया तथा सामान्य रूप से वैश्विक घटनाक्रमों व वर्तमान अंतरराष्ट्रीय कार्यों एवं विशेष रूप से भारत की विदेश नीति से संबंधित अनुसंधान शोधपत्रों, नीतिगत संक्षिप्तियां व संबंधित स्थिति रिपोर्टों को तैयार करने पर फोकस किया।

व्यापक मुद्दों पर दृष्टिकोण विकसित करने तथा शिक्षा जगत व नीतिगत समुदाय में इन्हें इन संभाषणों के अनुरूप रखने के लिए विदेश स्थित मिशनों और मंत्रालय के भीतर भी कार्मिकों को समर्थ बनाने के लिए प्रभाग प्रबुद्ध मंडल और शिक्षाविदों द्वारा विभिन्न आयोजित विभिन्न सेमीनारों व

सम्मेलनों के नियमित दैनिक रिपोर्टों को प्रचारित करता है, इसके सारों को जारी करता है और घटनाक्रम संबंधी रिपोर्ट प्रदान करता है।

इस प्रभाग द्वारा की गयी अन्य पहलें निम्नवत् हैं:

- विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर सेमीनार और चर्चाएं आयोजित करने के लिए प्रबुद्ध वर्ग और प्रमुख संस्थाओं के साथ संपर्क करना।
- भारत के विभिन्न भागों में प्रबुद्ध वर्गों द्वारा आयोजित विभिन्न सेमीनारों/ सम्मेलनों में भागीदारी करना। मंत्रालय और विदेश स्थित मिशनों में प्रचार के लिए कार्यवाहियों के मुख्य सार को प्रदान करते हुए रिपोर्टों का मासिक विस्तृत विवरण तैयार करना।
- मंत्रालय में ही दैनिक रिपोर्टों के रूप में अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों संबंधी समाचारों, घटनाओं की निगरानी और समेकन करना।
- विदेश में तैनात हमारे राजदूतों के भारत दौरे तथा भारत आने वाले विशेषज्ञों के प्रसिद्ध विषय वस्तु से विशिष्ट विषयों संबंधी प्रस्तुतिकरण को आयोजित करने के लिए पहल की निरंतरता।
- भारत के राष्ट्रीय हितों तथा महत्वपूर्ण विदेशी नीतिगत मामलों के संबंध में भारत के परिप्रेक्ष्यों को प्रसारित करने के लिए रूचि वाले विषयों पर भारत एवं विदेश स्थित विभिन्न प्रबुद्ध वर्गों, शैक्षिक संस्थाओं के शीर्ष विद्वानों, लेखकों और प्रतिनिधियों से महत्वपूर्ण इनपुट हासिल करने के लिए नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- भारत और अन्य देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा, जिसकी प्रस्तुति राजदूतों द्वारा की जाती है, के बाद नई दिल्ली में तैनात मिशन प्रमुखों द्वारा 'राजदूत व्याख्यान माला'' आयोजित करना।

नीतिगत योजना वार्ताएं

इस प्रभाग ने नीतिगत परिप्रेक्ष्यों और प्राथमिकताओं के संबंध में मूल्यांकनों को साझा करने के लिए कूटनीतिक साझेदारों के साथ नीतिगत योजना वार्ताएं की।

- नई दिल्ली में 09 अक्टूबर, 2018 को जर्मनी के साथ नीतिगत योजना वार्ता।
- नई दिल्ली में 18 जुलाई, 2018 को जापान के साथ नीतिगत योजना वार्ता।
- नई दिल्ली में 4 सितम्बर, 2018 को ईरान के साथ नीतिगत योजना वार्ता।

इस प्रभाग ने फ्रांस, आस्ट्रेलिया, ईस्राइल, जर्मनी, यूके, पोलेंड, दक्षिण कोरिया और जापान से आए शिष्टमंडल के साथ अनौपचारिक नीतिगत योजना परामर्श भी किया।

प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भागीदारी

इस प्रभाग ने भारत-चीन प्रबुद्ध मंडल मंच, भारत-अमेरिकी मंच, वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान (आईडीएसएस) द्वारा पश्चिम एशिया सम्मेलन, योग्यकर्ता, इंडोनेशिया भारत-इंडोनेशिया परस्पर विश्वास वार्ता (03-05 अक्टूबर, 2018) एवं पेरिस शांति मंच में (11-13 नवम्बर, 2018, पेरिस) सहित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भारत की भागीदारी में सहायता की और सुकर बनाया।

इस पीपी एवं आर प्रभाग ने 17वें भारत-कोरिया ट्रेक 1.5 वार्ता (31 अक्टूबर, 2018, सियोल); चौथी भारत-जापान ट्रेक 1.5 वार्ता (15-16 अक्टूबर, 2018, नई दिल्ली), प्रथम भारत-कनाडा ट्रेक 1.5 वार्ता (29 अक्टूबर-02 नवम्बर, 2018, ओटावा) और भारत-पाकिस्तान ट्रेक 2 निमराना वार्ता (28-30 अप्रैल, 2018) सहित ट्रेक 1.5 और ट्रेक 2 परस्पर बातचीत को भी समर्थन दिया।

सम्मेलन, वार्ता, बैठक और सेमीनारों का आयोजन

पीपी एवं आर प्रभाग ने भारत में अलग-अलग स्थानों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और सेमीनारों को आयोजित करने के लिए भारतीय प्रबुद्ध वर्ग के साथ अपना कार्य आगे बढ़ाया। इस प्रभाग द्वारा आयोजित सेमीनारों, सम्मेलनों, बैठकों और आंशिक या पूर्ण रूपेण वित्तपोषित अध्ययनों की सूची परिशिष्ट चार में दी गयी है।

पर्यवेक्षक अनुसंधान प्रतिष्ठान (ओआरएफ) के साथ साझेदारी में पीपी एवं आर प्रभाग द्वारा आयोजित ध्वजवाहक भू-राजनीतिक और भू-नीतिगत सम्मेलन विदेश मंत्रालय (एमईए) का रायसीना वार्ता है। रायसीना वार्ता का चौथा संस्करण 8-10 जनवरी, 2018 को आयोजित किया गया जिसका विषय था ''वर्ल्ड रिआर्डर: न्यू जियोमैट्री, फ्लुड पार्टनरशिप, अंसर्टेन आउटकम।'' इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज की उपस्थिति में नार्वे की प्रधानमंत्री सुश्री एमा सोलबर्ग द्वारा 8 जनवरी, 2019 को किया गया था। बानवे देशों के लगभग 600 से अधिक शिष्टमंडलों ने इस इस वार्ता में भागीदारी की।

हिंद महासागर सम्मेलन का तीसरा संस्करण 27 और 28 अगस्त, 2018 को हनोई, वियतनाम में आयोजित किया गया था। इसकी साझेदार संस्था थीं- भारतीय प्रतिष्ठान, कूटनीतिक एकेडमी आफ वियतनाम, एस. राजारत्नम स्कूल आफ इंटरनेशनल स्टडीज (आरएसआईएस), श्रीलंका एवं बांग्लादेश इंस्टीच्युट आफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज। इसका विषय था- ''बिल्डिंग रीजनल आर्किटेक्चर'' तथा इस सम्मेलन का उद्घाटन विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज और उनके वियतनामी समकक्ष फाम बिन्ह मिन, उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री द्वारा किया गया ।

भारत- अमेरिकी मंच का दूसरा संस्करण 6 और 7 अप्रैल, 2018 को अनंता केन्द्र के सहयोग से इस प्रभाग द्वारा आयोजित किया गया। इस मंच में भारत-अमेरिकी साझेदारी के विभिन्न आयामों पर चर्चा करने के लिए संसद सदस्यों और अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों, कारोबारियों व राजनीतिक नेताओं, प्रसिद्ध मीडिया कर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों और प्रबुद्ध नेताओं सहित कई भागीदारों को एक साथ लाया गया।

इसमें राजनीतिक और व्यापारिक संबंधों, सुरक्षा सहयोग व नवोन्मेषी, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण व ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख मुद्दों पर बातचीत की गयी।

मानव और वित्तीय संसाधनों की वृद्धि

पीपी एवं आर प्रभाग ने अपने संसाधनों को मजबूत बनाने के लिए सतत कार्य किया है। इस वर्ष 2018-19 में सेमीनारों और सम्मेलनों के आयोजन के लिए वित्तीय परिव्यय में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी देखी गयी और इस प्रकार पीपी एवं आर प्रभाग यथा उल्लिखित अपने कार्यकलापों के विस्तार में समर्थ हो सका। इस प्रभाग में परामर्शदाताओं की संख्या अब सात हैं।

20

प्रोटोकॉल

प्रोटोकॉल प्रभाग में कुल सात अनुभाग शामिल हैं। प्रोटोकॉल-1, प्रोटोकॉल- II, प्रोटोकॉल- III, प्रोटोकॉल (हैदराबाद हाउस), प्रोटोकॉल विशेष, प्रोटोकॉल (आतिथ्य और लेखा) और सरकारी आतिथ्य संगठन (जीएचओ)।

प्रोटोकॉल I अनुभाग, **प्रोटोकॉल** के उप प्रमुखों (सेरेमोनियल) के तहत राष्ट्राध्यक्षों/सरकार प्रमुखों, उप-राष्ट्रपतियों और विदेश मंत्री की भारत यात्राओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधान मंत्री की विदेश यात्राओं, मनोरंजन (दोपहर, रात्रि का आधिकारिक भोज और विदेश मंत्रालय की ओर से स्वागत) और औपचारिक समारोह, एयरपोर्ट पास, समारोह और रिजर्व लाउंज तक पहुंच आदि का कार्य संभालता है।

प्रोटोकॉल- II और **प्रोटोकॉल विशेष** अनुभाग, उप-प्रमुख प्रोटोकॉल (विशेषाधिकार) के प्रभार के तहत दोनों अनुभाग, भारत से बाहर स्थित राजनयिक मिशनों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संभालते हैं जैसे कि दिल्ली में और देश के विभिन्न राज्यों में विदेशी प्रतिनिधियों के संबंध में राजनयिक / आधिकारिक पहचान पत्र जारी करना; लाभकारी रोजगार के लिए करार को अंतिम रूप देना और बाद में, भारत में राजनयिक मिशनों और कौंसुली केंद्रों के सदस्यों के परिवार के सदस्यों के लिए लाभकारी रोजगार की अनुमति के लिए अनुरोध पर कार्रवाई; भारतीय विश्वविद्यालयों में नामांकन के लिए विदेशी राजनयिकों को अनुमति; भारत में विदेशी प्रतिनिधियों और उनके आवासों की सुरक्षा व्यवस्था; संयुक्त राष्ट्र (पी एंड आई) अधिनियम, 1947 के अनुच्छेद 3 के तहत मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों; पारस्परिकता के सिद्धांत पर कर छूट से संबंधित मुद्दे; भारत में राजनयिकों / अधिकारियों और राजनयिक मिशनों के संबंध में विभिन्न अदालतों द्वारा जारी किए गए अदालत के समन को अग्रेषित करना और मोटर वाहनों की खरीद / पंजीकरण / बिक्री और कस्टम ड्यूटी मुक्त आयात के अनुरोधों पर आगे की कार्रवाई करना।

प्रोटोकॉल- III अनुभाग के कार्य क्षेत्र में राष्ट्रीय दिवसों पर संदेशों और संप्रेषणों का आदान-प्रदान, प्रत्यय-पत्रों की

प्रस्तुति की व्यवस्था, भारत में नए कौंसुल जनरल के साथ-साथ मानद कौंसुल की नियुक्ति; मिशनों के प्रमुखों के क्रेडेंशियल दस्तावेजों को तैयार करना और कौंसुल जनरल की नियुक्ति करना; विदेशी राजनयिक मिशनों के प्रमुखों के आगमन और अंतिम रूप से प्रस्थान की व्यवस्था; भारत में विदेशी राजनयिक मिशनों / केंद्रों में नए पदों (सिविल और रक्षा) के सृजन के लिए अनुमति; भारत में राजनयिक मिशनों के लिए हवाई अड्डे पास के लिए हवाई अड्डे के अधिकारियों को पत्र जारी करना; स्वतंत्रता दिवस पर एक साथ भाषांतरण के साथ-साथ अन्य व्यवस्थाएं करना जैसे गणतंत्र दिवस और बीटिंग रिट्रीट समारोहों के दौरान की गई व्यवस्थाओं के अलावा मिशन प्रमुखों और अन्य राजनयिक अधिकारियों को निमंत्रण; विदेशी राजनयिक मिशनों में काम करने वाले स्थानीय कर्मचारियों से प्राप्त अदालती मामलों और शिकायतों को संभालना; नई दिल्ली में राजनयिक मिशनों के राष्ट्रीय दिवसों और अन्य संबंधित प्रोटोकॉल कार्यों के लिए मुख्य अतिथियों के नामांकन की व्यवस्था देखना शामिल है।

प्रोटोकॉल हाउसिंग अनुभाग केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के बागवानी, सिविल और इलेक्ट्रिकल विंग के सहयोग से हैदराबाद हाउस के रखरखाव और समारंक्षण के लिए जिम्मेदार है। इसमें इलेक्ट्रिकल / सिविल / बागवानी की मरम्मत और रखरखाव कार्य शामिल हैं। इसके अलावा, यह अनुभाग उनके प्रशासनिक, प्रबंधन और परिचालन व्यय के कारण आईटीडीसी को भुगतान संबंधी कार्रवाई का कार्य भी देखता है; दिल्ली में सभी राजनयिक मिशनों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के संबंध में भूमि की खरीद / बिक्री / आवंटन, निर्मित संपत्ति, पट्टे आदि से संबंधित मामले जिसमें भूमि आवंटन के लिए राज्य सरकारों के साथ पत्रव्यवहार, स्थायी पट्टा विलेख आदि पर हस्ताक्षर करना शामिल है; दिल्ली और अन्य राज्यों में भूस्वामियों और राजनयिक मिशनों के बीच विवाद / अदालती मामले; सैन्य इंजीनियरिंग सेवा (एमईएस) और सीपीडब्ल्यूडी की सहायता से वायु सेना स्टेशन, पालम में वीवीआईपी रिसेप्टोरियम चलाना और प्रचालन तथा एनडीएमसी, एमसीडी, डीडीए, एमटीएनएल इत्यादि जैसी सेवाओं के संबंध में राजनयिक

मिशनों की सहायता करना। इसके अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों में यह अनुभाग नई दिल्ली के द्वारका में आगामी दूसरी डिप्लोमैटिक एन्क्लेव परियोजना पर विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय कर रहा है।

2018 में, प्रोटोकॉल-I अनुभाग ने राष्ट्राध्यक्षों, उपराष्ट्रपति, शासनाध्यक्ष और विदेश मंत्री के स्तर पर 151 भारत की / विदेशी यात्राओं का कार्य संभाला (03 दिसंबर 2018 तक)।

प्रभाग ने जनवरी 2018 में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन (एआईसीएस 2018) और मार्च 2018 में भारतीय सौर गठबंधन (आईएसए 2018) को समन्वित किया।

इसके अलावा, प्रोटोकॉल-I ने 317 मनोरंजन समारोहों (03 दिसंबर 2018 को) का संचालन किया और हवाई अड्डा पास, लाउंज (औपचारिक और आरक्षित) और फ्रिस्किंग से छूट की सुविधा के लिए प्रति सप्ताह औसतन 139 अनुरोधों पर कार्रवाई की।

यात्राओं का वर्गीकरण और संख्या

दौरा शीर्ष	संख्या
राष्ट्राध्यक्ष/शासनाध्यक्ष/उप राष्ट्रपति और समकक्ष गणमान्य व्यक्तियों की राजकीय यात्राएं	13
राष्ट्राध्यक्ष/शासनाध्यक्ष/उपराष्ट्रपति और समकक्ष गणमान्य व्यक्तियों की आधिकारिक/कामकाजी यात्राएं	53
राष्ट्राध्यक्ष/शासनाध्यक्ष/उपराष्ट्रपति और समकक्ष गणमान्य व्यक्तियों की निजी/ट्रांजिट यात्राएं	4
विदेश मंत्रियों और समकक्षों द्वारा आधिकारिक यात्राएं	37
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधान मंत्री की विदेश यात्राएं	26
विदेश मंत्री की विदेश यात्राएं	18
कुल	**151**

यात्राओं का कैलेंडर

राष्ट्राध्यक्ष/शासनाध्यक्ष/उप राष्ट्रपति और समकक्ष गणमान्य व्यक्तियों की राजकीय यात्राएं

क्रम सं.	गणमान्य अतिथि	तारीख
1.	इज़राइल के प्रधानमंत्री की राजकीय यात्रा	14-17 जनवरी 2018
2.	कंबोडिया के प्रधानमंत्री की राजकीय यात्रा	24-28 जनवरी 2018
3.	कनाडा के प्रधानमंत्री की राजकीय यात्रा	17-24 फरवरी 2018
4.	ईरान इस्लामी गणतंत्र के राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा	15-17 फरवरी 2018
5.	जॉर्डन सम्राट की राजकीय यात्रा	28 फरवरी -2 मार्च 2018

6.	वियतनाम के राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा	02-04 मार्च 2018
7.	फ्रांस के राष्ट्रपति का राजकीय दौरा	09-12 मार्च 2018
8.	जर्मनी के राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा	22-26 मार्च 2018
9.	नेपाल के प्रधान मंत्री की राजकीय यात्रा	06-08 अप्रैल 2018
10.	सेशेल्स के राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा	22-27 जून 2018
11.	कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा	08-11 जुलाई 2018
12.	उजबेकिस्तान के राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा	30 सितंबर -01अक्टूबर 2018
13.	मालदीव के राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा	17-18 दिसंबर 2018
14.	भूटान के प्रधान मंत्री की राजकीय यात्रा	27-29 दिसंबर 2018

राष्ट्राध्यक्ष / शासनाध्यक्ष / उपराष्ट्रपति तथा समकक्षियों के आधिकारिक / कामकाजी दौरे

क्र. सं०	गणमान्य व्यक्ति	दिनांक
1.	लाओ पीडीआर (आसियान - भारत स्मारक शिखर सम्मेलन) के प्रधानमंत्री का दौरा	25-26 जनवरी, 2018
2.	वियतनाम के प्रधान मंत्री (आसियान - भारत स्मारक सम्मेलन) का दौरा	25-26 जनवरी 2018
3.	थाईलैंड के प्रधान मंत्री (आसियान - भारत स्मारक सम्मेलन) का दौरा	25-26 जनवरी 2018
4.	म्यांमार के स्टेट काउंसलर (आसियान - भारत स्मारक सम्मेलन) का दौरा	25-26 जनवरी 2018
5.	मलेशिया के प्रधान मंत्री (आसियान - भारत स्मारक सम्मेलन) का दौरा	25-26 जनवरी 2018
6.	इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का दौरा (आसियान - भारत स्मारक सम्मेलन)	25-26 जनवरी 2018
7.	फिलीपींस के राष्ट्रपति का दौरा (आसियान - भारत स्मारक सम्मेलन)	25-26 जनवरी 2018
8.	ब्रुनेई के सुल्तान का दौरा (आसियान - भारत स्मारक सम्मेलन)	25-26 जनवरी 2018
9.	सिंगापुर के प्रधान मंत्री (आसियान - भारत स्मारक सम्मेलन) का दौरा	25-26 जनवरी 2018
10.	कंबोडिया के प्रधान मंत्री का दौरा (आसियान - भारत स्मारक सम्मेलन)	25-26 जनवरी 2018
11.	भूटान के प्रधान मंत्री का दौरा	01-04 फरवरी 2018
12.	आगा खान का दौरा	20 फरवरी से 1 मार्च 2018
13.	बांग्लादेश के राष्ट्रपति का दौरा	12 मार्च 2018

क्र. सं०	गणमान्य व्यक्ति	दिनांक
14.	इक्वेटोरियल गिनी (आईएसए समिट) के राष्ट्रपति का दौरा	10-11 मार्च 2018
15.	जिबूती (आईएसए शिखर सम्मेलन) के राष्ट्रपति का दौरा	10-11 मार्च 2018
16.	रवांडा (आईएसए शिखर सम्मेलन) के राष्ट्रपति का दौरा	10-11 मार्च 2018
17.	टोगो के राष्ट्रपति (आईएसए शिखर सम्मेलन) का दौरा	10-11 मार्च 2018
18.	गैबॉन (आईएसए शिखर सम्मेलन) के राष्ट्रपति का दौरा	10-11 मार्च 2018
19.	नाइजर के राष्ट्रपति (आईएसए शिखर सम्मेलन) का दौरा	10-11 मार्च 2018
20.	वेनेजुएला (आईएसए शिखर सम्मेलन) के राष्ट्रपति का दौरा	10-11 मार्च 2018
21.	बांग्लादेश के राष्ट्रपति (आईएसए शिखर सम्मेलन) का दौरा	10-11 मार्च 2018
22.	नौरू (आईएसए शिखर सम्मेलन) के राष्ट्रपति का दौरा	10-11 मार्च 2018
23.	माली के राष्ट्रपति (आईएसए शिखर सम्मेलन) का दौरा	10-11 मार्च 2018
24.	ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल (आईएसए शिखर सम्मेलन) का दौरा	10-11 मार्च 2018
25.	श्रीलंका के राष्ट्रपति की यात्रा (आईएसए शिखर सम्मेलन)	10-11 मार्च 2018
26.	गुयाना के राष्ट्रपति (आईएसए शिखर सम्मेलन) का दौरा	10-11 मार्च 2018
27.	बुर्किना फ़ासो (आईएसए शिखर सम्मेलन) के राष्ट्रपति का दौरा	10-11 मार्च 2018
28.	कोमोरोस (आईएसए शिखर सम्मेलन) के राष्ट्रपति का दौरा	10-11 मार्च 2018
29.	सेशेल्स के राष्ट्रपति (आईएसए शिखर सम्मेलन) का दौरा	10-11 मार्च 2018
30.	घाना के राष्ट्रपति (आईएसए शिखर सम्मेलन) का दौरा	10-11 मार्च 2018
31.	घाना के राष्ट्रपति (आईएसए शिखर सम्मेलन) का दौरा	10-11 मार्च 2018
32.	तुवालु के प्रधान मंत्री की यात्रा (आईएसए शिखर सम्मेलन)	10-11 मार्च 2018
33.	फिजी के प्रधान मंत्री की यात्रा आईएसए शिखर सम्मेलन)	10-11 मार्च 2018
34.	वानुअतु (आईएसए शिखर सम्मेलन) के प्रधान मंत्री की यात्रा	10-11 मार्च 2018
35.	चाड के प्रधान मंत्री की यात्रा (आईएसए शिखर सम्मेलन)	10-11 मार्च 2018
36.	कोटे डी आइवर (आईएसए शिखर सम्मेलन) के उप राष्ट्रपति का दौरा	10-11 मार्च 2018
37.	सूरीनाम (आईएसए शिखर सम्मेलन) के उप राष्ट्रपति का दौरा	10-11 मार्च 2018

क्र. सं०	गणमान्य व्यक्ति	दिनांक
38.	अबू धाबी (आईएसए शिखर सम्मेलन) के क्राउन प्रिंस का दौरा	10-11 मार्च 2018
39.	नीदरलैंड के प्रधान मंत्री की यात्रा	24-25 मई 2018
40.	बांग्लादेश के प्रधान मंत्री की यात्रा	25-26 मई 2018
41.	समावेशी विकास हेतु महासचिव के विशेष अधिवक्ता के रूप में नीदरलैंड की रानी मैक्सिमा (यूएनएसजीएसए) का दौरा	28-30 मई 2018
42.	भूटान के प्रधान मंत्री का दौरा	05-07 जुलाई 2018
43.	नेपाल के पूर्व प्रधान मंत्री का दौरा	06-09 सितंबर 2018
44.	श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति का दौरा	10-13 सितंबर 2018
45.	अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का दौरा	19 सितंबर 2018
46.	भूटान नरेश का दौरा (पूर्व प्रधान मंत्री का निधन)	
47.	भूटान की राज माता का दौरा	21-24 सितंबर 2018
48.	रूस के राष्ट्रपति का दौरा	04-05 अक्टूबर 2018
49.	श्रीलंका के प्रधान मंत्री का दौरा	19-21 अक्टूबर 2018
50.	इटली के प्रधान मंत्री का दौरा	29-30 अक्टूबर 2018
51.	दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला की यात्रा	04-07 नवंबर 2018
52.	दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति का दौरा	16-19 नवंबर 2018
53.	थाईलैंड की महामान्या राजकुमारी की यात्रा	25-30 नवंबर 2018

राष्ट्राध्यक्ष / शासनाध्यक्ष / उपराष्ट्रपति तथा समकक्षियों द्वारा निजी/ट्रांजिट यात्राएं

क्र. सं०	गणमान्य व्यक्ति	दिनांक
1.	मोजाम्बिक के प्रधान मंत्री का दौरा	18-23 जून 2018
2.	श्रीलंका के प्रधान मंत्री का दौरा	02-03 अगस्त 2018
3.	श्रीलंका के राष्ट्रपति का दौरा	29 अगस्त -02 सितंबर 2018
4.	लेसोथो के प्रधान मंत्री की यात्रा	29 अक्टूबर - 05 नवंबर 2018

विदेश मंत्रियों और समकक्षों के आधिकारिक दौरे

क्र. सं०	गणमान्य व्यक्ति	दिनांक
1.	मालदीव के विदेश मंत्री का दौरा	10-12 जनवरी 2018
2.	जॉर्जिया और संयुक्त अरब अमीरात के पीआर का दौरा	14-17 जनवरी 2018
3.	बांग्लादेश के विदेश मंत्री का दौरा	16-19 जनवरी 2018
4.	गुयाना के विदेश मंत्री का दौरा	29 जनवरी-- 02 फरवरी 2018
5.	संयुक्त राष्ट्र के पीआर का दौरा (समूह 2)	04-10 फरवरी 2018
6.	उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्री का दौरा	11-12 फरवरी 2018
7.	भूटान के विदेश मंत्री का भ्रमण	20-23 फरवरी 2018
8.	कनाडा के विदेश मंत्री का दौरा	21-24 फरवरी 2018
9.	माल्टा के विदेश मंत्री का दौरा	05-08 मार्च 2018
10.	मिस्र के विदेश मंत्री का दौरा	22-24 मार्च 2018
11.	प्रधान मंत्री और सर्बिया के विदेश मंत्री का दौरा	01-04 मई 2018
12.	शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव का दौरा	07-08 मई 2018
13.	इथियोपिया के विदेश मंत्री का दौरा	09-10 मई 2018
14.	ईरान के विदेश मंत्री का दौरा	28 मई 2018
15.	संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री का दौरा	24-30 जून 2018
16.	घाना के विदेश मंत्री का दौरा	16-19 जुलाई 2018
17.	सिंगापुर के विदेश मंत्री की यात्रा (दिल्ली संवाद)	17-20 जुलाई 2018
18.	म्यांमार के विदेश मंत्री (दिल्ली संवाद) की यात्रा	18-20 जुलाई 2018
19.	स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री का दौरा	09-12 अगस्त 2018
20.	संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्वाचित अध्यक्ष की यात्रा	10-14 अगस्त 2018
21.	मोल्दोवा के विदेश मंत्री का दौरा	11-14 अगस्त 2018
22.	संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधियों का दौरा	22-28 अगस्त 2018
23.	संयुक्त राज्य अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दौरा	04-06 सितंबर 2018

क्र. सं०	गणमान्य व्यक्ति	दिनांक
24.	साओ टोम और प्रिंसिपे के विदेश मंत्री का दौरा	07-08 सितंबर 2018
25.	नेपाल के विदेश मंत्री का दौरा (पूर्व प्रधान मंत्री का निधन)	
26.	अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति का दौरा (पूर्व प्रधानमंत्री का निधन)	
27.	पाकिस्तान के कानून मंत्री का दौरा (पूर्व प्रधान मंत्री का निधन)	
28.	श्रीलंका के कार्यवाहक विदेश मंत्री का दौरा (पूर्व प्रधान मंत्री का निधन)	
29.	संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का दौरा	01-04 अक्टूबर 2018
30.	बांग्लादेश के विदेश मंत्री का दौरा (पूर्व प्रधान मंत्री का निधन)	
31.	तंजानिया के विदेश मंत्री का दौरा	13-17 अक्टूबर 2018
32.	क्रोएशिया के विदेश मंत्री का दौरा	20-22 अक्टूबर 2018
33.	दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला की यात्रा	04-07 नवंबर 2018
34.	रोमानिया के विदेश मंत्री का दौरा	24-27 नवंबर 2018
35.	मालदीव के विदेश मंत्री का दौरा	24-27 नवंबर 2018
36.	गैबॉन के विदेश मंत्री का दौरा	28-30 नवंबर 2018
37.	मोजाम्बिक के विदेश मंत्री का दौरा	28 नवंबर- 02 दिसंबर 2018

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के विदेश दौरे

क्र. सं०	गणमान्य व्यक्ति	दिनांक
1.	प्रधान मंत्री का स्विट्जरलैंड (डब्ल्यूईएफ) दौरा	22-23 जनवरी 2018
2.	प्रधान मंत्री की जॉर्डन, फिलिस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान यात्रा	09-12 फरवरी 2018
3.	राष्ट्रपति का मॉरीशस और मेडागास्कर दौरा	11-15 मार्च 2018
4.	राष्ट्रपति के इक्वेटोरियल गिनी, एस्वतिनी और जाम्बिया के दौरे	07-12 अप्रैल 2018
5.	प्रधान मंत्री की स्वीडन, ब्रिटेन और जर्मनी यात्रा	16-21 अप्रैल 2018
6.	प्रधान मंत्री की वुहान, चीन यात्रा	26-28 अप्रैल 2018
7.	उपराष्ट्रपति के ग्वाटेमाला, पनामा और पेरू दौरे	06-12 मई 2018

क्र. सं०	गणमान्य व्यक्ति	दिनांक
8.	प्रधान मंत्री की काठमांडू यात्रा	11-12 मई 2018
9.	प्रधान मंत्री की रूस (सोची) यात्रा	20-21 मई 2018
10.	प्रधान मंत्री की इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर यात्रा	29 मई - 02 जून 2018
11.	प्रधान मंत्री की किंगदाओ, चीन यात्रा	09-10 जून 2018
12.	राष्ट्रपति की ग्रीस, सूरीनाम और क्यूबा यात्रा	16-25 जून 2018
13.	प्रधान मंत्री की रवांडा, युगांडा और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) यात्रा	23-27 जुलाई, 2018
14.	राष्ट्रपति की साइप्रस, बुल्गारिया और चेक गणराज्य यात्रा	02-09 सितंबर 2018
15.	प्रधान मंत्री की नेपाल यात्रा (बिम्सटेक समिट)	30-31 अगस्त 2018
16.	उपराष्ट्रपति का संयुक्त राज्य अमेरिका दौरा	08-09 सितंबर 2018
17.	उपराष्ट्रपति की सर्बिया, माल्टा और रोमानिया यात्रा	14-20 सितंबर 2018
18.	राष्ट्रपति का ताजिकिस्तान दौरा	07-09 अक्टूबर 2018
19.	उपराष्ट्रपति का बेल्जियम दौरा	17-20 अक्टूबर 2018
20.	प्रधान मंत्री की टोक्यो और जापान की यमाकाशी यात्रा	27-30 अक्टूबर 2018
21.	उपराष्ट्रपति का बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मलावी दौरा	31 अक्टूबर - 06 नवंबर 2018
22.	फ्रांस के उपराष्ट्रपति का दौरा (शस्त्रागार शताब्दी और पेरिस शांति मंच)	09-11 नवंबर 2018
23.	प्रधानमंत्री की सिंगापुर यात्रा	14-15 नवंबर 2018
24.	प्रधान मंत्री की मालदीव यात्रा	17 नवंबर 2018
25.	राष्ट्रपति का ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम दौरा	18-24 नवंबर 2018
26.	अर्जेंटीना के प्रधान मंत्री की यात्रा (जी -20)	28 नवंबर - 02 दिसंबर 2018

विदेश मंत्री के विदेश दौरे

1.	थाईलैंड, इंडोनेशिया और सिंगापुर	04-08 जनवरी 2018
2.	नेपाल	01-02 फरवरी 2018
3.	सऊदी अरब	06- 08 फरवरी 2018
4.	जापान	28-30 मार्च 2018

5.	आज़रबाइजान	04- 06 अप्रैल 2018
6.	चीन	21-24 अप्रैल 2018
7.	मंगोलिया	25-26 अप्रैल 2018
8.	म्यांमार	10-11 मई 2018
9.	दक्षिण अफ्रीका	03-07 जून 2018
10.	इटली, फ्रांस, लक्समबर्ग और बेल्जियम	17-23 जून 2018
11.	मनामा, बहरीन	14-15 जुलाई 2018
12.	कजाकिस्तान गणराज्य, किर्गिज़ गणराज्य और उजबेकिस्तान गणराज्य	02- 05 अगस्त 2018
13.	वियतनाम और कंबोडिया	27-30 अगस्त 2018
14.	मास्को, रूस	13-14 सितंबर 2018
15.	न्यूयॉर्क, यूएसए	22-27 सितंबर 2018
16.	तजाकिस्तान	11-12 अक्टूबर 2018
17.	कतर और कुवैत	28-31 अक्टूबर 2018
18.	लाओ पीडीआर	22-23 नवंबर 2018

1 अप्रैल 2018 से 30 नवंबर 2018 के दौरान विदेशी मिशन प्रमुखों द्वारा प्रत्यय पत्र प्रस्तुति

क्र.सं.	देश	राजदूत/उच्चायुक्त का नाम	क्रेडेंशियल प्रस्तुति की तारीख
1.	बहरीन	राजदूत श्री अब्दुलरहमान मोहम्मद अहमद अल गौड	17 अप्रैल 2018
2.	लेबनान	राजदूत श्री राबी नार्स	17 अप्रैल 2018
3.	अर्जेंटीना	राजदूत श्री डैनियल चुबुरू	17 अप्रैल 2018
4.	इराक	राजदूत डॉ. फलाह अब्दुलहसन अब्दुलसदा	17 अप्रैल 2018
5.	आज़रबाइजान	राजदूत श्री अशरफ फरहाद शिखलियाव	31 मई 2018
6.	लिसोटो	उच्चायुक्त श्री बोथाटा साइकोने	31 मई 2018

क्र.सं.	देश	राजदूत/उच्चायुक्त का नाम	क्रेडेंशियल प्रस्तुति की तारीख
7.	साइप्रस	उच्चायुक्त श्री एगीस लोइज़ौ	31 मई 2018
8.	समोआ (अनिवासी)	उच्चायुक्त सुश्री फ़लावाउ पेरीना जैकलीन सिला-तुआलूलेई	31 मई 2018
9.	जमैका (अनिवासी)	उच्चायुक्त सीनेटर ऑबिन हिल	31 मई 2018
10.	स्लोवाक गणराज्य	राजदूत श्री इवान लांसरिक	11 जुलाई 2018
11.	एल साल्वाडोर	राजदूत श्री एरियल एंड्रेड गैलिंडो	11 जुलाई 2018
12.	इक्वेडोर	राजदूत श्री हेक्टर क्यूवा जैकोम	11 जुलाई 2018
13.	उरुग्वे	राजदूत श्री अल्वारो ए. माल्मिर्का	11 जुलाई 2018
14.	फ़िजी	उच्चायुक्त श्री योगेश पुंजा	11 जुलाई 2018
15.	केन्या	उच्चायुक्त श्री विली किपकिर बेट	11 जुलाई 2018
16.	आइसलैंड	राजदूत श्री गुडमुंदुर अरनी स्टीफेंसन	20 सितंबर 2018
17.	नीदरलैंड	राजदूत श्री मार्टन वैन डेन बर्ग	20 सितंबर 2018
18.	गिन्नी	उच्चायुक्त श्रीमती फतौमाता बाल्दे	20 सितंबर 2018
19.	लिथुआनिया	राजदूत मिस्टर जूलियस प्रणवीसियस	20 सितंबर 2018
20.	लक्समबर्ग	राजदूत श्री जीन क्लाउड कूगनर	20 सितंबर 2018
21.	कुवैत	राजदूत श्री जसीम इब्राहिम जेएम अल-नजीम	18 अक्टूबर 2018
22.	बेल्जियम	राजदूत श्री फ्रांस्वा डेल्हे	18 अक्टूबर 2018
23.	पुर्तगाल	राजदूत श्री कार्लोस जोस डे पिन्हो ई मेलो परेरा मार्केस	18 अक्टूबर 2018
24.	कंबोडिया	राजदूत श्री उंग सीन	18 अक्टूबर 2018
25.	वियतनाम	राजदूत श्री फाम सनाह चौ	13 नवंबर 2018
26.	लातविया	राजदूत श्री आर्टिस बर्टुलिस	13 नवंबर 2018
27.	जॉर्डन	राजदूत श्री मोहम्मद सलाम जमील वायुसेना अल-कायद	13 नवंबर 2018
28.	श्री लंका	उच्चायुक्त श्री ऑस्टिन फर्नांडो	13 नवंबर 2018

1 अप्रैल, 2018 से 30 नवंबर, 2018 के बीच विदेशी मिशन प्रमुखों की अंतिम प्रस्थान से संबंधित स्थिति

क्र.सं.	मिशन	मिशन के प्रमुख का नाम	अंतिम प्रस्थान की तारीख
1.	मैसेडोनिया	राजदूत डॉ. टोनी अटानासोवस्की	04 अप्रैल 2018
2.	साइप्रस	उच्चायुक्त श्री डेमेट्रियोस थियोफिलैक्टौ	05 मई 2018
3.	स्लोवाक गणराज्य	राजदूत श्री जिग्मुंड बर्टोक	20 मई 2018
4.	केन्या	उच्चायुक्त श्रीमती फ्लोरेंस इमीसा वीच	04 जुलाई 2018
5.	कंबोडिया	राजदूत श्री पिचखुन पाहा	27 जुलाई 2018
6.	कुवैत	राजदूत श्री फहद अहमद अलावदी	31 जुलाई 2018
7.	इजराइल	राजदूत श्री डैनियल कार्मोन	31 जुलाई 2018
8.	बेल्जियम	राजदूत श्री जान लुयुक्स	30 अगस्त 2018
9.	लक्समबर्ग	राजदूत श्री सैम श्राइनर	31 अगस्त 2018
10.	बोस्निया और हर्जेगोविना	राजदूत डॉ. सबित सुबासिक	01 सितंबर 2018
11.	जॉर्डन	राजदूत श्री हसन महमूद मोहम्मद अल जवारनेह	01 सितंबर 2018
12.	पुर्तगाल	राजदूत श्री जोआओ दा केमरा	11 सितंबर 2018 / स्वयं
13.	अफ़ग़ानिस्तान	राजदूत डॉ. शैदा मोहम्मद अब्दाली	22 सितंबर 2018
14.	वियतनाम	राजदूत श्री टन सिंह थान	29 सितंबर 2018
15.	बुल्गारिया	राजदूत श्री पेटको डॉयकोव	29 सितंबर 2018
16.	लातविया	राजदूत श्री ऐवरस ग्रोज़ा	13 अक्टूबर 2018 / स्वयं
17.	मिस्र	राजदूत श्री हेटम एल्सयेद मोहम्मद टैगेलिन	26 अक्टूबर 2018
18.	तजाकिस्तान	राजदूत श्री मिर्ज़ोफ़रीफ़ जलोलोव	26 अक्टूबर 2018
19.	नामीबिया	उच्चायुक्त श्री पायस दुनीस्की	28 अक्टूबर 2018
20.	श्री लंका	उच्चायुक्त श्रीमती चित्रानी वागीश्वर	31 अक्टूबर 2018
21.	लाओ पीडीआर	राजदूत श्री साउथम सकोनहिनहोम	09 नवंबर 2018
22.	ब्राजील	राजदूत श्री तोवर दा सिल्वा नून्स	15 नवंबर 2018
23.	मालदीव	राजदूत श्री अहमद मोहम्मद	24 नवंबर 2018

1 अप्रैल, 2018 से 30 नवंबर, 2018 तक अनुमोदित रेजिडेंट मिशनों / व्यापार कार्यालयों / वाणिज्य दूतावासों / उप उच्च आयोगों / मानद कौंसुलों की सूची

- **रेजिडेंट मिशन:** मॉल्दोवा
- **व्यापार कार्यालय:**

  1. कोरिया गणराज्य अहमदाबाद

- **सांस्कृतिक केंद्र:**

  1. डेनमार्क - नई दिल्ली

- **महाकौंसुल/ उप उच्च आयोग**

  1. ऑस्ट्रेलिया - कोलकाता
  2. संयुक्त अरब अमीरात - मुंबई

- **मानद महाकौंसुलावास / मानद कौंसुलावास:**

  1. बेल्जियम - कोलकाता
  2. कोलंबिया - बेंगलुरु
  3. चेक गणराज्य - मुंबई
  4. ब्राजील - हैदराबाद
  5. आयरलैंड - कोलकाता
  6. कजाकिस्तान - मुंबई
  7. नाइजर - कोलकाता
  8. चिली - मुंबई
  9. फिजी - कोलकाता
  10. मलावी - मुंबई
  11. लक्समबर्ग - मुंबई
  12. चेक गणराज्य - बेंगलुरु
  13. ग्वाटेमाला - कोलकाता
  14. रोमानिया - चेन्नई
  15. माली - मुंबई
  16. चेक गणराज्य - चेन्नई
  17. इंडोनेशिया - कोलकाता

1 अप्रैल, 2018 से 30 नवंबर, 2018 तक भारत में विदेशी राजनयिक मिशनों में नव सृजित पदों की माहवार सूची:-

01 अप्रैल 2018 - 30 नवंबर 2018 तक नए पदों के सृजन के लिए वार्षिक रिपोर्ट	
अप्रैल	07
मई	21
जून	02
जुलाई	12
अगस्त	11
सितंबर	11
अक्टूबर	09
नवंबर	00
कुल	73

21

वाणिज्य दूतावास, पासपोर्ट और वीजा सेवा

पासपोर्ट सेवाएं

मंत्रालय का वाणिज्य दूतावास, पासपोर्ट और वीजा (सीपीवी) प्रभाग भारत और विदेश में पासपोर्ट सेवाएं मुहैया कराता है। पासपोर्ट को जारी करना मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली सबसे उल्लेखनीय सांविधानिक और नागरिक केन्द्रित सेवाओं में से एक है। तदनुसार हीं, मंत्रालय ने देश में पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने में कई गुणात्मक और परिमाणात्मक सुधार किए हैं। भारतीय पासपोर्ट (पहचान प्रमाणपत्र, भारत में वापस आने वालों के लिए आपातकालीन प्रमाणपत्र, पुलिस अनुमति प्रमाणपत्र और जम्मू एवं कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर यात्रा अनुमति जैसे अन्य यात्रा दस्तावेजों सहित) को विदेश मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (सीपीओ) और इसके भारत भर में फैले छत्तीस पासपोर्ट कार्यालयों, सीपीवी प्रभाग (केवल कूटनीतिक और सरकारी पासपोर्टों) और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन के माध्यम से जारी किया जाता है। इस नेटवर्क का सरकारी - निजी भागीदारी (पीपीपी) तरीके में तेरानवे पासपोर्ट सेवा केन्द्रों (पीएसके) तथा 263 डाकघर पासपोर्ट सेवा केन्द्र (पीओपीएसके) (डाक विभाग के सहयोग से), पासपोर्ट कार्यालय के विस्तारित रूप में, व्यापक विस्तार किया गया है। दिनांक 2 जनवरी, 2019 तक ऐसे 356 पासपोर्ट केन्द्र कार्यरत हैं। विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए विदेश स्थित 184 भारतीय दूतावासों / वाणिज्य दूतावासों द्वारा पासपोर्ट और आपातकालीन प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।

पासपोर्ट सेवा परियोजना

पासपोर्ट सेवा परियोजना (पीएसपी), एक महत्वाकांक्षी मिशन मोड परियोजना है, जिसे सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में सेवा प्रदाता मैसर्स टाटा कंस्लटेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के साथ राष्ट्रीय ई-गर्वेंस योजना के भाग के रूप में सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। इस परियोजना ने अपने सफल प्रचालन के साढ़े छह वर्ष पूरे कर लिए हैं।

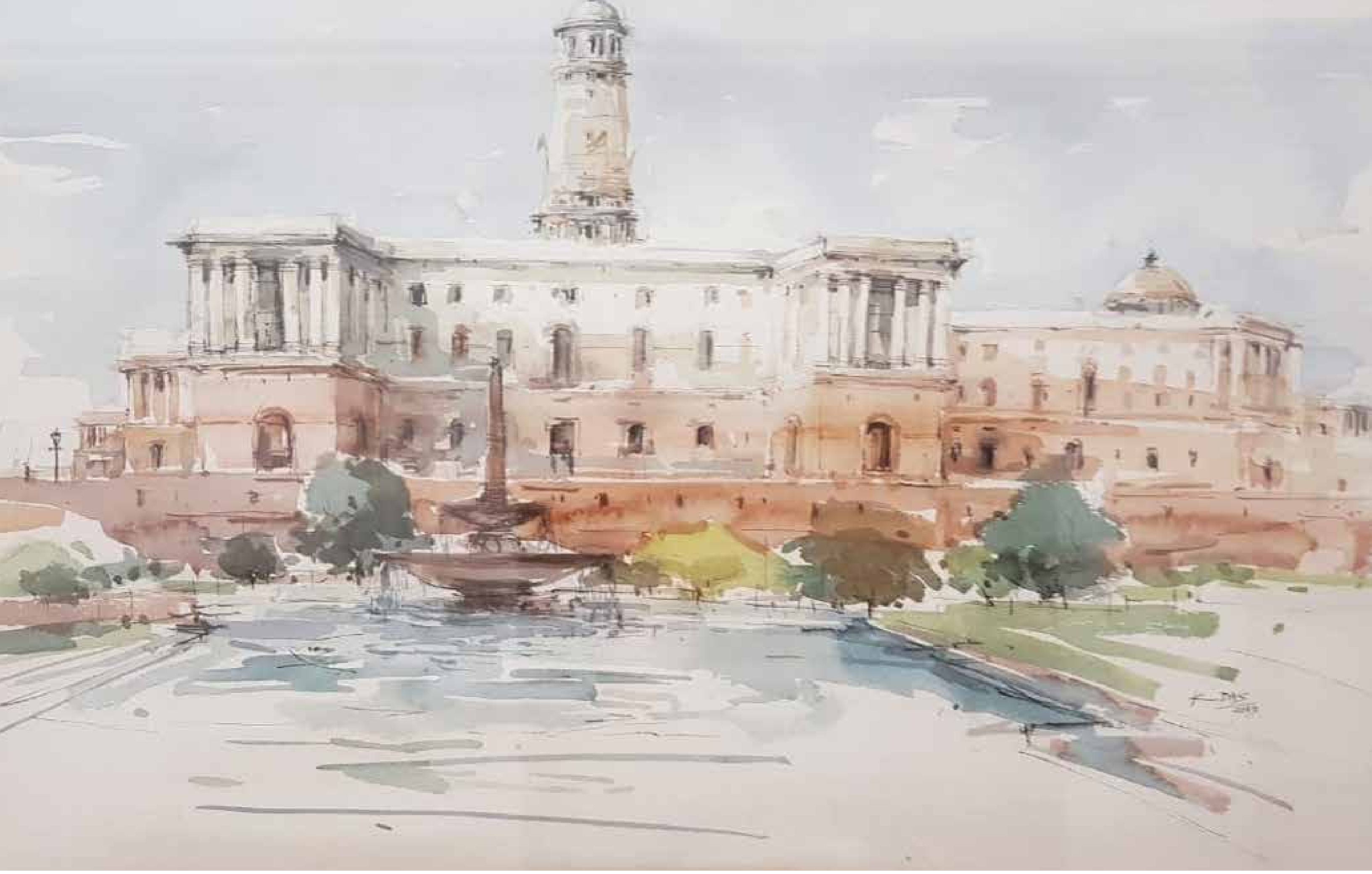

इसके अतिरिक्त, पीएसके और पीओपीएसके, एक 24x7 राष्ट्रीय कॉल सेंटर की स्थापना की गयी है, जो टॉल फ्री नम्बर (1800-258-1800) का प्रयोग करते हुए सत्रह भाषाओं में रीयल टाइम स्थिति और अद्यतन सूचना प्रदान करता है। इस कॉल सेंटर में प्रतिदिन 20,000 कॉल प्राप्त होता है। यह पोर्टल **http://passportindia.gov.in** अद्यतन रीयल टाइम सूचना भी प्रदान करता है जिसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। इस परियोजना को पोस्टल डिलिवरी हेतु भारतीय डाक तथा पासपोर्ट बुकलेट के लिए भारतीय सुरक्षा प्रेस (आईएसपी), नासिक के साथ आवेदक के व्यक्तिगत विवरणों के सत्यापन के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस प्रणाली के साथ समेकित किया जाता है। इस प्रणाली को अगस्त, 2015 से आधार के डाटाबेस के साथ देशभर में समेकित किया गया है। इस परियोजना में विदेश स्थित 184 भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों और आब्रजन प्राधिकरणों को वास्तविक सूचना भी प्रदान किया जाता है। पासपोर्ट भेजने के साथ ही आवेदक को एसएमएस/ईमेल अलर्ट भेजा जाता है।

31 दिसम्बर, 2018 तक के अनुसार 6.56 करोड़ पासपोर्ट सेवा संबंधी आवेदनों को संसाधित किया गया है और पीएसपी प्रणाली के माध्यम से 6.46 करोड़ सेवाएं प्रदान की गयी हैं। पीएसके में 63000 से अधिक नियुक्ति और पीओएसपीके में 14000 आवेदनों को दैनिक रूप में जारी किया जा रहा है जिसकी तुलना में फुटफॉल 50000 से अधिक है।

पासपोर्ट इंडिया पोर्टल

पासपोर्ट सेवाओं के संबंध में व्यापक और अद्यतन सूचना, नियुक्ति प्रक्रिया, प्रलेखीकरण, स्थिति संबंधी जांच और अन्य संबंधित मुद्दों पर जानकारी देते हुए पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल **http://passportindia.gov.in** सृजित की गयी है ताकि किसी भी समय और कहीं भी इसके लिए पहुंच बनायी जा सके। इस पोर्टल की

नियमित निगरानी और अद्‌यतन किया जाता है ताकि इसे अधिक प्रयोक्ता अनुकूल और सरल बनाया जा सके। यह पोर्टल द्विभाषीय है जिसमें सूचना को हिंदी में भी प्रदर्शित किया जाता है। इसे समय-समय पर पासपोर्ट सेवा विकासों के संबंध में जन सूचनाओं, एडवायजरी और प्रेस विज्ञप्तियों के साथ अद्‌यतन किया जाता है। इस पोर्टल पर रोजाना 1.7 करोड़ से अधिक हिट किया जाता है।

पासपोर्ट सेवाओं में वृद्धि

वर्ष 2018 के दौरान मंत्रालय ने वर्ष 2017 के 1.17 करोड़ की तुलना में 1.21 करोड़ से अधिक पासपोर्ट संबंधी आवेदनों को संसाधित किया इस प्रकार इसमें 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गयी। छत्तीस पासपोर्ट कार्यालय, मुख्यालयों और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव के कार्यालय को पुलिस अनुमति प्रमाणपत्र सहित पासपोर्ट और इससे संबंधित 1,21,74,758 आवेदन प्राप्त हुए जिसकी तुलना में 1,12,54,707 पासपोर्ट (449 कूटनीतिक पासपोर्ट, 18,009 सरकारी पासपोर्ट सहित) जारी किए गए। साथ हीं, 5,112 सरेंडर प्रमाणपत्र (एससी), 3,315 पहचान पत्र (आईसी) और 1946 नियंत्रण रेखा (एलओसी) अनुमति जारी किए गए। विदेश स्थित 184 भारतीय मिशनों/ पोस्टों ने लगभग 11,63,026 पासपोर्ट जारी किए। इस प्रकार, भारत सरकार ने कुल वर्ष 2018 में 1,24,17,733 पासपोर्टों को जारी किया। दिसम्बर, 2018 की स्थिति के अनुसार, 7.96 करोड़ से अधिक नागरिकों के पास वैध पासपोर्ट है। आज वैश्विक पासपोर्ट जारी करने के संबंध में चीन और संयुक्त राष्ट्र के बाद भारत तीसरे नम्बर पर है।

पासपोर्ट शुल्क के रूप में भारत के राजस्व में वर्ष 2011-12 में 110.42 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल-दिसम्बर, 2018 के बीच सभी पासपोर्ट सेवाओं से सृजित कुल राजस्व 1945.89 करोड़ रूपए है जबकि 2017-18 के दौरान कुल राजस्व 1778.36 करोड़ रूपए तथा वर्ष 2011-2012 में यह राजस्व 1030.58 करोड़ रूपए था।

एमपासपोर्ट सेवा मोबाइल एप

पासपोर्ट सेवा के लिए आवेदन, पे और अनुसूची नियुक्ति के लिए अतिरिक्त सुविधाओं सहित एम पासपोर्ट सेवा मोबाइल एप को 26 जून, 2018 को शुरू किया गया था। यह एप एंड्राइड और आईओएस प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। वर्ष 2018 में एमपासपोर्ट सेवा मोबाइल एप का प्रयोग करते हुए 2.23 लाख आवेदन दर्ज किया गया। नागरिकों को पासपोर्ट सेवाओं हेतु आवेदन के लिए किसी कंप्युटर और प्रिंटर तक पहुंच की आवश्यकता नहीं होगी। एमपासपोर्ट सेवा एप पासपोर्ट सेवाओं के संवर्धित सेट को सपोर्ट करेगा यथा:

i. न्यू यूजर पंजीकररण
ii. पंजीकृत यूजर अकांट के लिए साइन इन
iii. पासपोर्ट और पुलिस अनुमति प्रमाणपत्र हेतु आवेदन के लिए फाइल करने वाला आवेदन पत्र
iv. पासपोर्ट सेवा बनाम नियुक्ति अनुसूची के लिए पे
v. आवेदन उपलब्धता स्थिति vii. दस्तावेज एडवाइजर
vi. शुल्क संगणक

भारत में कहीं भी पासपोर्ट के लिए आवेदन

26 जून, 2018 से कोई भी आवेदक भारत में कहीं भी पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है। वर्ष 2018 के दौरान इस योजना के तहत एक लाख आवेदन किए गए। इस नागरिक अनुकूल पहल से आवेदकों को पासपोर्ट कार्यालय (पीओ) को चुनने में सहायता मिलेगी और इस प्रकार इस पीओ जहां वे इसके निरपेक्ष अपना आवेदन देने के इच्छुक हैं कि चयनित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) के क्षेत्राधिकार के तहत आवेदन में वर्तमान आवासीय पता विनिर्दिष्ट है या नहीं, के तहत अपेक्षित पासपोर्ट सेवा केन्द्र (पीएसके)/पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र (पीओपीएसके) का वे चयन कर पाएंगे। पुलिस सत्यापन (पीवी) कार्य उस पुलिस स्टेशन द्वारा किया जाएगा जिसके क्षेत्राधिकार में प्रपत्र में उल्लिखित पता आता है और पासपोर्ट उसी पते पर भेजा जाएगा।

सेवा आपूर्ति में उल्लेखनीय सुधार

पासपोर्ट सेवा परियोजना के कार्यान्वयन के साथ तथा मंत्रालय द्वारा किए जा रहे सतत प्रयास के जरिये देश में पासपोर्ट सेवा आपूर्ति में उल्लेखनीय सुधार आया है। पीएसके में पासपोर्ट आवेदन देने के लिए आनलाइन एप्वाइंटमेंट प्राप्त करना आसान और सहज हो गया है।

2 जनवरी, 2019 के अनुसार 253 पासपोर्ट केन्द्रों पर अगले दिन का एप्वाइंटमेंट उपलब्ध था, छप्पन पासपोर्ट केन्द्रों पर दो से सात दिनों का एप्वाइंटमेंट उपलब्ध था और सैंतालिस पासपोर्ट केन्द्रों पर सात दिनों से अधिक के समय का एप्वाइंटमेंट उपलब्ध था।

दिसम्बर, 2018 के आंकड़ों के आधार पर देशभर में तीन दिनों में 16 प्रतिशत सामान्य पासपोर्ट जारी किए गए थे; 31 प्रतिशत सात दिनों में; 14 दिनों में 48 प्रतिशत; इक्कीस दिनों में 67 प्रतिशत और तीस दिनों में 83 प्रतिशत (पुलिस सत्यापन में लगे समय को छोड़कर) पासपोर्ट जारी किए गए।

तत्काल पासपोर्ट के मामले में उसी दिन 46 प्रतिशत पासपोर्ट जारी किए गए; दो दिनों में 78 प्रतिशत और तीन दिनों में 93 प्रतिशत पासपोर्ट जारी किए गए। यदि पुलिस सत्यापन के समय को अंतिम आपूर्ति प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाए तो एक महीने के भीतर 83 प्रतिशत सामान्य पासपोर्ट जारी किए गए।

आवेदनों की संख्या:

प्राप्त पासपोर्ट संबंधी आवेदनों की संख्या के संबंध में शीर्ष पांच राज्य थे- महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, पंजाब और उत्तर प्रदेश जहां कुल आवेदनों की 60 प्रतिशत से अधिक आवेदन प्राप्त हुए।

प्राप्त आवेदनों की संख्या के संदर्भ में शीर्ष पांच पासपोर्ट कार्यालय हैं: मुम्बई, बंगलुरू, चंडीगढ़, अहमदाबाद और दिल्ली।

प्राप्त आवेदनों की संख्या के संबंध में शीर्ष पांच जिले हैं: पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद, मल्लपुरम और ठाणे।

पासपोर्ट सेवा शिविर और मेला

पासपोर्टों की बढ़ती मांग को पूरा करने तथा पीएसके से दूर रह रहे लोगों तक पहुंच बनाने के लक्ष्य से कई स्थानों पर पासपोर्ट सेवा शिविरों का आयोजन किया गया। अब तक देश के विभिन्न स्थानों पर दिसम्बर, 2018 तक 272 पासपोर्ट सेवा शिविरों का आयोजन किया गया है। इन शिविरों में 15,40,777 लाख से अधिक आवेदनों को संसाधित किया गया है। घर के निकट आईटी-चालित लोक सेवा ले जाने में यह एक अन्य नागरिक केन्द्रित उपाय है।

पासपोर्ट सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तथा एप्वाइंटमेंट प्राप्त करने में नागरिकों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के विचारार्थ पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा समय-समय पर सप्ताहांत पासपोर्ट मेला का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2014 में 380, वर्ष 2015 में 398, वर्ष 2016 में 138, वर्ष 2017 में 444 की तुलना में इस वर्ष दिसम्बर, 2018 तक 232 पासपोर्ट मेले का आयोजन किया गया है जिनमें कुल 1.02 लाख पासपोर्ट आवेदनों को संसाधित किया गया।

पासपोर्ट सेवाओं की पहुंच

मई, 2014 तक देश में सतहत्तर पीएसके कार्य कर रहे थे। वर्तमान सरकार ने सभी पूर्वोत्तर राज्यों सहित सोलह और पीएसके को शुरू किया गया है और इस प्रकार पासपोर्ट सेवा केन्द्रों की कुल संख्या तिरानवे हो गयी है।

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने डाक विभाग के सहयोग से देश में प्रधान डाक घरों (एचपीओ)/ डाक घरों में पासपोर्ट सेवा केन्द्रों को खोलने के लिए नवोन्मेषी पहल की है, इन्हें 'डाक घर पासपोर्ट सेवा केन्द्र (पीओपीएसके) के रूप में जाना जाता है। मंत्रालय ने 407 पीओपीएसके को खोलने की घोषणा की है जिनमें से 263 पीओपीएसके 2 जनवरी, 2019 तक कार्य कर रहा है। वर्ष 2018 के दौरान इन पीओपीएसके में 15.62 लाख से अधिक पासपोर्ट आवेदन प्राप्त हुए हैं। मंत्रालय का इरादा यथाशीघ्र शेष पीओपीएसके को शुरू करने के लिए अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करना है।

पासपोर्ट सेवा परियोजना में विदेश स्थित भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों का समाकलन:

विदेश स्थित भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को पासपोर्ट सेवा परियोजना में समाकलित करने की प्रक्रिया अक्टूबर, 2018 से शुरू की गयी थी। इसका लक्ष्य विदेश में रह रहे और पासपोर्ट संबंधी सेवा चाहने वाले भारतीय नागरिकों हेतु केन्द्रीकृत पासपोर्ट निर्गमन प्लेटफार्म और आवेदन प्रदान करना है। इस पायलट परियोजना के रूप में लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने 24 अक्टूबर, 2018 को पासपोर्ट सेवा परियोजना शुरू की और उसके बाद क्रमश: बर्मिंघम और एडिनवर्ग में भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा इसकी शुरूआत की गयी। वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास, न्यूयार्क, सेन फ्रांसिस्को, शिकागो, हस्टन और अटलांटा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासों ने नवम्बर, 2018 में इस परियोजना की शुरूआत की। इस मंत्रालय का लक्ष्य यथाशीघ्र विदेश स्थित सभी भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों के समाकलन करना है।

पुलिस सत्यापन

पासपोर्ट के समय पर जारी करने में पुलिस सत्यापन (पीवी) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंत्रालय पुलिस सत्यापन में तेजी लाने के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में पुलिस विभागों के साथ निकटता के साथ कार्य करता है। पुलिस सत्यापन को पूरा होने में अखिल भारतीय औसत दिनों की संख्या उन्नीस है तथा लगभग 80 प्रतिशत पीवी इक्कीस दिनों की अपेक्षित सीमित समय-सीमा में पूरा कर लिया जाता है। कुछ राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस सत्यापन का संसाधन समय सतत रूप से कम बनाए रखा गया है। उदाहरण के लिए, इस नयी प्रणाली के तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में औसतन पुलिस सत्यापन का कार्य चार दिनों में होता है उसके बाद हरियाणा और केरल का स्थान है जहां इस कार्य में औसतन आठ दिन लगता है, चंडीगढ में दस दिन, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और पुदुचेरी में बारह दिन और गोवा में तेरह दिन लगता है। मंत्रालय द्वारा किए गए सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप अधिक से अधिक जिले जिला पुलिस मुख्यालय सत्यापन मॉडल पर कार्य कर रहा है। इस प्रकार, 764 पुलिस जिलों में से 730 ने इस नई प्रणाली को अपनाया है तथा जिला मॉडल पर कार्य कर रहे हैं।

मंत्रालय ने पुलिस सत्यापन रिपोर्ट (पीवीआर) के शीघ्र सुपुर्दगी के लिए 'एमपासपोर्ट पुलिस' को शुरू किया है। इस मोबाइल एप्लिकेशन से इस प्रणाली को डिजिटल रूप से पीपीआर को कैप्चर करने के लिए क्षेत्र सत्यापन पुलिस अधिकारियों को सुविधा प्रदान करेगा। इस एप्लिकेशन को शुरू करने के साथ वास्तविक व्यक्तिगत विवरण प्रपत्र और प्रश्नावली के डाउनलोड और प्रिंट की आवश्यकता पुलिस अधिकारियों को नहीं होगी और इसके परिणामस्वरूप पीवीआर प्रक्रिया के कागज रहित अंतिम डिजिटल प्रवाह होगा। इससे इक्कीस दिनों की अपेक्षित समय-सीमा के भीतर पीवीआर को पूरा होने के लिए अपेक्षित समय में कमी आएगी और इसके परिणामस्वरूप तदनुसार हीं नागरिकों को पासपोर्ट और अन्य संबंधित सेवाओं की प्राप्ति में सहजता होगी। दिसम्बर, 2018 तक 2934 पुलिस स्टेशनों को शामिल करते हुए 116 डीपीएचक्यू एमपासपोर्ट मोबाइल एप्लिकेशन का प्रयोग कर रहे हैं। दिसम्बर, 2018 तक इस मोबाइल एप के माध्यम से कुल 3225132 आवेदन किए गए हैं।

न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के लिए कार्यमूलक संवर्धन/ प्रक्रियाओं का सरलीकरण।

किराये पर गर्भ प्रदान करने के लिए पासपोर्ट जारी करने के संबंध में नीति की समीक्षा की गयी थी और पंजीकृत सरोगेसी समझौते की आवश्यकता को सामाप्त कर दिया गया है। इसके पूर्व किराए के कोख से बच्चे पैदा करने के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए पंजीकृत सरोगेसी समझौता अनिवार्य था। अब इस प्रावधान में छूट प्रदान की गयी है तथा अन्य अपेक्षित दस्तावेजों के अतिरिक्त नोटेरीकृत सरोगेट समझौता करने के संबंध में सरोगेट चिल्ड्रन के लिए पासपोर्ट को जारी किया जा सकता है।

तत्काल आधार पर समय से पूर्व पासपोर्ट जारी करने की योजना को सरलीकृत किया गया है। तत्काल योजना के तहत अपेक्षित दस्तावेजों में छूट प्रदान की गयी है तथा अब तत्काल योजना के तहत पासपोर्ट जारी करने के लिए पूर्व में जो सत्यापन प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती थी, अब उनकी आवश्यकता नहीं है।

इस पुलिस सत्यापन प्रक्रिया को इस प्रकार फिर से शुरू किया गया है कि पुलिस को इस प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए आवेदक के केवल आपराधिक और राष्ट्रीयता वाले हिस्से की जांच की आवश्यकता होती है।

आपातकालीन प्रमाणपत्र की वैधता को तीन महीने से छह महीने की अवधिक तक के लिए विस्तारित किया गया है।

छात्र संबंधी पहल

छात्र संपर्क पहल का लक्ष्य समय पर उनके पासपोर्टों के लिए आवेदन देना और साथ हीं उन्हें ई-गवर्नेंस पहल के प्रति अवगत कराना है। इस पहल के भाग के रूप में संयुक्त एमईए और टीसीएस टीम भारत के विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं के छात्रों के साथ प्रस्तुतिकरण और प्रश्नोत्तरी सत्रों के माध्यम से जागरूकता फैलाती है। इस पहल की सहज और आसान तरीके में युवा पीढ़ी द्वारा उन्हें पासपोर्ट पाने के लिए उन्हें प्लेटफार्म देने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा स्वागत और प्रशंसा की गयी है।

समुद्रपारीय पासपोर्ट सेवा

वर्ष 2018 के दौरान विदेश स्थित भारतीय दूतावासों / वाणिज्य दूतावासों ने लगभग 11,63,026 लाख पासपोर्ट जारी किए। दो देश नामत: यूएई और सउदी अरब ने विदेश में कुल 40 प्रतिशत का योगदान दिया (स्थान-वार, दुबई, रियाद, कुवैत, मस्कट, जेद्दाह, आबूधाबी, सिंगापुर और दोहा ने इस सेवा का 60 प्रतिशत योगदान दिया।)। पासपोर्ट सेवाओं के दृष्टिकोण से दस शीर्ष देश थे: यूएई, सउदी अरब, अमेरिका, कुबैत, ओमान, कतर, सिंगापुर, बहरीन, यूके और कनाडा। उन्होंने सामूहिक रूप से विदेश में दी गयी कुल पासपोर्ट सेवाओं के 80 प्रतिशत का योगदान दिया।

पासपोर्ट सेवा दिवस

छठे पासपोर्ट सेवा दिवस और पासपोर्ट आफिसर्स सम्मेलन का आयोजन जवाहरलाल नेहरू भवन, नई दिल्ली में 26 और 27 जून, 2018 को विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया। इस सम्मेलन का उच्च स्तरीय भाग 26 जून, 2018 को हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, विदेश राज्य मंत्री जेनरल (डॉ.) वी. के. सिंह (सेवानिवृत्त) और श्री मनोज सिन्हा, संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा की गयी।

अपने भाषण में विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज और विदेश राज्य मंत्री जेनरल (डॉ.) वी. के. सिंह (सेवानिवृत्त) ने वर्ष 2018 के दौरान 1.17 करोड़ पासपोर्ट देने के लक्ष्य की प्राप्ति और इन्हें देने तथा पासपोर्ट संबंधी सेवाएं प्रदान करने पर पासपोर्ट अधिकारियों को बधायी दी। उन्होंने सभी पासपोर्ट अधिकारियों को सलाह दी कि वे नागरिकों को अधिक निष्ठा, विचारण और पारदर्शी व पेशेवर तरीके से पासपोर्ट देने व संबंधित सेवाओं की आपूर्ति करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का नवीकरण करें।

इस अवसर पर विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने एक नयी योजना को शुरू किया जिसके माध्यम से आवेदक भारत में कहीं भी पासपोर्ट के लिए आवेदन दे सकता है। उन्होंने पासपोर्ट सेवाओं हेतु आवेदन देने, शुल्क चुकाने तथा अनुसूचित एप्वाइंटमेंट लेने के अतिरिक्त सुविधाओं के साथ एमपासपोर्ट सेवा मोबाइल एप को भी शुरू किया।

विदेश मंत्रालय और डाक विभाग ने प्रत्येक लोक सभा संसदीय क्षेत्र जहां कोई पीएसके अथवा पीओपीएसके नहीं था, में पीओपीएसके खोलकर भारत के नागरिकों तक पहुंच बनाने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की। इससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक लोकसभा संसदीय क्षेत्र में कम से कम एक पीएसके अथवा पीओपीएसके उपलब्ध हो।

दिनांक 26 जून, 2018 को पासपोर्ट सेवा दिवस

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने नागरिकों को दी जाने वाली उत्कृष्ट सेवाओं की पहचान में बेहतर कार्यनिष्पादन वाले पासपोर्ट अधिकारियों और सेवा प्रदाता के कार्मिकों को पासपोट्र सेवा पुरस्कार प्रदान किया। चूंकि पुलिस सत्यापन पासपोर्ट जारी करने का एक महत्वपूर्ण संघटक है इसलिए तेलंगाना पुलिस विभाग, आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा पुलिस विभाग को अपनी त्वरित पुलिस अनुमति प्रदान करने के अपने प्रयासों के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए। तमिलनाडु, पुदुचेरी तथा महाराष्ट्र पुलिस विभागों को अपने संबंधित राज्यों में एमपासपोर्ट पुलिस एप के कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया।

दिनांक 26 जून, 2018 को पासपोर्ट सेवा दिवस

द्विभाषीय पासपोर्ट पुस्तिका

पासपोर्ट का पूर्व मुद्रित हिस्सा पहले से हीं हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में है। वर्तमान में आवेदक का व्यक्तिगत ब्यौरा केवल अंग्रेजी भाषा में ही मुद्रित किया जाता है। सरकार ने अब पासपोर्टों पर व्यक्तिगत ब्यौरों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में मुद्रित करने का निर्णय लिया है।

लोक शिकायत निवारण तंत्र

पासपोर्ट सेवा परियोजना के तहत एमईए ने एक मजबूत शिकायत निपटान प्रणाली स्थापित की है जिसके द्वारा एक बहुभाषायी राष्ट्रीय कॉल सेंटर की शिकायत निवारण और लोक फीडबैंक सहित विभिन्न पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के बारे में सूचना देने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्थापित की गयी है जिसका टोल फ्री संख्या 1800-258-1800 है और जो सत्रह भाषाओं व 24x7 आधार पर कार्य कर रही है, वर्तमान में यह प्रणाली केन्द्रीय प्रणाली प्लेटफार्म पर कार्य करती है। इसने वर्ष 2018 के दौरान प्रतिदिन लगभग 14,500 कॉलों को हैंडल किया (इनमें से 54 प्रतिशत कॉल हिंदी, 23 प्रतिशत अंग्रेजी में और 23 प्रतिशत क्षेत्रीय भाषाओं में थे)। पासपोर्ट पोर्टल पर ई-मेल आधारित हेल्पडेस्क भी है जहां सुझाव और शिकायत दर्ज की जा सकती है। नागरिक इस पोर्टल के माध्यम से अपने पासपोर्ट आवेदन/शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन भी देख सकता है।

संयुक्त सचिव (पीएसपी) और सीपीओ के निरीक्षण में पीएसपी प्रभाग में एक लोक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (पीजीआरसी) की स्थापना की गयी है, संयुक्त सचिव को केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के लोक शिकायत मंत्रालय के निदेशक के रूप में भी नामोद्दिष्ट किया गया है। यह टेलिफोन, ईमेल और डाक द्वारा सीधे ही सामान्य लोगों से प्राप्त शिकायतों को दूर करता है और राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय व केन्द्रीय सर्तकता आयोग आदि जैसे विभिन्न सरकारी कार्यालयों से संदर्भ भी प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त, सभी पासपोर्ट कार्यालय (पीओ) कार्मिक,

पासपोर्ट सेवा दिवस 2018 के दौरान विदेश मंत्री और अन्य गण्यमान्यों के साथ पीएसपी प्रभाग के अधिकारीगण।

लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय की सीपीजीआरएमएस वेबसाइट (https://pgportal.gov.in) के माध्यम से और पासपोर्ट पोर्टल से प्राप्त पासपोर्ट शिकायत अर्थात् सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) के कार्य को देखते हैं। आवेदकों की सहायता करने तथा शिकायतों को शीघ्रता से निपटने के लिए पीओ और पीएसके में नीतिगत स्थानों पर सूचना और सुविधा काउंटर, लोक शिकायत प्रकोष्ठ, शिकायत/सुझाव बॉक्स और हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है। लोक शिकायत अधिकारी के नाम, पता और दूरभाष संख्या को भी पीओ/पीएसके तथा पीओ की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। एक समय -सीमा में नागरिकों से किन्हीं शिकायतों को दूर करने और इनकी जांच करने के लिए सभी पीओ में एक लोक शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है।

सीपीजीआरएएम के तहत 1 जनवरी से 30 नवम्बर, 2018 तक के दौरान 9,281 शिकायतें प्राप्त की गयी (इनमें 2017 के दौरान प्राप्त लंबित 182 शिकायतें शामिल हैं) इनमें से 8, 663 शिकायतों का निपटान कर दिया गया । इसी अवधि के दौरान 39,434 लोक शिकायत याचिका (शिकायत/जांच और उपर लिखित सीपीजीआरएएमएस से संबंधित ईमेल, पोस्ट, फैक्स द्वारा प्राप्त 30,153 याचिका सहित) प्राप्त हुई और इनमें से 38680 शिकायतों का निपटान किया गया। आगे की कार्रवाई सहित उनके आवेदन की अद्यतन स्थिति को वेबसाइट पर डाला गया है जिन्हें लोग देख सकते हैं।

पासपोर्ट अदालत

पासपोर्ट कार्यालय पासपोर्ट आवेदकों की शिकायतों को दूर करने के लिए नियमित रूप से पासपोर्ट अदालतों का आयोजन करता है। ये अदालतें कुछ 7000 पुराने और जटिल मामलों को वर्ष 2017 में आवेदकों के साथ सीधे संपर्क कर निपटान करने में बड़ा उपयोगी रहीं हैं।

हज तीर्थयात्री: विशेष अभियान

जैसा कि भारतीय हज समिति (संसद के अधिनियम संख्या 2002 के 35 द्वारा गठित) द्वारा निर्णय लिया गया है, केवल वैध पासपोर्ट धारक भी हज के लिए आवेदन दे सकते हैं। पूर्व के वर्षों की तरह सभी पासपोर्ट कार्यालयों को अनुदेश जारी किए गए ताकि भावी हज आवेदकों के पासपोर्ट आवेदनों को अधिक प्राथमिकताएं प्रदान की जा सके तथा तत्परता के साथ ऐसे नागरिकों से प्राप्त अनुरोधों/ शिकायत संबंधी याचिकाओं को निपटाने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, सुविधा पटल खोलने, एप्वाइंटमेंट स्लॉटों को आरक्षित रख कर उन्हें शीघ्र पासपोर्ट जारी करने के लिए अपेक्षित सहायता प्रदान की जा सके।

पासपोर्ट कार्यालयों की जांच

विभिन्न राज्यों में पासपोर्ट कार्यालयों की नियमित जांच की जाती है। इन जांचों के दौरान प्रक्रिया संबंधी दक्षता में सुधार करने के लिए विचारों का आदान-प्रदान किया जाता है। संबंधित पीओ के क्षेत्राधिकार के तहत अवस्थित विभिन्न पीओ, पीएसके और पीओपीएसके द्वारा लोगों को दी जाने वाली पासपोर्ट सेवाओं की समग्र प्रक्रिया की व्यापक जांच करने के लिए देहरादून, लखनऊ, कोलकाता, भुवनेश्वर, बंगलुरू, जालंधर, विशाखापतनम, सूरत, पुणे, कोयम्बटूर और मदुरै में जांच की गयी । जांच के बाद पासपोर्ट कार्यालयों को सलाह दी गयी कि वे बेहतर परिचालन दक्षता, लंबित मामलों को समाप्त कर सेवा में सुधार करने तथा लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में बाधाओं को दूर करने के लिए उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई करें। संपूर्ण भारत में परिचालन में पासपोर्ट सेवा केन्द्रों की नियमित आधार पर गैर तकनीकी सेवा स्तर समझौते (एसएलए) के तहत जांच की गयी है।

सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी की प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय में नियुक्ति की गयी है ताकि आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदकों को सूचना प्रदान की जा सके। सीपीवी प्रभाग में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों की भी नियुक्ति की गयी है। संयुक्त सचिव (पीएसपी) और सीपीओ केवल मंत्रालय में पीएसपी प्रभाग से संबंधित मामलों के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकार है। 17 जून, 2014 से सभी पासपोर्ट कार्यालयों में एक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) पोर्टल का सृजन किया गया है। वर्ष 2018 के दौरान कुल 4231 ऑनलाइन आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए और इनमें से 3908 आवेदनों का निपटान किया गया।

अपील (पासपोर्ट अधिनियम की धारा 11 के तहत)

पीआईए के निर्णय के विरूद्ध अपील एक सांविधिक अधिकार है जो पासपोर्ट अधिनियम की धारा 11 के तहत पीड़ित लोगों को प्रदान किया गया है। इन मामलों के लिए संयुक्त सचिव (पीएसपी) और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी अपीलीय प्राधिकार है। 2018 में बारह अपील सत्र आयोजित किए गए जिनमें ईकतालिस अपीलीय कार्यवाहियां की गयी।

यात्रा संबंधी दस्तावेजों को तैयार करना और व्यक्तिकरण करना।

भारतीय सुरक्षा प्रेस, नासिक द्वारा सभी भारतीय यात्रा दस्तावेजों का निर्माण किया जाता है। संपूर्ण गुणवत्ता, कार्यमूलकता और भारतीय पासपोर्टों की सुरक्षा में सुधार करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। सभी पासपोर्ट कार्यालयों, मुख्यालयों और विदेश स्थित चयनित दूतावासों/ वाणिज्य दूतावासों को पठनीय पासपोर्ट मशीन जारी करता है। सभी पासपोर्ट कार्यालय अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार पठनीय पासपोर्ट मशीन जारी करता है।

विदेश स्थित 162 दूतावासों/ वाणिज्य दूतावासों तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और पोर्ट ब्लेयर स्थित सहायक सचिव (पासपोर्ट) के कार्यालय के लिए गौण छवि युक्त सुरक्षा विशेषता वाले मशीन पठनीय पासपोर्ट (एमआरपी) को सीपीवी प्रभाग, नई दिल्ली के केन्द्रीय भारतीय पासपोर्ट मुद्रण प्रणाली (सीआईपीपीएस) में मुद्रण किया जाता है। वर्ष 2018 के दौरान सीआईपीपीएस ने (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए 3212 सहित) 2,13,084 पासपोर्टों का मुद्रण किया।

ई-पासपोर्ट

अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) की मशीन पठनीय यात्रा दस्तावेजों में बायोमैट्रिक आंकड़ों को शामिल करने की सिफारिशों के अनुसार भारत ने अपने विद्यमान पासपोर्ट को उन्नत बनाने तथा उन्नत सुरक्षा विशेषता के साथ नागरिकों को चिप युक्त ई-पासपोर्ट जारी करने एवं बेहतर मुद्रण व कागज गुणवता वाला पासपोर्ट देने का भी निर्णय लिया। सरकार ने भारतीय सुरक्षा प्रेस (आईएसपी) नासिक को ई पासपोर्टों के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक कांटेक्टलेस इनले का अनुमोदन दे दिया है। इस संबंध में, आईएसपी को अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ)- शिकायत इलेक्ट्रॉनिक कांटेक्टलेस इनले की परिचालन प्रणाली के साथ इसके प्रापण के लिए वैश्विक त्रिस्तरीय निविदा जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है जो ई पासपोर्ट के निर्माण के लिए आवश्यक है। उन्नत सुरक्षा विशेषता और बेहतर मुद्रण व कागज गुणवत्ता वाले ई-पासपोर्ट का निर्माण आईएसपी, नासिक द्वारा निविदा और प्रापण प्रक्रिया के सफल रूप से पूरी होने के बाद शुरू हो जाएगा।

आवेदकों का व्यक्तिगत ब्यौरा इस चिप में डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित और भंडारित होगा। यदि कोई व्यक्ति इस चिप के साथ छेड़छाड़ करता है तो यह प्रणाली इसकी पहचान करेगा और इसके परिणामस्वरूप पासपोर्ट सत्यापन में असफल हो जाएगा। सूचना तक पहुंच को इस प्रकार सुरक्षित रखा जाता है कि पासपोर्ट के वास्तविक धारण के बिना इसे नहीं पढ़ा जा सकता है। इस प्रकार ई-पासपोर्ट धोखाधड़ी पूर्ण प्रचलनों और छेड़छाड़ों से अधिक सुरक्षा प्रदान करता है।

अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ)

भारत अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) के मशीन पठनीय यात्रा दस्तावेज (एमआरटीडी) संबंधी तकनीकी सलाहकार समूह (टीएजी) के सदस्य के रूप में सेवा प्रदान करता है और एमआरटीडी संबंधी आईसीएओ दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन करता रहा है। आईसीएओ ने केन्द्रीय संदर्भ के रूप में दस्तावेज 9303 के संबंध में नागर विमानन सुरक्षा में सुधार करने के लिए आईसीएओ के नीतिगत उद्देश्यों को सहायता प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक यात्रा दस्तावेज हेतु वैश्विक अंतर परिचालनीय ई-पासपोर्ट सत्यापन योजना को बढ़ावा देने हेतु साझा लागत आधार पर आईसीएओ लोक मुख्य डायरेक्ट्रीय (पीकेडी) की स्थापना की है। पीकेडी बोर्ड सदस्यों को आईसीएओ परिषद् द्वारा पीकेडी भागीदारी देशों द्वारा नामित और नियुक्त किया जाता है। भारत को फरवरी, 2009 में आईसीएओ पीकेडी को नामित किया गया था।

आरपीओ/पीएसके/पीओपीएसके में संसदीय समितियों द्वारा दौरा।

पासपोर्ट सेवाओं में संसद के निकट हित की पुष्टि बड़ी संख्या में संसदीय प्रश्न (पीक्यू) द्वारा की गयी थी और इसकी कई संसदीय समितियों द्वारा जांच/ अध्ययन दौरा किया गया:

संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम उप समिति ने 16 फरवरी, 2018 को बंगलुरू में स्थित पासपोर्ट कार्यालयों का दौरा/ जांच की; देहरादून में 9 जून, 2018 को; दिल्ली में 14 जून, 2018 को; लखनऊ में 8 सितम्बर, 2018 को और भुवनेश्वर में 30 अक्टूबर, 2018 को विदेश मंत्रालय और इसके कार्यालयों में राजभाषा के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए दौरा किया।

विदेश संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 25 मई से 1 जून, 2018 के बीच गुवाहाटी और गंगटोक में स्थित पासपोर्ट

कोलकाता में सरकारी आश्वासन संबंधी संसदीय समिति की हुई बैठक।

भुवनेश्वर में संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम उप समिति का दौरा।

सेवा केन्द्र का दौरा किया। समिति ने हाल के वर्षों में हुई प्रगति पर अपना संतोष प्रकट किया और नागरिकों को दी गयी सेवाओं के संदर्भ में इन स्थानों पर पासपोर्ट कार्यालयों में परिचालनों की समीक्षा की।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2017-18) द्वारा नए पासपोर्ट सेवा केन्द्रों को शुरू करने एवं एजेंटों व बिचौलियों द्वारा छात्रों के शोषण के संबंध में शिकायतों को दूर करने के लिए एमईए द्वारा संसदीय आश्वासनों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए 24 अगस्त, 2018 को कोलकाता का अध्ययन दौरा किया गया।

केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन

मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में 1959 में केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (सीपीओ) का सृजन किया गया और इसकी अध्यक्षता संयुक्त सचिव एवं मुख्य पासपोर्ट अधिकारी द्वारा की जाती है जो पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत एक अपीलीय प्राधिकार के रूप में तथा वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन नियम, 1978 के तहत विभाग प्रमुख के रूप में भी कार्य करता है।

1 दिसम्बर, 2018 के अनुसार सीपीओ की संस्वीकृत संख्या 2741 है । इसमें हाल ही में सृजित दो कनिष्ठ अनुवादकों, नौ वरिष्ठ हिंदी अनुवादकों और तीन पद सहायक निदेशक (राजभाषा) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पंद्रह तकनीकी और छह सहायक कर्मचारी पासपोर्ट सेवा परियोजना के परियोजना प्रबंधन एकक (पीएमयू) का कार्य देखते हैं। वर्तमान में समूह क के अट्ठाईस पद, समूह ख राजपत्रित स्तर के 235 पद, समूह ख अराजपत्रित के 509 पद और समूह ग के 772 पद रिक्त हैं। कर्मचारी चयन आयोग को समूह ख अराजपत्रित की सात रिक्तियों और 134 समूह ग के रिक्त पदों को भरने के लिए डोजियर भेजने का कार्य दिया गया है। समूह क के रिक्त पदों को अन्य सरकारी विभागों से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को लेकर भरा जाता है। मंत्रालय ने संस्वीकृत संख्या और अराजपत्रित पदों की कार्यबल संख्या के बीच के अंतर को पाटने के लिए आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से पासपोर्ट कार्यालयों के सुचारू कार्यकरण के लिए रिक्त अराजपत्रित पदों पर 361 डाटा एंटी आपरेटरों और छह कार्यालय सहायकों (मल्टी टास्किंग कर्मचारियों) की तैनाती की है।

मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए सीपीओ संवर्ग को पुनर्गठित व विस्तारित कर सीपीओ कार्मिकों की सेवा दशा में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए हैं कि उपलब्ध रिक्त पदों को भर्ती नियमों में पात्रता सेवा में पदों के अवनत में आवश्यक संशोधन कर/छूट प्रदान कर त्वरित पदोन्नति से भरा जाए। उत्पादकता संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआइएस) से आशा की जाती है कि वह पूर्व निर्धारित और परस्पर सहमति वाले मानकों के लिए व्यक्तिगत कार्यनिष्पादन को वित्तीय रूप से प्रोत्साहित करे। यह भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अद्‌वितीय योजना है। सीपीओ कर्मचारियों द्‌वारा दी गयी प्रतिभा सेवाओं की पहचान करने के मद्देजनर और इस प्रकार देश में शासन व्यवस्था में सुधार के लिए योगदान के लिए पासपोर्ट सेवा पुरस्कार को शुरू किया गया है। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष पासपोर्ट अधिकारी सम्मेलन के दौरान पासपोर्ट कार्यालयों के चयनित कर्मचारियों को वार्षिक रूप में प्रदान किया

वर्ष 2018 के दौरान सीपीओ में विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की नियमित बैठक आयोजित की गयी। दो सहायक पासपोर्ट अधिकारियों को उप पासपोर्ट अधिकारियों के पद पर पदोन्नत किया गया, सत्तावन वरिष्ठ अधीक्षकों को सहायक पासपोर्ट अधिकारियों के पद पर पदोन्नत किया गया, 110 अधीक्षकों को वरिष्ठ अधीक्षकों के पद पर पदोन्नत किया गया, ईक्कीस सहायक अधीक्षकों को अधीक्षकों के पद पर पदोन्नत किया गया, 373 कनिष्ठ पासपोर्ट सहायकों को वरिष्ठ पासपोर्ट सहायकों के पद पर पदोन्नत किया गया, पांच स्टेनोग्राफरों (ग्रेड तीन) को स्टेनोग्राफर (ग्रेड दो) में पदोन्नत किया गया तथा सात कार्यालय सहायकों को कनिष्ठ पासपोर्ट सहायकों के पद पर पदोन्नत किया गया। चौदह अधिकारियों को डीपीसी द्‌वारा न्यूनतम आश्वासन कैरियर पदोन्नति (एमएसीपी) और विभिन्न ग्रेडों में 377 अधिकारियों को सेवा में नियमित भी किया गया।

वर्ष के दौरान पच्चीस सहायक अधीक्षक और पैंतीस कार्यालय सहायकों ने कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के माध्यम से केन्द्रीय पासपोर्ट में ज्वाइन किया। कनिष्ठ पासपोर्ट सहायक ग्रेड में तिरानवे रिक्त पदों पर भर्ती का भार कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) को दिया गया है।

सीपीओ कर्मचारियों का प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास (एचआरडी) प्रकोष्ठ का सृजन।

समयबद्ध तरीके से सेवाओं में अधिक प्रभावी आपूर्ति के लिए केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (सीपीओ) संवर्ग के कर्मचारियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पीएसपी प्रभाग के एचआरडी प्रकोष्ठ द्‌वारा नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों ने एक प्रशिक्षण सुविधा प्रदाता के रूप में एमईए की भूमिका को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है जो पासपोर्ट संबंधी मामलों के शीघ्र निपटान के लिए व्यापक लोक मांग में विशेष रूप से मानव संसाधन प्रबंधन के एक बड़े महत्वपूर्ण पहलु के रूप में प्रशिक्षण पर फोकस करता है।

सीपीओ संवर्ग के अधिकारियों के लिए सेवा के मध्य में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना वर्ष 2018-19 के दौरान बनायी गयी। इस दौरान जनवरी, 2018 में छियालिस सहायक अधीक्षकों के लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसके पश्चात, दो चरणों में सीपीओ के वरिष्ठ पासपोर्ट सहायकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रथम चरण में मार्च से मई, 2018 के बीच चार बैचों के लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्‌यक्रम का आयोजन किया गया जिनमें कुल 162 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। दूसरे चरण में सात बैचों के लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन जुलाई से अक्टूबर, 2018 के बीच किया गया जिसमें कुल 372 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 3-7 दिसम्बर, 2018 के बीच उन्नीस कनिष्ठ हिंदी अनुवादकों के लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और उसके पश्चात 17-21 दिसम्बर, 2018 को तेईस स्टेनोग्राफरों के लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीपीओ संवर्ग के कुल 1322 अधिकारियों को अगस्त, 2016 से नवम्बर, 2018 के बीच प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

छब्बीस नए भर्ती किए गए सहायक अधीक्षकों और 200 वरिष्ठ अधीक्षकों व सहायक पासपोर्ट अधिकारियों के लिए वर्ष 2019 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

लोगों तक पहुंच

अपनी पहुंच के विस्तार के रूप में सीपीवी प्रभाग अर्द्ध वार्षिकी बुलेटिन 'पासपोर्ट पत्रिका' निकाल रहा है जिसमें सेवा प्रदाता के सहयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों से जुड़ी सूचनाएं होती हैं। मीडिया रोड शो का आयोजन कई पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा किया गया जिसके द्वारा पासपोर्ट सेवाओं को देने में सुधार के संबंध में संक्षिप्त सूचना प्रदान की गयी थी।

वीजा

विदेश स्थित मिशनों/पोस्टों द्वारा जारी वीजा

विदेश स्थित भारतीय मिशनों/ पोस्टों ने 1 जनवरी, 2018 से लेकर 30 नवम्बर, 2018 तक की अवधि के दौरान 31, 80, 561 वीजा जारी किए। नियमित वीजा के अलावा उपर्युक्त अवधि के दौरान 21,82,532 इलेक्ट्रॉनिक पर्यटन वीजा (ई-टीवी)/ ई -वीजा जारी किए गए।

वीजा प्रणाली का सरलीकरण

(क) भारत की वीजा प्रणाली को उदार और सरल बनाने के विचारार्थ सराकर ने अधिकांश देशों के राष्ट्रिकों को पांच वर्षीय पर्यटन और कारोबारी वीजा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। विदेशी निवेशकों को स्थायी निवासी दर्जा देने की एक नयी श्रेणी प्रदान की गयी है।

(ख) विश्व में कहीं से भी रोजगार और कारोबारी वीजा के लिए आवेदन देने की अनुमति प्रदान की गयी है (पूर्व में केवल मूल या डोमिसाइल देश में ही रोजगार और कारोबारी वीजा आवेदन दिए जा सकते थे।)

(ग) किसी भी प्रकार के वीजा के साथ पर्यटन संबंधी वीजा को शामिल करने की अनुमति देना। किसी भी प्रकार के वीजा पर भारत आने वाला कोई भी विदेश राष्ट्रिक (पाकिस्तानी नागरिक को छोड़कर) पर्यटन वीजा के तहत कारोबार करने की अनुमति प्राप्त कर सकता है।

(घ) छात्र वीजा पर किसी शैक्षणिक वर्ष में तीन से चार बार प्रविष्टियों को बढ़ाया गया है।

क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने की सुविधाएं

क्रूज सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए आव्रजन सुविधाएं पांच प्रमुख समुद्री पत्तनों यथा मुम्बई, कोचीन, मोर्मुगाओ, चेन्नई और न्यू मंगलोर में प्रदान की गयी हैं जहां यात्रियों को अपतटीय दृश्य देखने के लिए ई लैंडिंग की अनुमति प्रदान की गयी है। इन पत्तनों पर आने वाले ऐसे पर्यटकों के लिए बायोमैट्रिक नामांकन की शर्त को दिसम्बर, 2020 तक समाप्त कर दिया गया है ताकि त्वरित आव्रजन अनुमति प्रदान की जाए जिससे कि तट पर वे अधिकतम समय बिता सकें।

आगमन पर वीजा

भारत में छह नामोद्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों यथा दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलुरू और हैदराबाद के माध्यम से प्रवेश के लिए कारोबार, पर्यटन, सम्मेलन और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए 60 दिनों से अनधिक की अवधि के लिए दोहरे प्रवेश के साथ मार्च, 2016 को जापानी नागरिकों के लिए आगमन पर वीजा को शुरू किया गया था। दिनांक 1.10.2018 से हीं दक्षिण कोरिया के नागरिकों को इन्हीं शर्तों पर आगमन पर वीजा प्रदान करने की सुविधा प्रदान की गयी है।

सीपीवी प्रभाग द्वारा वीजा जारी करना

कंसुलर, पासपोर्ट और वीजा (सीपीवी) प्रभाग ने 1 जनवरी, 2018 से 30 नवम्बर, 2018 की अवधि के दौरान विदेशी राजनयिकों को 5597 वीजा जारी किए हैं। सीपीवी प्रभाग ने उपर्युक्त अवधि के दौरान स्थानांतरण और सरकारी अनुबंध पर विदेश स्थित भारतीय मिशनों/ पोस्टों पर जाने वाले भारतीय सरकारी अधिकारियों को 9071 वीजा नोट भी जारी किए हैं।

ई-पर्यटन वीजा (ई-टीवी)

अब ई-पर्यटन वीजा (ई-टीवी) का विस्तार 166 देशों/प्रदेशों के नागरिकों के लिए कर दिया गया है। कोई भी विदेशी नागरिक ई-वीजा को ऑनलाइन आवेदन कर सकता है जो भारत आने की संभावित तिथि से 120 दिन पूर्व तक हो सकता है। भारत के 26 नामोद्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और 5 समुद्री पत्तनों पर ई-वीजा सुविधा उपलब्ध है।

22

प्रवासी भारतीय कार्य

सुरक्षित और कानूनी प्रवास के संबंध में जागरूकता सृजन करने के लिए मंत्रालय द्वारा सतत प्रयास किए गए हैं। इस प्रभाग के संबंध में प्रमुख उपलब्धियां निम्नवत् हैं:

भारतीय कामगारों का कल्याण और सुरक्षा

खाड़ी क्षेत्र में निवासी भारतीय समुदाय लगभग 9 मिलियन है। उनमें से लगभग 70 प्रतिशत भारतीय शारीरिक श्रम करने वाले कामगार हैं। इस तथ्य को जानते हुए कि हमारे निम्न और अर्द्ध कुशल कामगार संवेदनशील होते है और कभी-कभी विदेशी नियोक्ताओं व बेईमान भर्ती एजेंटों द्वारा उनका उत्पीड़न और शोषण किया जाता है, मंत्रालय ने पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत किया है जो गंतव्य देशों में प्रवासन चक्र प्रस्थान पूर्व और वापसी पर सभी चरणों में प्रवासी कामगारों को सहायता प्रदान करती है।

मंत्रालय सुरक्षित, व्यवस्थित, कानूनी और मानवीय प्रवासन प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास करना जारी रखा है। इसमें प्रस्थान पूर्व अभिविन्यास (पीडीओ) कार्यक्रमों के माध्यम से प्रवासी कामगारों के कल्याण व सुरक्षा और जागरूकता सृजन के लिए व्यापक संस्थागत रूपरेखा शामिल है। यह महत्वपूर्ण है कि प्रवासी कामगारों को संवर्धित कौशल के साथ हीं सुरक्षित रूप से प्रवासन करना चाहिए। संदेश है: "सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं, विश्वास के साथ जाएं।" मंत्रालय का प्रवासी कामगारों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के संबंध में उन्हें आवश्यक जागरूकता प्रदान करना और संवेदनशील बनाना के लिए निम्नलिखित पर फोकस करना है:

(i) **मानकीकृत विषय-वस्तु के साथ मैनुअल और हैंडबुक तैयार करना:** भारत प्रवासन केन्द्र (आईसीएम) के तत्वावधान में मानकीकृत विषय-वस्तु के साथ प्रवासियों के लिए पीडीओ और हैंडबुक के लिए प्रशिक्षणकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए व्यापक मैनुअल को हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, मलयालम, तमिल और तेलगु भाषाओं में तैयार किया गया है। ई-बुक को भी तैयार किया गया है।

(ii) **प्रस्थान पूर्व अभिविन्यास कार्यक्रमों को शुरू करना:** प्रस्थान पूर्व अभिविन्यास प्रशिक्षण (पीडीओटी) कार्यक्रमों का लक्ष्य संस्कृति, भाषा, परंपरा और गंतव्य देश के

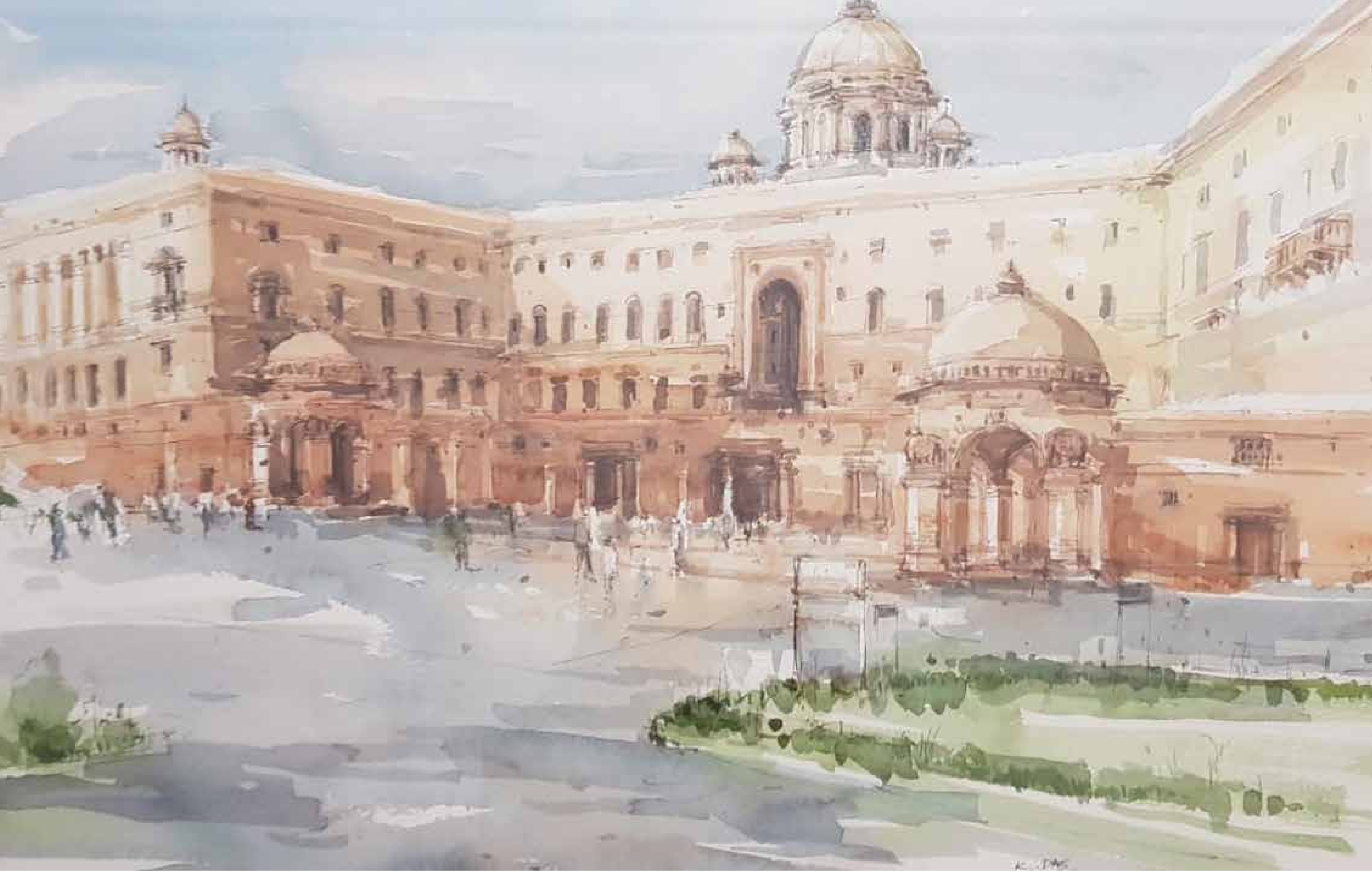

स्थानीय नियमों और विनियमों के संदर्भ में हमारे प्रवासी कामगारों के कौशल को संवर्धित करना, प्रवासी कामगारों को उनके कल्याण और सुरक्षा के लिए सुरक्षा और कानूनी प्रवास तथा विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के लिए तरीकों के बारे में उन्हें संवेदनशील बनाना है। प्रथम बार मानकीकृत फार्मेट के तहत दिल्ली, मुम्बई,

विदेश मंत्री संकट की स्थितियों में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए कार्य कर रहे भारतीय सामुदायिक संगठनों के अधिकारियों के साथ (05 मई, 2018)

कोच्चि और लखनऊ में मंत्रालय द्वारा एक दिवसीय प्रस्थान पूर्व अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शुरू किया गया। इस वर्ष लगभग 30,000 से अधिक प्रवासी कामगारों को पीडीओटी प्रदान किया गया। यह पहल सफल रहा है और इसका और विस्तार किया जाएगा।

(iii) **राज्यों के साथ समन्वय का विस्तार:** राज्यों के साथ मंत्रालय के सहयोग विस्तार पर व्यापक जोर दिया गया। प्रवासन संबंधी मामलों के लिए संस्थागत रूपरेखा के बारे में उन्हें संवेदनशीन बनाने तथा राज्य सरकारों द्वारा पीडीओ कार्यक्रम के विस्तार के लिए दिनांक 3 जुलाई, 2018 को प्रमुख श्रमिको भेजने वाले राज्यों और असम के साथ एक परामर्श बैठक आयोजित की गयी। इस संदर्भ में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यशालाओं का आयोजन मंत्रालय द्वारा भारतीय प्रवासन केन्द्र (आईसीएम) और राज्य सरकारों के सहयोग से किया गया था जिसका लक्ष्य प्रवासी कामगारों हेतु मंत्रालय के सुरक्षा, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन और कल्याण तथा सुरक्षोपायों के बारे में प्रतिभागियों को संवेदनशील बनाने के लिए जागरूकता सृजित करना है। टीओटी कार्यक्रमों का लक्ष्य राज्यों का क्षमता वर्धन है ताकि वे कामगारों को भेजने वाले जिलों में निचले स्तर पर पीडीओ कार्यक्रमों को शुरू करने में समर्थ बना सके। इन प्रतिभागियों में श्रम/ रोजगार/ कौशल विकास, स्थानीय मीडिया और शैक्षणिक संस्थाओं से अधिकारीगण शामिल थे।

डेढ़ वर्ष के दौरान 14 ऐसे कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। राज्य सरकार के संबंधित विभागों के सहयोग से आठ राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जागरूकता सृजन और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यशालाएं आयोजित की गयी हैं। प्रवासी कामगारों के लिए पीडीओ प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पीडीओ केन्द्रों के रूप में उनके द्वारा संस्तुत केन्द्रों के नामोद्दिष्ट के लिए राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान ऐसे कुल छह कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्र.सं.	राज्य	शहर	साझेदार	तिथि	प्रमाणी-कृत प्रशिक्षुओं की सं.
1.	राजस्थान	जयपुर	आईसीएम, आईओएम और आरएसएलडीसी	29-30 मई 2018	112
2.	पंजाब	चंडीगढ़	आईसीएम, आईओएम और एनआरआई कार्य विभाग	8-9 जून 2018	68
3.	राजस्थान	जयपुर	आईसीएम और आरएसएलडीसी	28-30 अगस्त 2018	29
4.	बिहार	पटना	आईसीएम और श्रम विभाग, बिहार	25-26 सितम्बर 2018	36
5.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	आईसीएम और श्रम विभाग, पश्चिम बंगाल	26-27 नवम्बर 2018	41
6.	केरल	तिरूवनंतपुरम	आईसीएम और श्रम विभाग, केरल	11-12 दिसम्बर 2018	23
				कुल	**309**

प्रवासी कौशल विकास योजना (पीकेवीवाई)

प्रवासी कौशल विकास योजना (पीकेवीवाई) मंत्रालय की मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है जो भावी उत्प्रवासियों के कौशल संवर्धन के लिए है। यह योजना, (इस मंत्रालय तथा कौशल विकास और प्रशिक्षण मंत्रालय (एमएसडीई) के बीच एक साझेदारी है) का लक्ष्य विदेश में रोजगार को सुकर बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों की तर्ज पर क्षेत्रों और रोजगार भूमिकाओं के चयन में भावी उत्प्रवासियों के कौशल को बढ़ाना है। शुरूआत में, इस योजना का फोकस उन क्षेत्रों पर होता है जिनकी ईसीआर देशों में मांग में है। पीकेवीवाई में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से एमएसडीई

द्वारा प्रदान की जाने वाली तकनीकी टॉप अप प्रशिक्षण शामिल होता है। यह प्रस्थान पूर्व अभिविन्यास प्रशिक्षण (पीडीओटी) का अनुपूरक होता है। वर्तमान में देश के विभिन्न भागों में सोलह ऐसे केन्द्रों की स्थापना की गयी है। इनके कार्यनिष्पादन की एमएसडीई द्वारा समीक्षा की जाती है।

प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी

प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी सहयोग का महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है जिसका लक्ष्य हमारे छात्रों और पेशेवरों के लिए जनसांख्यिकीय लाभ उठाना और गतिशीलता को बढ़ाना है।

10 मार्च, 2018 को फ्रांस के राष्ट्रपति श्री एम्मानुएल मैक्रोन की भारत यात्रा के दौरान भारत सरकार और फ्रांस गणतंत्र के सरकार के बीच एक प्रवासन और गतिशीलता समझौता साझेदारी हुई। इस समझौते में लोगों के बीच संबंध को बढ़ाने, छात्रों, शिक्षाविदों, अनुसंधान कर्ताओं और कुशल पेशेवरों की गतिशीलता को बढ़ाने, दोनों देशों के बीच गैर कानूनी प्रवासन और मानव तस्करी से संबंधित मामलों पर सहयोग को मजबूत करने में प्रमुख मील का पत्थर प्रस्तुत करता है। यह समझौता फ्रांस के साथ भारत के तेजी से बढ़ते बहु फलकीय साझेदारी का साक्ष्य है और यह दोनों पक्षों के बीच विश्वास और आत्मविश्वास के बढ़ने का संकेत है। यह समझौता प्रारंभ में सात वर्षों की अवधि के लिए वैध था और स्वचालित नवीकरण के लिए प्रावधान को निगमित करता है एवं संयुक्त कार्य समूह के माध्यम से निगरानी तंत्र स्थापित करता है।

भारत - डेनमार्क द्वितीय संयुक्त कार्य समूह (जेडब्लूजी) की बैठक 8 और 9 अगस्त, 2018 को श्रम गतिशीलता साझेदारी के संबंध में भारत-डेनमार्क समझौता ज्ञापन की रूपरेखा के तहत कोपेनहेगन में हुई थी। इस जेडब्लूजी बैठक में दोनों पक्ष छात्रों, इंटर्नों, अनुसंधानकर्ताओं, पर्यटकों, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में उच्च कुशलता प्राप्त पेशेवरों की आवाजाही को सुकर बनाने और प्रोत्साहित करने पर सहमत हुए जिससे दोनों पक्षों के बीच गतिशीलता में विद्यमान सहयोग में और सहयता मिलेगी।

प्रवासन और गतिशीलता के संबंध में उच्च स्तरीय वार्ता (एचएलडीएमएम) संबंधी मामला भारत-यूरोपीय संघ द्विपक्षीय साझेदारी की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। मार्च, 2016 में प्रवासन और गतिशीलता पर सामान्य कार्यसूची (सीएएमएम) संबंधी भारत-यूरोपीय संघ संयुक्त घोषणा तथा अप्रैल, 2017 में ब्रसेल्स में भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) एचएलडीएमएम पर हस्ताक्षर की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में दोनों पक्ष तकनीकी सहयोग के माध्यम से आगे बढ़ने तथा सीएएमएम के तहत परस्पर हित के क्षेत्रों में आगे बढ़ने पर सहमत हुए। ईयू पक्ष अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और ब्रसेल्स आधारित अंतरराष्ट्रीय प्रवासन और नीति विकास केन्द्र (आईसीएमपीडी) की पहचान की है वहीं भारतीय पक्ष ने इस परियोजना हेतु कार्यान्वयन साझेदारों के रूप में संबंधित मुद्दों संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रवासन पर विदेश मंत्रालय के एक प्रबुद्ध वर्ग भारतीय प्रवासन केन्द्र (आईसीएम) की पहचान की है। तकनीकी परियोजना की परियोजना परामर्श समिति (पीएसी) की प्रथम बैठक 1 जून, 2018 को नई दिल्ली में हुई थी। इनके फोकस क्षेत्र में अन्यों के साथ - साथ यूरोपीय क्षेत्रों में अल्पावधि और दीर्घावधि ठहराव के लिए भारतीय नागरिकों को ईयू की विद्यमान वीजा अवधि से संबंधित मामला, ईयू के सदस्य राष्ट्रों में भारतीय छात्रों की बढ़ती संख्या के हितों को आगे बढ़ाना, ईयू के बाजारों में हमारे पेशेवरों/कार्यबल के लिए सहज पहुंच तथा गैर कानूनी प्रवासन पर सेवा और सहयोग के उदारीकरण के माध्यम से अधिक गतिशीलता को आगे बढ़ाना शामिल है।

श्रम और जनशक्ति संबंधी मामलों पर सहयोग

खाड़ी सहयोग परिषद् के देशों (बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सउदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात) और जोर्डन के साथ श्रम और जनशक्ति सहयोग एमओयू/ समझौता किया गया है जो श्रम और जनशक्ति संबंधी मामलों पर सहयोग के लिए पहुंच रूपरेखा प्रदान करता है। श्रम और जनशक्ति सहयोग संबंधी मामलों के विभिन्न पक्षों पर आए शिष्टमंडलों के साथ चर्चाएं आयोजित की गयी। 31 अक्टूबर, 2018 को कुवैत में विदेश मंत्री के दौरे के दौरान कुवैत के साथ घरेलु कामगारों की भर्ती में सहयोग संबंधी व्यापक एमओयू लागू किया गया। भारत ने आबू धाबी वार्ता और कोलंबो प्रक्रिया जैसी उल्लेखनीय क्षेत्रीय परामर्शदात्री प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिया।

भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्लूएफ)

वर्ष 2009 में स्थापित आईसीडब्लूएफ का लक्ष्य माध्यम परीक्षण आधार पर सबसे अधिक पात्र मामलों में दुर्दशा और आपातकालीन समय में प्रवासी भारतीय नागरिकों को सहायता देना है। आईसीडब्लूएफ विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों और पोस्टों को सहायता प्रदान करता है। 1 सितम्बर, 2017 से प्रभावी आईसीडब्लूएफ दिशानिर्देशों की पुनरीक्षा ने विदेश स्थित भारतीय मिशनों और पोस्टों को विदेश में भारतीय नागरिकों द्वारा सहायेता के लिए अनुरोधों पर तेजी से कार्य करने की अधिक लचीली व्यवस्था प्रदान किया है। इन दिशानिर्देशों में तीन मुख्य क्षेत्र: (1) खराब दशा में प्रवासी भारतीय नागरिकों की सहायता करना (2) समुदाय कल्याण कार्य के लिए सहायता देना और (3) वाणिज्य दूतावास सेवा में सुधार करना।

इस वर्ष के पाठ्यक्रम के दौरान आईसीडब्लूएफ का प्रभावी रूप से कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात में एमनेस्टी योजनाओं में भारतीय नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया गया। कुवैती कंपनी खराफी नेशनल के लगभग 1700 दयनीय दशा में रह रहे भारतीय कामगारों को इस कोष से सहायता प्रदान की गयी थी। इस कोष से दी गयी सहायता की वैश्विक रूप से सराहना की गयी थी। इसने प्रवास करने वाले उत्प्रवासी कामगारों के बीच सहायता के बारे में आत्मविश्वास का भाव भी जगाया कि वे खराब समय में भारत से सहायता की आशा कर सकते हैं। इसकी शुरूआत से हीं इस कोष के लाभार्थियों की संख्या 130000 से अधिक थी। लगभग 90000 भारतीय नागरिकों ने 2014 से इस कोष का लाभ उठाया है।

प्रवासी भारतीय बीमा योजना को पुन: शुरू करना।

प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) ईसीआर देशों में रोजगार के लिए जाने वाले उत्प्रवासन जांच अपेक्षा (ईसीआर) श्रेणी के तहत आने वाले भारतीय कामगारों हेतु एक अनिवार्य बीमा योजना है जिसमें दो और तीन वर्षों की अवधि हेतु क्रमश: 275 और 375 रूपए की बीमा राशि पर दुर्घटना में मृत्यु/स्थायी विक्लांगता के मामले में 10 लाख रूपए का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इस योजना को संबंधित पणधारकों के साथ परामर्श कर 1 अगस्त, 2017 से व्यापक रूप से पुन: शुरू किया गया है, सरल बनाया गया तथा प्रवास करने वाले कामगारों के लिए अधिक लाभकारी बनाया गया है और इसका लक्ष्य दावों का शीघ्र निपटान करना है। वर्ष के दौरान ईसीआर श्रेणी के कामगारों को 330000 पीबीबीवाई पॉलिसियां जारी की गयीं।

भारतीय प्रवासन केन्द्र

भारतीय प्रवासन केन्द्र (आईसीएम) मंत्रालय का एक अनुसंधान प्रबुद्ध वर्ग है जो अंतरराष्ट्रीय प्रवासन के सभी मामलों से संबंधित है। संबंधित अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संबंधी मुद्दों पर अपनी प्रतिबद्धता के रूप में आईसीएम ने राज्य सरकारों के साथ सहयोग कर सुरक्षित और कानूनी प्रवासन पर विभिन्न क्षमता वर्धन कार्यशालाओं का आयोजन किया। वर्ष के दौरान आईसीएम ने सभी पीडीओ कार्यक्रमों के संबंध में एक संसाधन केन्द्र के रूप में अपनी स्थिति बनायी है। प्रवासी कामगारों के लिए प्रस्थान पूर्व अभिविन्यास संबंधी व्यापक मैनुअल को छह भाषाओं यथा अंग्रेजी, हिंदी, तेलगु, तमिल, मलयालम और बांग्ला में शुरू किया गया। उसी प्रकार प्रावासी कामगारों के लिए बहुमूल्य सूचना वाली प्रस्थान पूर्व अभिविन्यास संबंधी पुस्तिका को भी निकाला गया है। इस संबंध में की गयी पहल की सभी पणधारकों द्वारा सराहना की गयी है तथा आईसीएम आने वाले वर्षों में ऐसे क्रियाकलापों को बढ़ाने का इच्छुक है। आईएलओ, आईओएम और विभिन्न शिक्षा संस्थाओं जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग के अलावा आईसीएम को प्रवासन और गतिशीलता संबंधी सामान्य कार्यसूची (सीएएमएम) के लिए भारत-ईयू तकनीकी परियोजना के लिए भारतीय पक्ष के कार्यान्वयन साझेदार के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया।

प्रवासी भारतीय कार्य प्रभाग-दो

प्रवासी भारतीय कार्य प्रभाग-दो भारतीय समुदाय के साथ अनुबंध संबंधी मामलों को देखता है। इस प्रभाग द्वारा किए गए प्रमुख कार्यक्रमों/ योजनाओं में प्रवासी भारतीय दिवस अभिसमय, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय दिवस, भारतीय कार्यक्रम को जाने, समुदाय बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम, भारत को जाने प्रश्नोत्तरी, एनआरआई वैवाहिक विवाद, समुदायों के साथ सांस्कृतिक संबंध को बढ़ाना, छात्र पंजीकरण पोर्टल, प्रतिशतित पोर्टल, समुदाय से संबंधित शिकायतें, समुदाय से संबंधित अन्य मुद्दे शामिल हैं तथा सरकार द्वारा समय -समय पर नई पहलें की गयी हैं।

प्रवासी भारतीय दिवस

प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) को भारत सरकार के साथ प्रवासी भारतीय समुदाय के अनुबंध को मजबूत करने तथा भारत में उनकी जड़ों को पुन: जोड़ने के लिए प्रत्येक दो वर्ष में मनाया जाता है। इस अभिसमय के दौरान चयनित प्रवासी भारतीयों को भारत और विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान की पहचान करने के लिए प्रतिष्ठित ''प्रवासी भारतीय सम्मान'' पुरस्कार से नवाजा भी जाता है।

परंपरागत रूप से, पीबीडी को 7-9 जनवरी के दौरान मनाया जाता है, तथापि, व्यापक भारतीय समुदाय की भावना के सम्मान में पीबीडी का आयोजन 21-23 जनवरी, 2019 को मनाया गया ताकि 24 जनवरी, 2019 को प्रयागराज में कुंभ मेला में विदेशी भागीदार भाग ले सकें और 26 जनवरी, 2019 को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के पैरेड को देख सकें। सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा शुरू किी गयी विशिष्ट योजनाओं और पहलों को उद्धृत करते हुए भारत सरकार द्वारा की गयी महत्वपूर्ण विकास और प्रगति के बारे में बतलाने के लिए उक्त स्थान पर पीबीडी अभिसमय के समानांतर ''भारतीय हस्तकला और सांस्कृतिक बाजार'' और प्राचीन भारत: आधुनिक भारत शीर्षक से एक प्रदर्शनी लगायी जाएगी।

भारत में कृत्रिम बौद्धिकता के क्षमता वर्धन में भारतीय समुदाय की भूमिका, वहनीय कचरा प्रबंधन के लिए क्षमता वर्धन में भारतीय समुदाय की भूमिका और वहनीय सौर ऊर्जा के लिए क्षमता वर्धन में भारतीय समुदाय की भूमिका विषयों पर वर्ष के दौरान तीन पीबीडी सम्मेलन आयोजित किए गए। उनकी सिफारिशें और कृत कार्रवाई रिपोर्ट को पीबीडी अभिसमय में प्रस्तुत किया जाएगा।

समुदाय के साथ सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना (पीसीटीडी)

पीसीटीडी के तहत ओआईए -दो प्रभाग भारतीय मिशनों और वाणिज्य दूतावासों को उनकी पहलों के समर्थन के लिए अनुदान प्रदान करता है जिसका लक्ष्य प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ संबंधों को मजबूत करना; उनके भारतीय विरासत और संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखना और प्रदर्शित करना है। भारत में प्रबुद्ध वर्ग और अन्य संगठनों को अनुदान प्रदान किया जाता है जो प्रवासी भारतीय समुदाय के संबंध में कार्यक्रमों को आयोजित करता है। मिशनों/पोस्टों से कहा गया कि वे भारत को जानिए प्रश्नोत्तरी तथा प्रवासी भारतीय दिवस अभिसमय में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करें। इस संबंध में 14 मिशनों/ पोस्टों को वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है।

भारत को जानिए प्रश्नोत्तरी (बीकेजे)

भारत को जानिए प्रश्नोतरी के द्वितीय संस्करण के प्रथम दौर का आयोजन तीन श्रेणी के प्रतिभागियों के लिए नवम्बर, 2018 में संपूर्ण विश्व में किया गया यथा एनआरआई, पीओआई/ ओसीआई और विदेशी नागरिक; लगभग 40,000 लोगों ने इस प्रश्नोत्तरी के लिए पंजीकरण किया। तृतीय श्रेणी (विदेशी नागरिक) को जुलाई, 2018 में मिशन प्रमुखों के सम्मेलन में प्रधान मंत्री द्वारा की गयी घोषणा के बाद जोड़ा गया। जनवरी, 2019 में हमारे विदेश स्थित मिशन द्वारा प्रथम दौर

के विजेताओं को स्वर्ण/रजत/कांस्य पदक प्रदान किया गया। भारत को जानिए यात्रा के लिए प्रत्येक श्रेणी से दूसरे दौर के शीर्ष दस रैंकरों को बाद में भारत बुलाया गया तथा उन्होंने इस प्रश्नोत्तर के तीसरे और चौथे दौर में भाग लिया। चौथे दौर के विजेताओं को पीबीडी अभिसमय 2019 के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा पदक प्रदान किया गया।

भारत कार्यक्रम को जाने (केआईपी)

पीआईओ युवाओं को अपनी जड़ों तथा भारतीय कला, संस्कृति और विरासत से परिचित कराने तथा उन्हें देश के उद्गम के प्रति एक्पोजर प्रदान करने के लक्ष्य के साथ मंत्रालय द्वारा 2003 में भारत को जाने कार्यक्रम को शुरू किया गया। वर्ष 2018-19 के दौरान भारत सरकार ने छह नियमित केआईपी, दो प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना, एक गोल्डन जुबली संस्करण और एक भारत को जानिए यात्रा सहित भारत को जानिए दस कार्यक्रमों की घोषणा की गयी है। सरकार ने पहले हीं आज तक की तिथि तक 1652 युवा समुदाय की भागीदारी के साथ केआईपी के 49 संस्करणों का आयोजन किया है। विशेष भाव के रूप में प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना की भागीदारी के अतिरिक्त 50वें (गोल्डन जुबली), 51वें और 52वें केआईपी समूह पीबीडी अभिसमय 2019 में भाग लेंगे।

भारतीय समुदाय के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम (एसपीडीसी)

भारतीय समुदाय के बच्चों की विभिन्न क्षेत्रों (भारत में चिकित्सा और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों को छोड़कर) में भारतीय विश्वविद्यालयों/ संस्थाओं में उच्च शिक्षा तक पहुंच तथा उच्च शिक्षा के केन्द्र के रूप में भारत को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2006-07 के दौरान छात्रवृत्ति कार्यक्रम को शुरू किया गया। वर्तमान में, इस योजना के तहत डीएएसए योजना के तहत शामिल राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं और अन्य संस्थाओं द्वारा प्रत्यायित संस्थाओं, भारत के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों को करने के लिए 4000 अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष तक ईसीआर देशों में पीआईओ/ एनआरआई और भारतीय कामगारों के बच्चों को 150 छात्रवृत्तियां प्रदान की गयी हैं। मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए छात्रवृत्ति पाने वाले 106 अभ्यार्थियों को अंतिम रूप प्रदान किया है।

जागरूकता अभियान और मीडिया योजना

मंत्रालय ने (क) मंत्रालय के पास धोखाधड़ी वाले एजेंटों से बचने और केवल पंजीकृत एजेंटों से संपर्क करने; (ख) रोजगार के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने; और (ग) भारतीय दूतावास से संपर्क करने जहां वे कार्य कर रहे हैं, के बारे में उन्हें सलाह देते हुए विदेशों में सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के बारे में भावी प्रवासी कामगारों को संवेदनशील बनाने और उनमें जागरूकता सृजित करने के लिए हिंदी और आठ क्षेत्रीय भाषाओं में जागरूकता अभियान शुरू किया है।

सितम्बर, 2018 के महीने के दौरान शनिवार को सप्ताह में एक दिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल के दो प्रमुख दैनिकों में 'सुरक्षित और कानूनी प्रवासन" के संबंध में विज्ञापन छापे गए। 16 जुलाई से 16 अगस्त, 2018 के एक महीने के दौरान प्राइम चैनलों/ डीडी न्यूज पर हिंदी और आठ क्षेत्रीय भाषाओं में जागरूकता अभियान भी प्रसारित किया गया। इस अभियान को 17 अगस्त से 17 सितम्बर, 2018 तक विस्तार दिया गया था। दूरदर्शन, लोक सभा टीवी, राज्य सभा टीवी और निजी चैनलों पर इस अभियान को 11 दिसम्बर, 2018 को शुरू कर एक महीने के लिए पुन: चलाया गया ताकि पर्याप्त पहुंच सुनिश्चित हो सके।

एनआरआई वैवाहिक विवाद

हाल के वर्षों में ओआईए-दो प्रभाग ने कई पहलें शुरू की हैं जिनका लक्ष्य एनआरआई जीवन साथी के संबंध में विवाहित भारतीय पत्नियों का कल्याण और सुरक्षा देना, एक नागरिक केन्द्रित दृष्टिकोण, अग्र सक्रिय रूप से कई तरीकों से सहायता प्रदान करना है। 1 अप्रैल -30 नवम्बर, 2018 तक मंत्रालय ने उन्हें परामर्श प्रदान कर, दिशानिर्देशों और तंत्र के बारे में सुझाव और सूचना प्रदान कर 912 शिकायतों को निपटाया है। वर्ष के दौरान समेकित नोडल एजेंसी जिसकी अध्यक्षता महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव करते हैं, ने आठ बैठकें की और दोषी पति/पत्नि के विरूद्ध पांच लुक आउट परिपत्र जारी किया है। आईएनए एक प्रभावी निकाय के रूप में कार्य कर रहा है ताथा प्रभावित महिलाओं की समस्याओं के समयबद्ध समाधान के लिए एकल खिड़की योजना प्रदान कर रहा है।

विदेश मंत्रालय- राज्य पहुंच सम्मेलन

विदेश मंत्रालय ने हाल ही में कई पहलें की हैं जिनका लक्ष्य प्रवासी भारतीय समुदायों का कल्याण और सुरक्षा करना तथा विश्व भर में फैले भारतीय समुदायों के साथ हमारे संबंधों को मजबूत करना है। इस उद्देश्य के साथ विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में 'विदेश संपर्क' बैनर के तहत राज्य पहुंच कार्यक्रमों को शुरू किया जो मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच गहन वार्ता है। विदेश संपर्क पहल के तहत वर्ष 2018 के दौरान प्रभाग ने गुजरात और मध्य प्रदेश में राज्य पहुंच कार्यक्रमों को आयोजित किया।

ओई और पीजीई प्रभाग

प्रत्येक वर्ष भारत से बड़ी संख्या में लोग रोजगार के उद्देश्यों के लिए विदेश जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत से बाहर जाने वाले अधिकांश उत्प्रवासी खाड़ी देशों में गए है जहां अनुमानत: आठ मिलियन भारतीय कामगार रोजगार में लगे हैं। खाड़ी देशों सहित मध्य पूर्व में विशाल उत्प्रवासी अर्द्ध कुशल और अकुशल कामगार हैं तथा अधिकांश कामगार अस्थायी उत्प्रवासी हैं जो अपने संविदा रोजगार की समाप्ति पर भारत लौट आते हैं। उत्प्रवासन जांच अपेक्षा (ईसीआर) पासपोर्ट धारक को उत्प्रवासन अनुमति लेने की आवश्यकता होती है जब वे 18 नामोद्दिष्ट ईसीआर देशों में रोजगार के लिए जाते हैं। उत्प्रवासियों के दस रक्षकों द्वारा अब उत्प्रवासन अनुमति ऑन लाइन जारी किया जाता है जिनके कार्यालय चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कोच्चि, कोलकाता, मुम्बई, राय बरेली और तिरूवनंतपुरम में अवस्थित हैं। पिछले वर्ष नर्सों के संबंध में उत्पीड़न की शिकायतों के कारण विदेश में रोजगार के लिए जाने वाली नर्सों के हितों की रक्षा और कल्याण के लिए 'अपेक्षित उत्प्रवासन जांच' के तहत 'नर्स' के रूप में एक श्रेणी बनायी गयी है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दस पीओई कार्यालय द्वारा जारी पीओई-वार ईसी निम्नवत् है:

क्र.सं.	पीओई का नाम	2015	2016	2017	2018 (30.11.2018 की स्थिति के अनुसार)
1.	दिल्ली	185632	101000	62536	49230
2.	चंडीगढ़	36815	30317	44294	24653
3.	जयपुर	47573	31957	13205	15290
4.	राय बरेली	16468	18937	7068	5465

5.	हैदराबाद	48760	39006	41839	38741
6.	कोचीन	24079	16932	12392	10134
7.	त्रिवेंद्रम	18772	8872	2453	1836
8.	मुम्बई	353591	231609	170787	132414
9.	चेन्नई	41665	27491	26567	24976
10.	कोलकाता	10797	14817	9883	9540
	कुल	**784152**	**520938**	**391024**	**312279**

अब सितम्बर, 2017 से विदेश में रोजगार के लिए जाने से पूर्व भारत से समुद्र के रास्ते जाने वालों को भी ई-माईग्रेट प्रणाली में पंजीकृत किया जाता है। इससे समुद्री मार्ग से जाने वालों से जुड़ी शिकायतों में कमी आयी है।

प्रवास की प्रवृत्ति

वर्ष 2018 के दौरान (30 नवम्बर, 2018 की स्थिति के अनुसार) 3.12 लाख कामगार उत्प्रवासन अनुमति की प्राप्ति के पश्चात भारत से विदेश गए। चालू वर्ष के दौरान प्रमुख ईसीआर देशों के लिए दी गयी उत्प्रवासन अनुमति की देश-वार संख्या निम्न सारणी में दी गयी है:

उत्प्रवासित कामगार (लाख में)

क्र. सं.	देशों का नाम	वर्ष-2018 (30.11.2018)
1.	सउदी अरब	0.66
2.	यूएई	1.03
3.	कुवैत	0.52
4.	कतर	0.32
5.	ओमान	0.32
6.	बहरीन	0.09
7.	मलेशिया	0.16
8.	अन्य	0.02
	कुल	**3.12**

उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल राज्यों शीर्ष राज्यों में से थे जहां से उत्प्रवासित करने वालों की संख्या सबसे अधिक थी। वर्ष 2018 (30 नवम्बर, 2018) के दौरान इन राज्यों से उत्प्रवासित करने वाले लोगों की संख्या को पाई चार्ट में दर्शाया गया है।

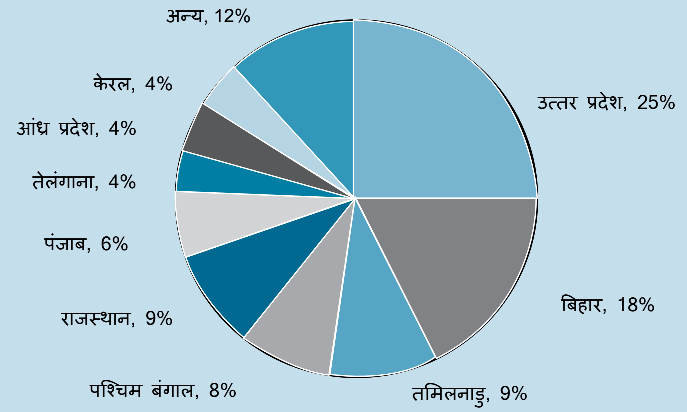

प्रवासियों की सुरक्षा और कल्याण

सरकार ने सुरक्षित और कानूनी प्रवासन तथा गणतव्य देशों में भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं:

(क) बेईमान एजेंटों द्वारा उत्पीड़न से भारतीय नर्सों को बचाने के लिए भारतीय नर्सों को ईसीआर देशों के लिए प्रवासी रोजगार हेतु प्रवास अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, भारतीय नर्सों को विदेशी नियोक्ता और भारतीय भर्ती एजेंट द्वारा पालन की जाने वाली निबंधन और शर्तों के साथ देश विशेष आदेश के माध्यम से सुविधाएं प्रदान की गयी हैं।

(ख) सभी प्रवासी कामगारों में से घरेलु नौकरानी और महिला (ईसीआर) कामगार सबसे संवेदनशील श्रेणियों में हैं। उनके हितों की रक्षा करने के लिए निम्नलिखित उपाए किए गए हैं:

- रोजगार की प्रकृति/श्रेणी के निरपेक्ष ईसीआर देशों के लिए ईसीआर पासपोर्टों पर उत्प्रवासन करने वाले सभी महिता प्रवासी (नर्सों को छोड़कर) के संबंध में 30 वर्ष की आयु सीमा अनिवार्य है;
- 2 अगस्त, 2016 की तिथि के आदेश के तहत अठारह ईसीआर देशों में प्रवासी रोजगार के लिए ईसीआर पासपोर्टों वाले सभी महिला कामगारों की उत्प्रावसन अनुमति को छह राज्य चालित भर्ती एजेंसियों के द्वारा ही अनिवार्य बना दिया गया है।
- विदेशी नियोक्ता यदि सीधे ही महिला कामगारों की भर्ती करता है तो उसे 2500 अमेरिकी डॉलर आरक्षित राशि जमा करना होगा जिसे कामगार के सुरक्षित भारत वापसी पर लौटा दिया जाएगा।
- सभी ईसीआर देशों के लिए सभी ईसीआर पासपोर्ट धारक महिला कामगारों की सीधी भर्ती के संबंध में दूतावास सत्यापन को अनिवार्य बनाया गया है।
- जून, 2015 से ई-माईग्रेट प्रणाली में विदेशी नियोक्ता (एफई) का पंजीकरण अनिवार्य बनाया गया है - एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें संबंधित भारतीय मिशन द्वारा एफई का सत्यापन शामिल है।

प्रवर्तन और शिकायत निवारण

गैर भुगतान/ मजदूरी के भुगतान में देरी, कामगारों की संविदा में एकतरफा परिवर्तन, मनमाने तरीके से कार्यों में परिवर्तन आदि के बारे में प्रवासी भारतीय कामगारों के उत्पीड़न के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं। ऐसे मामलों में

पीजीई संबंधित भर्ती एजेंट (आरए) को (यदि कामगार की भर्ती पंजीकृत आरए के माध्यम से हुई हो) अपने व्यय पर कामगारों को वापस भेजने का निर्देश दिया जाता है। यदि आरए ऐसा करने में असफल रहता है तो उसके पंजीकरण को रद्द करने तथा वापसी के खर्चे के वहन के लिए उसकी बैंक गारंटी को जब्त करने के लिए कार्रवाई की जाती है। विदेश स्थित भारतीय मिशन और वाणिज्य दूतावास संबंधित विदेशी नियोक्ता/ प्रयोक्ता के साथ अथवा गंतव्य देश में विदेशी सरकार के साथ ऐसी शिकायतों को उठाकर ऐसे मुद्दों का भी समाधान किया जाता है।

उन मामलों में जिनमें कथित तरीके से ठगने/ धोखाधड़ी किए जाने के संबंध में प्रवासी कामगारों/ भावी प्रवासी कामगारों अथवा उनके संबंधियों से गैर कानूनी एजेंटों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो ऐसी शिकायतों पर गैर कानूनी एजेंटों के विरूद्ध कारर्वाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के पास भेजा जाता है क्योंकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है तथा इसके अलावा ये एजेंट उन राज्यों में अपना परिचालन कर रहे हैं।

1 जनवरी, 2018 से 30 नवम्बर, 2018 तक के बीच कुल 324 शिकायतों को संबंधित राज्य सरकारों को अग्रेषित किया गया था। राज्य सरकारों / पुलिस अधिकारियों ने बदले में प्रवासी महारक्षक, विदेश मंत्रालय से जांच पश्चात अभियोजन की मंजूरी प्राप्त करता है, विदेश मंत्रालय प्रवासी अधिनियम, 1983 की धारा 27 के तहत उपयुक्त न्यायालय में दोषी पर अभियोजन चलान के लिए सक्षम प्राधिकारी होता है। ऐसी अभियोजन संस्वीकृति के लिए अनुरोध को प्रवासी के महारक्षक, विदेश मंत्रालय के कार्यालय द्वारा प्राथमिकता के आधार संसाधित और अभियोजन मंजूरी जारी किया जाता है। 1 जनवरी, 2018 से 30 नवम्बर, 2018 तक संबंधित राज्य सरकारों को पंद्रह अभियोजन संस्वीकृति जारी की गयी है जिन्होंने इसकी मांग की थी।

हाल में चिंता के साथ यह नोट किया गया है कि मानव तस्करी की दरें बढ़ रही हैं, विशेषकर बच्चों और महिलाओं की तस्करी संबंधी मामले। मंत्रालय ने छह राज्य चालित भर्ती एजेंसियों द्वारा अनुमति दिए जाने के लिए अठारह ईसीआर देशों में जाने वाले महिला कामगारों के कल्याण के लिए अग्रसक्रिय कदम उठाया है। तथापि, अधिकांश मामलों में भारतीय प्रवासियों की तस्करी गैर कानूनी एजेंटों के माध्यम से किया गया है जो इस प्रणाली की उपेक्षा करते हैं। विशेष रूप से ये एजेंट पर्यटन वीजा पर लोगों को विदेश भेज रहे हैं और उन्हें धोखा देते हैं अथवा कभी-कभी उनकी तस्करी करते हैं। जब कभी भी ओसी और पीजीई प्रभाग को मानव तस्करी संबंधी शिकायतों की सूचना दी जाती है, इन्हें इस मामले में कार्रवाई करने के लिए सीबीआई अपराध मैनुअल के अध्याय 3.5 (च) के तहत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेज दिया जाता है।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 10 जनवरी, 2018 को एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्री सहित एनआरआई मंत्रियों ने भाग लिया। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने इस पर जोर दिया कि राज्यों को अपने यहां परिचालन कर रहे गैर कानूनी एजेंटों को पकड़ने में कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने इसे भी रेखांकित किया कि राज्यों को गैर कानूनी एजेंटों के विरूद्ध मीडिया अभियान चलाना चाहिए।

विदेशी नियोक्ताओं के विरूद्ध शिकायतें

किसी उत्प्रवासी या उसके रिश्तेदार से शिकायत की प्राप्ति के तत्काल बाद मिशन /पोस्ट उक्त मामले को मैत्रीपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए विदेशी नियोक्ता और स्थानीय अधिकारियों के साथ उठाया जाता है। उपयुक्त स्थिति में वे संबंधित भर्ती एजेंट और उत्प्रवासियों के महारक्षक के साथ समन्वय कर कामगारों को वापस भेजने की कोशिश करते हैं। भारतीय मिशन और पोस्ट भी भारतीय उत्प्रवासियों के साथ बुरे बर्ताव की शिकायतों के आधार पर पूर्व अनुमोदित श्रेणी सूची में ऐसे विदेशी नियोक्ताओं को शामिल करने की भी सिफारिश करता है। ऐसी सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय पूर्व अनुमोदित श्रेणी में संबंधित विदेशी कंपनी को रखता है। जब किसी विदेशी कंपनी को पूर्व अनुमोदन श्रेणी सूची में शामिल किया जाता है तो उसे भारत में कामगारों को भर्ती करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

भर्ती एजेंटों के संबंध में 1 जनवरी, 2018 से 30 नवम्बर, 2018 की अवधि के दौरान ओई और पीजीई प्रभाग की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नवत् हैं:

क्र.सं.	क्रियाकलाप का नाम	स्थिति
1	जारी किया गया नया पंजीकरण प्रमाणपत्र	109
2.	दिए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण	258
3	जारी किए गए कमी संबंधी पत्र	245
4	एजेंसी के बंद होने पर जारी बैंक गारंटी	83
5	पते, शाखा कार्यालय, कार्यालय पदाधिकारियों के नाम आदि में परिवर्तन के लिए दिया गया अनुमोदन।	122
6	पंजीकृत भर्ती एजेंटों के विरूद्ध कार्रवाई- कारण बताओ नोटिस जारी करना (एससीएन)	61
7	गैर कानूनी एजेंटों के विरूद्ध राज्य सरकार को अभियोजन संस्वीकृति / पत्र	15
8	राज्य सरकारों को संदर्भित शिकायतों की संख्या	324

प्रवासी भारतीय केन्द्र (पीबीके)

प्रवासी भारतीय केन्द्र (पीबीके) जिसमें प्राथमिक रूप से ओसीआई/ पीआईओ कार्ड धारकों के लिए अत्याधुनिक आडिटोरियम, बहुउद्देशीय हॉल, सम्मेलन और विचार गोष्ठी हॉल और चौबीस अतिथि कक्ष है, का उद्घाटन 2 अक्टूबर, 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया था। यह केन्द्र, जो 15क, रिजाल मार्ग, चाणक्यापुरी, नई दिल्ली के केन्द्र में अवस्थित है, प्रवासी भारतीय समुदायों के लिए एक श्रद्धांजलि है और विश्व के विभिन्न भागों में उनके प्रवासन(उनके समक्ष विदेश में आने वाली चुनौतियों, उनकी उपलब्धियों और योगदान को स्मरण करता है।

पीबीके में नियमित रूप से उच्च स्तरीय बैठकें/ सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। इनमें से कुछ हैं- सभी पीबीडी सत्र और पीबीडी की संचालन समिति की बैठक, भारत-रूस कूटनीति संबंध के 70 वर्ष को मनाने के लिए वर्ष भर का समारोह, 9वां एचओएम सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लिखी गयी 'एक्जाम वारियर" को विमोचन करना, प्रथम पीआईओ संसदीय सम्मेलन, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की 4थी वर्षगांठ को मनाना, भारत-अमेरिका-जापान त्रिपक्षीय डीजी स्तरीय बातचीत, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संबंध में पुरस्कार देते हुए पृथ्वी पुरस्कार समारोह, 2018 के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम चैम्पियन, नीति आयोग के कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों तथा भारतीय चुनाव आयोग, भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों द्वारा आयोजित अन्य उच्च स्तरीय कार्यक्रमों को पीबीके में आयोजित किया गया है। जनवरी से नवम्बर, 2018 तक की अवधि के दौरान पीबीके में कुल 193 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, इनमें दो भारत के राष्ट्रपति स्तरीय कार्यक्रम, चार उप राष्ट्रपति स्तरीय कार्यक्रम, और तीन प्रधानमंत्री स्तरीय कार्यक्रम शामिल हैं। दिसम्बर, 2018 के लिए लगभग पंद्रह कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं।

एक परस्पर डिजिटल संग्रहालय नामत: 'महात्मा गांधी एक प्रवासी' को दक्षिण अफ्रीका में उनके आने और भारत वापस आने, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका तथा भारत में एक जन नेता के रूप में उनकी यात्रा के जीवन घटनाक्रम को दर्शाते हुए इस केन्द्र के प्रथम तल पर प्रदर्शित किया जा रहा है। इस प्रकार, इस संग्रहालय में पैंतीस राजदूतों/ उच्चायुक्तों / विदेशी शिष्टमंडलों को शामिल करते हुए ईक्यासी से अधिक देशों से 6000 से अधिक फुटबॉल का साक्ष्य है। साथ हीं, दिल्ली में और इसके आसपास के विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों से 4100 छात्रों ने इस प्रदर्शनी का शैक्षणिक भ्रमण किया है।

पीबीके पुस्तकालय भारतीय समुदाय के बारे में लिखित और साहित्य का एक बहुमूल्य संग्रह है। इसमें 3500 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है; इनमें से कुछ पुस्तक इन समुदायों, उनके इतिहासों, वंशावली, उद्‌वविकास, वृत्तिदान, शिक्षा और वर्तमान स्थिति की सुनवाई और क्लेश से संबंधित है। यहां प्रमुख समुदाय वाले देशों, उनके वर्तमान प्रकशनों और पत्रिकाओं से जुड़े साहित्य का एक कोना भी है। सभी राष्ट्रीय भाषाओं में साहित्य पाक्षिक, पुस्तक और डिजिटल सामग्री सहित, पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। डिजिटल सामग्री पर बल देने के साथ यह पुस्तकालय भारत में प्रमुख डिजिटल ज्ञान नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करता है। स्थल अध्ययन/ पठन के लिए पुस्तकालय में कार्यस्थल उपलब्ध हैं।

इस दौरान यह केन्द्र भारत और अपने समुदायों के बीच धारणीय, सहजीवी और परस्पर लाभप्रद आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अनुबंध के लिए क्रियाकलापों का एक केन्द्र विकसित कर रहा है।

23

प्रशासन और स्थापना

प्रशासनिक प्रभाग

प्रशासनिक प्रभाग का सतत प्रयास मुख्यालय स्तर पर मंत्रालय की मानव पूंजी प्रबंधन तथा विदेश स्थित 186 भारतीय मिशनों/ पोस्टों द्वारा जनशक्ति का इष्टतम प्रयोग रहा है। इसके लिए यह प्रभाग संवर्ग प्रबंधन का निरीक्षण करता है जिसमें भर्ती, प्रशिक्षण, पोस्टिंग/ स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति और अन्यों के बीच कैरियर उन्नयन जैसे विभिन्न पहलु शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग भारतीय मिशनों और पोस्टों के लिए स्थानीय कर्मचारियों सहित भारत सरकार के संगत सभी नियमों और विनियमों के निरूपण, संशोधन और सुधारों के माध्यम से अपने व्यक्तिगत नीतियों का अंशांकन भी करता है।

वर्ष 2018-21 के दौरान अफ्रीमा में अठारह नए मिशनों को खोलने के लिए मार्च, 2018 को मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसरण में प्रथम चरण में छह मिशनों को खोले जाने के लिए पहचान की गयी है। इनमें से रवांडा में मिशन पहले से ही खोल दिया गया है और जिबूती और इक्वेटोरियल गुएना में जल्द की मिशन खोला जाना है। कांगों गणतंत्र, बुरकीना फासो और गुएना में मिशनों के संबंध में प्रारंभिक प्रशासनिक तथा स्थापना संबंधी कार्य पहले से चल रहा है।

इस मंत्रालय की वर्तमान संस्वीकृत संख्या 4225 (परिशिष्ट पांच) जिसमें मिशनों और पोस्टों में ये पद लगभग 53 प्रतिशत हैं। कुल संख्या को मंत्रालय के विभिन्न संवर्गों में बांटा गया है यथा भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस), सामान्य संवर्ग, स्टेनोग्राफर संवर्ग, भाषांतरण संवर्ग तथा कानूनी और संधि संवर्ग और अन्य संवर्ग ।

मंत्रालय ने भर्ती वर्ष 2018-19 में प्रत्यक्ष भर्ती (डीआर) और विभागीय पदोन्नति (डीपी) के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर कार्मिक की भर्ती द्वारा अपनी जनशक्ति को संवर्धित किया (परिशिष्ट छह)। मंत्रालय भारत सरकार के नियमों की तर्ज पर अपने कार्मिकों में उनके उपयुक्त प्रतिनिधित्व के लिए विक्लांग व्यक्तियों हेतु पर्याप्त अवसर सुनिश्चित करता है। मंत्रालय भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/ राज्य सरकारों

तथा विशिष्ट एजेन्सियों से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को लेता है ताकि अपनी विविध आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

मंत्रालय यथा आवश्यक अंतरराष्ट्रीय कानून संबंधी विशिष्ट मोड्यूल, साइबर सुरक्षा, लैंगिक बजट, लेखा, वाणिज्य दूतावास और पासपोर्ट सेवाओं, सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग आदि के साथ अपने सभी संवर्गों के प्रशिक्षण पर ध्यान केन्द्रित करता है। भाषांतरण स्तर सहित आईएफएस अधिकारियों के भाषाई कौशल के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इन वर्षों में इसके परिणामस्वरूप सेवा में विदेशी भाषा कौशल के साथ अधिकारियों के उपयुक्त बड़े समूह का सृजन हुआ है (परिशिष्ट सात)।

यह प्रभाग मिशनों/ पोस्टों के कई कार्यमूलक क्षेत्रों में विचारों के आदान-प्रदान, सूचना संग्रहण और निगरानी के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में मुख्यालयों और मिशनों/पोस्टों के बीच एक ऑनलाइन इंटरफेस ई-समीक्षा पोर्टल के रूप में प्रौद्योगिकी टूलों का सक्रिय रूप से उपयोग करना जारी रखा। सरकार के डिजिटल अभियान पहल के साथ संबद्ध होकर कर्मचारी सूचना प्रणाली मोड्यूल को वर्ष के दौरान लागू किया गया था और मंत्रालय ने अपने सभी भुगतानों को करने के लिए जन वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना जारी रखा ।

स्थापना प्रभाग

स्थापना प्रभाग मंत्रालय के सभी कार्यालय भवनों और आवासीय परिसरों के अनुरक्षण और देखभाल का कार्य करता है; कार्यालय उपकरण, फर्नीचर और स्टेशनरी की खरीद व आपूर्ति करता है; तथा विदेश स्थित मिशनों और पोस्टों के लिए विशेष प्रापण वस्तुओं और कार्यालय वाहनों की खरीद और आपूर्ति से संबंधित मामलों को देखता है।

मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 के दौरान स्वच्छ भारत के विभिन्न क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी की है। मंत्रालय ने भारत में अपने सभी कार्यालयों और विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों/पोस्टों में 1-15 जनवरी, 2018 तक स्वच्छता

पखवाड़े का आयोजन किया। 15 सितम्बर से 02 अक्टूबर, 2018 के बीच स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम भी मनाया गया। विदेश स्थित मिशनों/ पोस्टों के अलावा चाणक्यपुरी और द्वारका परिसरों में भी विदेश मंत्रालय छात्रावासों में श्रमदान का आयोजन किया गया। दिल्ली में अपने सभी परिसरों में सफाई और उचित रखरखाव को बनाए रखने के लिए विदेश सचिव सहित सभी एमईए सचिवालयों द्वारा 16 जुलाई-10 अगस्त, 2018 से साप्ताहिक स्वच्छता जांच की गयी। एमईए के सभी कार्मिकों को भी सलाह दी गयी कि वे प्रत्येक दिन 'स्वच्छ समय' का पंद्रह मिनट रखे। साउथ ब्लॉक कार्यालय में कई शौचालयों को वर्ष के जीर्णोद्धार किया गया और वर्तमान में शेष शौचालयों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जगह बचाने तथा कार्यदशा में सुधार करने के लिए कॉम्पेक्टरों की स्थापना सहित कई कार्यालय कक्षों में मरम्मत और अनुरक्षण (आर एंड एम) कार्यों को भी किया गया। अप्रचलित और अप्रयुक्त वस्तुओं/ उपकरणों आदि के निपटान के लिए समीक्षा और फाइलों/ रिकार्डों को समाप्त करने पर विशेष ध्यान दिया गया।

मंत्रालय से एकल प्रयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बाहर निकालने के लिए मंत्रालय का एक प्लास्टिक लेखा परीक्षा हाल ही में गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) मैसर्स चिंतन एनवारामेंट रिसर्च एंड एक्शन ग्रुप द्वारा किया गया है। इसकी रिपोर्ट की जांच की जा रही है और मंत्रालय जल्द ही भारत और विदेश में सभी एमईए भवनों में एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने और इसमें कमी लाने के लिए अपनी कार्य योजना और दिशानिर्देश लेकर आएगा।

'कार्यालय आवंटन और मालसूची प्रबंधन पोर्टल' सृजन की प्रक्रिया में है ताकि विभिन्न कार्यालयों और कक्षों में संसाधनों/ वस्तुओं को बेहतर तरीके से प्रबंधन किया जा सके। अब ऑनलाइन स्टेशनरी प्लेटफार्म पूर्णत: कार्य करने लगेगा जिससे स्टेशनरी वस्तुओं की ऑनलाईन प्राप्ति हो पाएगी। पद आधारिक नेमप्लेट को समरूपता लाने के लिए साउथ ब्लॉक के सभी कार्यालयों में लगाया गया।

1 अप्रैल, 2018 -30 नवम्बर, 2018 की अवधि के दौरान विदेश स्थित हमारे मिशनों/ पोस्टों में सरकारी वाहनों के प्रतिस्थापन/खरीद के लिए अड़तालीस प्रस्तावों को मंत्रालय द्वारा संसाधित किया गया और संस्वीकृत किया गया। मंत्रालय एमबी ई 400 4एम के उत्पादन को बंद करने के बाद फ्लेग कार के अनुमोदित मॉडल के रूप में एमबी ई 450 4एम के नामोद्दिष्ट करने के लिए वित्त मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने पात्र अधिकारियों के आवास के लिए समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की खरीद के संबंध में प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को भी सरलीकृत किया है। शेष सभी भारतीय मिशनों और पोस्टों में वीडियो सम्मेलन सुविधाओं को लगाने के लिए प्रयास चल रहे हैं।

घरेलु स्रोतों से प्राप्त उपहारों के लिए कोष की स्थापना करने के लिए सरकार के निर्णय के बाद संबंधित विभाग को आवश्यक दिशानिर्देश दिया गया तथा इसके साथ एमईए के तोशाखाना के बेहतर प्रचलन को भी साझा किया गया। मिशनों/ पोस्टों और मुख्यालयों में प्रदर्शन करने के लिए ऑबजेक्ट डी आर्ट (ओडीए) की कमी को पूरा करने के साथ तोशाखाना से कई वस्तुओं को ओडिए प्रकोष्ठ में स्थानांतरित किया गया।

2018-19 में, एमईए छात्रावासों और आवासीय परिसरों के नियमित अनुरक्षण के अतिरिक्त बैडमिंटन कोर्ट के निर्माण, सोलर वाटर हीटरों के उन्नयन, बच्चों के पार्क को पुन: बनाने और पार्किंग क्षेत्रों के सीमांकन और पेंटिंग करने जैसी सुविधाओं को पूरा किया गया था। 15 सितम्बर- 2 अक्टूबर, 2018 को स्वच्छता ही सेवा मनाया गया तथा आवासीय परिसरों के आसपास के क्षेत्रों को साफ किया गया तथा इसी अवधि के दौरान कचरा पेटी भी लगाए गए। सभी आवासीय परिसरों में एलईडी लाइटों की स्थापना की गयी है। सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप, दो एमईए परिसारों के पुनर्विकास के कारण उत्पन्न आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संपदा निदेशालय द्वारा एमईए पूल को पचास फ्लेटों का कोटा आवंटित किया गया है। एमईए पूल आवासीय परिसर की मांग करते हुए सामान्य पूल आवासीय घरों (जीपीआरए) के तहत अनिवार्य एप्लिकेशन की नई नीति इस रिपोर्ट की अवधि के दौरान अपनायी गयी है ।

वैश्विक संपदा प्रबंधन (जीईएम)

हैदराबाद में विदेश भवन के निर्माण के लिए एक भूमि के टुकड़े को अधिगृहीत किया गया है। हमबर्ग में चांसरी के लिए एक निर्मित संपदा को अधिगृहीत किया गया है। नैरोबी और म्युनिख में मिशनों/ पोस्टों के लिए चांसरी के लिए संपत्ति

का अधिग्रहण अंतिम चरण में है। मैक्सिको शहर, केयेव और बिस्केक में अधिग्रहण के लिए चांसरी हेतु संपत्तियों की पहचान की गयी है। जीईएम पोर्टल को 2018 में शुरू किए जाने की संभावना है।

फ्युनतशोलिन और काबुल में दो नयी निर्माण परियोजनाएं चल रही हैं और उसके बाद नौ निर्माण परियोजनाएं चल रहीं हैं यथा निकोसिया, ताशकंत, अदिश अबाबा, इस्लामाबाद, पोर्ट लुईस, पोर्ट आफ स्पेन (एमजीआईसीसी), वेलिंग्टन, डब्लूएचएस (पोर्ट लुईस) और खारतोम। छह निर्माण परियोजनाएं हैं जो पूरी होने वालीं हैं यथा वार्साय, अबूजा, डारे सलाम, बहरीन, ढ़ाका और काठमांडू।

रिपोर्ट के तहत इस अवधि के दौरान बैंकॉक में चांसरी के व्यापक नवोन्मेष कार्य को पूरा कर लिया गया है। अराका, किंग्सटन, ब्रसेल्स, कैपटाउन, हरारे, सियोल, काठमांडू, बर्लिन, ब्रेसिलिया, होस्टन में ब्रेटिस्लावा कांसुल जनरल (सीजी) रेसिडेंस, हांगकांग (भारत भवन), फ्रैंकफर्ट और बीजिंग में चांसरी, पीएमआई, न्यूयार्क, जकार्ता, हेरात, जलालाबाद में दूतावास अवासों में विभिन्न आर एंड एम कार्य को अनुमोदित किया गया है तथा इनका कार्य चल रहा है। अटलांटा, बेलग्रेड, डारे सलाम, हरारे, मास्को, न्यूयार्क, ओटावा, वाशिंगटन, यंगून, पेरिस, पोर्ट लुईस, पोर्ट आफ स्पेन, वाशिंगटन और वार्सा में प्रमुख नवोन्मेषी परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में है जहां परामर्शदाता की नियुक्ति, वास्तुकला ड्राईंग की तैयारी और चल रहे नवोन्मेषी कार्य तक ठेकेदारों को कार्यो का ठेका देने के विभिन्न विकास चरणों के कार्य चल रहे हैं। डबलिन में चांसरी का नवोन्मेष कार्य पूरी तेजी से चल रहा है।

हैदराबाद, लखनऊ, बरेली, भुवनेश्वर, जयपुर, चेन्नई, तिरूवनंतपुरम में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों (आरपीओ)/ आव्रजन के प्रोटेक्टर (पीओई) में नवोन्मेष का कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्लूडी) को सौंपा गया है।

वायु सेना स्टेशन (एएफएस) पालम में रिसेप्टोरियम का आंतरिक नवोन्मेष और पुनर्निर्माण पूरी रफ्तार से चल रहा है।

कल्याण प्रभाग

कल्याण प्रभाग विदेश मंत्रालय (एमईए) के सभी कर्मचारियों के सामान्य कल्याण की देखभाल करता है। चालू वर्ष के दौरान एमईए ने पांच कर्मचारियों को खोया जिनके लिए आवश्यक सहायता एमईए कर्मचारी लाभ से प्रशाखा और अनुग्रह राशि का भुगतान दिया गया ताकि पीड़ित परिवारों को लाभ मिल सके।

कल्याण अनुभाग अनुकंपा आधारिक नियुक्ति के मामले में मृत्यु के मामले दर मामले को देखता है। इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति द्वारा मल्टी टास्किंग कर्मचारी (एमटीएस) और कनिष्ठ सचिवालय सहायक (जेएसए) के रूप में मंत्रालय में अनुकंपा आधारित नियुक्ति श्रेणी में नौ ऐसे आवेदकों की नियुक्ति की गयी।

एमईए अधिकारियों के पांच बच्चों को एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान किया गया तथा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में तैंतीस बच्चों को प्रवेश दिया गया । इन अभ्यर्थियों के चयन को इस उद्देश्य के लिए गठित समिति के माध्यम से पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से किया गया था।

केन्द्रीय विद्यालय के तैंतीस सीटों का इस्तेमाल अधिकारियों के बच्चों तथा मंत्रालय के कर्मचारियों तथा विदेश स्थित भारतीय मिशनों/ पोस्टों में तैनात अन्य केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के बच्चों द्वारा इस्तेमाल किया गया।

उपर्युक्त के अलावा, विभिन्न गतिविधियां यथा कोष बनाने के अभियान, अंतर मंत्रालयी खेल टूर्नामेंट आदि में एमईए कर्मचारियों की भागीदारी, रक्तदान और अंगदान जागरूकता शिविर में भागीदारी को कल्याण प्रभाग द्वारा आयोजन किया गया। कल्याण प्रभाग ने अनुदान सहायता प्रदान कर मनोरंजन क्लबों की स्थापना करने के लिए विदेश स्थित भारतीय मिशनों/ पोस्टों की भी सहायता की।

कल्याण विभाग ने जवाहरलाल नेहरू भवन (जेएनबी), विदेश मंत्रालय (एमईए) छात्रावास, के.जी. मार्ग, चाणक्यपुरी और द्वारका में एमईए आवासीय परिसरों में योग कक्षाओं को आयोजित करने के लिए मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के योग शिक्षकों के साथ समन्वय किया।

इसके अतिरिक्त, वाणिज्य विभाग ने आधार कार्डों और पैन कार्डों आदि प्राप्त करने में विभिन्न सरकारी / निजी विद्यालयों के लिए अपने बच्चों के प्रवेश के लिए मुख्यालयों के लिए मिशनों से एमईए से वापस आने वाले अधिकारियों को सामान्य सहायता और मदद दिया।

24

सूचना का अधिकार और मुख्य लोक सूचना अधिकारी

मंत्रालय ने वर्ष के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए प्रयास जारी रखा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपी एंड टी) के निर्देशों के अनुसार, स्व: प्रकटीकरण , आरटीआई आवेदनों / अपील / प्रतिक्रियाओं और मासिक आंकड़ों को सार्वजनिक डोमेन पर अपलोड करने का कार्यान्वयन किया गया । विदेशों में 184 मिशन / पोस्ट में आरटीआई आवेदनों की ऑनलाइन स्वीकृति और निपटान की प्रणाली को आरटीआई वेब पोर्टल के साथ संरेखित करके लागू किया गया है।

मंत्रालय में 1 अप्रैल 2018 से 30 नवंबर 2018 की अवधि के दौरान, आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए कुल 1946 आरटीआई आवेदन और 160 प्रथम अपीलें प्राप्त हुई हैं और उनका संतोषजनक तरीके से निस्तारण किया गया है। आवेदनों में, सामान्य रूप से, विषय थे- विदेशी संबंध, प्रशासनिक मुद्दे, हज यात्रा, द्विपक्षीय दौरे और उन पर किए गए व्यय।

सभी केंद्रीय सूचना आयोग की सुनवाई में संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों और आरटीआई सेल के प्रतिनिधि ने भाग लिया है और मंत्रालय को केंद्रीय सूचना आयोग से कोई प्रतिकूल निर्णय / टिप्पणी नहीं मिली है। समय पर आवश्यकतानुसार केंद्रीय सूचना आयोग में तिमाही विवरणी दाखिल की गई हैं।

25

ई-शासन और सूचना प्रौद्योगिकी

ई-शासन और सूचना प्रौद्योगिकी (ईजी एंड आईटी) प्रभाग को भारत सरकार के मानक मानदण्डों के अनुसार राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के समन्वय के साथ विदेश मंत्रालय (एमईए) में व्यवहार्यता अध्ययन संचालित करने, विभिन्न ई-शासन अनुप्रयोगों को डिजाइन, विकसित, परीक्षित, क्रियान्वित और अनुरक्षित करने का अधिदेश दिया गया है। ईजी एंड आईटी प्रभाग समस्त सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना की अधिप्राप्ति, अनुरक्षण और रख-रखाव के लिए विदेश मंत्रालय और विदेशों में स्थित मिशनों/पोस्टों को समस्त सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संबंधी समस्त जानकारी भी प्रदान करता है।

ईजी एंड आईटी प्रभाग विदेश मंत्रालय तथा विदेशों में स्थित समस्त मिशनों/पोस्टों में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विभिन्न अवयवों को क्रियान्वित करने के लिए कदम उठा रहा है। ई-क्रांति की चार मिशन मोड परियोजनाएं (डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के चार स्तंभ) अर्थात् ई-ऑफिस, ई-अधिप्राप्ति, आप्रवासन, वीजा, विदेशियों का पंजीकरण और ट्रैकिंग प्रणाली (आईवीएफआरटी) तथा पासपोर्ट सेवा परियोजनाएं (पीएसपी) एमईए और विदेशों में स्थित मिशनों/पोस्टों में वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही है।

विदेश मंत्रालय ने अनेक ई-शासन और स्वचालन परियोजनाएं भी संचालित की हैं जो डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप हैं। स्वचालन तथा नेटवर्किंग को विदेश मंत्रालय में कार्यकरण के सभी स्तरों पर सहक्रिया हासिल करने तथा सरकारी कर्मचारियों को कार्यकुशल सेवाएं प्रदान करने के लिए उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ईजी एंड आईटी प्रभाग ने अनेक ई-शासन परियोजनाएं पूर्णत: क्रियान्वित की हैं तथा उनमें से कुछ अभी तक क्रियान्वित की जा रही है। निम्नलिखित ई-शासन परियोजनाएं क्रियान्वित की गई हैं:-

- **विदेश सेवा संस्थान (एफएसआई) पूर्व-छात्र पोर्टल (http://fsialumani.gov.in).** यह पोर्टल विदेश सेवा संस्थान, नई दिल्ली के पूर्व-छात्रों के पंजीकरण और प्रबंधन में सहायता प्रदान करता है जिसके द्वारा विदेश मंत्रालय तथा उन विदेशी राजनयिकों के बीच में संपर्क

बनाने में सहायता मिलनी है जिन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत एफएसआई में प्रशिक्षण हासिल किया है।

- **ई-लेखापरीक्षा पोर्टल (लेखापरीक्षा पैरा प्रबंधन पोर्टल).** यह पोर्टल विदेश मंत्रालय के भीतर विभिन्न व्ययकारी यूनिटों जैसे प्रभागों और मिशनों/पोस्टों के संबंध में नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) तथा लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा उठाए गए विभिन्न लेखापरीक्षा पैराओं की ऑनलाइन रिपोर्टिंग और अनुवीक्षण को सुकर बनाता है।

- **नवीकृत भारत के जानें कार्यक्रम (केआईपी) पोर्टल (http://kip.gov.in).** यह पोर्टल केआईपी कार्यक्रमों के बारे में प्रयोक्ताओं को सूचना प्रदान करके, उन्हें कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करने में समर्थ बनाकर तथा उनके आवेदनों का प्रक्रमण करके विदेश मंत्रालय के महत्वाकांक्षी प्रवासी भारतीय क्रियाकलाप कार्यक्रम को सुविधा प्रदान करता है। नई प्रारंभ हुई केआईपी योजनाओं जैसे स्व-वित्त-पोषित केआईपी और स्वर्ण जयंती केआईपी के आवेदन के लिए रूपात्मकताओं को शामिल करने के लिए इस साइट को नवीकृत किया गया है।

- **नवीकृत प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) वेबसाइट (http://pbindia.gov.in).** पीबीडी 2017 की मौजूदा वेबसाइट को नवीकृत किया गया था तथा इसमें पीबीडी के नवीनतम संस्करण के लिए प्रयोक्ता रजिस्ट्रीकरण माड्यूल उपलब्ध कराया गयाहै और एक संवर्धित डिजाइन फार्मेट में उसके बारे में अद्यतन जानकारी को शामिल किया गया है।

- **राजनयिक पहचान पत्र रजिस्ट्रीकरण और निर्गम प्रणाली.** इस पोर्टल का आशय विद्यमान पहचान पत्रों में सुरक्षा संबंधी विशेषताओं का सुधार करते हुए और उनके विधिमान्यकरण को आसान बनाते हुए भारत में तैनात विदेशी राजनयिकों को पहचान पत्र जारी

करने की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाना है। यह परियोजना पूर्ण की जा चुकी है तथा इसे नयाचार प्रभाग द्वारा औपचारिक रूप से प्रारंभ किया जाना प्रतीक्षित है।

इसके अलावा, ईजी एंड आईटी प्रभाग ने अनेक परियोजनाएं संचालित की है जो विदेश मंत्रालय के आंतरिक कार्यकरण में सुधार लाने में सहायता करती हैं। ये परियोजनाएं अवसंरचना प्रबंध साफ्टवेयर, कार्मिक प्रबंध साफ्टवेयर आदि की प्रकृति की हैं। इनमें से कुछ परियाजनाएं हैं - स्थापना प्रभाग के लिए ऑनलाइन इन्वेंट्री प्रबंध प्रणाली, सुरक्षा ब्यूरो के लिए कार्मिक प्रबंध प्रणाली, वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली 2.0 आदि।

ऊपर उल्लेख की गई क्रियान्वित ई-शासन परियोजनाओं के अलावा, एकीकृत मिशन लेखाकरण प्रणाली वर्णन 2.0, प्रवासी भारतीय केन्द्र के लिए संपत्ति प्रबंध वेबसाइट तथा वैश्विक संपदा प्रबंध पोर्टल पर विकास कार्य पूर्ण होने के अंतिम चरण पर चल रहा है।

क्रियान्वित की गई ई-शासन परियोजनाएं विदेश मंत्रालय के अधिकारियों, अन्य सरकारी कर्मचारियों, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई)/भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) तथा द्विपक्षीय/त्रिपक्षीय सद्भावना कार्यक्रमों के लाभार्थियों को ई-शासन सेवाओं के लाभ प्रदान कर रही है।

विदेश मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया के हितों का लाभ उठाने के लिए सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का इष्टतमीकरण करने के प्रयोजनार्थ एक संकेन्द्रित दृष्टिकोण अपनाया है। इसके परिणामस्वरूप विदेश मंत्रालय में आईटी परिसंपत्तियों का आनुपातिक विकास हुआ है तथा आईटी अनुप्रयोगों पर निरंतर निर्भरता और आश्रिता में भी वृद्धि हुई है। इस दिशा में की गई पहलें इस प्रकार हैं:

- **विदेश मंत्रालय के भवनों में आईटी अवसंरचना का उन्नयन :** विदेश मंत्रालय के पटियाला हाउस और साउथ ब्लॉक भवनों में नेटवर्किंग अवसंरचना का उन्नयन हुआ है। विदेश मंत्रालय के सभी भवनों में सुरक्षा अवसंरचना की समीक्षा की जा रही है तथा इसे निरंतर अद्यतन बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
- **साइबर क्षमता भवन :** विदेश मंत्रालय में साइबर सुरक्षा के बारे जागरूकता में वृद्धि करने तथा उन्हें साइबर जोखिमों को प्रबंधित करने और उन्हें न्यून बनाने में समर्थ बनाने पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था। साइबर सुरक्षा पर तीसरा ऑनलाइन पाठ्यक्रम चल रहा है तथा अस्सी कर्मचारियों ने पाठ्यक्रम के लिए नामांकन कराया है।
- **'भारत में कृत्रिम आसूचना के क्षमता निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रवासी भारतीय दिवस पैनल चर्चा :** यह कार्यक्रम प्रवासी भारतीय केन्द्र, नई दिल्ली में 14 जून, 2018 को आयोजित किया गया जिसमें भारत और विदेश से कृत्रिम आसूचना विशेषज्ञों को कृत्रिम आसूचना की व्याप्ति तथा भारत के लिए उसके प्रभावों पर उनके विचार प्रस्तुत करने और इस क्षेत्र में क्षमता में वृद्धि करने के लिए उपाय सुझाने के लिए आमंत्रित किया गया था।

26

संसद और समन्वय प्रभाग

संसद प्रभाग

संसद प्रभाग संसद के साथ मंत्रालय का संपर्क-सूत्र तथा समस्त संसद संबंधी कार्यों के लिए मंत्रालय को नोडल बिंदु है। इसके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों में शामिल है - संसद प्रश्नों के उत्तरों के संबंध में मंत्रालय के समस्त प्रभागों के साथ संपर्क स्थापित करना, संसदीय आश्वासनों की पूर्ति करना, ध्यानकर्षण नोटिसों और प्रस्तावों पर कार्यवाही करना, अपनी ओर से वक्तव्य जारी करना, विदेश नीति पर वाद-विवाद/अल्कालिक चर्चाएं, विधायी कार्य, संसद में प्रतिवेदनों और दस्तावेजों को रखना आदि। संसद सत्र में प्रारंभ होने से पूर्व, प्रभाग आगामी सत्र के दौरान संसद में उठाए जा सकने वाले महत्वपूर्ण मामलों पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और संसदीय कार्य मंत्रालय के लिए सार-संग्रह भी करता है। प्रभाग विदेशी मामलों संबंधी परामर्शदात्री समिति की बैठकों का समन्वय भी करता है तथा विदेशी मामों संबंधी संसदीय स्थायी समित से संबंधित कार्यों को देखता है और अन्य संसदीय समितियों के साथ मंत्रालय का समन्वयन स्थापित करता है।

परामर्शदात्री समिति की बेठकें

अप्रैल, 2018 से दिसम्बर, 2018 की अवधि के दौरान विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने विदेशी मामलों संबंधी परामर्शदात्री समिति की दो बैठकों की अध्यक्षता की:

(i) परामर्शदात्री समिति की दूसरी बैठक (2018 की) परामर्श सेवाओं के बारे में विदेश मंत्रालय की नई पहलें विषय पर 9 अगस्त, 2018 को आयोजित हुई।

(ii) परामर्शदात्री समिति की तीसरी बैठक (2018 की) राज्यों में पहुंच स्थापित करने के लिए विदेश मंत्रालय की पहलें विषय पर 27 दिसम्बर, 2018 को आयोजित हुई।

परामर्शदात्री समिति की एक बैठक जनवरी से मार्च, 2019 की अवधि के दौरान आयोजित की जानी अपेक्षित है।

विदेशी मामलों संबंधी संसदीय स्थायी समित की बैठकें

अप्रैल, 2018 से दिसम्बर, 2018 की अवधि के दौरान विदेशी मामलों संबंधी संसदीय स्थायी समिति की आठ बैठकें आयोजित की गईं:

(i) 'संभावित उत्प्रवासियों के लिए उपयुक्त विधायी ढांचा और कौशल विकास पहलकदमों सहित उत्प्रवासी कर्मकारों से संबंधित मुद्दे' विषय पर 2 अप्रैल, 2018 को एक ब्रीफिंग बैठक आयोजित की गई जिसमें 'विवादग्रस्त क्षेत्रों में भारतीय कर्मकारों की सुरक्षा और संरक्षा' पर विशेष बल प्रदान किया गया था।

(ii) 'भारत-श्रीलंका संबंध : मछुआरों के मुद्दों सहित व्यापार और सुरक्षा' विषय पर 4 अप्रैल, 2018 को एक ब्रीफिंग बैठक आयोजित की गई।

(iii) 'दक्षेस देशों के साथ भारत का संबंध' विषय पर 14 मई, 2018 को एक ब्रीफिंग बैठक आयोजित की गई।

(iv) 'संभावित उत्प्रवासियों के लिए उपयुक्त विधायी ढांचा और कौशल विकास पहलकदमों सहित उत्प्रवासी कर्मकारों से संबंधित मुद्दे' विषय पर 18 जुलाई, 2018 को विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के समक्ष विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।

(v) 'संभावित उत्प्रवासियों के लिए उपयुक्त विधायी ढांचा और कौशल विकास पहलकदमों सहित उत्प्रवासी कर्मकारों से संबंधित मुद्दे' विषय पर 2 अगस्त, 2018 को एक मौखिक साक्ष्य बैठक आयोजित की गई।

(vi) 'पाकिस्तान में नई शासन-व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में भारत-पाक संबंध' विषय पर 26 अक्टूबर, 2018 को एक ब्रीफिंग बैठक आयोजित की गई।

(vii) 'भारत-श्रीलंका संबंध - मछुआरों के मुद्दों सहित व्यापार और सुरक्षा' विषय पर 14 दिसम्बर को एक ब्रीफिंग बैठक आयोजित की गई।

(viii) 'जापान के साथ भारत के सुदृढ़ होते संबंध : भावी संभावनाएं' विषय पर 19 दिसम्बर, 2018 को एक ब्रीफिंग बैठक आयोजित की गई।

जनवरी से मार्च, 2019 की अवधि के दौरान स्थायी समिति की बैठक आयोजित किए जाने की संभावना है।

संसद की अन्य समितियों की बैठकें

(i) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, लोक सभा के समक्ष लंबित आश्वासनों के बारे में 23 अप्रैल, 2018 को विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।

(ii) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, लोक सभा के साथ पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अंतर्गत बनाए गए नियमों/विनियमों के बारे में 11 जून, 2018 को विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा मौखिम ब्रीफिंग की।

समन्वयन प्रभाग

समन्वय प्रभाग राज्यपालों, संसद सदस्यों, केन्द्रीय मंत्रियों, राज्य सरकारों के मंत्रियों, राज्य विधानमंडलों, न्यायपालिका के सदस्यों, सरकारी कर्मचारियों आदि के विदेश दौरों के लिए राजनीतिक दृष्टिकोणों से अनापत्ति प्रदान करने के लिए समस्त प्रस्तावों का प्रक्रमण करता है। सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ समय-समय पर विनिर्धारित दिशा-निर्देशों पर विचार करते हुए, विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले दौरों, बैठकों के लिए राजनीतिक और कार्यात्मक औचित्य तथा संबंधित भारतीय मिशनों/पोस्टों की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए राजनीकि संस्वीकृति प्रदान की जाती है। अप्रैल, 2018 से दिसम्बर, 2018 की अवधि के दौरान समन्वय अनुभाग ने ऐसे दौरों के लिए 2,316 राजनीतिक संस्वीकृतियां जारी कीं।

प्रभाग विदेशी गैर-अधिसूचित सैन्य उड़ानों तथा विदेशी नौसेना पोतों द्वारा दौरों के लिए राजनयिक संस्वीकृतियां प्रदान करने से संबंधित कार्य भी देखता है। अप्रैल, 2018 से दिसम्बर, 2018 की अवधि के दौरान, अनुभाग ने विदेशी गैर-अधिसूचित सैन्य उड़ानों के लिए 406 संस्वीकृतियां तथा विदेशी नौसेना पोतों के दौरों के लिए चौतीस संस्वीकृतियां जारी की।

समन्वय प्रभाग ने भारतीय खेल दलों तथा खिलाड़ियों के विदेशो में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता तथा विदेशी खिलाड़ियों/टीमों के भारतीय दौरों के लिए अनुमोदनों का प्रक्रमण किया। अप्रैल, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक ऐसे बयासी मामलो का संस्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रक्रमण किया गया।

प्रभाग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगोष्ठियां कार्यशालाएं आदि आयोजित करने के लिए अनापत्ति प्रदान करने, भारतीय तार अधिनियम (1885) के अंतर्गत गैर-पेशेवर डब्ल्यू/टी लाइसेंस प्रदान करने, नाम पंजीकरण के लिए संस्वीकृतियों तथा विदेशों में स्थित भारत-विदेश मैत्री सांस्कृतिक सोसाइटियों को सहायतानुदान प्रदान करने के लिए अनुरोधों की समीक्षा भी करता है।

अप्रैल, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक, प्रभाग ने भारत में 1228 सम्मेलनों/संगोष्ठियों के लिए संस्वीकृतियां जारी कीं। इसके अलावा, विदेशी छात्रों/स्कालरों द्वारा भारत में प्रशिक्षण/शोधकार्य के लिए 120 अनुरोधों का प्रक्रमण किया गया।

प्रभाग पद्म पुरस्कारों, गांधी शांति पुरस्कार, टैगौर पुरस्कार, भारतीय श्रेण्य भाषाओं के विद्वानों को राष्ट्रपति सम्मान प्रशस्ति पुरस्कार आदि से संबंधित कार्य का समन्वय करता है। इन पुरस्कारों के लिए नामांकन प्रभाग द्वारा भारतीय मिशनों/पोस्टों से प्राप्त किए जाते हैं तथा मंत्रालय की सिफारिशों को नोडल मंत्रालयों को संप्रेषित किया जाता है।

समन्वय प्रभाग मंत्रालय तथा विदेश में स्थित मिशनों/पोस्टों में आतंकवाद-रोधी दिवस (21 मई), सद्भावना दिवस (20 अगस्त), राष्ट्रीय एकता दिवस (31 अक्टूबर) और कौमी एकता सप्ताह (19-25 नवम्बर) भी आयोजित करता है।

समन्वय प्रभाग प्रधानमंत्री के मासिक 'प्रगति' कार्यक्रम, शिकायत निवारण पर वीडियो कांफ्रेस तथा कार्यक्रमों और परियोजनाओं की समीक्षा, में मंत्रालय की भागीदारी का समन्वय भी करता है। यह मंत्रिमंडल सचिवालय के ई-समीक्षा

पोर्टल के लिए मंत्रालय की प्रतिक्रियाओं का समन्वय करता है। समन्वय प्रभाग मंत्रिमंडल टिप्पणियों के मसौदों संसद संबंधी कार्यों, मंत्रिमंडल सुरक्षा समिति (सीसीएफ) के निर्णयों आदि पर मंत्रालय की टिप्पणियों का प्रक्रमण करता है, जहां मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों से टिप्पणियों को संग्रहित किया जाना होता है।

शिक्षा

शिक्षा अनुभाग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विदेश मंत्रालय को आबंटित की गई सीटों पर स्व-वित्त पोषण स्कीम के अतर्गत भारत में विभिन्न केन्द्रीय संस्थाओं/महाविद्यालयों में एमबीबीएस, बीडीएस, बी.ई., बी.टेक, बी. आर्क और बी. फार्मेसी कार्यक्रमों के लिए सत्तावन मित्र पड़ोसी और विकासशील देशों से प्राप्त आवेदनों के संबंध में विदेशी छात्रों के चयन, नामांकन और प्रवेश से संबधित कार्य निष्पादित करता है। भारत में स्थित बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यक प्रवासियों को भी शैक्षणिक वर्ष 2016-17 से इस स्कीम के क्षेत्राधिकार के भीतर शामिल किया गया है।

अप्रैल, 2018 से दिसम्बर, 2018 की अवधि के दौरान नामांकित सीटों पर चयन के लिए छात्र प्रकोष्ठ में विदेशी राष्ट्रिकों से प्राप्त/प्रक्रमण किए गए आवेदनो के विवरण नीचे दिए गए हैं:

(i) आयुर्विज्ञान संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए पांच स्नातकोत्तर चिकित्सा (एमडी/एमएस) सीटों के संबंध में नामांकन के लिए नेपाल से सात तथा भारत में स्थित बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यक प्रवासियों से दो आवेदन प्राप्त हुए थे। सभी पांच सीटें नेपाल को आबंटित की गई।

(ii) शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए अड़सठ बी.ई., बी.टेक., बी.आर्क. और बी.फार्मेसी सीटों के संबंध में नामांकन/चयन के लिए भारत में स्थित पाकिस्तान के उत्पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यक प्रवासी के एक आवेदन सहित इकानवे आवेदन प्राप्त हुए थे। पैंतालीस सीटें (जिसमें पाकिस्तान के उत्पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यक प्रवासी के लिए एक सीट भी शामिल थी) आबंटित की गईं।

(iii) शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए तैंतीस एमबीबीएस/बीडीसी सीटों के संबंध में नामांकन/चयन के लिए भारत में स्थित बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यक प्रवासियों से बारह आवेदनों सहित कुल 290 आवेदन प्राप्त हुए थे। छब्बीस सीटें विदेशी राष्ट्रिकों को आबंटित की गई तथा सात सीटें भारत में स्थित बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यक प्रवासियों को आबंटित की गईं।

वैकल्पिक-प्रशिक्षण, प्रेक्षणवृत्ति, अल्प/दीर्घकालिक प्रशिक्षण और शोध परियोजनाओं के लिए विदेशी छात्रों के संबंध में राजनीतिक संस्वीकृति के 359 मामलों का भी प्रक्रमण किया गया जब भारत सरकार के नोडल मंत्रालयों/विभागों द्वारा इसके लिए संपर्क स्थापित किया गया।

अप्रैल, 2018 से दिसम्बर, 2018 की अवधि के दौरान स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षाओं में बैठने वाले विदेशी छात्रों/राष्ट्रिकों के संबंध में राजनीतिक संस्वीकृति से संबंधित 1308 मामलों पर शिक्षा अनुभाग द्वारा कार्यवाही की गई। अनुभाग ने शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के दौरान केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा में प्रवेश के लिए विदेशी छात्रों/राष्ट्रिकों के संबंध में 106 राजनीतिक संस्वीकृतियां भी जारी कीं।

27

बाह्य प्रचार और लोक राजनयिकता प्रभाग

एक तेजी से विकसित होते संचार परिवेश में बाह्य प्रचार और लोक राजनयिकता प्रभाग (एक्सपीडी) ने बाहरी विश्व के प्रति हमारी विदेश नीति की प्राथमिकताओं की बेहतर समझ को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखे। यह लक्ष्य मीडिया के साथ हमारे गहन संबंधों के माध्यम से तथा भारत और विदेश, दोनों ही स्थानों पर सार्वजनिक राजनयिकता में वृद्धि करते हुए हासिल किया गया है। इसका मूल-मंत्र 'लोक-केन्द्रित' रहा है, जिसका तात्पर्य है विदेश नीति को निचले स्तर तक लेकर जाना जिसके लिए विद्यमान और नए पहलकदमों की श्रृंखला क्रियान्वित की गई है। हमारे अपेक्षित उद्देश्यों को अधिकतम व्यापकता प्रदान करने के लिए डिजिटल मीडिया और आधुनिक उपकरणों का इष्टतम प्रयोग किया गया है।

प्रभाग ने इस अवधि के दौरान तीन विशेष पहलकदम उठाए हैं। छात्र और एमईए संपर्क कार्यक्रम (एसएएमईईपी) के अंतर्गत, आईएफएस अधिकारी उनके विद्यालयों अथवा विश्वविद्यालयों में जाते हैं तथा विदेश मंत्रालय की भूमिका और भारतीय विदेश नीति पर प्रस्तुतीकरण पेश करते हैं। इसके अलावा, एक्सपीडी प्रभाग ने 'विदेश आया प्रदेश के द्वार (विदेश नीति आपके द्वार पर) भी प्रारंभ किया है जिसके अंतर्गत प्रदेशों के मीडिया के साथ चर्चा करने के लिए राज्यों की राजधानियों में विशेष संपर्क सत्र आयोजित किए गए। विदेश में स्थित जिज्ञासु युवाओं के लिए प्रभाग ने 'भारत एक परिचय' कार्यक्रम प्रारंभ किया है जिसका उद्देश्य विदेशी पुस्तकालयों में एक पृथक भारतीय कार्नर स्थापित करना है, जिसमें भारत के विषय में सतर्कतापूर्वक चुनी गई इक्यावन पुस्तकें रखी जाएंगी।

एक्सपीडी प्रभाग ने भारत और विदेश में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किए गए समारोहों में नोडल भूमिका निभाई है। इसकी एक विशेष उपलब्धि महात्मा गांधी के प्रिय भजन 'वैष्णव जन तो' की वीडियो मेडली को जारी किया जाना थी, जिसके लिए समूचे विश्व

के 140 देशों के गायकों द्वारा योगदान दिया गया था। इस मेडली का विमोचन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर, 2018 को स्वच्छ भारत सम्मेलन में किया गया था। एक अनूठी और महत्वाकांक्षी पहल के तहत, 2 अक्टूबर को समूचे विश्व की राजधानियों में महात्मा गांधी पर एलईडी प्रोजेक्शन प्रदर्शित किया गया।

इस प्रयासों ने मंत्रालय और सरकार की विदेश नीति के अति-सक्रिय और प्रभावी स्वरूप के विषय में जागरूकता का सृजन करने में एक निर्णायक भूमिका निभाई है जिसके फलस्वरूप विश्व में भारत की छवि में वृद्धि होने के साथ-साथ अनेक अन्य सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं।

मीडिया के साथ संपर्क

प्रेस कवरेज

एक्सपीडी प्रभाग ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री के विदेश दौरों की मुख्य विशेषताओं का समुचित प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के लिए समुचित संभार-तंत्र संबंधी व्यवस्थाएं की हैं जिनमें पूर्णत: सज्जित मीडिया-केन्द्रों की स्थापना और प्रचालन, मीडिया ब्रीफिंग का आयोजन तथा विदेश के पचास से अधिक दौरों के अवसरों पर इन गणमान्य व्यक्तियों के साथ जाने वाले मीडिया कर्मियों को समुचित सहायता प्रदान करना शामिल है ताकि दौरों की मुख्य विशेषताओं का प्रचार सुनिश्चित किया जा सके। प्रभाग ने विश्व के नेताओं तथा अन्य विदेशी गण्यमान्य अतिथियों की भारत की यात्राओं की व्यापक मीडिया कवरेज सुनिश्चित करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

शिखर-सम्मेलन/सम्मेलन तथा संपर्क कवरेज

प्रभाग ने 18 और 19 जुलाई 2018 को आयोजित दिल्ली वार्ता-X तथा 06 सितम्बर 2018 को भारत में आयोजित भारत-यूएस 2+2 वार्ता और साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विदेश यात्राओं के दौरान आयोजित शिखर-सम्मेलनों की मीडिया कवरेज का भी सफलतापूर्वक आयोजन किया। इसमें 17 और 18 अप्रैल 2018 को यूके में राष्ट्रमंडल सरकार प्रमुखों की बैठक (चोगम); 9 और 10 जून 2018 को चीन में आयोजित 18वां शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर-सम्मेलन; 01 जून 2018 को सिंगापुर में आयोजित शांग्री-ला वार्ता, 25-27 जुलाई 2018 को दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स 2018; 4-15 नवम्बर 2018 को सिंगापुर में आयोजित पूर्व एशिया शिखर-सम्मेलन तथा 29 नवम्बर से 01 दिसम्बर 2018 तक अर्जेंटीना में आयोजित जी-20 शिखर-वार्ता भी शामिल थीं।

विदेश मंत्री की वार्षिक प्रेस कांफ्रेस

एक्सपीडी प्रभाग ने मई 2018 में विदेश मंत्री की वार्षिक प्रेस कांफ्रेस का आयोजन किया जो समस्त भारतीय और विदेशी मीडिया को आमंत्रित किया गया था। अनेक मीडिया हाउसों के 150 पत्रकारों ने इसमें भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान, विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने सरकार की उपलब्धियों के चार वर्ष पर 'अभूतपूर्व संपर्क, अतुलनीय परिणाम' नामक काफी-टेबल पुस्तक का विमोचन भी किया। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 14 दिसम्बर 2018 को भारतीय और विदेशी पत्रकारों के लिए वार्षिक मीडिया मध्याह्ण-भोज का आयोजन किया।

'विदेश आया प्रदेश के द्वार' पहल

एक्सपीडी प्रभाग ने क्षेत्रीय मीडिया केन्द्रों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए एक नई पहल भी प्रारंभ की जिसका उद्देश्य सरकार की विदेश नीति की पहलों के बारे में जागरूकता का व्यापक प्रचार करना था। 'विदेश आया प्रदेश के द्वार' (विदेश नीति आपके द्वार पर) के तीन संस्करण 22 मार्च 2018 को हैदराबाद में, 17 जुलाई 2018 को गुवाहाटी में तथा 28 सितम्बर, 2018 को जालंधर में आयोजित किए गए। इस पहल ने एक्सपीडी प्रभाग को राज्यों में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों (आरपीओ) के साथ कार्य करने में समर्थ भी बनाया जिससे क्षेत्रीय मीडिया के साथ नियमित रूप से संपर्क बनाए रखने के लिए एक तंत्र स्थापित करने में सहायता मिली।

वित्तीय वर्ष 2018-2019 के दौरान जागरूकता दौरे

मित्र देशों के मध्य भारत के बारे में जागरूकता में वृद्धि करने तथा मीडिया आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, एक्सपीडी प्रभाग विदेशी और भारतीय पत्रकारों द्वारा जागरूकता दौरों का आयोजन करता है। इस अवधि के दौरान, पच्चीस देशों से 119 पत्रकारों ने भारत का दौरा किया जिनमें चीन, रूस, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश, आसियन के नौ देश तथा अफ्रीका के ग्यारह फ्रैंकोफोन देश शामिल हैं। प्रभाग मार्च 2019 तक दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, अफगानिस्तान और मंगोलिया से चार और शिष्टमंडलों की मेजबानी कर रहा है।

डिजिटल पहुंच

विदेश मंत्रालय की वेबसाइट

विदेश मंत्रालय की वेबसाइट विदेश नीति तथा द्विपक्षीय संबंधों पर भारत के पक्ष को वर्णित करती है। वर्तमान पोर्टल उपभोक्ता-हितैषी, प्रयोग-योग्य, लचीला, सतत् तथा मानक विनिर्देशनों के अनुरुप है। प्रचारित की जाने वाली सूचना के इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, वेबसाइट को मुख्यालय तथा विदेश स्थित मिशनों/पोस्टों के लिए एक-समान रूप से डिजाइन किया गया है। विदेश मंत्रालय का पोर्टल उन सभी व्यक्तियों के लिए एक ही स्थान पर समस्त जानकारी उपलब्ध कराने वाले का कार्य करता है जो विदेश मंत्रालय की घोषणाओं; भारतीय विदेश नीति तथा अन्य राष्ट्रों के साथ संबंधों के बारे में जानकारी; विदेश मंत्रालय और इसके सबद्ध संगठनों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं; महत्वपूर्ण भारतीय वेबसाइटों के लिंकों; समस्त मिशनों/पोस्टों तथा उनकी वेबसाइटों के लिंकों के बारे में जानकारी; लोक राजयनिक पहुंच (श्रव्य-वीडियो विषय-वस्तु और अन्य प्रिंट मीडिया प्रकाशन); महत्वपूर्ण आयोजनों पर जानकारी जैसे प्रवासी भारतीय दिवस, कैलाश मानसरोवर यात्रा आदि; राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की समस्त विदेशी और घरेलू यात्राओं; भारतीय संधि डाटाबेस आदि के

बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। विदेश मंत्रालय वेब पोर्टल दृष्टि-बाधित तथा बधिर व्यक्तियों के लिए भी सुलभ है। सितम्बर 2012 में इसकी औपचारिक शुरुआत के बाद से, वेब पोर्टल ने अब तक चार करोड़ से अधिक व्यू पंजीकृत कर लिए हैं, तथा यह इसने मंत्रालय की डिजिटल छवि को पूरी तरह से रूपातंरित कर दिया है। वेबसाइट का नेटिव मोबाइल एप्प (एमईएइंडिया) भी एंड्रायड और आईओएस प्लेटफार्म पर उपलब्ध है, जिसके 2,10,000 से अधिक डाउनलोड है **http://mea.gov.in/mea.mobile-app.htm.** विदेश मंत्रालय सोशल मीडिया हैंडलों के आइकन सुलभ एक्सेस के लिए होम पेज की दाईं ओर प्रदर्शित किए गए हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफार्म

समान डिजिटल पहचान अर्जित कर लेने के उपरांत, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर विदेश मंत्रालय की उपस्थिति में निरंतर वृद्धि होती जा रही है।

(क) विदेश मंत्रालय, भारत के **फेसबुक पेज** पर फालोअर्स की संख्या में वृद्धि हुई है और आज यह संख्या दो मिलियन तक पहुंच गई है। विदेश स्थित मिशनों और पोस्टों ने भी ऑनलाइन जगत में प्रवेश कर लिया है तथा वे मेजबान देशों की स्थानीय जनसंख्या और प्रवासी भारतीयों के साथ सीधे संपर्क बनाते हैं। आज लगभग 172 भारतीय मिशनों और पोस्टों की फेसबुक में उपस्थिति है। फेसबुक के साथ कार्य करते हुए, मंत्रालय ने सभी खातों का सत्यापन किया है और उन्हें एक शीर्षक के अंतर्गत मानकीकृत कर दिया है, जैसे 'यूएसए में भारत', 'आयरलैंड में भारत' आदि। इन एकाउंटों का प्रयोग नेमी रूप से दूतावास के क्रियाकलापों, भारत के विषय में सॉफ्ट गाथाओं, निवेश के माध्यमों और प्रमुख कार्यक्रमों जैसे मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया में प्रतिभागिता के बारे में जानकारी प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है।

(ख) **ट्विटर** समाचार प्रसारित करने का एक प्रभावशाली माध्यम है। अधिकारित प्रवक्ता के ट्विटर एकाउंट (@MEA India) और भारतीय राजनयिकता ट्विटर एकाउंट ने फालोअर्स की संख्या में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए उन्हें 32.80 लाख तक पहुंचा दिया है। इस प्लेटफार्म का प्रयोग भारत और भारत की विदेश नीति पर ट्वीट करने के लिए किया जाता है। द्विपक्षीय/बहुपक्षीय क्रियाकलापों के दौरान, ट्विटर को रीयल टाइम आधार पर अद्यतन बनाया जाता है।

(ग) विदेश मंत्रालय के **यू-ट्यूब चैनल** कुल 43,634 सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने 10,78,332 व्यू किए हैं तथा व्यू के कुल मिनट 25,25,591 हैं। भारतीय राजनयिक यू-ट्यूब चैनल के आंकड़े हैं : 59,072 सब्सक्राइबर, 21,93,282 व्यू तथा कुल 74,65,945 मिनट के व्यू। पूर्व वर्ष की तुलना में संयुक्त सदस्यता में 48 प्रतिशत की कुल वृद्धि दिखाई देती है।

(घ) **फ्लिकर एकाउंट (http://www.flickr.com/photos/meaindia)** ने मंत्रालय के सभी प्रमुख समारोहों के फोटोग्राफों के उपयोगी और लोकप्रिय ऑनलाइन निक्षेपागार के रूप में कार्य करना जारी रखा।

(ङ.) एमईए ने **इंस्टाग्राम** पर उल्लेखनीय स्थान हासिल कर लिया है जिसमें इसके सक्रिय होने की एक अल्प अवधि के भीतर ही फालोअर्स की संख्या में 155 प्रतिशत वृद्धि हुई तथा यह संख्या 1,54,250 तक पहुंच गई।

(च) विदेश मंत्रालय ने पिछले वर्ष **लिंकेंडइन** में भी प्रवेश किया तथा इस छोटी सी अवधि के भीतर ही इसके 1,645 फालोअर्स बन गए हैं।

सोशल मीडिया में अपनी पहुंच को विस्तारित करने के विदेश मंत्रालय के प्रयासों की लोकप्रियता और सफलता डिजिटल क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज़ करने के पश्चात् इसके फालोअर्स में होने वाली निरंतर वृद्धि से देखी जा सकती है।

(छ) **महात्मा गांधी पर वार्ताएं - सत्य व्रत** : महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर विदेश मंत्रालय ने अपने यू-ट्यूब प्लेटफार्म पर सत्यव्रत होस्ट किया है जिसमें महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रभावित समूचे विश्व के लोगों के भाषणों और उनके साथ चर्चाओं को तथा आधुनिक संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता को दर्शाया गया है।

(ज) **एलईडी प्रोजेक्शन :** 'समसामयिक विश्व में बापू के संदेश की प्रासंगिकता' विषय पर तैयार की गई कथाओं और दृश्यों का प्रदर्शन 100 से अधिक देशों के ऐतिहासिक भवनों में किया गया जैसे अन्य के साथ-साथ लंदन का पिकाडिली सर्कस, बुर्ज खलीफा, वियना में विएन संग्रहालय, बुडापेस्ट में बुडा कैसल, रोम में प्लाजो सेनाटोरियो, इंडोनेशिया में प्रम्बनन टेम्पल, पेरू में म्यूज़िओ डी आर्टे जिसके माध्यम से महात्मा गांधी के संदेश को पूरे विश्व में प्रसारित किया गया।

लोक राजनय और संपर्क

दृश्य संपर्क - फिल्में और वृत्त चित्र

प्रभाग विभिन्न वृत्तचित्रों का निर्माण करता है जिनका उद्देश्य समूचे विश्व में भारत की छवि को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करना होता है। वृत्तचित्रों की डीवीडी विदेशी टीवी चैनलों पर प्रस्तुतीकरण, प्रदर्शन और प्रसारण के लिए विदेश स्थित भारतीय मिशनों को भेजी जाती हैं। गैर-वाणिज्यिक प्रदर्शन के लिए गैर-वाणिज्यिक प्रदर्शन अधिकारों के साथ फीचर फिल्मों का निर्माण और आपूर्ति करना, फिल्म समारोह आदि आयोजित करना, फोटोग्राफ प्रदर्शनियां आयोजित करना प्रभाग द्वारा संचालित किए जाने वाले अन्य प्रचार-प्रसार संबंधी क्रियाकलाप हैं। प्रस्तुतीकरण के प्रयोजन लिए विदेश स्थित मिशनों/पोस्टो को भेजे जाने के लिए लोकप्रिय भारतीय शास्त्रीय/बॉलीवुड संगीत सीडी के विशेषीकृत सेटों की खरीद की जाती है।

वर्ष के दौरान दो वृत्तचित्र पूर्ण किए गए अर्थात् इस्लाम और द्वैतवाद की भारतीय विरासत तथा विश्व हिन्दी सम्मेलन 2018 के संप्रतीक पर एनिमेटेड फिल्म।

व्हाट एमईए डज, डा. बी.आर. अम्बेडकर, रेस्क्यू आप्रेशंस बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैलाश मानसरोवर यात्रा, भारत की विदेश नीति, भारत के विकास सहयोग पहलकदम, यूएन शांति-स्थापना में भारत की भूमिका, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का समारोह नामक वृत्तचित्रों का निर्माण कार्य भी प्रारंभ किया गया तथा ये निर्माण की विभिन्न अवस्थाओ में हैं।

प्रभाग द्वारा अधिप्राप्त वृत्तचित्रों को भारतीय राजनयिक चैनल में यू-ट्यूब पर अपलोड किया जाता है तथा उन्हें लोक राजनयिकता ट्वीटों और एमईए फेसबुक में भी शामिल किया जाता है ताकि उनका वैश्विक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जा सके तथा उन्हें मंत्रालय और मिशनों के सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से लोकप्रिय बनाया जाता है।

सुरक्षित और विधिक उत्प्रवास पर एक विज्ञापन अभियान भारत में विभिन्न चैनलों पर चलाया गया तथा इसे विदेश स्थित हमारे मिशनों और पोस्टों द्वारा सोशल चैनलों पर भी चलाया गया। विश्व हिन्दी सम्मेलन 2018 के लिए हिन्दी संप्रतीक पर एक एनिमेटेड फिल्म का विमोचन भी विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा किया गया तथा भारत में विभिन्न मीडिया चैनलों तथा विदेश स्थित हमारे मिशनों/पोस्टों द्वारा सोशल चैनलों में उसका प्रचार-प्रसार किया गया।

एक्सपीडी डिवीजन ने राष्ट्रीय नेताओं जैसे महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार बल्लभभाई पटेल और डा. बी.आर. अम्बेडकर से संबंधित स्मारक समारोहों के आयोजन के लिए सभी मिशनों को सहयोग प्रदान किया गया। यह योगदान फिल्मों, फोटोग्राफों आदि को उपलब्ध कराने के रूप में था।

उपर्युक्त के अलावा, वृत्तचित्रों को देखने और उन तक पहुंच बनाने के लिए मिशनों को सहायता प्रदान करने के लिए वृत्तचित्रों का एक डिजिटल कैटालॉग भी तैयार किया जा रहा है।

विशिष्ट व्याख्यान श्रृंखला

विशिष्ट व्याख्यान श्रृंखला के तत्वावधान में प्रभाग के जनता तक पहुंच बनाने की पहल वर्ष 2010 में इसकी स्थापना के बाद से ही धीरे-धीरे विस्तारित होती जा रही है। आज व्याख्यान श्रृंखला ने अपने क्षेत्राधिकार में 253 शिक्षण संस्थाओं को शामिल कर लिया है। ये व्याख्यान समूचे भारत में दिए जा रहे हैं - कश्मीर से त्रिवेन्द्रम तक, कांगड़ा से त्रिची तक, गांधीनगर से मिजोरम तक और झारखण्ड से नागालैंड तक जिनमें विविधतपूर्ण विषयों को शामिल किया जाता है जैसे भारत की एक्ट ईस्ट नीति, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (दक्षेस), भारत के बहुपक्षीय संबंध, पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक विकास, नि:शस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक और आर्थिक राजनयिकता तथा भारत और संयुक्त राष्ट्र। अब तक 252 व्याख्यान आयोजित किए जा चुके हैं।

समीप-छात्र और विदेश मंत्रालय संपर्क कार्यक्रम

समीप एक्सपीडी प्रभाग की एक संपर्क पहल है जिसका उद्देश्य समूचे भारत के विभिन्न शहरों और नगरों में छात्र समुदाय तक पहुंच बनाना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालयों

और कालेजों के छात्रों को विदेश मंत्रालय की भूमिका और कार्यों, भारत की विदेश नीति के प्रमुख अवयवों तथा विदेश नीति के क्षेत्र में सफलता गाथाओं और उपलब्धियों से अवगत कराना है। इस कार्यक्रम में पूर्णत: स्वैच्छिक आधार पर छुट्टियों के दौरान मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा उनके गृह नगर/राज्यों में स्थित विद्यालयों और कॉलेजों में किए जाने वाले दौरों को शामिल किया गया है जिसके दौरान छात्रों के साथ उनका संपर्क होता है तथा वे विदेश मंत्रालय में कार्य करने के अपने अनुभव भी उनके साथ साझा करते हैं। अब तक ऐसे सत्ताईस कार्यकम पहले ही जालंधर, त्रिची, दिल्ली, सोनीपत, इंफाल, पोर्टब्लेयर, मल्लापुरम, बेंगलूर, बिजनौर, हैदराबाद, विशाखापत्तन, सोलन, नादेड़, बहादुरगढ़, अहमदाबाद, उल्हासनगर, कल्याण, हसन, मालापुरम और कोलकाता में आयोजित किए जा चुके हैं।

महात्मा गांधी के प्रिय भजन का वैश्वीकरण

पन्द्रहवीं शताब्दी के कवि नरसिंह मेहता द्वारा लिखा गुजराती का प्रसिद्ध भजन 'वैष्णव जन तो तेने कहिए जे' महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक था जिसे उनके द्वारा अपनी बैठकों से पूर्व नियमित रूप से गाई जाने वाली प्रार्थना के रूप में शामिल किया गया था। 2 अक्टूबर, 2018 से महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में, मंत्रालय द्वारा इस भजन को समूचे विश्व के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा रिकार्ड किए जाने की कवायद शुरु की गई थी। अब तक 155 से अधिक देशों के प्रमुख स्थानीय कलाकारों/समूहों ने महात्मा गांधी के इस प्रसिद्ध भजन को अपनी आवाज दी है। प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर को इसके मेडली संस्करण का विमोचन किया गया जिसमें इकतालीस देश शामिल थे। यूरोप/यूरेशियाई और अफ्रीकी देशों के वीडियो से दो और फ्यूज़न वीडियो तैयार किए गए हैं जिनका प्रदर्शन विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा 9 जनवरी 2018 को 'वैशणव जन तो पर काफी टेबल बुक' के पुस्तक विमोचन समारोह के अवसर पर किया गया। अरब देशों द्वारा एक और फ्यूज़न वीडियो तैयार किया जा रहा है।

पुस्तकें और पत्रिकाएं

(क) पुस्तक समिति

पुस्तक समिति एक लोक राजनयिक पहल है जिसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विविधता, उसकी विरासत, उसके लोकाचारों, धर्मों और भूगोल आदि को प्रवर्तित करना है। 40वीं पुस्तक समिति के भाग के रूप में, विभिन्न श्रेणियों जैसे भारतीय शास्त्रीय विषयों, विदेश नीति और और मामले, प्रौद्योगिकी और लोकप्रिय विज्ञान, हिन्दी और संस्कृत, कला और संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिकता, बच्चों की पुस्तकें तथा राजनीति ओर अर्थशास्त्र से 338 शीर्षकों का चयन किया गया। पुस्तकें खरीदी जा रही हैं तथा उन्हें आने वाले समय में संबंधित मिशनों/पोस्टों के साथ साझा किया जाएगा।

(ख) भारत एक परिचय

यह कार्यक्रम विदेश स्थित हमारे मिशनों/पोस्टों तथा शैक्षणिक संस्थाओं के पुस्तकालयों में समर्पित स्थान स्थापित करने के माध्यम से भारत के बारे में जानकारी और समझ का प्रचार-प्रसार करता है जिसमें इकावन पुस्तकों का सेट साझा किया जाएगा जिनमें से बीस पुस्तकें ज्ञान भारतीय शास्त्रीय विषयों पर, इक्कीस पुस्तकें भारतीय राजभाषा में तथा दस पुस्तकें विदेश स्थित प्रत्येक मिशन/पोस्ट द्वारा अनुशंसित विषयों पर रखी जाएंगी। इसके अलावा, पहुंच में वृद्धि करने के लिए भारतीय विषयों पर आधारित सामाग्रियां जैसे उपहार बॉक्स, कोस्टर्स, बुक-मार्क और शो-कार्ड्स भी उपहार और वितरण प्रयोजनों के लिए विदेश भेजे जा रहे हैं।

(ग) भारत संदर्श

मंत्रालय की महत्वाकांक्षी पत्रिका सत्रह भाषाओं में उपलब्ध कराई जा रही है अर्थात् हिन्दी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, भाषा इंडोनेशियन, इटैलियन, पश्तो, प्रशियन, पुर्तगाली, रूसी, सिंघली, स्पैनिश, तमिल, चीनी और जापानी। इसे www.indiaperpectives.in पर तथा मंत्रालय की वेबसाइट www.mea.gov.in पर भी ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है।

(घ) बापू @150

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को मनाने के लिए मिशनों/पोस्टों को महात्मा गांधी की जीवनी : दि स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरीमेंट्स विद ट्रूथ - एन ऑटोबायोग्राफी (अंग्रेजी) तथा सत्य के प्रयोग - आत्मकथा (हिंदी) की प्रतियां विदेश स्थित विद्यालयों में आयोजित वार्ता-कार्यक्रमों में वितरण के लिए प्रेषित की गईं।

(ड.) कॉफी-टेबल बुक्स

विदेश मंत्रालय के चार वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक 'अभूतपूर्व पहुंच अतुलनीय परिणाम' शीर्षक पर कॉफी-टेबल बुक का विमोचन विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी में किया गया।

28

विदेश सेवा संस्थान

विदेश सेवा संस्थान (एफएसआई) में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विषय-वस्तु तथा क्रियाविधि के संदर्भ में समीक्षा की गई है, उसमें संशोधन किया गया है और उसे नवीकृत बनाया गया है। अब विशेष ध्यान अनिवार्य ज्ञान और अपेक्षित कौशल प्रदान करने के लिए शिक्षण का मामला अध्ययन पद्धति तथा मौके पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिएजाने पर दिया गया है। विभिन्न स्तरों पर अनिवार्य कैरियर-मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमसीटीपी) पर भी अत्यधिक बल प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2018 में, विदेशी राजनयिकों के लिए एफएसआई की स्थापना के बाद से सर्वाधिक संख्या में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारी प्रशिक्षु

2017 बैच के आईएफएस अधिकारी प्रशिक्षुओं (ओटी) ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) में अपना फाउंडेशन पाठ्यक्रम समाप्त करने के उपरांत अधिष्ठापन स्तरीय प्रशिक्षण के लिए छह माह लंबे प्रक्षिक्षण हेतु दिसम्बर, 2017 में एफएसआई ज्वाइन किया जो जून, 2018 में समाप्त हुआ।

ओटी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों, विदेश नीति, भारत के पड़ोसी देशों और बड़ी शक्तियों तथा बहुपक्षीय संगठनों के साथ द्विपक्षीय संबबंधों पर मॉड्यूल शामिल थे। वित्त, लेखा, प्रशासन, स्थापना, परामर्श कार्य, पासपोर्ट और वीजा, अंतर्राष्ट्रीय विधि, नयाचार, आर्थिक और वाणिज्यिक राजनयिकता, रक्षा राजनयिकता, साइबर सुरक्षा, घरेलू नीति, आतिथ्य और मीडिया प्रबंध पर माड्यूलों को भी

शामिल किया गया था। साफ्ट पावर तथा संप्रेषण कौशलों पर भी बल प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण पारस्परिक संपर्क व्याख्यानों, समूह चर्चाओं, पैनल चर्चाओं, मामला अध्ययनों, भूमिका-निर्वहन तथा अनुकरण और समसामयिक विषयों पर प्रस्तुतीकरण के माध्यम से संचालित किया गया ताकि सृजनात्मक चिंतन विकसित किया जा सके।

31 मई, 2018 को विदाई समारोह आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा की गई। इस अवसर पर, 2017 बैच के सर्वश्रेष्ठ ओटी के लिए विदेश मंत्री का स्वर्ण पदक, सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व के लिए राज्य मंत्री का रजत पदक, श्रेष्ठ शोध-प्रबंध के लिए राजदूत विमल सान्याल स्मारक पदक, श्रेष्ठ समिति के लिए ट्रॉफी तथा श्रेष्ठ खिलाड़ियों के लिए ट्रॉफियां सुपात्र ओटी को प्रदान की गईं।

2018 बैच के आईएफएस अधिकारी प्रशिक्षु इस समय एलबीएसएनएए, मसूरी में फाउंडेशन पाठ्यक्रम में भाग ले रहे हैं। उनतालीस अधिकारी प्रशिक्षुओं तथा दो भूटानी राजनयिकों ने 10 दिसम्बर, 2018 से एफएसआई में प्रशिक्षण प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया है।

कैरियर-मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रम-I

सोलह उप सचिव (डीएस)/अवर सचिव (यूएस) स्तरीय अधिकारियों के लिए कैरियर-मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रम-I निम्नलिखित तालिका के अनुसार 9-27 जुलाई, 2017 तक आयोजित किया गया:

क्रम सं.	अवधि	माड्यूल	संस्थान का नाम
1	9-11 जुलाई, 2018	विदेश नीति	विदेश सेवा संस्थान
2.	12-14 जुलाई, 2018	साइबर सुरक्षा	गुजरात अपराध-विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधीनगर
3	16-20 जुलाई, 2018	प्रबंध	भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद
4	23-27 जुलाई, 2018	व्यापार राजनयिकता और घरेलू नीति	विदेश सेवा संस्थान
5	19-20 सितम्बर, 2018	राज्य दौरा	आबंटित राज्य में

कैरियर-मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रम-II

वर्ष 2003 और 2004 बैचों के तैंतालीस आईएफएस अधिकारियों के लिए कैरियर-मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रम-II निम्नलिखित तालिका के अनुसार 3-28 सितम्बर तक आयोजित किया गया:

क्रम सं.	अवधि	माड्यूल	संस्थान का नाम
1	3-7 सितम्बर, 2018	विदेश नीति	विदेश सेवा संस्थान
2.	10-14 सितम्बर, 2018	प्रबंध	भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद
3	15-17 सितम्बर, 2018	साइबर सुरक्षा	गुजरात अपराध-विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधीनगर
4	19-20 सितम्बर, 2018	राज्य दौरा	आबंटित राज्य में
5	22 सितम्बर, 2018	भारतीय प्रवासी व्यक्ति, बहुपक्षीय राजनयिकता और वाल स्ट्रीट से विचार' पर संपर्क सत्र	काउंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया, न्यूयार्क सिटी, यूएसए
6	24-28 सितम्बर, 2018	राजनयिकता	फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी, टफ्टस यूनीवर्सिटी यूएसए

कैरियर-मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रम-III

3-20 जुलाई, 2018 तक 1992 और 1993 बैचों के छब्बीस आईएफएस अधिकारियों के लिए कैरियर-मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रम-III निम्नलिखित तालिका के अनुसार संचालित किया गया:

क्रम सं.	अवधि	माड्यूल	संस्थान का नाम
1	3-6 जुलाई, 2018	विदेश नीति	विदेश सेवा संस्थान
2.	9-13 जुलाई, 2018	प्रबंध	इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद
3	16-20 जुलाई, 2018	राज्य अटैचमेंट	आबंटित राज्य में

वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

यूरोपीय संघ (ईयू) से आए वाणिज्यिक प्रतिनिधियों (सीआर) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 25-29 जून, 2018 तक आयोजित किया गया। ईयू के बीस सीआर ने एफएसआई में आयोजित इस कार्यक्रम में भाग लिया।

खाड़ी देशों, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका, यूरेशिया और दक्षिणी एशिया से आए वाणिज्यिक प्रतिनिधियों (सीआर) के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 12-16 नवम्बर, 2018 तक एफएसआई में आयोजित किया गया। क्षेत्र के पन्द्रह सीआर ने एफएसआई में आयोजित इस कार्यक्रम में भाग लिया।

रक्षा अताशे के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

उन्नीस रक्षा अताशे के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 8-12 अक्टूबर, 2018 को एफएसआई में आयोजित किया गया।

भारत-यूएस प्रगत लाइसेंसिंग और प्रवर्तन आदान-प्रदान

राजस्व आसूचना निदेशालय, विदेश व्यापार महानिदेशालय तथा विदेश मंत्रालय के उनासी अधिकारियों के लिए 29 अक्टूबर से 2 नवम्बर, 2018 तक एफएसआई में भारत-यूएस प्रगत लाइसेसिंग और प्रवर्तन आदान-प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

आईसीसीआर के कार्यक्रम निदेशकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के चौदह कार्यक्रम निदेशकों के लिए 30 और 31 अक्टूबर, 2018 को एफएसआई में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

गैर-सादृशमूलक ग्रेड प्रशिक्षण कार्यक्रम

अनुभाग अधिकारियों/निजी सचिवों/सहायक अनुभाग अधिकारियों/पीए/स्टेनो/ एसएसए/जेएसए के लिए प्रोन्नति संबंधी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन नियमित आधार पर किया जाता रहा। भारत सरकार के नियमों एवं कार्यालय प्रक्रियाओं, सूचना का अधिकार अधिनियम, (आरटीआई) और विदेश मंत्रालय से संबंधित विषयों जैसे आईएफएस (पीएलसीए) नियम, वित्त, बजट, परामर्श, पासपोर्ट और वीजा आदि पर विद्यमान आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (छह-दिवसीय माड्यूल) के अलावा दो-दिवसीय लेखा प्रशिक्षण, पांच दिवसीय आईएमएएस लेखा प्रशिक्षण, पांच-दिवसीय आईएमएएस (एकीकृत मिशन लेखाकरण प्रणाली) तथा दो-दिवसीय आईवीएफआरटी (प्रवासन, वीजा और विदेशी रजिस्ट्रीकरण और ट्रैकिंग) प्रशिक्षण भी तिमाही आधार पर प्रदान किया जाता है। मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के लिए एक पांच दिवसीय मॉड्यूल भी तिमाही आधार पर संचालित किया जाता है।

वर्ष 2018 में, विदेश मंत्रालय के गैर-सादृशमूलक ग्रेड (एनआरजी) के लिए प्रशिक्षण के भाग के रूप में निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए:

- 13-20 अप्रैल, 2018 तक आधारभूत प्रशिक्षण मॉड्यूल में इक्कीस प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 26 अप्रैल से 3 मई, 2018 तक एमटीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पैंतीस प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 1-4 मई, 2018 तक आईवीएफआरटी प्रशिक्षण कार्यक्रम में अठावन प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 28 और 29 मई, 2018 को लेखा प्रशिक्षण कार्यक्रम में 106 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 30 मई से 5 जून, 2018 तक 69वें आई-एमएएस प्रशिक्षण में अठाइस प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- 6-12 जून, 2018 तक 69वें आई-एमएएस प्रशिक्षण में पच्चीस प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 13-19 जून, 2018 तक 69वें आई-एमएएस प्रशिक्षण में सत्ताइस प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 14 और 15 जून, 2018 को अनुभाग अधिकारियों और निजी सचिवों के लिए प्रोन्नति संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम में बारह प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 20-26 जून, 2018 तक 69वें आई-एमएएस प्रशिक्षण में पच्चीस प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 5 जुलाई, 2018 को एएसओ के लिए टंकण परीक्षा में तेइस प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 09 और 10 जुलाई, 2018 को एएसओ, एएसओ (साइफर), पीए, एसएसए, जेएसए और स्टेनों के लिए प्रोन्नति संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम में सोलह प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 18-25 जुलाई, 2018 तक आधारभूत प्रशिक्षण माड्यूल में छब्बीस प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 1-7 अगस्त, 2018 तक आईवीएफआरटी प्रशिक्षण कार्यक्रम में 103 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 23 और 24 अगस्त, 2018 को लेखा प्रशिक्षण कार्यक्रम में उनासी प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 27-31 अगस्त, 2018 तक 70वें आईएमएएस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अठाइस प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 4-10 सितम्बर, 2018 तक 70वें आईएमएएस प्रशिक्षण कार्यक्रम में छब्बीस प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 11-17 सितम्बर, 2018 तक 70वें आईएमएएस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 17-24 सितम्बर, 2018 तक एमटीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उनतीस प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 26 सितम्बर, 2018 को एएसओ के लिए टंकण परीक्षा में सोलह प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 27 सितम्बर, 2018 को 70वीं आईएमएएस पुन:परीक्षा में बारह प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 8-11 अक्टूबर, 2018 तक आईवीएफआरटी प्रशिक्षण कार्यक्रम में उनहत्तर प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 29 अक्टूबर - 2 नवम्बर, 2018 तक एमटीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बाइस प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 13 और 14 नवम्बर, 2018 को लेखा प्रशिक्षण कार्यक्रम में उनसठ प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 15-22 नवम्बर, 2018 को 71वें आईएमएएस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अठाईस प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 26-30 नवम्बर, 2018 को 71वें आईएमएएस प्रशिक्षण कार्यक्रम में तीस प्रतिभागियों ने भाग लिया।

विदेशी राजनयिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

एफएसआई ने 2018 में विदेशी राजनयिकों के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए:-

- 9 मई से 8 जून, 2018 तक सोमाली राजनयिकों के लिए दूसरा विशेष पाठ्यक्रम जिसमें इकतीस राजनयिकों ने भाग लिया।
- 20 जून - 20 जुलाई, 2018 तक गांबियन राजनयिकों के लिए प्रथम विशेष पाठ्यक्रम जिसमें बीस राजनयिकों ने भाग लिया।
- 20-24 अगस्त, 2018 तक लातिन अमेरिकी देशों से रेजिडेंट ऑफ मिशन (एचओएम) के लिए प्रथम परिचायक कार्यकम जिसमें सत्रह एचओएम ने भाग लिया।
- 30 जुलाई - 10 अगस्त, 2018 तक नाइजीरिया के राजनयिकों के लिए प्रथम विशेष पाठ्यक्रम जिसमें बाइस राजनयिकों ने भाग लिया।
- 12 सितम्बर - 12 अक्टूबर, 2018 तक विदेशी राजनयिकों के लिए 66वां वृत्तिक पाठ्यक्रम (पीसीएफडी) जिसमें इकावन राजनयिकों ने भाग लिया।
- 15-26 अक्टूबर, 2018 तक अफगान राजनयिकों के लिए प्रथम भारत-चीन संयुक्त पाठ्यक्रम जिसमें दस राजनयिकों ने भाग लिया।
- 29 अक्टूबर - 09 नवम्बर, 2018 तक ट्यूनीशिया के राजनयिकों के लिए प्रथम विशेष पाठ्यक्रम जिसमें इकावन राजनयिकों ने भाग लिया।
- 14-20 नवम्बर, 2018 तक एशिया-यूरोप बैठक

(एएसईएम) राजनयिकों के लिए चौथा विशेष पाठ्यक्रम जिसमें तेईस राजनयिकों ने भाग लिया।

- 14-27 नवम्बर, 2018 तक दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) के राजनयिकों के लिए बाहरवां विशेष पाठ्यक्रम जिसमें चौदह राजनयिकों ने भाग लिया।
- 14-27 नवम्बर, 2018 तक म्यांमार के राजनयिकों के लिए प्रथम विशेष पाठ्यक्रम जिसमें दस राजनयिकों ने भाग लिया।
- 19 नवम्बर से 02 दिसम्बर, 2018 तक बांग्लादेश के राजनयिकों के लिए तीसरा विशेष पाठ्यक्रम जिसमें पच्चीस राजनयिकों ने भाग लिया।
- 26 नवम्बर से 08 दिसम्बर, 2018 तक ईरानी प्रशिक्षुओं के लिए पहला विशेष पाठ्यक्रम जिसमें चौबीस राजनयिकों ने भाग लिया।

समझौता ज्ञापन

वर्ष 2018 में,एफएसआई ने निम्नलिखित विदेशी संस्थानों के साथ समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए:

- 4 अप्रैल, 2018 को अजरबैजान का एडीए विश्वविद्यालय
- 7 मई, 2018 को ग्वाटेमाला की डिप्लोमेटिक एकेडमी
- 9 मई, 2018 को इथियोपिया का विदेश प्रशिक्षण संस्थान
- 10 मई, 2018 को म्यांमार का स्टैटेजिक स्टडीज एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट
- 23 मई, 2018 को नीदरलैंड्स का विदेश मंत्रालय
- 5 जून, 2018 को सोमालिया का विदेश मंत्रालय
- 18 जून, 2018 को ग्रीस का विदेश मंत्रालय
- 20 जून, 2018 को सूरीनाम का डिप्लोमेटिक इंस्टिट्यूट
- 24 जून, 2018 को शेशेल्स का विदेश विभाग
- 25 जून, 2018 को यूएई की एमिरेट्स डिप्लोमेटिक एकेडमी
- 29 अगस्त, 2018 को कम्बोडिया का नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिप्लोमेसी
- 17 सितम्बर, 2018 को माल्टा की मेडिटेरियन एकेडमी ऑफ डिप्लोमेटिक स्टडीज (एमएटीएस)
- 16 अक्टूबर, 2018 को तंजानिया का विदेशी संबंध केन्द्र विदेशी और पूर्वी अफ्रीकी सहयोग मंत्रालय (एमएफएईएसी)

'भारत को जानें' कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रम

भारतीय अधिकारियों/कर्मचारियों तथा विदेशी राजनयिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा, एफएसआई ने 'भारत को जानें कार्यक्रम (केआईपी)' के प्रतिभागियों, आसियान देशों के छात्रों तथा सिंगापुर राजनयिक अकादमी (एसडीए) से आए प्रतिनिधियों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम भी संचालित किए। केआईपी भारतीय प्रवासी युवाओं के लिए है। केआईपी का मुख्य उद्देश्य प्रवासी भारतीय युवाओं को उनके भारतीय मूल, विरासत और संस्कृति से जोड़ना तथा समकालीन भारत के विभिन्न आयामों के बारे में जागरूकता को प्रोत्साहित करना है।

केआईपी प्रतिभागियों तथा आसियान छात्रों के लिए वर्ष 2018 में एफएसआई द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किए गए:

- आसियान देशों से आए छात्रों के लिए 10 मई, 2018 को एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम जिसमें 214 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- सिंगापुर राजनयिक अकादमी से आए शिष्टमंडल के लिए 17 सितम्बर, 2018 को अभिमुखीकरण कार्यक्रम जिसमें अड़तीस प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 28 सितम्बर, 2018 को 47वां भारत को जानें कार्यक्रम जिसमें चालीस प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 29 सितम्बर, 2018 को 48वां भारत को जानें कार्यक्रम जिसमें चालीस प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 22 नवम्बर, 2018 को 49वां भारत को जानें कार्यक्रम जिसमें चालीस प्रतिभागियों ने भाग लिया।

29

नालंदा प्रभाग

नालंदा विश्वविद्यालय में 2017 और 2018 में अंतर्राष्ट्रीय पदचिह्न में वृद्धि हुई। वर्तमान में, इसमें लगभग 378 छात्र हैं, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, ब्राजील, चीन, ग्रीस, जापान, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नाइजीरिया, पेरू, रोमानिया, रूस, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, वियतनाम और जिम्बाब्वे जैसे विभिन्न देशों के चालीस अंतर्राष्ट्रीय छात्र शामिल हैं। । नालंदा के आदर्श आगामी वर्षों में और अधिक छात्रों को आकर्षित करेंगे ।

विश्वविद्यालय के प्रबंधन ने वर्ष 2018 में नए स्कूल खोले । विश्वविद्यालय में वर्तमान में कुल सात स्कूलों चल रहे हैं और विश्वविद्यालय में वर्तमान में चार स्कूलों में स्नातकोत्तर कार्यक्रम चल रहे है : पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय अध्ययन ; ऐतिहासिक अध्ययन स्कूल ; बौद्ध अध्ययन , दर्शन और तुलनात्मक धर्म स्कूल ; और भाषा व साहित्य / मानविकी स्कूल।

नालंदा विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर के निर्माण का पहला चरण जारी है। आंतरिक सड़कों के निर्माण और जल निकायों के निर्माण के लिए निविदा पैकेज 1 ए पर काम अप्रैल 2018 में पूरा हो गया था। निविदा पैकेज 1 बी (प्रशासनिक और शैक्षणिक भवनों का निर्माण) का काम चल रहा है और 2019 की शुरुआत (पांच इमारतों) में और 2020 की शुरुआत में अन्य के पूरा होने की आशा है। टेंडर पैकेज 1 सी (आवासीय भवनों का निर्माण) पर काम सितंबर 2018 में शुरू किया गया था। सरकार नालंदा विश्वविद्यालय के विकास के लिए पूरी तरह से बौद्धिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक अध्ययन और सम्बद्ध मामलों के अध्ययन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संस्था के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ।

30

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन और विदेशों में हिंदी का प्रचार

विदेश मंत्रालय में विदेशों में हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम है, जिसे विदेशों में इसके मिशन और पोस्ट के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

मॉरीशस सरकार के सहयोग से 18-20 अगस्त 2018 को मॉरीशस में 11 वां विश्व हिंदी सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। सम्मेलन का उद्घाटन मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने किया। सम्मेलन में पैंतालीस देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

विश्व भर में हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, मॉरीशस सरकार के साथ एक द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत मॉरीशस में एक विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की गई है। विश्व हिंदी सचिवालय का बजट दोनों देशों द्वारा समान रूप से साझा किया जाता है। भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित विश्व हिंदी सचिवालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने मार्च 2018 में किया था।

विदेश मंत्रालय अपने मिशनों और पोस्टो, सांस्कृतिक संगठनों और संगठनों की भागीदारी से विदेशों में हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें सितंबर में हिंदी पखवाड़ा और हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस शामिल है। हिंदी शिक्षण सामग्री, जिनमें हिंदी पाठ्य पुस्तकें और बच्चों की पुस्तके आदि शामिल हैं, विदेशों में शिक्षण संस्थानों में नि: शुल्क आपूर्ति की जाती है। विदेश मंत्रालय विदेशों की शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

अनेक विदेशी देशों में हिंदी भाषा को लोकप्रियता मिल रही है और लोग हिंदी सीखने में रुचि ले रहे हैं। विदेश में अपने मिशनों और पोस्टों के माध्यम से और स्थानीय संगठनों और संस्थानों के सहयोग से विदेश मंत्रालय के निरंतर प्रयासों से

हिंदी को अब स्कूल और विश्वविद्यालय स्तर पर इकहत्तर मिशनों और पोस्टों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में पढ़ाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र रेडियो, संयुक्त राष्ट्र सोशल मीडिया और संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइटों सहित कई प्लेटफार्मों में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा दिया है।

विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को उच्च प्राथमिकता देना जारी रखा है । विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज की अध्यक्षता में विदेश मंत्रालय में एक हिंदी सलाहकार समिति कार्यरत है। विदेश मंत्रालय राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग का जायजा लेने के लिए नियमित रूप से अपने अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करता है।

31

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद

अपने शैक्षणिक और बौद्धिक क्रियाकलापों के भाग के रूप में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) ने अपनी विभिन्न छात्रवृत्ति स्कीमों के अंतर्गत भारत में अध्ययन कर रहे विदेशी राष्ट्रिकों को 3,940 छात्रवृत्ति स्थान प्रदान किए। जनवरी, 2018 में 'एडमीशन टु एलुमनी (ए2ए)' पोर्टल की शुरुआत के साथ आईसीसीआर ने पहली बार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की। अपने कल्याणकारी क्रियाकलापों के भाग के रूप में, आईसीसीआर द्वारा सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर 2018 में दिल्ली तथा बेंगलूरु, मुंबई, पुणे, कोलकाता और गुवाहाटी में भारत में स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों में नए प्रवेश दिए गए विदेशी छात्रों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

आईसीसीआर ने नई चेयरों की स्थापना के लिए दस समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए तथा भारतीय अध्ययन की सत्तर विद्यमान चेयरों को प्रशासित किया। आईसीसीआर ने विभिन्न हिन्दी चेयरों/भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों में विदेश जाने वाले अपने पैनल पर रखे गए हिन्दी प्रोफेसरों/शिक्षकों के लिए 7 और 8 जून, 2018 को आईसीसीआर आजाद भवन, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली में एक दो-दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया। आईसीसीआर समूचे विश्व में सैंतीस पूर्णकालिक भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र (आईसीसी) तथा सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत दो केन्द्र संचालित करता है।

आईसीसीआर ने चार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/संगोष्ठियों का आयोजन किया जिसमें 26-28 अप्रैल, 2018 को सेंट पीटर्सबर्ग में भारत-विद्या पर आयोजित तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन; 20 और 21 जून, 2018 को न्यूयार्क सिटी में आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन; मानविकी और सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान के सहयोग से प्रशियन और संस्कृत भाषा के बीच भाषायी संबंधों पर संगोष्ठी (संस्कृत व्याकरणविद् पाणिनी के विशेष संदर्भ में) जिसका उद्घाटन 1 और 2 दिसम्बर, 2018 को आईसीसीआर के अध्यक्ष डा. विनय शहस्त्रबुद्धे द्वारा किया गया था; जनवरी और फरवरी 2019 में यूएस, यूके, जर्मनी, यूएई और सिंगापुर में 'लोकतंत्र का क्रियान्वयन' पर संगोष्ठियों की श्रृंखला शामिल

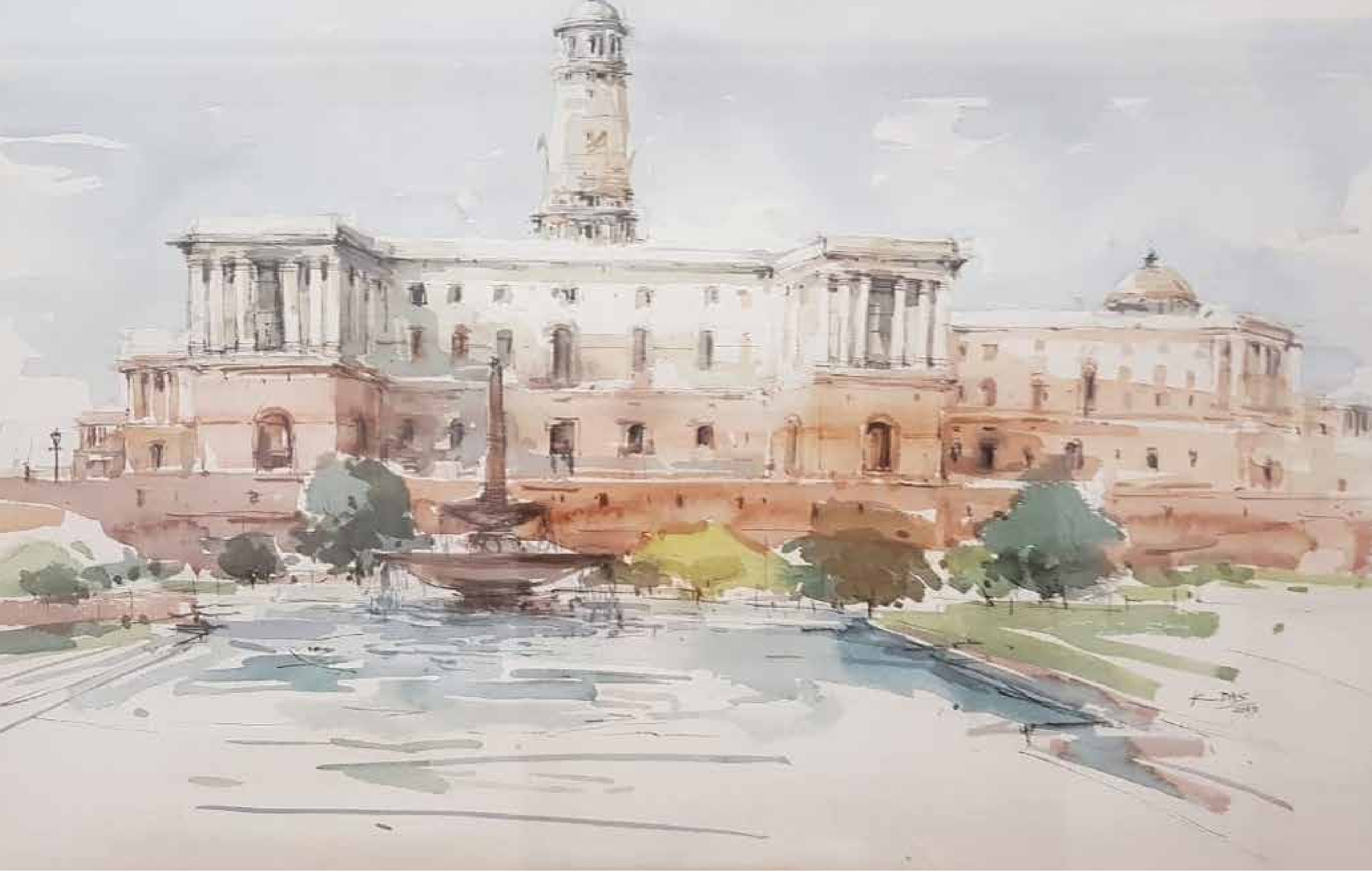

थी। उक्तसंदर्भित कार्यक्रमों के अलावा, आईसीसीआर ने भारत और विदेश में सात सम्मेलनों/संगोष्ठियों के आयोजन को भी सहायता प्रदान की जिसमें भारत की साफ्ट पावर 'वसुधैव कुटुम्बकम' पर सम्मेलन भी शामिल थे। इसने 16-30 सितम्बर, 2018 तक यूके के विभिन्न शहरों में विराट हिन्दी कवि सम्मेलन तथा 17-21 अगस्त, 2018 तक मारीशस में विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन भी किया।

आईसीसीआर ने 21 मई, 2018 को विश्व संस्कृति दिवस के उपलक्ष्य पर 'पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्मारक अंतर्राष्ट्रीय भाषण' नामक एक व्याख्यान माला भी प्रारंभ की। इसका पहला उद्बोधन विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा दिया गया।

आईसीसीआर ने आंतरिक प्रदर्शनियों के अंतर्गत दोहा, कतर में एक चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया तथा कटारा सांस्कृतिक ग्राम, दोहा के प्रतिष्ठित कलाकार श्री हसन अल मुल्ला के दौरे को सहायता प्रदान की। इसने दि लक्जरी सिंपोजियम 2018 में भाग लेने के लिए फ्रांस के छह प्रतिभागियों को यात्रा अनुदान भी प्रदान किया। बाह्य प्रदर्शनियों के संबंध में, आईसीसीआर ने 2018 में सात प्रदर्शनियों का आयोजन किया।

आईसीसीआर ने 128 कला समूहों के दौरे को प्रायोजित किया जिसमें इकानवे देशों के 778 कलाकार शामिल थे, जिन्होंने समूचे विश्व में 396 प्रदर्शन कार्यक्रम संचालित किए। भारत अक्टूबर, 2018 में मैक्सिको में आयोजित सर्वेटिनों समारोह का मेजबान देश था। आईसीसीआर ने उन्नीस देशों से आए इक्कीस प्रदर्शन कला समूहों द्वारा समूचे भारत में चौवन कार्यक्रमों का आयोजन किया। मई, 2018 में अफ्रीका समारोह, अक्टूबर, 2018 में अंतर्राष्ट्रीय रामायण समारोह तथा अक्टूबर/नवम्बर, 2018 में भारत में 'रूसी संस्कृति के दिवस' इसके मुख्य आकर्षण थे। आईसीसीआर द्वारा भ्रमणकारी विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के सम्मान में उत्कृष्ट भारतीय कलाकारों द्वारा सोलह प्रदर्शन कार्यक्रमों का भी आयोजन किया। शिक्षाविदों सहित प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों की मेजबानी करने की अपनी योजना के अंतर्गत आईसीसीआर ने विभिन्न देशों के तैंतीस आंगतुकों की मेजबानी की। अप्रैल, 2018 में प्रतिष्ठित पुरस्कार अर्थात् 2016 और 2017 के लिए गिएस्ला बोन

पुरस्कार तथा आईसीसीआर उत्कृष्ट पूर्व-छात्र पुरस्कार 2017 प्रदान किए गए। आईसीसीआर की महत्वाकांक्षी हिन्दी पत्रिका 'गगनांचल' के नियमित द्वि-मासिक अंकों के अलावा, विश्व हिन्दी सम्मेलन 2018 पर एक विशेष अंक प्रकाशित किया गया। मई, 2018 में संसदीय राजभाषा स्थायी समिति की मेजबानी की गई। आईसीसीआर ने सितम्बर, 2018 में हिन्दी पखवाड़े का आयोजन भी किया गया जिसमें आईसीसीआर के कर्मचारियों ने सक्रियता के साथ भाग लिया। फ्रांस, मैक्सिको, वियतनाम, जर्मनी और फिजी में स्थित पांच भारतीय मिशनों को स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, डा. बी.आर. अम्बेडकर, सरदार पटेल और लाल बहादुर शास्त्री की अर्ध-प्रतिमाएं प्रदान की गई ताकि उन्हें महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थापित किया जा सके। आईसीसीआर ने आईसीसीआर के संस्थापक अध्यक्ष मौलाना आजाद की दुर्लभ पुस्तकों और पांडुलिपियों को शामिल करने वाले गोशा-ए-आजाद संग्रहण के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को जारी रखा जिससे विद्वानों और जन साधारण तक उसकी पहुंच को बढ़ाया जा सके तथा भावी पीढ़ियों के लिए उन दुर्लभ दस्तावेजों को संरक्षित किया जा सके।

32

भारतीय विश्व मामले परिषद

भारतीय विश्व मामले परिषद (आईसीडब्ल्यूए) ने विषय पर संसूचित विचारों के निकाय का विकास करने के उद्देश्य के साथ भारतीय विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय कार्यों के अध्ययन को प्रवर्तित करने के अपने अधिदेशित उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में अनेक क्रियाकलाप और पहलें संचालित की। इसने एशिया, अफ्रीका, यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स, लातिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा विकास तथा एक व्यापक भू-रणनीतिक परिवेश पर अपने शोध कार्य को जारी रखा। उन मुद्दों का निवारण करने के लिए प्रयास जारी रखे गए जो विदेश नीति के एजेंडा में प्राथमिकता पर थे तथा उसने अपने शोध परिणामों को नीतिगत रूप से प्रभावी बनाया। संचालित किए गए शोध-कार्य को स्प्रू हाउस पत्रों, इशू ब्रीफों, नीतिगत सारों और दृष्टिकोणों, चर्चा-पत्रों, शोध लेखों के रूप में प्रचारित-प्रसारित किया गया जिसे आईसीडब्ल्यूए की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया। इसके अलावा, आईसीडब्ल्यूए ने अपने शैक्षणिक परिणामों को हिन्दी में अनुवाद करने की प्रक्रिया को जारी रखा जिसे नियमित रूप से इसकी वेबसाइट पर रखा जाता है। उपर्युक्त परिणामों के अलावा, परिषद ने दीर्घकालिक परियोजनाओं को भी जारी रखा जिन्हें पुस्तकों और स्प्रू हाउस पत्रों के रूप में प्रकाशित किया गया। परिषद की नवीकृत वेबसाइट शीघ्र ही प्रारंभ की जाने वाली है जिसके अधिक प्रयोक्ता-हितैषी होने की संभावना है। आईसीडब्ल्यू ने आम जनता के लिए भी अपने पुस्तकालय को खोल दिया है तथा सदस्यता के नियमों को सरल बनाया गया है।

अपने अधिदेश के अनुरूप, आईसीडब्ल्यूए ने अनेक संख्या में समारोहों का आयोजन किया जिनमें वार्ताएं, सम्मेलन, संगोष्ठियां, व्याख्यान, संपर्क-सत्र, गोलमेज चर्चाएं तथा पहुंच संबंधी क्रियाकलाप शामिल हैं। उसने चर्चाओं और वाद-विवाद में विभिन्न विषयक मुद्दों को शामिल करने पर प्राथमिकता प्रदान की। समूचे देश की विभिन्न विचारक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों से विशेषज्ञों और विद्वानों को इनमें विषय-विशेषज्ञों के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। दिल्ली के बाहर से विषय विशेषज्ञों/विद्वानों को इनमें शामिल करने के विशेष प्रयास किए गए।

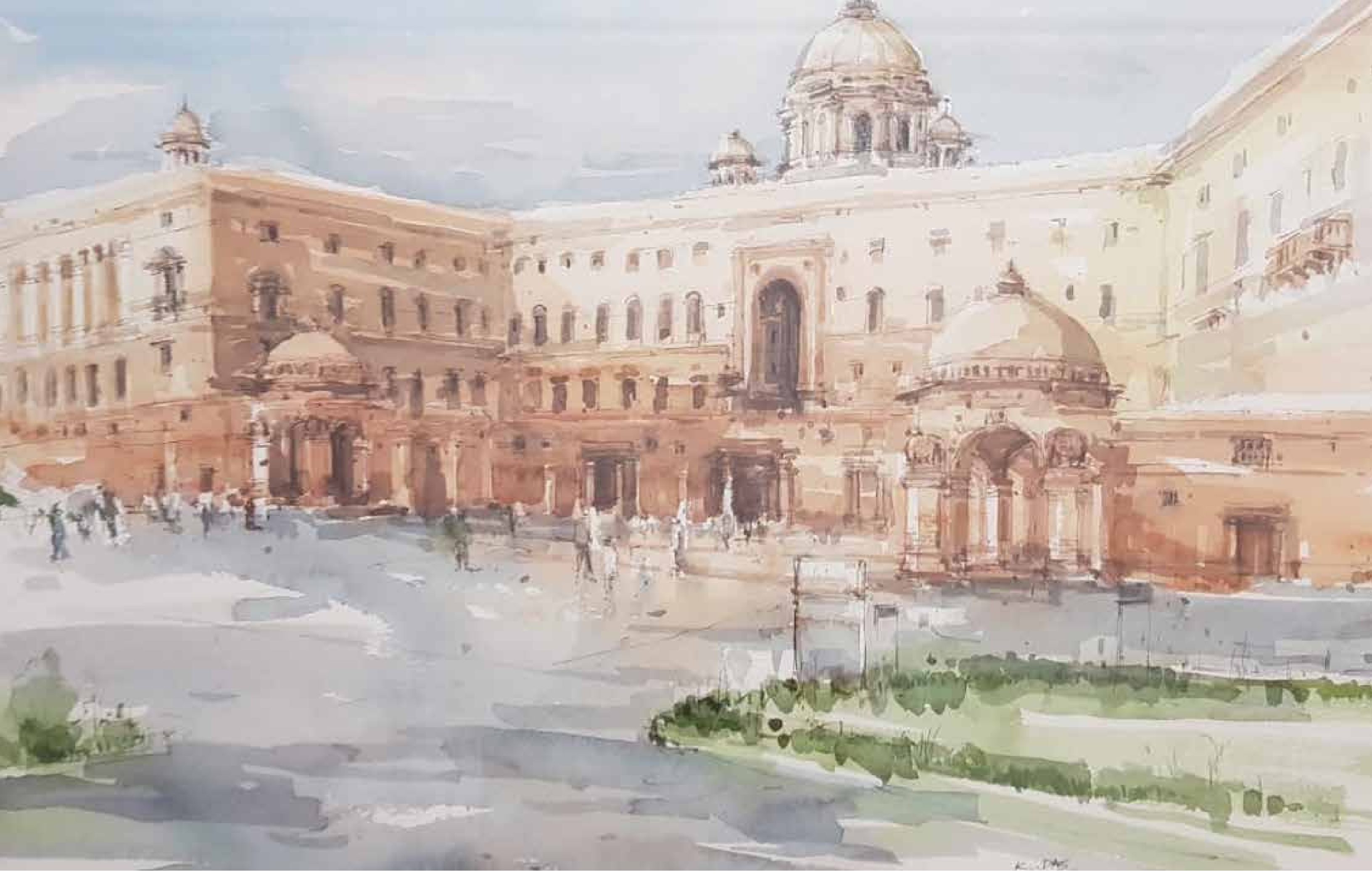

शोध

शोध संकाय की वर्तमान संख्या इस प्रकार है:

(क) निदेशक (शोध) - 1
(ख) शोध फेलो - 23
(ग) शोध इंटर्न (आरआई)- 1

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, परिषद के शोध संकाय ने एक नीतिगत सार, सैंतालीस इशू ब्रीफ, अठावन दृष्टिकोण, चार शोध लेख तथा मीडिया और अन्य जर्नलों में अनेक लेख प्रकाशित किए। उन्होंने प्रमुख राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक प्रवृत्तियों तथा विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में घटनाक्रमों के विषयों पर अध्ययन और शोध संचालित किया। भारत के निकटवर्ती और विस्तारित पड़ोस पर अध्ययन पर भी अधिक ध्यान-केन्द्रित किया गया जिसमें भारत-प्रशांत क्षेत्र शामिल था। चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, अफगानिस्तान, मिश्र, लीबिया, सउदी अरब, ईरान, तुर्की, यूएसए और रूस पर देश-विशिष्ट नीतिगत अध्ययन संचालित किए गए। इसके अलावा, बहुपक्षीय और क्षेत्रीय संगठनों जैसे एनएटीओ, एपीईसी, जी-20, ब्रिक्स और आईबीएमए पर अध्ययन भी संचालित किए गए। विभिन्न समसामयिक मुद्दों जैसे महासागर अर्थव्यवस्था, आतंकवाद, विकास भागीदारियां, साइबर सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर विशेष अध्ययन संचालित किए गए।

पुस्तक परियोजनाओं के क्षेत्र में, परिषद ने नए और समसामयिक विषयों को शामिल करने के लिए शोध-कार्य के वैविध्यीकरण करने का प्रयास किया जैसे प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मीडिया और विदेश नीति, विज्ञान और राजनयिकता, भारत और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि (आईएमएफ), लातिन अमेरिका और दक्षिण गठबंधन। परिषद ने विशेष अध्ययनों और परियोजनाओं का संचालन करते हुए मंत्रालय की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए पहलकदम भी उठाए। विदेश मंत्रालय सहित विभिन्न हितधारकों को सारांश/प्रतिवेदन/चर्चा पत्र प्रस्तुत किए गए।

अधिक से अधिक संख्या में जनता तक पहुंचने के लिए आईसीडब्ल्यूए ने अपने शैक्षणिक लेखों के हिन्दी मे अनुदित संस्करणों को प्रकाशित करना जारी रखा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सैंतालीस इशू ब्रीफ हिन्दी में अनुदित करा दिए गए हैं। आईसीडब्ल्यू ने विदेश नीति जागरूकता कार्यक्रम (हिन्दी में) की शुरुआत की तथा विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थाओं के सहयोग से संगोष्ठियों का प्रायोजन किया जहां परिषद के अधिकारियों तथा एक या अधिक शोध फेलो द्वारा उनमें प्रतिनिधित्व किया गया।

अपने पहुंच क्रियाकलापों के भाग के रूप में तथा युवाओं के मध्य विदेश नीति से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता का सृजन करने के लिए, आईसीडब्ल्यूए ने विद्यालय जाने वाले छात्रों (10-12 कक्षा) और स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए तीन राष्ट्रीय स्तर की निबंध लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की। चार निर्णायकों की समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर दोनों श्रेणियों के चुने गए विजेताओं को स्प्रू आउस में आयोजित किए जाने वाले सम्मान समारोह में आमंत्रित किया जाएगा।

अपनी 'संकाय तक पहुंच' पहल के भाग के रूप में, आईसीडब्ल्यूए अपने शोध संकाय को महत्वपूर्ण विषयों पर छात्रों को व्याख्यान देने के लिए समूचे भारत के विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों तक लेकर जा रहा है ताकि सरकार द्वारा संचालित की गई विदेश नीति संबंधी पहलों को प्रोत्साहित और प्रचारित-प्रसारित किया जा सके। आईसीडब्ल्यूए ने जम्मू विश्वविद्यालय, बंगलौर और इग्नू से अनुरोध प्राप्त किए हैं।

प्रकाशन

अवधि के दौरान निकाले गए आईसीडब्ल्यूए प्रकाशनों का ब्योरा इस प्रकार है:

1. अप्रैल, 2018 - नवम्बर, 2018 की अवधि के दौरान आईसीडब्ल्यूए के महत्वाकांक्षी जर्नल 'इंडिया क्वाटर्ली (एक प्रतिष्ठित सहयोगी-समीक्षित जर्नल) के तीन खंड प्रकाशित किए गए।
2. आईसीडब्ल्यूए ने अप्रैल, 2018 - नवम्बर, 2018 के दौरान तीन पुस्तकें प्रकाशित की जिनके शीर्षक है : सी.वी. रंगनाथन और संजीव कुमार संपा. द्वारा 'चायना एंड यूरेशियन रीजन : ज्योग्राफिक एंड ज्योपालिटिकल इंफ्लूएंसेस' भास्वती मुखर्जी द्वारा 'इंडिया एंड ईयू : एन इंसाइडर्स व्यू' तथा दिलीप सिन्हा द्वारा 'लेजिटिमेसी ऑफ पावर : दि परमानेंस ऑफ फाइव इन दि सिक्यूरिटी काउंसिल।'

स्प्रू हाउस पत्र

क्रम सं	शीर्षक	लेखक
1.	क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस थीसेस : मेगा नेरेटिव्स वर्सेज लोकल नेरेटिव्स एंड करंट अरब टर्मोइल	डा. फजर रहमान सिद्दीकी
2.	स्प्रू हाउस विशेष श्रृंखला खंड-2	राजदूत विजय के. नाम्बियार
3.	स्प्रू हाउस विशेष श्रृंखला खंड-2	राजदूत आजाद सिंह तूर

आईसीडब्ल्यूए सम्मेलन/संगोष्ठियां तथा अन्य क्रियाकलाप

परिषद के अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संपर्क क्रियाकलापों में शामिल है परिषद में तथा अनेक भागीदार देशों में सम्मेलनों, संगोष्ठियों और व्याख्यानों का आयोजन करना तथा उनमें प्रतिभागिता करना। इसने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर अपने समझौता-ज्ञापन भागीदारों के साथ अपनी वार्ताओं को सुदृढ़ बनाया है। आईसीडब्ल्यूए के संपर्क कार्यक्रमों में अनेक भारतीय विश्वविद्यालयों तथा विचारक संस्थाओं के साथ संयुक्त सम्मेलनों और संगोष्ठियों का आयोजन

करना शामिल है जिसमें परिषद के राष्ट्रीय समझौता-ज्ञापन भागीदार भी सम्मिलित हैं।

1 अप्रैल, 2018 से 30 नवम्बर, 2018 की प्रतिवेदन अवधि के दौरान परिषद ने निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया:

व्याख्यान	-	09
संगोष्ठियां/सम्मेलन	-	08
द्विपक्षीय रणनीतिक वार्ता	-	09
गोलमेज चर्चाएं/संपर्क	-	09
पुस्तक जारी/विमोचन/चर्चा कार्यक्रम	-	02
कुल		**37**

व्याख्यान

क्रम सं	तारीख	समारोह
1.	22 अप्रैल, 2018	श्री वी. श्रीनिवास, आईएएस, अध्यक्ष, राजस्थान राजस्व बोर्ड एवं अध्यक्ष राजस्व कर बोर्ड द्वारा 'दि रोल ऑफ चाइना इन दि इंटरनेशनल मॉनीटरी सिस्टम' पर वार्ता **अध्यक्षता :** राजदूत नलित सूरी, महानिदेशक, आईसीडब्ल्यूए
2.	3 मई, 2018	सर्बिया गणराज्य के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री श्री इविका डैसिक द्वारा सर्बिया इन दि रीजन, यूरोप एंड दि वर्ल्ड' पर 29वां सप्रू हाउस व्याख्यान **अध्यक्षता :** राजदूत नलित सूरी, महानिदेशक, आईसीडब्ल्यूए
3.	26 जून, 2018	यूनाइटेड अरब अमीरात (यूएई) के विदेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायेद अल नहयान द्वारा 'रीजनल अफेयर्स' पर 30वां सप्रू हाउस व्याख्यान। **अध्यक्षता :** राजदूत नलित सूरी, महानिदेशक, आईसीडब्ल्यूए
4.	28 जून, 2018	संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियान अवर महासचिव श्री जीन-पिएरे लैक्रोइक्स द्वारा 'दि करंट स्टेट ऑफ यूएन पीस कीपिंग एंड दि वे फार्वर्ड' पर वार्ता। **अध्यक्षता :** राजदूत नलित सूरी, महानिदेशक, आईसीडब्ल्यूए
5.	16 जुलाई, 2018	सीएआरआई, अर्जेंटीना के प्रोफेसर और शोध स्कालर डा. लिया रॉड्रिक्स द्वारा 'दि चेंजिंग पॉलिटिकल एनवायर्नमेंट इन लैटिन अमेरिका' पर वार्ता। **अध्यक्षता :** श्री अजनीश कुमार, उप महानिदेशक, आईसीडब्लयूए
6.	7 सितम्बर, 2018	नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री एवं नेपाल साम्यवादी दल के सह-अध्यक्ष श्री पुष्प कमल दहाल 'प्रचण्ड' द्वारा 'रीसेंट डेवलपमेंट्स इन पेपाल एंड एडवांसिंग इंडिया - नेपाल पार्टनरशिप फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी' पर 31वां सप्रू हाउस व्याख्यान **अध्यक्षता :** डा. टी.सी.ए. राघवन, महानिदेशक, आईसीडब्लयूए, स्थान : सप्रू हाउस सभागार

7.	25 सितम्बर, 2018	सोफिया विश्वविद्यालय, जापान के प्रो. अत्सुको कानेहारा द्वारा 'इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ एंड मैरीटाइम सिक्यूरिटी' पर वार्ता **अध्यक्षता :** श्री नरिन्द्र सिंह, पूर्व विधि सलाहकार, विदेश मंत्रालय तथा अध्यख, यूएन अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग
8.	16 अक्टूबर, 2018	तंजानिया, संयुक्त गणराज्य के विदेश मंत्री डा. ऑगस्टीन पी. महीगा द्वारा 'इंडिया-अफ्रीका रिलेशंस : दि तंजानियन पर्सपेक्टिव' पर व्याख्यान। **अध्यक्षता :** राजदूत राजीव के. भाटिया
9.	30 नवम्बर, 2018	मोजाम्बिक गणराज्य के विदेश और सहयोग मंत्री श्री जोस कोंडुगुआ एंटोनियो पछेको द्वारा 'प्रोस्पेक्टस ऑफ मोजाम्बिक इंडिया कोओपेरेशन' पर व्याख्यान **अध्यक्षता :** राजदूत पिनाक रंजन चक्रवर्ती, अध्यक्ष भारतीय राजनयिक संघ एवं पूर्व सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार

संगोष्ठियां/सम्मेलन

क्रम सं	तारीख	कार्यक्रम
1.	6 और 7 अप्रैल, 2018	'भारतीय लोकतंत्र के 70 वर्ष : भावी चुनौतियां' पर दो-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी राजनीति विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज, चक्रधरपुर, झारखंड द्वारा आयोजित स्थान : झारखंड
2.	13 और 14 अप्रैल, 2018	जीडीसी स्मारक कॉलेज, भिवानी में हिन्दी में विदेश नीति जागरूकता कार्यक्रम 'वर्तमान भारतीय सुरक्षा व विदेश नीति' पर दो-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी स्थान : भिवानी, हरियाणा
3.	18 मई, 2018	'इंडिया एंड लैटिन अमेरिका एंड दि कैरिबियन : स्ट्रैंथनिक दि पार्टनरशिप' विषय पर द्वितीय आईसीडब्ल्यूए-एलएसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्थान : ब्राजील
4.	15 और 16 सितम्बर, 2018	'आईडेंटिटी एंड दि पॉलिटिक्स ऑफ सिक्यूरिटी, सोवर्निटी एंड दि चैलेंजेज़ ऑफ वर्ल्ड पॉलीटिक्स' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्थान : गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात
5.	13 और 14 अक्टूबर, 2018	'इंडियाज़ सिक्यूरिटी चैलेंजेज एंड आप्शंस : फ्रॉम इंटरनल टु ग्लोबल' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी स्थान : फैजाबाद - 224123

6.	23 और 24 अक्टूबर, 2018	'करंट डेवलपमेंट एंड इट्स इंफैक्ट ऑन वर्ल्ड पॉलिटीज : विद रेफेरेंस टु ब्रिक्स, एससीओ एंड इंडो - पैसेफिक' स्थान : नैनीताल, उत्तराखंड
7.	15 और 16 नवम्बर, 2018	'एक्ट ईस्ट थ्रू नार्थ ईस्ट : इंडियाज़ वे टु ए न्यू एरा ऑफ डिप्लोमेसी' पर संगोष्ठी स्थान : ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश
8.	29 नवम्बर, 2018	'फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता अंतर्राष्ट्रीय दिवस' के अवसर पर समारोह आधार व्याख्यान : राजदूत संजय सिंह

द्विपक्षीय और रणनीतिक वार्ताएं

क्रम सं	तारीख	कार्यक्रम
1.	21 अप्रैल, 2018	भारत और न्यूजीलैंड के बीच तृतीय ट्रैक II वार्ता [भारतीय विश्व मामले परिषद (आईसीडब्ल्यूए), न्यूजीलैंड इंडिया रिसर्च इंस्टिट्यूट (एनजैडआईआरआई) एशिया न्यूजीलैंड फाउंडेशन (एएनजैडएफ)]
2.	4 और 5 मई, 2018	13वां शंघाई सहायोग संघ (एससीओ) फोरम बैठक स्थान : अस्ताना, कजाखस्तान
3.	16 और 17 मई, 2018	दि एलेक्जेंडर डी गुस्मासो फाउंडेशन (एफयूएनएजी), ब्राजील के साथ 'ब्राजील भारत: राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष' पर प्रथम द्विपक्षीय संगोष्ठी स्थान : ब्राजील
4.	28 मई, 2018	आईसीडब्ल्यूए - आईएफएएनएस द्विपक्षीय ट्रैक 1.5 वार्ता स्थान : सियोल, कोरिया
5.	13 और 14 सितम्बर, 2018	आईसीडब्ल्यूए और सेंटर फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस स्टडीज़ (सीआईआरएस), उज्बेकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित पांचवीं 'भारत-मध्य एशिया वार्ता' स्थान : समरकंद, उजबेकिस्तान
6.	25 सितम्बर, 2018	चाइनीज़ पीपल्स इंस्टिट्यूट ऑफ फारेन अफेयर्स (सीपीआईएफए) के साथ पांचवीं आईसीडब्ल्यूए द्विपक्षीय वार्ता स्थान : चीन
7.	28 सितम्बर, 2018	उज्बेकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति की अध्यक्षता में भारतीय विश्व मामले परिषद (आईसीडब्ल्यूए) तथा इंस्टिट्यूट फॉर स्ट्रेटैजिक एंड रीजनल स्टडीज (आईएसआरएस) के बीच संपर्क तथा सहयोग पर समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर

8.	14 और 15 नवम्बर, 2018	द्वितीय आईसीडब्ल्यूए - रशिया इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल (आरआईएसी) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा आईसीडब्ल्यूए और आरआईएसी के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर
9.	28 नवम्बर, 2018	'मोरक्को-भारत संबंध : रणनीतिक भागीदारी की स्थापना के लिए क्या अपेक्षित है?' विषय पर अंतर्राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी [रॉयल इंस्टिट्यूट फॉर स्ट्रेटैजिक स्टडीज (आईआरईएस), रबात, मोरक्को के साथ सहयोग में]

गोलमेज चर्चाएं और संपर्क

क्रम सं	तारीख	कार्यक्रम
1.	10 अप्रैल, 2018	नीति और अनुसंधान केन्द्र, विदेश मंत्रालय, इजराइल के दौरे पर आए विशेषज्ञों के साथ गोलमेज चर्चा
2.	30 मई, 2018	दि ब्रेंट थ्रस्ट फाउंडेशन, दक्षिण अफ्रीका के निदेशक डा. ग्रेग मिल्स तथा आईसीडब्ल्यूए के शोध संकाय के बीच पारस्परिक वार्ता **अध्यक्षता :** श्री अजनीश कुमार, उपमहानिदेशक, आईसीडब्ल्यूए
3.	28 अगस्त, 2018	ट्सिंघुआ यूनीवर्सिटी, चीन के प्रो. यान जेयूटोंग द्वारा 'एमर्जिंग बायलेटेरिज्म इन ग्लोब्लाइजेशन' पर व्याख्यान **अध्यक्षता :** डा. टी.सी.ए. राघवन, महानिदेशक, आईसीडब्ल्यूए
4.	4 सितम्बर, 2018	मोरक्कन सेंटर फॉर स्ट्रेटैजिक स्टडीज (सीएमईएस) के अध्यक्ष श्री मोहम्मद बेनहामो तथा सीएमईएस परियोजना और कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री अस्मा सेब्बर के साथ संपर्क वार्ता **अध्यक्षता :** डा. टी.सी.ए. राघवन, महानिदेशक, आईसीडब्ल्यूए
5.	6 सितम्बर, 2018	सेंटर फॉर इंटरनेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन के प्रमुख तथा इंस्टिट्यूट फॉर पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल स्टडीज (आईपीआईएस) के अध्यक्ष डा. सैयद मोहम्मद काजेम सज्जदपोर के साथ "इंडिया-ईरान इन ए ट्रासीशनल वर्ल्ड" पर गोलमेज चर्चा **अध्यक्षता :** डा. टी.सी.ए. राघवन, महानिदेशक, आईसीडब्ल्यूए
6.	6 सितम्बर, 2018	यूनिवर्सिटी ऑफ हैफा, इजराइल में नेशनल सिक्यूरिटी स्टडीज सेंटर के निदेशक डा. डैन शुफ्तान के साथ' चेंजिंग डायनैमिक्स ऑफ दि मिडल ईस्ट एंड इंटरनेशनल रिलेशंस' पर संपर्क वार्ता **अध्यक्षता :** डा. टी.सी.ए. राघवन, महानिदेशक, आईसीडब्ल्यूए
7.	18 सितम्बर, 2018	"पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक विवाद : वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए विवक्षाएं" विषय पर गोलमेज चर्चा **अध्यक्षता :** डा. टी.सी.ए. राघवन, महानिदेशक, आईसीडब्ल्यूए

8.	22 नवम्बर, 2018	इंस्टिट्यूट फॉर डेमोक्रेसी, दक्षिण कोरिया के निदेशक श्री किम मिंसेओक के साथ संपर्क चर्चा **अध्यक्षता :** डा. टी.सी.ए. राघवन, महानिदेशक, आईसीडब्ल्यूए
9.	5 सतिम्बर, 2018	सप्रू हाउस नई दिल्ली में इंस्टिट्यूट फॉर नेशनल सिक्यूरिटी स्ट्रेटैजी (आईएनएसएस) दक्षिण कोरिया से आए शिष्टमंडल के साथ संपर्क-चर्चा

पुस्तक जारी/विमोचन/चर्चा कार्यक्रम

क्रम सं	तारीख	कार्यक्रम
1.	9 अक्टूबर, 2018	“इंडिया एंड ईयू : एन इंसाइडर्स व्यू” शीर्षक पर आईसीडब्ल्यूए प्रकाशन का विमोचन [लेखक राजदेत भास्वती मुखर्जी] अध्यक्षता : राजदूत राजीव डोगरा
2.	16 नवम्बर, 2018	भारत-पेरू राजनयिक संबंधों पर “55 यीअर्स ऑफ डिप्लोमैटिक रिलेशंस पेरू-इंडिया क्रोनोलॉजी - मेन ईवेंट्स 26 मार्च, 1963 - 26 मार्च, 2018)

एशिया-प्रशांत सुरक्षा सहयोग परिषद

आईसीडब्ल्यूए वर्ष 2001 से एशिया-प्रशांत सुरक्षा सहयोग परिषद (सीएससीएपी) - भारत समिति की मेजबानी कर रहा है।

1 अप्रैल, 2018 से 30 नवम्बर, 2018 की अवधि के दौरान, परिषद ने निम्नलिखित क्रियाकलापों में प्रतिभागिता की:

1. 3-5 अप्रैल, 2018 तक सियोल, दक्षिण कोरिया में आयोजित गैर-प्रचुरोद्भवन और नि:शस्त्रीकरण संबंधी सीएससीपी अध्ययन ग्रुप की 5वीं बैठक।
2. 7-9 मई, 2018 तक कुअलालम्पुर, मलेशिया में आयोजित 32वीं एशिया-प्रशांत गोलमेज बैठक।
3. 9 और 10 मई, 2018 को कुअला लम्पुर, मलेशिया में आयोजित 49वीं संचालन समिति बैठक।
4. 5-14 नवम्बर, 2018 तक सियोल, दक्षिण कोरिया में ‘भावी एशिया-प्रशांत नेता के लिए वैश्विक कोरिया कार्यशाला’ पर सीएससीएपी बैठक।
5. 29 और 30 नवम्बर, 2018 को पर्थ, आस्ट्रेलिया में आयोजित 50वीं संचालन समिति बैठक।

आईसीडब्ल्यूए पुस्तकालय

1955 में अपनी स्थापना के बाद से ही सप्रू हाउस पुस्तकालय भारतीय और विदेशी स्कॉलरों के लिए एक अग्रणी संसाधन केन्द्र के रूप में उभरकर सामने आया है। वतमान में, इसके पास 1,55,553 पुस्तकें, जर्नल, मानचित्र तथा संयुक्त राष्ट्र (यूएन) एवं यूरोपीय संघ (ईयू) दस्तावेज हैं। यह अनुमान है कि 31 मार्च, 2018 तक लगभग 620 और पुस्तकें पुस्तकालय के संग्रह में जोड़ दी जाएंगी। संपूर्ण संग्रह डिजिटल अनुक्रमणिका के माध्यम से पहुंच-योग्य है तथाइ से ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग के माध्यम से सर्च किया जा सकता है। सप्रू हाउस पुस्तकालय का एक बड़ा भाग तथा साथ ही आईसीडब्ल्यूए जर्नल इंडिया क्वार्टरली का संपूर्ण संग्रहण डिजिटल फार्मेट में शोध स्कालरों के लिए सुलभ है। प्रमुख ऑनलाइन संसाधनों जैसे प्रोजेक्ट म्युज़, जेएसटीओआर और ओपीएसी के साथ सज्जित यह पुस्तकालय सदस्यों तथा आगंतुकों के समस्त प्रमुख शोध और शैक्षणिक क्रियाकलापों के लिए एक व्यापक मंच उपलब्ध कराता है।

पुस्तकालय का लक्ष्य दक्षिण एशिया पर विशेष ध्यान-केन्द्रित करते हुए भारतीय विदेश नीति के प्रमुख क्षेत्रों में उपलब्ध शोध सामग्री और दस्तावेजों का एक व्यापक भण्डार स्थापित करने का है। यह अपनी विषय-सूची और

सुविधाओं का निरंतर उन्नयन करने के माध्यम से हमारी शोध परियोजनाओं के निरंतर विस्तारित होते क्षेत्र की मांगों की पूर्ति करने के लिए कड़े प्रयास कर रही है।

प्रचार-प्रसार

आईसीडब्ल्यूए ने अपने शोध-परिणामों तथा क्रियाकलापों को यथासंभव विशाल संख्या में वैश्विक जन तक पहुंचाने तथा राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में भारतीय चिंताओं और आकांक्षाओं के बारे में जागरूकता का सृजन करने के लिए उनके व्यापक प्रचार-प्रसार की नीति प्रारंभ की है। प्रकाशनों के बारे में सूचना परिचालित करने की प्रणाली, वेबसाइट www.icwa.in का नवीनीकरण, सोशल मीडिया के उपकरणों का प्रयोग तथा महत्वपूर्ण आयोजनों की वेबकास्टिंग आईसीडब्ल्यूए के अधिदेश की प्राप्ति में सहायक सिद्ध हुए हैं।

33

आरआईएस

दिल्ली वार्ता एक्स: भारत- आसियान समुद्री सहयोग को मजबूत करना।

विकासशील देशों हेतु अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस), दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान)-आरआईएस में भारत केन्द्र (एआईसी), राष्ट्रीय समुद्री प्रतिष्ठान (एनएमएफ), नई दिल्ली; आसियान सचिवालय, जकार्ता; आसियान और पूर्वी एशिया (ईआरआईए) हेतु आर्थिक अनुसंधान संस्थान, जकार्ता की साझेदारी में विदेश मंत्रालय (एमईए) ने नई दिल्ली में 19 और 20 जुलाई, 2018 को दिल्ली वार्ता के दसवें संस्करण का आयोजन किया। इस दसवें दिल्ली वार्ता का विषय ''भारत-आसियान समुद्री सहयोग को मजबूत करना'' था। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने इस मंत्रालयी सत्र का मुख्या संबोधन किया; विदेश राज्य मंत्री जेनरल (डॉ.) वी. के. सिंह (सेवानिवृत्त), पूर्व विदेश राज्य मंत्री श्री एम. जे. अकबर और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सातों राज्यों के मुख्या मंत्रियों ने इस मंत्रालयी और विशेष पूर्णकालिक सत्रों में क्रमश: मुख्या भाषण दिया। आसियान के सदस्य राष्ट्रों के कई वरिष्ठ मंत्रियों सहित लगभग 300 शिष्टमंडलों और वरिष्ठ स्तरीय अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों, प्रसिद्ध विद्वानों, प्रैक्टिशनरों, कूटनीतिज्ञों, शिक्षाविदों, अनुसंधानकर्ताओं, कारोबारियों, कारोबारी संघों आदि ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

इस उद्घाटन सत्र में आसियान- भारत साझेदारी के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं अर्थात् कनेक्टिविटी, वाणिज्य और संस्कृति के 3सी सहित प्रमुख विषय शामिल किए गए थे। संपूर्ण सत्र में शामिल प्रमुख विषयों में आसियान के साथ एक्ट ईस्ट पॉलिसी में पूर्वोत्तर की भूमिका, सामाजिक - सांस्कृतिक संबंधों की मजबूती, भारत-आसियान साझेदारी और उभरती विश्व व्यवस्था, समुद्री सहयोग: भारत-आसियान साझेदारी के लिए एक नयी रूपरेखा, निवेश और प्रौद्योगिकी, विकास सहयोग, लघु-मध्यम उद्यम और क्षेत्रीय विकास, पर्यटन सहयोग तथा स्मार्ट शहरों का निर्माण थे।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज नई दिल्ली में दिल्ली वार्ता X के दौरान आसियान प्रतिनिधि मंडल प्रमुखों के साथ (19-20 जुलाई, 2018)

विदाई भाषण में भारत में थाईलैंड के राजदूत श्री चुतिनटोर्न गोंगसाक्डी तथा आवासन और शहरी मामले के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा भाषण दिया गया।

एआईआईबी नेतृत्व वाला कार्यक्रम और मेजबान देश सेमीनार

एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) की वार्षिक बैठक के संबंध में आरआईएस कार्यक्रम के अंत में निम्नलिखित विषयों पर देश में सात विभिन्न स्थानों पर सात शीर्ष कार्यक्रम आयोजित किए गए यथा - पत्तन और तटीय अवसंरचना में बढ़ोतरी: मुख्य क्षेत्रों के संबंध में प्रवेशिका (विशाखापत्तनम में 3 और 4 अप्रैल, 2018); शहरी विकास: तकनीकी समाधान और शासन संबंधी चुनौतियां (अहमदाबाद में 19 और 20 अप्रैल, 2018); भावी, नमनीय और डिजिटल अवसंरचना (बंगलुरू में 3 और 4 मई, 2018); क्षेत्रीय विकास के लिए वास्तविक और सामाजिक अवसंरचना (14 और 15 मई, 2018, गुवाहाटी); स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा (भोपाल में 21 मई, 2018); जल और स्वच्छता (पुर्ण में 31 मई और 1 जून, 2018); और निजी क्षेत्र भागीदारी एवं संसाधन जुटाने में नवोन्मेष (मुम्बई में 11 जून, 2018)। प्रमुख कार्यक्रमों के संबंधित विषयों के संबंध में गहन पृष्ठभूमि शोधपत्र में प्रसिद्ध विशेषज्ञों ने बहुत योगदान दिया।

एआईआईबी की तीसरी वार्षिक बैठक के दौरान दिनांक 25 जून, 2018 को मुम्बई में वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा 'अवसंरचना हेतु वित्तीय संग्रह के लिए नई खोज' नामक रिपोर्ट रखी गयी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फड़नवीस; उत्तराखंड के मुख्य मंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत; बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी; वित्त राज्य मंत्री श्री पी. राधाकृष्णन भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस रिपोर्ट में कई नीतिगत सिफारिशें थीं जो सभी हितधारकों के लिए उपयोगी होंगी।

तीसरी एआईआईबी की वार्षिक बैठक में आरआईएस अनुबंध

भारत सरकार ने 25 और 26 जून, 2018 को मुम्बई में एआईआईबी की तीसरी वार्षिक बैठक का आयोजन किया। आरआईएस ने भारत के शीर्ष औद्योगिक संघ - भारतीय चैम्बर्स आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री परिसंघ (फिक्की), भारतीय औद्योगिक संघ (सीआईआई) और एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आफ इंडिया (एसोचेम) की साझेदारी के साथ ज्ञान साझेदार के रूप में वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) के साथ मिलकर कार्य किया है। एआईआईबी की तीसरी वार्षिक बैठक के रनअप में आरआईएस ने सामूहिक रूप से संसाधन जुटाने और संस्थागत चुनौतियों से निपटने तथा कनेक्टिविटी और अवसंरचना विकास से लाभ संवृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों और नागरिक समाज संगठन के साथ सहयोग किया । वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली और एआईआईबी के अध्यक्ष श्री जिनलिक्विन ने नई दिल्ली में 27 फरवरी, 2018 को एआईआईबी की तीसरी वार्षिक बैठक का उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन जयराम गड़करी तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने नीति निर्धारकों, कूटनीतिज्ञों, बैंकरों, बहुपक्षीय संस्थाओं, उद्योग एवं अन्य पणधारकों के बड़े संघ के साथ अपनी अनुबोधक दृष्टिकोण को साझा किया।

विषय तथा शीर्ष सम्मेलनों के शहर निम्न प्रकार थे: कोलकाता में मास रैपिड परिवहन व्यवस्था; विशाखापतनम में पत्तन और तटीय अवसंरचना; अहमदाबाद में शहरी विकास; बंगलोर में भावी, नमनीय और डिजिटल अवसंरचना; गुवाहाटी में क्षेत्रीय विकास; भोपाल में साफ और नवीकरणीय ऊर्जा; पुणे में जल और स्वच्छता; और मुम्बई में निजी क्षेत्र भागीदारी और संसाधन संग्रहण में नवोन्मेष।

इन लीड-अप घटनाओं के आधार पर आरआईएस ने 'अवसंरचना हेतु निधि योजन की नई खोज' नामक रिपोर्ट प्रस्तुत किया।

दिल्ली प्रक्रिया IV के माध्यम से ब्युनेस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन (बीएपीए) +40 तक का मार्ग।

आरआईएस ने संयुक्त रूप से विदेश मंत्रालय, दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओएसएससी), नेटवर्क आफ सदर्न थिंक टैंक (एनईएसटी) और ''दक्षिण-दक्षिण सहयोग एवं बीएपीए+40- सैद्धांतिक परिदृश्य एवं

अनुभव जन्य वास्तविकताओं' के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भारतीय विकास सहयोग हेतु फोरम (एफआईडीसी) का आयोजन 13 और 14 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली में किया। इस सम्मेलन का फोकस दक्षिण-दक्षिण सहयोग (एसएससी) तथा विकास सहयोग की वैश्विक समझ का विस्तार- इसकी सैद्धांतिक रूपरेखा तथा संगत अनुभवजन्य मान्यीकरण के सैद्धांतिक भेदों को मजबूत करना था। सैद्धांतिक निर्माण जिसे इस वर्ष दिल्ली की प्रक्रिया में विचार हेतु लिया गया था, का फोकस किसी अवसंरचना को सृजित करने एवं एसएससी के कतिपय गैर-परक्राम्य सिद्धांतों पर सहमति एवं एसएससी में शामिल तौर तरीकों के सैद्धांतिक मॉडलिंग के रूप में विकास कॉम्पेक्ट के आविर्भाव पर था।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र का अध्यक्ष-चुनाव सुश्री मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा गार्सेज ने उद्‌घाटन भाषण दिया तथा प्रो. अमिताभ आचार्य, प्रसिद्ध प्रोफेसर, अमेरिकी विश्वविद्यालय, वाशिंगटन डीसी ने मुख्य भाषण दिया। राजदूत मोहन कुमार, अध्यक्ष, आरआईएस ने इस उद्‌घाटन सत्र की अध्यक्षता की और प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया। श्री जॉर्ज चेडिक, निदेशक, यूएनओएसएससी; भारत में अर्जेंटीना के राजदूत डेनियल चुबुरू; और सचिव (आर्थिक संबंध) श्री टी. एस. त्रिमूर्ति, विदेश मंत्रालय ने विशेष भाषण के जरिए इस सम्मेलन का मान बढ़ाया।

इस सम्मेलन में सामूहिक रूप से न केवल उनके अपने विकास वर्णन का स्वामित्व लेने हेतु देशों के लिए हीं नहीं बल्कि उत्तर-दक्षिण, दक्षिण-दक्षिण तथा त्रिकोणीय सहयोग से लाभ लेने के लिए एसएससी के स्तंभ के रूप में घरेलु क्षमता के महत्व को रेखांकित किया।

एसडीजी संबंधी दक्षिण एशियाई मंच

आरआईएस ने सितम्बर, 2015 में उनके विकास और अंगीकरण की प्रक्रिया से ही सक्रिय रूप से धारणीय विकास लक्ष्य (एसडीजी) में लगा रहा है। घरेलु और अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया विशेषकर एसडीजी के स्थानीयकरण के संबंध में भारतीय विचार बिंदू से एसडीजी की कार्यसूची के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एसडीजी के प्रमुख कार्यक्रम के रूप में आरआईएस ने कार्य किया। आरआईएस ज्ञान साझेदारी को मजबूत करने के लिए एसडीजी संबंधी विशिष्ट मुद्दों पर भारत में मुख्य प्रबुद्ध वर्ग और संगठनों के साथ सहयोग भी कर रहा है। नीति आयोग, भारत सरकार, भारत में एसडीजी के कार्यान्वयन में सहयोग और दिशा देने के लिए नोडल एजेंसी है। नीति आयोग, आरआईएस और यूएन भारत द्‌वारा कई राष्ट्रीय एसजीडी परामर्शों का आयोजन किया गया; इसमें विभिन्न राज्य/ संघ शासित सरकारों ने सक्रिय रूप से भागीदारी की।

आरआईएस ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र हेतु संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी) और नीति आयोग के सहयोग से नई दिल्ली में 4-6 अक्टूबर, 2016 को धारणीय विकास संबंधी एशिया-प्रशांत फोरम (एपीएफएसडी) के लिए धारणीय विकास लक्ष्य- उप क्षेत्रीय प्रारंभिक बैठक संबंधी दक्षिण एशियाई मंच का आयोजन किया।

यह बैठक 2019 की शुरूआत में बैंकाक में होने वाली धारणीय विकास संबंधी एशिया-प्रशांत मंच (एपीएफएसडी) की छठी बैठक के उप क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य और इनपुटों के साथ हुई। 2030 की कार्यसूची और धारणीय विकास लक्ष्य (एसडीजी) के कार्यान्वयन की अनुवर्ती कार्रवाई और समीक्षा के लिए मुख्य प्लेटफार्म के रूप में एपीएफएसडी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद् और महासभा दोनों के संदर्भ में उच्च स्तरीय राजनीतिक धारणीय विकास (एचएलपीएफ) के लिए तैयारी का समर्थन करता है।

डॉ. नागेश कुमार, निदेशक और प्रमुख, यूएनईएससीएपी दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम एशिया कार्यालय (यूएनईएससीएपी-एसएसडब्लूए) के शुरूआती भाषण दिया; श्री यूरी अफानासिव, संयुक्त राष्ट्र निवासी समन्वयक, भारत और अफगानिस्तान के उप आर्थिक मंत्री डॉ. ईस्माइल राहिमी, डॉ. पुष्पराज काडेल, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय योजना आयोग, नेपाल ने मुख्य भाषण दिया। डॉ. राजीव कुमार, उपाध्यक्ष, नीति आयोग, भारत ने उद्‌घाटन भाषण दिया।

बैठक में निम्नलिखित सत्र हुए: दक्षिण एशिया में 2030 कार्यसूची के कार्यान्वयन में प्रगति और उपलब्धियों की समीक्षा; दक्षिण एशिया में एचएलपीएफ 2019 के लिए चयनित लक्ष्यों की समीक्षा; दक्षिण एशिया में एचएलपीए के लिए चयनित लक्ष्यों की समीक्षा; कार्यसमूह द्‌वारा रिपोर्टिंग और आगे के रास्ता; ''लोगों का सशक्तिकरण और समावेशी व समानता को सुनिश्चित करना'' विषय पर 2019 के एपीएफएसडी और एचएलपीएफ विषय पर उप क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य;

दक्षिण एशिया में एसडीजी के कार्यान्वयन का माध्यम; वित्त, प्रौद्योगिकी और क्षमता संवर्धन (एसडीजी 17) में मुख्य अंतर की पहचान करना; दक्षिण एशिया में एसडीजी के कार्यान्वयन का माध्यम; संकेतकों, आंकड़ों, सांख्यिकी और अनुवर्ती और समीक्षा (एसडीजी 17); एसडीजी की प्राप्ति में तेजी लाने के लिए क्षेत्रीय सहयोग; समापन सत्र; आगे का मार्ग। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत के विशेषज्ञों ने इस विचार-विमर्श में हिस्सा लिया।

एसडीजी की प्राप्ति के लिए दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की क्षमता जानने के लिए नीतिगत वार्ता

आरआईएस ने यूएनईएससीएपी और नीतिगत अध्ययन हेतु दक्षिण एशिया केन्द्र की साझेदारी से नई दिल्ली में 6 अक्टूबर, 2018 को धारणीय विकास लक्ष्य:आगे का रास्ता के लिए दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की क्षमता की पहचान करने के लिए एक नीतिगत वार्ता का आयोजन किया।

डॉ. नागेश कुमार, प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र ईएससीएपी दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम एशिया कार्यालय (यूएनईएससीएपी-एसएसडब्लूए); राजदूत (डॉ.) मोहन कुमार, अध्यक्ष, विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस); प्रो. दीपक नैयर, उपाध्यक्ष, नीतिगत अध्ययन हेतु दक्षिण एशिया केन्द्र (एसएसीईपीएस) ने शुरूआती भाषण दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री रजनीश ने विशेष भाषण भाषण दिया और राष्ट्रीय योजना आयोग, नेपाल के उपाध्यक्ष डॉ. पुष्प राज कडल द्वारा उद्घाटन भाषण दिया गया।

इस वार्ता के सत्रों में शामिल थे: उभरती वैश्विक प्रवृत्ति के पृष्ठभूमि में दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के लिए क्षमता और चुनौतियां; परिवहन और ऊर्जा कनेक्टिविटी की क्षमता और चुनौतियां; कृषि, खाद्य सुरक्षा और पोषण में क्षेत्रीय सहयोग; दक्षिण एशिया में एसडीजी की प्राप्ति के लिए प्रबुद्ध वर्ग सहयोग संबंधी गोलमेज वार्ता; और समापन सत्र। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत के प्रतिनिधियों ने इन विचार-विमर्श में हिस्सा लिया।

सभी-एसडीजी 2 रोडमैप रूपरेखा के लिए स्वस्थ्य भोजन को सुनिश्चित करने के लिए धारणीय कृषि और किसानों की आय को दोगुना करना।

8 मई, 2018 को नई दिल्ली में 'सभी -एसडीजी 2 रोडमैप रूपरेखा के लिए स्वस्थ्य भोजन सुनिश्चित करने के लिए धारणीय कृषि और किसानों की आय को दोगुना करना' के संबंध में पणधारकों की कार्यशाला आयोजित की गयी। शिक्षा जगत के सदस्यगण, विशेषज्ञों, नागरिक समाज संगठनों, केन्द्रीय/ राज्य / संघ शासित प्रदेश (यूटी) सरकारों, यूएन संगठनों/ निकायों ने भारतीय संदर्भ में एसडीजी 2 की प्राप्ति में अपनी आकांक्षाओं और प्रतिबद्धताओं को साझा किया। विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) के सहयोग से आरआईएस द्वारा 'एसडीजी 2 रोडमैप फ्रेमवर्क' नाम से एक रिपोर्ट को भी इस सत्र में रखा गया।

इस कार्यक्रम की शुरूआत नीति आयोग के सलाहकार डॉ. अशोक कुमार जैन द्वारा दिए गए स्वागत भाषण से हुई। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, ने इस संदर्भ का निर्धारण किया। डॉ. हमीद नूरू, डब्लूएफपी के प्रतिनिधि और राष्ट्र निदेशक ने शुरूआती भाषण दिया। श्री यूरी अफानेसिव, संयुक्त राष्ट्र निवासी समन्वयक और भारत में यूएनडीपी निवासी प्रतिनिधि ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया। डॉ. राजीव कुमार, उपाध्यक्ष, नीति आयोग, भारत सरकार ने मुख्य भाषण दिया। डॉ. पी. के. आनंद, अतिथि फेलो, आरआईएस ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया।

सीएसआर और फ्लैगशिप कार्यक्रम के साथ एसडीजी और इस स्तर तक जाना।

आरआईएस ने तीसरी एआईआईबी वार्षिक बैठक के इतर मुम्बई में 25 जून, 2018 को भारतीय विकास सहयोग (एफआईडीसी) के लिए रिच स्केल और फोरम के साथ परस्पर बातचीत के सत्र का आयोजन किया।

प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस की टिप्पणियों के साथ सीएसआर और फ्लैगशिप कार्यक्रम के साथ एसडीजी और मूविंग अप द स्केल के सत्र की शुरूआत हुई। रीच स्केल के संस्थापक और सीईओ श्री डेविड विल्कोस ने शुरूआती भाषण दिया। आवासन और शहरी मामले मंत्रालय में राज्यमंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने विशेष भाषण दिया। सुश्री मेगन फेलोन, सीईओ, बेयरफुड कॉलेज इंटरनेशनल; प्रो. अमिताभ कुंडू, अतिविशिष्ट फेला, आरआईएस; और श्री रविचंद्रन नटराजन, प्रमुख साझेदार और सहयोग संबंध, टाटा ट्रस्ट, मुम्बई ने भी इस अवसर पर भाषण दिया। खुली चर्चा के साथ इस सत्र की समाप्ति हुई।

विकास सहयोग के लोकतांत्रीकरण के संबंध में गोलमेज वार्ता

एफआईडीसी और आरआईएस ने आरआईएस में 9 अगस्त, 2018 को बहु पणधारक साझेदारी के माध्यम से विकास सहयोग के लोकतांत्रीकरण' के संबंध में एक गोलमेज वार्ता का आयोजन किया।

पीआरआईए के अध्यक्ष डॉ. राजेश टंडन ने इस सत्र की अध्यक्षता की। प्रो. गुलशन सचदेव, प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्याय; कार्ल गर्समन, अध्यक्ष, नेशनल इंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी, यूएसए, और प्रो. मैको ईचीहारा, एसोसिएट प्रोफेसर, हितोत्सुबासी यूनिवर्सिटी, जापान मुख्य वक्ता थे।

प्रो. सेयूंजू ली, प्रो. चुंग आंग विश्वविद्यालय, दक्षिण कोरिया, और प्रो. मिलिंदो चक्रवर्ती, अतिथि फेलो, आरआईएस मुख्य चर्चा करने वाले थे। वैश्विक शासन संस्थाओं के लोकतांत्रीकरण संबंधी सत्र की अध्यक्षता आरआईएस के अतिविशिष्ट फेलो श्री अमर सिन्हा द्वारा की गयी।

उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच, 2018

आरआईएस शिष्टमंडल जिसमें महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी और डॉ. सब्यसांची, सहायक प्रोफेसर शामिल थे, ने इस उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच (एचएलपीएफ), 2018 में 10-13 जुलाई, 2018 के दौरान न्यूयार्क में यूएन मुख्यालय में भाग लिया। आरआईएस शिष्टमंडल ने आवासन और शहरी मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी तथा यूएन भारत से शिष्टमंडल की अध्यक्षता में भारत सरकार के शिष्टमंडल के साथ संयुक्त रूप से एचएलपीएफ के इन बैठकों में भाग लिया। इस यात्रा के भाग के रूप में भारत और वैश्विक रूप में, विशेषकर दक्षिणी देशों में एसडीजी के कार्यान्वयन के लिए और साझेदारी करने के लिए आरआईएस शिष्टमंडल ने यूएन और यूएन एजेंसियों के लिए भारत के स्थायी मिशन में वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की।

आरआईएस ने "एसडीजी कार्यान्वयन की समीक्षा: एसडीजी 11- शहरों और मानव पर्यावासों को समावेशी, सुरक्षित, नमनीय और धारणीय बनाना" और "एसडीजी कार्यान्वयन की समीक्षा: एसडीजी 17- धारणीय विकास के लिए वैश्विक साझेदारी के कार्यान्वयन और पुनरूद्धार करने के माध्यमों को सुदृढ़ बनाना" संबंधी मुख्य एचएलपीएफ समीक्षा बैठकों में भी भाग लिया। आरआईएस टीम ने "विकास हेतु वित्तपोषण: प्रगति और प्रत्याशा 2018" के संबंध में अलग से कार्यक्रम में भी भाग लिया। अंत में, आरआईएस के महानिदेशक ने 13 जुलाई, 2018 को दक्षिण-दक्षिण सहयोग के संबंध में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में "एसडीजी युग में दक्षिण-दक्षिण सहयोग के प्रभाव को आकर्षित करना" पर अलग से कार्यक्रम में पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।

बिम्सटेक पूर्व शिखर उच्च स्तरीय परामर्शदात्री बैठक

आरआईएस ने नीतिगत एवं सामाजिक -आर्थिक अनुसंधान (आईएसएसआर) और पैवेलियन ग्रुप संस्थान के साथ 2 और 3 अगस्त, 2018 को काठमांडू में बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (बिम्सटेक) शिखर उच्च स्तरीय परामर्श बैठक के लिए पूर्व-बंगाल की खाड़ी पहल का आयोजन किया। प्रो. डॉ. गोविंद नेपाल, कार्यकारी अध्यक्ष, आईएसएसआर नेपाल ने इस बैठक की अध्यक्षता की। नेपाली विदेश मंत्री श्री प्रदीप कुमार गयावाली मुख्य अतिथि थे और उन्होंने उद्घाटन भाषण दिया। बाद में इस समूह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।

बांग्लादेश के राजदूत सुश्री मसफीबिंटे शाम; नेपाल में भारत के राजदूत श्री मंजीब सिंह पुरी; श्रीलंका की राजदूत सुश्री डब्लू. स्वर्णलता परेरा; म्यामार के राजदूत श्री यू. टुन ने लिन; प्रो. (डॉ.) विश्वम्भर प्याकुरयाल, श्रीलंका और मालदीव के राजदूत तथा संयुक्त सचिव (बिम्सटेक और सार्क) एमईए श्री पीयूष श्रीवास्तव ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। इस परामर्शदात्री बैठक की मुख्य सिफारिशों को 26 अगस्त, 2018 को नेपाल के प्रधानमंत्री श्री खाडगा प्रसाद शर्मा ओली के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

वैश्विक व्यापार प्रणाली की सुरक्षा और बहुपार्श्ववाद की भूमिका।

आरआईएस जापान के साथ भारत के व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापक अनुसंधान कार्य को करता रहा है। आरआईएस ने एशिया अफ्रीका विकास कोरिडोर (एएजीसी) पर व्यापक कार्य किया, जो 2017 में अफ्रीकी विकास बैंक (एफडीबी) वार्षिक बैठक के दौरान अहमदाबाद में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अभिस्वीकृत एक पहल थी। आरआईएस ने एएजीसी के सिद्धांत को वास्तविक रूप देने के लिए आठ चर्चा पत्र लेकर आया है। जापानी संस्थाओं के साथ संबंधों को विकसित करने के लिए आरआईएस ने जापान आर्थिक प्रतिष्ठान (जेईएफ) की साझेदारी में नई दिल्ली में 22 और 23 नवम्बर, 2018 को दिल्ली में एशिया -प्रशांत मंच की सह मेजबानी की।

एपीएफ 2018 का मुख्य कार्यक्रम 22 नवम्बर, 2018 को 'वैश्विक व्यापार प्रणाली की सुरक्षा तथा बहुपार्श्ववाद की भूमिका' विषय के तहत उनकी अपनी सार्वजनिक विचारगोष्ठी थी जिसमें तीन पैनल सत्र था जिनका फोकस व्यापार और नयी प्रौद्योगिकी; क्षेत्रीय समाकलन के लिए अपरिहार्यता: सेवा क्षेत्र की बढ़ती भूमिका; और भारत-प्रशांत क्षेत्र में एसडीजी का महत्व और इसकी भूमिका: एसडीजी की प्राप्ति की नीतियां शामिल थीं। इस सार्वजनिक विचारगोष्ठी में एशिया प्रशांत क्षेत्र से प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा संबोधित किया गया तथा इसमें भारतीय विशेषज्ञ शामिल हुए। इस सार्वजनिक विचारगोष्ठी में विषय संबंधी विशेषज्ञों, शिक्षा विद, प्रबुद्ध वर्ग, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन, निवासी कूटनीतिज्ञ, सेवारत और पूर्व उच्च पदस्थ अधिकारियों की भागीदारी हुई। इस सार्वजनिक विचारगोष्ठी में मुख्य भाषण एमईए की पूर्व सचिव (पूर्व) सुश्री प्रीति सरण द्वारा दिया गया। इस सार्वजनिक विचारगोष्ठी के बाद दिनांक 23 नवम्बर, 2018 को आरआईएस के महानिदेशक तथा जेईएफ के अध्यक्ष के नेतृत्व में एपीएफ सदस्यों के साथ परामर्श कार्य किया गया।

ब्लू इकोनोमी के संबंध में द्वितीय आसियान-भारत कार्यशाला।

विदेश मंत्रालय ने संयुक्त रूप में वियतनाम के विदेश मंत्रालय; आसियान सचिवालय, जकार्ता; आसियान और पूर्वी एशिया के लिए आर्थिक अनुसंधान संस्थान (ईआरआईए), जकार्ता; राष्ट्रीय समुद्री प्रतिष्ठान (एनएमएफ), नई दिल्ली और नई दिल्ली में आरआरईएस में आसियान - भारत केन्द्र (एआईसी) ने नई दिल्ली में 18 जुलाई, 2018 को ब्लू इकोनोमी पर द्वितीय आसियान-भारत कार्यशाला का आयोजन किया। ईआरआईए के अध्यक्ष प्रो. हाइडेतोषी निशीमुरा तथा भारत में वियतनाम के राजदूत श्री टोन सिंन थान्ह ने शुरूआती भाषण दिया। मुख्य भाषण राजदूत प्रीति सरण, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्री द्वारा दिया गया। इस कार्यशाला में प्रत्येक आसियान सदस्य राष्ट्र, वरिष्ठ अधिकारियों और आसियान

व भारत के विशेषज्ञों के शिष्टमंडल प्रमुखों ने भाग लिया।

इस कार्यशाला का उद्देश्य नहा तरंग, वियतनाम में 24 और 25 नवम्बर, 2017 को ब्लू इकोनोमी संबंधी प्रथम आसियान-भारत कार्यशाला में चर्चा करना और आसियान-भारत नीतिगत साझेदारी के मुख्य पहलू के रूप में समुद्री क्षेत्र में आसियान-भारत सहयोग में प्रगति में नेताओं के दृष्टिकोण की प्राप्ति के लिए प्रयासों में बल देना था। विशिष्ट गतिविधियों और क्षेत्रों जहां आसियान और भारत साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं, की पहचान इस कार्यशाला के अंत में की गयी जो इस प्रतिष्ठान के रूप में कार्य करेगा जिन पर आसियान और भारत इस सहयोग में आगे की प्रगति के लिए कार्ययोजना बना सकते हैं। इस कार्यशाला का परिणाम दिल्ली वार्ता X में मंत्रालयी सत्र में दर्ज की गयी जिसका आयोजन नई दिल्ली में 19 और 20 जुलाई, 2018 को किया गया था। इस कार्यशाला को उन विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करने के लिए गहनता से चर्च करने को सुकर बनाने के लिए चार भागों में बांटा गया था जहां आसियान और भारत मिलकर सहयोग और कार्य कर सकते हैं। ये चार सत्र थे -ब्लू इकोनोती और समुद्री कनेक्टिविटी, ब्लू इकोनोमी की सहायता में प्रौद्योगिकी; ब्लू इकोनोमी और समुद्री सुरक्षा व कूटनीति तथा ब्लू इकोनोमी में विकास शामिल थे।

अंत में विदाई सत्र में भारत में वियतनाम के राजदूत श्री टोन सिन थान्ह ने समापन भाषण दिया। संयुक्त सचिव (आसियान बहुपक्षीय), एमईए श्री अनुराग भूषण ने यह विदाई भाषण दिया जबकि डॉ. प्रबीर डे, एआईसी समन्वयक ने इस कार्यशाला के बारे में संक्षेप में बताया और धन्यवाद भाषण दिया।

गांधी-मंडेला विरासत- आगे का रास्ता

महात्मा गांधी की 150 वीं जन्मशती और नेल्सन मंडेला की 100वीं जन्मशती को मनाने के लिए अग्रदूती के रूप में आरआईएस ने संयुक्त रूप से दक्षिण अफ्रीका उच्चायोग, नई दिल्ली, गांधी शांति प्रतिष्ठान और नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय के साथ संयुक्त रूप से ''गांधी-मंडेला विरासत: आगे का रास्ता'' नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 26 सितम्बर, 2018 को नई दिल्ली में किया। यह कार्यक्रम नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय (एनएमएमएल) के निदेशक श्री शक्ति सिन्हा और आरआईएस के अतिविशिष्ट फेलो श्री अमर सिन्हा द्वारा उद्घाटन भाषण के साथ शुरू हुआ। ये टिप्पणियां उच्चायोग नामोद्दिष्ट, दक्षिण अफ्रीकी उच्चायोग, नई दिल्ली डॉ. एच. एन. मंजिनी द्वारा दिए गए भाषण ने इस अवसर पर विशेष टिप्पणी दी। श्री राम माधव, सभापति, भारतीय प्रतिष्ठान ने मुख्य भाषण दिया। श्री कुमार प्रशांत, अध्यक्ष, गांधी शांति प्रतिष्ठान, जिन्होंने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की, ने गांधी -मंडेला विरासत पर भी बोला।

समुद्री सुरक्षा और सहयोग पर तीसरा ईएएस सम्मेलन।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमपी एवं एनजी); एनएमएफ; और आरआईएस में आसियान-भारत केन्द्र (एआईसी) की साझेदारी में विदेश मंत्रालय ने भुवनेश्वर, ओडिशा में 8 और 9 जून, 2018 को समुद्री सुरक्षा और सहयोग पर तीसरा पूर्वी एशिया शिखर (ईएएस) सम्मेलन का आयोजन किया। डॉ. प्रबीर डे, समन्वयक, एआईसी, आरआईएस द्वारा स्वागत भाषण दिया गया। उप एडमिरल प्रदीप कुमार चौहान, निदेशक, एनएमएफ द्वारा उद्घाटन भाषण दिया जबकि संयुक्त सचिव (आसियान -एमएल) श्री अनुराग भूषण द्वारा विशेष भाषण दिया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र पधान ने उद्घाटन भाषण दिया।

ईएएस सदस्य देशों ने अपने संबंधित देशों से अधिकारियों और विशेषज्ञों को नामित किया। लगभग पचपन प्रतिभागियों ने इस दो दिवसीय सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन को पांच सत्रों में विभाजित किया गया ताकि समुद्री सुरक्षा, समुद्री संरक्षा, समुद्र में व्यवस्था बने रहने, नीली अर्थव्यवस्था और आगे के पैनल चर्चा पर गहन विचार विमर्श हो सके। अंत में, संयुक्त सचिव (आसियान-एमएल) श्री अनुराग भूषण ने समापण भाषण दिया और डॉ. प्रबीर डे ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया। शिष्टमंडल ने 8 जून, 2018 को सांस्कृतिक

कार्यक्रम का आनंद उठाया और साथ हीं ओडिशा राज्य के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए एक्पोजर प्राप्त करने के उद्देश्य से 9 जून, 2018 को धौली और कोणार्क का क्षेत्र दौरा भी किया।

विज्ञान कूटनीतिक कार्यक्रम को शुरू करना।

हाल के दशकों में विज्ञान कूटनीति विदेश नीति में एक मुख्या औजार बनकर उभरा है। इसका इस्तेमाल वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए किया गया है जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी समस्या की पहचान करने तथा समाधान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। विज्ञान कूटनीति विकास सहयोग के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अन्य देशों और समूहों के साथ गहरे सहयोग को सुकर बना रही है। आरआईएस ने राष्ट्रीय उच्च स्तरीय अध्ययन संस्थान (बंगलुरू) के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार के सहयोग से विज्ञान कूटनीति संबंधी संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम को शुरू किया है। इस कार्यक्रम को नई दिल्ली में 7 मई, 2018 को शुरू किया गया था।

राजदूत डॉ. मोहन कुमार, अध्यक्ष, आरआईएस ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने इस परियोजना की रूपरेखा प्रस्तुत की। एमईए के सचिव (आर्थिक संबंध) श्री टी. एस. त्रिमूर्ति ने मुख्य भाषण दिया। प्रो. आशुतोष शर्मा, सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उद्घाटन भाषण दिया। प्रो. डी. सुबा चन्द्रन, अंतरराष्ट्रीय नीति और सुरक्षा अध्ययन, राष्ट्रीय उच्चस्तरीय अध्ययन संस्थान (एनआईएएस), बंगलुरू ने धन्यवाद प्रस्ताव किया।

प्रारूप नए नैदानिक परीक्षण नियम, 2018 के संबंध में पणधारक परामर्श

आरआईएस नीति अनुसंधान में इसका पता लगाया जाता है कि कैसे उभरता भारत अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने, उत्पादन श्रृंखला को आगे ले जाने तथा अपने अंतरराष्ट्रीय छाप में बढ़ोतरी करने के लिए वैश्विक मंच पर अपने लिए तुलनात्मक लाभ प्राप्त कर सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में आरआईएस ने पूर्व के संशोधनों को ध्यान में रखते हुए तथा देश में नैदानिक परीक्षणों के संबंध में इन बदलावों के प्रभावों के लिए इन नियमों की जांच करने, मूल्यांकन करने और चर्चा करने के लिए प्रारूप नियमों के संबंध में पणधारकों के विचारों को स्पष्ट करने के लिए 7 अप्रैल, 2018 को प्रारूप नए नैदानिक परीक्षण नियम, 2018 के संबंध में पूर्ण दिवसीय विशेषज्ञ परामर्श का आयोजन किया।

इस परामर्श में शिक्षा क्षेत्र, उद्योग जगत, निजी और सरकारी संविदा अनुसंधान संगठनों, आचार समितियों, मीडिया के विविध पणधारकों और सरकार को एक मंच पर ला दिया। इससे इस चर्चा में उपस्थित विभिन्न प्रतिभागियों से विभिन्न परिप्रेक्ष्यों की साझेदारी और आदान-प्रदान हुआ। इस संपूर्ण दिवसीय परामर्श सत्र को चार तकनीकी सत्रों में बांटा गया था जिनमें प्रारूप नियम, 2018 के मूलभूत पहलु शामिल थे। इसमें आंकड़ा संग्रहण, आंकड़ों की उपलब्धता और पारदर्शिता, सामंजस्य संबंधी मुद्दों, क्षमता निर्माण, शिक्षा क्षेत्र और औद्योगिक अनुसंधान इंटरफेस, बेहतर नैदानिक और प्रयोगशाला प्रचलन, प्रौद्योगिकी व बौद्धिक संपदा के विविध विषय शामिल थे।

उद्घाटन संबोधन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) के पूर्व महानिदेशक प्रो. समीर ब्रह्मचारी ने दिया। प्रो. डी. प्रभाकरन, उपाध्यक्ष, भारतीय लोक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पीएचएफआई) और डॉ. नंदिनी कुमार, पूर्व उप महानिदेशक (वरिष्ठ ग्रेड) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आईसीएमआर) द्वारा विशेष संबोधन किया गया। प्रो. टी. सी. जेम्स, अतिथि फेलो, आरआईएस ने इस परामर्श में विचारण हेतु इन मुद्दों को प्रस्तुत किया। अन्य वक्ताओं में राजदूत सुधीर टी. देवारे, अध्यक्ष, अनुसंधान परामर्श परिषद्, आरआईएस; डॉ. जाकिर थॉमस, पूर्व निदेशक (मुक्त स्रोत औषधि खोज), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर); प्रो. वैद्य के. एस. धिमान, महानिदेशक, केन्द्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएएस), आयुष मंत्रालय; डॉ. सरादीनदु भदुरी, अध्यक्ष, केन्द्रीय विज्ञान

नीति अध्ययन (सीएसएसपी), जेएनयू; डॉ. चिराग त्रिवेदी, अध्यक्ष, भारतीय नैदानिक अनुसंधान सोसाइटी; और श्री अशोक मदन, भारतीय औषधि विनिर्माण संघ (आईडीएमए) शामिल थे। इस परामर्श के आधार पर आरआईएस ने प्रारूप नियमों के संबंध में खंड-वार टिप्पणियां तैयार की और इन्हें उचित विचारण के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंप दिया।

आईओआरए और ब्रिक्स की दक्षिण अफ्रीकी अध्यक्षता: शिखर सम्मेलन में मुद्दे

आरआईएस और पांडिचेरी विश्वविद्यालय ने संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को), मदनजीत सिंह दक्षिण एशियाई सांस्कृतिक सहयोग संस्थान, पांडिचेरी विश्वविद्यालय में 4 अप्रैल, 2018 को संयुक्त रूप से हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग (आईओआरए) और ब्रिक्स की दक्षिण अफ्रीकी अध्यक्षता: शिखर सम्मेलन में मुद्द' के संयुक्त पैनल चर्चा का आयोजन किया।

प्रो. गुरमीत सिंह, उप कुलपति, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम को आरआईएस के प्रोफेसर डॉ. एस. के. मोहंती के शुरूआती भाषण के साथ आगे बढ़ाया गया। डॉ. अनिल सूकलाल, उप महानिदेशक, अंतरराष्ट्रीय संबंध और सहयोग विभाग, दक्षिण अफ्रीका, ने विशेष भाषण दिया। इसके बाद भारत में दक्षिण अफ्रीका के उच्चायोग के उच्चायुक्त डॉ. एन. मंजिनी तथा विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (एमईआर), श्री आलोक ए. दिमरी का संबोधन हुआ तथा उसके पश्चात आपसी विचार-विमर्श हुआ। डॉ. ए. सुब्रमणियम राजू, प्रमुख, दक्षिण एशियाई अध्ययन और समन्वयक केन्द्र, यूजीसी समुद्री अध्ययन केन्द्र, पांडिचेरी विश्वविद्यालय ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया।

भारत का शहरी पुनर्जागरण

आरआईएस और राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (एनआईयूए) ने संयुक्त रूप से नई दिल्ली में 2 जून, 2018 को 'भारत का शहरी पुनर्जागरण' के संबंध में परस्पर बातचीत सत्र का आयोजन किया। राजदूत अमर सिन्हा, अतिविशिष्ट फेलो, आरआईएस ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम की शुरूआत आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी के स्वागत भाषण के साथ हुई। प्रो. जगन शाह, निदेशक ने इस प्रस्तुतिकरण को नेतृत्व प्रदान दिया। आवासन और शहरी मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने मुख्य भाषण दिया। बड़ी संख्या में प्रतिभागियों द्वारा मुक्त चर्चा के साथ इसका समापन हुआ।

आसियान एचओएम के साथ दिल्ली वार्ता X के संबंध में परामर्श बैठक

वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका

आरआईएस ने नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय (एनएमएमएल); सभ्यता अनुसंधान संस्थान वार्ता (डीओसी), बर्लिन; और दैनिक भास्कर के साथ संयुक्त रूप से 3 जुलाई, 2018 को नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली में ''विश्व व्यवस्था में भारत की भूमिका' के संबंध में गोइज़ुवेटा बिजनेस स्कूल आफ इमोरी यूनिवर्सिट, अटलांटा, अमेरिका में डॉ. जगदीश सेठ, चार्ल्स एच. केलस्टेडट, प्रोफेसर, मार्केटिंग द्वारा एक सार्वजनिक व्याख्यान आयोजित किया ।

डॉ. जगदीश सेठ भू राजनैतिक विश्लेषण में अपने विद्वतापूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं। उन्हें सदर्न कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनोआइस, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, एमआईटी और एमोरी विश्वविद्यालय में अध्यापन और अनुसंधान का पचास वर्ष से अधिक का साझा अनुभव है।

डॉ. विनय प्रभाकर सहस्रबुद्धि, अध्यक्ष, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् (आईसीसीआर), ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इसकी शुरूआत आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन

चतुर्वेदी के स्वागत भाषण से हुआ तथा श्री शक्ति सिन्हा, निदेशक, एनएमएमएल, श्री पुरण चंद्र पांडेय, परियोजना प्रबंधन निदेशक, सभ्यता अनुसंधान संस्थान की वार्ता, ने शुरूआती भाषण दिया। श्री दीपक द्विवेदी, अध्यक्ष, बोर्ड एवं प्रधान संपादक, दैनिक भास्कर ने विशेष संबोधन किया।

इस अवसर पर आरआईएस और डीओसी अनुसंधान संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से रखी गयी 'वैश्विक संदर्भ में भारत- रूस संबंध'' संबंधी रिपोर्ट भी जारी की गयी।

भारतीय औषधि प्रणाली के वैश्विक संवर्धन के संबंध में औद्योगिक परामर्श।

आयुष मंत्रालय और आरआईएस के सहयोग से भारतीय परंपरागत औषधि मंच (एफआईटीएम) ने 18 मई, 2018 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में भारतीय औषधि प्रणाली के वैश्विक संवर्धन संबंधी एक औद्योगिक परामर्श का आयोजन किया। इसका मुख्य उद्देश्य नीतिगत कार्य सिफारिशों को तैयार करने के लिए औद्योगिक-सरकारी वार्ता को सुकर बनाना था। पैनालिस्टों में उद्योगों, शिक्षा जगत और भारत सरकार के मंत्रालयों के प्रतिनिधिगण शामिल थे। इस परामर्श में चर्चा का आधार प्रतिभागियों का व्यवहारिक ज्ञान था।

इस परामर्श में चार प्रमुख पैनल चर्चा था जिनमें भारतीय औषधि प्रणाली के वैश्विक उन्नयन के लिए चुनौतियों और समाधान की पहचान करना था। इनमें निर्यात संवर्धन संबंधी घरेलु नीति और विनियामक तैयारी की समीक्षा; अधिक वैज्ञानिक मान्यीकरण के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय निर्माण मानक और गुणवत्ता आश्वासन के लिए उपाय करना तथा फार्माकोपियल मानकों के लिए अभिदत्त; औषधीय पौधों के संग्रहण और उपज सहित कच्चे मालों की आपूर्ति के साथ संबद्ध चुनौतियां; तथा भारत और विदेश में प्रैक्टिशनरों के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु स्वास्थ्य उद्योग संबंधी विनियामक एवं आईएसएम क्षेत्र के संबंध में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संधियों और समझौतों के प्रभाव शामिल थे।

भारतीय औषधि प्रणाली के लिए दृष्टिकोण की समीक्षा को पूर्व वाणिज्य सचिव और आरआईएस के अतिविशिष्ट फेलो श्री राजीव खेर द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा डॉ. आकाश तनेजा, संयुक्त महानिदेशक, विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने मुख्य भाषण दिया। डॉ. मनोज नेसारी, सलाहकार, आयुष मंत्रालय ने इस परामर्श का उद्घाटन किया। श्री वैद्य राजेश कोटेचा, सचिव, आयुष मंत्रालय तथा श्री प्रमोद कुमार पाठक, अपर सचिव, आयुष मंत्रालय ने भी इस परामर्श में शामिल हुए।

औद्योगिक प्रतिनिधित्व वाली भारतीय औषधि प्रणाली के वैश्विक संवर्धन के लिए चुनौतियों और समाधान की पहचान के लिए चार पैनल चर्चा हुई। इनमें निर्यात संवर्धन संबंधी घरेलु नीति और विनियामक तैयारी की समीक्षा; अधिक वैज्ञानिक मान्यीकरण के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय निर्माण मानक और गुणवत्ता आश्वासन के लिए उपाय करना तथा फार्माकोपियल मानकों के लिए अभिदत्त; औषधीय पौधों के संग्रहण और उपज सहित कच्चे मालों की आपूर्ति के साथ संबद्ध चुनौतियां; तथा भारत और विदेश में प्रैक्टिशनरों के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु स्वास्थ्य उद्योग संबंधी विनियामक एवं आईएसएम क्षेत्र के संबंध में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संधियों और समझौतों के प्रभाव शामिल थे। इन परामर्शों के आधार पर सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए आयुष मंत्रालय को सौंपी गयी।

आसियान-भारत गैर प्रशुल्क उपायों (एनटीएम) पर एक सेमीनार

आरआईएस में आसियान-भारत केन्द्र (एआईसी) ने नई दिल्ली, भारत में 20 अप्रैल, 2018 को आसियान-भारत गैर प्रशुल्क उपाय (एनटीएम) पर एक सेमीनार आयोजित किया। यह सेमीनार आसियान और भारत के बीच एनटीएम संबंधी एआईसी द्वारा आयोजित अनुसंधान अध्ययन का परिणाम था। आरआईएस में एआईसी के समन्वयक तथा आरआईएस के प्रोफेसर डॉ; प्रबीर डे द्वारा स्वागत भाषण दिया गया। विदेश मंत्रालय, आसियान-एमएल के संयुक्त सचिव श्री अनुराग भूषण द्वारा शुरूआती भाषण दिया गया था। डॉ. प्रबीर डे और डॉ. दुरईराजकुमार स्वामी द्वारा इस अध्ययन संबंधी प्रस्तुतिकरण दिया गया। इन प्रस्तुतिकरण पर श्री प्रणव कुमार, प्रमुख, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और नीति प्रभाग, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और डॉ. अनिल जौहरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), राष्ट्रीय प्रमाणपत्र निकाय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीसीबी), नई दिल्ली से टिप्पणियां प्राप्त हुई। अंत में, डॉ. प्रबीर डे ने इस अध्ययन का सार दिया और धन्यवाद भाषण दिया। इस सेमीनार में सरकारी अधिकारियों, निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों, औद्योगिक विशेषज्ञों, अनुसंधान विद्वानों आदि ने भाग लिया।

क्षमता संवर्धन कार्यक्रम

अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत और प्रचलन संबंधी आरआईएस-एक्जिम बैंक समर स्कूल।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में कार्यरत विद्वानों के क्षमता वर्धन के योगदान के लिए आरआईएस ने भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विशेषज्ञता हासिल कर रहे है एमफिल और पीएचडी छात्रों के लिए 11-16 जून, 2018 के दौरान नई दिल्ली में समर स्कूल कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का आयोजन किया।

व्यापार और धारणीयता

आरआईएस ने 9-20 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली में 'व्यापार और धारणीयता' के संबंध में प्रथम आईटीईसी पाठ्यक्रम का आयोजन किया। विभिन्न विकासशील देशों के मध्य स्तरीय सरकारी अधिकारियों, नीति निर्धारकों और शिक्षाविदों सहित पच्चीस से अधिक प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

इस कार्यक्रम में व्यापक रूप में कई विषय शामिल किए गए यथा उत्पादन और व्यापार, विनियामक रूपरेखा, जैव प्रौद्योगिकी आदि। आरआईएस संकाय-सदस्यों, प्रसिद्ध विशेषज्ञों ने इन विषयों पर व्यापक परिप्रेक्ष्य पर इनपुट दिया। इस कार्यक्रम का समन्वयन आरआईएस के प्रो. एस. के. मोहंती द्वारा किया गया।

धारणीय विकास लक्ष्य

आरआईएस ने 6-17 अगस्त, 2018 में नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में 'धारणीय विकास लक्ष्य' पर आईटीईसी क्षमता- संवर्धन पाठ्यक्रम का प्रथम संस्करण आयोजित किया।

चौबीस देशों के मध्य स्तरीय सरकारी अधिकारियों/ कूटनीतिज्ञों, नीति निर्धारकों और शिक्षाविदों सहित बत्तीस से अधिक प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेषी नीति (एसटीआईपी) मंच व्याख्यान श्रृंखला

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था तैयार करने में नवोन्मेषी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी व नवोन्मेषी नीति (एसटीआईपी) मंच व्याख्यान श्रृंखला के भाग के रूप में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के सृजन में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष संबंधी नौवीं एसटीआईपी श्रृंखला में 19 जून, 2018 को नई दिल्ली में भारत सरकार के मुख्या वैज्ञानिक सलाहकार तथा मंत्रिमंडल (एसएएसी-सी) के लिए वैज्ञानिक सहलाकार परिषद् के अध्यक्ष प्रो. के. विजय राघवन द्वारा व्याख्यान दिया गया। राजदूत भास्कर बालाकृष्णन, पूर्व भारतीय कूटनीतिज्ञ और आरआईएस के वैज्ञानिक कूटनीति अध्येतावृत्ति ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। प्रो. के. विजय राघवन 28 जनवरी, 2013 से 2 फरवरी, 2018 तक भारत सरकार में जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के सचिव थे। वे भारतीय विज्ञान अकादमी, रॉयल सोसाइटी, एकेडमी आफ मेडिकल साइंस (यूके) के एक फेलो हैं तथा यूएस नेशनल एकेडेमी आफ साइंस के विदेशी एसोसिएट हैं। उन्हें वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री का पुरस्कार प्रदान किया गया था।

प्रोटीन संबंधी कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए दलहन क्रांति

7 अगस्त, 2018 को 'प्रोटीन संबंधी कुपोषण हेतु दलहन क्रांति' पर ग्यारहवें एसटीआईपी मंच पर डॉ. त्रिलोचन महापात्रा, सचिव, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग तथा महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) द्वारा व्याख्यान दिया गया और इसकी अध्यक्षता आईसीएआर के पूर्व डीजी तथा कृषि विज्ञान उन्नयन न्याय (टीएएएस) के अध्यक्ष द्वारा की गयी थी। वर्तमान स्थिति के पूर्व डॉ. महापात्रा प्रतिष्ठित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान,

नई दिल्ली के निदेशक-सह-उप कुलपति के पद पर थे। और इसके पूर्व उन्होंने राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (पूर्व में सीआरआरआई), कटक के निदेशक के रूप में कार्य किया।

स्वास्थ्य देखभाल के लिए मितव्ययी नवोन्मेष

10 सितम्बर, 2018 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के डीजी प्रो. बलराम भार्गव द्वारा 'स्वास्थ्य देखभाल के लिए मितव्ययी नवोन्मेष' विषय पर बारहवें एसटीआईपी मंच पर व्याख्याान दिया गया। इसकी अध्यक्षता नीति आयोग, भारत सरकार के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार द्वारा की गयी, प्रो. भार्गव अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली के कार्डियोलोजी के प्रोफेसर हैं और स्टेनफोर्ड इंडिया बायोडिजाइन केन्द्र, स्कूल आफ अंतरराष्ट्रीय बायोडिजाइन (एसआईबी) के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य करते हैं।

34

पुस्तकालय और अभिलेखागार

विदेश मंत्रालय पुस्तकालय, पुस्तकालय के कर्तव्यों का निर्वहन करता है और विदेश में भारतीय मिशनों और पोस्टों के साथ-साथ मुख्यालय में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के उपयोग के लिए एक संसाधन और सूचना केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। पुस्तकालय वर्तमान में पटियाला हाउस और जवाहरलाल नेहरू भवन (जेएनबी) में कार्यरत है। पटियाला हाउस में पुस्तकालयमें आठ कक्ष के साथ वर्चुअल पठान कक्ष है और यह उपयोगकर्ताओं / अनुसंधान विद्वानों के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा से सुसज्जित है।

पुस्तकालय में एक लाख से अधिक पुस्तकें, समृद्ध संसाधन सामग्री और नक्शे, माइक्रोफिल्म और आधिकारिक दस्तावेजों का एक बड़ा संग्रह है। यह नीति नियोजन और अनुसंधान का समर्थन करने के लिए आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। पुस्तकालय 300 से अधिक पत्रिकाओं और समाचार पत्र (ऑनलाइन पत्रिकाओं और डेटाबेस सहित) की सदस्यता है और उनका रखरखाव करता है।

पुस्तकालय समिति पुस्तकों की खरीद और पत्रिकाओं और डेटाबेस की सदस्यता सहित गतिविधियों का प्रबंधन करती है। विदेश सचिव, पुस्तकालय समिति का गठन / पुन: गठन करते है। पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष की प्रत्यायोजित प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों से ऊपर रुपये 2,50,000 / - से अधिक व्यय वाले प्रस्तावों पर विदेश सचिव की मंजूरी ली जाती है। वर्तमान समिति में अतिरिक्त सचिव (नीति नियोजन एवं अनुसंधान), अध्यक्ष के रूप में, 3-4 क्षेत्रीय प्रभागों से निदेशक / उप सचिव सदस्य के रूप में और निदेशक (पुस्तकालय और सूचना) सदस्य-सदस्य के रूप में शामिल हैं। विक्रेताओं द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत पुस्तकों को सर्वप्रथम समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है जिनकी पुस्तकालय अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है। पुस्तकालय के लिए पुस्तकों के चयन के लिए प्रति वर्ष नियमित अंतराल पर तीन से चार समिति की बैठकें की जाती हैं। अनुरोधित / अनुशंसित पुस्तकें दिन-प्रतिदिन के आधार पर खरीदी जाती हैं। अंतर-पुस्तकालय ऋण के माध्यम से भी पुस्तकों की खरीद की जाती है और अधिकारियों को आपूर्ति की जाती है। पुस्तकालय ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर ई-पुस्तकों का एक संग्रह भी खरीदा है और ये ई-पुस्तकें मंत्रालय के मुख्यालय के सभी अधिकारियों और विदेशों में मिशनों के लिए उपलब्ध हैं।

मंत्रालय के अधिकारियों और मुख्यालय में तैनात कर्मचारियों और विदेशों में मिशनों को नियमित रूप से पुस्तकालय सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पुस्तकालय सेवाएं प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कार्यालय, भारतीय विश्व मामलों की परिषद (आईसीडब्ल्यूए), भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर), राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस), राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के साथ-साथ उनके मंत्रालयों और विभागों को भी समय-समय पर प्रदान की जाती हैं। पुस्तकालय, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और संबद्ध विषय क्षेत्रों पर अपने समृद्ध और विशेष संग्रहों के माध्यम से अध्ययन और अनुसंधान के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों के अनुसंधान विद्वानों का स्वागत भी करता है।

एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर “वेब सेंट्रिक लिबसिस 7” के प्रयोग द्वारा सभी प्रलेखन / ग्रंथ सूची सेवाओं के साथ-साथ अन्य पुस्तकालय संचालन और उपयोगकर्ता सेवाओं को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। सभी पुस्तकों और दस्तावेजों के साथ-साथ पुस्तकालय में प्राप्त पत्रिकाओं / पत्रिकाओं से चयनित लेखों की जानकारी ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग (ओपीएसी) के माध्यम से उपलब्ध है। लाइब्रेरी की जानकारी विदेश मंत्रालय की पुस्तकालय वेबसाइट http://mealib.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

पुस्तकालय में प्राप्त सभी नए दस्तावेजों और पत्रिकाओं और पत्रिकाओं से चयनित लेख विदेशी मामलों (एफएआईआरएस) पर डेटाबेस में नियमित रूप से दर्ज किए जाते हैं। ऑनलाइन डेटाबेस और पत्रिकाओं / पत्रिकाओं को उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड के माध्यम से वेब पर पहुँचा जा सकता है। उपलब्ध ऑनलाइन संसाधनों और डेटाबेस की एक सूची नियमित रूप से परिचालित की जाती है और मंत्रालय के इंट्रानेट पर भी उपलब्ध है।

अपने उपयोगकर्ताओं को प्रलेखन, ग्रंथ सूची और संदर्भ सेवाएं प्रदान करने के लिए, पुस्तकालय नियमित रूप से विभिन्न बुलेटिन जैसे “निवर्तमान के अतिरिक्त” और “विदेशी मामलों के दस्तावेज बुलेटिन” जारी करता है। इसके अतिरिक्त, पुस्तकालय कई ऑनलाइन डेटाबेस / सेवाओं तक अभिगम्यता प्रदान करता है। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के उपयोग के लिए लाइब्रेरी फाइनेंशियल टाइम्स (ft.com), वॉल स्ट्रीट जर्नल (wsj.com) और इंटरनेशनल न्यूयॉर्क टाइम्स (nyt.com) की समूह सदस्यता भी है।

विदेश मंत्रालय पुस्तकालय में दुर्लभ पुस्तकों का उत्तम संग्रह है। चयनित दुर्लभ पुस्तकों की एक सूची बनाए रखी जाती है और इन दुर्लभ पुस्तकों को जवाहर लाल नेहरू भवन में एक अलग दुर्लभ पुस्तकालय में रखा जाता है।

पुस्तकालय ने 1947 से 2017 तक "भारत की द्विपक्षीय संधियों और समझौतों को संयुक्त घोषणाओं और सम्प्रेशनो " को पुनः प्रकाशित करने के लिए एक परियोजना पूरी की है और यह 18 संस्करणों में प्रकाशित हुई है ।

विदेश मंत्रालय पुस्तकालय ने वित्त मंत्रालय के आदेशों के अनुसार श्रेणी IV से श्रेणी V पुस्तकालयों के लिए पुन: वर्गीकरण के लिए प्रवासी भारतीय केंद्र पुस्तकालय हेतु अध्ययन किया है और वर्ष के दौरान इसे श्रेणी III पुस्तकालय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

विदेश मंत्रालय पुस्तकालय, समय-समय पर दिल्ली के विभिन्न संस्थानों में अध्ययनरत पुस्तकालय विज्ञान के छात्रों / पेशेवरों को व्यावहारिक प्रशिक्षण / इंटर्नशिप प्रदान करता है। यह पुस्तकालय, भारतीय पुस्तकालय एसोसिएशन (आई एल ए), भारतीय विशेष पुस्तकालय और आसूचना केंद्र एसोसिएशन (आई ए एस एल आई सी), केंद्रीय सरकार पुस्तकालय एसोसिएशन (सी जी एल ए), अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय एसोसिएशंस और संस्थान फेडरेशन (आई एफ एल ए) और `विशेष पुस्तकालय एसोसिएशन (एस एल ए) का संस्थागत सदस्य है। निदेशक (पुस्तकालय और आसूचना) और अन्य अधिकारी नियमित रूप से आई एल ए, आई ए एस एल आई सी , सी जी एल ए , आई एफ एल ए और एस एल ए की वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों / संगोष्ठियों / बैठकों में भाग लेते हैं। 2017-2019 की अवधि के लिए निदेशक (पुस्तकालय और आसूचना) को आई एफ एल ए- सरकारी पुस्तकालयों अनुभाग की स्थायी समिति का सदस्य चुना गया है। 2017-2019 की अवधि के लिए एल ए आई ओ को आई एफ एल ए-आर एस सी ए ओ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और 2015-17 के लिए आई एफ एल ए-सरकारी सूचना और आधिकारिक प्रकाशन अनुभाग की स्थायी समिति सदस्य हैं । विशेष निमंत्रण पर, श्री संजय कुमार बिहानी, एल ए आई ओ ने मार्च 2018 के दौरान बार्सिलोना, स्पेन में आयोजित आई एफ एल ए अध्यक्षीय बैठक और वैश्विक दृष्टि कार्यशाला में भाग लिया और मई 2018 में लेबनान के बेरूत में लेबनानी पुस्तकालय एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस 2018 में भाग लिया।

अभिलेखागार

मंत्रालय का अभिलेखागार और अभिलेख प्रबंधन प्रभाग, अभिलेखागार और अभिलेख प्रबंधन से संबंधित सभी मामलों से संबंधित है। अभिलेख प्रबंधन सॉफ्टवेयर (आरईएम) का उन्नयन, मौजूदा सॉफ्टवेयर का प्रतिस्थापन और मौजूदा सर्वर को दो नए सर्वरों के साथ-साथ पुराने डेस्कटॉप जो रिकॉर्ड प्रबंधन सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटा तक पहुंचने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं, को ई-शासन और सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है । नए सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड को स्कैन / डिजिटलीकरण करने के प्रावधान के साथ, मौजूदा डेटा को पुराने सॉफ़्टवेयर से नए सॉफ़्टवेयर में स्थानांतरित किया जा सकता है।

इस प्रभाग ने नवंबर 2018 तक, नष्ट करने की स्वीकृति प्राप्त होने पर 2256 पुराने अभिलेख / रजिस्टर / पुस्तके नष्ट कर दी है । सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम और नियम 1993/1997 के अंतर्गत उचित मूल्यांकन के बाद पच्चीस वर्ष से अधिक पुराने गैर-वर्तमान सार्वजनिक अभिलेख / पच्चीस वर्ष से अधिक पुरानी फाइलों को संरक्षण और स्थायी अभिरक्षा के लिए भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थानांतरित कर दिया गया था।

35

वित्त और बजट

विदेश मंत्रालय का वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमान स्तर पर आबंटित कुल बजट रुपए 15011.00 करोड़ था।

2. प्रमुख आबंटन के लिए बजट का क्षेत्रीय वितरण इस प्रकार था :

क्षेत्रीय		आबंटन (करोड़ रुपए में)
विदेशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	अनुदान	5398.55
	ऋण	836.50
	कुल तकनीकी और आर्थिक सहयोग	**6235.05**
विदेशों में भारतीय मिशन और पोस्ट		2701.00
विशेष राजनयिक व्यय		2400.01
पासपोर्ट और उत्प्रवासन		1058.75
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अंशदान		912.10
लोक निर्माण और आवास पर पूंजीगत परिव्यय		550.00
विदेश मंत्रालय सचिवालय		440.64

संस्थानों को सहायता-अनुदान	288.27
अन्य	425.18
वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कुल बजट अनुमान	**15011.00**

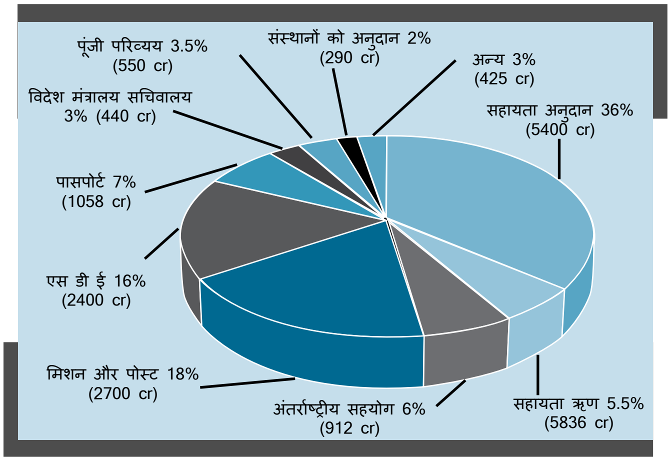

3. मंत्रालय के बजट में सबसे बड़ा आबंटन विदेशों में अनुदान और ऋण के रूप में सहायता के जरिए तकनीकी और आर्थिक सहयोग (टीईसी) के लिए था। वित्त वर्ष 2018-19 में, कुल बजट रुपए 15011 करोड़, तकनीकी और आर्थिक सहयोग परिव्यय 41.53% या रुपए 6235.05 करोड़ था, जिसमें से रुपए 5398.55 करोड़ (35.96%) अनुदान कार्यक्रमों के लिए थे और रुपए 36 836.50 करोड़ (5.57%) ऋण के लिए था। वित्त वर्ष 2018-19 में तकनीकी और आर्थिक सहयोग परिव्यय का शीर्ष-वार वितरण निम्नानुसार था :

तकनीकी और आर्थिक सहयोग शीर्ष		आबंटन (करोड़ रुपए में)	कुल तकनीकी और आर्थिक सहयोग का प्रतिशत
भूटान	अनुदान	1813.50	42.50 %
	ऋण	836.50	
	कुल भूटान	**2650.00**	
नेपाल		650.00	10.42 %
मॉरिशस		525.00	8.42 %
अफ़ग़ानिस्तान		400.00	6.42 %
सेशेल्स		300.00	4.81 %
म्यांमार		280.00	4.49 %
आई टी ई सी कार्यक्रम		280.00	4.49 %
अफ्रीकी देश		200.00	3.21 %
बांग्लादेश		175.00	2.81 %
श्री लंका		150.00	2.41 %
चाहबहार बंदरगाह , ईरान		150.00	2.41 %
मालदीव्स		125.00	2.00 %
अन्य विकासशील देश		115.00	1.84 %
निवेश प्रचार और संवर्धन कार्यक्रम		75.00	1.2 %
आसियान बहु-पक्षीय कार्यक्रम		45.00	0.72 %
यूरेशियन देश		30.00	0.48 %
बहु-पक्षीय आर्थिक संबंध कार्यक्रम		30.00	0.48 %
लातिन अमरीकी देश		20.00	0.32 %
आपदा राहत		20.00	0.32 %
सार्क कार्यक्रम		10.00	0.16 %
मंगोलिया		5.00	0.08 %
ऊर्जा संरक्षा		0.05	-
कुल		**6235.05**	

4. मंत्रालय के बजट में दूसरा सबसे बड़ा आवंटन विदेशों में 180 से अधिक भारतीय राजनयिक मिशनों और पोस्ट के रखरखाव के लिए था। वित्त वर्ष 2018-19 में, सभी मिशनों और पोस्ट के लिए कुल आवंटन 18% अथवा रुपए 2,701 करोड़ था, जिसका शीर्ष-वार वितरण निम्नानुसार था :

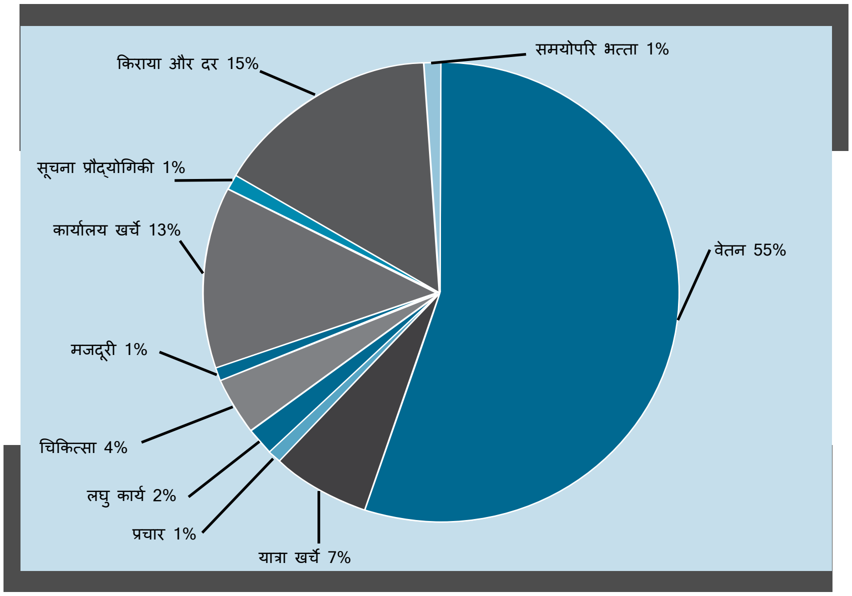

5. वित्तीय वर्ष 2018-19 के रुपए 15011 करोड़ के कुल बजट में से स्थापना शीर्ष और गैर-स्थापना शीर्ष में आबंटन का विभाजन क्रमश 28% (रुपए 4,223 करोड़) और 72% (रुपए 10,788 करोड़) था

6. स्थापना और गैर-स्थापना परिव्यय के क्षेत्रीय वितरण निम्मानुसार था :

वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना परिव्यय रुपए 4223 करोड़

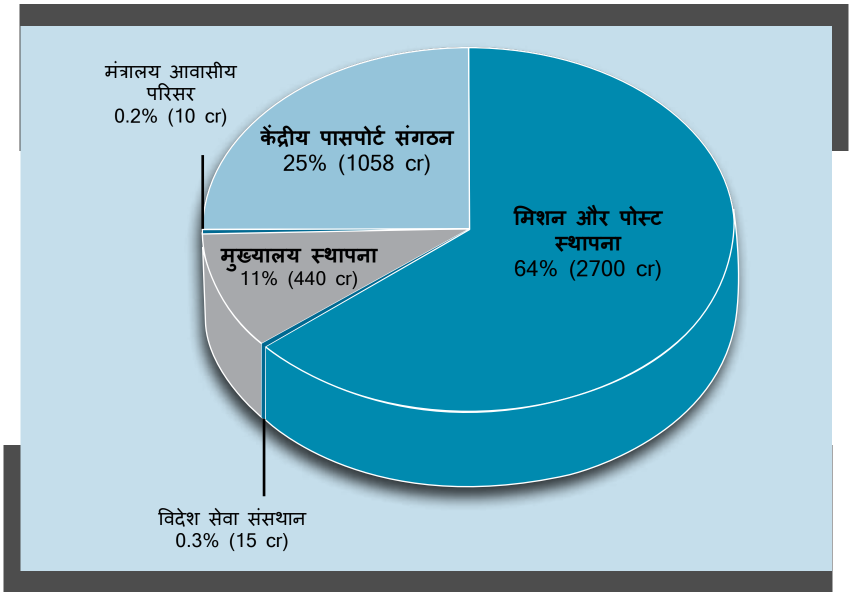

गैर-स्थापना परिव्यय-रुपये 10788 करोड़ : वित्त वर्ष 2018-19 में वितरण

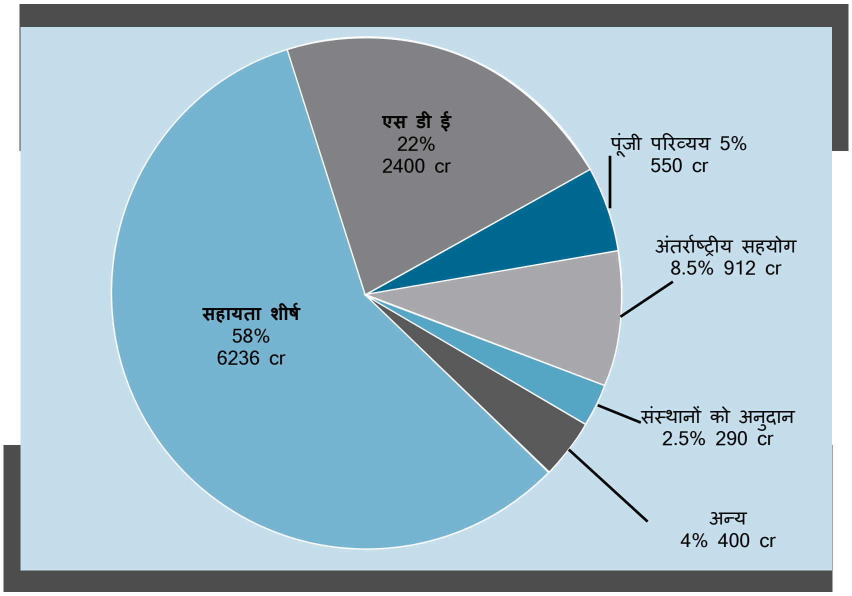

7. मंत्रालय ने स्थापना शीर्षों पर अपना व्यय कुल बजट का 30 % बनाए रखा है, जैसा कि पिछले छह वित्तीय वर्षों के लिए नीचे दर्शाया गया है :

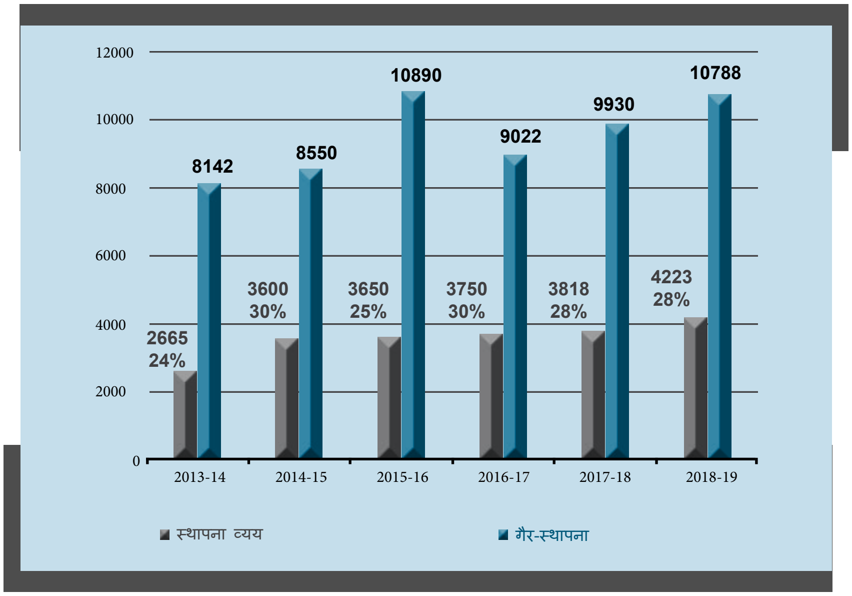

8. मंत्रालय ने अपने आवंटित बजट का व्यय स्थिर बनाए रखा है, जैसा कि पांच वित्तीय वर्षों के पहली तिमाही और दूसरी तिमाही के निधि उपयोग स्वरूप में नीचे दर्शाया गया है :

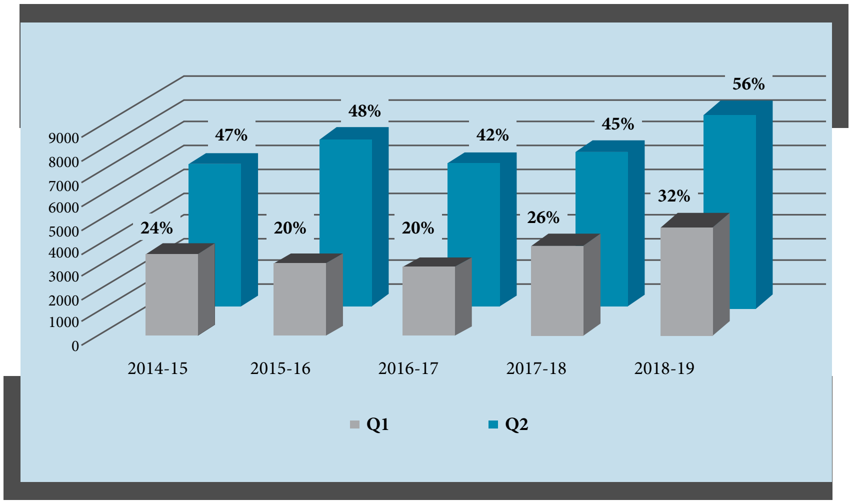

9. मंत्रालय वित्तीय वर्ष के पुनरीक्षित अनुमान चरण में अपनी आबंटित निधियों का अधिकतम उपयोग करता रहा है जैसा की पिछले दस वित्त वर्ष के लिए नीचे दर्शाया गया है :

वित्त वर्ष	बजट अनुमान आबंटन	पुनरीक्षित अनुमान आबंटन	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान के % के रूप में उपयोगिता	पुनरीक्षित अनुमान के % के रूप में उपयोगिता
	करोड़ रुपए में; पूर्णांकित				
2008-09	5062	6868	6746	133 %	98 %
2009-10	6293	6333	6291	100 %	99 %
2010-11	6375	7120	7154	112 %	100 %
2011-12	7106	7836	7873	111 %	100 %
2012-13	9662	10062	10121	105 %	100 %
2013-14	11719	11794	11807	101 %	100 %
2014-15	14730	12620	12149	82 %	96 %
2015-16	14967	14967	14541	97 %	97 %
2016-17	14663	13426	12772	87 %	95 %
2017-18	14798	13690	13747	93 %	100 %
2018-19	**15011**	**15582**	**11362 (30 सितंबर 2018 अथवा तीसरी तमिाही के अंत तक**	**Average BE Utilization: 102 %**	**Average RE Utilization: 98.5 %**

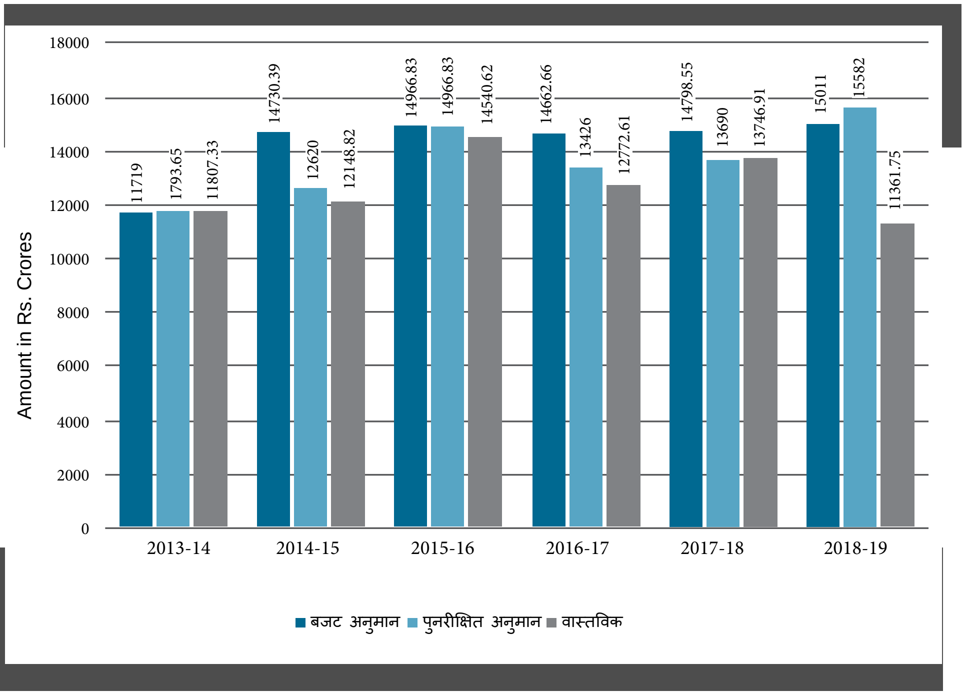

10. मंत्रालय को वित्त वर्ष 2018-19 में, 31 दिसंबर 2018 में रुपये 4280.11 करोड़ का राजस्व, पासपोर्ट सेवाओं से (रुपये 1957.64 करोड़), वीज़ा शुल्क (रुपये 1,823.08 करोड़) और अन्य प्राप्तियों (रुपये 499.39

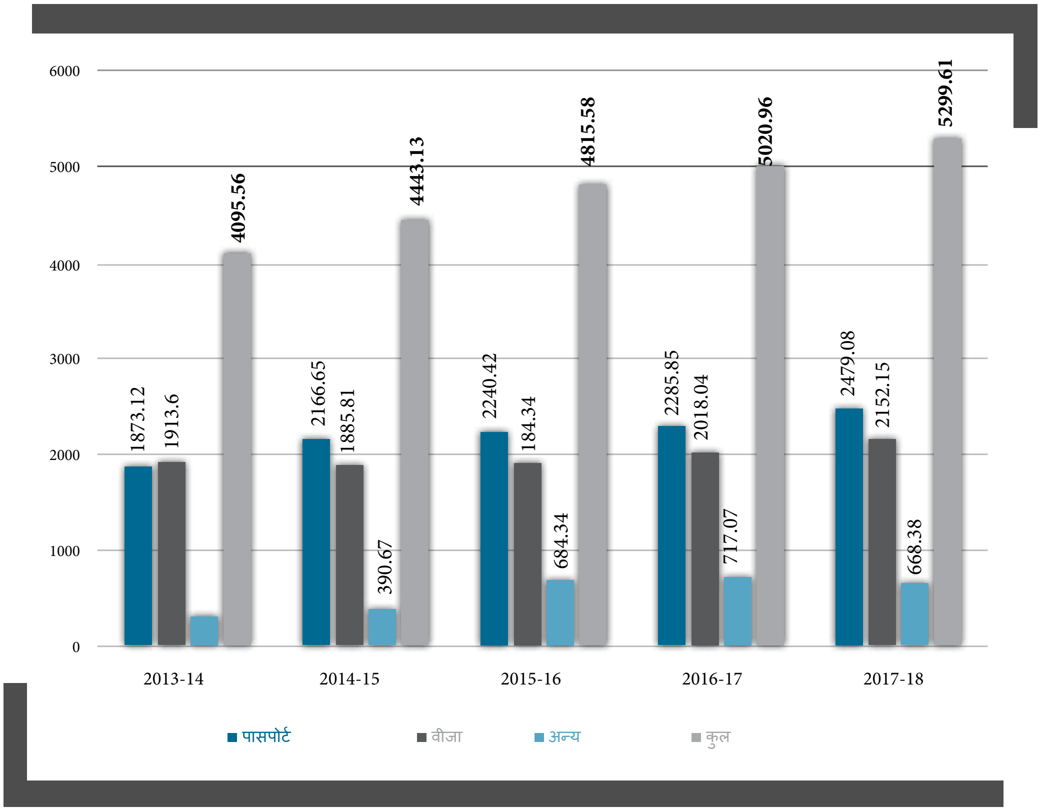

करोड़) प्राप्त हुआ । पिछले पांच वित्तीय वर्षो, वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2017-18 तक की राजस्व प्राप्तियां निम्नानुसार दर्शित हैं :

11. मंत्रालय में जुलाई 2015 में, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की विभिन्न रिपोर्टों से चौदह पैरा लंबित थे। मार्च 2017 तक, सभी चौदह पैरा का निपटान किया गया और कोई पैरा लंबित नहीं था । तब से, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की दो रिपोर्टों (2017 की संख्या 12 और 2018 की संख्या 4) में मंत्रालय से संबंधित पैरा हैं। इन दो रिपोर्टों में मंत्रालय से संबंधित कुल नौ पैरा में से चार पैरा 2017 की रिपोर्ट संख्या 12 में थे और पांच पैरा 2018 की रिपोर्ट संख्या 4 में थे। इन नौ पैरा पर अंतिम कृत कार्रवाई टिप्पणी प्रस्तुत करने की स्थिति नीचे दी गई है :

वर्ष	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	कुल पैरा की संख्या	अंतिम कृत कार्रवाई टिप्पणी प्रस्तुत	अंतिम कृत कार्रवाई टिप्पणी प्रस्तुत- प्रगति में
2017	रिपोर्ट संख्या 2017 का 12	**4**	**3**	**1**
2018	रिपोर्ट संख्या 2018 का 4	**5**	**2**	**3**
कुल		9	5	4

12. इन नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक रिपोर्ट के पैरो का ब्यौरा और स्थिति नीचे दी गई है :

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक रिपोर्ट संख्या	पैरा संख्या	विषय	स्थिति
2017 का 12	**9.1**	ई ओ आई ब्रासिलिअ में परिहार्य किराया व्यय	अंतिम कृत कार्रवाई टिप्पणी प्रस्तुत लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार्य - पैरा का निपटान हो गया
	9.2	सी जी आई सैन फ्रांसिस्को में आंतरिक नियंत्रण की कमी	अंतिम कृत कार्रवाई टिप्पणी प्रस्तुत लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार्य - पैरा का निपटान हो गया
	9.3	ई ओ आई टोक्यो में सरकारी लेखे के बाह्य पावतियाँ और व्यय	अंतिम कृत कार्रवाई टिप्पणी- प्रगति में
	9.4	नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना और कार्यात्मकता	अंतिम कृत कार्रवाई टिप्पणी प्रस्तुत लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार्य - पैरा का निपटान हो गया

2018 का 4	**7.1**	साउथ एशियाई विश्वविद्यालय के लिए कैंपस का निर्माण	नवंबर 2018 में अंतिम कृत कार्रवाई टिप्पणी प्रस्तुत
	7.2	मिशन और पोस्ट में कांसुलर सेवाओं में राजस्व की हानि	मई 2018 में मसौदा कृत कार्रवाई टिप्पणी प्रस्तुत संशोधित कृत कार्रवाई टिप्पणी नवंबर 2018 में प्रस्तुत लेखापरीक्षा की संवीक्षा टिप्पणी की प्रतीक्षा है
	7.3	संपत्ति प्रबंधन में लागत वृद्धि और परिहार्य व्यय	अंतिम कृत कार्रवाई टिप्पणी प्रस्तुत लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार्य - पैरा का निपटान हो गया
	7.4	अमेरिका में आउटसोर्स सेवा प्रदाता द्वारा अति प्रभारित कूरियर शुल्क	जून 2018 में मसौदा कृत कार्रवाई टिप्पणी प्रस्तुत संशोधित कृत कार्रवाई टिप्पणी नवंबर 2018 में प्रस्तुत लेखापरीक्षा की संवीक्षा टिप्पणी की प्रतीक्षा है
	7.5	सी जी आई के वैंकोवर, हॉस्टन, सैन फ्रांसिस्को में आकस्मिक नियुक्त कर्मचारी	जून 2018 में मसौदा कृत कार्रवाई टिप्पणी प्रस्तुत संशोधित कृत कार्रवाई टिप्पणी अक्टूबर 2018 में प्रस्तुत लेखापरीक्षा की संवीक्षा टिप्पणी की प्रतीक्षा है

परिशिष्ट

परिशिष्ट I	2018 की द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय और बहुपक्षीय संधियों /करारों की सूची	418
परिशिष्ट II	2018 में अनुसमर्थनों की सूची	449
परिशिष्ट III	2018 में जारी किए गए पूर्ण शक्तियों के दस्तावेज़ों की सूची	457
परिशिष्ट IV	नीति आयोजना और अनुसंधान प्रभाग द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से वित्त पोषित संगोष्ठियां, सम्मेलन, आदि	459
परिशिष्ट V	मंत्रालय की वर्तमान स्वीकृत कार्मिक संख्या	461
परिशिष्ट VI	डीआर, डीपी और एलडीई मोड के माध्यम से भर्ती संबंधी डेटा	463
परिशिष्ट VII	विभिन्न भाषाओं में प्रवीणता वाले भारतीय विदेश सेवा अधिकारियों की संख्या	463
परिशिष्ट VIII	पासपोर्ट केंद्रों की राज्य-वार सूची	465
परिशिष्ट IX	कार्यशील डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीओपीएसके) की सूची	467

परिशिष्ट I

क: बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन/करार/संधि

	शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	देश	मंत्रालय
1	बिम्सटेक ग्रिड इंटरकनेक्शन की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन	31-08-2018	**बिम्सटेक**	विदेश मंत्रालय
2	पर्यावरणीय सहयोग पर समझौता ज्ञापन	27-07-2018	**ब्रिक्स**	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
3	क्षेत्रीय उड्डयन भागीदारी पर समझौता ज्ञापन	27-07-2018	**ब्रिक्स**	नागर विमानन मंत्रालय
4	डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर एवं ब्लॉक चेन टेक्नॉलोजी पर सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन	26-07-2018	**ब्रिक्स**	वित्त मंत्रालय
5	आईबीएसए फंड करार	17-10-2017	**ब्रिक्स**	विदेश मंत्रालय
6	सामाजिक और श्रम क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	03-08-2018	**ब्रिक्स**	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
7	बाहय अर्थव्यवस्था और विदेश व्यापार के लिए उत्तरदायी एससीओ सदस्य राष्ट्रों के मंत्रालयों के बीच सूक्ष्म, लघु और मध्यम प्रकार के व्यवसायों के क्षेत्र में एससीओ के अंतर्गत सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन।	10-06-2018	**एससीओ**	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
8	ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों के सीमा पार आवाजाही संबंधी सूचना के आदान-प्रदान के लिए एससीओ सदस्यों की सीमा शुल्क सेवाओं के मध्य समझौता ज्ञापन	10-06-2018	**एससीओ**	वित्त मंत्रालय
9	सीमा पार एपीजूटिक रोगों के विरुद्ध संयुक्त रोकथाम और इन्हें समाप्त करने में तकनीकी सहायता पर एससीओ सदस्य राष्ट्रों के प्राधिकृत विभागों के बीच समझौता ज्ञापन	12-10-2018	**एससीओ**	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
10	बांग्लादेश में रूप्पुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना के कार्यान्वयन में त्रिपक्षीय सहयोग पर भारत, रूस और बांग्लादेश के बीच समझौता ज्ञापन	01-03-2018	**त्रिपक्षीय**	परमाणु ऊर्जा विभाग

	शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	देश	मंत्रालय
11.	नेपाल के गोरखा जिले में भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त 26,912 भूकंप-प्रभावित आवास लाभग्राहियों को सामाजिक-तकनीकी सुविधा प्रदान करने के लिए भारत और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के बीच साझेदारी करार	08-03-2018	**संयुक्त राष्ट्र**	विदेश मंत्रालय
12.	"हिंदी परियोजना" के लिए संयुक्त राष्ट्र के लोक सूचना विभाग और भारत सरकार के बीच स्वैच्छिक वित्तीय अंशदान करार	08-03-2018	**संयुक्त राष्ट्र**	विदेश मंत्रालय
13.	डब्ल्यूआईपीओ निष्पादन एवं फोनोग्राम संधि, 1996	17-08-2018	**डब्ल्यूआईपीओ**	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
14.	डब्ल्यूआईपीओ कॉपीराइट संधि, 1996	17-08-2018	**डब्ल्यूआईपीओ**	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

ख: द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन/करार/संधि

	शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	देश	मंत्रालय
1	भारत और अल्जीरिया के बीच विकास के लिए अंतरिक्ष, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	19-09-2018	**अल्जीरिया**	अंतरिक्ष विभाग
2	भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अक्षमता क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	22-11-2018	**ऑस्ट्रेलिया**	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
3	सीसीआरएच और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन लिमिटेड, ऑस्ट्रेलिया के बीच होम्योपैथी में अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	10-05-2018	**ऑस्ट्रेलिया**	आयुष मंत्रालय
4	अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), आयुष मंत्रालय और मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ़ ग्राज़, ग्राज़ के बीच समझौता ज्ञापन	26-09-2018	**ऑस्ट्रेलिया**	आयुष मंत्रालय
5	राजनयिक, सरकारी और सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा अपेक्षाओं से छूट पर भारत और अज़रबैजान के बीच करार	07-04-2018	**अज़रबैजान**	विदेश मंत्रालय

	शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	देश	मंत्रालय
6	भारत और अज़रबैजान के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन	07-04-2018	**अज़रबैजान**	विदेश मंत्रालय
7	विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय और एडीए विश्वविद्यालय, अज़रबैजान गणराज्य के विदेश मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन	04-04-2018	**अज़रबैजान**	विदेश मंत्रालय
8	भारत और अज़रबैजान के बीच वर्ष 2019-2023 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	12-10-2018	**अज़रबैजान**	संस्कृति मंत्रालय
9	राजनयिक और विशेष/सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा अपेक्षाओं से छूट पर भारत और बहरीन के बीच करार	15-07-2018	**बहरीन**	विदेश मंत्रालय
10	भारत गणराज्य सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और बहरीन साम्राज्य सरकार के विद्युत् और जल प्राधिकरण मंत्रालय के बीच नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	15-07-2018	**बहरीन**	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
11	भारत गणराज्य सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और बहरीन साम्राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच स्वास्थ्य देख-भाल में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	15-07-2018	**बहरीन**	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
12	भारत और बांग्लादेश के बीच सिलीगुड़ी (भारत में) और पर्बतीपुर (बांग्लादेश में) भारत -बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के निर्माण पर समझौता ज्ञापन	09-04-018	**बांग्लादेश**	विदेश मंत्रालय
13	परिशिष्ट 1 वैश्विक परमाणु ऊर्जा साझेदारी केंद्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत और बांग्लादेश परमाणु ऊर्जा आयोग के बीच बांग्लादेश में परमाणु विद्युत् संयंत्र परियोजनाओं के सम्बन्ध में सहयोग पर अंतर-एजेंसी करार	09-04-018	**बांग्लादेश**	परमाणु ऊर्जा विभाग
14	प्रसार भारती और बांग्लादेश बेतार के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन	09-04-2018	**बांग्लादेश**	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
15	एच सी आई, बांग्लादेश और बांग्लादेश वित्त मंत्रालय और रंगपुर सिटी कारपोरेशन के बीच राणपुर सिटी कारपोरेशन के अंतर्गत विभिन्न सड़कों के पुनर्वास और सुधार के लिए समझौता ज्ञापन	09-04-2018	**बांग्लादेश**	विदेश मंत्रालय

	शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	देश	मंत्रालय
16	भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग, राज्य परमाणु ऊर्जा निगम "रोसाटॉम" (रूसी संघ) और बांग्लादेश के बीच बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना के कार्यान्वयन में त्रिपक्षीय सहयोग पर समझौता ज्ञापन।	01-03-2018	**बांग्लादेश**	परमाणु ऊर्जा विभाग
17	भारत और बांग्लादेश के बीच संशोधित यात्रा व्यवस्था	15-07-2018	**बांग्लादेश**	गृह मंत्रालय
18	भारतीय सेना और बांग्लादेश सेना के बीच शैक्षणिक विनिमय और सहयोग पर समझौता ज्ञापन	08-05-2018	**बांग्लादेश**	रक्षा मंत्रालय
19	भारत और बांग्लादेश के बीच 48 डिग्री ई पर प्रस्तावित साउथ एशिया सेटेलाइट के ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी समन्वय से संबंधित करार में संशोधन	03-10-2018	**बांग्लादेश**	अंतरिक्ष विभाग
20	भारत में और भारत से सामन के आवागमन के लिए चट्टोग्राम और मोंगला बंदरगाह के प्रयोग पर भारत और बांग्लादेश के बीच करार	25-10-2018	**बांग्लादेश**	पोत परिवहन मंत्रालय
21	अन्तर्देशीय जल पारवहन और भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापर पर प्रोटोकॉल के परिशिष्ट पर 6 जून, 2015 को हस्ताक्षर किए गए	25-10-2018	**बांग्लादेश**	पोत परिवहन मंत्रालय
22	भारत और बांग्लादेश के बीच तटीय और प्रोटोकॉल मार्ग पर यात्री और क्रूज सेवाओं पर समझौता ज्ञापन का एस ओ पी	25-10-2018	**बांग्लादेश**	पोत परिवहन मंत्रालय
23	सीसीआरएम और हमदर्द विश्वविद्यालय, बांग्लादेश के बीच यूनानी चेयर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन	10-02-2018	**बांग्लादेश**	आयुष मंत्रालय
24	भारतीय उच्चायुक्त, ढाका और चांदपुर अयाचक आश्रम, पूरन अदालतपरा, चांदपुर, बांग्लादेश में पांच मंजिले छात्रावास के निर्माण के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता ज्ञापन	29-07-2018	**बांग्लादेश**	विदेश मंत्रालय
25	सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद और बांग्लादेश पुलिस अकादमी, सरदह, राजशाही के बीच क्षमता निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन	09-04-2018	**बांग्लादेश**	विदेश मंत्रालय

	शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	देश	मंत्रालय
26	भारत और बांग्लादेश के बीच संशोधित यात्रा व्यवस्था, 2018	15-07-2018	**बांग्लादेश**	गृह मंत्रालय
27	भारत और बेलारूस के बीच संसदीय सहयोग के लिए व्यवस्था	11-06-2018	**बेलारूस**	लोक सभा
28	भारत और बोत्सवाना के बीच राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा अपेक्षाओं से छूट पर समझौता ज्ञापन	01-11-2018	**बोत्सवाना**	विदेश मंत्रालय
29	भारत और ब्रूनेई दारुस्सलम के बीच सैटेलाइट और लांच वाहनों के लिए टेलीमेट्री ट्रैकिंग और टेलेकमाण्ड के प्रचलन में सहयोग और अंतरिक्ष अनुसन्धान, विज्ञान और अनुप्रयोग के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	19-07-2018	**ब्रूनेई दारुस्सलम**	अंतरिक्ष विभाग
30	भारत और बुल्गारिया के बीच पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	05-09-2018	**बुल्गारिया**	पर्यटन मंत्रालय
31	भारत और बुल्गारिया के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग कार्यक्रम	05-09-2018	**बुल्गारिया**	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
32	भारत और बुल्गारिया के बीच 2018-2020 की अवधि के सहयोग कार्यक्रम	15-03-2018	**बुल्गारिया**	संस्कृति मंत्रालय
33	इन्वेस्ट बुल्गारिया एजेंसी और इन्वेस्ट इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन	05-09-2018	**बुल्गारिया**	वित्त मंत्रालय
34	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और सोफिया विश्वविद्यालय सेंट क्लेमेंट ओह्डिस्की के बीच हिंदी भाषा के लिए आईसीसीआर चेयर की स्थापना पर समझौता ज्ञापन	05-09-2018	**बुल्गारिया**	विदेश मंत्रालय
35	मानव तस्करी, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की तस्करी की रोकथाम; छुटकारे, बहाली, प्रत्यापर्पण और तस्करी के शिकारों के पुनः-एकीकरण पर सहयोग में भारत और कंबोडिया के बीच समझौता ज्ञापन	27-01-2018	**कंबोडिया**	गृह मंत्रालय
36	भारत और कंबोडिया के बीच वर्ष 2018-2022 के लिए सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम	27-01-2018	**कंबोडिया**	संस्कृति मंत्रालय
37	आपराधिक मामले में परस्पर विधिक सहायता पर भारत और कंबोडिया के बीच संधि	27-01-2018	**कंबोडिया**	गृह मंत्रालय

	शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	देश	मंत्रालय
38	भारत और कंबोडिया के बीच प्राह विहार मंदिर, कंबोडिया के संरक्षण-मरम्मत पर समझौता ज्ञापन	29-08-2018	**कंबोडिया**	संस्कृति मंत्रालय
39	विदेश सेवा संसथान, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली और राष्ट्रीय राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध संस्थान, कंबोडिया के बीच समझौता ज्ञापन	29-08-2018	**कंबोडिया**	विदेश मंत्रालय
40	भारत और कनाडा के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग मुद्दों पर समझौता ज्ञापन	23-02-2018	**कनाडा**	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
41	भारत और कनाडा के बीच उच्च शिक्षा में सहयोग मुद्दों पर समझौता ज्ञापन	23-02-2018	**कनाडा**	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
42	भारत और कनाडा के बीच निवेश संवर्धन और सुविधा पर समझौता ज्ञापन	23-02-2018	**कनाडा**	वित्त मंत्रालय
43	भारत और कनाडा के बीच खेलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	22-02-2018	**कनाडा**	युवा और खेल मंत्रालय
44	सूचना संचार प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और कनाडा में बीच मंशा की संयुक्त घोषणा	23-01-2018	**कनाडा**	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
45	भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नवाचार विभाग, कनाडा के विज्ञान और आर्थिक विकास के बीच सूचना संचार प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में सहयोग पर मंशा की संयुक्त घोषणा	23-02-2018	**कनाडा**	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
46	औद्योगिक नीति विभाग और संवर्धन, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत और कैनेडियन बौद्धिक सम्पदा कार्यालय के बीचबौद्धिक सम्पदा अधिकारों के सम्बन्ध में समझौता ज्ञापन	23-02-2018	**कनाडा**	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
47	भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और कनाडा के प्राकृतिक संसाधन विभाग के बीच भारत -कनाडा मंत्रालयी ऊर्जा वार्ता के सन्दर्भ की शर्ते	23-02-2018	**कनाडा**	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
48	भारत और चिली के बीच उच्च स्तरीय संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन	23-05-2018	**चिली**	विदेश मंत्रालय

	शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	देश	मंत्रालय
49	भारत और होंगकोंग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ़ चीन के बीच दोहरे कराधान को हटाने और आय पर करों के सम्बन्ध में राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए करार	19-03-2018	**चीन**	वित्त मंत्रालय
50	भारत और होंगकोंग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ़ चीन के बीच दोहरे कराधान को हटाने और आय पर करों के सम्बन्ध में राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए करार (प्रोटोकॉल)	26-11-2018	**चीन**	वित्त मंत्रालय
51	भारत सरकार और लोकतांत्रिक चीन सरकार के बीच दोहरे कराधान को हटाने और आय के सम्बन्ध में राजकोषीय चोरी की रोकथाम पर करार और नई दिल्ली में 18 जुलाई, 1994 को हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल को संशोधित करने वाला प्रोटोकॉल	26-11-2018	**चीन**	वित्त मंत्रालय
52	भारत और कोलंबिया के बीच पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	04-10-2018	**कोलंबिया**	पर्यटन मंत्रालय
53	भारत और कोलंबिया के बीच निवेश और संवर्धन और संरक्षण के समझौते के संबंध में भारत और कोलंबिया के बीच संयुक्त व्याख्यात्मक घोषणा, 10 नवंबर 2009 को हस्ताक्षरित	04-10-2018	**कोलंबिया**	वित्त मंत्रालय
54	भारत और कोटे डि'वायर के बीच कोटे डी'वाइर में ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन	28-02-2018	**कोटे डी'वोइरे**	विदेश मंत्रालय
55	भारत और कोटे डी'वायर के बीच संस्कृति और कला के क्षेत्र में सहयोग पर करार	28-02-2018	**कोटे डी'वोइरे**	संस्कृति मंत्रालय
56	चिकित्सा और होम्योपैथी के पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्र में भारत और क्यूबा के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन	22-06-2018	**क्यूबा**	आयुष मंत्रालय
57	जैव प्रौद्योगिकीय क्षेत्र में सहयोग पर भारत और क्यूबा के बीच समझौता ज्ञापन	22-06-2018	**क्यूबा**	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

	शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	देश	मंत्रालय
58	भारत और सायप्रस के बीच मनी लॉन्ड्रिंग, संबंधित अपराध और आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित वित्तीय खूफिया जानकारी के आदान-प्रदान में सहयोग और सहमति पर समझौता ज्ञापन	03-09-2018	**सायप्रस**	वित्त मंत्रालय
59	भारत और सायप्रस के बीच पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	03-09-2018	**सायप्रस**	पर्यावरण मंत्रालय
60	भारत और चेक गणराज्य के बीच राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकताओं से छूट पर करार	07-09-2018	**चेक**	विदेश मंत्रालय
61	वर्ष 2019-2022 के लिए भारतीय-चेक संयुक्त परियोजनाओं के समर्थन के लिए कार्य योजना	07-09-2018	**चेक**	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
62	आर्थिक सहयोग पर संयुक्त आयोग के ग्यारहवें सत्र का प्रोटोकॉल	23-10-18	**चेक गणराज्य**	वाणिज्य विभाग
63	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारत और चेक गणराज्य विज्ञान अकादमी, चेक गणराज्य के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग पर समझौता ज्ञापन	07-09-2018	**चेक गणराज्य**	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
64	इन्वेस्ट इंडिया और चेक इन्वेस्ट के बीच समझौता ज्ञापन	23-10-2018	**चेक गणराज्य**	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
65	भारत और डेनमार्क के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर करार	22-05-2018	**डेनमार्क**	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
66	भारत और डेनमार्क के बीच कृषि अनुसंधान और शिक्षा में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	16-04-2018	**डेनमार्क**	कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय
67	भारत और डेनमार्क के बीच सतत और स्मार्ट शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	16-04-2018	**डेनमार्क**	आवास और शहरी मामले मंत्रालय
68	भारत और डेनमार्क के बीच पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	16-04-2018	**डेनमार्क**	कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय
69	भारत और डेनमार्क के बीच खाद्य सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन	16-04-2018	**डेनमार्क**	उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण

	शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	देश	मंत्रालय
70	भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और जिबोटी गणराज्य के विदेश मंत्रालय के बीच परामर्श पर समझौता ज्ञापन	04-10-2018	**जिबोटी**	विदेश मंत्रालय
71	भारत के आयुष मंत्रालय और इक्वेटोरियल गिनी सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच पारंपरिक प्रणालियों के चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।	08-04-2018	**इक्वेटोरियल गिनी**	आयुष मंत्रालय
72	भारत और इरीट्रिया के बीच परामर्श पर समझौता ज्ञापन	20-04-2018	**इरीट्रिया**	विदेश मंत्रालय
73	भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और इरीट्रिया राष्ट्र के विदेश मंत्रालय के बीच परामर्श पर समझौता ज्ञापन	20-04-2018	**इरीट्रिया**	विदेश मंत्रालय
74	भारत और इथियोपिया के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन	09-05-2018	**इथियोपिया**	विदेश मंत्रालय
75	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और बिज़नेस ऑफ़ फिनलैंड के बीच जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन 30 नवंबर 2018 को हस्ताक्षरित किया गया	30-11-2018	**फ़िनलैंड**	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग
76	ऐतिहासिक अलंकृत गुफाओं और रॉक पार्सल के संरक्षण के क्षेत्र में एक इंडो-फ्रेंच सहयोग के लिए आशय पत्र	18-06-2018	**फ्रांस**	संस्कृति मंत्रालय
77	भारत और फ्रांस के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग पर करार	10-03-2018	**फ्रांस**	आवास और शहरी मामले मंत्रालय
78	भारत और फ्रांस के बीच रेलवे के तकनीकी क्षेत्र में सहयोग पर आशय पत्र	10-03-2018	**फ्रांस**	रेल मंत्रालय
79	भारत और फ्रांस के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन	10-03-2018	**फ्रांस**	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
80	भारत और फ्रांस के बीच शैक्षणिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता सुविधा देने के लिए करार	10-03-2018	**फ्रांस**	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
81	भारत और फ्रांस के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन	10-03-2018	**फ्रांस**	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

	शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	देश	मंत्रालय
82	भारत और फ्रांस के बीच नारकोटिक्स ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक पदार्थों और रासायनिक एस्कॉर्स और संबंधित अपराधों में गैरकानूनी आवागमन और खपत में कमी को रोकने के लिए करार	10-03-2018	**फ्रांस**	गृह मंत्रालय
83	भारत और फ्रांस के बीच एक समुद्री क्षेत्र में जागरूकता मिशन के पूर्व गठन के अध्ययन के लिए व्यवस्था लागू करना	10-03-2018	**फ्रांस**	अंतरिक्ष विभाग
84	भारत और फ्रांस के बीच प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी	10-03-2018	**फ्रांस**	विदेश मंत्रालय
85	भारत के रेल मंत्रालय और फ्रांसीसी गणराज्य के पारिस्थितिक और समावेशी संक्रमण मंत्रालय के बीच आशय पत्र	10-03-2018	**फ्रांस**	रेल मंत्रालय
86	भारत और फ्रांसीसी गणराज्य के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता	10-03-2018	**फ्रांस**	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
87	भारत और फ्रांसीसी गणराज्य के बीच शैक्षणिक योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता की सुविधा के लिए समझौता	10-03-2018	**फ्रांस**	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
88	भारत और सेवा हाइड्रोग्राफिक एंटेनोाग्राफिक डी ला मरीन (शोम) फ्रांस के बीच हाइड्रोग्राफी और समुद्री कार्टोग्राफी के मामले में सहयोग करने से संबंधित द्विपक्षीय व्यवस्था	08-03-2018	**फ्रांस**	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
89	इसरो और केन्स के बीच समुद्री क्षेत्र में जागरूकता मिशन के प्रति-गठन के अध्ययन के लिए व्यवस्था लागू करना	10-03-2018	**फ्रांस**	विदेश मंत्रालय
90	रेल मंत्रालय और संक्फमबलिटेस के बीच रेलवे के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर समझौता ज्ञापन	10-03-2018	**फ्रांस**	रेल मंत्रालय
91	भारत सरकार और फ्रांसीसी गणराज्य सरकार के बीच उनके सशस्त्र बलों के बीच पारस्परिक रसद समर्थन के प्रावधान के संबंध में करार	10-03-2018	**फ्रांस**	रक्षा मंत्रालय

	शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	देश	मंत्रालय
92	भारत और फ्रांस के बीच वर्गीकृत और संरक्षित जानकारी के आदान-प्रदान और पारस्परिक संरक्षण के संबंध में करार	10-03-2018	**फ्रांस**	रक्षा मंत्रालय
93	भारतीय अंतरिक्ष अनुसन्धान संगठन और सेंटर नेशनल डी'इट्डेस स्पटीकल्स ऑफ़ फ्रांस के बीच अंतरिक्ष जोडेसी कार्यकलाप और अनुप्रयोग पर कार्यान्वयन व्यवस्था	02-12-2018	**फ्रांस**	अंतरिक्ष विभाग
94	अंतर्राष्ट्रीय सौर संयोजन (आईएसए) संरचना पर करार	20-02-2018	**गैम्बिया**	नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय
95	डीजीएफएएसएलआई और डीजीयूवी के बीचव्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	13-11-2018	**जर्मनी**	श्रम और रोजगार मंत्रालय
96	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, भारत और जर्मन रिसर्च फाउंडेशन, जर्मनी के बीच जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए कार्यक्रम	08-10-2018	**जर्मनी**	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
97	भारत और घाना के बीच वर्ष 2018-2022 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	18-07-2018	**घाना**	विदेश मंत्रालय
98	भारतीय मानक ब्यूरो और घाना मानक प्राधिकरण के बीच मानकीकरण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन	18-07-2018	**घाना**	उपभोक्ता मामले मंत्रालय
99	भारत और घाना के बीच मानकीकरण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन	18-07-2018	**घाना**	उपभोक्ता मामले मंत्रालय
100	भारत और ग्रीस के बीच राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	18-06-2018	**ग्रीस**	विदेश मंत्रालय
101	भारत और ग्रीस के बीच वर्ष 2018-2020 के लिए सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम	18-06-2018	**ग्रीस**	संस्कृति मंत्रालय
102	भारत और ग्रीस के बीच मानकीकरण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	18-06-2018	**ग्रीस**	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजानिक वितरण मंत्रालय
103	विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय, भारत और राजनयिक अकादमी, विदेश मंत्रालय, ग्वाटेमाला गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन	07-05-2018	**ग्वाटेमाला**	विदेश मंत्रालय

	शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	देश	मंत्रालय
104	भारत और इक्वेटोरियल गिनी के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) में सहयोग पर कार्य योजना	08-04-2018	**गिनी**	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
105	गिनी के राष्ट्रीय स्वतंत्र चुनाव आयोग (CENI) के साथ भारत के चुनाव आयोग का समझौता ज्ञापन	24-01-2018	**गिनी**	भारतीय निर्वाचन आयोग
106	भारत गणराज्य सरकार और गुयाना सहकारी गणतंत्र सरकार के बीच वर्ष 2018-2021 में सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	18-06-2018	**गुयाना**	संस्कृति मंत्रालय
107	भारत और जॉर्डन के हाशमाइट साम्राज्य के बीच सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता पर करार	01-03-2018	**जॉर्डन**	वित्त मंत्रालय
108	भारत और इंडोनेशिया के बीच रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर समझौता ज्ञापन	29-05-2018	**इंडोनेशिया**	रेल मंत्रालय
109	भारत और इंडोनेशिया के बीच फार्मास्युटिकल पदार्थों, जैविक उत्पाद और सौंदर्य प्रसाधन विनियामक कार्यो के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	29-05-2018	**इंडोनेशिया**	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
110	भारत और इंडोनेशिया के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	28-05-2018	**इंडोनेशिया**	अंतरिक्ष विभाग
111	भारत और इंडोनेशिया के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर समझौता ज्ञापन	28-05-2018	**इंडोनेशिया**	विदेश मंत्रालय
112	भारत और इंडोनेशिया के बीच नीतिगत संवाद और सरकारों और विचार मंथन लिए वार्ता पर समझौता ज्ञापन	28-05-2018	**इंडोनेशिया**	विदेश मंत्रालय
113	भारत और ईरान के बीच दोहरे कराधान से बचने और आय पर कर के संबंध में राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए करार	17-02-2018	**ईरान**	वित्त मंत्रालय
114	भारत और ईरान के बीच राजनयिक पासपोर्ट के धारकों के लिए वीजा की अपेक्षा से छूट पर समझौता ज्ञापन	16-02-2018	**ईरान**	विदेश मंत्रालय
115	भारत और ईरान के बीच सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सहयोग पर समझौता ज्ञापन	17-02-2018	**ईरान**	डाक विभाग

	शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	देश	मंत्रालय
116	डाक विभाग, भारत और नेशनल पोस्ट कंपनी, ईरान के बीच समझौता ज्ञापन	17-02-2018	**ईरान**	डाक विभाग
117	आयुष मंत्रालय, भारत और स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय, ईरान के बीच पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	17-02-2018	**ईरान**	आयुष मंत्रालय
118	भारत और ईरान के बीच कृषि और सहायक कार्यकलापों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	17-02-2018	**ईरान**	कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय
119	पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन (पीएमओ), ईरान और इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के बीच अंतरिम अवधि के दौरान चाबहार के शहीद बेहेश्टी पोर्ट - चरण 1 के हिस्से के लिए पट्टे का अनुबंध।	17-02-2018	**ईरान**	नौवहन मंत्रालय
120	परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यापार उपायों पर एक विशेषज्ञ समूह की स्थापना पर समझौता ज्ञापन।	17-02-2018	**ईरान**	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
121	स्वास्थ्य और औषध के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	17-02-2018	**ईरान**	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
122	भारत और इरेल के बीच और राजनयिक, वाणिज्य दूतावास, तकनीकी व लाभप्रद नियोजन में संलिप्त राजनयिक व कांसुलर मिशन के प्रशासनिक कर्मचारियों के आश्रितों के लिए करार	21-03-2018	**आयरलैंड**	विदेश मंत्रालय
123	भारत और इजराइल के बीच फिल्म सह-उत्पादन पर करार	15-01-2018	**इजराइल**	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
124	भारत गणराज्य के ऊर्जा मंत्रालय और इजरायल राज्य के ऊर्जा और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	15-01-2018	**इजराइल**	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
125	सीसीआरएच और सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव कॉम्प्लिमेंट्री मेडिसिन, शारजेडेक मेडिकल सेंटर, यरूशलेम के बीच समझौता ज्ञापन	15-01-2018	**इजराइल**	आयुष मंत्रालय
126	भारत और इटली के बीच राजनयिक, कांसुलर, प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों की पारिश्रमिक गतिविधि पर करार	13-02-2018	**इटली**	विदेश मंत्रालय

	शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	देश	मंत्रालय
127	वी. वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई), नोएडा, श्रम और रोजगार मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इटली के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र के बीच समझौता ज्ञापन	30/10/2012 से 30/10/2018	**इटली**	श्रम और रोजगार मंत्रालय
128	भारत और जापान के बीच खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में सहयोग का ज्ञापन	29-10-2018	**जापान**	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
129	भारत और जापान के बीच डिजिटल साझेदारी पर सहयोग का ज्ञापन		**जापान**	
130	भारत और जापान के बीच डाक क्षेत्र में सहयोग का ज्ञापन	29-10-2018	**जापान**	डाक विभाग
131	भारत और जापान के बीच स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में सहयोग का ज्ञापन	29-10-2018	**जापान**	आयुष मंत्रालय
132	भारत और जापान के बीच पर्यावरण सहयोग के क्षेत्र में सहयोग का ज्ञापन	29-10-2018	**जापान**	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
133	जापान द्वारा कृषि और मत्स्य पालन के क्षेत्र में भारत में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम	29-10-2018	**जापान**	कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय
134	भारत के आयुष मंत्रालय और जापान की कनागावा प्रान्त सरकार के बीच स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन	29-10-2018	**जापान**	आयुष मंत्रालय
135	भारत और जॉर्डन के बीच राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की अपेक्षा से छूट पर करार	01-03-2018	**जॉर्डन**	विदेश मंत्रालय
136	भारत और जॉर्डन के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	01-03-2018	**जॉर्डन**	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
137	भारत और जॉर्डन के बीच प्रस्तावित खनन और रॉक फॉस्फेट के लाभ पर समझौता ज्ञापन, जॉर्डन में फॉस्फोरिक एसिड / डीएपी / एनपीके उर्वरकों के लिए जॉर्डन में उत्पादन सुविधा स्थापित करना, 100 प्रतिशत की छूट के लिए एक दीर्घकालिक समझौते के साथ भारत ले जाने के लिए समझौता ज्ञापन	01-03-2018	**जॉर्डन**	विदेश मंत्रालय

	शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	देश	मंत्रालय
138	भारत और जॉर्डन के बीच सीमा-शुल्क मामले में सहयोग और पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर करार	01-03-2018	**जॉर्डन**	गृह मंत्रालय
139	भारत और जॉर्डन के बीच जॉर्डन में भावी पीढ़ी के उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन	01-03-2018	**जॉर्डन**	विदेश मंत्रालय
140	भारत और जॉर्डन के बीच जनशक्ति के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	01-03-2018	**जॉर्डन**	विदेश मंत्रालय
141	भारत और जॉर्डन के बीच रक्षा सहयोग में समझौता ज्ञापन	03-01-2018	**जॉर्डन**	रक्षा मंत्रालय
142	भारत और जॉर्डन के बीच वर्ष 2018-2022 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	03-01-2018	**जॉर्डन**	संस्कृति मंत्रालय
143	भारत और कोरिया के बीच पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	05-11-2018	**कोरिया**	पर्यटन मंत्रालय
144	संचार मंत्रालय, भारत गणराज्य और विज्ञान और आईसीटी मंत्रालय, कोरिया गणराज्य के बीच दूरसंचार/आई सी टी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	10-07-2018	**कोरिया**	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
145	भारत और कुवैत के बीच राजनयिक, विशेष और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा अपेक्षा से परस्पर छूट पर करार	31-10-2018	**कुवैत**	विदेश मंत्रालय
146	भारत गणराज्य और लिकटेंस्टीन की रियासत की सरकार के बीच वित्तीय लेखे की सूचना के स्वचालित विनिमय के क्षेत्र में परस्पर करार	11-10-2018	**लिकटेंस्टीन**	वित्त मंत्रालय
147	भारत और मेडागास्कर के बीच मौजूदा द्विपक्षीय वायु सेवा समझौते में सहकारी विपणन व्यवस्था पर समझौता ज्ञापन	31-03-2018	**मेडागास्कर**	नागर विमानन मंत्रालय
148	भारत और मेडागास्कर के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	31-03-2018	**मेडागास्कर**	रक्षा मंत्रालय
149	परमाणु ऊर्जा भागीदारी वैश्विक केंद्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत और प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा और खनन मंत्रालय, मलावी के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग का समझौता ज्ञापन	05-11-2018	**मलावी**	परमाणु ऊर्जा विभाग
150	भारत और मलावी के बीच प्रत्यर्पण संधि	05-11-2018	**मलावी**	गृह मंत्रालय

	शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	देश	मंत्रालय
151	भारत और मलावी के बीच राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की अपेक्षा से छूट पर समझौता	05-11-2018	**मलावी**	विदेश मंत्रालय
152	भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग पर समझौता ज्ञापन	21-11-2018	**मलेशिया**	रक्षा मंत्रालय
153	भारत और माल्टा के बीच पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	17-09-2018	**माल्टा**	पर्यटन मंत्रालय
154	विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय, भारत गणराज्य और मेडिटरेनीयन अकादमी ऑफ़ डिप्लोमेटिक स्टडीज, माल्टा विश्वविद्यालय के बीच आपसी सहयोग पर समझौता ज्ञापन	17-09-2018	**माल्टा**	विदेश मंत्रालय
155	भारत और माल्टा के बीच समुद्री सहयोग पर समझौता ज्ञापन	17-09-2018	**माल्टा**	पोत परिवहन मंत्रालय
156	भारत और मारीशस के बीच नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में समझौता ज्ञापन	12-03-2018	**मारीशस**	विदेश मंत्रालय
157	भारत और मारीशस के बीच सांस्कृतिक सहयोग के लिए कार्यक्रम	12-03-2018	**मारीशस**	संस्कृति मंत्रालय
158	केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत और मारीशस विश्वविद्यालय, शिक्षा और मानव संसाधन मंत्रालय, तृतीयक शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान के बीच आयुर्वेद में एक "शैक्षणिक अध्यक्ष" की स्थापना पर समझौता ज्ञापन	12-03-2018	**मारीशस**	आयुष मंत्रालय
159	भारत के संघ लोक सेवा आयोग और पीएससी, मॉरीशस के बीच समझौता ज्ञापन	12-03-2018	**मारीशस**	संघ लोक सेवा आयोग
160	भारत के चुनाव आयोग और मोल्दोवा के केंद्रीय चुनाव आयोग के बीच समझौता ज्ञापन	24-01-2018	**माल्डोवा**	भारतीय निर्वाचन आयोग
161	प्रसार भारती, भारत और मंगोलियाई राष्ट्रीय सार्वजनिक राडिया और टेलीविजन, मंगोलिया के बीच प्रसारण पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	09-05-2018	**मंगोलिया**	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
162	भारत और मोरक्को के बीच खनन और भूविज्ञान के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन	11-04-2018	**मोरक्को**	खान मंत्रालय

	शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	देश	मंत्रालय
163	भारत और मोरक्को के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	10-04-2018	**मोरक्को**	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
164	भारत गणराज्य के विधि व न्याय मंत्रालय और मोरक्को साम्राज्य के न्याय मंत्रालय के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन	02-04-2018	**मोरक्को**	विधि और न्याय मंत्रालय
165	भारत और मोरक्को के बीच नागरिक और वाणिज्यिक मामलों में कानूनी और न्यायिक सहयोग में करार , जिसमें समन की तामील, न्यायिक दस्तावेज, अनुरोध पत्र और निर्णयों का निष्पादन और मध्यस्थता पुरस्कार शामिल हैं।	12-09-2018	**मोरक्को**	विधि और न्याय मंत्रालय
166	भारत और मोरक्को के बीच हवाई सेवा करार	19-09-2018	**मोरक्को**	नागर विमानन मंत्रालय
167	भारत और मोरक्को के बीच आधुनिकीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर संयुक्त घोषणा	12-11-2018	**मोरक्को**	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
168	मोरक्कन टूरिज़्म डेवलपमेंट एजेंसी और भारत पर्यटन विकास निगम के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन	17-09-2018	**मोरक्को**	पर्यटन मंत्रालय
169	भारत गणराज्य सरकार और मोरक्को साम्राज्य सरकार के बीच अंतरिक्ष के लाभप्रद प्रयोगों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	25-09-2018	**मोरक्को**	अंतरिक्ष विभाग
170	भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी-इन), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और मोरक्को कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (मा-सीईआरटी), मोरक्को के साम्राज्य के राष्ट्रीय रक्षा प्रशासन, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर (एमओयू) के बीच समझौता ज्ञापन 25 सितंबर 2018)	25-09-2018	**मोरक्को**	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
171	दाण्डिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता पर करार	12-09-2018	**मोरक्को**	गृह मंत्रालय
172	भारतीय गणराज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय आसूचना विज्ञान केंद्र के बीच सूचना और प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण और उपयोग के क्षेत्र में सहयोग की मंशा पर संयुक्त घोषणा	12-09-2018	**मोरक्को**	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

	शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	देश	मंत्रालय
173	भारत गणराज्य और मोरक्को राष्ट्र सरकार के बीच प्रत्यर्पण करार	13-11-2018	**मोरक्को**	विदेश मंत्रालय
174	भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार और मोजांबिक के राष्ट्रीय प्रलेखन और सूचना केंद्र के बीच अभिलेखीय सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन	29-11-2018	**मोजांबिक**	संस्कृति मंत्रालय
175	भारत और मोजांबिक के बीच अभिलेखीय सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन	29-11-2018	**मोजांबिक**	संस्कृति मंत्रालय
176	भारत और म्यांमार के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन	10-05-2018	**म्यांमार**	विदेश मंत्रालय
177	भारत और म्यांमार के बीच सिटवे बंदरगाह के संचालन और रखरखाव और पलटवा अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल और संबद्ध सुविधाओं के लिए एक निजी प्रचालक की नियुक्ति के लिए समझौता ज्ञापन	22-10-2018	**म्यांमार**	पोत परिवहन मंत्रालय
178	भारत और नेपाल के बीच रक्सौल और काठमांडू के बीच ब्रॉड गेज लाइन के इंजीनियरिंग-सह-यातायात सर्वेक्षण के संबंध में समझौता ज्ञापन	24-09-2018	**नेपाल**	विदेश मंत्रालय
179	भारत और नेदरलैंड के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन	23-01-2018	**नेदरलैंड**	विदेश मंत्रालय
180	विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय, भारत गणराज्य और नेदरलैंड साम्राज्य के विदेश मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन	23-05-2018	**नेदरलैंड**	विदेश मंत्रालय
181	भारत और नेदरलैंड के बीच स्थानिक योजना, जल प्रबंधन और गतिशीलता प्रबंधन के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर समझौता ज्ञापन	11-04-2018	**नेदरलैंड**	जल संसाधन मंत्रालय
182	नीदरलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए	24-05-2018	**नेदरलैंड**	नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय
183	भारत और नाइजर के बीच महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर के निर्माण से संबंधित समझौता ज्ञापन	19-09-2018	**नाइजर**	विदेश मंत्रालय
184	भारत और नाइजीरिया के बीच अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग के क्षेत्र में सहयोग पर करार	19-09-2018	**नाइजीरिया**	अंतरिक्ष विभाग

	शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	देश	मंत्रालय
185	भारत गणराज्य सरकार के रक्षा मंत्रालय औ रनाइजीरिया के संघीय गणराज्य के रक्षा मंत्रालय के बीच रक्षा अनुसंधान और विकास में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन	20-11-2018	**नाइजीरिया**	रक्षा मंत्रालय
186	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और उमरु मूसा यरदुआ विश्वविद्यालय, कटसीना नाइजीरिया के बीच संस्कृत भाषा के लिए आई सी सी आर चेयर की स्थापना पर समझौता किया गया	08-10-2018	**नाइजीरिया**	संस्कृति मंत्रालय
187	केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान स्टेशन, नई दिल्ली और नार्वे के जियोटेक्निकल इंस्टीट्यूट, ओस्लो, नॉर्वे के बीच जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	06-06-2018	**नॉर्वे**	जल संसाधन, गंगा पुनरोद्धार और गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय
188	भारत और ओमान के बीच राजनयिक , विशेष, सेवा और आधिकारिक पासपोर्ट के धारकों के लिए परस्पर वीजा छूट पर करार	11-02-2018	**ओमान**	विदेश मंत्रालय
189	भारत और ओमान के बीच पर्यटन सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन	11-02-2018	**ओमान**	पर्यटन मंत्रालय
190	भारत और ओमान के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	11-02-2018	**ओमान**	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
191	भारत और ओमान के बीच कूटनीतिक अध्ययन और प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन	11-02-2018	**ओमान**	विदेश मंत्रालय
192	भारत और ओमान के बीच बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग परसमझौता ज्ञापन	11-02-2018	**ओमान**	अंतरिक्ष विभाग
193	भारत और ओमान के बीच नागरिक और वाणिज्यिक मामलों में कानूनी और न्यायिक सहयोग पर करार	11-02-2018	**ओमान**	विधि और न्याय मंत्रालय
194	भारत और पनामा के बीच राजनयिक, आधिकारिक और कांसुलर पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा अपेक्षा की छूट पर करार	09-05-2018	**पनामा**	विदेश मंत्रालय
195	भारत और पनामा के बीच कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए वर्ष 2018-2019 के लिए कार्य योजना	09-05-2018	**पनामा**	कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय

	शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	देश	मंत्रालय
196	भारत गणराज्य के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और पेरू गणराज्य के ऊर्जा और खनन मंत्रालय के बीच नवीन और नवीन ऊर्जा में सहयोग पर करार	11-05-2018	**पेरू**	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
197	भारत और पेरू के बीच सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता पर करार	05-12-2018	**पेरू**	वित्त मंत्रालय
198	वायु सेवाओं पर समझौता ज्ञापन	12-07-2018	**फिलीपींस**	नागर विमानन मंत्रालय
199	इन्वेस्टमेंट बोर्ड (फिलीपींस) और इन्वेस्ट इंडिया (भारत) के बीच समझौता ज्ञापन		**फिलीपींस**	वित्त मंत्रालय
200	भारत और रोमानिया के बीच पर्यटन सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन	19-09-2018	**रोमानिया**	पर्यटन मंत्रालय
201	भारत और रूस के बीच 2019-2023 की अवधि के लिए परामर्श हेतु प्रोटोकॉल	05-10-2019	**रूस**	विदेश मंत्रालय
202	भारत और रूस के बीच मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम के अंतरगत संयुक्त गतिविधियों पर समझौता ज्ञापन	05-10-2018	**रूस**	इसरो
203	भारत और रूस के बीच रेलवे में तकनीकी सहयोग पर एमओसी	05-10-2018	**रूस**	रेल मंत्रालय
204	भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से परमाणु क्षेत्र में सहयोग क्षेत्रों के प्राथमिकताकरण और कार्यान्वयन की कार्य योजना	05-10-2018	**रूस**	परमाणु ऊर्जा विभाग
205	भारत और रूस के बीच परिवहन शिक्षा में सहयोग के विकास में समझौता ज्ञापन	05-10-2018	**रूस**	रेल मंत्रालय
206	रूसी संघ के आर्थिक विकास मंत्रालय और नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफ़ॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग) के बीच समझौता ज्ञापन	05-10-2018	**रूस**	नीति आयोग
207	भारत और रवांडा के बीच कृषि और पशु संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	23-07-2018	**रवांडा**	कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय
208	भारत और रवांडा के बीच वर्ष 2018-2022 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	23-07-2018	**रवांडा**	विदेश मंत्रालय

	शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	देश	मंत्रालय
209	भारत और रवांडा के बीच व्यापार सहयोग ढांचा	23-07-2018	**रवांडा**	विदेश मंत्रालय
210	भारत और रवांडा के बीच क्षमता निर्माण, रक्षा उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रक्षा क्षेत्रों में सहयोग पर करार	23-07-2018	**रवांडा**	रक्षा मंत्रालय (वेबसाइट पर नहीं)
211	भारत और सेंट किट्स और नेविस के बीच राजनयिक और आधिकारिक / सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की अपेक्षा से छूट पर करार	16-02-2018	**सेंट किट्स एंड नेविस**	विदेश मंत्रालय
212	भारत और द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ साओ -टोमे के बीच फ्रेमवर्क समझौता और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में सहयोग पर संरचना करार	07-09-2018	**साओ -तोमे**	अंतरिक्ष विभाग
213	राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुष मंत्रालय और कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय, साओ-टोम के बीच औषधीय पौधों के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	14-03-2018	**साओ -तोमे**	आयुष मंत्रालय
214	आयुष मंत्रालय, भारत और स्वास्थ्य मंत्रालय, साओ -तोमे के बीच पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	14-03-2018	**साओ -तोमे व प्रिन्सिपे**	आयुष मंत्रालय
215	भारत और सेनेगल के बीच सेंटर डी'एंट्रेप्रेनरियत एट डे डेवलपमेंट टेक्निक के विकास और आधुनिकीकरण के लिए इस परियोजना से संबंधित समझौता ज्ञापन	27-02-2018	**सेनेगल**	विदेश मंत्रालय
216	भारत और सर्बिया के बीच संस्कृति, कला, युवा, खेल और मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग पर करार	03-05-2018	**सर्बिया**	संस्कृति मंत्रालय
217	भारत और सर्बिया के बीच समझौता ज्ञापन	25-01-2018	**सर्बिया**	विदेश मंत्रालय
218	भारत और सर्बिया के बीच पादप स्वस्थता और पादप संगरोध में करार	15-09-2018	**सर्बिया**	कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय
219	भारत और सर्बिया के बीच हवाई सेवा करार	15-09-2018	**सर्बिया**	नागर विमानन मंत्रालय
220	भारत और सेशेल्स के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन	24-06-2018	**सेशेल्स**	विदेश मंत्रालय

	शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	देश	मंत्रालय
221	भारत और सेशेल्स के बीच असम्प्शन द्वीप, सेशेल्स में विकास, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव पर सुविधाओं और प्रबंधन पर करार	27-01-2018	**सेशेल्स**	विदेश मंत्रालय
222	भारतीय नौसेना और सेशेल्स गणराज्य के बीच राष्ट्रीय सूचना साझाकरण और समन्वय केंद्र के वाइट शिपिंग जानकारी साझा करने पर तकनीकी करार	24-06-2018	**सेशेल्स**	रक्षा मंत्रालय
223	भारत गणराज्य के भारतीय कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-आईएन), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सेशल्स गणराज्य के सूचना संचार प्रौद्योगिकी के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	24-06-2018	**सेशेल्स**	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
224	भारत गणराज्य सरकार और सेशेल्स गणराज्य सरकार के बीच स्थानीय निकाय, शैक्षिक और व्यावसायिक संस्थानों के माध्यम से लघु विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारतीय अनुदान सहायता के सम्बन्ध में समझौता ज्ञापन	24-06-2018	**सेशेल्स**	विदेश मंत्रालय
225	पणजी शहर (नगर निगम) कारपोरेशन और सेशल्स गणराज्य के विक्टोरिया शहर के बीच मैत्री और सहयोग की स्थापना पर ट्विनिंग समझौता	24-06-2018	**सेशेल्स**	आवास और शहरी विकास मंत्रालय
226	भारत सरकार और सेशल्स गणराज्य सरकार के बीच वर्ष 2018-2022 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	24-06-2018	**सेशेल्स**	संस्कृति मंत्रालय
227	सिंगापुर गणराज्य की नौसेना और भारत गणराज्य की नौसेना के बीच नौसेना जहाज, पनडुब्बी और नौसेना वायुयान (विमानन परिसंपत्तियां धारित जहाज सहित) परस्पर समन्वय लोजिस्टिक्स और सेवा समर्थन के लिए व्यवस्था कार्यान्वित करना	01-06-2018	**सिंगापुर**	रक्षा मंत्रालय
228	राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) और सिंगापुर कोऑपरेशन एंटरप्राइज के बीच नियोजन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	01-06-2018	**सिंगापुर**	वित्त मंत्रालय
229	भारत के कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय और सिंगापुर गणराज्य के लोक सेवा प्रभाग के बीच कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	01-06-2018	**सिंगापुर**	कार्मिक , जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय

	शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	देश	मंत्रालय
230	भारत के आर्थिक मामले विभाग और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) के बीच समझौता ज्ञापन	01-06-2018	**सिंगापुर**	वित्त मंत्रालय
231	भारत - सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग करार पर द्वितीय समीक्षा पर संयुक्त वक्तव्य	01-06-2018	**सिंगापुर**	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
232	भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत और सिंगापुर कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, साइबर सुरक्षा एजेंसी सिंगापुर के बीच, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन का विस्तार	01-06-2018	**सिंगापुर**	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
233	भारत गणराज्य और सिंगापुर के बीच नर्सिंग सेवाओं पर परस्पर मान्यता करार पर व्यापक आर्थिक सहयोग करार	01-06-2018	**सिंगापुर**	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
234	भारत के कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय और सिंगापुर गणराज्य के लोक सेवा प्रभाग के बीच कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	01-06-2018	**सिंगापुर**	कार्मिक , जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय
235	भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सिंगापुर के सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो के बीच नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक पदार्थों और उनके प्रकरसोरस में अवैध तस्करी रोकने के सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	01-06-2018	**सिंगापुर**	गृह मंत्रालय
236	सिंगापुर गणराज्य की नौसेना और भारत गणराज्य की नौसेना के बीच नौसेना जहाज, पनडुब्बी और नौसेना वायुयान, (विमानन परिसंपत्तियां धारित जहाज सहित) परस्पर समन्वय लोजिस्टिक्स और सेवा समर्थन के लिए व्यवस्था कार्यान्वित करना	01-06-2018	**सिंगापुर**	रक्षा मंत्रालय
237	भारत और सोमालिया के बीच समझौता ज्ञापन	05-06-2018	**सोमालिया**	विदेश मंत्रालय
238	भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दक्षिण अफ्रीका में कारीगर कौशल के लिए गांधी मंडेला विशेषज्ञता केंद्र की स्थापना से संबंधित समझौता ज्ञापन	26-07-2018	**दक्षिणी अफ्रीका**	विदेश मंत्रालय
239	भारत और श्रीलंका के बीच सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	15-01-2018	**श्रीलंका**	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

	शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	देश	मंत्रालय
240	भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में पारगमन संबंधी अवैध गतिविधियां और क्षेत्रीय सहयोग विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन	09-05-2018	**श्रीलंका**	रक्षा मंत्रालय
241	भारतीय तटरक्षक और श्रीलंका तटरक्षक के बीच समझौता ज्ञापन	05-06-2018	**श्रीलंका**	रक्षा मंत्रालय
242	भारत और सूरीनाम के बीच लाभप्रद नियोजन में संलिप्त राजनयिक मिशन अथवा कांसुलर पोस्ट के सदस्यों के आश्रितों को अधिकृत करने की व्यवस्था करना	18-06-2018	**सूरीनाम**	विदेश मंत्रालय
243	भारत और सूरीनाम के बीच आशय पत्र	18-06-2018	**सूरीनाम**	विदेश मंत्रालय
244	भारत और सूरीनाम के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन	18-06-2018	**सूरीनाम**	विदेश मंत्रालय
245	भारत और सूरीनाम के बीच चुनाव के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर समझौता ज्ञापन	18-06-2018	**सूरीनाम**	भारतीय निर्वाचन आयोग
246	भारत और सूरीनाम के बीच सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए एक केंद्र की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन	18-06-2018	**सूरीनाम**	विदेश मंत्रालय
247	भारत के चुनाव आयोग और महासचिव, चुनाव, गृह मंत्रालय, सूरीनाम के बीच समझौता ज्ञापन	18-06-2018	**सूरीनाम**	गृह मंत्रालय
248	भारत और स्वाज़ीलैंड के बीच राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की अपेक्षा से छूट पर करार	09-04-2018	**स्वाज़ीलैंड**	विदेश मंत्रालय
249	भारत और स्वाज़ीलैंड के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	09-04-2018	**स्वाज़ीलैंड**	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
250	आंध्र प्रदेश राज्य और ज्यूरिख के कैंटन के बीच सिस्टर स्टेट समझौते के लिए जनवरी 2018 में आशय पत्र	22-01-2018	**स्विट्ज़रलैंड**	आंध्र प्रदेश सरकार
251	भारत और सीरिया के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन	25-01-2018	**सीरिया**	विदेश मंत्रालय

	शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	देश	मंत्रालय
252	तजाकिस्तान गणराज्य की सरकार और भारत सरकार के बीच सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता पर करार	08-05-2018	**तजाकिस्तान**	वित्त मंत्रालय
253	भारत गणतंत्र के युवा मामले और खेल मंत्रालय और युवा मामलों और तजिकिस्तान गणराज्य सरकार के अंतर्गत युवा मामले व खेल समिति के बीच युवा मामलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	08-10-2018	**तजिकिस्तान**	युवा मामले और खेल मंत्रालय
254	विदेश मंत्रालय, भारत और तजिकिस्तान के बीच 2018-21 की अवधि के लिए सहयोग कार्यक्रम	08-10-2018	**तजिकिस्तान**	विदेश मंत्रालय
255	भारत गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय और ताजिकिस्तान गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-1923 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	08-10-2018	**तजिकिस्तान**	संस्कृति मंत्रालय
256	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, भारत और ताजिक एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज के बीच कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए समझौता ज्ञापन	08-10-2018	**तजिकिस्तान**	भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्
257	केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय और " अबुअलीबन सिनो नामक ताजिक स्टेट चिकित्सा विश्वविद्यालय के बीच यूनानी चिकित्सा क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	08-10-2018	**तजिकिस्तान**	आयुष मंत्रालय
258	भारत और तजिकिस्तान के बीच आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन	08-10-2018	**तजिकिस्तान**	गृह मंत्रालय
259	भारत और ताजिकिस्तान के बीच विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लाभप्रद प्रयोगों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	08-10-2018	**तजिकिस्तान**	अंतरिक्ष विभाग
260	नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय, भारत और ऊर्जा और जल संसाधन मंत्रालय, ताजिकिस्तान के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	08-10-2018	**तजिकिस्तान**	नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय
261	भारत और तंज़ानिया के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन	16-10-2018	**तंज़ानिया**	विदेश मंत्रालय

	शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	देश	मंत्रालय
262	भारत और तिमोर-लेस्ते के बीच स्वास्थ्य देख-भल और जन स्वास्थ्य के सहयोग में समझौता ज्ञापन	07-04-2018	**तिमोर-लेस्ते**	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
263	वीवीजीएनएलआई और आईटीसी, आईएलओ, तुरीन प्रशिक्षण और शिक्षा गतिविधियों अंडरटेकिंग के बीच दुनिया में अच्छे काम को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन	28-11-2018	**तुरीन**	श्रम और रोजगार मंत्रालय
264	यूगांडा और भारत के बीच राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट के धारकों के लिए वीजा की अपेक्षाओं से छूट पर करार	24-07-2018	**यूगांडा**	विदेश मंत्रालय
265	भारत और यूगांडा के बीच रक्षा सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन	24-07-2018	**यूगांडा**	रक्षा मंत्रालय
266	भारत और यूगांडा के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर समझौता ज्ञापन	24-07-2018	**यूगांडा**	संस्कृति मंत्रालय
267	भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच कूटनीतिक अध्ययन और प्रशिक्षण के क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	25-06-2018	**संयुक्त अरब अमीरात**	विदेश मंत्रालय
268	संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच रेल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर समझौता ज्ञापन	10-02-2018	**संयुक्त अरब अमीरात**	रेल मंत्रालय
269	भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जनशक्ति के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन	10-02-2018	**संयुक्त अरब अमीरात**	विदेश मंत्रालय
270	संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच जनशक्ति के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन के लिए घरेलू कामगारों पर प्रोटोकॉल	10-02-2018	**संयुक्त अरब अमीरात**	विदेश मंत्रालय
271	अमीरात डिप्लोमेटिक अकादमी और भारत के विदेश सेवा संस्थान के बीच राजनयिक अध्ययन और प्रशिक्षण के क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	25-06-2018	**संयुक्त अरब अमीरात**	विदेश मंत्रालय
272	भारत की वित्तीय आसूचना यूनिट(FIU) और संयुक्त अरब अमीरात के मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और संदिग्ध मामलों यूनिट के बीच संबद्ध अपराध और आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधित वित्तीय आसूचना के आदान-प्रदान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	10-02-2018	**संयुक्त अरब अमीरात**	वित्त मंत्रालय

	शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	देश	मंत्रालय
273	विदेश मंत्रालय और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय के बीच अफ्रीका में परियोजनाओं में संयुक्त सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	24-06-2018	**संयुक्त अरब अमीरात**	वित्त मंत्रालय
274	भारतीय रिज़र्व बैंक और संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक के बीच भारतीय रुपया / संयुक्त अरब अमीरात दिरहम द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय व्यवस्था	04-12-2018	**संयुक्त अरब अमीरात**	विदेश मंत्रालय
275	विदेश मंत्रालय और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय के बीच अफ्रीका में परियोजनाओं में संयुक्त सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	30-11-2018	**संयुक्त अरब अमीरात**	
276	भारत और स्कॉटलैंड के बीच गंगा कायाकल्प पर समझौता ज्ञापन	04-12-2018	**संयुक्त अरब अमीरात**	विदेश मंत्रालय
277	भारत और यूनाइटेड किंगडम द्वारा ब्रिटेन में भारतीय कंपनियों के लिए एक फास्ट ट्रैक तंत्र की स्थापना पर संयुक्त घोषणा	17-04-2018	**यूनाइटेड किंगडम**	वित्त मंत्रालय
278	भारत और ब्रिटेन के बीच गंगा पुनर्जीवन के लिए समझौता ज्ञापन	17-04-2018	**यूनाइटेड किंगडम**	जल संसाधन, गंगा विकास और गंगा पुनरोद्धार मंत्रालय
279	भारत और ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम और उत्तरी आयरलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय आपराधिकता का मुकाबला करने और गंभीर संगठित अपराध से निपटने के लिए सहयोग और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन	17-04-2018	**यूनाइटेड किंगडम**	गृह मंत्रालय
280	भारत और ग्रेट ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम और उत्तरी आयरलैंड के बीच कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	17-04-2018	**यूनाइटेड किंगडम**	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
281	भारत और ग्रेट ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम और उत्तरी आयरलैंड के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	17-04-2018	**यूनाइटेड किंगडम**	आवास और शहरी मामले मंत्रालय
282	भारत और ग्रेट ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम और उत्तरी आयरलैंड के बीच पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	17-04-2018	**यूनाइटेड किंगडम**	कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय

	शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	देश	मंत्रालय
283	यूके-भारत के लिए साइबर संबंध फ्रेमवर्क	17-04-2018	**यूनाइटेड किंगडम**	गृह मंत्रालय
284	भारत के विदेश मंत्रालय और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलें और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय के बीच अफ्रीका में विकास सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	17-04-2018	**यूनाइटेड किंगडम**	राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय
285	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और व्यापार, ऊर्जा और औद्योगिक रणनीति विभाग (पहले व्यापार विभाग, नवाचार और कौशल विभाग के रूप में जाना जाता था) ग्रेट ब्रिटेन और ब्रिटेन के उत्तरी आयरलैंड की सरकार के बीच मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान और साझेदारी को शामिल करने के लिए न्यूटन-भाभा कार्यक्रम के लिए समझौता ज्ञापन में संशोधन	18-04-2018	**यूनाइटेड किंगडम**	आयुष मंत्रालय
286	नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग, भारत गणराज्य सरकार और व्यवसाय, ऊर्जा और औद्योगिक रणनीति विभाग (BEIS) के बीच पारस्परिक समझ और सहयोग के लिए द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी पर मंशा का वक्तव्य	2018	**यूनाइटेड किंगडम**	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
287	भारत और संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के बीच नेपाल के नुवाकोट जिले में भारत सरकार द्वारा भूकंप से प्रभावित 23,088 आवास लाभार्थियों को सामाजिक-तकनीकी सुविधा प्रदान करने के लिए साझेदारी करार	2018	**यूनाइटेड किंगडम**	नीति आयोग
288	संयुक्त राज्य अमेरिका रक्षा नवाचार इकाई और भारतीय रक्षा नवाचार संगठन के बीच- रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार का मंशा ज्ञापन	2018	**संयुक्त राष्ट्र अमेरिका**	रक्षा मंत्रालय
289	भारत और उजबेकिस्तान के बीच राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की अपेक्षा से छूट पर करार	2018	**संयुक्त राष्ट्र अमेरिका**	रक्षा मंत्रालय
290	विदेश मंत्रालय, भारत और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बीच 2019-2020 के लिए सहयोग का कार्यक्रम	01-10-2018	**उज़्बेकिस्तान**	विदेश मंत्रालय

	शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	देश	मंत्रालय
291	भारत और उजबेकिस्तान के बीच पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग पर करार	01-10-2018	**उज़्बेकिस्तान**	विदेश मंत्रालय
292	भारत और उज़्बेकिस्तान के बीचकृषि और संबद्ध क्षेत्रों के क्षेत्र में सहयोग पर करार	01-10-2018	**उज़्बेकिस्तान**	कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय
293	भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार पर सहयोग के लिए करार	01-10-2018	**उज़्बेकिस्तान**	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
294	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत और स्वास्थ्य मंत्रालय, उज़्बेकिस्तान के बीच स्वास्थ्य और औषधीय विज्ञान में सहयोग पर करार	01-10-2018	**उज़्बेकिस्तान**	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
295	(i) अंदिजन क्षेत्र, उज़्बेकिस्तान के खोकीमियत (ii) स्वास्थ्य मंत्रालय, उज़्बेकिस्तान के अंतर्गत फार्मास्यूटिकल्स उद्योग के विकास के लिए एजेंसी (iii), रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत में फार्मास्यूटिकल्स विभाग के बीच उज़्बेकिस्तान गणराज्य के अंदिजन क्षेत्र में उज़्बेक -भारतीय मुक्त फार्मास्यूटिकल जोन की स्थापना के लिए सहयोग पर समझौता ज्ञापन	01-10-2018	**उज़्बेकिस्तान**	रसायन और उर्वरक मंत्रालय
296	भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक पदार्थों और उनके प्रकरसोरस में अवैध तस्करी रोकने के सहयोग के लिए करार	01-10-2018	**उज़्बेकिस्तान**	गृह मंत्रालय
297	विधि और न्याय मंत्रालय, भारत और न्याय मंत्रालय, उज़्बेकिस्तान के बीच विधि और न्याय के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	01-10-2018	**उज़्बेकिस्तान**	विधि और न्याय मंत्रालय
298	भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अन्वेषण और बाह्य अंतरिक्ष की खोज के प्रयोग में सहयोग पर करार	01-10-2018	**उज़्बेकिस्तान**	अंतरिक्ष विभाग
299	रक्षा मंत्रालय, भारत और रक्षा मंत्रालय, उज़्बेकिस्तान के बीच सैन्य शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन,	01-10-2018	**उज़्बेकिस्तान**	रक्षा मंत्रालय
300	राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, भारत और उज़्बेकिस्तान राष्ट्रपति के अंतर्गत सुरक्षा परिषद् कार्यालय के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	01-10-2018	**उज़्बेकिस्तान**	रक्षा मंत्रालय

	शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	देश	मंत्रालय
301	भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच फार्मास्युटिकल क्षेत्र उद्योग के विकास के लिए समझौता ज्ञापन	01-10-2018	**उज़्बेकिस्तान**	रसायन और उर्वरक मंत्रालय
302	भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच वर्ष 2019-2023 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	08-10-2018	**उज़्बेकिस्तान**	संस्कृति मंत्रालय
303	भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन	08-10-2018	**उज़्बेकिस्तान**	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
304	भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	08-10-2018	**उज़्बेकिस्तान**	गृह मंत्रालय
305	भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	08-10-2018	**उज़्बेकिस्तान**	अंतरिक्ष विभाग
306	भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच युवा मामलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	08-10-2018	**उज़्बेकिस्तान**	युवा और खेल मंत्रालय
307	भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच सूचना और प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग पर करार	01-10-2018	**उज़्बेकिस्तान**	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
308	वियतनाम के समाजवादी गणराज्य के सूचना और संचार मंत्रालय और भारत गणराज्य के संचार मंत्रालय के बीच संचार के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	24-01-2018	**वियतनाम**	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
309	भारत और जाम्बिया के बीच राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की आवश्यकता से छूट पर समझौता ज्ञापन	20-11-2018	**जाम्बिया**	विदेश मंत्रालय
310	भारत और ज़ाम्बिया के बीच ज़ाम्बिया में उद्यमिता विकास और सहकारी विकास केंद्र की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन	11-04-2018	**ज़ाम्बिया**	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
311	भारत और ज़ाम्बिया के बीच द्विपक्षीय न्यायिक क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	11-04-2018	**ज़ाम्बिया**	विधि और न्याय मंत्रालय
312	भारत और ज़ाम्बिया के लिए दोहरे कराधान से बचाव और आय पर कर के संबंध में राजकोषीय चोरी की रोकथाम पर करार	11-04-2018	**ज़ाम्बिया**	विधि और न्याय मंत्रालय

	शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	देश	मंत्रालय
313	भूविज्ञान, खनन के क्षेत्र में सहयोग और खनिज संसाधन के लिए समझौता ज्ञापन	11-04-2018	**ज़ाम्बिया**	वित्त मंत्रालय
314	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर कार्य योजना	2018	**ज़िम्बाब्वे**	खान मंत्रालय
315	पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	03-11-2018	**ज़िम्बाब्वे**	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
316	कला, संस्कृति और विरासत के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	2018	**ज़िम्बाब्वे**	आयुष मंत्रालय
317	प्रसारण पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	2018	**ज़िम्बाब्वे**	संस्कृति मंत्रालय
318	भारत और जाम्बिया के बीच राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा अपेक्षा की छूट पर समझौता ज्ञापन	11-04-2018	**ज़ाम्बिया**	विदेश मंत्रालय
319	शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए सुरक्षित परमाणु ऊर्जा उपयोग के विनियमन के क्षेत्र में सूचना और सहयोग के आदान-प्रदान की व्यवस्था	03-11-2018	**ज़िम्बाब्वे**	विदेश मंत्रालय

परिशिष्ट II

अनुसमर्थनों की सूची

	करार/संधि/समझौता ज्ञापन का नाम	देश / संगठन	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / अभिगमन की तिथि	लागू किए जाने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
1	भारत गणराज्य और अफगानिस्तान के इस्लामिक गणराज्य के बीच यात्री, व्यक्तिगत और कार्गो वाहन यातायात के विनियमन के लिए करार	**अफगानिस्तान**	11-09-17	02-02-18	कोई सूचना उपलब्ध नहीं।	विदेश मंत्रालय
2	भारत और अज़रबैजान के बीच राजनयिक, आधिकारिक और सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकता से छूट पर करार	**अज़रबैजान**	04-04-18	01-05-18	कोई सूचना उपलब्ध नहीं।	विदेश मंत्रालय
3	भारत और बहरीन के बीच राजनयिक और विशेष/ आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकता की छूट पर करार	**बहरीन**	15-07-18	24-09-18	कोई सूचना उपलब्ध नहीं।	विदेश मंत्रालय
4	बिम्सटेक ग्रिड इंटरकनेक्शन की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन	**बिम्सटेक**	31-08-18	13-11-18	कोई सूचना उपलब्ध नहीं।	विदेश मंत्रालय
5	भआरत गणराज्य की सरकार और बोत्सावाना गणराज्य की सरकार के बीच राजनयिक पासपोर्टधारकों के लिए वीज़ा आवश्यकताओं से छूट पर समझौता करार	**बोत्सवाना**	01-11-2018	18-12-18	कोई सूचना उपलब्ध नहीं	विदेश मंत्रालय

	करार/संधि/समझौता ज्ञापन का नाम	देश / संगठन	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / अभिगमन की तिथि	लागू किए जाने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
6	भारत और चीन जनवादी गणराज्य के हाँग काँग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के बीच आयकर और उससे संबंधित प्रोतोकॉल के संबंध में दोहरे कराधान से बचाव और वित्तीय धोखाधड़ी निवारण संबंधी करार	**चीन**	19-03-18	01-05-18	30-11-2018	वित्त मत्रांलय
7	भारत और चेक गणराज्य के बीच राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकताओं से छूट पर करार	**चेक**	07-09-18	01-10-18	कोई सूचना उपलब्ध नहीं।	विदेश मंत्रालय
8	यूरोपीय बैंक के पुनर्निर्माण और विकास के लिए 1990 करार	**यूरोप**		17-04-18	कोई सूचना उपलब्ध नहीं।	वित्त मत्रांलय
9	भारत और फ्रांसीसी गणराज्य के बीच नशीले पदार्थ, मादक द्रव्य तथा रासायनिक प्रीकरसर्स की अवैध तस्करी एवं उससे जुड़े अपराधों की रोकथाम संबंधी करार	**फ्रांस**	10-03-18	16-04-18	कोई सूचना उपलब्ध नहीं।	गृह मंत्रालय
10	भारत और फ्रांसीसी गणराज्य के बीच उनके सशस्त्र बलों के बीच पारस्परिक रसद समर्थन के प्रावधान के बारे में करार	**फ्रांस**	10-03-18	18-10-18	कोई सूचना उपलब्ध नहीं।	रक्षा मंत्रालय

	करार/संधि/समझौता ज्ञापन का नाम	देश / संगठन	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / अभिगमन की तिथि	लागू किए जाने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
11	डब्ल्यूआईपीओ प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि, 1996	**डब्लयूआईपीओ**	20-12-96	17-08-18	कोई सूचना उपलब्ध नहीं।	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
12	डब्ल्यूआईपीओ कॉपीराइट संधि, 1996	**डब्लयूआईपीओ**	20-12-96	17-08-18	कोई सूचना उपलब्ध नहीं।	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
13	भारत और जर्मनी के बीच सामाजिक सुरक्षा पर करार के कार्यान्वयन के लिए भारत और जर्मनी के बीच प्रशासनिक व्यवस्था।	**जर्मनी**	12.10.2011	26-03-2018	कोई सूचना उपलब्ध नहीं।	विदेश मंत्रालय
14	विदेश सेवा संस्थान (एफएसआई), विदेश मंत्रालय और डिप्लोमैटिक अकादमी, ग्वाटेमाला गणराज्य के विदेश मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन	**ग्वाटेमाला**	07-05-18	17-08-18	कोई सूचना उपलब्ध नहीं।	विदेश मंत्रालय
15	10 सितंबर, 2010 को बीजिंग में हस्ताक्षरित विमान (बीजिंग प्रोटोकॉल) के गैरकानूनी जब्ती के दमन के लिए अभिसमय से संबंधित अनुपूरक प्रोटोकॉल।	**आईसीएओ**	10-09-10	30-11-2018	कोई सूचना उपलब्ध नहीं।	नागरिक उड्डयन मंत्रालय
16	आईबीएसए निधि करार	**भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका**	17-10-17	05-11-18	कोई सूचना उपलब्ध नहीं।	विदेश मंत्रालय

	करार/संधि/समझौता ज्ञापन का नाम	देश / संगठन	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / अभिगमन की तिथि	लागू किए जाने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
17	भारत और ईरान इस्लामिक गणतंत्र के बीच राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की आवश्यकता से छूट पर समझौता ज्ञापन	**ईरान**	16-02-18	16-03-18	कोई सूचना उपलब्ध नहीं।	विदेश मंत्रालय
18	भारत और ईरान इस्लामिक गणतंत्र के बीच आयकर और उससे संबंधित प्रोतोकॉल के संबंध में दोहरे कराधान से बचाव और वित्तीय धोखाधड़ी निवारण संबंधी करार	**ईरान**	17-02-18	01-05-18	कोई सूचना उपलब्ध नहीं।	वित्त मत्रांलय
19	इज़राइल राज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच फिल्म सह-उत्पादन पर करार	**इजराइल**	15-01-18	01-10-18	कोई सूचना उपलब्ध नहीं।	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
20	भारत और जॉर्डन हाशेमाइट अधिराज्य के बीच राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्टधारकों के लिए वीज़ा आवश्यकता से छूट पर करार	**जॉर्डन**	01-03-18	16-03-18	कोई सूचना उपलब्ध नहीं।	विदेश मंत्रालय
21	भारत और जॉर्डन हाशेमाइट अधिराज्य के बीच सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर करार	**जॉर्डन**	01-03-18	31-05-18	कोई सूचना उपलब्ध नहीं।	वित्त मत्रांलय

	करार/संधि/समझौता ज्ञापन का नाम	देश / संगठन	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / अभिगमन की तिथि	लागू किए जाने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
22	भारत और कुवैत के बीच राजनयिक, विशेष और आधिकारिक पासपोर्टधारकों के लिए वीज़ा आवश्यकताओं में परस्पर छूट पर करार	**कुवैत**	31-10-18	13-11-18	कोई सूचना उपलब्ध नहीं।	विदेश मंत्रालय
23	भारत गणराज्य की सरकार और मलावी गणराज्य की सरकार के बीच राजनयिक, विशेष और आधिकारिक पासपोर्टधारकों के लिए वीजा की आवश्यकता से छूट पर करार	**मलावी**	5-11-18	8-12-18	कोई सूचना उपलब्ध नहीं।	विदेश मंत्रालय
24	भारत गणराज्य और लिथुआनिया के बीच प्रत्यर्पण संधि	**लिथुआनिया**	09-10-2017	18-12-18	कोई सूचना उपलब्ध नहीं	गृह मंत्रालय
25	मोरक्को और भारत के बीच आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता पर करार	**मोरक्को**	12-11-18	30-11-18	कोई सूचना उपलब्ध नहीं।	गृह मंत्रालय
26	भारत और ओमान की सल्तनत के बीच राजनयिक, विशेष, सेवा और आधिकारिक पासपोर्टधारकों के लिए आपसी वीजा छूट पर करार	**ओमान**	11.02.18	04-04-18	कोई सूचना उपलब्ध नहीं।	विदेश मंत्रालय

	करार/संधि/समझौता ज्ञापन का नाम	देश / संगठन	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / अभिगमन की तिथि	लागू किए जाने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
27	कतर राज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच कौशल विकास और योग्यता की पहचान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	**कतर**	05-06-16	08-12-2018	कोई सूचना उपलब्ध नहीं।	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
28	भारत और फेडरेशन ऑफ सेंट किट्स एंड नेविस के बीच राजनयिक तथा आधिकारिक / सेवा पासपोर्टधारकों के लिए वीजा की आवश्यकता से छूट पर करार	**संत किट्स और नेविस**	16-02-18	16-03-18	कोई सूचना उपलब्ध नहीं।	विदेश मंत्रालय
29	भारत और सूरीनाम के बीच राजनयिक, आधिकारिक और सेवा पासपोर्टधारकों के लिए वीजा की आवश्यकता से छूट पर करार	**सूरीनाम**	28-04-2017	06-06-18	कोई सूचना उपलब्ध नहीं।	विदेश मंत्रालय
30	भारत और स्वाजीलैंड अधिराज्य के बीच राजनयिक एवं आधिकारिक पासपोर्टधारकों के लिए वीजा की आवश्यकता से छूट पर करार	**स्वाज़ीलैंड**	09-04-18	08-05-18	कोई सूचना उपलब्ध नहीं।	विदेश मंत्रालय
31	भारत और ताजिकिस्तान के बीच सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता पर करार	**ताजिकिस्तान**	08-05-18	31-05-18	कोई सूचना उपलब्ध नहीं।	वित्त मत्रांलय

	करार/संधि/समझौता ज्ञापन का नाम	देश / संगठन	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / अभिगमन की तिथि	लागू किए जाने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
32	युगांडा गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकताओं से छूट पर करार	**युगांडा**	24-07-18	08-12-18	कोई सूचना उपलब्ध नहीं।	विदेश मंत्रालय
33	मरक्यूरी पर मिनामता अभिसमय	**संयुक्त राष्ट्र**	30-09-14	16-04-18	कोई सूचना उपलब्ध नहीं।	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
34	तम्बाकू उत्पादों में अवैध व्यापार को समाप्त करने के लिए प्रोटोकॉल	**संयुक्त राष्ट्र**		18-05-18 [क]	25-09-18	स्वास्थ्य मंत्रालय
35	भारत गणराज्य की सरकार तथा वियतनाम समाजवादी गणराज्य की सरकार के बीच शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए बाहृय अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में सहयोग पर कार्यढाँचा करार	**वियतनाम**	03-09-16	10-07-18	कोई सूचना उपलब्ध नहीं।	अंतरिक्ष विभाग
36	भारत गणराज्य की सरकार और जाम्बिया गणराज्य की सरकार के बीच राजनयिक पासपोर्टधारकों के लिए वीजा आवश्यकताओं की छूट पर समझौता ज्ञापन	**जाम्बिया**	11-04-18	25-06-18	कोई सूचना उपलब्ध नहीं।	विदेश मंत्रालय

	करार/संधि/समझौता ज्ञापन का नाम	देश / संगठन	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / अभिगमन की तिथि	लागू किए जाने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
37	भारत गणराज्य की सरकार और जिम्बाब्वे गणरज्य की सरकार के बीच राजनयिक पासपोर्टधारकों के लिए वीज़ा आवश्यकताओं से छूट पर करार	**जिम्बाब्वे**	03-11-2018	18-12-18	कोई सूचना उपलब्ध नहीं	विदेश मंत्रालय

अनुलग्नक III

2018 में जारी किए गए पूर्ण शक्तियों के दस्तावेज़ों की सूची

	संधि / समझौते का शीर्षक	देश	जारी करने की तारीख	प्रशासनिक मंत्रालय
1	सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता पर भारत और आर्मेनिया के बीच समझौता	**आर्मेनिया**	31-10-18	वित्त मत्रांलय
2	निवेश के संबंध में भारत और बेलारूस के बीच संधि	**बेलारूस**	17-09-18	वित्त मत्रांलय
3	सूचना के आदान-प्रदान और करों के संबंध में संग्रहण में सहायता के लिए भारत गणराज्य की सरकार और ब्रुनेई दारुसलाम के महामहिम सुल्तान और यांग डि-पर्टुआन की सरकार के बीच करार हेतु पूर्ण शक्तियां	**ब्रुनेई दारुस्सलाम**	18-10-18	वित्त मत्रांलय
4	भारत गणराज्य की सरकार और चिली गणराज्य की सरकार के बीच एक उच्च स्तरीय संयुक्त आयोग के गठन के लिए समझौता ज्ञापन	**चिली**	10-07-18	विदेश मंत्रालय
5	दोहरे कराधान से बचने और आय पर करों के संबंध में राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए भारत और चीन के जनवादी गणराज्य के हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के बीच समझौता।	**चीन**	09-03-18	वित्त मत्रांलय
6	दोहरे कराधान से बचने और आय और उसके प्रोटोकॉल पर करों के संबंध में राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए भारत और चीन के बीच समझौते में संशोधन संबंधी प्रोटोकॉल ।	**चीन**	15-10-18	वित्त मत्रांलय
7	भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति पर सहयोग के लिए भारत गणराज्य के आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी मंत्रालय और कोलंबिया गणराज्य के स्वास्थ्य और सामाजिक संरक्षण मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन।	**कोलंबिया**	01-10-18	आयुष मंत्रालय

	संधि / समझौते का शीर्षक	देश	जारी करने की तारीख	प्रशासनिक मंत्रालय
8	कृषि और मत्स्य पालन के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में भारत गणराज्य के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और कोलंबिया गणराज्य के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन।	**कोलंबिया**	01-10-18	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
9	पर्यटन विकास में सहयोग पर भारत गणराज्य के पर्यटन मंत्रालय और कोलंबिया गणराज्य के व्यापार, उद्योग और पर्यटन मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन।	**कोलंबिया**	01-10-18	पर्यटन मंत्रालय
10	भारत और कोलंबिया के बीच निवेश को बढ़ावा देने और संरक्षण के लिए समझौते के संबंध में कोलंबिया गणराज्य और भारत गणराज्य के बीच संयुक्त व्याख्यात्मक घोषणा पर 10 नवंबर, 2009 को हस्ताक्षर किए।	**कोलंबिया**	01-10-18	वित्त मत्रांलय
11	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत सरकार और डेनमार्क अधि राज्य की सरकार के बीच समझौता	**डेनमार्क**	08-05-18	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
12	दोहरे कराधान से बचने और आय और इसके प्रोटोकॉल पर करों के संबंध में राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए भारत और ईरान इस्लामी गणराज्य के बीच समझौता	**ईरान**	16-04-18	वित्त मत्रांलय
13	सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता पर भारत और पेरू के बीच समझौता	**पेरु**	30-11-18	वित्त मत्रांलय
14	सहकारिता पर भारत और फिलीपींस के बीच समझौता	**फिलीपींस**	23-01-18	वित्त मत्रांलय
15	करों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान के लिए भारत गणराज्य की सरकार और समोआ सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	**समोआ**	18-12-18	वित्त मंत्रालय
16	सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और आपसी सहायता पर भारत और ताजिकिस्तान के बीच समझौता	**ताजिकिस्तान**	04-04-18	वित्त मत्रांलय

अनुबंध IV

प्रभाग द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से वित्त पोषित सेमिनार, सम्मेलन, आदि

क्रम. सं.	संगोष्ठी / सम्मेलन	साझेदार/सहयोगी संगठन	दिनांक, स्थान
1	तीसरा भारत महासागर सम्मेलन	इंडिया फाउंडेशन	27 और 28 अगस्त 2018, हनोई, वियतनाम
2	चौथा रायसीना डायलॉग 2019	ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन	8-10 जनवरी 2019, नई दिल्ली
3	दूसरा इंडिया-यूएस फोरम	अनंत सेंटर	6 और 7 अप्रैल 2018, नई दिल्ली
4	तीसरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी शिखर सम्मेलन	कार्नेगी इंडिया	17-19 दिसंबर 2018, बेंगलुरु
5	प्रथम इंडिया यूरोपीय यूनियन स्ट्रैटेजी फोरम	कार्नेगी इंडिया	अराबिदा, पुर्तगाल
6	17 वां भारत-कोरिया ट्रैक 1.5 डायलॉग	अनंत सेंटर	31 अक्टूबर -1 नवंबर, 2018, सियोल, दक्षिण कोरिया
7	प्रथम भारत-कनाडा ट्रैक 1.5 डायलॉग	गेटवे हाउस	29 अक्टूबर - 2 नवंबर 2018, ओटावा, कनाडा
8	भारत-पाकिस्तान ट्रैक 2 डायलॉग	नीमराना पहल	28-30 अप्रैल 2018, इस्लामाबाद
9	तीसरा पश्चिम एशिया सम्मेलन	आईडीएसए	5 और 6 सितंबर 2018, नई दिल्ली
10	चौथा भारत-जापान ट्रैक 1.5 डायलॉग	दिल्ली नीति समूह	15 और 16 अक्टूबर 2018, नई दिल्ली
11	"ट्रम्प प्रेसीडेंसी, भारत, चीन, निकट पूर्व और ईरान के साथ अमेरिकी संबंधों" पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	विद्या प्रसारक मंडल	27 और 28 अप्रैल 2018, मुंबई
12	जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल-हुसैन द्वारा विशेष संबोधन	भारत इस्लामिक सेंटर	1 मार्च 2018, नई दिल्ली
13	त्रिपक्षीय आयोग की बैठकें (भारत सचिवालय)	अनंत सेंटर	वित्त वर्ष 2018-19

क्रम. सं.	संगोष्ठी / सम्मेलन	साझेदार/सहयोगी संगठन	दिनांक, स्थान
14	"बाहरी अंतरिक्ष साझेदारी" पर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	एकीकृत राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए फोरम (एफआईएनएस)	23 अक्टूबर 2018, गोवा
15	विदेश नीति पहुंच संबंधी पहल	पुणे इंटरनेशनल सेंटर	वित्त वर्ष 2018-19
16	एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर संगोष्ठी और सम्मेलन	जादवपुर एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस (जेएआईआर)	18 नवंबर 2018, डेरा नटुंग गवर्नमेंट कॉलेज, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश
17	"एशिया इन ट्रांजिशन" पर 9 वां द्विवार्षिक सम्मेलन	इंडियन एसोसिएशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक स्टडीज, कोलकाता	1 और 2 नवंबर 2018, चंडीगढ़

परिशिष्ट V

मंत्रालय की वर्तमान संस्वीकृत संख्या

क्र.सं.	संवर्ग / पद	मुख्यालय में पद	मिशनों में पद	कुल
1	ग्रेड I	5	28	33
2	ग्रेड II	6	40	46
3	ग्रेड III	38	132	170
4	ग्रेड IV	58	152	210
5	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड / वरिष्ठ स्केल	117	234	351
6	(i) जूनियर स्केल	10	37	47
	(ii) परिवीक्षार्थी रिजर्व	62		62
	(iii) अवकाश रिजर्व	15		15
	(iv) प्रतिनियुक्ति रिजर्व	19		19
	(v) प्रशिक्षण रिजर्व	7		7
	उप योग I	**337**	**623**	**960**
	भारतीय विदेश सेवा (बी)			
7	(i) ग्रेड I	118	125	243
	(ii) प्रतिनियुक्ति रिजर्व	6		6
8	(i) एकीकृत ग्रेड II और III	359	235	594
	(ii) अवकाश रिज़र्व	30		30
	(iii) प्रतिनियुक्ति रिजर्व	16		16
	(iv) प्रशिक्षण रिजर्व	25		25
9	(i) ग्रेड IV	214	539	753
	(ii) अवकाश रिज़र्व	60		60
	(iii) प्रतिनियुक्ति रिजर्व	54		54

क्र.सं.	संवर्ग / पद	मुख्यालय में पद	मिशनों में पद	कुल
10	(i) ग्रेड V / VI	173	84	257
	(ii) अवकाश रिज़र्व	60		60
	(iii) प्रतिनियुक्ति रिजर्व	14		14
11	(i) साइफर संवर्ग का ग्रेड II	47	47	94
	(ii) अवकाश रिज़र्व	5		5
12	(i) आशुलिपिक संवर्ग	383	544	927
	(ii) अवकाश रिज़र्व	47		47
	(iii) प्रशिक्षण रिजर्व (हिंदी)	10		10
	(iv) प्रतिनियुक्ति रिजर्व	12		12
13	दुभाषिया कैडर	9	26	35
14	एलएंडटी कैडर	20	3	23
	उप योग II	**1662**	**1603**	**3265**
	सकल योग (उप योग I + II)	**1999**	**2226**	**4225**

परिशिष्ट VI

सीधी भर्ती, प्रतिनयुक्ति और एलडीई पद्धति के माध्यम से भर्ती संबंधी आंकड़े

क्र.सं.	समूह	रिक्तियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
1	समूह 'क'	169	33	22	18
2	समूह 'ख'	173	30	23	0
3	समूह 'ग'	78	16	15	3
	कुल	**420**	**79**	**60**	**21**

परिशिष्ट VII

विभिन्न भाषाओं में दक्षता रखने वाले भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की संख्याः

क्रम संख्या	भाषा	अधिकारियों की संख्या
1	अरबी	114
2	बहासा इंडोनेशिया	10
3	बहासा मलय	02
4	बर्मी	06
5	चीनी	90
6	चेक	01
7	फ्रेंच	102
8	जर्मन	35
9	हिब्रू	08
10	जापानी	28

क्रम संख्या	भाषा	अधिकारियों की संख्या
11	कजाख	01
12	किश्वाहिली	02
13	कोरियाई	08
14	नेपाली	01
15	पश्तो	02
16	फ़ारसी	22
17	पोलिश	01
18	पुर्तगाली	25
19	रूसी	106
20	सिंहली	07
21	स्पेनिश	92
22	तुर्की	07
23	यूक्रेनी	01
24	वियतनामी	03
	कुल	**674**

परिशिष्ट -VIII

पासपोर्ट केंद्रों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों	संख्या	स्थान
1	आंध्र प्रदेश	4	विजयवाड़ा, तिरुपति, विशाखापत्तनम, भीमावरम
2	अरुणाचल प्रदेश	1	ईटानगर
3	असम*	1	गुवाहाटी
4	बिहार	2	पटना, दरभंगा
5	चंडीगढ़ UT	1	चंडीगढ़
6	छत्तीसगढ़	1	रायपुर
7	दिल्ली एनसीटी ***	3	हेराल्ड हाउस, शालीमार प्लेस, भीकाजी कामा प्लेस
8	गोवा	1	पणजी
9	गुजरात	5	मिताकली (अहमदाबाद), विजय क्रॉस रोड (अहमदाबाद), वडोदरा, राजकोट, सूरत।
10	हरियाणा	2	अंबाला, गुड़गांव।
11	हिमाचल प्रदेश	1	शिमला
12	जम्मू और कश्मीर	2	जम्मू, श्रीनगर
13	झारखंड	1	रांची
14	कर्नाटक	5	लालबाग (बेंगलुरु), मराठाहल्ली (बेंगलुरु), हुबली, मैंगलोर, कालाबुरागी।
15	मध्य प्रदेश	2	भोपाल, इंदौर।
16	महाराष्ट्र	8	अंधेरी (मुंबई), लोअर परेल (मुंबई), मलाड (मुंबई), पुणे, नागपुर, नासिक, सोलापुर, ठाणे।
17	मणिपुर	1	इंफाल
18	मेघालय	1	शिलांग
19	मिजोरम	1	आइजोल

क्र.सं.	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों	संख्या	स्थान
20	नगालैंड	1	दीमापुर
21	ओडिशा	1	भुवनेश्वर
22	पुडुचेरी	1	पुडुचेरी
23	पंजाब	5	अमृतसर, लुधियाना, जालंधर I और II, होशियारपुर।
24	राजस्थान	4	जयपुर, जोधपुर, सीकर, उदयपुर।
25	सिक्किम	1	गंगटोक।
26	तमिलनाडु	8	अमिनजिकराई (चेन्नई), सालिग्रामम (चेन्नई), तांबरम (चेन्नई), त्रिची, तंजावुर, मदुरै, तिरुनेलवेली, कोयंबटूर
27	तेलंगाना	5	अमीरपेट, बेगमपेट, टोली चौकी, निजामाबाद, करीमनगर
28	त्रिपुरा	1	अगरतला
29	उत्तर प्रदेश	6	लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद।
30	उत्तराखंड	1	देहरादून
31	पश्चिम बंगाल	3	कोलकाता, बेरहामपुर, सिलीगुड़ी।
	कुल	**93**	

* आरपीओ गुवाहाटी वर्तमान में पांच अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को भी कवर करता है।
** आरपीओ चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों को कवर करता है।
*** आरपीओ दिल्ली हरियाणा के कुछ हिस्सों को कवर करता है।
@आरपीओ कोलकाता में सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं।

परिशिष्ट -IX

कार्यशील डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीओपीएसके) की सूची

क्र.सं.	स्थान	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	पासपोर्ट कार्यालय
1	अनंतपुर	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
2	अमलापुरम	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम
3	राजमपेट (कोडुर)	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
4	बापतला	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
5	चित्तूर	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
6	एलुरु	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम
7	गुंटूर	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
8	कृष्णा-गुडिवाडा	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
9	नांदयाल	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
10	नरसारावपेट	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
11	ओंगोल	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
12	श्रीकाकुलम	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम
13	हिन्दुपुर	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
14	कडप्पा	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
15	काकीनाडा	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम
16	कुरनूल	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
17	नेल्लोर	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
18	राजमुंदरी	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम
19	विजयनगरम	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम
20	चांगलांग	अरुणाचल प्रदेश	गुवाहाटी
21	तिरप	अरुणाचल प्रदेश	गुवाहाटी
22	बारपेटा	असम	गुवाहाटी

क्र.सं.	स्थान	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	पासपोर्ट कार्यालय
23	डिब्रूगढ़	असम	गुवाहाटी
24	धुबरी	असम	गुवाहाटी
25	गोलपाड़ा	असम	गुवाहाटी
26	कार्बी आंगलोंग	असम	गुवाहाटी
27	कोकराझार	असम	गुवाहाटी
28	मंगलदोई	असम	गुवाहाटी
29	नौगांव	असम	गुवाहाटी
30	उत्तर लखीमपुर	असम	गुवाहाटी
31	सिलचर	असम	गुवाहाटी
32	सोनितपुर (तेजपुर)	असम	गुवाहाटी
33	तिनसुकिया	असम	गुवाहाटी
34	बेगूसराय	बिहार	पटना
35	बक्सर	बिहार	पटना
36	छपरा	बिहार	पटना
37	पूर्वी चंपारण (मोतिहारी)	बिहार	पटना
38	गया	बिहार	पटना
39	हाजीपुर	बिहार	पटना
40	मधुबनी	बिहार	पटना
41	मुंगेर	बिहार	पटना
42	मुजफ्फरपुर	बिहार	पटना
43	नालंदा	बिहार	पटना
44	नवादा	बिहार	पटना
45	पूर्णिया	बिहार	पटना
46	भागलपुर	बिहार	पटना
47	समस्तीपुर	बिहार	पटना

क्र.सं.	स्थान	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	पासपोर्ट कार्यालय
48	सिवान	बिहार	पटना
49	बेतिया	बिहार	पटना
50	बिलासपुर	छत्तीसगढ़	रायपुर
51	दुर्ग	छत्तीसगढ़	रायपुर
52	जांजगीर-चंपा	छत्तीसगढ़	रायपुर
53	राजनंदगांव	छत्तीसगढ़	रायपुर
54	सरगुजा	छत्तीसगढ़	रायपुर
55	सिलवासा	दादर और नगर हवेली	मुंबई
56	दमन	दमन	मुंबई
57	जनक पुरी	दिल्ली	दिल्ली
58	नेहरू प्लेस	दिल्ली	दिल्ली
59	पटपड़गंज	दिल्ली	दिल्ली
60	यमुना विहार	दिल्ली	दिल्ली
61	दक्षिण गोवा	गोवा	पणजी
62	अमरेली	गुजरात	अहमदाबाद
63	आनंद	गुजरात	अहमदाबाद
64	बारडोली	गुजरात	सूरत
65	भरूच	गुजरात	अहमदाबाद
66	दाहोद	गुजरात	अहमदाबाद
67	गांधीनगर	गुजरात	अहमदाबाद
68	जामनगर	गुजरात	अहमदाबाद
69	जूनागढ़	गुजरात	अहमदाबाद
70	खेड़ा	गुजरात	अहमदाबाद
71	पालनपुर	गुजरात	अहमदाबाद

क्र.सं.	स्थान	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	पासपोर्ट कार्यालय
72	भुज	गुजरात	अहमदाबाद
73	भावनगर	गुजरात	अहमदाबाद
74	मेहसाणा	गुजरात	अहमदाबाद
75	पोरबंदर	गुजरात	अहमदाबाद
76	पाटन	गुजरात	अहमदाबाद
77	साबरकांठा	गुजरात	अहमदाबाद
78	सुरेंद्रनगर	गुजरात	अहमदाबाद
79	वेरावल	गुजरात	अहमदाबाद
80	नवसारी	गुजरात	सूरत
81	वलसाड	गुजरात	सूरत
82	भिवानी	हरियाणा	चंडीगढ़
83	कैथल	हरियाणा	चंडीगढ़
84	करनाल	हरियाणा	चंडीगढ़
85	हिसार	हरियाणा	चंडीगढ़
86	पानीपत	हरियाणा	चंडीगढ़
87	यमुनानगर	हरियाणा	चंडीगढ़
88	फरीदाबाद	हरियाणा	दिल्ली
89	नारनौल	हरियाणा	दिल्ली
90	रोहतक	हरियाणा	दिल्ली
91	सोनीपत	हरियाणा	दिल्ली
92	मंडी	हिमाचल प्रदेश	शिमला
93	पालमपुर	हिमाचल प्रदेश	शिमला
94	हमीरपुर	हिमाचल प्रदेश	शिमला
95	कांगड़ा	हिमाचल प्रदेश	शिमला

क्र.सं.	स्थान	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	पासपोर्ट कार्यालय
96	कुल्लू	हिमाचल प्रदेश	शिमला
97	ऊना	हिमाचल प्रदेश	शिमला
98	कठुआ	जम्मू और कश्मीर	जम्मू
99	राजौरी	जम्मू और कश्मीर	जम्मू
100	अनंतनाग	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर
101	बारामूला	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर
102	उधमपुर	जम्मू और कश्मीर	जम्मू
103	लेह	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर
104	बोकारो	झारखंड	रांची
105	हजारीबाग	झारखंड	रांची
106	जमशेदपुर	झारखंड	रांची
107	देवघर	झारखंड	रांची
108	धनबाद	झारखंड	रांची
109	दुमका	झारखंड	रांची
110	मेदिनीनगर	झारखंड	रांची
111	मैसूर	कर्नाटक	बेंगलुरु
112	बेलगावी	कर्नाटक	बेंगलुरु
113	बेल्लारी	कर्नाटक	बेंगलुरु
114	बीदर	कर्नाटक	बेंगलुरु
115	दावणगेरे	कर्नाटक	बेंगलुरु
116	गडग	कर्नाटक	बेंगलुरु
117	हसन	कर्नाटक	बेंगलुरु
118	रायचूर	कर्नाटक	बेंगलुरु
119	शिवमोगा	कर्नाटक	बेंगलुरु

क्र.सं.	स्थान	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	पासपोर्ट कार्यालय
120	तुमाकुर	कर्नाटक	बेंगलुरु
121	उडुपी	कर्नाटक	बेंगलुरु
122	विजयपुर	कर्नाटक	बेंगलुरु
123	चैंगानूर	केरल	कोचीन
124	इडुक्की (कट्टप्पना)	केरल	कोचीन
125	कासरगोड	केरल	कोझिकोड
126	पलक्कड़	केरल	कोचीन
127	पथानामथिट्टा	केरल	त्रिवेंद्रम
128	कवारती	लक्षद्वीप	कोचीन
129	बालाघाट	मध्य प्रदेश	भोपाल
130	बेतुल	मध्य प्रदेश	भोपाल
131	छिंदवाड़ा	मध्य प्रदेश	भोपाल
132	दमोह	मध्य प्रदेश	भोपाल
133	देवास	मध्य प्रदेश	भोपाल
134	होशंगाबाद	मध्य प्रदेश	भोपाल
135	विदिशा	मध्य प्रदेश	भोपाल
136	जबलपुर	मध्य प्रदेश	भोपाल
137	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	भोपाल
138	रतलाम	मध्य प्रदेश	भोपाल
139	सागर	मध्य प्रदेश	भोपाल
140	सतना	मध्य प्रदेश	भोपाल
141	अहमदनगर	महाराष्ट्र	पुणे
142	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	मुंबई
143	बारामती	महाराष्ट्र	पुणे

क्र.सं.	स्थान	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	पासपोर्ट कार्यालय
144	बीड	महाराष्ट्र	पुणे
145	चंद्रपुर	महाराष्ट्र	नागपुर
146	घाटकोपर / विक्रोली	महाराष्ट्र	मुंबई
147	जलगांव	महाराष्ट्र	मुंबई
148	जलना	महाराष्ट्र	पुणे
149	लातूर	महाराष्ट्र	पुणे
150	वर्धा	महाराष्ट्र	नागपुर
151	कोल्हापुर	महाराष्ट्र	पुणे
152	नांदेड़	महाराष्ट्र	पुणे
153	पंढरपुर	महाराष्ट्र	पुणे
154	पिंपरी चिंचवड़	महाराष्ट्र	पुणे
155	राजापुर	महाराष्ट्र	मुंबई
156	सांगली	महाराष्ट्र	पुणे
157	सतारा	महाराष्ट्र	पुणे
158	तुरा	मेघालय	गुवाहाटी
159	अस्का	ओडिशा	भुवनेश्वर
160	बालासोर	ओडिशा	भुवनेश्वर
161	बारीपदा	ओडिशा	भुवनेश्वर
162	बेरहामपुर	ओडिशा	भुवनेश्वर
163	भवानीपटना	ओडिशा	भुवनेश्वर
164	ढेंकनाल	ओडिशा	भुवनेश्वर
165	क्योंझर	ओडिशा	भुवनेश्वर
166	राउरकेला	ओडिशा	भुवनेश्वर
167	संबलपुर	ओडिशा	भुवनेश्वर

क्र.सं.	स्थान	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	पासपोर्ट कार्यालय
168	कोरापुट	ओडिशा	भुवनेश्वर
169	कराईकल	पुडुचेरी	तिरुचिरापल्ली
170	बठिंडा	पंजाब	चंडीगढ़
171	पटियाला	पंजाब	चंडीगढ़
172	पठानकोट	पंजाब	जालंधर
173	फगवाड़ा	पंजाब	जालंधर
174	मोगा	पंजाब	जालंधर
175	अजमेर	राजस्थान	जयपुर
176	अलवर	राजस्थान	जयपुर
177	बांसवाड़ा	राजस्थान	जयपुर
178	बाड़मेर	राजस्थान	जयपुर
179	चित्तौड़गढ़	राजस्थान	जयपुर
180	चुरू	राजस्थान	जयपुर
181	करौली-धौलपुर	राजस्थान	जयपुर
182	कोटा	राजस्थान	जयपुर
183	बीकानेर	राजस्थान	जयपुर
184	हनुमानगढ़	राजस्थान	जयपुर
185	झुंझुनू	राजस्थान	जयपुर
186	जैसलमेर	राजस्थान	जयपुर
187	झालावाड़	राजस्थान	जयपुर
188	नागौर	राजस्थान	जयपुर
189	पाली	राजस्थान	जयपुर
190	श्रीगंगानगर	राजस्थान	जयपुर
191	कुन्नूर	तमिलनाडु	कोयंबटूर

क्र.सं.	स्थान	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	पासपोर्ट कार्यालय
192	कुड्डालोर	तमिलनाडु	चेन्नई
193	देवाकोत्तई	तमिलनाडु	मदुरै
194	तब मैं	तमिलनाडु	मदुरै
195	तेनकासी	तमिलनाडु	मदुरै
196	तिरुवन्नामलाई	तमिलनाडु	चेन्नई
197	वेल्लोर	तमिलनाडु	चेन्नई
198	विलुप्पुरम	तमिलनाडु	चेन्नई
199	राशिपुरम	तमिलनाडु	कोयंबटूर
200	सलेम	तमिलनाडु	कोयंबटूर
201	कन्याकूमारी	तमिलनाडु	मदुरै
202	डिंडीगुल (कोडई रोड)	तमिलनाडु	मदुरै
203	विरुधुनगर	तमिलनाडु	मदुरै
204	पेरम्बलुर	तमिलनाडु	तिरुचिरापल्ली
205	आदिलाबाद	तेलंगाना	हैदराबाद
206	भोंगीर	तेलंगाना	हैदराबाद
207	खम्मम	तेलंगाना	हैदराबाद
208	मेडक	तेलंगाना	हैदराबाद
209	महबूबनगर	तेलंगाना	हैदराबाद
210	नलगोंडा	तेलंगाना	हैदराबाद
211	सिद्दीपेट	तेलंगाना	हैदराबाद
212	वारंगल (हनमकोंडा)	तेलंगाना	हैदराबाद
213	अलीगढ़	उत्तर प्रदेश	गाज़ियाबाद
214	अमेठी	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
215	बदायूं	उत्तर प्रदेश	बरेली

क्र.सं.	स्थान	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	पासपोर्ट कार्यालय
216	बिजनौर	उत्तर प्रदेश	बरेली
217	बुलंदशहर	उत्तर प्रदेश	गाज़ियाबाद
218	चुनार	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
219	मुरादाबाद	उत्तर प्रदेश	बरेली
220	पीलीभीत	उत्तर प्रदेश	बरेली
221	आगरा	उत्तर प्रदेश	गाज़ियाबाद
222	फतेहपुर	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
223	मथुरा	उत्तर प्रदेश	गाज़ियाबाद
224	मेरठ	उत्तर प्रदेश	गाज़ियाबाद
225	बलिया	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
226	बलरामपुर	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
227	झांसी	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
228	गाजीपुर	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
229	अयोध्या / फैजाबाद	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
230	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
231	आजमगढ़	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
232	बहराइच	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
233	देवरिया	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
234	गोंडा	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
235	जौनपुर	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
236	मऊ	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
237	उन्नाव	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
238	प्रतापगढ़	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
239	रायबरेली	उत्तर प्रदेश	लखनऊ

क्र.सं.	स्थान	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	पासपोर्ट कार्यालय
240	रामपुर	उत्तर प्रदेश	बरेली
241	सीतापुर	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
242	सुल्तानपुर	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
243	अल्मोड़ा	उत्तराखंड	देहरादून
244	हल्द्वानी (काठगोदाम)	उत्तराखंड	देहरादून
245	नैनीताल	उत्तराखंड	देहरादून
246	रुड़की	उत्तराखंड	देहरादून
247	रुद्रपुर	उत्तराखंड	देहरादून
248	श्रीनगर	उत्तराखंड	देहरादून
249	अलीपुरद्वार	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
250	आसनसोल	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
251	बेलूरघाट	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
252	बर्धमान	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
253	बीरभूम (रामपुरहाट)	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
254	कूचबिहार	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
255	रायगंज (उत्तर दिनाजपुर)	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
256	चिनसुरा	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
257	डायमंड हार्बर	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
258	जलपाईगुड़ी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
259	मेदिनीपुर (खड़गपुर)	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
260	नादिया (कृष्णानगर)	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
261	उत्तरी कोलकाता (बीडॉन स्ट्रीट)	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
262	मालदा	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
263	बैरकपुर	पश्चिम बंगाल	कोलकाता

टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ

विदेश मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट
2018-19

यह वार्षिक रिपोर्ट वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है।

www.mea.gov.in